Index/अनुक्रमणिका

01. Index/ अनुक्रमणिका 01

02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board 06/07

03. Referee Board 08

04. Spokesperson 10/11

(Science / विज्ञान)

05. Evaluation Of Antidiabetic Activity In Vitro Studies Of Successive Extract Of Vinca Rosea Roots (Manoj Kumar Gajbhiye, Anun Kakkar, Praveen Koushley) 12

06. Species As Bio - Indicators Of Water Pollution In Narmada River At Jabalpur (Dr. Bazgha Athar, Dr. Gohar Hujaifa Khan) 16

07. A Statistical Approach To Multivariate Analysis Of Ground Water Quality (Dr. Neelu Singhai) 19

08. Indole Alkaloids In Catharanthus Roseus (Dr. Sushama Singh Majhi) 23

09. The College Campus Biodiversity Of Medicinal Plants Used In The Cure Of Skin Diseases (Dr. Shobha Sharma) 26

10. Environmental Pollution Causes And Its Effect On Human Health (Deepa Shroti) 29

11. Fixed Point Theorem In Pseudo Compact Tichonov Space (Ganesh Kumar Soni) 32

12. Ethno-Veterinary Uses Of Grasses In Nimar Region (M.P.) (Dr. Kiran Surage, Dr. Shweta Tiwari, Dr. Seema Agrawal) 34

13. Incidence Of Iron Deficiency Anemia In Pregnant Woman Coming To Distt. Hospital, Satna (Dr. Rashmi Singh) 36

14. Effect Of In Vivo Incubation Of Bovine Spermatozoa In The Uterus Of Rats Actively Xenoimmunized With Bovine Spermatozoa On Sperm Motility And Viability (Jayshree Hardenia, S.K. Jain, Asha Khanna) 38

15. रासायनिक उर्वरकों के स्वरूप एवं कृषि में प्रयोग का अध्ययन (छ.ग. के बिलासपुर संभाग के विशेष संदर्भ में) (नोर्बेलता एक्का) 40

16. वायु प्रदूषण एवं वाहनों से निष्कासित धुँआ (अंचल रामटेके) 44

17. ई-अवशिष्ट एवं इसके दुष्प्रभाव (अनिता सिंह, रागिनी सिंह) 47

(Home Science / गृह विज्ञान)

18. Health Status Of Girl Child Labourers In Relation To Their Family Environment (Dr. Nasreen Gazdar, Prof. Usha Kothari) 49

19. Water - The Prime Resource (Mamta Goyal) 53

20. समायोजन से जूझती वेतनभोगी महिलाएँ (डॉ. गीताली सेनगुप्ता) 56

21. महेश्वर हथकरघा उद्यमियों में सामान्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अध्ययन (डॉ. मंजु शर्मा, प्रतिष्ठा दासौंधी)... 59

(Commerce & Management / वाणिज्य एवं प्रबंध)

22. Equitable Role Of Agricultural Produce Markets In Economic Reforms And Development Of Farmers - An Analytical Study (Special reference to the Farmers of Indore Region in M.P.)(Dr. Rajesh Jain) 61

23. A Study Of Customer Retention Management In Telecom Sector (Amit Garg, Dr. Kamalijeet Bhatia) 65

24. An Analytical Study Of Profit And Loss Statement Of Sbi And Hdfc Mutual Fund Companies 70
(Garima Shrivastava, Dr. Vasudev Mishra, Dr. Ashish Pathak)

25. A Comparative Study Of Job Satisfaction Among Day And Night Shiftemployees 75
(Anjali Gupta, Jeesha Boyat)

26. Maheshwari Sarees - A Story Of Royalty Told In Warps And Wefts (Dr. Snigdha Bhatt) 78

27. Mobiling Manufacturing - A Source Of Services (Roshni Siddiqui) 81

28. E-Waste Management And Its Effect On Environmental & Human Health A Review 83
(Dr. Shweta Singh)

29. Impact On Organizational Culture In Government And Private College (Sukrati Rathore) 86

30. म.प्र. में औषधीय फसलों के उत्पादन का एक अध्ययन- नीमच जिले के विशेष संदर्भ में 88
(अलका शर्मा, डॉ. एल.एन. शर्मा)

31. भारत के विकास में कोल इण्डिया लिमिटेड की भूमिका (डॉ. दीपचंद भावरकर) 92

32. भारत संचार निगम लिमिटेड खंडवा का वित्तीय प्रबंधन -एक अध्ययन (ऋचिका डोंगरे, डॉ. प्रतापराव कदम) 95

33. उद्यानिकी जैव विविधता (डॉ. दयाराम साहू) 99

34. जैव विविधता विषय में शोध की आवश्यकता (डॉ. दयाराम साहू) 102

35. परिवहन का आर्थिक महत्व (इन्दौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के संदर्भ में) (डॉ. धीरज शर्मा)............. 105

36. नार्दन कोल फील्ड लिमिटेड में मानव संसाधन की वर्तमान स्थिति (डॉ. दीपचंद भावरकर) 107

37. मध्यप्रदेश के आर्थिक विकास में पर्यटन उद्योग का महत्व (बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में)(डॉ. डी.सी.कुमरावत)109

38. धार जिले में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की स्थिति एक अध्ययन (वर्ष 2002-2011) 111
(डॉ. बी. एस. सिसोदिया)

39. बचत एवं विनियोग को प्रोत्साहित करने में वित्तीय संस्थाएँ: डाकघर एवं बैंक (डॉ. एन.एल.गुप्ता, ऊँकार सिंह रावत)113

40. भारत में महिला उद्यमियों के विकास हेतु - सरकारी प्रयास (डॉ. अनिल तौहेल).................................... 115

41. धार जिले में मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम की स्थिति - एक अध्ययन (वर्ष 2002-03 से 2010-11)...... 117
(डॉ. बी.एस. सिसोदिया)

42. भारत में महिला सशक्तिकरण हेतु - सरकारी प्रयास (डॉ. अनिल तौहेल) 119

(Economics / अर्थशास्त्र)

43. A Comparative Study Of Capital Adequacy Ratio Of Indian Public And Private Sector Banks 120
With Special Emphasis On Basel II Norms (Rishi Vaidya, Dr. Kamalijeet Bhatia, Dr. N. K. Totala)

44. छ.ग. के बिलासपुर संभाग में फसल चक्र का प्रभाव (नोर्बेलता एक्का)... 124

45. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के विभिन्न पहलु - एक सिंहावलोकन (डॉ. ललिता सोलंकी, प्रो. तपन चौरे) 127

46. गांवो के बदलते स्वरूप में भारत निर्माण योजना (डॉ. आर.एस. मण्डलोई)... 130

(Political Seience / राजनीति विज्ञान)

47. Naxalbari Movemnet In India (Dr. Indira Barman) 132

48. राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान - नीति आयोग (विकास के परिप्रेक्ष्य में) (डॉ. कान्ता अलावा) 134

49. महिला सशक्तिकरण चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ (डॉ. हर्षा चचाने, डॉ. राजू रैदास) 137

(History / इतिहास)

50. रीवा जिला की प्रमुख सरायें एवं धर्मशालाओं का ऐतिहासिक महत्व (डॉ. मो. स्वालकीन खान) 139
51. संस्कृति तथा सभ्यता (डॉ. सुनीता शुक्ला) 142
52. प्रत्येक भारतीय को समानता व गरिमामय जीवन जीने का संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए 144
(प्रीति राठौर, डॉ. मदनलाल पँवार)
53. 20वीं शताब्दी से पूर्व डूँगरपुर राज्य में शिक्षा (निमेश कुमार चौबीसा) 146
54. गौतम बुद्ध के दार्शनिक व शैक्षिक विचारों की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता (सुरेन्द्र प्रताप सिंह खरे) 148
55. मुगलकालीन भारतीय सांस्कृतिक परिवेश को जानने के स्त्रोत (डॉ. सुनीता शुक्ला) 150

(Geography / भूगोल)

56. Impact Of Tea Production On The Economic And Geographical Scenario Of Kumaon Mandal 152
(Uttarakhand) 'A Brief Study From Kausani (Bageshwar)' (Manoj Kumar Tamta, Dr. Jyoti Joshi)
57. A Trend Analysis Of Rural Population Dependency In A City Region (Dr. Prabhakar Mishra) 156
58. Nutritional Iron Deficiency Among Women In Betul District (Smt. Kaneez Fatima) 158
59. डिण्डौरी जिले की बैगा जनजातीय के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का शिक्षा पर प्रभाव 160
(एकता मथनियाँ , डॉ. ए.एल. महोबिलया)
60. बालाघाट जिले में लिंगानुपात का क्षेत्रीय अध्ययन (दीपिका दोहरे , डॉ.जे.एल.बरमैया) 164

(Sociology / समाजशास्त्र)

61. मैक्स वेबर की नौकरशाही की अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण (मनोज कुमार चंदोलिया) 167
62. शिक्षित महिलाओं में धर्म के साथ सामंजस्य (लक्ष्मी मेहरा) 171
63. दिव्यांगता एवं सामाजिक पुनर्वास (सशक्तिकरण का माध्यम)(डॉ. ज्योति मेहता) 173
64. आतंकवाद एक सामाजिक विश्लेषण (डॉ. रश्मि दुबे) 175
65. गन्दी बस्ती में स्थित आवासों में उपलब्ध सुविधाओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (होशंगाबाद जिले के संदर्भ में)178
(कंचन ठाकुर)

(Psychology / मनोविज्ञान)

66. Effect Of Examination Anxiety And Hypnotherapy On Students 180
(Dr. Bharti Joshi, Dr. Nitendra Singh Rajput)
67. Study Of Relationship Of Bullying With Academic Performance Of Adolescents 185
(Dr. Saroj Kothari, Richa Mandovra)

(English Literature / अंग्रेजी साहित्य)

68. Hybridity & Alienation in the works of Ruskin Bond (Dr. Shailendra Kumar Chourasia) 188
69. The Problem Of Modern Wasteland In K.A. Porter's Flowering Judas (Dr. Anita Tripathi) 191
70. Socio-Economic Aspects In The Novels Of Ruth Prawer Jhabvala (Dr. Kehkashan Khan) 193

(Hindi Literature / हिन्दी साहित्य)

71. व्यंग्य का विकास एवं परिभाषा (डॉ. रश्मि सिलारपुरिया) 195
72. हिन्दी के समकालीन ऐतिहासिक उपन्यासों में जनचेतना के विविध आयाम (डॉ. लक्ष्मी गोयल) 198

73. हिन्दी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप (डॉ. अमित शुक्ल) 201
74. जयप्रकाश कर्दम रचित 'मोहरे' कहानी की प्रमुख समस्याएँ (डॉ. मजीद कुरैशी) 203
75. केदारनाथ अग्रवाल की कविता में लोक सौन्दर्य दृष्टि (डॉ. कुमुद कला मेहता) 205
76. राष्ट्रकवि 'दिनकर' के काव्य का अनुशीलन - राजनीति के विशेष संदर्भ में (डॉ. इला द्विवेदी) 207
77. लोक साहित्य में होली गीतों मे श्रंगारिकता (डॉ. एस. एस. राठौर) 209
78. आचार्य श्रीराम शर्मा के साहित्य में जीवन-मूल्य की सार्थकता (डॉ. वर्षा ठाकरे) 211
79. गुलेरी जी की कहानी 'उसने कहा था' में आदर्श प्रेम - विश्लेषण (डॉ. मजीद कुरैशी) 213
80. रघुवीर सहाय की कविताओं का भावबोध, भाषा और शिल्प (डॉ. कुमुद कला मेहता) 215
81. शैलेश मटियानी का उपन्यास रामकली के सन्दर्भ में (मनीषा टैगोर) 217
82. बाणभट्ट की आत्मकथा - सांस्कृतिक आख्यान (डॉ. रंजना मिश्रा) 219

(Sanskrit / संस्कृत)

83. वैदिक पुराण साहित्य में प्रतिपादित ऋषभ तथा भरत के चरित्र (डॉ. सावित्री मिश्रा) 220
84. चाणक्य-माणिक्य में शिक्षा नीति (डॉ. भावना श्रीवास्तव) 222
85. आदिपुराण के आधार पर ऋषभ एवं भरत का चरित्र चित्रण (डॉ. सावित्री मिश्रा) 224

(Law/ विधि)

86. Judicial Review - A Study In Indian Perspective (Dr. Vijay Srivastava, Devender Goel) 225
87. Independency And Accountability Of Judiciary - A Study In Indian Perspective (Anjum Parvez, Subhra) 228
88. Powers of Presiding Officer Under Xth Schedule of the Constitution (Mamta Goswami) 231
89. The progressive and regressive constitutional arrangements in Nepali : A study in the light of constitution of India (Dr. Vijay Srivastava, Mr. Jivesh Jha) 233
90. Rights Of Women In India-With Special Reference To Workplace (Dr. Vijay Srivastava, Divya Priyadarshni) 236

(Education / शिक्षा)

91. Academic Stress In Relation To Study Habit Among Higher Secondary Students (Dr. Harendra Kumar, Tabassum) 238
92. महिला शिक्षिकाओं का सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन (डॉ. कौशिक वी. पाण्डया, डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव, समन्दर सिंह) 242
93. विद्यालयों में सांस्कृतिक व साहित्यिक आयोजनों में विद्यार्थियों की रूचि (सुषमा सिंह चुण्डावत) 246
94. शिक्षक शिक्षा में मूल्यों का समावेश - पाठ्यक्रम (डॉ. सुनीता शर्मा) 248

(Others / अन्य)

95. Empowering Women Economically Through Traditional Crafts (Dr. Sabra Qureshi) 250
96. भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास व विकास (शारीरिक भाषा के विशेष संदर्भ में) (डॉ. सचिन सैनी) 255
97. देवात्मा का प्रकृति-दर्शन (डॉ. आशा चौधरी) 258

98. तुलसीदास का जीवन और समाज सम्बन्धी दृष्टिकोण (कामिनी देवी) 260
99. विश्व प्रसिद्ध भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ– महाराजा दक्ष प्रजापति (डॉ. ईश्वरलाल प्रजापति) 262
100. Climate Change: A Health Hazard (Dr. Kiran Yadav) 265
101. सेवासदन उपन्यास में आधुनिक जीवन बोध (डॉ. जगमोहन सिंह गुर्जर) 267
102. Algorithm Methods (Single Black Hole Attack and Cooperative Black Hole Attack) (Dharmendra Kumar Meena) 269
103. भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद : समस्या एवं निदान (डॉ. भरत लाल मीणा) 271
104. Overview and Applications of Ionic Liquids (Mukesh Kumar Mehta) 273
105. The Impact of Social Media on Children's Behavior (Dr. Sandhya Jaipal) 277
106. Women Empowerment in India: Challenges and Opportunities (Dr. Anjali Jaipal) 281
107. Optimal Location of Phasor Measurement Units for Voltage Security of Power Systems (Sonali R. Nandanwar, N. P. Patidar) 284
108. छायावाद के प्रवर्तक और आधार-स्तम्भ (हितेश कुमार) 291
109. 21वीं सदी की चुनौतियाँ : मीडिया और साहित्य आलेख मैं आश्वस्त हूँ और आपको करना चाहता हूँ (डॉ. हजारी लाल मौर्य) 294
110. लोकतंत्र में व्यवस्थापिका की भूमिका (डॉ. नीरजा शर्मा) 297
111. अलंकार : अर्थ एवं स्वरूप (डॉ. अनुपमा सक्सेना) 300
112. The Role Of Women In Regency Society As Portrayed In Jane Austen's Works (Dr. Panchali Sharma) 302
113. Fluoride Contamination in Groundwater and the Effect of Fluoride on Flora and Fauna; A Brief Review (Dr. Pratibha Rao) 306
114. अर्थशास्त्र में कार्मिक व्यवस्था, चयन, नियुक्ति, सेवा शर्तें (डॉ. कुलकिरण गढ़वाल) 308
115. The Chemistry of Water Treatment: Methods and Technologies (Dr. Anjul Singh) 312
116. Impact of Natural Elements Upon Wordsworth's Mind in His Autobiographical Epic the Prelude (Mahender Kumar) 320
117. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक तनाव, पर यौगिक क्रियाओं के प्रभाव का अध्ययन (डॉ. आर.पी. जैन, भारती) 324
118. प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, भारत में महिलाओं की स्थिति का समाजशास्त्र (डॉ. आराधना सक्सेना) 329
119. Energy Empower with Intrusion Detection Routing Protocol with Intrusion Detection for Mobile Ad Hoc Networks (Dr. Makarand Rambhau Shahade, Dr. Sachin S Agrawal, Prof. R. S. Jaiswal) 334
120. Impact of Climate Change on Horticulture Crops (Dr. Govind Prakash Acharya) 338
121. Issues and Prospects in Teacher Education Programme (Dr. Kalpana Singh) 342
122. Study of Energy and Momentum of Super Bis String Using String Bis Theory (V.P. Singh) 345
123. Theoretical Study of Bis-Scalar Field,Bis- Phase in Seismology (V.P. Singh) 348

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employbility Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. N.S. Rao - Director, Janardhanrai Nagar Raj. Vidhyapeeth University, Udiapur (Raj.) India
8. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
9. Prof. Dr. P.P. Pandey - HOD, Commerce(Dean), Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
10. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
11. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
12. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
13. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
14. Prof. Dr. R.P. Upadhayay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
16. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
17. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
18. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharastra) India
19. Prof. Dr.Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
20. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof.,Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
21. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
22. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
23. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
24. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
25. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anooppur (M.P.) India
26. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
27. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
28. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
29. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
31. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
32. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
33. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
34. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
35. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
36. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
37. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - Former Controller, Madhya Pradesh Professional Examination Board Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls PG College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management Deptt. Shri Atal Bihari Vajpai Hindi University, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls PG College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. PG College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.K. Jain - Professor, Commerce, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh PG College, Jaora (M.P.) India
26. Prof. Dr. Tapan Chore - HOD,Economics, Vikram University, Ujjain (M.P.) India

****

Referee Board

Maths - (1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
Physics - (1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
Computer Science - (1) Prof. Dr. Umesh Kumar Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
Chemistry - (1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College,Ujjain (M.P.)
Botany - (1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls PG College, Kota (Raj.)
(2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
Life Science - (1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
- (2) Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
Statitics - (1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
Military Science - (1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
Biology - (1) Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
Geology - (1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
Medical Science - (1) Dr.H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
Microbiology Sci. - (1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)

***** Commerce *****

Commerece - (1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
(3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)

***** Management *****

Management - (1) Prof. Dr. Rameshwar Soni, HOD, Research Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
Human Resources - (1) Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
Business Administration - (1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls PG College, Kota (Raj.)

***** Law *****

Law - (1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)

***** Arts *****

Economics - (1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls PG College, Neemuch (M.P.)
(2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
(3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
Political Science - (1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.)
(2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
(3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
Philosophy - (1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
Sociology - (1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
(2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. PG College, Dhar (M.P.)
(3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
Hindi - (1) Prof. Dr.Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)

		(2)	Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
		(4)	Prof. Dr. Jaya Priyadarshini Shukla, Vansthali Vidyapeeth (Raj.)
		(5)	Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
English	-	(1)	Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
Sanskrit	-	(1)	Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls PG College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. PG College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
History	-	(1)	Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.)
Geography	-	(1)	Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
		(2)	Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
Psychology	-	(1)	Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls PG College, Chhindwara (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls PG College, Indore (M.P.)
Drawing	-	(1)	Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls PG College, Bhopal (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
Music/Dance	-	(1)	Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak),Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
		(2)	Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)
			***** Home Science *****
Diet/Nutrition Science	-	(1)	Prof.Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls PG College, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
		(3)	Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
Human Development	-	(1)	Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
		(2)	Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
Family Resource Management	-	(1)	Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)
			***** Education *****
Education	-	(1)	Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
		(2)	Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific EducationCollege, Udaipur (Raj.)
		(3)	Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
		(4)	Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education,Tigaon, Faridabad (Haryana)
			***** Architecture *****
Architecture	-	(1)	Prof. Kiran P. Shindey, Principal,School of Architecture,IPS Academy, Indore (M.P.)
			***** Physical Education *****
Physical Education	-	(1)	Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
			***** Library Science *****
Library Science	-	(1)	Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

****

Spokesperson's

1.	Prof. Dr. Davendra Rathore	-	Govt. PG College, Neemuch (M.P.)
2.	Prof. Smt. Vijaya Wadhwa	-	Govt. Girls PG College, Neemuch (M.P.)
3.	Dr. Surendra Shaktawat	-	Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4.	Prof. Dr. Devilal Ahir	-	Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5.	Shri Ashish Dwivedi	-	Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6.	Prof. Manoj Mahajan	-	Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7.	Shri Umesh Sharma	-	Krishna Education College, Javi, Distt. Neemuch (M.P.)
8.	Prof. Dr. S.P. Panwar	-	Govt. PG College, Mandsaur (M.P.)
9.	Prof. Dr. Puralal Patidar	-	Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10.	Prof. Dr. Kshitij Purohit	-	Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11.	Prof. Dr. N.K. Patidar	-	Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12.	Prof. Dr. Y.K. Mishra	-	Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13.	Prof. Dr. Suresh Kataria	-	Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14.	Prof. Dr. Abhay Pathak	-	Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15.	Prof. Dr. Malsingh Chouhan	-	Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16.	Prof. Dr. Gendalal Chouhan	-	Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17.	Prof. Dr. Prabhakar Mishra	-	Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18.	Prof. Dr. Prakash Kumar Jain	-	Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19.	Prof. Dr. Kamla Chauhan	-	Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20.	Prof. Abha Dixit	-	Govt. Girls PG College, Ujjain (M.P.)
21.	Prof. Dr. Pankaj Maheshwari	-	Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22.	Prof. Dr. D.C. Rathi	-	Swami Vivekanand Career Gudiance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23.	Prof. Dr. Anita Gagrade	-	Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24.	Prof. Dr. Sanjay Pandit	-	Govt. M.J.B. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25.	Prof.Dr. Rambabu Gupta	-	Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26.	Prof. Dr. Anjana Saxena	-	Govt. Maharani Laxmibai Girls PG College, Indore (M.P.)
27.	Prof. Dr. Sonali Nargunde	-	Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28.	Prof. Dr. Bharti Joshi	-	Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29.	Prof. Dr. M.D. Somani	-	Govt. M.J.B. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30.	Prof. Dr. Priti Bhatt	-	Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31.	Prof. Dr. Sanjay Prasad	-	Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32.	Prof. Dr. Meena Matkar	-	Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33.	Prof. Dr. Mohan Waskel	-	Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34.	Prof. Dr. Nitin Sahariya	-	Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35.	Prof. Dr. Manju Rajoriya	-	Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36.	Prof. Dr. Shahjad Qureshi	-	Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37.	Prof. Dr. Shail Bala Sanghi	-	Maharani Lakshmibai Govt. Girls PG College, Bhopal (M.P.)
38.	Prof. Dr. Praveen Ojha	-	Shri Bhagwat Sahay Govt. PG College, Gwalior (M.P.)
39.	Prof. Dr. Omprakash Sharma	-	Govt. PG College, Sheopur (M.P.)
40.	Prof. Dr. S.K. Shrivastava	-	Govt. Vijayaraje Girls PG College, Gwalior (M.P.)
41.	Prof. Dr. Anoop Moghe	-	Govt. Kamlaraje Girls PG College, Gwalior (M.P.)
42.	Prof. Dr. Hemlata Chouhan	-	Govt. College, Badnagar (M.P.)
43.	Prof. Dr. Maheshchandra Gupta	-	Govt. PG College, Khargone (M.P.)
44.	Prof. Dr. Mangla Thakur	-	Govt. PG College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45.	Prof. Dr. K.R. Kumhekar	-	Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)
46.	Prof. Dr. R.K. Yadav	-	Govt. Girls College, Khargone (M.P.)

47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta - Govt. PG College, Badwani (M.P.)
48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi - Govt. PG College, Dhar (M.P.)
49. Prof. Dr. Prabha Pandey - Govt. PG College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50. Prof. Dr. Rajesh Kumar - Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel - Govt. PG College, Satna (M.P.)
52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta - Govt. PG College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash - Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava - Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55. Prof. Dr. Sunil Vajpai - Govt. Tilak PG College, Katni (M.P.)
56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya - Govt. PG College, Dhar (M.P
58. Prof. Dr. A. K. Pandey - Govt. Girls College, Satna (M.P.)
58. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain - Govt. PG College, Agar-Malwa (M.P.)
59. Prof. Dr. Niyaz Ansari - Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.)
60. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel - Govt. College, Harda (M.P.)
61. Dr. Suresh Kumar Vimal - Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
62. Prof. Dr. Amar Chand Jain - Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
63. Prof. Dr. Rashmi Dubey - Govt. Autonomus Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.)
64. Prof. Dr. A.K. Jain - Govt. PG College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65. Prof. Dr. Sandhya Tikekar - Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
66. Prof. Dr. Rajiv Sharma - Govt. Narmada PG College, Hoshangabad (M.P.)
67. Prof. Dr. Rashmi Srivastava - Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
68. Prof. Dr. Laxmikant Chandela - Govt. Autonomus PG College, Chhindwara (M.P.)
69. Prof. Dr. Balram Singotiya - Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
70. Prof. Dr. Vimmi Bahel - Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
71. Prof. Aprajita Bhargava - R.D.Public School, Betul (M.P)
72. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan - Govt. College, Maksi, Distt. Shajapaur (M.P.)
73. Prof. Dr. Pallavi Mishra - Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
74. Prof. Dr. N.P. Sharma - Govt. College, Datia (M.P.)
75. Prof. Dr. Jaya Sharma - Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
76. Prof. Dr. Sunil Somwanshi - Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
77. Prof. Dr. Ishrat Khan - Govt. College, Raisen (M.P.)
78. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi - Govt. PG College, Sehore (M.P.)
79. Prof. Dr. Bhawana Thakur - Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
80. Prof. Dr. Keshavmani Sharma - Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
81. Prof. Dr. Renu Rajesh - Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
82. Prof. Dr. Avinash Dubey - Govt. PG College, Khandwa (M.P.)
83. Prof. Dr. V.K. Dixit - Chhatrasal Govt. PG College, Panna (M.P.)
84. Prof. Dr. Ram Awdesh Sharma - M.J.S. Govt. PG College, Bhind (M.P.)
85. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri - Sarojini Naidu Govt. Girls PG College, Bhopal (M.P.)
86. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla - Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
87. Prof. Dr. Anoop Parsai - Govt. J. Yoganand Chattisgarh PG College, Raipur (Chattisgarh)
88. Prof. Dr. Anil Kumar Jain - Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
89. Prof. Dr. Kavita Bhadiriya - Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
90. Prof. Dr. Archana Vishith - Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
91. Prof. Dr. Kalpana Parikh - S.S.G. Parikh PG College, Udaipur (Rajasthan)
92. Prof. Dr. Gajendra Siroha - Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
93. Prof. Dr. Krishna Pensia - Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
94. Prof. Dr. Pradeep Singh - Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
95. Prof. Dr. Smriti Agarwal - Research Consultant, New Delhi

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

Evaluation Of Antidiabetic Activity In Vitro Studies Of Successive Extract Of Vinca Rosea Roots

Manoj Kumar Gajbhiye* Anun Kakkar Praveen Koushley*****

Abstract - Vinca rosea (VR) roots was successively extracted and inhibitory activities was done in Petroleum ether (PE-5), Ethyl acetate (EA-6), Ethanol (EtOH-7), and aqueous (HOH-8), on á- amylase at varying conc. Diabetes mellitus is a clinical condition characterized by hyperglycemia in which an elevated amount of glucose circulates in the blood plasma. α - amylase inhibitors are used to achieve greater control over hyperglycemia in type II diabetes mellitus. The present work intends to screen novel α - amylase inhibitors from natural sources like plants in order to minimize the toxicity and side effects of the inhibitors currently used to control hyperglycemia. The α -amylase inhibition assay showed that the PE-5, EA-6, EtOH-7, and HOH-8 extracts of VR 57.08 μg/mL, 44.77 μg/mL, 26.33 μg/mL, 40.56 μg/mL exhibited 50% α - amylase inhibition activity at the mentioned conc. respectively. The result indicated the potential of these extract to manage hyperglycemia.
Key Word - Petroleum ether, Ethyl acetate, Ethanol, α -amylase, IC50, Acarbose, Vinca rosea

Introduction - Diabetes mellitus is a chronic endocrine disorder characterized by hyperglycemia resulting from insufficient defective insulin secretion, which resist to insulin action or both [1]. Diabetes mellitus is a common disease whole population of the world. It affected nearly 171 million people all around the world one and half decade before and the number is projected to increase to around 366 million by 2030 [2]. Type II diabetes usually occur in obese individuals and is associated with hypertension and dyslipidemia. The capacity of extract/drugs to stimulate insulin release from the pancreatic β cells reflects their ability to augments oxidative fluxes in the islet of Langerhans cells [3] The control of hyperglycemia is important in treatments of all forms of diabetes because in the long term, acute and cronic problems can occur when the blood glucose concentration is not kept in the normal range [4-5] For a long time natural products from plants have been used for the treatment of diabetes, mainly under developed countries where the resources are limited affordability and access to modern medicines treatment is difficult [6]. Herbal medicines have been used for the treatment of diabetic patients since long and they are currently accepted as an alternative therapy for diabetic treatment though the kinetics is slow [7-9]. Therapeutic options for diabetes are diet, exercise, oral hypoglycemic drugs and insulin therapy. Plant drugs are frequently considered to better and free from side effect than allopathic ones [10]. α - amylase inhibitors decrease the high sugar levels that can occur after a meal by slowing the speed with which α -amylase can convert starch to monosaccharides especially glucose. [11] In diabetic people where low insulin levels prevent the fast clearing of extracellular glucose from blood [12]. Also α - amylase inhibitors are one of the antidiabetic drug groups, of which Acarbose is the most well-known. These molecules have a very strong advantage and are suitable for treatment of non-insulin dependent diabetes mellitus (Type II Diabetes [13-14]. Today phytotherapy is often used to treat several diseases, besides medicine. Lot of natural product extract has been reported to have antidiabetic activities and are utilized for the treatment of diabetes. Herbal extract are nowadays used preferentially than modern medicines. [15 17]

Vinca rosea (= catharanthusroseas, catharanthus, periwinkle) is dicotyledonous plant belongs to family apocynaceae. Phytochemical studies reveals the presence of about 20 dimeric indoledinydroindole alkaloids. Among them vincristine & vinblastine are most significant. Other are ajmalicine, lochnerine, serpentine, tetrahydroalstonine etc. [18].

Material and Method -

Source of plant material - Roots of Vinca rosea was collected from tribal areas of Kirnapur and Lanji, district Balaghat, M.P., India. The present study was conducted at Govt. Science College, Jabalpur (M.P.) India. The plant was botanically identified, verified and authenticated by Mr. Hemant Ganveer, Assistant Professor (Botany) Govt. S. S. P. College, Waraseoni, Balaghat (M.P.), India.

Preparation of plant extracts - Roots of Vinca rosea was obtained and washed with distilled water and then air dried, crushed to make powder and used for the preparation of extracts. PE-5, EA-6, EtOH-7, and HOH-8 extractswas obtained by extracting using Soxhlet extractor of dried plant

*Natural Product Lab (Chemistry) Govt. Science College, Jabalpur (M.P.) INDIA
**Natural Product Lab (Chemistry) Govt. Science College, Jabalpur (M.P.) INDIA
***Govt. J. S. T. P. G. College, Balaghat (M.P.) INDIA

root powder taking solvents with increasing polarity.

The control samples were prepared without any plant extracts.The % inhibition was calculated according to formula [19]

Inhibition (%) = Abs 595 (Control) – Abs 595
(Sample Extract) X 100
Abs 595(Control)

The IC 50 values were determined from plots of percent inhibition versus log inhibitor conc and were calculated by non-linear regression analysis from the mean inhibitory values. Acarbose was used as the reference á-amylase inhibitor.

In vitro α-Amylase Inhibitory Assay - The assay was carried out following the standard protocol with slight modifications. Starch azure (2 mg) was suspended in 0.2 mL of 0.5M Tris–HCl buffer (pH 6.9) containing 0.01 M $CaCl_2$ (substrate solution). The tubes containing substrate solution were boiled for 5 mins and then pre-incubated at 37°C. All sample extracts were dissolved in DMSO in order to obtain conc of 10, 20, 40, 60, 80, and 100 µg/mL. Then, 0.2 mL of sample of particular conc.Was added to the tube containing the substrate solution. 0.1 mL of porcine pancreatic amylase in Tris–HCl buffer (2 units/mL) was added to the tube containing the plant extract and substrate solution. The reaction was carried out at 37°C for 10 min. The reaction was stopped by adding 0.5 mL of 50% acetic acid in each tube. The reaction mixture was centrifuged at 3000 rpm for 5 min at 4°C. The absorbance of resulting supernatant was measured at 595 nm using spectrophotometer (Systronic India 2202 UV–VIS spectrophotometer). Acarbose, a known α-amylase inhibitor was used as a standard drug. The concentration of Acarbose and plant extracts required to inhibit 50% of a-amylase activity under the conditions was defined as the IC50 value. The a-amylase inhibitory activities of plant extracts and Acarbose were calculated, and its IC50 values was determined [20].

Results and Discussion - In present work, the inhibition activities of all the four extracts obtained from VR roots was investigated on the α-amylase enzyme and IC50 values was calculated and shown in the tables and Graphs below. The IC50 value of the positive control Acarbose was measured as 15.5 µg/ml is given in table 1. PE-5 Extracts revealed weaker activity in all extracts as shown in table 2. In EA-6 Extract in all conc showed lower activity similar to PE-5, as given in table 3.The maximum á-amylase inhibitory activity 62.58% at Conc 50 µg/ml was shown by the EtOH-7 extract as depicted in the table 4. And HOH-8 extract showed less activity similar to PE-5 & EA-6 extract activity as given in table 5.

The plant-based α-amylase inhibitor offers a prospective therapeutic approach for the management of diabetes [21]. The results of study indicate that ethanol EtOH-7 extracts of VR plant roots showed appreciable α-amylase inhibitory effects. This study supports the ayurvedic concept VR could be useful in management of diabetes. Further, in vivo and hyphenated technique like GC-MS, LC-MS analysis are required to confirm the present observations and findings after isolation of active constituents present in VR roots EtOH extract. In vivo studies are necessary to recognize a potential chemical substance entity for clinical utilization in the therapy of diabetes and other related problems.

Table 1 - α-amylase inhibitory effects of Acarbose (Standard α-amylase inhibitors)

Concentration (µg/ml)	% Inhibition	IC50(µg/ml)
10	46.99	15.54±41.21
20	52.00	
30	59.13	
40	63.25	
50	69.71	

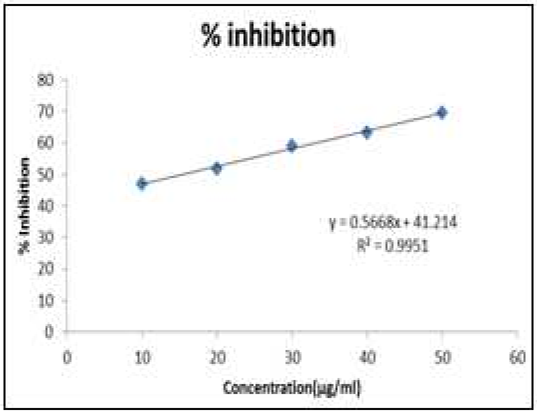

Graph 1 - α-amylase inhibitory effects of Acarbose (standard á-amylase inhibitor)

Table 2 - α-amylase inhibitory effect of Petroleum ether (PE-5) extract of Vincarosea

Concentration (µg/ml)	%Inhibition	IC50(µg/ml)
10	23.39	57.08±16.26
20	26.61	
30	33.96	
40	39.64	
50	46.44	

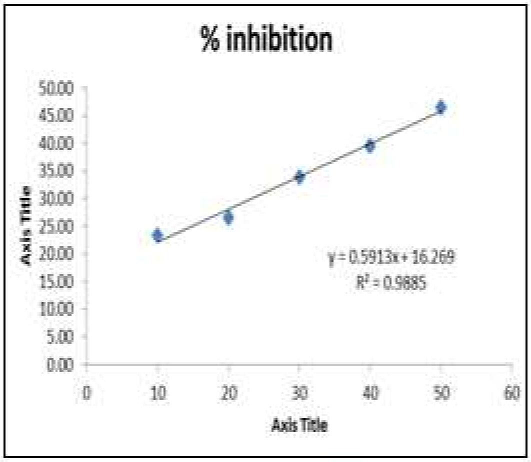

Graph 2 - α-amylase inhibitory effects of Petroleum ether (PE-5) extract of V. rosea

Table 3 - α-amylase inhibitory effect of Ethyl acetate (EA-6) extract of V. rosea

Concentration (µg/ml)	% Inhibition	IC50(µg/ml)
10	30.51	44.77±24.66
20	35.30	
30	42.54	
40	46.99	
50	53.01	

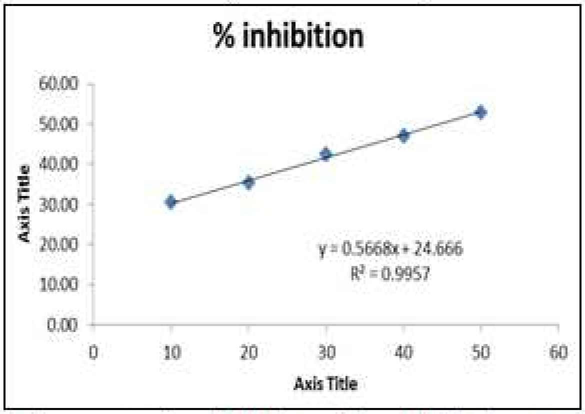

Graph 3: α - amylase inhibitory effect of Ethyl acetate (EA-6) extract of V. rosea

Table 4: α -amylase inhibitory effects of Ethanol (EtoH-7) extract of V. rosea

Concentration (µg/ml)	%Inhibition	IC50(µg/ml)
10	41.09	26.33±35.62
20	46.10	
30	52.56	
40	57.80	
50	62.58	

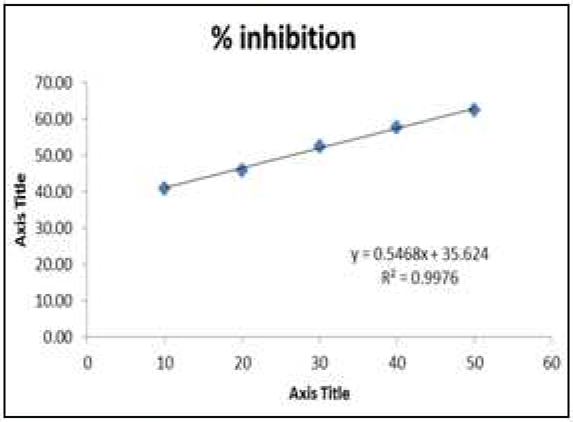

Graph 4 - α -amylase inhibitory effects of Ethanol (EtoH-7) extract of V. rosea

Table 5 - α -amylase inhibitory effects of Aqueous (HOH-8) extracts of V. rosea

Concentration (µg/ml)	% Inhibition	IC50 (µg/ml)
10	33.07	40.56±27.61
20	37.97	
30	45.21	
40	50.00	
50	54.68	

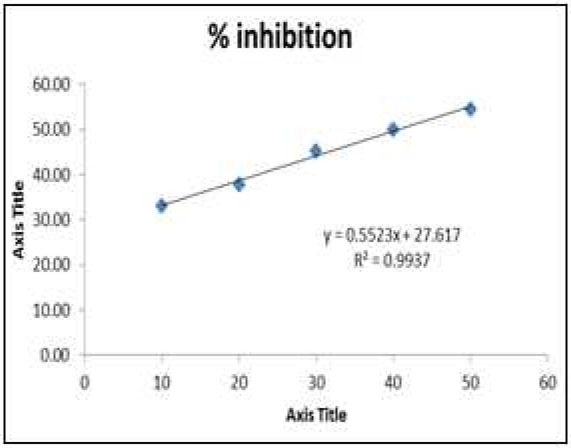

Graph 5 - α -amylase inhibitory effects of Aqueous (HOH-8) extract of V. rosea

Acknowledgement - First author is thankful to state research fellowship, Govt. of MP, India for providing financial support during the research work. Dr. Anjali Bajpai , Head, Department of Chemistry , Govt. Science College, Jabalpur (MP) for giving laboratory facilities. Dr. A. L. Mahobiya principal (Govt. Science College Jabalpur) and Dr. R. C. Mourya, UTD, Rani DurgavatiVishwavidhyalaya Jabalpur (MP) for valuable support and guidance in the present work.

References:-

1. Gavin JR III, Albert KG MM, Daudison MB. (1997) - Report of the expert committee on the diagnosis and classification of diabetes mellitus diabetes care, 20, 1183
2. Mall Grijesh kumar, Mishra Pankaj Kishore, Prakash Veeru (2009), Antidiabetic and hypolypidemic, activities Global journal of biotechnology & bio chemistry 4 (1):37-42.
3. Malaisse WJ (1983), Insulin release the fuel concept diabetes 9, 313
4. Funke I, and M.F. Melgzig (2006). Traditionally used plants in diabetes therapy phytotherapeutics as inhibitor of á-amylase activity Braz. J.Pharmacogn 16:1-5
5. Ye, F.Z.,Shen and M. Xie (2002) alpha Glucosides inhibition from a Chinese medical herb in normal and diabetic rats and mice phyto medicine 9: 161-166
6. Nickavar B, Yousefian N (2009), Iran J pharmaceut res., 8 (1) : 53-57
7. Batfua GR, Mamidipalli BN, Parimia R (2007), Hypoglycemic and antihypoglycemic effect of alcoholic extracts of Benincasahispida in normal and in alloxan induced diabetic rats pharmacog Mag, 3
8. Modak M, Dixit P, Londhe J (2007), Indian herbs and herbal drugs used for the treatment of diabetes J ClinBiochemNutre 40, 163
9. Badde S, Patel N, Bodhankar S (2006), Antihyperglycemic activity of aqueous extract of leaves of coculushirsutus (L) Diet in alloxan induced diabetic mice Indian Journal pharmacol 38, 49
10. Mall Grijesh kumar, Mishra Pankaj Kishore, Prakash Veeru (2009), Antidiabetic and hypolipidemic activity,

.Global Journal of biotechnology & biochemistry 4 (3), 37-42

11. Biovin M, Zinsmeister AR, GOVL Mayo (1987), Clin Proc,; 62: 249-255
12. Mohammed A, Adelaiye AB, Bakari AG, Mabrouk MA, (2009): International journal of Medicine and Medicinal Science, 1 (12)530-535
13. Cheng, A.Y.Y., and I.G. Fantus, (2005), Oral antihyperglycemic therapy for type II diabetes mellitus can Med Assoc. J, 172: 213-226
14. Upadhyay RK, and Ahmad S, (2011), Management strategies for control of stored Grain insect pests in former stores and public ware house world Journal of Agricutural science, 7(5):527-549
15. De Sales PM., PM de Souza, LA Simeoni, PO. Magalhaes and D Silveira (2012), Amylase inhibitors: A review of raw materials and isolated compound from plant source. J pharma Sci, 15, 141-183
16. Marles, R., Farnsworth, N. (1994), Plant as source of antidiabetic agents. In: Wagner, H. Farnsworth, N.R. (Eds.), Economic and Medicinal Plant Research, 6 149-187.
17. Buyukbalci, A. and E. Sedef Nehire (2008), Determination of in vitro antidiabetic effects, antioxidant activities and phenol contents of some herbal teas. Plant food Hum. Nutr. 63, 27-33
18. Wealth of India –Raw materials vol-II, V revised Edition, 6, 7.
19. Jung M, Park M, Chul H.L, Kang Y, Seok-kang E, Ki-King S, (2006), Antidiabetic agents from medicinal plants.Curr. Med. Chem., 13(10), 1203-18.
20. Iniyan G.Tamil, B. Dineshkumar, M. Nandhakumar, M. Senthilkumar, and A. Mitra (2010), In vitro study on á-amylase inhibitory activity of an Indian medicinal plant Phyllanthusamarus, Indian J Pharmacol.; 42(5), 280–282.
21. McCue P, Vattem D, Shetty K. (2004), Inhibitory effect of clonal oregano extracts against porcine pancreatic amylase in vitro. Asia Pac J. ClinNutr; 13, 401-8.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

Species As Bio - Indicators Of Water Pollution In Narmada River At Jabalpur

Dr. Bazgha Athar* Dr. Gohar Hujaifa Khan**

Abstract - The purpose of this study is to evaluate the faunal seasonal diversity in the river Narmada at Jabalpur. Jabalpur city is located in the heart of the country. The location of Jabalpur is $23^{0}10'$ North latitude and $79^{0}59'$ East longitude . The city of Jabalpur is the administrative headquarters of the district. The area of the district is 10,160 km^2 having population of 2,460,714 (2011 census). Jabalpur District is located in the mahakosal region of Madhya Pradesh, on the divide between the watersheds of Narmada and the Sone. Jabalpur situated at a distance of 309 km, from Amarkantak. The Total distance covered by the Narmada river in Jabalpur is 35 km, the Narmada river in Jabalpur is being polluted from several sources the discharge of sewage, domestic wastes, dairy effluents, washing of cloths, bathing of cattle , ashes remains of bodies after cremation, plastics, flowers, Garlands , oily substance, floating suspected matter, organic contamination, oil & grease and various organic and inorganic matter including Polythene bags etc. Annual fairs and festivals increase the pollution load in the river proportionate the number of visitors and it takes longer time to recover during low water periods. Faunal are good indicators of water quality and they differ in their sensitivity to water pollution. Some faunal are very sensitive to pollution and cannot survive in polluted water. Others are less sensitive to pollution and can be found even in much polluted water. This study has been carried out from March 2009 to Feb 2010 in four monitoring site of Narmada river at Jabalpur at Jabalpur. Surveys of India Topo-sheet no. 55M/16 64 A/8 on the scale of two cm equal to 1 km were used to pinpoint the approachable sites. Twelve water quality parameters were selected for an analysis of the each site. Water samples from selected sampling sites were collected in porcelain and sterilized polyethylene bottles of IL capacity in the morning between 8 to 10 a.m. The entire chemicals used were (AR) grade. The water sample analyzed as per standard methods prescribed by APHA (1985) and Trivedy and Goel (1986). Some parameters as temp, colour, pH, odor , D.O are analyzed at the field itself. The collected samples transported to laboratory in the ice boxes. Analyzed vizh. Hardness , calcium, magnesium, alkalinity, dissolved oxygen, and chloride. All the sampling station shows the bad water quality, unsatisfactory for drinking purposes. A total 43 taxa were recorded in four sampling site. These taxa divided in four group 1. Intolerant to pollution 2. Moderately intolerant to pollution 3. Fairly tolerant to pollution 4. Very tolerant to pollution. While tolerance levels can actually vary by species and different species can have varying tolerances levels can actually vary by species and different species can have varying tolerances to specific pollutants, the levels given are generalized for the family of organism. Water quality and faunal diversity index were calculated (Water quality index and Simpson's diversity index)

Key - words - Bio - indicator, Faunal diversity, Water quality, Water quality index, Narmada.

Introduction - Jabalpur city is located in the heart of the country. The city of Jabalpur is the administrative headquarters of the district. The area of the district is 10,160 km^2 having population of 2,167,469 (2001 census). Jabalpur District is located in the Mahakoshal region of Madhya Pradesh, on the divided between the watersheds of river Narmada and river Sone. Jabalpur is situated at a distance of 309 km from Amarkantak. Jabalpur lies on the banks of the Narmada River and sprawls over the plains of its tributaries Hiran, Gaur, ken & Sone. Geographically, the city is located at $23^{0}10'$ North latitude and $79^{0}57'$ East longitude, at an altitude of 393 meters above mean sea level. During recent years serious concern has been voiced about the rapidly deteriorating fresh water bodies of Jabalpur with respect to pollution. But at present, Narmada River is facing a number of serious environmental and ecological challenges. The purity and freshness of our river water is now lost.

Faunal species owing to their wide variation of response to pollutants have been extensively utilized to evaluate quality of aquatic systems. Seasonal samples of the macro invertebrate community can indicate the effects of pollutant sources which may not have been detected by either physico-chemical sampling of continuous monitoring

***Environmental Research Laboratory P.G. Deptt. of Environmental Science Govt. Model Science College, Jabalpur (M.P.) INDIA**
****Govt. (Autonomous) P.G. College, Satna (M.P.) INDIA**

of a restricted range of parameter. Biological monitoring, or bio-monitoring, is the systematic use of living organisms of their responses to determine the quality of the aquatic environment (Barbour and Paul, 2010).

Fauna roles in the ecosystem are one of the most important environmental habitats. Species communities contain important part of aquatic organisms in river environments. The aquatic organisms are exposed to anthropogenic disturbances as well as natural change in their habitats which cause them to react in different ways. There fore aquatic organisms have an important Macrobenthose diversity is closely related to both environmental factors and anthropogenic alteration (Nouri et al.., 2008). Diversity indices are generally scalar ecological indicators. Using these indices is common in ecological analysis. Species diversity indicates the status of the ecosystems (Izsak, 2007). Macrobenthic assemblages have been used to indicate stress as they are sensitive to pollution and are also different due to the sensitivity degree. Based of sensitivity role in bio assessment (Mooraki et al., 2009; Girgin, 2010).

Materials And Methods - Monthly water samples of river Narmada at Jabalpur were collected at Jamtara ghat, Jilaheri ghat Tilwara ghat and Lamhata ghat station during the year 2009-2010. Water samples from selected sampling sites were collected in porcelain and sterilized polyethylene bottles of IL capacity in the morning between 8 to 10 a.m. The collected samples transported to laboratory in the ice boxes. Analyzed viz.-Hardness, calcium, magnesium, alkalinity, dissolved oxygen, and chloride. Immediately after collection samples at site while other parameters are analyzed in laboratory within six hours as per the standard methods. The entire chemicals used were (AR) grade. The water sample analyzed as per standard methods prescribed by APHA (1985) and Trivedy and Goel (1986). The aquatic insects were collected by aquatic insects net (Mesh size 40-80/cm^2) from water body monthly and the average counts were recorded ; Insects were sorted out order wise and preserved with 70% alcohol with few drops of glycerin for studies. they were taken into the laboratory for identification.

Results -

Physico - chemical parameter analysis of Narmada river water has been conducted during the year 2008 - 2009 at Jamtara ghat Jilaheri ghat Tilwara ghat and Lamhata ghat station. The data from the water analysis are shown in Table land2. Results given as seasonal mean values, the water temperatures range between 32.75^{0}C to 35.25^{0}C in the summer season. In the Rainy season temperatures range between 27^{0}C to 28^{0}C In the winter season temperatures range between 18.5^{0}C to 21.75^{0}C (Figure-1) Water pH levels increased and decreasing in sampling ghats. pH values ranged from 8.5 to 8.27 in the summer season. In the Rainy season pH range between 9 to 9.2 in the winter season pH range between 7.8 to 8.1 (Figure-2) Hardness values ranged from 520 to 595 mg/1. In the summer season. In the Rainy season hardness range between 510 to 560 mg/1 in the Winter season Hardness range between 400 to 495. (Figure-3) calcium values ranged from 230 to 290 mg/1 in the total 27 species of insect fauna were collected during the study time. Abundance and diversity were related mainly to Do concentration The collection is higher in summer season and lower in winter season. Index result shows higher pollution load during the summer season at Tilwara ghat. The lower pollution load during winter season at Jilaheri ghat. stoneflies are often considered to be clean water benthos. But when thinking about worms and midges, water quality professionals often view these as indicators of dirty water, especially in rivers and streams. There are few photograph given viz. mayfly , Dragonfly , Damselfly , stonefly, water Strider, Giant water Bug, Water Scorpion , Caddisfly , Predaceous Diving Beetle was collected at river Narmada. All these species found as a indicator river pollution fig.(11, 12 and 13).

Some class I organisms - Pollution intolerant. These organisms are highly sensitive to Pollution

Some class II organisms - Pollution intolerant. These organisms will be found in clean and slightly polluted water

Some class III organisms - Pollution intolerant. These organisms will be found in polluted water

Discussion - There are a great variety of bio-indicator present in Narmada river Some invertebrates are sensitive in pollution of poor water quality while others are able to survive more demanding conditions . The presence or absence of certain types of invertebrates is one indication of the quality of water in that place. Adverse effects of invasive species on ecosystems have been discussed by several authors (e.g. Lodge, 1993; Cairns & Bidwell , 1996; Torchin et al., 2003). The advantage of bioindicators over chemical of physical detectors is their ability to supply extensive both spatially and temporally - rather than limited and instantaneous data, thus making such information more "representative" . Kumar et al. (2002) similar study reported that river Krishni have been studied and results indicate a marked variations in biological characteristics and its diversity at the different sampling points. the faunal species are highly sensitive to the polluted water. In many instances the bio indicator takes samples for us-a service that is undoubtedly valuable even though it must be linked to a sound knowledge of the organism's "ethogram" and biology so as to arrive at a scientifically legitimate interpretation of the data provided (Giorgio Celli 1992)

Conclusion - Narmada river is losing its values due to the particular pollution situation at specific areas as Jamtara ghat, Jilehari ghat, Tilwara ghat and Lamheta ghat at Jabalpur. The values goes very high in summer months because of concentration of various organic wastes and human activities. It can, there fore, be concluded from the present investigation that the water of the Narmada river is polluted. Aquatic insects offer and excellent way to examine biological aspects of water quality and scientists in many countries are increasingly using water quality criteria based on insect. This study provides evidence that the Bio-

indicator such as stoneflies is being increasingly used as indicators of water quality.

References:-

1. APHA (1985)- Standard methods for the examination of waste water (16th ed). American Public Health Association and Water Pollution Control Federation , Washington D.C. p.p. 2-1193.
2. Barbour M.T. and Pual M.j. (2010). Adding value to water resource through biological assessment of river Hydrobiologia , 651:17-24.
3. Bhatt, J.P. and Pandit, M.K. (2010). A new macro - invertebrate based new index to monitor river water quality Current science, 99(2):196-203.
4. Cairns, J. Jr. & J.R. Bidwell, (1996)- Discontinuities in technological and natural systems caused by exotic species Biodiversity and Conservation 5: 1085 -1094
5. Giorgio. Celli (1992). Bio - indicators in the monitoring of environmental pollution Aerobiologia volume 8 Number 1.
6. Kumar, Neeraj, Sharma R.C.(2002). water quality of river krishni (Part-2 Biological Characteristics and bioindicators J Nature conse Vator 14(2):299- 333.
7. Lodge, D.M. (1993) Biological invasions - lessons for ecology. Trends in Ecology & Evolution 8: 133_137 .
8. Trivedy, R.K. and Goel, P.K. (1990) Chemical and Biological methods for water pollution studies Environmental Publication Post Box 60. Karad 415110.
9. Torchin M.E. K.D. Lafferty, A.P. Dobson, V.J. McKenzie & A.M. Kuris,(2003). Introduced species and their missing parasites Nature 421:628- 630.

****

A Statistical Approach To Multivariate Analysis Of Ground Water Quality

Dr. Neelu Singhai*

Abstract - Quality of ground water of M.P. Nagar Zone 1 area, Bhopal, M.P, India has been determined by analyzing its physico chemical Parameters such as Temperature, Turbidity, pH, Electrical conductivity (EC), Total Dissolved Solids (TDS), Total Alkalinity (TA), Total Hardness (TH), Calcium Hardness (CaH), Magnesium Hardness (MgH), Chloride (Cl), Sulphate (SO_4) and Nitrate (NO_3). Samples were analyzed for a periods of one year from November 2016 to October 2017.

Key Words - Ground water, physico chemical parameters, statistical analysis, correlation, pollutant.

Introduction - Water is one of the most important compounds to the ecosystem. Better quality of water described by its physical, chemical and biological characteristics. But some correlation was possible among these parameters and the significant one would be useful to indicate quality of water. Human and ecological use of ground water depends upon ambient water quality. Human alteration of the landscape has an extensive influence on watershed hydrology[1]. Rapidly shrinking surface water resources due to over-exploitation and resulted contamination with several chemical and biological agents all over the globe has shifted tremendous pressure on the groundwater resources[2]. The health effects of unsafe potable water are most apparent in the developing countries, among the unfortunately communities that suffer from scarcity of the clean water resources[3]. The natural aquatic resources are causing heavy and varied pollution in aquatic environment leading to water quality and depletion of aquatic biota due to increased human population, use of fertilizers in agriculture and man-made activity. Therefore it is necessary to check drinking water quality at regular time interval. Ground water is ultimate and most suitable fresh water resource. The problem in case of water quality monitoring is the complexity associated with analysis of the large number of measured variables. In recent years an easier and simpler approach based on statistical correlation, has been developed using mathematical relationship for comparison of physico chemical parameters[4]. In present study involves the analysis of ground water quality in terms of physico chemical parameters of M.P. Nagar Zone 1 area, Bhopal, M.P, India.

Materials and methods - Samples from tube well were collected from the outlet after flushing water for 10–15 minutes in order to remove the stagnant water. All the samples collected in tight capped high quality sterilized polyethylene bottles were immediately transported to the laboratory under low temperature conditions in ice boxes. The samples were stored in the laboratory at 4°C until processed/analyzed. The collected samples were kept in the refrigerator maintained at 4°C and analyzed for a few important parameters in order to have an idea on the quality of drinking water. Standard procedures involving AAS spectrophotometers, flame photometry, volumetric analysis and other related instruments were used for the determination of temperature, turbidity, pH, electrical conductivity, total dissolved solids, total alkalinity, total hardness, calcium hardness, magnesium hardness, sulphate, chloride and nitrate[5]. All the chemicals used were of AR grade. SPSS® statistical package was used for correlation studies among various Parameters.

Results and discussion - The monthly variation in physico chemical Parameters are presented in Table 1. **(See in the last page)**

Temperature - Water temperature plays an important role in deciding the chemical, Biochemical and Biological characteristics of water body[6]. In the present study water temperature varies from 26.2°C to 23.6°C. The maximum (26.2°C) temperature was recorded in the month of May (summer) and minimum (23.6°C) in the month of December (winter). The maximum permitted standard of drinking water is 25°C.

Turbidity - Suspension of particles in water interfering with passage of light is called turbidity. As per IS: 10500-2012 the acceptable and permissible limits of turbidity are 1 and 5 NTU respectively. In the present study water turbidity varies from 1.1 to 3.4 NTU. The maximum (3.4) turbidity was recorded in the month of June (summer) and minimum (1.1) in the month of January (winter). Ideally drinking water should have a turbidity of <1 NTU for aesthetic quality as well as for efficient disinfection.

*Asst. Professor (Chemistry) Govt. M.V.M., Bhopal (M.P.) INDIA

pH - As per IS: 10500-2012 desirable limit for pH is 6.5-8.5 and no relaxation in permissible limit. In the Present Study water pH varies from 7.25 to 8.95. The maximum pH value (8.95) was recorded in the month of June and minimum (7.25) in the month of December. Corrosion effects may become significant at a pH below 6.5 and scaling may become a problem at a pH above 8.5.

Electrical conductivity - Conductivity is the capacity of water to carry an electrical current and varies both with number and types of ions the solution contains. In the present study water EC varies from 400 to 542 micro mho cm^{-1}. The maximum EC (542) was recorded in the month of June (summer) and minimum (400) in the month of January (winter). The conductance of water in the study area has values greater than the maximum permissible limit (0.3 mmho cm^{-1}) of USPH and indicates that water is markedly polluted with its reference.

Total dissolved Solids - High values of TDS in ground water are generally not harmful to human beings but high concentration of these may affect persons who are suffering from kidney and heart diseases. TDS values in the studied area varied between 183-349 mg/l. As per IS: 10500-2012 desirable limit and permissible limit for TDS is 500 and 2000 mg/l respectively.

Total Alkalinity - Various ionic species that contribute to the alkalinity include hydroxide, carbonates, bicarbonates and organic acids. Alkalinity value in the studied domestic area varied between 157-250 mg/l. As per IS: 10500-2012 desirable limit and permissible limit for total alkalinity is 200 and 600 mg/l respectively.

Hardness - The total hardness is relatively high in all samples due to the presence of calcium, magnesium, chloride and sulphate ions. Hardness value in the studied area varied between 270-396 mg/l. The maximum value of hardness (396) was recorded in the month of April (summer) and minimum (270) in the month of December. Hujare reported total hardness was high during summer than monsoon and winter[7]. High value of hardness during summer can be attributed to decrease in water volume and increase of rate of evaporation of water. As per IS: 10500-2012 desirable limit and permissible limit for hardness lies between 200 to 600 mg/l respectively.

Calcium Hardness - Calcium hardness value in the studied area varied between 116-186 mg/l. If calcium is present beyond the maximum acceptable limit, it causes incrustation of pipes, poor lathering and deterioration of the quality of clothes. As per IS: 10500-2012 desirable and permissible limit for calcium is 75 and 200 mg/l respectively.

Magnesium Hardness - Magnesium hardness value in the studied area varied between 112-216 mg/l. Too high magnesium will adversely affect crop yields as the soils become more alkaline. As per IS: 10500-2012 desirable and permissible limit for Magnesium is 30 and 100 mg/l respectively.

Chloride - Chloride value in the studied area varied between 175-278 mg/l. The maximum value (278mg/l) was recorded in the month of May (summer) and minimum value (175 mg/l) in the month of February. Similar results were also reported earlier[8]. As per IS: 10500-2012 desirable and permissible limit for chloride is 250 and 1000 mg/l respectively. Chloride content above the permissible limit changes the taste of water which may become objectionable to the consumer.

Sulphate - Sulphate occurs naturally in water as a result of leaching from gypsum and other common minerals. Sulphate value in the studied area varied between 47-95 mg/l. Ingestion of water with high sulphates causes laxative effect and gastro-intestinal irritation. As per IS: 10500-2012 Desirable and permissible limit for Sulphate is 200 and 400 mg/l respectively.

Nitrate - Ground water contains nitrate due to leaching of nitrate with the percolating water and by sewage and other wastes rich in nitrates. Nitrate is produced from chemical and fertilizer factories, matters of animals, decline vegetables, domestic and industrial discharge Nitrate value in the studied area varied between 22-49 mg/l. As per IS: 10500-2012 desirable limit for nitrate is maximum 45 and no relaxation in permissible limit.

Correlation Studies - Interrelationship studies among different water quality parameters are very helpful in understanding geochemistry of the studied area. The regression equations for the parameters having significant correlation coefficients are useful to estimate the concentration of other constituents. Values of **c**orrelation coefficient among different parameters are presented in Table2. **(See in the last page)**

A positive and significant correlation has been observed among various parameters. Temperature shows significant correlation with **t**urbidity, TDS, TA, Cl and SO_4 indicating that **t**urbidity TDS, TA, Cl and SO_4 increases with rise in temperature. Turbidity shows significant correlation with EC, TA, Cl and SO_4 indicating that the EC, TA, Cl and SO_4 increases with rise in turbidity. pH shows significant correlation with MgH indicating that magnesium hardness increases with rise in pH. TDS shows significant correlation with TA, TH, and Cl indicating that the TDS is due to Ca and Mg chloride. Alkalinity shows significant correlation with magnesium and Cl indicating that the alkaline nature of ground water is mainly due to magnesium chloride. Magnesium shows good correlation with sulphate indicating that magnesium is associated with sulphate in water of the studied area.

Conclusion - Water quality is dependent on the type of the pollutant added and the nature of mineral found at particular zone of bore well. Estimation of water quality index through formulation of appropriate using methods and evaluate the quality of tube well water by statistical analysis. According to WHO, nearly 80% of all the diseases in human beings are caused by water[9]. Result of water quality assessment showed that most of the water quality parameters slightly higher in the summer season than in the winter season. Interpretation of data through correlation

studies shows that ground water of the area is slightly polluted and appropriate treatment will be needed for future use of water in the region to protect human beings from adverse health effects. It is, therefore, immediately required that the water source be properly protected from potential contaminants. The above analysis is also cost effective and time saving because statistical equations used for calculating the value of physicochemical parameters and to measure the extent of pollution in ground water of the study area.

References :-

1. Claessens L. Hopkinson C. and Rastetter N. (2006): J. Vallino, Water Resources Research, 42,03426. doi:10.1029/2005WR004131
2. Singh V.K., Sinha. S., Singh, K.P., Malik A. and Mohan, D. (2006): Evaluation of Groundwater Quality in Northern Indo-Gangetic Alluvium Region Environmental Monitoring and Assessment (112: 211–230 DOI: 10.1007/s10661-006-0357-5 _c 2006)
3. Borah K. K., Bhuyan B. and Sharma H. P. H. P. (2008): Int. J. Chem. Sci., 6(4), 20-23.
4. Chakrabarty S. and Sarma H.P. (2011): A statistical approach to multivariate analysis of drinking waterquality in Kamrup district, Assam, India, Archives of Applied Sci. Research, 3(5), 258-264.
5. APHA (1996): Standard methods for the examination of water and waste water, Public Health Association, 19th ed., Washington DC.
6. Salve, V. B. and Hiware C. J. (2008): Study on water quality of Wanparakalpa reservoir Nagpur, J. Aqua. Biol., 21(2), 113-117.
7. Hujare, M. S. (2008): Seasonal variation of physico-chemical parameters in the perennial tank of Talsande, Maharashtra. Ecotoxicol. Environ. Monit. 18(3): 233-242.
8. Swaranlatha, S. and Narsingrao A. (1998): Ecological studies of Banjara lake with reference to water pollution. J. Envi. Biol., 19(2), 179-186.
9. Dilli Rani G., Suman M., Narasimha Rao C., Reddi Rani P., Prashanth V. G., Prathibha R. and Venkateswarlu P. (2011): Current World Environment, 6(1), 191-196.

Table-1
Physico Chemical Parameters

	Temp	Turb	pH	EC	TDS	TA	TH	CaH	MgH	Cl	SO_4	NO_3
Unit	^0C	NTU		µmho	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Nov-16	24.4	1.6	7.62	439	223	177	290	178	112	214	51	24
Dec-16	23.6	1.2	7.25	420	204	157	270	130	140	204	61	22
Jan-17	24.2	1.1	7.33	400	250	198	280	180	100	214	47	42
Feb-17	23.8	1.3	7.34	482	183	147	282	116	166	175	64	34
Mar-17	24.2	1.9	8.52	529	247	218	380	182	198	228	67	44
Apr-17	24.8	2.4	8.44	520	257	200	396	180	216	219	89	45
May-17	26.2	3.2	8.1	524	349	250	392	180	212	278	95	49
Jun-17	25.1	3.4	8.95	542	270	232	388	186	202	245	79	42
Jul-17	25	3.3	8.45	530	210	210	310	150	160	230	81	46
Aug-17	25.5	2.5	8.2	510	230	198	315	152	163	215	72	38
Sep-17	24.2	2.7	7.44	521	197	187	300	170	130	218	66	29
Oct-17	24.1	2.2	7.77	522	200	189	287	173	114	224	52	28

Table-2

Correlation Coefficients

	Temp	Turb	pH	EC	TDS	TA	TH	CaH	MgH	Cl	SO_4	NO_3
Temp	1											
Turb	0.75462	1										
pH	0.60222	0.7326	1									
EC	0.49916	0.82402	0.74241	1								
TDS	0.77093	0.43488	0.46223	0.22104	1							
TA	0.79769	0.73763	0.73783	0.55893	0.83496	1						
TH	0.63168	0.60646	0.81682	0.65011	0.75334	0.78611	1					
CaH	0.38576	0.36411	0.46732	0.25763	0.59215	0.71662	0.57717	1				
MgH	0.55116	0.53262	0.73021	0.64468	0.58392	0.92906	0.89116	0.14385	1			
Cl	0.77503	0.72417	0.56713	0.47453	0.83966	0.92906	0.67444	0.66719	0.44662	1		
SO_4	0.74103	0.74768	0.65624	0.66427	0.60322	0.61385	0.7822	0.12035	0.88103	0.58365	1	
NO_3	0.66355	0.52218	0.6709	0.47271	0.66742	0.76719	0.72568	0.36481	0.67672	0.55053	0.68547	1

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

Indole Alkaloids In Catharanthus Roseus

Dr. Sushama Singh Majhi*

Abstract - The natural product compound has some form of biological activity and that compound is known as the active principle. Many of today's medicines are obtained directly from a natural source. On the other hand, some medicines are developed from a lead compound originally obtained from a natural source. This means the lead compound, Can be produced by total synthesis, or can be a starting point (precursor) for a semi synthetic compound, or can act as a template for a structurally different total synthetic compound. This is because most biologically active natural product compounds are secondary metabolites with very complex structures. This has an advantage in that they are extremely novel compounds but this complexity also makes many lead compounds' synthesis difficult and the compound usually has to be extracted from its natural source - a slow, expensive and inefficient process.
Key Words - Natural product, biological activity, active principle, medicines, natural source.

Introduction - An analog of the didemnins isolated from the Mediterranean tunicate has shown activity against certain tumor types (medullary thyroid carcinoma, renal carcinoma, melanoma, and tumors of neuroendocrine origin). It has also been reported to inhibit the secretion of vascular, endothelial growth factor related to angiogenesis and to arrest the cell cycle at the Gland. It is one of the most thoroughly investigated plants of Apocynaceae and over 120 alkaloids of different types have been isolated from it. It is also known as the source of chemical compounds now used in the treatment of cancer. Their discovery led to one of the most important medical breakthroughs of the last century. Whilst researching the anti-diabetic properties of the plant in the 1950s, scientists discovered the presence of several highly toxic alkaloids in its tissues.

These alkaloids are now used in the treatment of a number of different types of cancer, with one derived compound, called vincristine, having been credited with raising the survival rate in childhood leukemia from less than 10 % in 1960 to over 90 % today. Originally the name alkaloid, (which means alkali like) was given to all organic bases isolated from plants. The name alkaloid teas first suggested by Meitner in 1819. Alkaloids have highly complex molecular structures and often manifest significant pharmacological activity and play an important role in medicine. When administered to animals most alkaloids produce striking physiological effects which vary greatly from alkaloid to alkaloid, Alkaloids are known to stimulate the central nervous system, cause paralysis, elevate or lower blood pressure, act as pain relievers, tranquilizers and as antibiotics. Most alkaloids are toxic at high, and some at even very loin doses. In spite of this, many alkaloids find use in medicine.

The function of alkaloids in plants is not clearly established. Some experiments suggest that alkaloids are waste products from the nitrogen metabolism of plants. Other work indicates that the alkaloids are not end products but metabolic intermediates. It has been proposed that alkaloids may serve to protect plants by discouraging animals from eating them because of their bitter taste or poisonous effects. Certain alkaloids may serve as metal-ion carriers through chelation. Alkaloids have been of interest to chemist for al-Most two centuries and in that time thousands of alkaloids have been isolated. Most of these have had their structures determined through the application of chemical and physical methods and in many instances these structures have been confirmed by independent synthesis. A complete account of the chemistry of the alkaloids would occupy volumes. The occurrence of alkaloids is not confined to any specific plant organ but appears to be-a characteristic of all organs. The histological distribution suggests strongly that alkaloids are synthesized principally in young active growing tissues.

Alkaloids have been classified into the following groups –

1. Phenylethylamine
2. Quinoline group
3. Pyrrolidine group
4. Isoquinoline group
5. Pyrrolidine and Pyrideine
6. Phenathrene group
7. Piperidine group

*Asst. Professor (Chemistry) Govt. Motilal Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

8. Indole group

Indole Alkaloids - Indole alkaloids are one of the largest group of alkaloids. The majority of indole alkaloids are confined to the dicotyledons, occurring most frequently in the Apocynaceae family and to a lesser extent in the Asclepiadaceae. Loganiaceae and Rubiaceae families. The indole alkaloids are complex organic molecules, possessing indole or dihydroindole (indoline) nucleus. Many of these alkaloids possess marked physiological properties. The investigation of Apocynaceae as well as other families resulted the discovery of indole alkaloids such as vinblastine (1) and vincristine (2) which are used for the treatment of choriocarcinoma and certain forms of leukaemia and Hodgkins disease.

(See in the next page)

Other physiologically active compounds include reserpine (3), which has been used as a hypotensive sedative drug and lysergic acid diethylamide (LSD) (4) a powerful hallucinogen possessing the remarkable physiological property of inducing symptoms similar to schizophrenia. Many indole alkaloids, particularly of the *corypianthe* and *yohimbe* series contain a 3- carboline nucleus (5) and some of these are physiologically important. Thus vincamine (6) is a cereberal vasodilator while ajmaline (7) is used in cardiac arrhythmias. Other physiological active compounds include morphine (8), nicotine (9), quinine (10) and corynantheine (11).

References :-

1. P.Potier, N.Langlois, Y.Langlois and F.Gueritte, Chem.Commu. 670 (1975) .
2. P.Potier, N.Langlois, F.Gueritte and Y.Langlois, *J. Amer.Chem. Soc.* , 89, 7017 (1976) .
3. A.I. Scott, F.Gueritte and S.L.Lee, *J.Amer Chem. Soc.* 100 6253 (1978).
4. R.L.Baxter, C.A.Dorschel, S.L.Lee and A.I.Scott, *Chem. Comm.*, 257 (1979).
5. P.Potier, N.Langlois, Y.Langlois and F.Gueritte, *Chem. Comm*, 670 (1975).
6. P.Potier, N.Langlois, F.Gueritte and Y.Langlois, *J. Amer. Chem. Soc.*, 89 7017 (1976)
7. K.L.Stuart, J.P.Kutney and B.R.Worth, *Heterocycles,* (in press).
8. K.L.Stuart, J.P.Kutney, T.Honda and B.R.Worth, *Heterocycles*, (submitted for publication).
9. K.L.Stuart, *Heterocycles,* 9 (10), 1419 (1978).
10. R.L.Baxter, C.A.Dorschel, S.L.Lee and A.I.Scott, *Chem. Comm*., 257 (1979).
11. K.L.Stuart, J.P.Kutney, T.Honda and B.R.Worth, *Heterocycles*, 9, 1391 (1978).
12. W.T.Stearn, *Lloydia* 29, 196 (1966).

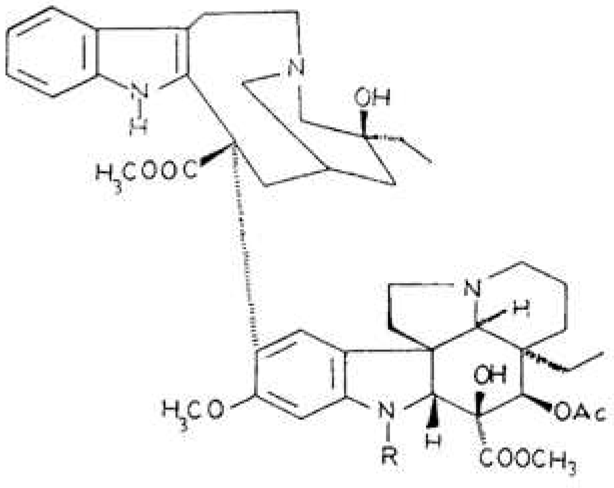

(1) VINBLASTINE R = CH_3

(2) VINCRISTINE R = CHO

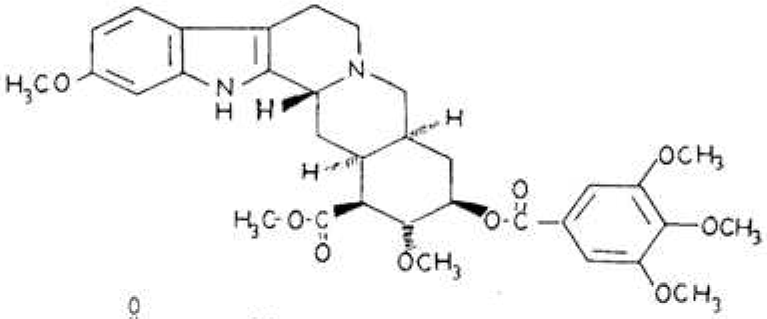

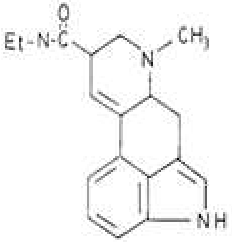

(4)

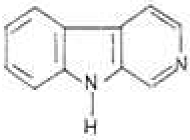

(5)

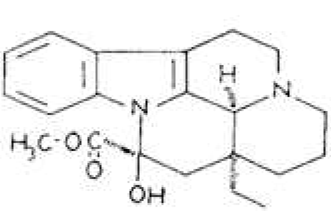

(6)

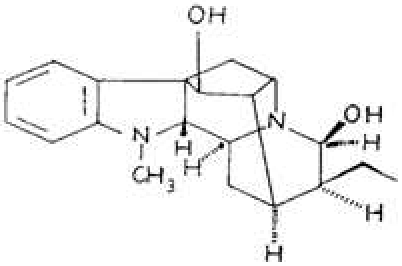

(7)

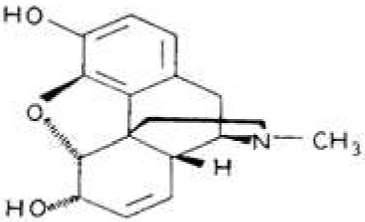

(8)

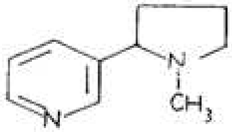

(9)

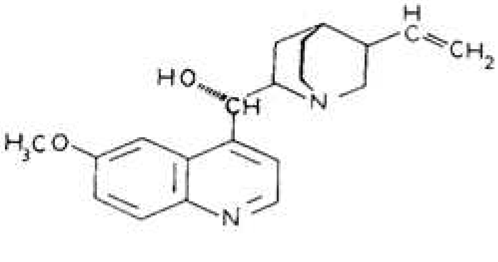

(10)

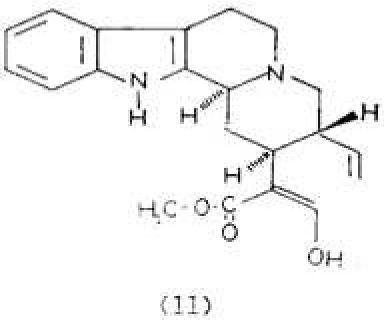

(11)

****

The College Campus Biodiversity Of Medicinal Plants Used In The Cure Of Skin Diseases

Dr. Shobha Sharma*

Abstract - The skin is a part of body that protects the underlying tissue from exposure to harmful /toxic agents. Socio-economic status, over crowding, un hygienic, malnutrition are the causative factors for skin diseases. Associated factors are chemicals for cosmetics, pollution and modern life style particularly by the food habits make the individuals prone to skin diseases.

In India the Ayurvedic system of medicine has been use for over thousands year. The folk and ethno medicinal uses in rural India have been playing a great role in the treatment of diseases. The paper deals with the original ethno botanical information that are used for various skin diseases. A number of plant species belonging to the families useful in skin diseases have been reported from M.L.B. Govt. Girls P.G. College campus Indore.

Introduction - There are a number of people in India suffering from common skin problems. These are found in children, young and adults as well as in old person. Most common skin problems are dermatitis, eczema, acne, urticaria, psoriasis, etc. which do not get cured completely. It is very difficult to find out the specific allergens responsible for common skin problems so the treatment is very complex and it does not yields 100 percent result in such patients. Ultimate way of prevention of such diseases is that "Live away from inciting agent of allergy". Thus there is an increased need for the development of alternative medicines. One possible approach is to screen local medicinal plants in search of suitable antifungal, antibacterial substances. The various preparations of medicinal plants in treating diseases such as eczema, scabies, psoriasis etc. In Ayurveda various dermatologic conditions and its treatment of options are elaborately described. Ayurvedic medicines appear to be a natural manage of skin diseases. These medicines are obtained from plant sources, minerals, organic acids, steroides etc. There are diversity of medicinal plants observed in the college campus in the form of herbs, shrubs and trees. There plant parts are being used to make medicines in the form of oral drug, ointment, medicinal ghee, oil etc.

Traditional Drugs for Ayurvedic Texts - Traditional methods employed in treatment of various skin diseases and locally available medicinal plants in college campus from which herbal drugs can be obtained for an effective treatment of skin diseases.

1. Kustha Diseases: Juice of fresh stem of Guduchi Tinospora Cordifolia- 10 to 30ml is to be taken twice a day.
2. Paste prepared from the Rhizome of turmeric curcumalonga 10 to 20 gms is to be taken with 50-100 ml of Gomutra (cow's urine) twice a day.
3. Churna of dryed leaves of Azadirachta indica neem 1 to 3 gm is to be taken with water twice a day.
4. Oil obtained from seeds of Karanja Pongamia Pinnata is to be used for massage.
5. Mix sulphur 20g m in 50-100 ml of mustard oil exposed to sun and use for massage.
6. Decoction of part of fruitrind of Awala Phyllanthus officinales and bark of khair Acaciacatechu 10 ml to 20 ml to be taken with 10 gm honey twice a day.
7. Bark of Palash Butea Momnosperma 1-5 gm to be taken with juice of sugarcane saccharum officinerum 10-15 ml twice a day.

Biodiversity of Angiospermic medicinal plants - The angiosperms are the biggest dominating, economically group of plant kingdom in number and structural diversities on the Earth. These diversities are on the basis of size, shape and habit are found in the plant kingdom. Plants also exhibit diversity on the basis of their physiology specially in the nature and quality of their chemical products. All the chlorophyll containing plants manufacture sugar in the process of photosynthesis but they utilize this sugar differently. Some plants store sugar in the form of fatty substances in their tissues and some plants store in the form of starch. Some plants are rich in organic acids eg. Citric acid, oxalic acid, are found in large quantities in citrus fruits. Some plants manufacture aromatic oils, some plants have yellow, green, blue, red pigments in their organs. These chemical compounds are converted in to secondary metabolites to form complex organic compound in the form of carotenoids, flavinoides, steroides, vitamins, harmones, proteins, amino acids etc. These chemical compounds are to be extracted by the different mechanisms and utilizes to formulation of different kind drugs, medicines to cure various

*Associate Professor (Botany) M.L.B Govt. Girls P.G. College, Kila Bhawan, Indore (M.P.) INDIA

types diseases. So that those plants having benefical organic compounds which are utilized in form of medicines are generally called medicinal plants. These medicinal plants shows diversities in their morphology, cytology, physiology is known as biodiversities of medicinal plants. There are 50-60 types of medicinal plants are recognized in the our college campus.

List of medicinal plants observed in college campus commonly used in skin disease treatment.

List of herbs commonly used in skin diseases treatment (Table see in the next page)

Discussion - This is because of secondary metabolites which are not evenly deposited in all parts of the plant. In using fresh material, medicinal plants have preventive as well as curative properties. Different health care system have their own way of approach while medicinal plants remain constant and occupy the central position. Various parts of the plant have different medicinal properties while single plant having the same efficiency differs in percentage from one part to the other.

Conclusion - Ayurvedic medicinal plant products are most convenient and have greater acceptance amongst the users due to their easy availability, easy bio-degradability, easy to handling, economic cost, environment friendly nature and minimum side effects. The traditional knowledge system in India is facing a major problem due to lack of sufficient documentation. The information available in the text could be helpful to drug designers and research. The traditional knowledge with its holistic system approach supported by experimental bare can serve as an innovative for newer, safer and affordable medicine. There is need to conservation of these medicinal plants in college campus. Bio-diversity of medicinal plant conversation can be done by in-situ conservation in which plants are conserved in natural environment they grow and need to plantation of medicinal plants.

References :-

1. Gopi Radha A K. Siddha herbs exclusively used in skin disease. NISCAIR. New Delhi
2. Chopra RN, Nayar SL, Chopra IC. Glossary of Indian medicinal plants. 3rd, CSIR, New Delhi
3. Google Search- Biodiversity
4. Taxonomy Medicinal Plants
5. Unified Botany by S.B. Agrawal
6. National Seminar Research Paper Pubalished by Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth National Academy of Ayurveda ,New Delhi.

List of medicinal plants observed in college campus commonly used in skin disease treatment.
List of herbs commonly used in skin diseases treatment

Acacia catechu (Leguminosae)	Khadira	Dried pieces	Kustha
Acacia nilotica (Leguminosae)	Babbula	Dried mature stem bark	Kustha
Achyranthes aspera (Amaranthaceae)	Apamarga	Dried whole plant	Kandu
Adhatoda vasica (Acanthaceae)	Vasa	Fresh, dried, mature leave	Kustha
Adhatoda Zeylanica (Acanthaceae)	Vasa	root	Kustha
Allium Sativum (Liliaceae)	lasuna	Bulb	Kustha
Alstoniascholaris (Apocynaceae)	Saptaparna	Stem bark	Kustha
Alternathera sessilis(Amaranthaceae)	Matsyaksi	Dried whole plant	Kustha
Artocarpusheterophyllus (moraceae)	Panasa	Dried root bark	Tvakroga
Azadirachta indica (Meliaceae)	Nimba	Dried leaf	Kustha
Bacopa monnieri Linn. Wettst (Scrophulariaceae)	Brahmi	Dried whole plant	Kustha
Brassica compestris (Brassicaceae)	sarsapa	Dried seed	Kustha
Butea monosperma (Fabaceae)	Palasa	Seed	Kustha
Caesalpiniabonduc (Caesalpiniaceae)	Latakaranja	Seed	Kustha
Caesalpinia crista (Caesalpiniaceae)	Putikaranja	Stem bark	Kustha
Calotropis procera (Asclepiadaceae)	Arka	Dried stem bark	Kustha
Calotropis procera (Ascepiadacease)	Arka	Dried Root	Kandu
Euphorbia prostrate (Euphorbiaceae)	Dughika	Whole plant	Kustha
Ficus Glorumeta (Moraceae)	Phalgu	Dried fruits	Kustha
Glorio sasuperba (Liliaceae)	Langali	Dried tuberous root	Kustha
Gymnema Sylvestre (Asciepiadaceae)	Mesasringi	Dried Leaf	Kustha
Indigofera aspalathoides (Fabaceae)	Siva-Nili	Dries roots and stem	Kustha
Jasminum officianale (Oleasceae)	Jati	Dried Leaf	Kustha
Jatropha glandulifera (Euphorbiacea)	Dravanti	Dried seed	Kustha
Lawsonia inermis (Lythraceae)	Madayanti	Leaf	Kustha

Michelia Champaca (Magnoliaceae)	Campaka	Flower	Kustha
Mimosa Pudica (Fabaceae)	Lajjalu	Dried whole plant	Kustha
Momordica charantia (Cucurbitaceae)	Karavallaka	Fresh fruit	Kustha
Moringa oleifera (Moringaceae)	Sigru	Root bark	Kustha
Buta monosperma (Fabaceae)	Palasa	Flower	Kustha
Murraya koenigii Spreng. (Rutaceae)	Saurabhanimba	Dried leaves	Kustha Svitra
Nerium indicum (Apocynaceae)	Karavira	Dried root	Kustha
Nerium indicum (Apocynaceae)	Karavira	Dried leaf	Kustha
Ocimum sanctum (Lamiaceae)	Tulsi	Dried whole plant	Kustha
Oxalis corniculata (Oxalidaceae)	Cangeri	Dried whole plant	Kustha
Phyllanthus officinates (Euphorbiaceae)	Amalaki	Root, stem and leaf	Kustha
Pistia stratiotes (Araceae)	Jalakumbhi	Dried whole plant	Kustha
Pongamia pinnata (Fabaceae)	Karanja	Dried root bark	Kustha Kanda
Prosopis cineraria (Mimosaceae)	Sami	Leaves	Kustha
Psoralea corylifolia (Leguminosae)	Bakuci	Dry ripe Fruit	Kustha
Pterocarpus marsupium (Leguminosae)	Asana	Heart Wood	Kustha
Raphanus sativus (Brassicaceae)	Mulaka	Dried seed	Kustha Sidhma
Rosa centifolia	Satapatrika	Dried Flower	Kustha
Salix alba (Salicaceae)	Sveta vetasa	Dried leaves	Savitra
Solanum nigrum (Solanaceae)	Kakamaci	Dried whole plant	Kustha
Tectona grandis (Verbenaceae)	Saka	Dried heart wood	Kustha
Tinospora cordifolia (menispermaceae)	Guduchi	Stem	Kustha
Vernonia cineraa (Asteraceae)	Sahadevi	Dried whole plant	Sidhma
Vitex negundo (Verbanaceae)	Nirgundi	Root	Kustha
Ziziphus Xylopyrus (Rhamnaceae)	Ghonta	Fruit	Kustha
Calamus thwaitesil (Arecaceae)	Kumarivetra	Rhizome	Kustha
Euphorbia Prostrate (Euphorbiaceae)	Dugdhika	Whole Plant	Kustha
Carica Papaya (Caricaceae)	Erandakarkati	Dried seed	Kustha
Cassia fistula (Fabaceae)	Aragvadha	Stem bark	Kustha
Cassia tora (Fabaceae)	Prapunnada	Dried seed	Kustha
Chrysanchemum indicum (Asteraceae)	Guladaudi	Dried fruit	Kustha
Curcuma longa (Zingiberaceae)	Haridra	Dried rhizomes	Kustha
Cynodon dactylon (Poaceae)	Durva	Whole Plant	Kustha
Dalbergia sissoo (Fabaceae)	Simsapa	Dried heart wood	Kustha
Datura metel (Solanaceae)	Dhattura	Whole Plant	Kustha
Euphobia hirta (Euphobiaceae)	Brihat Dugdhika	Dried Whole plant	Kustha

****

Environmental Pollution Causes And Its Effect On Human Health

Deepa Shroti *

Abstract - Environmental pollution remains a major source of concern throughout the world. There are numerous sources of environmental pollution and these are a major source of health risk throughout the world, though risks are generally higher in developing countries, where poverty, lack of investment in modern technology and weak environmental legislation combine to cause high pollution levels. Nevertheless, in recent years, several attempts have been made to assess the global burden of disease because of environmental pollution, either in terms of mortality or disability-adjusted life years. About 8–9% of the total disease burden may be attributed to pollution, but considerably more in developing countries. Unsafe water, poor sanitation and poor hygiene are seen to be the major sources of exposure, along with indoor air pollution.

Introduction - Environment is the natural surroundings which help life to grow, nourish and destroy on this planet called earth. Natural environment plays a significant role in the existence of life on earth and it helps human beings, animals and other living things to grow and develop. Most important perquisite is that everyone must know how to protect our environment to keep it safe as well as ensure the nature's balance on this planet to continue the existence of life.

The situation which keeps us from realizing the nature of our problem, is that we are victims of our past. For man's entire existence on planet Earth, he has been free to do as he pleases without regard to the consequences. Humankind could indiscriminately use what was found in nature; transform it into anything desired without noticeable consequence, and discard anything without concern for the impact that this would have on our environment.

As recently as fifty years ago, industrial corporate stock certificates pictured factories with billowing smokestacks because a smoking chimney was a sign of wealth and prosperity. The accepted panacea of the day for poisonous waste was, "dilution is the solution to pollution". We have come a long way from those days, but unfortunately, we have not come far enough. Many people are now sensitized to the need to keep our environment clean and certainly there are now many laws in existence to ensure this is the case, but these laws are a Band Aid on a severed artery. They make us feel better and enable us think we are doing something to solve the problem, but are we? The truth of the matter is that we still behave like the world will supply us with an endless flow of raw materials and that it has the capability to absorb an endless flow of waste and pollutants. Environmental pollution not only include chemicals, but also organisms and biological materials, as well as energy in its various forms (e.g. noise, radiation, heat).Mass extinction, mankind is presently causing and witnessing the greatest mass extinction event that has ever occurred in the history of life on our planet. If established trends continue, one half of all the species that presently existed will be gone in the next several decades. This rate of destruction of life is even greater than the mass extinction caused by a giant meteor collision that occurred sixty-five million years ago and wiped out the dinosaurs. Our present mass extinction is being fueled by human activity which destroys the habitants of plant and animal life.

Fourteen billion pounds of solid waste and nineteen trillion gallons of liquid waste are dumped in the oceans of the world each year. Ocean pollution affects every nation around the world because water movement disperses pollution to every corner of the globe. Presently, in the center of the Pacific Ocean, there is a huge area where ocean currents concentrate solid waste and this area looks like a garbage dump. Industrialization is the prime source of water pollution and as nations become more industrialized water pollution increases and has a greater impact on fish stocks and the oceans ability to support life.

The link between pollution and health is both a complex and contingent process. For pollutants to influence health, susceptible individuals must receive doses of the pollutant, or its decomposition products, sufficient to trigger detectable symptoms. For this to occur, these individuals must have been exposed to the pollutant, often over relatively long periods of time or on repeated occasions. Such exposures require that the susceptible individuals and pollutants shared the same environments at the same time. For this to happen, the pollutants must not only be released into the

*Associate Professor (Zoology) C.S.A. Govt. P.G. Nodal College, Sehore (M.P.) INDIA

environment, but then be dispersed through it in media used by, or accessible to, humans. Health consequences of environmental pollution are thus far from inevitable, even for pollutants that are inherently toxic; they depend on the coincidence of both the emission and dispersion processes that determine where and when the pollutant occurs in the environment, and the human behaviors that determine where and when they occupy those same locations.

Emissions to the atmosphere tend to be more closely modelled and measured, and more generally reported, than those to other media, partly because of their greater importance for environmental pollution and health (emissions to the atmosphere tend to be more readily discernible and to spread more widely through the environment), and partly because of the existence of better established policy and regulation. Emissions from low-level sources such as road vehicles and low-temperature combustion sources such as domestic heating, in contrast, tend to be much less widely dispersed. As a result, they contribute to local pollution hotspots and create steep pollution gradients in the environment.

These fugitive and local emissions are often overlooked in epidemiological and other studies that use modelling techniques to estimate exposures, but they can be extremely important, both because they are frequently responsible for the highest concentrations of environmental pollution, and because—unlike high-level emissions—they remain close to source and show marked dilution gradients with distance from source. It also must be recognized that pollutants rarely occur in isolation; more typically they exist in combination. Exposures are therefore not singular. Instead we are usually exposed to mixes of pollutants, often derived from different sources, some of which may have additive or synergistic effects. Unravelling the effects of individual pollutants from this mix is a challenging problem that has yet to be adequately resolved in many areas of epidemiology.

One of the underlying tenets of environmental epidemiology is that, for the health effects of interest, a relationship exists between the level of exposure (or dose) and the degree of effect. Effects can, in fact, be represented in two different ways: by the type of effect or by its severity or the probability of its occurrence (often termed the ‘response’). In either case, these associations are generally assumed to be broadly linear, such that the effect or response increases with each increment of exposure to a pollutant. For many pollutants and many health effects, this assumption seems to hold true at least over a wide range of exposures and responses. Some, however, appear to be characterized by more complex associations. Thresholds may exist below which no detectable health effect. At high levels of exposure, responses may weaken, so that the dose–response relationship is essentially curvilinear-convex or S-shaped. In a few cases, there is some evidence that)”- or, more rarely, U-shaped relationships may exist—for example, in relation to solar radiation or vitamin intake. One of the main purposes of epidemiology is to demonstrate and, if possible, quantify these relationships, where they exist.

For all the reasons outlined above, estimating the contribution of environmental pollution to the burden of disease is far from easy. The difficulties are severe in developed countries, where disease surveillance, reporting of mortality, environmental monitoring and population data are all relatively well established. In most developing countries they become all but insurmountable, because of the generally impoverished state of routine monitoring and reporting. Given that controls on emissions and exposures in the developing world are often limited, it is in these countries that risks from environmental pollution are likely to be greatest. Such uncertainties thus render any attempt to quantify the environmental burden of disease highly approximate at best.

Assessments of the disease burden attributable to different forms and sources of pollution are nevertheless worth the effort. They are needed, for example, to raise awareness about some of the risks associated with environmental pollution, and as a basis for advocacy—to ensure that those most in need have a voice. They are needed to help motivate and prioritize action to protect human health, and to evaluate and monitor the success of interventions. They provide the foundation, therefore, for extremely powerful indicators for policy support, and a means of pricking the global conscience about inequalities in health.

Over recent years, therefore, many attempts have been made to assess the health status of the population, both nationally and globally, and to deduce the contribution made by pollution and other environmental factors. In Europe, for example, more than 50 national environmental health action plans have been developed, following the Helsinki Conference in June 1994, setting out strategies to tackle problems of environmental health. Although these differ substantially in terms of their content and scope, many have involved attempts to make formal assessments of the disease burden attributable to different environmental hazards, and to rank these in terms of their public health significance. Various methods were used for this purpose, though most relied on some form of expert judgement, informed where available by quantitative data on mortality or disease rates. Whatever the weaknesses of these assessments, their practical importance is evident, for they have contributed directly to policy prioritization and development in the countries concerned.

The same need has arisen to support the development of environmental health indicators. Since the early 1990s, largely motivated by WHO, increasing attention has been given to constructing indicators on environmental health at all levels from the local to the global scale, and severalindicator sets have been created (and to a lesser extent used). As such they depend upon an understanding of the association between pollution and health, either in the form of what have been called ‘exposure-side indicators’, which use information on exposures to imply degrees of

health risk, or 'health-side indicators', which use information on health outcome to suggest attributable effects.

Crude estimates of the number and proportion of deaths due to different diseases, of this nature, obviously give only a distorted picture of the true burden of disease, for they take no account of the age of death or the duration of any preceding illness and disability, nor the amount of suffering involved. To redress this, Murray and Lopez also computed estimates of the 'years of life lost' (YLL) and 'disability adjusted life years' (DALYs). Years of life lost are estimated as the difference between age at death and the life expectancy in the absence of the disease, based on an advanced developed country (82.5 years for women and 80 years for men at that time). DALYs also incorporate an allowance for the number of years lived with a disability due to disease or injury, weighted according to its severity (based on expert assessments of the relative impact of some 500 different conditions and disease sequelae). The years of disability or life lost are also discounted according to the age of onset (since it is assumed that future years of life lost contribute less to the burden of disease than current ones).

It is quite evident that because of our unchecked actions we have disturbed the ecological balance of our environment and hence are facing these issues. There are several ways through which we can effectively contribute towards the cause. For instance, we can grow more and more trees in our living surroundings as well as where we find an empty piece of land. Or if you have a backyard or a piece of land at your home, then start planting trees. Plants, as we all know, absorb carbon dioxide for the process of photosynthesis and release oxygen into the environment. The estimation says that a single tree can soak up to one ton of carbon dioxide till the time it lives. No issues, if you don't have much space, you can even keep small tubs of plants in your balcony, doorway or windows.

We must adapt our process of manufacturing and domestic product to be in harmony with the environment. More of regenerative, reusable and recyclable techniques must be used in manufacturing units, etc. Latest technological advancements in the field of science have made us more empowered, of which I think we are taking undue advantage, by utilizing the environmental resources indiscriminately and giving it nothing in return, but harmful chemicals and pollution.

Conclusion - The complexities involved in the link between environmental pollution and health, and the uncertainties inherent in the available data on mortality and morbidity, in existing knowledge about theetiology of diseases, and in environmental information and estimates of exposure, all mean that any attempt to assess the environmental contribution to the global burden of disease is fraught with difficulties. The estimates produced to date must therefore be regarded as no more than order-of-magnitude estimates. Environmental pollution plays a significant role in several health outcomes, and in several cases, this adds up to a serious public health concern. Water pollution, sanitation and hygiene, indoor air pollution, and to a lesser extent outdoor air pollution and exposures to chemicals in both the indoor and outdoor environment are all important risk factors in this respect. Ionizing and non-ionizing radiation and noise are also causes for concern in many cases.

The distribution of risks from these factors is not equal across the world. The global burden of disease may be difficult to quantify, but stark contrasts in that burden are evident between the developed and the developing world, between rich and poor, and often between children and adults. The developed world is not risk-free, and development is no panacea for all environmental health ills. On occasions, in fact, the opposite is true: developments, such as increased reliance on road transport, increased use of chemicals in agriculture, and increased proportions of time spent in modern, hermitically sealed buildings surrounded by chemically-based fabrics and furnishings may increase exposures and exacerbate health risks. But overall the developing world is far more severely affected by pollution, and in many instances becoming more so, as pressures from development add to traditional sources of exposure and risk.

References :-

1. Sexton K, Adgate JL. Looking at environmental justice from an environmental health perspective, J Expos Anal Environ Epidemiol, 2000; 9: 3–8.
2. Jarvis KE, Parry SJ, Piper JM. Temporal and spatial studies of autocatalyst-derived platinum, rhodium, palladium and selected vehicle-derived trace element in the environment. Environ Sci Technol. 2001; 35: 1031–6.
3. Department of Food, Environment and Rural Affairs. The Government's Strategic Review of Diffuse Water Pollution from Agriculture in England. Agriculture and Water: A Diffuse Pollution Review . London: DEFRA, 2001.
4. Fisher A, Matthews L. The social behaviour of sheep. In: Keeling LJ, Gonyou HW (eds) Social Behaviour in Farm Animals. Wallingford: CAB International, 2001.
5. UK Sustainable Development Commission. State of Sustainable Development in the UK. Preparatory Paper. London: UK Sustainable Development Commission, 2001.
6. Pirog R, van Pelt T, Enshayan K, Cook E. Food, Fuel and Freeways. An Iowa Perspective on how Far Food Travels, Fuel Usage and Greenhouse Gas Emissions. Ames, IA: Leopold Centre, Iowa State University, 2001.
7. Jones A. Eating Oil: Food Supply in a Changing Climate . London: Sustain and Elm Farm Research Centre, 2001.
8. Bro-Rasmussen F. Contamination by persistent chemicals in food chain and human health. Sci Total Environ 1996; 188: S45–S60.
9. McFarland M, Kaye J. Chlorofluorocarbons and ozone. PhotochemPhotobiol 1992; 55: 911–29.

Fixed Point Theorem In Pseudo Compact Tichonov Space

Ganesh Kumar Soni *

Abstract - In this present paper, we discuss the existence and unique of fixed point theorem in Pseudo Compact Tichonov space.
Keywords - Fixed point, Pseudo Compact Tichonov Space, Self mapping.

Introduction - There are several generalization of Banach Contraction mapping principle [1]. During the past few years a number of authors like Jain and Dixit[2]Pathak[3] Khan and Sharma [4] worked on Pseudo Compact Tichonov Spaces.

Preliminaries -

Pseudo Compect Tichonov Space - A topological space X is said to be Pseudo compact space if every real valued continous function on X is bounded it may be noted that every compact space is Pseudo compact but converses may not be true. However in a metric space notation compact and Pseudo Compact coincide. By Tichonov space we means a completely regular Housdorff space.

Our Main Result - Theorem :Let P be a Pseudo compact Tichonov space and d be a non- negative real valued continuous function over P x P (P x P is Tichonov but need not be Pseudo compact) satisfy following inequilities;

(i). d (x, x) = 0 for all x $\in$ P

$d(x,y) \le d(x,z) + d(z,y)$ *for* all x, y, z$\in$ P

Let $T : P \to P$ be a continuous map satisfying

(ii) $$d(Tx,Ty) \le \alpha \left[\frac{d(y,Tx)\sqrt{d(x,Ty)} + d(x,Tx)\sqrt{d(y,Ty)}}{d(x,y)}\right]^2$$

$$+\beta \left[\frac{d(x,Tx)\sqrt{d(y,Ty)} + d(x,Ty)\sqrt{d(y,Tx)}}{d(x,y)}\right]^2$$

$$+\gamma \left[\frac{\sqrt{d(x,y)d(x,Ty)} + \sqrt{d(x,y)d(y,Tx)}}{\sqrt{d(x,Ty)+d(y,Tx)}}\right]^2$$

Where $\alpha, \beta,$ *and* γ is non- negative reals such that $(\beta + \gamma + 2\delta) < 1$.Then T a unique fixed point in P.

Proof - We define $\phi : P \to R$ by $\phi(p) = d(p,Tp)$ for all p $\in$ P where R is the set of positive real numbers clearly ϕ is continuous being the composite of two continuous function T and d. Since P is Pseudo compact Tichonov sapce every real valued continuous function over P is bounded and attend its bounds.

Thus there exists a point z ε P such that $\phi(v)$ inf $\{\phi(p)$: p $\in$ P$\}$ where 'inf' denotes the infimum or the greatest lower bound in R (note $\phi(P) \subset R$).

We suppose that z is a fixed point for T if not.Let us suppose that $Tz \neq z$. Then using (II) we have.

$$[\phi(Tz)] = \{d(Tz,T^2z)\}$$

$$\le \alpha \left[\frac{d(Tz,Tz)\sqrt{d(Tz,T^2z)} + d(z,Tz)\sqrt{d(Tz,T^2z)}}{d(z,Tz)}\right]^2$$

$$+\beta \left[\frac{d(z,Tz)\sqrt{d(Tz,T^2z)} + d(z,T^2z)\sqrt{d(Tz,Tz)}}{d(z,Tz)}\right]^2 +$$

$$\gamma \left[\frac{\sqrt{d(z,Tz)d(z,T^2z)} + \sqrt{d(z,Tz)d(Tz,Tz)}}{\sqrt{d(z,T^2z)+d(Tz,Tz)}}\right]^2$$

$$\le \alpha \left[\frac{d(Tz,Tz)\sqrt{d(Tz,T^2z)} + d(z,Tz)\sqrt{d(Tz,T^2z)}}{d(z,Tz)}\right]^2$$

$$+\beta \left[\frac{d(z,Tz)\sqrt{d(Tz,T^2z)} + d(z,T^2z)\sqrt{d(Tz,Tz)}}{d(z,Tz)}\right]^2$$

$$+\gamma \left[\frac{\sqrt{d(z,Tz)d(z,T^2z)} + \sqrt{d(z,Tz)d(Tz,Tz)}}{\sqrt{d(z,T^2z)+d(Tz,Tz)}}\right]^2$$

$$\le \alpha\, d(Tz,T^2z) + \beta\, d(Tz,T^2z) + \gamma\, d(z,Tz)$$

$$(1-\alpha-\beta)\, d(Tz,T^2z) \le \gamma\, d(z,Tz)$$

$$(Tz,T^2z) \le \left[\frac{\gamma}{(1-\alpha-\beta)}\right] d(z,Tz)$$

$$d(Tz,T^2z) \le d(z,Tz) \text{ i.e. } \phi(Tz) \le \phi(z)$$

This is a contradiction. So we have z = Tz i.e. z is a fixed point of Tin P. This establishes the theorem.

*Deptt. of Mathematics, Govt. P.G. College, Narsinghpur (M.P.) INDIA

Uniqueness - To prove the uniqueness of z if possible let $w \in P$ be another fixed point for T i.e. Tw= w and $w \neq z$ The using (II) we have.

$$d(z,w) = d(Tz,Tw)$$

$$\leq \alpha \left[\frac{d(w,Tz)\sqrt{d(z,Tw)} + d(z,Tz)\sqrt{d(w,Tw)}}{d(z,w)}\right]^2$$

$$+\beta \left[\frac{d(z,Tz)\sqrt{d(w,Tw)} + d(z,Tw)\sqrt{d(w,Tz)}}{d(z,w)}\right]^2$$

$$+ \gamma \left[\frac{\sqrt{d(z,w)d(z,Tw)} + \sqrt{d(z,w)d(w,Tz)}}{\sqrt{d(z,Tw) + d(w,Tz)}}\right]^2$$

$$\leq \alpha \left[\frac{d(w,z)\sqrt{d(z,w)} + d(z,z)\sqrt{d(w,w)}}{d(z,w)}\right]^2$$

$$+\beta \left[\frac{d(z,z)\sqrt{d(w,w)} + d(z,w)\sqrt{d(w,z)}}{d(z,w)}\right]^2$$

$$+ \gamma \left[\frac{\sqrt{d(z,w)d(z,w)} + \sqrt{d(z,w)d(w,z)}}{\sqrt{d(z,w) + d(w,z)}}\right]^2$$

$$\leq \alpha d(z,w) + \beta d(z,w) + 2\delta d(z,w)$$

$$\leq (\beta + \gamma + 2\delta) d(z,w)$$

Which is contradiction. Hence z $\in$ P is a unique for T in P. This completes the proof.

References :-

1. Banach, S. (1922) Surles operation dans ensembles abstraits etleur application aux equations integrals ,fund. Maths 133-18 .
2. Jain R.K. and Dixit, S.P. (1986) “ Some results on fixed points in Pseudo compact Tichonov spaces”. Indian J. Pure and appl. Math 5. 455-458 .
3. Pathak, H.K. (1986)”Some theorems on fixed points in Pseudo compact Tichonov Spaces” Indian J. Pure and Appl. Math 15; 180-186 .
4. [4]Khan S. and Sharma P.L. (1991) “ Some results on fixed points in Pseudo compact Tichnov Spaces”. Acta Cinenia India, 17. 483-488 (1991)

****

Ethno-Veterinary Uses Of Grasses In Nimar Region (M.P.)

Dr. Kiran Surage * Dr. Shweta Tiwari ** Dr. Seema Agrawal ***

Abstract - The grasses are ethnically and intimately connected with man due to greatest economic and ethno-veterinary importance. They play a significant role in the lives of the human being and animals but not much is known about the ethno-veterinary importance of this group of plants. The present paper gives an account of the ethno-veterinary uses of **8** grasses found in Nimar region Madhya Pradesh.
Key Words - Ethno-Veterinary Grasses, Human and Veterinary, significant role of grasses, animal husbandry health care practices are used.

Introduction - Cattle contribute a major source of lively hood for tribal people. To maintain this live stock, indigenous animal husbandry health care practices are used. These are cheap, safe, time tested and based on local resources. Grasses are valuable for the live stock population of the area. Grasses are also used in medicine more especially in indigenous system of medicine.

The present paper deals with the enlistment of ethno-veterinary important grasses of tribal areas after exploring their ethno-veterinary uses among the tribal people viz. Gond, koru, Bhil and Bhilala of Nimar region.

The Nimar is located in the south west part of Madhya Pradesh and lies between **21°35' - 22°> 6' N** Latitude and **>4°25' - 76°14' E** longitude. Topographically the area is situated centrally in Northern part covered with Vindhyan range and in southern part with Satpura range. It is bounded on the east by Betul and Hoshangabad districts of M.P. and Amrawati districts of Maharashtra. On the south by Jalgaon and Buldhana (Maharashtra) districts. On the west by Alirajpur district and in the North by Dewas district. It has an area of 22474 sq. km. of which forest cover is **4709 sq. km**.It is divided into 2 regions.

I. East Nimar - Khandwa and Burhanpur districts.
II. West Nimar - Khargone and Barwani districts.

Materials & Methods - The ethno-veterinary survey was conducted in different areas of the Nimar. The grasses and their products used by the different ethnic groups of people were collected during this study. The local medicine men were interviewed for getting the first hand information on ethno-veterinary uses of grasses.

The grasses collected during the study were identified and the specimens were deposited in botany department P.M.B. Gujarati Science College Indore. The information gathered is described in alphabetical order of Latin names of plants.

Observation - The ethno-veterinary uses of grasses of Nimar region are follows as-

1. Apluda muticaL.
- *Local name*- Phuli, Phuler.
- *Uses*-
- Poultice of plant is used to cure sores of cattle.
- Paste of plant along with small fish is given to cattle in treatment of flatulence.
- Roots are crushed in mustard oil to prepare a paste. This is applied on the mouth sores of cattle.

2.Arundo donax L.
- *Local name*- Barru.
- *Use*-
- Rhizome paste and common salt mixed with fodder is administered to cure dyspepsia.

3. Bothriochloa pertusa(L.) A. Camus
- *Local name*- Seroti,Phuli, Phulara, Malhar.
- *Uses*-
- 500 gm. flour of grains is fed to animals once a day for 5 days in diarrhoea.
- Flour is also used in healing of "Nathela" (a wound of nostrils).

4. Dendrocalamus strictus(Roxb.) Nees
- *Local name*- Bans.
- *Use*-
- 50 ml. infusions of tender shoots or leaves is given twice a day for 30 days to cure bone fracture of animals.

5. Desmotachya binnata(L.) Stapf
- *Local name*- Kusha, Darba.
- *Use*-
- Entire plant is crushed and given to cows as galactogogues.

6. Saccarum spontaneumL.
- *Local name*- Kans.
- *Uses*-

*Head (Horticulture) Shree Jain Diwakar Collage, Indore (M.P.) INDIA
** Head (Seed Technology) Shree Jain Diwakar Collage, Indore (M.P.) INDIA
*** Head (Chemistry) Shree Jain Diwakar Collage, Indore (M.P.) INDIA

- Inflorescence ash mixed with mustard oil is applied on the wounds for 3 days.
- Plant is given with normal fodder to cattle as galactogayl.

7. Setaria pumila (Poir) Roem and Schultz.

- *Local name*- Langat.
- *Use*-
- Paste of grains with paste of black peppers applied on sores of neck region of bulls.

8.Themeda quadrivalvis(L.) Kuntze

- *Local name*- Gundel/Gunhar.
- *Use*-
- Small fishes mixed with in grass are given to cure flatulence in cattle, especially buffalos.

Results & Discussion - 8 grass species of ethno-veterinary medicinal importance have been recorded and enumerated. The data on these grasses such as the botanical name, local name and their traditional methods of drugs administration in different ailments are given. These plants are being used by various ethnic group of Nimar region to treat ailments such as animal injuries, wounds, fever, diarrhea, bone fracture, asthma, cough & cold, mouth sores, dyspepsia, galactogogues by using fresh or dried plant materials.

References :-

1. **Anil Kumar & Yadav D.**K. **2006.** Important Ethnomedicinal Plants of family Poaceae in Gaya District, Bihar. *J. Econ. Taxon. Bot*. Vol. 30.
2. **Caius. J. F. 1936.**The medicinal and poisonous grasses of India. *J. Bombay nat. Hist*. Soc. 38: 54o-584.
3. **Chopra, R.N. I.C. Chopra & B.S. Verma 1969.** Supplement to Glossary of Indian medicinal plants. C.S.I.R., New Delhi.
4. **Guria, B.D.1997.** Ethnobotanical studies on the grasses of South East Rajasthan, PhD. Thesis, M. L. Sukhadia University, Udaipur, India.
5. **Jadhav, Dinesh 2006.** Ethnomedicinal plants used by Bhil tribe of Bibdod, Madhya Pradesh. *Indian Journal of Traditional Knowledge*. Vol. 5 (2): 263-267.
6. **Potdar, G. G. Salunkhe, C. B. & Yadav, S. R.2012.**Grasses of Maharashtra. Shivaji University, Kolhapur.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

Incidence Of Iron Deficiency Anemia In Pregnant Woman Coming To Distt. Hospital, Satna

Dr. Rashmi Singh*

Introduction - According to WHO experts Hb level in blood below 10gm/dl is defined as Anemia, Hb level between 10 to 11 gm/dl is defined As early Anemia. Adult human body contains 3-4 gm of iron of which 60 to 70% in blood in form of Hb iron rest 1 to 1.5 gm as stored iron. Each grams of Hb contains 3.34 mg of iron. Iron is essential for many functions of body which includes formation of Hb, brain development, regulation of body temperature, muscle activity, catecholamine's metabolism, lack of iron directly affect the immune system, beside hemoglobin, central function of iron is oxygen transport and cell respiration. In pregnant woman iron requirement during first half is 0.8 mg daily and in second half 3.5 mg daily, 50 to 60% of the woman of low socioeconomic group are anemic in last trimester of pregnancy. Maternal mortality rate (MMR) is 1% in 15 to 49 age group, hemorrhage is 38% responsible of total maternal death due to anemia.

Iron deficiency anemia is traditionally been defined as microcytic hypo chromic anemia secondary to a total body iron deficit, in iron deficiency anemia there is negative iron balance and iron deficient erythropoiesis, there is inbalance between normal physiological demand and level of dietry iron intake as seen in pregnancy, red blood cell morphology indicates a negative iron balance and severe anemia stimulate the production of poorly hemoglobinized cells, these clinical states in any population indicates the character of directly iron supply, the efficiency of iron absorption and incidence of disease states that result in iron loss in adult female daily intake of balanced diet will give 10 to 15 mg/dl, only 1-2 mg of iron needs to be absorbed for desquamation of skin and mucosal cells.

Material And Method - This study has been conducted in Obstetrics & Gynecology Dept. D.H. Satna from 1st August 2017 to 30th September 2017 attending OPD, total PT's were 4628, new ANC cases were 322, high risk Pregnancy Cases were 68, age of the cases were between 15 to 49 years of age, patients socioeconomic status, literacy, rural & urban background, other associated diseases, primi or multipara were also considered. Hb level estimations done in OPD & ward as a routine in all ANC cases

Observation & Result - It has been observed that total number of high risk pregnancy were 68 out of 322 ANC cases, ratio was 1:4.7 high risk pregnancy were cases whose Hb level was 8 to 9 gm/dl. Cases found anemic were generally of low socio-economic gp their ratio was to well to-do patient was 3:1, cases belonging to rural areas were found more Anemic than urban population probably due to poor nutrition, ignorance & illiteracy Ratio was 4:1, Anemia was more observed in multipara, ratio between primipara & multipara was 1 to 3, maximum number of Anemic cases were observed between 30 to 40 year of age probably due to poor nutrition and repeated delivery, in 10% of cases associated other diseases like Leucorrhoea, dysfunctional uterine Bleeding, fungal infection of genitala were also observed.

Discussion - In our study all the patients having severe anemia clinically presented with fatigue, pallor, mouth soreness, difficulty in swallowing, softening and **curling of nails called spooning**, as our study denotes that iron deficiency anemia was more common in rural areas, illiterate class, low socioeconomic group of patients and in multiparas, it reflects that inadequate dietry intake of iron, other associated diseases like worm infestation dysfunctional uterine bleeding, poor intestinal absorption due to amoebiasis and other associated diseases are responsible for anemia,

Conclusion - Our study denotes that all the antenatal cases coming to our hospital should be investigated routinely their hemoglobin level should be seen and cases which are anemic, they should be categorized as per their severity and they should be treated properly. Cases who are preanemic means their Hb level is between 10 to 11 gm/dl should be given one tablet 3-4 times a day of ferrous sulfate containing 325 mg of iron or syrup containing each 5 ml have 300 mg of iron 3 to 4 times a day. Iron deficient patients will absorb 40-60 mg of iron per day but as the Hb level reaches 11 to 12 gm/dl dose of iron should be reduced, this treatment should be continued for at least 6 months to maintain the reticulo endothelial iron stores.

Prevention :

1. Govt of India has started a programme in which 100 mg of Iron & 500 mg of Folic acid are distributed daily to pregnant woman through antenatal clinics, PHC & mini PHC.
2. ANM'S Antenantal visit 1st at 20 Wks, 2nd 32 Wks, 3rd 36 Wks.

*Deptt. of Zoology, Govt. P.G. College, Satna (M.P.) INDIA

3. 3.2 lac village Health guides are appointed in our country to work for 2-3 hrs./ day for welfare of pregnant woman.
4. Health worker female are appointed at PHC level to distribute iron and folic acid tab to pregnant woman among 350 to 500 families.
5. Health insurance proposed for pregnant woman.

References :-

1. World Health Organization. Iron Deficiency Anaemia: Assessment, Prevention, and Control. A Guide for Programme Managers. Geneva: World Health Organization; 2001. Accessed at http://www .who.int/ nutrition/publications/en/ida_assessment_ preven tion_control .pdf.
2. Institute of Medicine, Committee on the Prevention, Detection, and Management of Iron Deficiency Anemia Among U.S. Children and Women of Childbearing Age. Iron Deficiency Anemia: Recommended Guidelines for the Prevention, Detection, and Management Among U.S. Children and Women of Childbearing Age. Washington, DC: National Academies Press; 1993. [PubMed]
3. World Health Organization. Guideline: Daily Iron and Folic Acid Supplementation in Pregnant Women. Geneva: World Health Organization; 2012.
4. Healthy People 2010. US Government; 2000. Available at: http://www.healthypeople.gov/2020/default.aspx. Accessed February 17, 2011..
5. Weiss, G., Goodnough, L.T. Anemia of chronic disease. N Engl J Med. 2005;352:1011–1023.
6. Andrews, N.C. Forging a field: the golden age of iron biology. Blood. 2008;112:219–230.
7. Baker, W.F. Jr. Iron deficiency in pregnancy, obstetrics, and gynecology. Hematol Oncol Clin North Am. 2000;14:1061–1077.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

Effect Of In Vivo Incubation Of Bovine Spermatozoa In The Uterus Of Rats Actively Xenoimmunized With Bovine Spermatozoa On Sperm Motility And Viability

Jayshree Hardenia* S.K. Jain Asha Khanna*****

Introduction - Rapid developments in the field of immunology have diverted the attention of many researchers to the role of immunological response in the pathogenesis of infertility. Consequently, several cases of unexplained infertility were reported to have an immunological basis of conception failure in cattle (Awasthi *et al*., 1988 and Bhardwaj, 1992) and buffaloes (Jain, 1985 and Jain and Gupta, 1988). In the present investigation, the effect of in vivo incubation of bovine spermatozoa in the uterus of rats actively xenoimmunized by intramuscular route with bovine spermatozoa, and non immmunized rat model (as control) on the sperm motility and sperm viability was studied.

Materials And Methods -

Experimental rats - Albino rats (n=6) were actively immunized with bull semen (0.25 ml intramuscularly). Primary injection - 200 x 10^6 sperms/ml in Fruend's Complete Antigen (FCA); Ist booster - 200 x 10^6 sperms/ ml in saline and IInd booster - 200 x 10^6 sperms/ml in saline. Sperm antibody titre was determined by Capillary Agglutination Test (Jain, 1985) and Tube Slide Agglutination Test (Shulman, 1975). Titre of 1:32 to 1:64 was obtained in the rats were used as experimental animals.

Control: Non immunized rats (n=6).

Experimental procedure - Rats in oestrus were anaesthetized and posterior laparotomy was performed exposing the abdominal cavity. The bifurcation of the uterine horn was exposed and each uterine horn was ligated separately at the base and tip using sterile cotton thread. Freshly collected bovine spermatozoa were given two washings in normal saline and reconstituted to 500 x 10^6 sperm cells per ml of saline. Before use, individual motility and sperm viable count was recorded. This constituted the antigen used for challenge.

A dose of 0.1 ml of the antigen was deposited for incubation in both the horns with the help of a 24 gauge needle just anterior to the base ligature. A sterile gauge soaked with saline was placed over the wound and kept wet by frequent spraying of normal saline over it. The rats were left for 15 mins and one horn was removed by severing from below the ligature near the bifurcation and above the ligature for the apex. The other horn was removed after 30 minutes. The uterus was then dissected out from the abdominal cavity, separated into left and right horn and gentle washing of the horns was done with normal saline to remove adhered blood and rolled over a clean blotting paper to dry it. The tip of the horn was severed and flushed with 0.1 ml normal saline.

Parameters studied -

1. Sperm progressive motility (Zemjanis, 1970).
2. Sperm viability (Swanson and Bearden, 1951).

Results And Discussion -

1. Effect of incubation of bovine spermatozoa in uterus of xenoimmunized and non immunized rats on sperm motility - The data on the effect of incubation of bovine spermatozoa in uterus of xenoimmunized and non immunized rats on sperm motility are presented in table 1.

Table 1. Effect of incubation of bovine sperms in uterus of actively xenoimmunized and nonimmunized rats on sperm motility expressed as percentage of progressively motile spermatozoa (Mean±S.E.).

	Percent decline in motility	
	15 min	30 min
Immunized rat	71.94 ± 5.36	91.50 ± 0.55
Non-immunized rat	49.17 ± 6.91	39.89 ± 4.21

On introduction of bull spermatozoa in the bovine sperm xenoimmunized uterus, the decline in the sperm motility was 61.94±12.32 per cent as compared to that in the nonimmunized rats (49.17±6.91 per cent) over 15 minutes incubation. This higher decline in the immunized group over the nonimmunized group at 15 minutes was significant (P<0.05). Comparing the results obtained at 30 mins, it can be observed that in the immunized group the per cent decline in motility was 91.50±0.55 per cent as compared to 38.89±4.21 per cent in the nonimmunized group which was highly significant (P<0.05). Within the immunized group, the decline between 15 (71.94±5.36 per cent) and 30 (91.±0.55 per cent) minutes was also highly significant (P<0.01), whereas, within the non immunized group, the decline was non significant between 15 (49.17±6.91 per cent) and 30 (38.89±4.21 per cent) minutes.

*Research Scholar, Rani Durgavati Vishwa Vidyalaya, Jabalpur (M.P.) INDIA
** Deptt. of Veterinary Gynaecology & Obstetrics, College of Veterinary Science & A.H., Jabalpur (M.P.) INDIA
***Govt. (Autonomous) Science College, Jabalpur (M.P.) INDIA

The initial reduction in motility in the uterus of non immunized rats at 15 mins may be due to the non activation of the sperm motility activating factor. However, by 30 mins, early events of capacitation of the bovine sperm in the uterus of rats might have taken place which enhanced the motility, since, capacitation of spermatozoa of one species has also been shown to occur in the biological fluids of another species (Yanagimachi, 1969, 1970).

1. Effect of incubation of bovine spermatozoa in uterus of xenoimmunized and non immunized rats on sperm viability - The data on the effect of incubation of bovine spermatozoa in uterus of xenoimmunized and non immunized rats on sperm viability are presented in table 2.

Table 2. Effect of incubation of bovine sperms in uterus of actively xenoimmunized and nonimmunized rats on sperm viability expressed as percentage of viable spermatozoa (Mean±S.E.).

	Percent decline in sperm viability	
	15 min	30 min
Immunized rat	19.20 ± 5.97	21.21 ±7.47
Non-immunized rat	18.28 ±3.96	11.01 ±2.75

On introduction of bull spermatozoa in the bovine sperm xenoimmunized uterus, the per cent decline in the viable spermatozoa was 19.20 ±5.97 per cent as compared to that in the nonimmunized rats (18.28±3.96 per cent) over 15 minutes incubation. This higher per cent decline in the immunized group over the nonimmunized group at 15 minutes was non significant. Comparing the results obtained at 30 mins, it can be observed that in the immunized group the per cent decline in viable spermatozoa was 47.00±4.77 per cent as compared to 57.67±2.47 per cent in the nonimmunized group which was also non significant. Within the immunized group, the decline between 15 (19.20±5.97 per cent) and 30 (21.21±7.47 per cent) minutes was also non significant, and within the non immunized group, the decline was also non significant between 15 (18.28 ±3.96 per cent) and 30 (11.01±2.75 per cent) minutes.

It was interesting to note that when the bovine spermatozoa were incubated in the uterus of non immunized rats, the per cent decline in viable spermatozoa at 15 minutes (18.28±3.96 per cent) was higher as compared to that at 30 mins incubation (11.01±2.75 per cent). Thus the number of viable sperms at 30 mins increased in the non immunized group, whereas, in the immunized group, the per cent decline being higher indicates a lower number of viable sperms. This increase in viable sperms was non significant. This indicates that there is a high disposal of dead spermatozoa as the incubation time increases in the absence of sperm antibodies, whereas, in its presence, it continues to dispose off more spermatozoa.

It was concluded that systemic immunization of the rats by intramuscular injection with bovine sperm (xenoimunization) results in an immune response reflected by presence of antisperm antibodies in serum. Incubation of the bovine sperm in bovine sperm actively xenoimmunized uterus of rats results in a dramatic loss in sperm motility and percentage of viable sperms.

References :-

1. Awasthi M.K.; Kharche K.G. and Jain S.K. (1988). Antisperm antibody titre associated with conception failure in repeat breeder cross bred cows. Cheiron, 17: 15-18.
2. Bhardwaj, A.K. (1992). Studies on sperm antigen-antibody interactions in repeat breeder cross bred cows. M.V.Sc. A.H. Thesis, J.N.K.V.V., Jabalpur.
3. Jain S.K. (1985). Hormonal, biochemical and immunological studies on conception failure in buffaloes. Ph.D. Dissertation, Haryana Agricultural University, Hisar.
4. Jain S.K. and Gupta R.C. (1988). Sperm agglutinating antibody titres associated with conception failure in buffaloes (Bubalus bubalis). Proceedings of the 11th International Congress on Animal Reproduction and Artificial Insemination, June 26-30, 1988, Dublin, Ireland. No.534.
5. Shulman, S. (1975). Sperm antibodies and their relation to infertility. In: Reproduction and Antibody Response, CRC Press Inc., U.S.A. pp 37-92.
6. Swanson E.W. and Bearden H.J. (1951). An eosine-nigrosin stain for differential staining of live and dead bovine sperms. J. Anim. Sci. 10:981-987.
7. Yanagimachi, R. (1969). In vitro acrosome reaction and capacitation of golden hamster spermatozoa by bovine follicular fluid and its fractions. J. Exp. Zool. 170: 269.
8. Zemjanis R. (1970). Diagnostic and Therapeutic Techniques in Animal Reproduction. Williams and Wilkins Co., Baltimore, U.S.A. pp. 145-152.

****

रासायनिक उर्वरकों के स्वरूप एवं कृषि में प्रयोग का अध्ययन (छ.ग. के बिलासपुर संभाग के विशेष संदर्भ में)

नोर्बेलता एक्का *

शोध सारांश– भारत सरकार की नवीन कृषि नीति और अनुसंधान के तहत् रासायनिक खाद के उपभोग को बढ़ाने के लिये सभी स्तरों पर तेजी से प्रयास किये गये हैं, भारत में रासायनिक उर्वरकों का उपभोग 1960 किलो ग्राम प्रति हेक्टर हो गया है। लेकिन भारत आज भी रासायनिक खाद के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। आज भी रासायनिक खाद का बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है, रासायनिक खाद के प्रयोग की कुछ सीमायें भी उजागर हैं। रासायनिक खाद की ऊँची कीमत के कारण भारत सरकार को पर्याप्त मात्रा में सब्सिडी देनी पड़ती है। रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग कैसे किया जाए अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है।

शब्द कुंजी – रसायन, उर्वरक, नाइट्रोजन, उत्पादकता, फॉस्फेट, पोटाश।

प्रस्तावना – बिलासपुर संभाग की उपजाऊ भूमि के उपरान्त भी कृषकों की कमजोर आर्थिक स्थिति, जल के लिए मानसून पर निर्भरता तथा पुराने परम्परागत साधनों एवं रासायनिक उर्वरकों से फसल पर निर्भरता ने कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि नहीं होने दी है। वर्तमान में आधुनिक रासायनिक उर्वकों के उपयोग से कृषि उत्पादन में सकारात्मक परिवर्तन हुये हैं।

रासायनिक उर्वरक से आशय – रासायनिक उर्वरक से आशय कृषि में उपज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त रसायन से है जोकि पेंड़–पौधों की वृद्धि में सहायता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पानी में शीघ्र घुलने वाले ये रसायन मिट्टी में या पत्तियों में छिड़काव करके प्रयुक्त किये जाते हैं। पौधे मिट्टी से जड़ों द्वारा एवं उपरी छिड़काव करने पर पत्तियों द्वारा उर्वरकों को अवशोषित कर लेते हैं।

उर्वरक – भारतीय कृषि क्षेत्र के कृषि विकास में तकनीकी परिवर्तन लाने में खाद और उर्वरक की भूमिक अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने में उर्वरक का सबसे प्रमुख स्थान है। कृषि वैज्ञानिक के अनुसार बाकी चीजों के साथ रहते हुये, एक टन पोषण उर्वरक खाद्यान्न के उत्पादन को लगभग 10 टन बढ़ाता है। इस प्रकार उर्वरकों की वार्षिक खपत से फसलों के उत्पादन में देश की उपलब्धि का अच्छी तरह पता चल सकता है। उर्वरकों की खपत के मामले में विश्व में भारत का स्थान पर्याप्त संतोष जनक है। रासायनिक उर्वरकों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं, क्योंकि जैविक खादों की अपेक्षा इनका भार कम होता है। विश्व में प्रमुख कृषि प्रधान देशों की उर्वरा शक्ति घटती जाती है। फसलें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश जैसे – आवश्यक पोषक तत्व जड़ो द्वारा प्राप्त करती हैं। अत: इस प्रकार भूमि से इन तत्वों की कमी होती जाती है। नीचे दिये गये सारणी क्रमांक 01 से भिन्न–भिन्न फसलों के क्रय स्वरूप भूमि में विभिन्न तत्वों की होने वाली न्यूनता दर्शाई गयी है।

तालिका क्रमांक 01 **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाये रखने के लिए आवश्यक है, समय–समय पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश जैसे रासायनिक तत्वों की कमी को पूरा किया जाये। इसके अनेक कारण है –

- गोबर या कम्पोस्ट खाद से भूमि की रासायनिक उर्वरा शक्ति में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती है।
- मिट्टी की बनावट और जलवायु के अनुसार खाद के स्वरूप में परिवर्तन होतारहता है।
- परंपरागत खाद सभी पोषक तत्वों की कमी को पूरा नहीं कर पाते है।
- गोबर जैसे खाद में नाइट्रोजन की मात्रा 7 प्रतिशत से भी कम होती है। इसी प्रकार फास्फोरस तथा पोटाश की अधिकतम प्रतिशत 5 तथा 2 प्रतिशत होती है। जो उत्पादकता को उच्च स्तर तक बढ़ाने में सहायक नहीं है।
- मृदा उर्वरकों को बनाये रखने तथा पौधों को पर्याप्त पोषक तत्व देने के लिये उर्वरकों का समय–समय पर प्रयोग जरूरी है।
- आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के तहत् नवीन खाद संरचना में उर्वरकों में नवीन अनुसंधान और खोज की संभावना अधिक है।
- उर्वरक केवल सिंचित क्षेत्र में उत्पादकता को नहीं बढ़ाते बल्कि सूखे और न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में भी कृषि विकास के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
- रासायनिक उर्वरक का उत्पादन बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योगों द्वारा संचालित होते हैं। जिनकी आपूर्ति किसी भी सीमा तक बढ़ाकर संपूर्ण कृषि फसलों की उत्पादकता में क्रांतिकारी वृद्धि ला सकती है।
- उर्वरक संवर्धन संपूर्ण कृषि विकास कार्यक्रम का मुख्य घटक होना चाहिये।
- आधुनिक कृषि प्रणाली में जिन वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का समावेश किया जाता है वह रासायनिक खाद और उर्वरक के प्रयोग ओर अध्ययन के बिना अपूर्ण होगा।

उर्वरकों का वर्गीकरण – पोषक के आधार पर उर्वरकों को निम्न तीन भागों में विभाजित किया
जा सकता है–

1. नाइट्रोजन धारी उर्वरक,
2. फास्फोरस धारी उर्वरक एवं
3. पोटाशधारी उर्वरक।

*शोधार्थी, डॉ.सी.व्ही.रमन विश्वविद्यालय, करगीरोड़, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

1. नाइट्रोजनधारी उर्वरक – इन उर्वरकों की उनकी रासायनिक एवं उनमें पायी जाने वाली नाइट्रोजन के प्रकार के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है– 1. नाइट्रेटउर्वरक, 2. अमोनियम उर्वरक, 3. अमोनियम और नाइट्रेट उर्वरक, 4. एमाइड उर्वरक।

तालिका क्रमांक 02 **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग –

1. धान के खेतों में नाइट्रेट के उर्वरकों का उपयोग नहीं करना चाहिये।
2. रबी मौसम की फसलों में सभी प्रकार के नाइट्रोजनधारी उर्वरकों का उपयोग किया जा सकता है।
3. वर्षा ऋतु में नाइट्रोजनधारी उर्वरकों को एक साथ न देकर किस्तों में देना चाहिए।
4. रेतीली मृदाओं में भी इन उर्वरकों के किस्तों में देना चाहिए।
5. यूरिया, गेंहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, तिलहन, आलू, गन्ना, सब्जियाँ, हरे चारे फसलों के लिये उत्तम उर्वरक है।

2. फॉस्फोरसधारी उर्वरक – उर्वरक के रूप में भी आवश्यक मात्रा में अधिक फॉस्फेट देना पड़ता है क्योंकि इसकी पर्याप्त मात्रा भूमि में पहुँच कर स्थिर हो जाती है।

फॉस्फोरस उर्वरकों का उपयोग –

1. पौधों की जड़ों का विकास बहुत कम होता हैं।
2. पौधे बौने दिखाई पड़ते है।
3. पत्तियाँ हरे रंग की हो जाती है।
4. फसल देरी से पकती है।
5. बीज और फसल का निर्माण उचित प्रकार से नहीं होता।
6. फूल कम और देर से निकलते हैं, और उनका आकार भी छोटा होता है।
7. अधिक कमी की अवस्था में पौधों की पत्तियाँ और तनों पर कत्थई रंग धब्बों का निर्माण हो जाता है।

तालिका क्रमांक 03 **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

3. पोटेशियमधारी उर्वरक – नाइट्रोजन व फॉस्फेट की अपेक्षा पोटेशियम भूमि में अधिक होता है। अधिकांश खनिज पदार्थो जैसे– अभ्रक, जियोलाइट, कैल्सपार,शोरा, पोटेशियम, सल्फेट, क्लोराईड इत्यादि के रूप में यह पर्याप्त मात्रा में पायाजाता है।

तालिका क्रमांक 04 **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

पोटेशियम धारी उर्वरकों का उपयोग – पोटाश पौधों को धींरे–धींरे प्राप्त होता है।अत: इसका उपयोग फसल द्वारा प्रारंभ से फसल पकने तक किया जाता है।

मिश्रित उर्वरक – दो या दो से अधिक साधारण उर्वरकों को मिलाने पर उसे मिश्रित उर्वरक संज्ञा दी जाती है। इनके प्रचलन का श्री गणेश 1850 में अमेरिका में हुआ।खाद के बोरों पर आपने तीन संख्यायें लिखी देखी होगी– 5–10–15 इस मिश्रित उर्वरक में N, Po, K की प्रतिशत मात्रा होती है।मृदा में कई बार एक से अधिक तत्वों की कमी होती है। इस दशा में 2 या3 उर्वरकों के स्थान पर एक मिश्रित उर्वरक ही उपयोग हो जाती है। इसका कोई निश्चित सूत्र नहीं है। इन्हें विशिष्ट मापदण्ड से बनाया जाता है। और उनसे प्राप्त तत्वों का प्रतिशत लिख दिया जाता है। सूक्ष्म पोषण तत्वों को इनके साथ मिलाकर दिया जा सकता हैं। परन्तु इनके उपयोग से पूर्व मृदा जांच कराकर सही पता लगालेना चाहिए कि मृदा में किस तत्व का किन तत्वों की कितनी कमी है। उसी के आधार पर इतनी मात्रा देनी चाहिए, यदि पोषक तत्व का आभाव है, तो उस स्थितिमें मिश्रित उर्वरक का उपयोग व्यर्थ है।

उर्वरकों का उत्पादन एवं वितरण– भारत में रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन उनकी मांग से कम होता है। अत: मांग की इस कमी को पूरा करने के लिये उर्वरकों का आयात किया जाता है। भारत में उर्वरकों के उत्पादन में क्रमश: वृद्धि हुई है। वर्ष 1960–61 में भारत में कुल उर्वरकों का उत्पादन 150 हजार टन थाजो बढ़कर 2003–04 में 14,200 हजार टन हो गया, परन्तु पोटाश युक्त रासायनिक खाद की पूरी मात्रा आयात की जाती है। निम्न सारणी में भारत में उर्वरकों के उत्पादन एवं आयात की मात्रा को प्रदर्शित किया गया है।

तालिका क्रमांक 05

भारत में उर्वरकों का उत्पादन एवं आयात (हजार मीटर टन में)

वर्ष	एन.	पी.	एन.पी.	एन.पी.के.
1960–61	98	52	150	419
1990–91	6993	2052	9045	2758
2000–01	10962	3743	14705	2090
2006–07	11382	4230	15620	2305

स्रोत– भारत सरकार की बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा – 2007–08, पृ. 165

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि देश में रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के साथ–साथ आयात की मात्रा भी क्रमश: बढ़ती गई है। इसका तात्पर्य यह है कि देश में उर्वरकों की खपत में पर्याप्त बढ़ोत्तरी होती जा रही है।

रासायनिक उर्वरकों की उपयोग की सीमाएँ – प्राय: रासायनिक खाद और कीटनाशक का बहुत कम हिस्सा अपने वास्तविक उद्देश्य के काम आता है। इनका एक बड़ा हिस्सा हमारे विभिन्न जल स्रोतों में पहुँच जाता है और भू–जल को प्रदूषित करता है। इसके कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ इस पानी का उपयोग करने वाले स्थानी निवासियों और पालतू पशुओं दोनों में देखी गई हैं। नदी और अन्य जल स्रोतों के प्रदूषण का बुरा असर मछलियों को भी भुगतना पड़ता है। एक खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के प्रयास में दूसरे खाद्यान्न का ह्रास होता है। तालाब जैसे जल स्रोत में नाइट्रोजन अधिक पहुँचने से हानिकारक पौधों का तेज प्रसार तालाब की उपयोगिता को समाप्त कर सकता है। मिट्टी का उपजाऊपन बनाने वाले अनेक सूक्ष्म जीवों केंचुओं आदि के लिए ये रसायन कहर ढाते हैं। साथ ही किसानों के मित्र अन्य कीट पतंगों, पक्षियों और अन्य जीवों के लिए भी ये रसायन हानिकारक होते हैं।

निष्कर्ष – कृषि में रासायनिक उर्वराकों के प्रयोग से कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही साथ लागत में भी कमी आयी है किन्तु कृषि भूमि एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी परिलच्छित हुए हैं।

सुझाव – फसलों को जिन विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता है, कुछ की अधिक मात्रा में और कुछ की सूक्ष्म मात्रा में, उन्हें उपलब्ध करावाने के लिए प्रकृति की अपनी व्यवस्था है। जैसे– दलहनी फसलों में वायुमण्डल से नाइट्रोजन निशुल्क प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता है। अत: हमें मिट्टी की उर्वरा–शक्ति को बनाये रखने के लिए फसल चक्र सरीखे तरीकों का प्रयोग करना चाहिए।

मृदा परीक्षण उपरान्त ही सन्तुलित मात्रा में ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए ताकि नकारात्मक पक्ष से बचा जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. मिश्र, डॉ0 जय प्रकाश, कृषि अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स– आगरा।
2. आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़,

रायपुर।
3. वार्षिक रिपोर्ट, भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, नई देल्ही।
4. जिला सांख्यिकीय कार्यालय, बिलासपुर, छ.ग.।
5. http://cg.nic.in/revenue/Table Of Agriculture Statistics 2013-14

तालिका क्रमांक 01

फसलों के स्वरूप भूमि में विभिन्न तत्वों की होने वाली न्यूनता

फसल	उपज कि.ग्रा. प्रति हेक्ट्रोजन	पोषक तत्वों में अपनयन की मात्रा (कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर)		
		नाइट्रोजन (N)	फॉस्फोरस (P2O5)	पोटाश (K20)
चावल	2800	37	13	9
गेंहूँ	2240	35	22	11
गन्ना	90317	85	60	190
कपास (लिंट)	104	27	20	87
पटसन	1120-1680	112-280	112-123	168-224

स्रोत- कृषि विश्वविद्यालय, पंत नगर नैनीताल, वार्षिक प्रतिवेदन 1980-81

तालिका क्रमांक 02

नाइट्रोजन धारी उर्वरकों का वर्गीकरण

नाइट्रेट कारखाना	सामग्री का नाम	नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा	तुलयांक	
			अम्लता	क्षारत्व
नाइट्रेट	सोडियक नाइट्रेट	16.0	-	29
	कैल्शियम नाइट्रेट	15.0	-	21
	पोटेशियम नाइट्रेट	13.0	-	29
	सोडा पोटाश का नाइट्रेट	15.0	-	28
अमोनियम	अमोनियम सल्फेट	20.5	110	-
	निर्जल अमोनियम	82.2	148	-
	अमोनियम क्लोराइड	25.0	128	-
	मोनो अमोनियम फास्फेट	11.0	65	-
	डाई अमोनियम फास्फेट	21.0	78	-
नाइट्रेट और अमोनिया	अमोनिया सल्फेट नाइट्रेट	26.0	99	-
	अमोनिया नाइट्रेट	23.5	60	-
	कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	20.5	-	-
एमाइड	कैल्शियम साइनाइड	22.0	-	63
	यूरिया	46.6	80	-

स्रोत – ए हेण्ड बुक ऑफ एग्रीको, एस कुमार, पृ. 59

तालिका क्रमांक 03
फॉस्फोरसधारी उर्वरकों के गुण

उर्वरक	प्रतिशत फॉस्फेट P2O5			उर्वरक की प्रकृति	आद्रता शोषित
	जल विलेय	साइट्रेट विलेय	कुल मात्रा		
ए – जल विलेय उर्वरक					
1. सिंगलासु पर फॉस्फेट	16.0	–	16.5	उदासीन	आद्रता व शोषी
2. ट्रिपल सुपर फॉस्फेट	42.5	–	46.0	अम्लीय	तदैव
बी – साइट्रेट विलेय उर्वरक					
1. डाई कैल्शियम फॉस्फेट	–	34.0	34.0	अम्लीय	तदैव
2. अस्थिी चूर्ण असंतृप्त	–	8.0	20.0	क्षारीय	अनार्द्रता व शोषी
3. अस्थिी चूर्ण वाष्पित 4. बेसिक स्लेग	– –	26.0 –	25.0 3.0 और 8.0	क्षारीय क्षारीय	तदैव तदैव
सी – जल और नाइट्रेट दोनों में अविलय					
1. रॉक फास्फेट	–	–	20.0–40.0 तक	क्षारीय	तदैव

स्रोत – ए हेण्ड बुक ऑफ एग्रीको, एस कुमार, पृ. 59।

तालिका क्रमांक 04
प्रमुख पोटाशधारी उर्वरक

उर्वरक	स्त्रोत जल विलेय पोटाश(K2O) प्रतिशत
पोटेशियम क्लोराइड (म्यूरिएट ऑफ पोटाश)	60.0
पोटेशियम सल्फेट (सल्फेट ऑफ पोटाश)	48.0–52.0
पोटेशियम कार्बोनेट	65.0
पोटेशियम मैग्नीशियम कार्बोनेट	20.0
पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट	21.0–30.0
पोटेशियम नाइट्रेट	44.0
सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट	15.0
विटर्न पोटाश	7.0
लकड़ी की राख	0.5–36.0

स्रोत– ए हेण्ड बुक ऑफ एग्रीको, एस कुमार, पृ.61।

****

वायु प्रदूषण एवं वाहनों से निष्कासित धुंआ

अंचल रामटेके *

शोध सारांश – वायु प्रदूषण वायुमण्डलीय हवा में बाह्य तत्वों का मिश्रण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन हैं। वायु प्रदूषण विभिन्न मानवीय गतिविधियों जैसे– जीवाष्म ईधन का जलना, कोयला और तेल का जलना, कारखानों एवं वाहनों के धुंए के कारण हो रहा है। विभिन्न हानिकारक गैसें जैसे– कार्बनडाई आक्साइड, सल्फर डाई आक्साइड, कार्बन मोनो आक्साइड, नाईट्रोजन आक्साइड आदि वायुमण्डल में मिश्रित हो रही है जो वायु प्रदूषण का स्तर बढा रही है। जिस हवा को प्राणी सॉस के द्धारा प्रति क्षण अन्दर ले रहा है वह पूरी तरह से प्रदूषित है तथा फेफडों एवं रक्त परिसंचरण द्धारा पूरे शरीर में फैल रहा है तथा विभिन्न बिमारियों का कारण बन रही है। जैसे–जैसे मानव प्रगति के पथ पर बढ रहा है विभिन्न बिमारियां उसके शरीर में घर बना रही हैं। यदि कानून एवं सामाजिक जागृति को अपनाया नहीं गया तथा पेडों को कटने से न बचाया गया तो यह समस्या बढती ही जायेगी।

शब्द कुंजी – वायु प्रदूषण

प्रस्तावना – ऑक्सीजन को प्राण वायु कहा जाता है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वर्तमान समय में बढते प्रदूषण के कारण शुद्ध वायु शब्द एक कल्पना बनता जा रहा है। एक मनुष्य दिन भर में 20 हजार बार सांस लेता है तथा वायु के बिना 5–6 मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकता है। बढते हुये औद्योगिकरण, यातायात साधनों का अधिक उपयोग वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कृछ ऐसे मानव कृत्य हैं जिन्होंने पर्यावरण में गैसों का संतुलन बिगाड दिया है। वायु प्रदूषण के कारण ओजोन परत को लगातार नुकसान पहूँच रहा है तथा ग्लोबल वार्मिंग भी इसी का परिणाम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वे के अनुसार 2014 में विश्व में 20 लाख लोगों की मृत्यु का करण वायु प्रदूषण रहा है। वर्तमान समय में यातायात के साधनों में लगातार वृद्धि हो रहा है तथा वाहनों का धुंआ वातावरण को तीव्रता से प्रदूषित कर रहा है।

शोध उद्देश्य – वायु प्रदूषण के लिये जिम्मेदार एवं विभिन्न वाहनों से निकलने वाली गैसों की मात्रा का अध्ययन व उनका शरीर व वातावरण पर प्रभाव ज्ञात करना।

शोध विधि – इस हेतु समाचार पत्र, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट से प्राप्त जानकारी एवं छात्रों को दिये गये प्रोजेक्ट वर्क के अंतर्गत प्राप्त वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र के आकडों को द्धितीयक स्त्रोत के रूप में प्रयोग किया गया है।

वाहनों से निष्काषित एवं वायु प्रदूषक मुख्य गैसें व उनका शरीर पर प्रभाव –

(1) कार्बन मोनो ऑक्साइड (CO) :– कार्बन मोनो ऑक्साइड रक्त की विभिन्न उत्तकों एवं अंगों जैसे एवं मस्तिष्क आदि में ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता को कम करता है। जब श्वसन में उज ली जाती है तो यह हीमोग्लोबीन के साथ मिलकर कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। एक बार हीमोग्लोबिन से जुडने के पश्चात् यह हीमोग्लोबील की उपलब्धता को कम कर देता है।

CoHb (कार्बोक्सीहीमोग्लोबीन) की सांद्रता से संबंधित लक्षण–क्र.

	सांद्रता	लक्षण
1	10% CoHb	कोई लक्षण नहीं
2	15% CoHb	हल्का सिरदर्द
3	25% CoHb	अरूचि एवं तेज सिरदर्द।
4	45% CoHb	बेहोशी
5	50% CoHb	मृत्यु

यह एक रंगहीन, गंधहीन विशैली गैस है। यह ईंधन जैसे प्राकृतिक गैसों, कोयला, आदि के दहन से उत्पन्न होती है, वाहनों द्धारा निष्कासित धुऑ वातावरण में Co की मात्रा के लिए जिम्मेदार है।

(2) Co_2 कार्बन डाई आर्वेसाइड – "Green House Gas" के रूप में इसकी मुख्य भूमिका है अत: इसे बुरे प्रदुषक के रूप में जाना जाता है। Co_2 वातावरण का मुख्य घटक तथा पौधो के लिए आवश्यक है। वनों के कटने, औद्योगिकीकरण तथा जीवाश्म ईधनों के दहन से वातावरण में इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। Co_2 से संबंधित क्षेत्रों में व्यक्तियों को सिरदर्द की समस्या हो रही है। Co_2 की मात्रा में वृद्धि के साथ जलवायु में परिवर्तन देखा जा रहा है।

(3) So_2 सल्फरडाई आर्वेसाइड – सल्फरडाई आर्वेसाइड एक रासायनिक यौगिक है जो कि विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों द्धारा उत्पन्न की जाती है। कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थो में प्राय: सल्फर के यौगिक उपस्थित होते है जिनके दहन से So_2 उत्पन्न होती है। So_2 का ऑक्सीकरण उत्प्रेरक जैसे No_2 की उपस्थिती में होता है तथा H_2So_4 उत्पन्न होती है, जिसका परिणाम है अम्लीय वर्षा। So_2 त्वचा तथा ऑख, नाक, गला व फेफड़ों की म्यूकस झिल्ली व श्वसन तंत्र में जलन उत्पन्न करती है। So_2 की उच्च सांद्रता फेफड़ों के कार्य को प्रभावित करती है।

(4) Nitrogen Oxide (No_2)– ईंधन के दहन के पश्चात् जब नाइट्रोजन मुक्त होती है तो वह O_2 से जुड़कर Nitric Oxide (No) बनाती है। यह पुन: O_2 से जुड़कर No_2 बनाता है। यह प्राकृतिक रूप से वातावरण में बिजली चमकने के दौरान भी उत्पन्न होती है। यह एक मुख्य प्रदुषक है क्योंकि इसके द्धारा Photo Chemical Smog का निर्माण होता है। यह श्वसन तंत्र में बाधा उत्पन्न करता है। यह फेफड़ों में संक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता कम करता है तथा फेफड़ों में सूजन पैदा करतीं है। इसके कारण

* सहायक प्राध्यापक (प्राणिशास्त्र) शासकीय स्नातक महाविद्यालय, नैनपुर, जिला मण्डला (म.प्र.) भारत

बुखार, खॉसना, छीकना, सर्दी आदि उत्पन्न होती है।

(5) Hydrogen Cynide (HC) – संश्लेखित रेशे तथा प्लास्टिक बनाने वाले कार्बनिक यौगिक के निर्माण में मुख्यत: इसका उपयोग किया जाता है। धातु की प्रोसेसिंग, औद्योगिक सफाई एजेंट, तथा Agriculture fumigant के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी कुछ मात्रा सिगरेट के धुएँ में भी पाई जाती है। HC शरीर में O_2 का परिवहन रोकता है तथा चेतना में कमी करता है। इसके कारण कमजोरी, सिरदर्द, अनिच्छा, उल्टी, जलन तथा आंखों में संक्रमण होता है।

(6)क्लोरो फ्लोरोकार्बन (CFC) – यह ओजोन पर्त के लिए अत्यंत घातक है। यह गैस मुख्य रूप से AC, फ्रिज, erosol, स्प्रे आदि से मुक्त की जाती है। यह ओजोन पर्त को लगातार नष्ट कर रहा है जो सूर्य से आने वाली पराबैगनी किरणों को पृथ्वी में आने से रोकती है। ओजोन पर्त के नष्ट होने से त्वचा का कैंसर तथा आंखों की बीमारियां बढ़ रही है।

(5) विभिन्न वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र से प्राप्त गैसों के ऑकड़े –
(Table) :-

1. Vehicle Type, 2 Wheeler

Fuel	Test gas	Prescribed standard	Measured Level
Petrol	CO	3.5%	1.97
	HC	4500PPM	0543
	Co_2	%	1.56%
	O_2	%	18.25%

2. Vehicle Type, 2 Wheeler

Fuel	Test gas	Prescribed standard	Measured Level
Petrol	CO	4.5%	1.96
	HC	9000PPM	1017
	Co_2	%	1.96
	O_2	%	16.34

3. Vehicle Type, 4 Wheeler

Fuel	Test gas	Prescribed standard	Measured Level
Petrol	CO	3.5%	2.88
	HC	4500PPM	0413
	Co_2	%	11.76
	O_2	%	2.92

4. Vehicle Type, 2 Wheeler

Fuel	Test gas	Prescribed standard	Measured Level
Petrol	CO	3.5%	0.32
	HC	4500PPM	0266
	Co_2	%	4.08
	O_2	%	15.23

5. Vehicle Type, 2 Wheeler

Fuel	Test gas	Prescribed standard	Measured Level
Petrol	CO	4.5%	1.19
	HC	9000PPM	0345
	Co_2	%	4.23
	O_2	%	14.36

6. Vehicle Type, 2 Wheeler

Fuel	Test gas	Prescribed standard	Measured Level
Petrol	CO	4.5%	1.19
	HC	9000PPM	0345
	Co_2	%	4.23
	O_2	%	14.36

7. Vehicle Type, 2 Wheeler

Fuel	Test gas	Prescribed standard	Measured Level
Petrol	CO	3.5%	0.49
	HC	4500PPM	0299
	Co_2	%	2.62
	O_2	%	16.57

8. Vehicle Type, 2 Wheeler

Fuel	Test gas	Prescribed standard	Measured Level
Petrol	CO	3.5%	1.07
	HC	4500PPM	0269
	Co_2	%	3.47
	O_2	%	16.26

9. Vehicle Type, 2 Wheeler

Fuel	Test gas	Prescribed standard	Measured Level
Petrol	CO	3.5%	1.14
	HC	4500PPM	0474
	Co_2	%	2.11
	O_2	%	17.04

10. Vehicle Type, 2 Wheeler

Fuel	Test gas	Prescribed standard	Measured Level
Petrol	CO	3.5%	0.68
	HC	4500PPM	0535
	Co_2	%	0.93
	O_2	%	18.73

11. Vehicle Type, 4 Wheeler

Fuel	Test gas	Prescribed standard	Measured Level
Petrol	CO	4.5%	2.29
	HC	9000PPM	0334
	Co_2	%	4.26
	O_2	%	12.62

वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के उपाय –

1. जहां संभव हो पैदल चले या बाइक का उपयोग करें।
2. कार या बाई शेयर करें।
3. सार्वजनिक यातायात के साधनों का प्रयोग करें।

4. Ride Sharing Services का उपयोग करें।
5. वहनों का प्रबंधन सही समय पर करें जैसे :– समय पर तेल बदलना, सर्विसिंग करना।
6. ऐसे वाहन जो अधिक धुआॅ उत्पन्न न करें जैसे :– बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, Hydrogen fuel cell, electric वाहन।

उपसंहार – स्वच्छ वायु जीवन का आधार है परन्तु आज मानव के विभिन्न क्रियाकलापों ने वायु को प्रदूषित कर दिया है। हवा की संरचना में परिवर्तन होने पर स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। वायु प्रदूषण के विभिन्न स्त्रोतों जिनमें औद्योगिक, घरेलू यातायात शामिल है पर यदि प्राथमिक स्तर पर ही रोक लगा दी जाए तो समस्या का निदान काफी सीमा तक संभव है। यातायात के लिए निजी के स्थान पर सार्वजनिक वाहन प्रणाली का उपयोग एवं पेट्रोल डीजल के स्थान पर सौर, जल, गैस (CNG, LPG) तथा विद्युत ऊर्जा से चलने वाले वाहनों का आविष्कार एवं उत्पादन करना आवश्यक है। सीसा रहित पेट्रोल के उपयोग को बढ़ावा दें। वायु प्रदूषण का नियंत्रण जनता की सहभागिता के बिना असंभव है अत: जनता को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का बोध कराना जरूरी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. समाचार पत्र,
2. इंटरनेट
Link :- EPA So_2- effect of Health, Sulfer effect on visibility, Air quality website.
3. वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र से प्राप्त आंकडे।

****

ई-अवशिष्ट एवं इसके दुष्प्रभाव

अनिता सिंह * रागिनी सिंह **

प्रस्तावना – आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी पुरानी मानव के आधुनिक मानव के रूप में विकास की कहानी।

मनुष्य प्रारंभ से ही जिज्ञासु प्रवृति का रहा है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिये जहाँ एक ओर उसने प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की है वहीं दूसरी ओर अपने ज्ञान और तार्किक क्षमता के बल पर विज्ञान को जन्म दिया है। यह विज्ञान का ही चमत्कार है कि मनुष्य बहुत से अबूझ और अनजान तथ्यों का रहस्य जान पाने में समर्थ हुआ है। साथ ही यह मनुष्य की प्रबल जिज्ञासु प्रवृति का परिणाम है कि वह आज प्रकृति की सत्ता को भी कड़ी चुनौती दे रहा है।

पुरातन युग से आधुनिक युग की इस विकास यात्रा में विज्ञान ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है और इसी क्रम में आधुनिक इलेक्ट्रानिक उपकरण अस्तित्व में आये। इन इलेक्ट्रानिक उपकरणों में हमारी दिन-प्रति-दिन की जिंदगी में काम आने वाले उपकरण यथा टेलीविजन, कम्प्यूटर, पंखे, फ्रिज, ए.सी., टेलीफोन, सेलफोन आदि हैं।

तेजी से बदलने वाली वैज्ञानिक तकनीक तथा नवधनाढ्यों द्वारा प्रतिदिन नयी-नयी वस्तुएँ खरीदने की होड़ में ये इलेक्ट्रानिक उपकरण शीघ्र ही प्रचलन के बाहर हो जाते हैं और बाजार में नयी तकनीक पर आधारित नये इलेक्ट्रानिक उपकरण इनको स्थानच्युत कर कबाड़ की श्रेणी में परिवर्तित कर देते हैं और यही कारण है ई-अवशिष्ट की अवधारणा के अस्तित्व में आने का।

ई-अवशिष्ट क्या है ? – ई-अवशिष्ट या इलेक्ट्रानिक-अवशिष्ट उन सभी इलेक्ट्रानिक उपकरणों को कहा गया है जो अपना सामान्य जीवन-काल पूर्ण करने के पश्चात् अपनी सम्पूर्ण कार्य-क्षमता के साथ कार्य करने में असमर्थ होने के कारण पुर्नचक्रण के योग्य हो गये हैं।

प्रचलन के बाहर हो गये टी.वी., टेलीफोन, सेलफोन, कम्प्यूटर, वी.सी.आर., सी.डी. प्लेयर, फैक्स मशीन, प्रिन्टर आदि सभी ई-अवशिष्ट की श्रेणी में आते हैं।

इलेक्ट्रानिक-अवशिष्ट में भारी मात्रा में हानिकारक पदार्थ पाये जाते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से कैडमियम, निकल, क्रोमियम, बेरीलियम, आर्सेनिक, मरकरी, जस्ता आदि के अतिरिक्त मूल्यवान धातु जैसे सोना, चाँदी भी हैं। ई-अवशिष्ट का विषैला पदार्थ मुख्यत: बैटरी, प्लास्टिक, सर्किट बोर्ड, लिक्विड क्रिस्टल डिस्पले आदि में पाया जाता है।

कुछ समय पूर्व तक कबाड़ी को दिये जाने वाले कबाड़ में कॉपी, किताब, अखबार आदि की रद्दी, लोहे का सामान, प्लास्टिक की बोतलें आदि था परंतु आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। आज कबाड़ के रूप में दी जाने वाली वस्तुओं में पुराने टी.वी., कम्प्यूटर, बैटरी, टेलीफोन आदि हैं। इनसे मूल्यवान पदार्थ प्राप्त करने के उद्देश्य से कबाड़ी द्वारा इन्हें असुरक्षित तरीके से नष्ट किया जाता है अथवा जलाया जाता है जिससे निकलने वाली विषैली गैसें मानवीय स्वास्थ्य तथा पर्यावरण दोनों को ही क्षति पहुँचाती है।

दुनिया भर में प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाले ई-अवशिष्ट ने खतरनाक रूप ले लिया है। इनमें मौजूद भारी धातुओं से फैलने वाला प्रदूषण मानवीय स्वास्थ्य समस्या तथा पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण बन रहा है।

ई-अवशिष्ट से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ लीवर तथा किडनी को तो प्रभावित करते ही हैं, कैंसर तथा लकवे जैसी बीमारी उत्पन्न करने का कारण भी बनते हैं। असुरक्षित तरीके से खुले में जलाये जाने पर इनसे उत्पन्न होने वाली गैसें पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं।

ई-अवशिष्ट से निकलने वाली गैसें तथा जहरीले पदार्थ मिट्टी और पानी में मिलकर उन्हें बंजर तथा विषाक्त बना देते हैं। इस परिस्थिति में उत्पन्न होने वाली फसलों पर भी इनका दुष्प्रभाव पड़ता है। ये फसलें जब मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण की जाती हैं तो उसे अस्वस्थ करने का कारण बनती हैं।

ओजोन परत को क्षति पहुंचाने में फ्रिज आदि से उत्पन्न क्लोरो-कार्बन की महति भूमिका है।

ई-अवशिष्ट में पाये जाने वाले कुछ विषैले पदार्थ –

लेड – विश्व के पर्यावरणविदों के अनुसार सोलर ट्रांजिस्टर, सर्किट बोर्ड, एल.ई.डी. आदि में पाया जाने वाला लेड मस्तिष्क, किडनी, प्रजनन-तंत्र तथा तंत्रिका-तंत्र के लिये अत्यंत हानिकारक है। लेड की पर्यावरण में उपस्थिति पानी तथा मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।

मरकरी – टी.वी, रेफ्रिजरेटर, सी.एफ.एल. आदि में मरकरी की सूक्ष्म मात्रा मौजूद रहती है। जब इसे लेण्डफिल या पानी पर फेका जाता है तो यह जैविक पदार्थों के साथ मिलकर अत्यंत विषाक्त पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। मरकरी मनुष्य के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण दोनों पर ही प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

केडमियम – केडमियम मनुष्य के सम्पर्क में आने पर कैंसर पैदा करने का कारण बनता है। केडमियम युक्त इलेक्ट्रानिक-वेस्ट को जलाये जाने पर उत्पन्न गैस के प्रभाव से फेफड़ों की कार्य-क्षमता समाप्त होने की संभावना रहती है। भूमि के सम्पर्क में आने पर यह मिट्टी की गुणवत्ता में कमी लाता है।

बेरीलियम – बेरीलियम स्विच-बोर्ड तथा प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड में पाया जाता है। यह कैंसर कारक है तथा श्वसन के माध्यम से शरीर में प्रविष्ट होकर

* सहायक प्राध्यापक (गणित) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (भौतिकी) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

फेफड़े संबंधी विकार उत्पन्न करता है।

आर्सेनिक – यह कई इलेक्ट्रानिक उपकरणों की मायक्रो–चिप में पाया जाता है तथा कैंसर कारक है।

क्रोमियम – क्रोमियम–6 श्वसन द्धारा शरीर में प्रविष्ट होने पर लीवर तथा किड़नी को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही अस्थमा की समस्या भी उत्पन्न कर सकता है।

विगत् कुछ वर्षो से ई–अवशिष्ट मानवीय स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिये कड़ी चुनौती बन कर उभरा है। इसके बढ़ते हुए खतरों से हमारी भावी पीढ़ी को बचाने के लिये जन–जागरण अति आवश्यक है। असुरक्षित तथा अवैज्ञानिक तरीकों से इनको नष्ट करने की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिये कड़े कदम उठाये जाने चाहिये तथा इन्हें सुरक्षित तरीकों से नष्ट करने हेतु वैज्ञानिक विधियों तथा सुरक्षित तकनीकों को सुनिश्चित किया जाना चाहिये। इसके साथ–साथ सरकारी स्तर पर भी ई–अवशिष्ट को सुरक्षित रूप से समाप्त करने हेतु कठोर कानून बनाना एवं उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. ई–कचरा – स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का खतरा (E-waste - The threat to health and environment, hindi.indiawater portal.org/node) – डॉ. विनोद गुप्ता।
2. इलेक्ट्रानिक कचरा (ई–वेस्ट) (Electronic waste, hindi. indiawaterportal.org/node) – दीप्ति सिंह
3. ई–अवशिष्ट का कायदे से हो प्रबंधन – एम.एच. फुलेकर, भावना पाठक।

****

Health Status Of Girl Child Labourers In Relation To Their Family Environment

Dr. Nasreen Gazdar* Prof. Usha Kothari**

Introduction - Children grow progressively and become visible as they move towards adulthood. If they are burdened in their childhood and deprived of basic necessities, their physical and mental growth is influenced. Children are universally recognized as the most important asset of any nation. Everyone has the right to an environment favourable to his physical, mental, emotional and intellectual growth and development. The functions of work in childhood ought to be psycho social development and not just economic, children's work as social good is directly opposite to child labour as a social evil (by fuller 1962).

India, the largest democracy in the world also has the highest child labour population in the world. These are children, between 6-14 years, belonging to the most deprived sections of the society and are engaged in labour when actually they should be studying and playing. Majority of them are girls. In the recent supreme court judgment on abolishing child labour it was observed that "none of the official estimates include child labour in the unorganised sector and therefore, are obviously gross under estimates. Estimates from various non-governmental sources as to the actual number of working children range from 44 million to 100 million."

Children, more so girl children, are especially rendered vulnerable by the norms and practices of the society at large. Consider, too, social inequality and discrimination, which are important, but are often overlooked, causes of child labour. Asian society is generally stratified on the basis of class, caste, community, ethnicity and gender. These social divisions have various facets that contribute to the perpetuation of child labour. (Kairta Ratna, 1995).

Poverty has an obvious relationship with child labour and studies have "revealed a positive correlation in some instances a strong one between girl child labour and such factors as poverty" (Mehra 1996). The greater the poverty, the more aggravated is the situation of the girl child. Denied education, nutrition and health care in many ways further restrict her growth and development. In certain communities, the rules of permission and restriction on women are much more stringent thus allowing for their greater exploitation and discrimination.

The injustice against girls or gender discrimination has become an acute problem in India. It was only in year (1990), the SAARC (South Asian Association for Regional Co-operation) provided an opportunity to the countries in the region to focus their attention on the girl child. In India, girl child is undesired, uncared for, neglected and treated as an inferior being. She is compelled to accept a second class status in the traditional male dominated socio-economic religious setup.

Girls constitute 50 percent of the child labour force in India who are mostly deprived of fair wages and are exploited by the employers. Their employment do not create any skill formation. Compared to male children, the girl children are more exploited in the payment of wages and appreciation of work. What is more horrible is that "the cruel methods adopted to kill the child in the womb if she is a girl is a sad reflection on the womb-to tomb syndrome."

The problem of child labour is so enormous and the need for action is urgent, choices must be made about where to concentrate available human and material resources. The most humane strategy must therefore be to focus scare resources first on the most intolerable forms of child. Labour such as slavery, debt bondage, child prostitution, work in hazardous occupations and industries, and the very young, especially girls. Most studies however delimit their analysis to the victims of child labour without mentioning the girl child labour as separate entity, child labour among girls is much bigger problem than child labour alone.

Girl child labour harms not only the present generation but also the posteriori. If one conceives the idea of a girl child labour it brings before the eyes the picture of exploitation of little, physically tender, illiterate, under occupation and unhealthy conditions. The problem of girl child labour is such that it can hardly be legislated away as its roots lie in object poverty and backwardness of the society.

Objectives -

1. To find out and compare the level of health status among the different categories of girl child laboure (a) Rag pickers (b) Domestic Servants (c) Factory workers.

*Asst. Professor (Home Science) Shri Mahalaxmi Girls College, Pratap Nagar, Jodhpur (Raj.) INDIA
**Professor & Head (Home Science) Jai Narain Vyas University, Jodhpur (Raj.) INDIA

2. To find out and compare the pattern of family environment among the different categories of child laborers. (a) Rag pickers (b) Domestic Servants (c) Factory workers.

Hypothesis -

1. Level of health status will be lower among rag pickers and factory workers as compared to domestic servants.
2. Positive environment i.e. concerned, committed, helpful, supportive, open expression, organized and competitive environment will lead to better health status

Methodology - A incidental purposive sample of 300 girl child labour, aged 8-14 years of studied, within the municipal limits of Jodhpur City, Rajasthan. Out of these 300 girl child labourers were rag pickers, 100 were factory workers and 100 were domestic servants.

Tools - To investigate the, health status and family environment, these scales and standards were used

(a) Family Environment Scale (FES) of MOOS adapted by Joshi and Vyas (1996) was used.
(b) Health Status was measured according to standards of ICMR (1990) and NCHS, WHO Geneva (1983). The dimension of the health status were -

Weight for Age -

- Gomez et. al (1956)
- Indian Academy of Paediatrics (1972)

Height for Age

- Vishwaswara Rao's (19)
- Waterlow's (1972)

Weight for Height

- Waterlow's (1972)

Procedure - After the selection of the girl child labourers localities, the family environment scale, was administered on the selected sample, anthropometry measurement were taken individually and in small groups to find out the health status.

Analysis of Data - The overall analysis of percentage was attempted from data obtained from all the samples. The samples were analyzed into distinguishable categories in each area and then factor wise mean scores were tested for the significance difference by 't' test at 0.05 and 0.01 level of significance and product moment correlations.

Result -

Health Status - (Graph see in the last page)

In this present investigation, according to Weight for Age more rag pickers 33% were malnourished as compared to 30% domestic servants and 29% of factory workers.

Comparatively the lowest percentage of normal degree (23.33%) was found in rag pickers where as factory workers and domestic servants have same percentage i.e. 25.33% on normal degree under Height for Age.

Same data when compared according to Weight for Height. 24% of the rag pickers were malnourished as compared to 15% of factory workers and 13% of domestic servants. Maximum percentage of domestic servants displayed normal health status.

Overall it was observed that the Health Status of Rag pickers suffer poorer health because they are more exposed to unhealthy surroundings, poverty, lack of food and lack of values attached to girl child. Generally these rag pickers spend most of their time on streets.

Thus the hypothesis on Health Status is accepted as the level of Health status is lower among the rag pickers and factory workers as compared to domestic servants.

Girls child labourers on Family Environment Scale (Table see in the last page)

Overall data in above table reveals the percentage of girls on family environment scale. It can be concluded that in the present sample rag pickers are below average on cohesion. On control subscale whereas conflict subscale, factory workers are below average. But on achievement orientation both factory workers and rag pickers are below average.

So it can be concluded that the family member of domestic servants are concerned and committed to the family. They are supportive and helpful to each other. On the other hand family members of rag pickers are least bothered about the members in the family and even they do not know where about of their children.

Rag pickers feels more frustrated in the home and spend more time involving herself in busy task. As the girl do not want to go home and works all the day there is no competitive framework in the family and they are unaware of new activities going around them. The head of the family is the eldest male. Whenever they are at home, they have to follow rules and regulation of the head of the family. In such circumstances the head of the family controls the family. There is lot of conflict in the family of factory workers causing tension at home which makes them frustrated.

Achievement orientation is below average in rag pickers and factory workers. They are having fewer skills for competitive framework because of lack of exposure. As they belong to extremely poor family. They are not anxious to be independent and self-reliant which is necessary for the development of need on achievement. They are worried about their everyday living.

The hypothesis is accepted as positive environment i.e. concerned, committed, helpful, supportive, open expression, organized and competitive environment will leads to better health status and less behaviour problems.

Recommendation- We shall join hands to promote and ensure a child friendly environment a new system and to welcome a **NEW DAWN** where:-

All the girls up to 18 years of age shall be in schools where relevant and quality education is ensured.

- The health status of the girls improved, Infant mortality rate reduced, early child birth and related problem controlled.
- Parents are educated and became responsive for better child care.
- Girl child labour is made practically impossible as all the girls join schools and not available for work.
- Exploitation and discrimination of girls resisted.

- Illiteracy is eradicated.

Media can be used very effectively in this regard. E.g. radio/television etc. apart from the schools can serve as the best place for educating parents about how to treat and care for their children. For those parents and people who do not send their children to schools once again media can serve as an important tool for educating them through different programs.

We should realize that all children are our children and children are born to be loved. What we need are strong laws so that the real offenders are punished. Only then, the abuse of children will stop.

References :-

1. Agarwal R. (1987) A Situational analysis of girl ragpickers (Dissertation), department of child development, Lady Irwin College, University of Delhi.
2. Assessment of Nutritional Status, Department of Human Nutrition London School of Hygine and Tropical Medicine, Keppel Street, London (1985).
3. Bagchi, Jasodhara and Guha Java, (1997). Loved & Unloved : The girl child in the family. Calcutta, stree . 212 p.
4. Bamji. Rao, Reddy (1998), Textbook of Human Nutrition Published by Mohan Primlani for Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., 66 Janpath, New Delhi.
5. Behind Closed Doors: Child domestic labour. ILO-IPEC International Labour office. Geneva (2004).
6. Bhima Sangha(2004), “Girl At Work : Situation in Asia” in Asian Regional Meeting on the Worst forms of Child Labour Phuket, Thailand: ILO
7. Gomez, F, Ramos, GR, Frenk, S, Cravioto, J, Chavez, R, Vazquez, J (1956) Mortality in second and third degree malnutrition, J. Trop, Pediatr 2:77-83.
8. Child Labour forms (1997), The State of World’s Children SACCS - UNICEF Report .
9. Efforts against child labour often overlook domestic workers (June 11, 2004). UNICEF Press release.
10. FAO on Child Domestic Labour (2004) - ILO London.
11. Caroline Hunt (October 1996); Child waste pickers in India; the occupation and its health risks. Environment and Urbanization, vol 8, No. 2.

Health Status

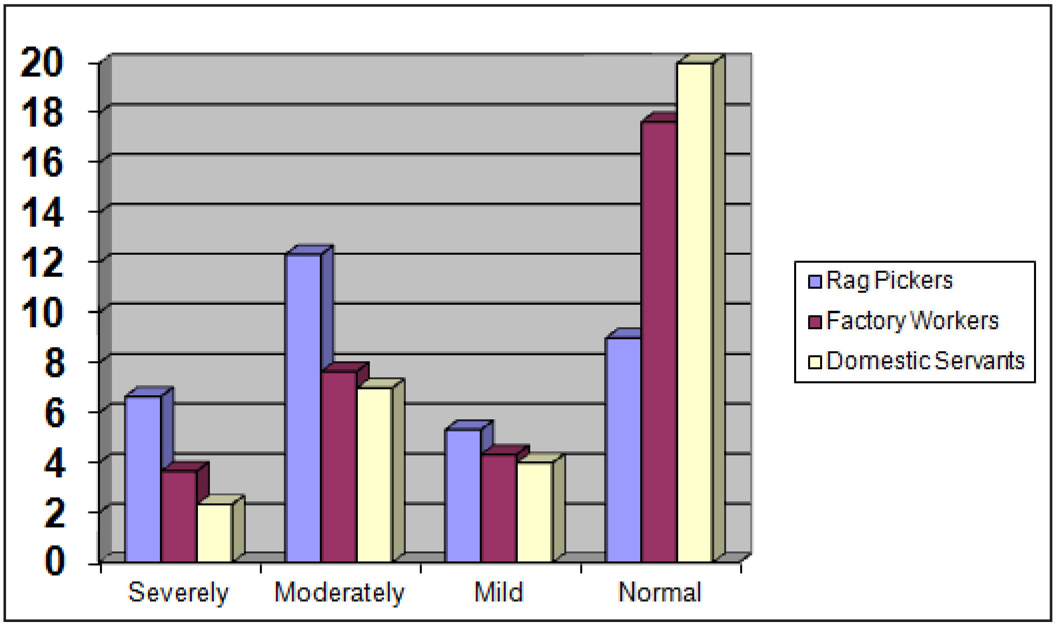

Girls child labourers on Family Environment Scale

Groups	Subscales	Below Average	Average	Above Average
Domestic Servants	Cohesion	6.0%	40.0%	54.0%
	Conflict	13.0%	32.0%	55.0%
	Achievement Orientation	13.0%	30.0%	57.0%
	Control	5.0%	36.0%	59.0%
Rag Pickers	Cohesion	64.0%	22.0%	14.0%
	Conflict	29.0%	50.0%	21.0%
	Achievement Orientation	41.0%	21.0%	38.0%
	Control	56.0%	37.0%	7.0%
Factory Workers	Cohesion	21.0%	54.0%	25.0%
	Conflict	52.0%	45.0%	3.0%
	Achievement Orientation	45.0%	42.0%	13.0%
	Control	22.0%	56.0%	22.0%

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

Water - The Prime Resource

Mamta Goyal*

Introduction - Of all the resource of the earth, water is the most fundamental to human life. Water is the unique essential for all forms of life-vegetative animal and human life. It is utilized in various ways e.g. for agriculture, industry, transport and energy as well as for domestic uses like drinking. Cooking, washing etc.

Water is found in abundance on the earth. Nearly 71 per cent of earth's surface in covered by water. Out of this water nearly 97 per cent of water is found in oceans and seas. It is saline and not suitable for human life consumption. 2 per cent of this resource is in the solid from of ice and in locked in the ice caps and the glaciers. It is also inaccessible to man. Nearly 0.0001 per cent ins found is gaseous form in the atmosphere. Remaining only 1 per cent of water is found in the form of fresh water which is useful to mankind.

Necessity of water Conservation - Water of usable quantity and quality, present in the right place as the right time, is exhaustible. No doubt, it is renewable resource but one of which the demand is for greater than the supply in many areas of the world, water shortages are becoming grave global phenomenon. It is a major problem in most of Africa, west Asia, most of south Asia, a large part of the western U.S.A. North-west Mexico, Some regions of South America and nearly all of Australia. Most of our planet is drying.

1. Increase in Population and More Consumption of Water Per Head - With ever-growing population of roughly 85 million additional people per year, the demand for the fresh water is increasing.

Ten years now, India will have an extra 250 million people. Regions with scarce water have the highest rates of growth of population. Population grow and water demands increase. Global consumption of water is doubling every 20 years, more than twice the rate of human population growth. Moreover, the distribution of population is very uneven. The country sides are losing their people while cities are becoming over-crowded. Coastal plain of southern California provides an example of unbalanced distribution of population. In an area one eighth the size of California lives more half the population of the state. The cities like Los Angeles face acute shortage of fresh water and have to bring it from distant highland areas. Apart for drinking, bathing, cooking, urban centers also require large amound of water for the disposal of wastes, e.g. in most of the urban areas cisterns require about 12.5 liters of water per flushing.

Irrigation and its Faulty Methods - In order to feed large number of people, large areas has been brought under cultivation. In areas receiving less rainfall , supply of water is made through water obtained from rivers, canals, tanks or wells. Lrrigation consumes about 60 to 70 percent of all water used by humans. Most of the rivers are dammed to create reservoirs that are able to provide water for irrigation. After few years , due to silting, the capacity of reservoirs to store water reduces considerably. If the canals are not lined, some water is lost due to seepage. Many of the farmers do not know how much water is needed to the farm. They just over water it and much of irrigation water is lost through evaporation. In many countries the nitrates, pesticides and insecticides are used in the farms. The residues of these chemicals find their outlet in river water or ground water and water gets polluted and useless for drinking. It leads to depletion of fresh water reserves.

Large scale Use of fresh Water in Industries and Water pollution - This is a major cause of diminishing supplies of fresh water. Industrial use of water is predicted to double by 2025 if current growth trends continue. Apart from using fresh water on large scale in manufacturing sector, industries produce large amount of water In the U.S. alone, the computer manufacturing industry will soon be using over 1500 billion liters of water producing over 300 billion liters of waste water each year. The waste water comprising toxic substances, ranging from metallic salts to organic chemicals and physical pollutant of thermal and radioactive substances and dumped in rivers, Lakes, streams or enter in ground water. Nearly 70 percent of river water is polluted and not suitable for human being. For example, nearly 60 percent of river water in Maharashtra is highly polluted and not suitable for drinking the problem of water pollution is more serious in developing countries of the world.

Increasing numbers of people are moving to cities, where dense population place terrible strains on limited water supplies with their sanitation services. The sewage water finds outlet in nearby –rivers or lakes and make fresh water unsuitable for human consumption.

*Asst. Professor (Home Science) Govt. Girls College, Khargone (M.P.) INDIA

Evaporation take place over the surfaces of reservoirs, rivers and canals, thus large amount of fresh water is lost in the atmosphere deprecating of vegetation cover in catchment areas is also responsible for depletion of fresh water as the rain drops are not absorbed near the surface, they find their outlet and join Rivera. The floods are severe in many areas of the word where large scale destruction of forest cover has taken place. The water joins the oceans to become salty, not useful for humans

The above mentioned factors throw light on the following truth -

I. The entire human race is facing the problem of acute shortage of water.
II. The supply of fresh water will create grave problem in the future where world population is increasing very rapidly as compared with the supplies of fresh water.
III. Man is pollution fresh water on a large scale, thus making large part of fresh water unsuitable for consumption

The following facts throw light on the gravity of scarcity of water: In many developing countries, less than 20 percent of the population has access to clean drinking water. In India over 60 percent of families do not get water through pipes. Only 29 percent of the families and 65 percent of urban areas get water at home. In 1990,243 million urban and 988 million rural people were without access to potable water. This number has increased by 2.1 billion people (813 million in cities and 1.3 billion in countryside) in 2000

we are unable to interfere in the hydrological cycle. We are unable to increase the amount of precipitation. So, water conservation is the most effective and environmentally sound way to reduce our demand of water, e.g. the city of Los Angeles has grown by one million since 1970 but still uses the same amount of water

What is Conservation of water? - Water conservation refers to reducing usa of fresh water, through technological or social method. The goals of water conservation efforts include:

1. **Sustainability -** To ensure available of water for future generation. The withdrawal of fresh water form an ecosystem should not exceed its natural replacement rate.
2. **Energy Conservation -** Water pumping, delivery and waste water treatment facilities a significant amount of energy . Over 15 percent of total electricity consumption is devoted to water management , hence it is necessary to conserve the energy.
3. **Habitat conservation -** Minimizing human water use helps to presser fresh water habitats, reduces the need to build new dams and other water diversion infrastructure.

Thus more efficient use of water is an obvious response to supply shortages, this may achieved by reducing losses in the delivery and application of water or by limiting the growth of demand.

Let us study the various method of conservation of this precious resource.

1. **Conservation of water used in the Industries -** The industrial wastes, the residues of the manufacturing processes are dumped in rivers and lakes. The waste waters contain highly toxic chemicals which can render large streams or river unfit for any further use. The development of unclear energy as a new power source brought a new source of pollution radioactive contamination of water and is far more dangerous and lasting than any type of pollutant. Ground water reserves also get polluted by industrial chemicals, e . g. molasses from the sugar mills .

Thus, the industries have to devise recalculating systems whereby the waste water is processed, the chemicals reclaimed for further use and the water rendered pure enough for reuse. Such systems are very expensive, but once they are installed, cut down on the fresh water requirement and make it possible to operate where water supplies are limited. Some paper mills have devised this method of water recalculating. In most of the Industries water is used for culling purposes. By using the recycled water over and over again, fresh can be conserved.

The effluent should be treated before disposing them. This measure have achieved

Significant successes in some rivers and lakes which have been badly affected by in

Industrial discharges. Water quality in the river Rhine has improved sharply as a result of any international clean-up programme.

2. **Conservation of Water use in Agriculture-Irrigation -** A large amount of fresh water is utilized for irrigation farms. Which some of used for small farms. Increasing amount of water used for commercial farming, which overuses and wastes water? e.g. sugarcanes cultivation in India requires large water supply. Much of irrigation water comes from open canals, water runs freely in the fields and there is large loss of water form evaporation. Thus, water should be planned in such a way to give each plant no more or more or less then its own needs for best growth and so that there is only an unavoidable minimum loss by evaporation. Seepage losses from canals can be minimized by lining them. Conservative practices like sprinklers are necessary as Then check the water losses through seepage and rate of evaporation form soil is controlled. Drip or trickle irrigation is the most important

Method of irrigation, especially in areas that receive scanty rainfall. It supplies water to the roots of the plants through underground pipes. It is charactunately, the more efficient methods of irrigation are very costly and hence they are more common in developed than the developing countries,

Multi- purpose dams besides controlling the floods provide water for power irrigation and other uses. As reported by the world commission on dams, by 2000,there were more than 48000 large dams (over 15 m high) in the world. The most elaborate series of dams are built in the

u.s. along the Tennessee river, the dams constructed at several place have converted much of river into a chain of fresh-water lakes. Such dams control

Floods the excess amount of water, instead of going the oceans of storted in the reservoirs to use it for irrigation.

3. Rain water harvesting - for the last thousands of years, a technique of rain water harvesting is practiced in many countries of the word. In the method, sufficient amount of water is collected by creating a small pond in the soil surface. The water thus following down-hill over a fairly impermeable hill-side collects into pond or small reservoirs by building small ditches or rook walls sloping gradually across the hill-side contours. Clearing, rocks or compacting hill-side soils in various ways increases the amount of overland flow and the amount of rainwater is harvested by the hill-side ditches.

4. Water Recycling - Recycling of cooling and process water have become common in most developed countries of the world. | Tokyo has established a water recycling Centre which takes waste water form sewage treatment facilities, chlorinates it and pumps it to multi –storeyed buildings for use in flushing toilets. Israel is a desert country. She has made recycling an important part of her national water policy. In 2000, the country used 80 percent of her waste water. Thus, this policy saves fresh water which can be used for better purposes.

5. Conservation of water Through flood Control - During floods, excess amount of water ultimately joins the oceans and this precious fresh water is lost is become saline. In order to prevent the floods, upland areas near the sources of the rivers and watersheds should have vegetation cover. By planting trees and protecting grass cover in upland areas, control of floods is possible The water drops obstructed by the vegetation cover come down to the earth slowly to enter in the soil. Thus, water is absorbed in the soil due to infiltration and water loss in the run –off is less. Over grazing in such areas should be allowed otherwise land will remain unprotected and rainwater will flow down the slope unchecked instead of entering in the soil. Thus the best natural managers of water are the trees. The sponge organic soils of well managed forest land are a tremendous reservoir for water is the trees. The bulk of moisture percolates through it before it has a chance to run –off and starts damaging floods. Trees themselves drink in gallons of water, to release it slowly to the atmosphere as a water vapor where it may again collect in clouds for future rains. Removing this soil‘s natural blanket of vegetation, particularly on sloping land, gives rise to gullies through which rainwater runs unchecked.

6. Contribution of Individuals in Water Conservation-

(I) For individuals, there are many effective ways to conserve water in and around the home -

a. Water your lawn it needs it.
b. Fix leaky faucets and plumbing joints. It saves 20 gallons of water per day for every leaks stopped
c. Don‘t run the house while washing your car, use a bucket of water. Save 150 gallons of water each time.
d. Install water-saving shower heads.
e. Run only full loads in washing machine and dish water.
f. Turn off the water tap while brushing teeth.
g. Turn of ht water tap while shaving.
h. It you wash dishes by hand, don‘t leave the water running for rinsing.
i. Don‘t defrost frozen foods with running water.

(II) Outside the home

a. Put a layer of mulch around the trees and plants to slow down evaporation.
b. Water your plants during a cool part of the day.
c. Don‘t water the lawn on windy days. There is too much evaporation.
d. Direct the water drain line of air conditioner to a flower bed or a tree.
e. Harvest rainwater.
f. Divert water used in the bathroom and in kitchen to the garden.

If people follow these method of conservation of water, then the day is not very far when all people will have adequate water for their consumption.

References :-

1. Agrawal Pushpendra (2007), Hydrology and water Resources of India.
2. Aasit K.Vishwas (2009) Water Resource of Indian subcontinent.
3. Garg, Vikash (2006) Development of water resources in India.
4. Zimmer, D. & Renaull, D. (2003) Virtual water in food production and global trade.

****

समायोजन से जूझती वेतनभोगी महिलाएँ

डॉ. गीताली सेनगुप्ता*

प्रस्तावना – इतिहास साक्षी है वैदिक काल से लेकर वर्तमान स्थिति तक नारी के जीवन में विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव आये है, परिणाम स्वरूप हमारे जीवन मूल्य एवं प्रतिमान भी तीव्रता से बदलते जा रहे है। वर्तमान में भारतीय नारियाँ अपने अधिकार और कर्त्तव्य निर्धारण के प्रति अधिक सजग हो गई है। आज भारतीय स्त्रियों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। भारत में एक स्त्री का सुख जो आभूषणों, वस्त्रों तथा अन्य भौतिक साधनो पर निर्भर था वह आज एक नई प्रतिस्पर्धा की दौड़ में आलोकित होने लगा है।

यह सच है कि प्रत्येक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन एवं नवाचार समाज के आदर्शों एवं मान्यताओं में क्रांतिकारी परिवर्तन ला देता है। औद्योगीकरण, नगरीकरण तथा आधुनिककरण ने परम्परागत जीवन को उखाड़ने की चेष्टा की है तथा आधुनिक 'मूल्यों' के कारण स्त्रियों की जीवन प्रणाली में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। इस परिवर्तन का नारी जीवन पर सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है।

प्रस्तुत अध्ययन में वेतनभोगी महिलाओं के पारिवारिक समायोजन के संदर्भ में अध्ययन कर तथ्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। समायोजन सुखी पारिवारिक जीवन का मूल आधार है। सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में मनुष्य को कई प्रकार के समायोजन करने पड़ते है। पारिवारिक समायोजन से तात्पर्य परिवार के सदस्यों के पारस्परिक संबंध की उस स्थिति से है जिनमें उनके अन्त: क्रियात्मक व्यवहार के लक्षणों तथा दृष्टिकोणों में अनुकूलता अपने कलहो को सुलझाने की प्रवृत्ति के साथ-साथ एक-दूसरे के प्रति सामंजस्य रखने की भावना, पारस्परिक प्रत्याषाओं की पूर्ति तथा स्वयं व दूसरे से प्रसन्नता व संतुष्टि प्राप्त करने की भावना निहित है। इस प्रकार पारिवारिक परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालना ही पारिवारिक समायोजन है।

प्रस्तुत अध्ययन में वेतनभोगी महिलाएॅं जो विभिन्न कार्यक्षत्रों से जुड़ी हुई है। यहॉं उनकी व्यावसायिक स्थिति एवं पारिवारिक समायोजन का आपस में क्या सह-सम्बन्ध है इस तथ्य का पता लगाना है। यहॉं यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि वेतनभोगी महिलाओं से क्या तात्पर्य है।

'वर्तमान में सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाओं में पूरे समय काम करते हुए नियमानुसार वेतन प्राप्त करने वाली महिला, वेतनभोगी महिला है।'

समकालीन संदर्भ में, समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक संरचना के साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के अन्तर्गत महिलाओं की प्रस्थिति और भूमिका में विविध परिवर्तन परिलक्षित होते है। सामाजिक संरचना में व्यवसाय संलग्न महिलाओं के साथ यथोचित सांमजस्य का है, जिसके अभाव में पारिवारिक सामाजिक तथा वैयक्तिक स्तर पर त्रिकोणात्मक असंतुलन एवं विसंगतियॉं उभर रही है।

उद्देश्य-

- आधुनिक समाज में जो भूमिका विभेदीकरण हो रहा है उसमें भारतीय स्त्रियों नई-नई भूमिकाऍं ग्रहण कर रही है।
- भारतीय नारी के दृष्टिकोण एवं विचार आधुनिक हो रहे है।
- व्यवसाय संलग्न बहुसंख्यक महिलाऍं व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य भूमिकाओं को वहन करने में कठिनाई का अनुभव करती है।

प्राकल्पना – वेतनभोगी महिलाओं को व्यवसाय एवं पारिवारिक समायोजन की दोहरी भूमिका निभाने में द्वंद का सामना करना पड़ता है।

समग्र एवं निर्देशन – अध्ययन हेतु खण्डवा शहर की 250 वेतनभोगी महिलाओं को सप्रयोजन व स्तरीत निदर्शन के आधार पर चुनाव किया गया है।

अध्ययन पद्धति – वेतनभोगी महिलाओं की दोहरी भूमिका अर्थात व्यवसाय एवं पारिवारिक समायोजन के मध्य संबंध के विश्लेषण के लिए समाज वैज्ञानिक अनुसंधान की मानक विधियों जैसे – साक्षात्कार अनुसूची, असहभागी अवलोकन प्रणाली तथा साक्षात्कार तथा विधि का प्रयोग किया गया।

तथ्यों का प्रस्तुतीकरण – प्रस्तुत अध्ययन आधुनिक अन्वेषणात्मक एवं विष्लेषणात्मक है।

सारणीयन – विभिन्न वर्गो के तथ्यों को पंक्तियों एवं समस्त स्तम्भों में व्यवस्थित किया गया है। इस प्रकार सारणी की आवृत्तियों के आवंटन में सामग्री को व्यवस्थित रूप प्रदान किया जाता है – व्यावसायिक स्थिति एवं पारिवारिक समायोजन का आपस में सह-संबंध है दोनों ही स्थितियॉं एक-दूसरे को प्रभावित करती है। यह निम्न तालिकाओं के माध्यम से स्पष्ट परिलक्षित होती है।

तालिका क्रमांक – 1
उत्तरदात्रियों की परिवार में स्थिति

क्र.	स्थितियॉं	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	मुखिया की	25	10
2.	जीविकोपार्जन करने वाले विशिष्ट सदस्य की	40	16
3.	अधीनस्थ अथवा आश्रित को	178	71.2
4.	कोई विशेष नहीं	7	2.8
	योग	250	100

X^2 = 101.23 (स्वतंत्र कोटि = 3 , मान 7.815) परिणाम सार्थक

* प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष (गृहविज्ञान) माखन लाल चतुर्वेदी शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.) भारत

कभी –कभी प्रस्थिति, संघर्षशील स्थिति को भी उत्पन्न करने में सहायक हो जाती है। पारिवारिक जीवन में प्रस्थिति संघर्ष की स्थिति असमायोजन तथा असंतुलन के लिए उत्तरदायी है।

तालिका क्रमांक – 2

परिवार की गतिविधियो में तटस्थ दर्शक की भूमिका

क्र.	प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	55	22
2.	नहीं	195	78
	योग	250	100

यह उल्लेखनीय है कि भूमिका का न निभाना पारिवारिक जीवन में भूमिका द्वन्द्व की स्थिति उत्पन्न करता है और ऐसी अन्तर्द्वन्द्वात्मक दशा परिवार को असंमजन की ओर ले जाती है जबकि सफल भूमिका निर्वाह सामाजिक पारिवारिक समायोजन का एक शक्तिशाली तथ्य है।

तालिका क्रमांक – 3

स्त्रियों का घर से बाहर नौकरी करना उनके परिवार के सदस्यों को कैसा लगता है

क्र.	प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अच्छा	218	87.2
2.	बुरा	3	1.2
3.	कुछ विशेष नहीं	29	11.6
	योग	250	100

X^2 = 331.5 (स्वतंत्र कोटि = 2 , 5 पर मान 5.991) परिणाम सार्थक अधिकांश वेतनभोगी महिलाओं का सकारात्मक पक्ष यह सिद्ध करता है कि स्त्रियों का घर से बाहर नौकरी करना पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा है और आनंददायक। यह स्थिति समायोजन तथा पारिवारिक संतुलन का संकेतक है।

तालिका क्रमांक – 4

नौकरी के प्रति परिवार के सदस्यों का दृष्टिकोण

क्र.	प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	सहयोगात्मक	129	51.6
2.	रूखा	04	1.6
3.	तटस्थ	117	46.8
	योग	250	100

X^2 = 114.2 (स्वतंत्र कोटि = 2 , 5% मान 5.991) परिणाम सार्थक X^2 के मान से भी इस कथन की यर्थाथता प्रमाणित सिद्ध होती है।

तालिका क्रमांक – 5

नौकरी को लेकर परिवार में समस्या या विवाद

क्र.	प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हॉ	17	6.8
2.	नहीं	233	93.2
	योग	250	100

अधिकांश उत्तरदात्रियों का रूख नकारात्मक व 6.8 प्रतिशत ने सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रकट की।

तालिका क्रमांक – 6

नौकरी को लेकर परिवार में समस्या या विवाद

क्र.	कारण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	नौकरी एवं परिवार के दायित्वों में तालमेल के अभाव के कारण	3	17.64
2.	सदस्यों की उपेक्षित स्थिति के कारण	9	52.94
3.	गृहस्थी के बोझ के कारण	5	29.42
	योग	17	100

X^2 = 3.29 (स्वतंत्र कोटि = 2 पर 5% पर मान 5.991) परिणाम – सार्थक नहीं

तालिका क्रमांक – 7

नौकरी के कारण पारिवारिक जीवन प्रभावित होने पर नौकरी छोड़ने का पक्ष

क्र.	प्रतिक्रिया	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	125	50
2.	नहीं	125	50
	योग	250	100

इस प्रयुत्तर में 50 प्रतिशत का सकारात्मक 50 प्रतिशत का नकारात्मक प्रतिक्रिया रही।

निष्कर्ष –शोध अध्ययन से विभिन्न निष्कर्ष उभकर सामने आए।

- अधिकांश वेतनभोगी महिलाओं को परिवार में मुख्य भूमिका प्रदान नहीं की जाती। उन्हें अधीनस्थ तथा आश्रित सदस्य के रूप में ही पहचाना जाता है।
- अधिकतर महिलाएँ पारिवारिक गतिविधियों में तटस्थ नहीं रहती अपितु सक्रिय भूमिका निभाती है। सफल भूमिका पारिवारिक समायोजन में सहायक सिद्ध होती है।
- महिलाओं का घर से बाहर नौकरी करना परिवार के सदस्यों को अच्छा तो लगता है किन्तु उन्हें परिवार से पर्याप्त सहयोग नहीं मिलता, परिणाम स्वरूप समायोजन को प्रक्रिया प्रभावित होती है।
- वेतनभोगी महिलाओं को नौकरी एवं पारिवारिक दायित्व दोनों को निभाना पड़ता है, अत: कुछ वेतनभोगी महिलाएँ नौकरी एवं परिवार के दायित्व के बीच ठीक ढंग से तालमेल स्थापित नहीं कर पाती है।
- जो महिलाएँ नौकरी करना चाहती है उन पर बहुत अधिक दबाव और रोक लगाई जाती है तो वे हीनता का अनुभव करती है।
- नौकरी एवं पारिवारिक जीवन का सह–सम्बन्ध एक–दूसरे को प्रभावित करता है।
- नौकरी के कारण यदि पारिवारिक जीवन प्रभावित होता है तो कुछ महिलाएँ नौकरी छोड़ने की मानसिकता रखती है तथा नौकरी छोड़ने के पक्ष में नहीं है।
- वेतनभोगी महिलाएँ अपनी दोहरी भूमिका से निरन्तर संघर्ष करते हुए भी समायोजन के प्रति सकारात्मक रूख रखती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. एवरेट जे. एन. – वूमेन एण्ड सोश्यल चेन्ज इन इण्डिया, एर्टेज पब्लिशर्स नई दिल्ली, 1974।
2. घोष, एस. के – वोमेन इन ए. चेजिंग सोसाइटी, एशिया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली , 1984।
3. गुडे विलियम जे. एवं हाट पाल के – मेथड्स इन सोश्यल रिसर्च में ग्राहित बुक को न्यूयार्क , 1952।
4. कपूर प्रमिला – भारत में विवाह ओर कामकाजी महिलाएँ , राजकमल प्रकाशन 1974।
5. खन्ना गिरिना एवं मरियम्मा ए. बरगीज – इण्डियन विमेन टुडे, दिल्ली

विकास, 1978।

6. लैंडिस , जूडसन एवं लैडिंस मेरी जी – पसर्नल एडजस्टमेंट, मेरेज एण्ड फेमिली लविंग ऐम्हो वुड, क्लिप्स, एन. जे. प्रैटिंस हाल इंक, 1958।

7. गीताली सेनगुप्ता – वेतनभोगी महिलाओं की समाज मनोवैज्ञानिक समस्याओं को अध्ययन (खण्डवा नगर के संदर्भ में) सागर विश्वविद्यालय, सागर द्वारा स्वीकृत शोध प्रबंध

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

महेश्वर हथकरघा उद्यमियों में सामान्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अध्ययन

डॉ. मंजु शर्मा * प्रतिष्ठा दासौंधी **

प्रस्तावना – प्रस्तुत शोध पत्र महेश्वर हथकरघा बुनकर उद्यमियों के सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित है इसमें बुनकरों के व्यवसायिक कार्यो के दौरान शरीर में दर्द संबंधित समस्याएँ व श्वास संबंधित समस्याओं पर है। जिनमें उनकी सामान्य समस्याओं के बारे में पता किया गया है बुनकरों को व्यवसायिक कार्य में संलग्न रहते-रहते वे अपनी शरीर के स्वास्थ्य व अपने दैनिक दिनचर्या पर ध्यान नहीं दे पाते जिससे उनमें कई प्रभाव सामने ऊभर कर आते है। जो धीरे-धीरे बड़ी समस्याओं में परिवर्तित होते जाते है। जो तकलिफ दायक व कष्टदायक होते है, जिसका अध्ययन किया है।

महेश्वर हथकरघा बुनकर उद्योग का परिचय – महेश्वर, महेश्वरी साड़ियों के उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है महेश्वर हथकरघा की नींव होल्कर राज्य की रानी देवी अहिल्या बाई होल्कर ने सन् 1967 ई.मैं रखी गई थी। बुनकरों के द्वारा वस्त्रों पर कई प्रकार से कारीगरी की जाती है जिससे वस्त्रों की सुंदरता बढ़ जाती है। यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है जिसके भिन्न-भिन्न घाट बने है तथा उन तटीय घाटों पर बनी गई कारीगरी को बुनकरो ने महेश्वरी सड़ियों के पल्लू व बार्डर पर उतारा साथ ही अन्य वस्त्रों पर भी डिजाइन डाली गई। जिससे वस्त्रों की शोभा बहुत अधिक बढ़ जाती है। यहाँ पर लगभग 1900 हथकरघें कार्यशील अवस्था में है। जिन पर 4-5 हजार बुनकर कार्यरत् है। जो भी वस्त्र बुनकर बुनते हैं वह महेश्वर के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है व निर्यात किये जाते है। उनकी लोकप्रियता अधिक है।

बुनकर उद्यमियों के सामान्य स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की स्थिति– बुनकर उद्यमिया के जीवन की बात करें तो कई समस्याएँ उन पर प्रभाव डालती है, लेकिन हम उनकी सामान्य स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की बात कर रहे है, जिनका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन प्रभावों के कारण इनके कार्य पर किस प्रकार का असर दिखाई देता है।

शारीरिक रूप से स्वास्थ्य रहने के लिए उचित व्यायाम व संतुलित भोजन व उचित आराम की आवश्यकता होती है। बुनकरो का जीवन बहुत जटिलताओं से भरा है। सुबह से शाम तक के कार्यो की निरंतरता व व्यस्तता रहने के कारण वे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नही दें पाते और धीरे-धीरे शरीर में सामान्य समस्याएँ उत्पन्न होती रहती है। यदि सामान्य समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाये तो कोई बड़ी समस्याएँ होने का खतरा बना रहता है।

उद्देश्य – महेश्वर हथकरघा बुनकर उद्यमियों में श्वास (दमा) व शरीर में दर्द संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना।

साहित्य का पुर्नरावलोकन – साहित्य के पुर्नरावलोकन से हमें शोधकार्य करने में मदद मिलती हैं

तिवारी एट. एल के अनुसार – वर्धा के कपड़ा मजदूरों में मोटापा व शारीरिक बीमारियों के अध्ययन में यह पाया गया कि उनके शरीर में तपेदिक व शरीर में अकड़न देखी गई।

ज्यनती के अनुसार – ओटाई की मजदूर महिलाओं में फेफड़ों का संक्रमण 60 प्रतिशत देखा गया व त्वचा का संक्रमण 40 प्रतिशत देखा गया।

शोध पद्धति – महेश्वर हथकरघा शोध अध्ययन में हमारे द्वारा खरगोन जिले के महेश्वर स्थान का चयन उद्देश्यानुसार किया गया है हमारे द्वारा मजदूर बुनकरो को लिया गया है जहाँ उनके सामान्य स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को देखगें। यही समग्र के रूप में है हमारे द्वारा शोध कार्य में साक्षात्कार अनुसूचि का प्रयोग किया गया है हमारे द्वारा महेश्वर हथकरघा बुनकर उद्यमियों को लिया गया है, जिनका चयन दैव-निर्दशन विधि से किया गया है। जिसमें 50 बुनकरों को चयनित किया गया है।

तथ्यों का सारणीयन एवं वर्गीकरण – शोध पत्र में एकत्रित तथ्यों को मुख्य सारणीयों में प्रयुक्त किया गया है व सारणीयों के अनुसार ही ग्राफ आलेखों में प्रस्तुत किया गया है। सामान्य स्वास्थ्य से संबंधित बुनकरो का विवरण इस प्रकार है।

तालिका – 1

श्वास समस्या संबंधी बुनकरो का विवरण

क्र.	श्वास संबंधी समस्याएँ	बुनकर	प्रतिशत (%)
1	जुकाम का बना रहना	22	44%
2	श्वास का फूलना	14	28%
3	फेफड़ो में संक्रमण होना	4	8%
4	सामान्य अवस्था	10	20%

तालिका – 2

बुनकरो मे शारीरिक दर्द की समस्या का आंकलन करना

क्रं.	शरीर में दर्द समस्याएँ	बुनकर	प्रतिशत (%)
1	घुटनों में दर्द एवं सूजन का बना रहना	20	40%
2	बैठने उठने में परेशानी होना	15	30%
3	रीढ़ की हठी में दर्द होना	07	14%
4	सामान्य अवस्था	08	16%
	योग	50	100%

निष्कर्ष एवं सुझाव – प्रस्तुत शोध में तालिकाओं के विवरण एवं प्रस्तुत ग्राफ चार्ट के आँकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि बुनकरों के सामान्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में श्वास संबंधी समस्याओं में जुकाम

* प्राध्यापक (गृह विज्ञान) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इंदौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (गृहविज्ञान) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इंदौर (म.प्र.) भारत

44 प्रतिशत बुनकरों में है श्वास का फूलना 28 प्रतिशत बुनकरों में है एवं फेफड़ों का संक्रमण 8 प्रतिशत बुनकरों में है, साथ ही सामान्य अवस्था में 20 प्रतिशत बुनकर पाये गये।

शरीर में दर्द समबन्धि समस्याओं में यह ज्ञात हुआ कि घुटनो में दर्द में 40 प्रतिशत बुनकरों में दिखाई दी, उठने बैठने में तकलीफ 30 प्रतिशत बुनकरों में दिखाई दी एवं रीढ़ की हठी की समस्याएँ 14 प्रतिशत बुनकरों में दिखाई दी। साथ की सामान्य अवस्था स्थिति में 16 प्रतिशत बुनकर पाये गये। बुनकरों में स्वास्थ्य की सामान्य समस्याएँ उनके कार्य की अनुकूलता व व्यस्तता के कारणों को दर्शाती है।

सुझाव – बुनकरो में ये सामान्य समस्याएँ अधिकतर बनी रहती है क्योंकि उनको कार्य करने में एक स्थान पर बैठे रहना पीठ सीधे करके बैठना तथा कताई करना बुनाई करना व लगातार रूप में कार्य करने से धूल के बारीक कणों का श्वास नली के द्वारा मुँह में प्रवेश हो जाता है, जिससे ये सारी प्रक्रियाएँ स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं इसलिए हमें बीच – बीच में आराम करना चाहिए। मॉस्क पहनकर कार्य करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का कचरा श्वान नली में नहीं पहुँच पाये। साथ ही महीने में एक बार बुनकरों का मुफ्त चिकित्सकीय परीक्षण भी करवाना चाहिए ताकि उन्हें स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती रहे तथा स्वास्थ्य में परिवर्तन लाकर बुनकरों के जीवन में अच्छे आयाम स्थापित कर सकें, जिससे वे अधिक से अधिक कार्य सम्पन्न कर सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. हथकरघा प्रशिक्षण केन्द्र – टी.एम. अंसारी।
2. व्यवसायिक प्रबंध के सिद्धांत – आर.सी. अग्रवाल।
3. सांख्यिकी के मूलतत्व – डॉ.एच.के. कपील।
4. शैक्षिक शोध – डॉ. हंसराज पाल।
5. संसाधन प्रबंध का परिचय – डॉ. मंजु शर्मा।
6. अनुसंधान सांख्यिकी – डॉ. मंजु पाटनी।
7. इंटरनेट सुविधा के द्वारा – बेवसाइट के द्वारा।

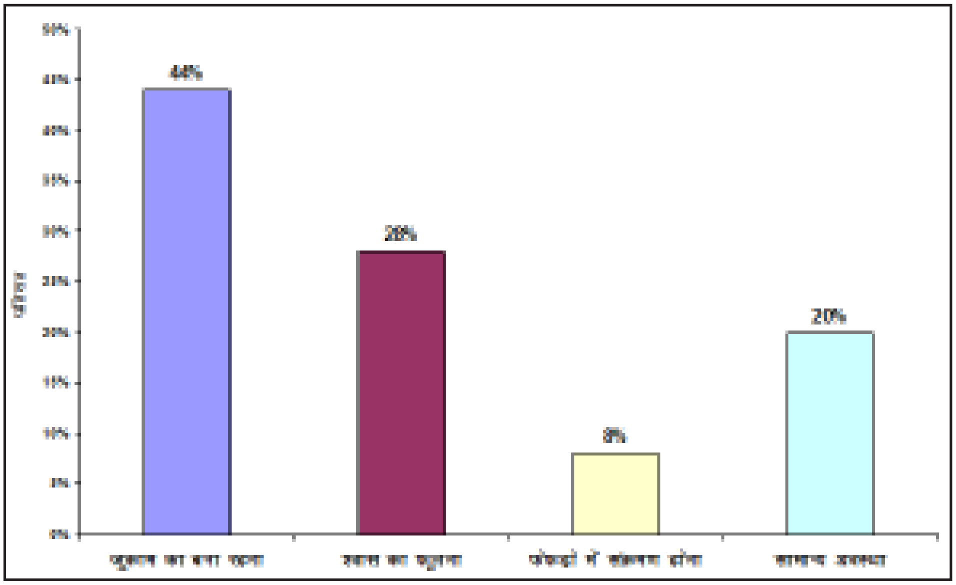

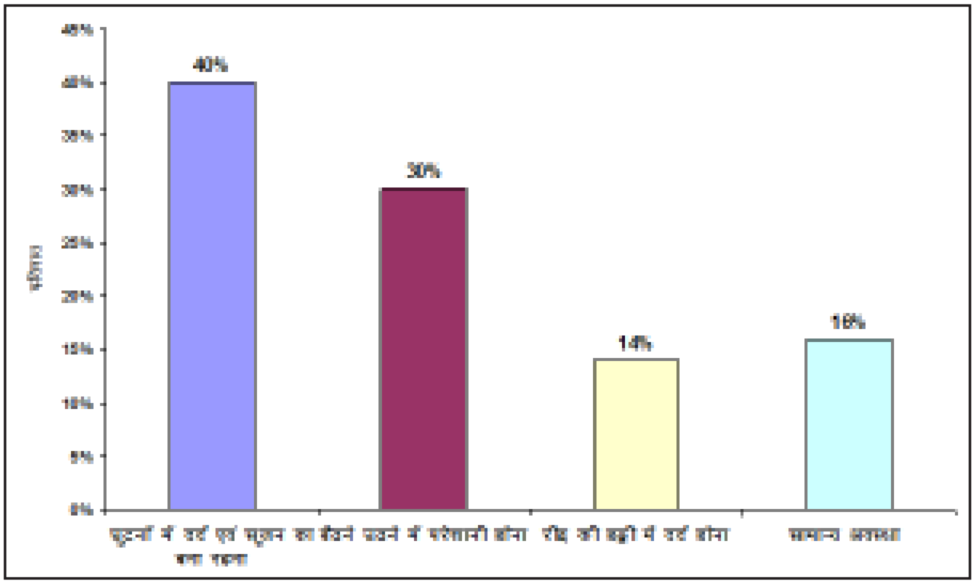

****

Equitable Role Of Agricultural Produce Markets In Economic Reforms And Development Of Farmers - An Analytical Study (Special reference to the Farmers of Indore Region in M.P.)

Dr. Rajesh Jain*

Abstract - For providing better facility and minimum support values of crops to the farmers, government generated regulated agro markets. Establishment of Agriculture Markets in Indore Region successfully provided better infrastructure and other facilities to the farmers. For getting better prices, farmers carried out bulk quantity of crops in agro markets. In this research paper, I tried to study that foundation of agriculture markets helpful to eco-socio development of farmers. The main objectives of my research to know the contribution of agro markets in financial development of farmers. For this I used different statistical tools like Chi-square test, T-test, Ranking, and Percentage etc. With the help of agro markets officers and staff, government follows up rules and regulations strictly which are favorable for farmers. From this, farmers not only getting better values on crops but also improve their assets and living standard. There is association between strictly follow government rules and regulations in Agro-Markets across reliability grow in farmers for the same. There is association between continuously economic developments of farmers across the establishment of Agro-Markets.
Key Words - Region, T-test, association, reliability, crops.

Introduction - Indore region is one of the important area for produce agro-crops like wheat, pulses, gram etc. in Malwa. For providing better prices of crops and other suitable facilities to the farmers of state, MP government build up MP Agriculture Regulation Act. It's helpful to regulate and control various Agriculture Markets in all over the state. Agro-Market not only provide better platform to sale crops in better price but also provide various facilities to the farmers of Indore Region. Many schemes are running by state government for the betterment of farmers through Agriculture Markets.

Research Objectives -

1. To study about the function and present status of Agriculture Markets
2. To study regarding impact of Agro-Markets Policy on farmers
3. To study about economic and socio development of the farmers through Agro-Markets

Research Methodology - The research is based on primary and secondary data collection methods and the research type is descriptive. A structured questionnaire will be designed to gather information for primary data and, for secondary data-internet, books and websites previous dissertations/research papers/marketing journals/ magazines/text etc will be used. A five point multi item liker t scale (1- strongly agree and 5- strongly disagree.) will be used for the study the research will be conducted in different District of Indore Region It will involve gathering of information from the farmers who belong from Indore Region. Convenience sampling method will be used to get the responses from target farmers. Sample size of 500 respondents in the age group 18 to 65 year will be taken for the survey. To do the research following statistical tools will be used: percentage analysis, Rank analysis, Chi-square analysis, T-test.

Hypothesis -

1. H1- HA: There is association between strictly follow government rules and regulations in Agro-Markets across reliability grow in farmers for the same.
2. H2- HA: There is association between continuously economic developments of farmers across the establishment of Agro-Markets.
3. H3- HA: There is no association between strictly follow government rules and regulations in Agro-Markets across reliability grew in farmers for the same.
4. H4- HA: There is no association between continuously economic developments of farmers across the establishment of Agro-Markets.

Research Contribution - This research work is multiple tasks to study about the contribution of Agro-Markets for the economic and socio development of farmers in Indore Region. Due to burden of loan, over-under rainfall and so many problems are facing by the farmers recently but proper operating of Agro- Markets with regulation its helpful to remove farmers from the circle of loans and others problems. This research also helpful for investors, farmers, agro-merchant, agents, finance institutions and public.

Review of Literature - According from Bharti, Rajni (1996), Appointment of new forth class workers in agro-markets it's helpful to operate regular works easily. After using new

*Asst. Professor (Commerce) IPS Academy, Indore (M.P.) INDIA

technology by the farmers in agriculture, production and crops delivery were increase by 11% and 29% respectively. According from Mahajan, Vishal (2003) development of Agro markets improved crops delivery in market by 34.8% in Barwani and 28.91% in Khargon. Barwani market got 84% income from market duty and from other sources 16%. In Khargone its 89% & 11% respectively. Kannode, Rameshchandra (2010) In west Nimarh, utilized better quality seeds, fertilizers and new technology of farming its grew up production of crops by 122% and income of farmers by 116%. It's always improving farmers fixed assets as well as living standard.

Analysis and Discussion - In the data analysis there is classification and Frequency of different demographic profile like as Reliability grow and economic development statement. Chi-square test, T- test, as help to understand the relation between different demographic factors, farmers economic development. from the cross tabulation of different factors I make the relation then apply the chi-square test on the basis of the test result we come to know the Association or No association among different factors.

Table 1 - (See in the last page)

SA(1)= Strongly agree, A (2) =Agree, N (3) = Neutral, D(4) Disagree, SD (5) Strongly disagree, St. D = Standard deviation

Interpretation - From above Table, it is being Interpreted that the -

- Mean value for Government rules and regulations follow strictly in Agro markets 1.37
- Mean value for Agro market successfully provide better marketing facility to the farmers is 1.81
- Mean value for Improve in inward of crops in agro markets is 1.60
- Mean value for the Economic and socio development of farmers is 1.79

(A) Chi-Square Test Role of Agriculture Market in financial development of farmers

Hypothesis 1

HO - There is no association between strictly follow government rules and regulations in Agro-Markets across reliability grow in farmers for the same.

HA - There is association between strictly follow government rules and regulations in Agro-Markets across reliability grow in farmers for the same.

Table 2 (See in the last page)

Inference - The above HO : is Rejected (chi-square with 4 degree of freedom=13.44, p=.0038). There is association between strictly follow government rules and regulations in Agro-Markets across reliability grow in farmers for the same.

Hypothesis 2 -

HO - There is association between continuously economic developments of farmers across the establishment of Agro-Markets.

HA - There is no association between continuously economic developments of farmers across the establishment of Agro-Markets.

Table 3 (See in the last page)

Inference - The above HO : is accepted. (Chi Square with 4 degree of freedom=6.88, p= 0.086). There is association between continuously economic developments of farmers across the establishment of Agro-Markets.

(A) Ranking of factor for Role of Agriculture Market

Table 4 (See in the last page)

Inference - The Table 4 gives the distribution of the respondent according to the ranking of the factor for preference towards a particular restaurant…. Financial & Socio Development was ranked 1st, 2nd for Minimum Support Value, 3rd for Improve Reliability, 4th for Improve in Wealth, 5th for Better Infrastructure, 6th for Bank Loan & Other Facility.

(B) T-Test For Analyzing the Role of Agro-Markets for financial development of farmers

Hypothesis 3 -

HO - There is association between strictly follow government rules and regulations in Agro-Markets across reliability grew in farmers for the same.

HA - There is no association between strictly follow government rules and regulations in Agro-Markets across reliability grew in farmers for the same.

Table 5 (See in the last page)

Inference - The above HO : is Accepted, (p=.27 > .04, t= 1.29). There is association between strictly follow government rules and regulations in Agro-Markets across reliability grew in farmers for the same.

Hypothesis 4 -

HO - There is association between continuously economic developments of farmers across the establishment of Agro-Markets.

HA - There is no association between continuously economic developments of farmers across the establishment of Agro-Markets.

Table 6 (See in the last page)

Inference - The above HO : is Accepted (p=0.74 p >.05, f=.729). There is association between continuously economic developments of farmers across the establishment of Agro-Markets

Results and Findings -

- Out of all the respondent 92% are regular members of agriculture markets.
- Out of all the respondent 97% sold their crops in agriculture markets and remain 3% in open markets.
- Out of all the respondent 53% are satisfied from the facility provided by agriculture markets, 27% are in no responding zone.
- Due to development of Agriculture markets, 85% farmers getting better prices for their crops and improved wealth thereon.
- There is association between strictly follow government rules and regulations in Agro-Markets across reliability grow in farmers for the same.

Conclusion - Finally, establishment of agriculture markets in Indore region of M.P. not only helpful to farmers on fi

nancial development but also socio improvement. Its provided better infrastructure in agro markets which attract farmers to sold their crops in that place within bulk quantity. Minimum support values also being provided by government through agriculture markets. It's a single platform where farmers can sold their different crops in favorable values. With the help of agro markets officers and staff, government follow up rules and regulations strictly which are favorable for farmers. From this, farmers not only getting better values on crops but also improve their assets and living standard.

References :-

1. Abbas, Muhammad Akhtar., and Tahir Hussain. "General Agriculture." 1st ed., vol. 2, ser. 4, Publishers Emporium, 2000, pp. 132–179. 4. Retrieved from https://www.amazon.in/General-Agriculture-Examinations-Ph-25th/dp/8183601413.
2. Alagh, Yoginder K The Future of Indian Agriculture, 2nd ed., vol. 4, ser. 1, National Book Trust, India, 2013, pp. 134–165. 1. Retrieved from https://www.amazon.in/Future-Indian-Agriculture-PB-Alagh/dp/8123767366
3. Deb, Bimal J., and B. Datta-Ray. Changing Agricultural Scenario in North-East India, 1st ed., vol. 3, ser. 1, Concept Pub. Co., 2006, pp. 14–28. 1. Retrieved from https://books.google.co.in/books/about/Changing_Agricultural_Scenario_in_North.html
4. Mamoria, C. B., and Badri Bishal. Tripathi. Agricultural Problems of India, 2nd ed., vol. 3, Kitab Mahal, 2008, pp. 27–42. Retrieved from https://www.amazon.in/Agricultural-Problems-India-C-B-Mamoria/dp/8122500919
5. Rao, B. Sambasiva. Agriculture in India: Policy and Performance, 1st ed., vol. 2, Serials Publ., 2003, pp. 116–135. Retrieved from http://www.indiaclub.com/Agriculture-in-India—Policy-and-Performance_p_389145.html
6. The Agricultural Economics of the 21st Century, 1st ed., vol. 2, Springer Verlag, 2016, pp. 62–89. Retrieved from https://books.google.co.in/books/about/The_Agricultural_Economics_of_the_21st_C.htm

Table 1- Mean value among different measures

Statement	SA	A	N	D	SD	M	St. D
Government rules and regulations follow strictly in Agro markets	59	25	3	_	_	1.37	0.52
Agro market successfully provide better marketing facility to the farmers	24	55	5	2	3	1.81	0.71
Improve in inward of crops in agro markets	40	39	6	2	2	1.60	0.69
Economic and socio development of farmers	31	40	8	3	1	1.79	0.70

Table 2

Chi-Square Tests	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson ChiSquare	13.44	2	0.0038
Likelihood Ratio	15.47	2	0.0002
Linear-by-Linear Association	14.02	1	0.0001
N of Valid Cases	83	_	_

Table 3

Chi-Square Tests	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson ChiSquare	6.88	4	0.086
Likelihood Ratio	7.46	4	0.077
Linear-by-Linear Association	3.83	1	0.091
N of Valid Cases	83	_	_

(A) Ranking of factor for Role of Agriculture Market

Table 4

Serial No	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**WAS**	**Rank**
Factor	Count	Count	Count	Count	Count	Count	Count	Count	_	_
Improve Reliability	46	10	8	6	11	2	1	5	6.12	3
Better Infrastructure	6	26	16	21	9	3	5	3	5.09	5
Minimum Support Value	11	6	16	4	9	24	12	16	6.22	2
Bank Loan & Other Facility	9	15	21	24	12	7	8	3	4.93	6
Financial & Socio Development	13	13	10	19	18	8	6	4	7.19	1
Improve in Wealth	19	15	8	10	14	12	9	2	5.25	4

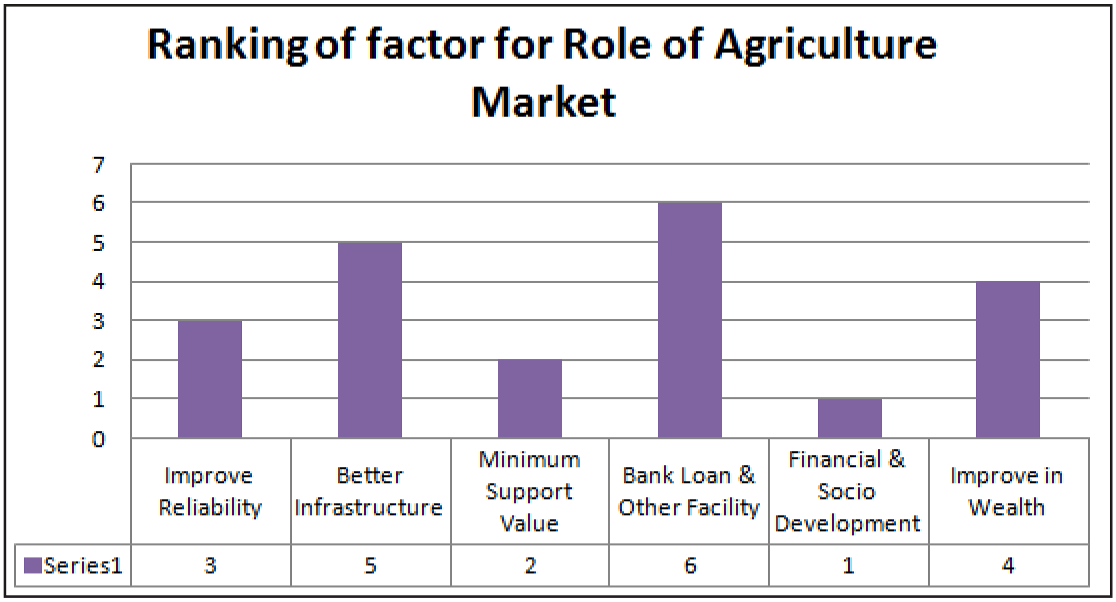

Table 5

Levine's Test for Equality of Variance s			**t-test for Equality of Means**		
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
Equal variances assumed	5.02	0.04	1.29	87	0.27

Table 6

	Sum of Squares	**df**	**Mean Square**	**F**	**Sig.**
Between Groups	5.94	18	0.33	0.729	0.74
Within Groups	37.97	70	0.54	_	_
Total	43.91	88	_	_	_

****

A Study Of Customer Retention Management In Telecom Sector

Amit Garg* Dr. Kamalijeet Bhatia**

Abstract - The Indian telecom sector has grown extremely in last few years. The number of players as well as the level of competition is continuously increasing. The regulators are frequently coming up with new regulations and policies. Hence, now it has become necessary to understand the expectations of customers and provide the best of the services to them. This is not only important for attracting new customers but also helps in retaining them. The players are required to understand the customer retention strategies for mobile telecommunication sector in India. The mobile telecommunication industry being a service oriented industry has to maintain on the quality of customer service. The survival and growth of a mobile service provider not only depends upon its ability to provide qualitative services to its customers on a sustained basis, but also in building long-term mutually beneficial and trust-worthy relationships with its patrons.

Key Words - Customer retention, customer satisfaction, Telecommunication.

Introduction - Today is the era which is majorly based on the economy that has customer focus nature. Customer retention is a very important element for maintaining healthy and long term Customer-firm relationship.

The importance of customer retention has increased since a majority of firms started to suffer a noticeable loss of customers, along with the complexity and high costs of acquiring new customers (Bird, 2005; Goyles and Gokey, 2005; Voss and Voss, 2008).

Morgan and Hunt (1994) provide a broad definition of RM as "all marketing activities directed towards establishing, developing, and maintaining successful relational exchanges. This highlights the need to change existing attitudes toward marketing from a series of independent transactions to a dynamic process of establishing, maintaining and enhancing relationships in the long term. It indicates that the relationship between consumer and firm is built upon two parties engaged in a continuous process of exchange whereby both will benefit in the long term. While such relationships are sometimes available, they are not necessarily always long-term (Karantinou, 2005). Thus, the primary relational goal is the long-term continuity of exchange between two parties. Therefore, the "customer retention" trend has emerged in order to increase organizations' profits and minimize both costs and customer switching in the long run. This view is confirmed by Farquhar (2003) who explained that, in order to be able to build long-term relationships with customers, institutions must first be able to retain existing customers. Christopher et al. (1991) also assert that the function of RM is "getting and keeping customers" which will be the challenge of survival in volatile markets. Accordingly, customer retention is that part of relationship marketing knowledge concerned mainly with maintaining existing customers by manipulating the relationship in a way that enables parties, the firm and the customer, to benefit through long-term, repeat business.

Major Telecom Service Providers in India - The market shares, as on March 31, 2015, of the major wireless telecom service providers in India are shown in Figure 1.

It is evident from the figure, the top seven wireless telecom service providers are Bharti, Vodafone, Idea, Reliance, BSNL, Aircel and Tata.

Others include Sistema, Videocon, MTNL and Quadrant

Source: Adapted from Annual Reports on the TRAI website (www.trai.gov.in).

Figure 1 Market Share of Wireless Service Providers (See in the last page)

Literature Review -

Frazier, Spekman & O'Neal (1988) - found that total quality movement is the force which is driving the adoption of CRM. When companies started embracing Total Quality Management (TQM) philosophy to improve quality and reduce costs, it became necessary to involve suppliers and customers in implementing the program at all levels of the value chain. This needed close working relationships with customers, suppliers, and other members of the marketing infrastructure.

Gronroos (1995) - finds that the de-intermediation process and consequent occurrence of CRM is also due to the growth of the service economy. Since services are typically produced and delivered at the same institutions, it minimizes

*Research Scholar, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore (M.P.) INDIA
**Principal, SDPS Womens College of Commerce and Management, Indore (M.P.) INDIA

the role of the middlemen. A greater emotional bond between the service provider and the service users also develops the need for maintaining and enhancing the relationship. It is therefore not difficult to see that CRM is important for scholars and practitioners of services marketing.

Storbacka (2000) - suggests that the company must be careful in tailoring its program and marketing efforts by segmenting and selecting suitable customers for individual marketing programs. In certain cases, it could even lead to "outsourcing of some customers" so that a company can better utilize its resources on those customers that it can serve better and create mutual value.

Skogland & Siguaw (2004) - identified how the satisfied customers become loyal to any organization. They specifically underpinned that the customer satisfaction is not suitable for all the industries to become loyal to the organisations. The research paper quoted the dizzy nature of customer satisfaction in hospitality industry. The study further argues that in hospitality management, an automated system alone will not ensure the customer satisfaction to optimise the returns from the customers. They identified the repeated purchase cases and the satisfaction in FMCG products that create loyalty among the customers with optimistic dimensions.

Rahman, Haque & Ahmad (2011) - investigated the choice criteria for a mobile phone operator in the Malaysian mobile telecom market by the customers. It was found that the price and service, quality hypothesis are more important than the brand image hypothesis. Network quality was one of the important factors of overall service quality.

Alireza et al. (2011) - proposed an integrative model to examine the relations among service quality, value, image, satisfaction, and loyalty in Iran. Their study revealed that service quality directly influences perceived value, image perceptions and customer satisfaction that value and image influence satisfaction, that corporate image influences value, and that both customers satisfaction corporate image are significant determinants of loyalty. Customer satisfactions mediate the impact of service quality, value and corporate image on customer loyalty. In most aspects evidence suggests the loyalty model in Iran is similar to what researchers have found in western countries.

Research Methodology -

1 Objectives of the Study

- To study the level of customer satisfaction in telecom sector for customer retention on management.
- To study the current market scenario in telecom sector for customer retention on management.
- To study the factors important for customer retention on management.

2 Hypotheses of the Study - On the basis of defined objectives, the following hypotheses are designed to be tested in the research study:

H_{01} - The perceived service quality in mobile telecom sector has a significant positive impact on customer retention.

H_{02} -The customer satisfaction in mobile telecom sector has a significant positive impact on customer retention.

3 Sample Design and Sample Size - Four major telecom service providers namely Bharti Airtel Ltd., Bharat Sanchar Nigam Limited, Idea Cellular Ltd. and Reliance Communications Ltd. are selected in the research study. Primary data is collected from a sample of 540 mobile telecom customers residing in Indore city. In order to collect the necessary data, the researcher administered the questionnaire personally to the respondents. The respondents were requested to provide the relevant information after sufficiently explaining the nature and purpose of the study. The quota and judgemental sampling method is used in the research study.

Data Analysis and Interpretation -

(a) Impact of perceived service quality on customer retention.

H_{01} - The perceived service quality in mobile telecom sector has a significant positive impact on customer retention.

Figure 2 - Service Quality and Customer Retention (See in the last page)

Table 1 - Relationship between Service Quality and Customer Retention (See in the last page)

Table 2 - Model fit index Service Quality and Customer Retention (See in the last page)

The results of the above mentioned hypothesis is shown in table 1. The results indicate that the structured regression rate of the relationship between perceived service quality and customer retention is .812 and is found to be significant (p=.000). Hence, with the 95% confidence level the null hypothesis of no cause and effect relationship cannot be accepted. Hence, it can be concluded that the perceived quality of services in mobile telecom sector have a positive significant impact on customer retention. The goodness of fit indicators such as CFI (.945), GFI (.839), NFI (.915), AGFI (.759), RMSEA (.062) indicate that the tested structural equation model is have a significant fit.

(b) The customer satisfaction in mobile telecom sector has a significant positive impact on customer retention.

H_{02}: The customer satisfaction in mobile telecom sector has a significant positive impact on customer retention.

Figure 3 - Customer Satisfaction and Customer Retention (See in the last page)

Table 3 - Relationship between Customer Satisfaction and Customer Retention (See in the last page)

Table 4 - Model fit relationship between Customer Satisfaction and Customer Retention (See in the last page)

The results of the above mentioned hypothesis is shown in table 3. The results indicate that the structured regression rate of the relationship between customer satisfaction and customer retention is .839 and is found to be significant (p=.000). Hence, with the 95% confidence level the null hypothesis of no cause and effect relationship cannot be accepted. Hence, it can be concluded that the customer satisfaction in mobile telecom sector have a

positive significant impact on customer retention. The goodness of fit indicators such as CFI (.998), GFI (.916), NFI (.976), AGFI (.870), RMSEA (.031) indicate that the tested structural equation model is have a significant fit.

Conclusion - In the research study an effort is made to analyse the impact of perceived service quality in mobile telecom sector on customer retention. Seven dimensions of service quality namely *tangibility, reliability, responsiveness, assurance, empathy, network quality* and *convenience* are considered in this research study and accordingly the impact of all these dimensions of service quality on customer retention has been checked. It is observed in the research study that the perceived quality of services in mobile telecom sector have a positive significant impact on customer retention. Hence it is suggested that mobile telecom operators should design their customer retention strategies by keeping in view the service quality aspect. Accordingly, it can be concluded that telecom operator can use service quality as a tool of customer retention strategies in mobile telecom services.

Customer satisfaction refers to the assessment of all interactions with product or service from a provider, relative to expectations. It seems logical that a highly satisfied customer would be a retained customer. In this research study the effort is made to analyse the impact of customer satisfaction in mobile telecom sector on customer retention. It is found and concluded that the customer satisfaction in mobile telecom sector has positive significant impact on customer retention. Hence it is suggested that mobile telecom operators should strengthen their efforts to satisfy the customer and satisfied customers would lead to retained customers.

References :-

1. Alrubaiee. L. and Alkaaida. F. (2011). “The mediating effect of patient satisfaction in the patients’ perceptions of healthcare quality – patient trust relationship”, International Journal of Marketing Studies, 3(1), 103-127.
2. Casaló. L. V., Flavián. C. and Guinalíu. M. (2008). “The role of satisfaction and website usability in developing customer loyalty and positive word-of-mouth in the e-banking services”. International Journal of Bank Marketing, 26(6), 399-417.
3. Cheung. C.M.K. and Lee, M.K.O. (2005). “Research Framework for Consumer Satisfaction with Internet Shopping”, Working Papers on Information Systems, 5(26), 1-17.
4. Frazier, G., Spekman, R.E., & O’Neal, C.R. (1988). “Just-In-Time Exchange Relationships in Industrial Markets”, *Journal of Marketing*, 52(4), 52-67.
5. Morgan. R. M. and Hunt. S. D. (1994). “The commitment-trust theory of relationship marketing”, Journal of Marketing, 58(3), 20-38.
6. Zhou, T. (2011). “An empirical examination of initial trust in mobile banking”, Internet Research, 21(5), 527-540.

Figure - 1 Market Share of Wireless Service Providers

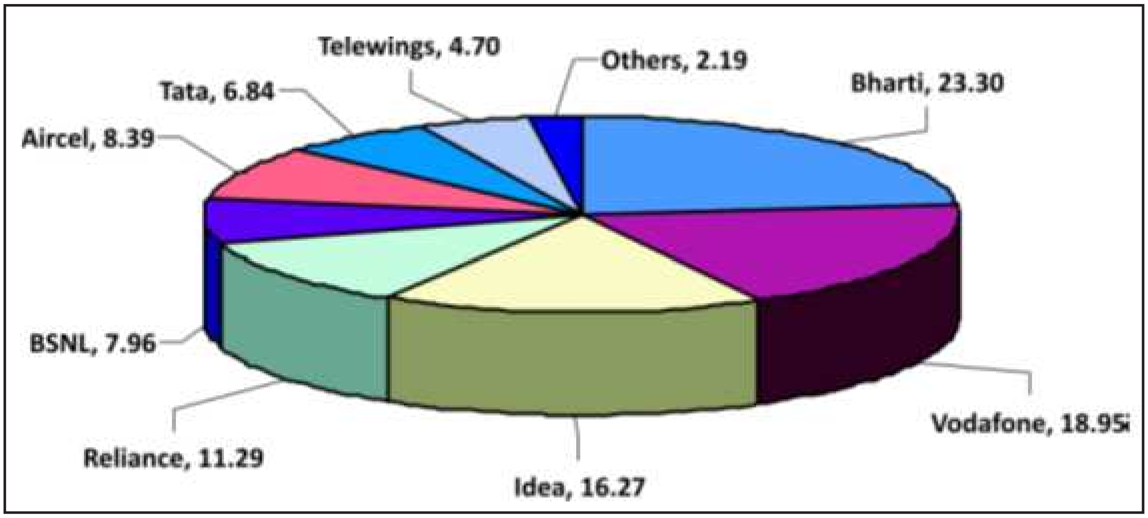

Figure 2 - Service Quality and Customer Retention

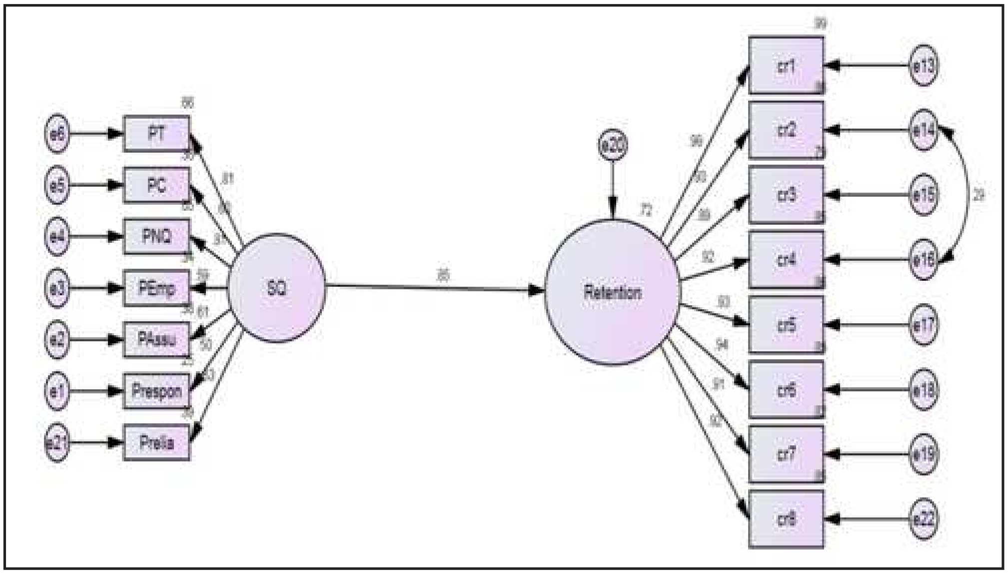

Figure 3 - Customer Satisfaction and Customer Retention

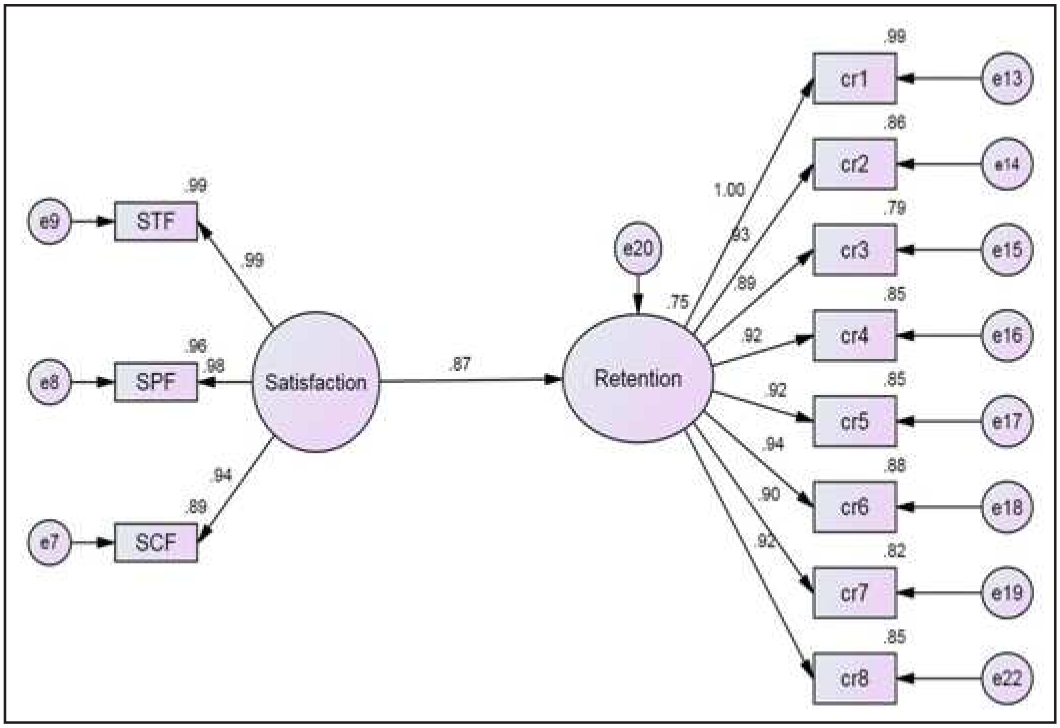

Table 1 - Relationship between Service Quality and Customer Retention

Exogenous Construct	Endogenous Construct	Standardized Regression Coefficient	Unstandardized Regression Coefficient	CR	P Value	Squared multiple correlation
Service Quality	Customer Retention	0.812	3.652	5.124	0	0.636

Table 2 - Model fit index Service Quality and Customer Retention

Fitness of Model Index	CFI	NFI	RFI	RMSEA	LO 90	Hi 90
Value	.945	.915	.921	.062	.034	.100

Table 3 - Relationship between Customer Satisfaction and Customer Retention

Exogenous Construct	Endogenous Construct	Standardized Regression Coefficient	Unstandardized Regression Coefficient	CR	P Value	Squared multiple correlation
Customer Satisfaction	Customer Retention	0.839	1.842	14.44	0	0.748

Table 4 - Model fit relationship between Customer Satisfaction and Customer Retention

Fitness of Model Index	CFI	NFI	RFI	RMSEA	LO 90	Hi 90
Value	.998	.976	.969	.031	.037	.077

****

An Analytical Study Of Profit And Loss Statement Of Sbi And Hdfc Mutual Fund Companies

Garima Shrivastava* Dr. Vasudev Mishra Dr. Ashish Pathak*****

Introduction - A mutual fund is nothing more than an assembly of stocks and bonds.

A mutual fund as a company brings mutually a group of persons and invests their valuable money in stocks, bonds, and other securities.

Each depositor own shares, which represents a part of holdings of the fund.

Mutual funds are one of the best opportunities for investor's money to increase. Depending on risk desire, it gives the option to choose stability, insistent growth or both.

In simple words, a mutual fund is a intermediates that brings together a group of investors who are normal people; to invest their money in bonds, stocks and other securities available in market. Each investor purchases his shares, which represent a part of holdings of the fund. Hence, a mutual fund is one of the most possible investment options for the common man as it recommends an opportunity to invest in an expanded, professionally managed box of the securities at a comparatively low cost.

Now-a-days, we hear more and more about mutual fund as a means of investment. As we know most of the public, investment their money in Banks in saving account or as fixed deposit when the amount is larger.

Meaning Of Profit And Loss Statement - The **profit & loss (P&L) statement** is one of the three major financial statements used to evaluate a company's performance and financial position and the two others are the balance sheet and the cash flow statement.

How It Works With Example - The profit & loss statement reviews the revenues and expenses produced by the company over the whole reporting period. The profit & loss statement is also known as the income statement, statement of earnings, statement of operations, or statement of income.

The basic equation on which a profit & loss statement is based is Revenues – Expenses = Profit.

All companies need to produce revenue to stay in business. Revenues are used to pay expenses, interest payments on debt, and taxes owed to the government. After the costs of doing business are paid, the amount left over is called net income. Net income is theoretically available to shareholders, though instead of paying out dividends, the firm's management often chooses to retain earnings for future investment in the business.

Profit & loss statements are all organized the same way, regardless of industry. The basic outline is shown in the following example:

Profit & Loss Statement for Company XYZ, Inc.
for the year ended December 31, 2008

Total Revenue	$100,000
Cost of Goods Sold	($ 20,000)
Gross Profit	$ 80,000
Operating Expenses	
Salaries	$10,000
Rent	$10,000
Utilities	$ 5,000
Depreciation	$ 5,000
Total Operating Expenses	($ 30,000)
Operating Profit (EBIT)	$ 50,000
Interest Expense	($ 10,000)
Income before taxes (EBT)	$ 40,000
Taxes	($ 10,000)
Net Income	$ 30,000
Number of Shares Outstanding	30,000
Earnings Per Share (EPS)	$1.00

Why It Matters? - A firm's ability or inability to produce earnings over the long term is the key driver of stock and bond prices. Operating profit (EBIT) is the source of debt repayment, and if a company can't generate enough EBIT to pay its debt obligations, it will have to enter bankruptcy or sell itself. Net income is the source of compensation to shareholders (owners of the company), and if a company cannot generate enough profit to compensate owners for the risks they've taken, the value of the owners' shares will plummet. Conversely, if a company is healthy and growing, higher stock and bond prices will reflect the increased availability of profits.

Why Profit and Loss statement monitoring is important? - Monitoring of P&L by investment policy and investor (product) schemes flow is important for organization in concluding the overall powers and weak points of a firm. It is a very important tool for Investment

*Research Scholar, E-84, L.I.G. Colony, Indore (M.P.) INDIA
**Prof. and Principal, Shri Cloth Market Institure of Professional Studies, Ganesh Ganj, Indore (M.P.) INDIA
***Professor (Coomerce) Shri Atal Bihari Vajpayee Govt. Arts and Commerce College, Indore (M.P.) INDIA

companies to measure marketing and to attract investors. P&L also helps investors in getting an indication of the size of a company's operations and its competition with other companies.

Profit and Loss statement as a Factor for Investment - P&L statement may also be an important reflection for fresh fund investors and wealth management services inclusively. Products with higher profit can usually have higher market trading quantities which positively manipulate the liquidity of a product. In the wealth management industries, some investment managers may have obligations based on P&L, and it may conclude if an investor is capable for some type of investments. An investor's personal profit can also be an issue in concluding the type of services receiving from a financial advisor , broker or any brokerage company. In some cases, individual assets under management may as well match with an individual's net worth.

On the whole, P&L is only one portion used in evaluating a company or investment. It is generally also deemed as conjunction with management performance and management practice. While it is simply one aspect used by investors in investment judgments, generally investors can believe that higher investment inflows and higher profit indicates as a positive quality.

Review Of Literature -

Dr. Sandeep Bansal and Deepak Garg (2012), have studied Impact of Sharpe Ratio & Treynor's Ratio on some Selected Mutual Fund Schemes. This paper studies the performance of some selected mutual fund schemes that the risk report of the collective mutual fund universe can be exactly evaluate by a simple market index to offers relative monthly liquidity, returns, organized & unsystematic risk.

Dr. K. Veeraiah(Jan 2014), conducted a research on Comparative Performance Analysis of Selected Indian Mutual Fund Schemes. This study investigates the presentation of Indian personal mutual funds and match up to their performance.

Dr Surender Kumar Gupta and Dr. Sandeep Bansal (Jul 2012), have done a Comparative Study on Debt Scheme of Mutual Fund of Reliance and Birla Sun life. This study gives an outline of the performance of debt scheme of mutual fund of Reliance, and Birla Sun life with the help of Sharpe Index after calculating Net Asset Values and Standard Deviation.

Prof. V. Vanaja and Dr. R. Karrupasamy (2013) have done a Study on the Performance of selected Indian Private Sector Balanced Category Mutual Fund Schemes. The purpose of the study is to evaluate the performance of selected Private sector balanced schemes on the basis of returns and comparison with their bench marks and also to evaluate the performance of different categories of funds.

Objectives Of The Study - The objective of study is to analyze and to know the Profit and Loss Statement of two companies. Companies for analysis taken in this paper are SBI and HDFC. The main objectives are:-

1. To know the meaning of Mutual funds and its P&L statement.
2. To know calculation of P&L statement of Mutual Fund.
3. To know P&L statement of two companies.
4. To draw graphs of both the companies.
5. To analyses the data taken.

Hypothesis Of The Study -

1. Ho: Investors know P&L statement very well.
   Ha: Investors did not know P&L statement very well.
2. Ho: Investors invests according to P&L of MF Company.
   Ha: Investors did not invest according to P&L of MF company.

Research Methodology - While deciding about the method of data collection to be used for the study, the researcher should keep in mind two types of data, primary and secondary.

Primary data - The primary data are those which are collected afresh or for the first time, and thus happen to be original in character. The primary data were collected through distribution of questionnaire, surveys, observation, personal interviews, through schedules.

Secondary data - Those data which have already been collected by someone else and which have already been passed through the statistical process. This data may be published or unpublished data. The secondary data may be collected through journals, books, magazines, and newspapers. Through public record, reports and publications, historical document etc.

Period of study - The research period is taken from 2010 to 2017 for study and all the data collected for P&L is taken from AMFI.

Data source - The data sources for the present research work were the Different Government reports in respect of financial sector of India, Records and Data published by AMFI, Annual reports of leading Mutual Funds companies of India.

Data collection procedure - The present study is based on secondary data. A thorough search of the published records and reports of Government as well as organizations associated with finance sector of India was made to collect the information regarding the growth of Mutual Funds industry in last 7 years.

Calculating Profit and Loss statement of mutual fund companies - Methods of calculating P&L statement differ among companies. Total firm profit will increase when investment performance increases or when new investors and new assets are obtained. Factors cause's decreases in profit also decreased market value from investment performance losses, fund closures and client redemptions.

1. State Bank Of India - As an asset management company in the SBI Group, the job of SBI Asset Management is to work as a planned Business Innovator to recognize customer needs and generate and give innovative investment management products that go with those needs, and to offer time after time high service quality. Using the home and worldwide networks of the SBI Group,

we repeatedly develop new investment methods and products that unite consistently good investment performance with access to transparent information. Through our investment trusts, we provide our customers with opportunities to invest in Japanese emerging companies and emerging markets, especially in Asia, by offering products that combine transparency with low costs.

Chart Of Sbi Mutual Fund Asset Management Company Profit And Loss Statement, From Year 2010 To 2017 See in the next page)

Analysis -

Revenue from operations is high in the year 2016-2017 and in the year 2011-2012.

Profit before tax is high in the year 2016-2017 and low low in the year 2011-2012.

Profit after tax is high in the year 2016-2017 and low low in the year 2011-2012.

Net worth is high in the year 2016-2017 and is low in the year

There is a continuous growth in the investment of MF in SBI which shows the trust of investors in this government body. There is no negative figures that means loss in this MF company and a growing This mutual fund is commonly preferred by MF investors.

profit year by year.

for its customers. This mutual fund is also commonly known by the Mf investors.

Graph Of Sbi Mutual Fund Asset Management Company Profit And Loss Statement, From Year 2010 To 2017(See in the next page)

1. **HDFC Asset Management Company -** HDFC Asset Management Company Ltd. is a privately hold investment manager. The firm manages equity, fixed income, and balanced mutual funds for its customers. It also manages hedge funds for its clients. It also invests in private equity with a center on real estate. The firm invests in public equity and fixed income markets. It employs fundamental analysis to make its investments. The organization was founded in 1999 and is based in Mumbai, Maharashtra. HDFC Asset Management Company Ltd. operates as a supplementary of Housing Development Finance Corporation Limited.

Profit And Loss Statement Of Hdfc Mutual Fund Company(See in the last page)

Analysis -

Revenue from operations are high in the year 2017 and low in year 2010

Profit before tax is high in the year 2017 and low in year 2010.

Profit after tax is high in the year 2017 and low in year 2010.

Net worth is high in the year 2017 and low in year 2010.

It is clear from the above chart that in HDFC Mutual fund there is a continuous growth in profit and loss statement.

Graph Of Profit And Loss Statement Of Hdfc Mutual Fund, From Year 2010 To 2017(See in the last page)

Recommendations -

1. The term P&L statement should be easier to be understood.
2. Financial advisor, brokers, agents have sufficient knowledge, so to explain investors.
3. It is very easy to compare and invest in Companies with their P&L statement for investors, so it should be very clear.
4. P&L statement gives ranking to Companies and helps in better investment.
5. Past performance is also seen through P&L statement of Company.

Conclusion - This study shows that P&L statement of Mutual Fund Companies is very important for investors for their investment decision. It shows the actual financial condition of a company. It shows the actual reports of past years. It shows the actual status of the companies which are performing in the market. P&L statement is like a mirror of the companies that shows the up and down of the companies. Companies their selves also come to with comparing data of past years for their actual position. The analysis of the two companies that is SBI and HDFC shows the Profit and Loss of the mutual fund companies of past seven years. It helps investors to invest in companies.

References :-

1. Mutual fund of Industry, Mutual Fund India, 2015, New Delhi.
2. A comparative study of performance of top five mutual fund of India,2014.
3. One fund Asset Management Companies (AMCs)
4. Mutual fund of India, Wikipedia.

Books and Newspapers -

1. India today
2. Economic times
3. Dainik bhaskar Daily News paper
4. Raj express Daily News paper
5. Times of India Daily News paper

Websites -

1. www.investmentnetwork.in
2. www.investindia.gov.in
3. www.investorwords.com
4. www.theguardian.com

**Chart Of Sbi Mutual Fund Asset Management Company
Profit And Loss Statement, From Year 2010 To 2017**

Years	Revenue From Operations	Profit Before Tax	Profit After Tax	Net Worth
Year 2010-2011	23976.05	11690.47	7884.76	22757.91
Year 2011-2012	22364.75	8378.94	2327.03	25439.37
Year 2012-2013	27634.36	12052.99	8568.29	29591.2
Year 2013-2014	38516.96	23138	15576	39318.36
Year 2014-2015	43397.7	24287	16321	48776.94
Year 2015-2016	54155.87	25098	16488	58091.04
Year 2016-2017	73634.17	32967	22409	72097.84

**Graph Of Sbi Mutual Fund Asset Management Company
Profit And Loss Statement, From Year 2010 To 2017**

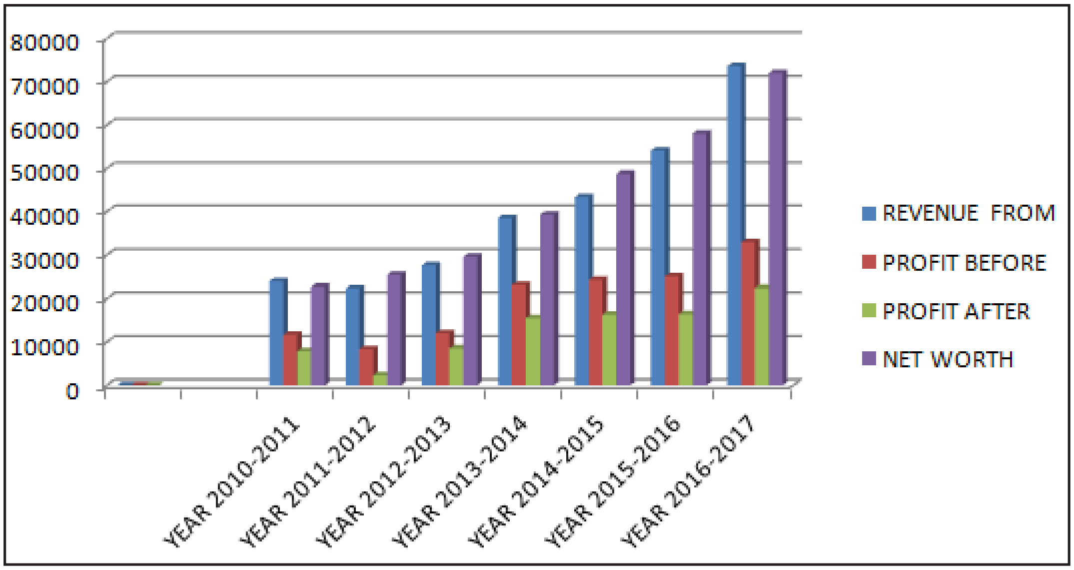

Profit And Loss Statement Of Hdfc Mutual Fund Company From Year 2010 To 2017

Years	Revenue From Operations	Profit Before Tax	Profit After Tax	Net Worth
Year 2010 Mar	624.94	316.29	208.36	394.87
Year 2011 Mar	680.76	355.78	242.17	478.96
Year 2012 Mar	633.32	381.49	269.14	577.13
Year 2013 Mar	715.72	446.82	318.75	676.75
Year 2014 Mar	858.54	522.45	357.77	876.01
Year 2015 Mar	1022.43	622.6	415.5	1094.64
Year 2016 Mar	1442.54	708.25	477.88	1126.05
Year 2017 Mar	1480.03	799.8	550.25	1397.77

Graph Of Profit And Loss Statement Of Hdfc Mutual Fund, From Year 2010 To 2017

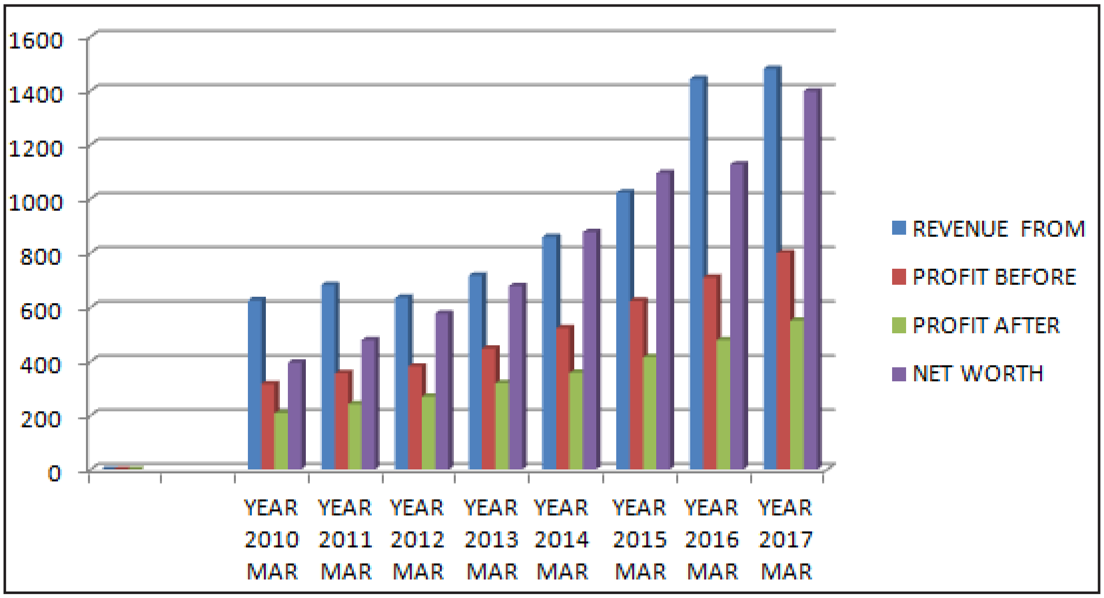

****

A Comparative Study Of Job Satisfaction Among Day And Night Shiftemployees

Anjali Gupta* Jeesha Boyat**

Abstract - India is a land of emotions feeling belongingness and skilled worker as well, in this technical world more than 60% of the population working in different sectors of industry as skilled and unskilled, permanent and temporary, employee or as labour people are busy with the machine and they are spending less time with their family members and with their self so we find difficult to understand with feelings others have, in fact we can say that we are not able to understand what we feel for our self as we don't have a time to spend for our self and affecting our personal life. In this research we try to find out job satisfaction level on the basis of parameters economical, health and psycho-social conditions of employees working in day and night shift. This study particularly conducted in Indore city. A structured questionnaire was prepared and data were collected from 100 employees which include 50 from day shift and 50 from night shift.

Introduction - Job Satisfaction may be defined as the collection of feelings and beliefs people have about their current jobs. A person with high level of job satisfaction holds a positive attitude towards his/her heir job while persons with negative job satisfaction hold a negative attitude towards their job.

According to **Vroom** "Job satisfaction is generally considered to be an individual perceptual or emotional reaction to important part of work."

According to Keith Davis "Job satisfaction is a set of the favourable or unfavourable feelings with which employees view their work."

A traditional job requires a employee to work under 9am to 5pm schedule. But Shift work is work that takes place on a schedule outside the traditional 9am to 5pm day. It can involve evening or night shifts, early morning shifts, and rotating shifts. Many industries which require continuous production and timely delivery of their product and services rely heavily on shift work, and millions of people work in jobs that require shift schedules.

Review Of Literature -

BiranchiN.Puhan (1999) - This study result reveal that the employees of public & private sectors differed significantly in their job & work involvement. Demographic variables such as age, length of service, monthly income & work experience in the present job also affected their job & work involvement. However gender of the employees did not influencethese variables.5s were dissatisfied with their family and social life.

Fred Luthans (2005) - This review says that, Job satisfaction as involving cognitive, effective and evaluative reactionsor attitudes, and satesit is a pleasurable or appraisal of ones job or job experience. Job satisfaction is a result of employee perception of how well their job provides those things that are received as important. It is generally recognized in the organizational behaviour field that job satisfaction is the most important and frequently studied attitude. Some factors influence on job satisfaction ex pay, promotion, supervision, working condition etc. who are promptedon the basis of performance is more satisfied then who are prompted on the basis of seniority..

Rational of study - Day by day India is becoming a global market. So like other countries Indian industries have started to develop 24*7 working culture. So by adopting these work culture by Indian industries how criteria of job satisfaction among day and night shift employees ischanging and this study provide some insight to industries that how would they provide proper job satisfaction to employees working under different shifts.

Objectives -

1. To find out satisfaction level of employees working among day and night Shift.
2. To study the impact of economic, health and psycho-social conditions on employees.

Hypothesis -

H_1- There is Significant difference occurs on the basis of shift system in job satisfaction.

H_0-No significant difference occurs on the basis of shift system in job satisfaction.

Research Methodology -

Research design - The research design will be Comparative research because in this study we will be

*Professor, Sanghavi Institute Of Management And Science, Indore (M.P.) INDIA
**Professor, Sanghavi Institute Of Management And Science, Indore (M.P.) INDIA

comparing level of job satisfaction on the basis of shift system.

Sample design - Here we are taking random sample design because we collect data randomly from day and night shift employees.

Research Tool - We are using likerd scale (5 point Scaler) in questionnaire for collecting primary data.

Research Framework - (Diagram See in the next page)

Sampling for data -

No of Respondents

S.No	Shift	Number	Percentage
1	Day	50	50
2	Night	50	50
	Total	**100**	**100**

Respondents Demography On The Basis Of Age

S.No	Age	Night	Perce - ntage	Morning	Perce - ntage
1	20-30	25	25	11	11
2	31-40	24	24	26	26
3	41-50	1	1	10	10
4	51-60	0	0	3	3
	Total	**50**	**50**	**50**	**50**

Respondents Demography On The Basis of Gender

S.No	Gender	Night	Perce - ntage	Morning	Perce - ntage
1	Male	35	35	28	28
2	Female	15	15	22	22
	Total	**50**	**50**	**50**	**50**

Respondents Demography on the Basis Of experience

S.No	Experi- ence	Night	Perce - ntage	Morning	Perce - ntage
1	0-3	22	22	15	15
2	3-7	24	24	13	13
3	7-15	3	3	15	15
4	More Than 15	1	1	7	7
	Total	**50**	**50**	**50**	**50**

Respondents Demography on the Basis of Marital status

S.No	Marital status	Night	Perce - ntage	Morning	Perce - ntage
1	Married	7	7	33	33
2	Unmarried	43	43	17	17
	Total	**50**	**50**	**50**	**50**

Result and Discussion -

Health Condition 1.1

Health Condition	Day Shift	Night Shift
Have you lost much sleep over worry?	120	156
Do you think your shift system negatively affect your health?	139	178
Do you think you are not taking proper care of your health/ yourself?	132	170
Do you feel you have lost or gain too much weight since you have started working in your current shift?	150	171
Do you think occurrence of body pain/ backache/ headache has been started/ increased since you have started working in your current shift?	170	180
Total	711	855

Table No 1.2

	Day shift	Night shift
Total	711	855
Mean	14.22	17.1

Table No 1.2 shows the health condition of the employees reveals that the Day shift employees obtained a raw score is 711 with mean of 14.22. The night shift employees obtained a raw score is 855 with mean of 17.1. It reveals that day shift employees are well-satisfied then night shift employees on the basis of health conditions.

Economic Condition 2.1

Economic condition	Day shift	Night shift
Are you happy .with regard to economic advantages like salary, allowances, Provided by your company.	120	112
Are you happy with facility provided by your company like medical facility, travelling allowances.	132	121
In some emergence after me,my job has provisions to offer job to my children orfamily, ex gratia grants etc.	105	102
Total	**357**	**335**

Table No 2.2

	Day Shift	Night Shift
Total	357	335
Mean	7.14	6.7

The table no.2.2 indicates thatthe economic condition (Salary, allowance, medical care) of the day & night shift employees. It reveals that the day shift employees obtained a raw score is 251 with mean of 10.04 and the night shift employees obtained a raw score is 239 with mean of 9.56. This result shows that day shift employees are satisfied then night shift employees in the area of Economic condition. But there is no much difference because bothare getting same facilities from the company.

Psycho-social conditions 3.1

Psycho-social condition	Day Shift	Night shift
Are you able to spend quality time with your family/ friends/ partner?	178	150
Do you feel that your social life is quite normal as like others?	155	135

Psycho-social condition	Day Shift	Night shift
Are you able to join family or social get together or family/ friends outing most of the times?	172	132
Are you able to get involved in important decisions or discussions of your family/ friends?	172	155
Are you able to equally participate in sharing the family/ friends work load/ distribution?	175	146
Total	852	718

Table No.3.3

	Day shift	Night shift
Total	852	718
Mean	17.04	14.36

Table No 3.3 shows the Psycho-social condition of the employees reveals that the Day shift employees obtained a raw score is 852with mean of 17.04. The night shift employees obtained a raw score is 718 with mean of 14.36. It reveals that day shift employees are well-satisfied then night shift employees on the basis of Psycho-social conditions.

Hypothesis Testing - AS from above given tables we find out that day shift employees are more satisfied as compare to night shift employees in terms of health, economical and psycho-social conditions.so our null hypothesis is rejected and so that alternate hypothesis (H1) is accepted.

Major Findings - According to our study following findings came into light;

1. Youngsters (Age between 20 to 35 Years) prefer night shift as compared to middle age group employees.
2. As compared to female, male prefer more to work in night shift as only 30% female prefer to work in night shift.
3. Employees who just started their career prefer more to work in night shift. In long run people prefer to work in morning shift as only 6% employees choose to work in night shift for more than 10 years.
4. Unmarried people are more comfortable with night shift jobs as compared to married people as only 14% married people choose to work in night shift.

Conclusion - Satisfaction is the relative phenomena it is mental, physical, economical, and social state of person. A satisfied man is an important asset to the society like wise a satisfied employee in an important gift to the organization. The job satisfactioncannot be achieved by single factor Thefactors are wages, supervisions, working condition, recognition and scope of advancement etc., determines the level of job satisfaction. For achievement of grater or higher level of job satisfaction the actual needs of employees have to be fulfilled. Increase in the level of job satisfaction will be beneficial not only to the employee but also for the organization in which he works.

References :-

1. Jadimurthi Hudeda, Sanjay Gandhi, 3Dhruva B Jyothi (September 2015) “Comparative Study on Job Satisfaction of Day And Night Shift Workers” A Case Study of Falcon Tyres Ltd., Mysore.
2. Keith Davis (2002) Organizational Behavior (Human Behavior at Work), 11th edition, Tate McGraw Hill Publishing Company Limited.
3. https://oshwiki.eu/wiki/Job_satisfaction:_ theories_ and_definitions.
4. Fred Luthans (2005) Organizational Behavior, Tenth Edition,McGraw Hill / Irwin New York.
5. https://www.researchgate.net/publication/ 322675588_Comparing_the_effects_of_ Day_and_ Night_shift_on_employees_job_satisfaction_ A_case_ study_at_Cement_Industry

Research Framework

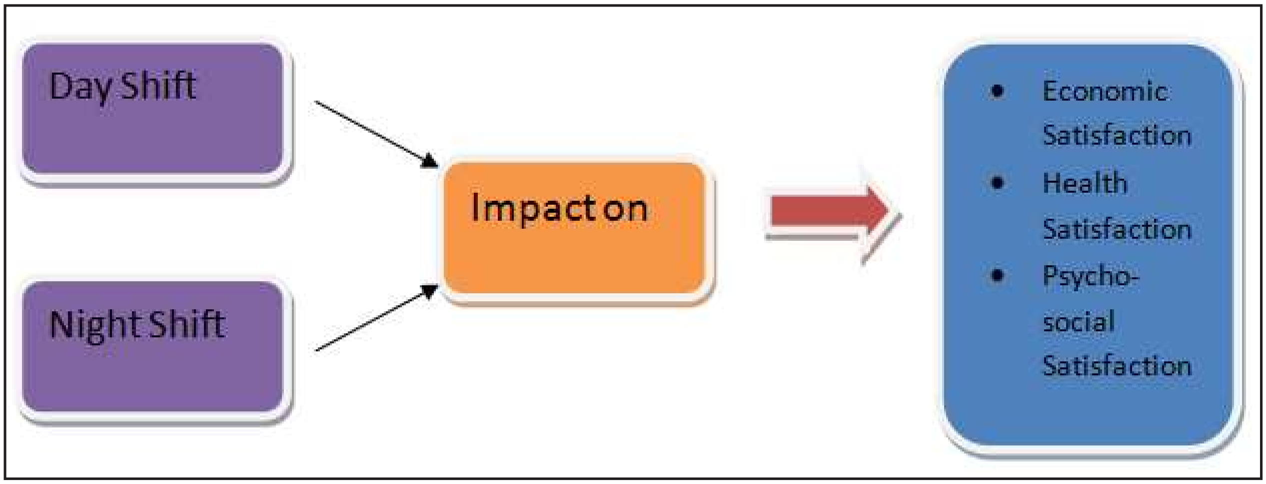

****

Maheshwari Sarees - A Story Of Royalty Told In Warps And Wefts

Dr. Snigdha Bhatt*

Abstract - Witnessing a glamorous wedding ceremony of a beautiful Indian Bride dressed in a bright orange and red silk saree with golden motifs made me wonder about the rich cultural heritage of India. The case focuses primarily on the handloom weavers of Madhya Pradesh, the central Province of India famous for its rich Maheshwari and Chanderi Handloom art. It's a small step to visualize the state of weavers of this rich heritage in terms of financial soundness , skills development , technological up gradation and efforts by union and state government to motivate them both financially and non financially through specially designed schemes and programs .The Case will try to address the structural changes that drives the trends in the fashion industry with emphasis on technological and societal perceptions transformation.

Key Words - Handloom, Heritage, Revive, Microfinance, Government Schemes, Marketing.

Introduction - Handlooms is one of the remarkable portrayal of India's rich Diversity of Culture that reigns from not only the multi-linguistic, multiple religions or culinary but many sources. The heritage of Indian Handlooms as is old as the Indus valley Civilization that was one of the prime export items from time immemorial for the Indian Economy. Industrialization changed the functioning of world economic system in 19th century and the way forward was the mechanization for producing standard quality of output in huge volumes. The fight against the evils of mechanization and automation for existence based on the unique skills of the weavers that passes from generations to generations began under British colonial period and followed post independence due to indebtedness of weavers.

The Textile sector of India could be sub divided primarily into Handlooms, Power looms and the Mill segment based on the differentiation of modern technology, capital, and volume of outputs often competing for the same market share. As of the total handlooms work force 76% (29.08 lakh weavers) constitute the adult workforce (in their productive years) out of which 64% are full time engaged in weaving but nearly two third had no formal education.

However looking at the declining number of weavers the Government had appraised the sectors with differentiated policy schemes to restructure the sector acknowledging the potential of employment generation and generating foreign res reserve apart from fulfilling the fuelled domestic consumption demand, with the changes in demographics and lifestyle in Indian Subcontinent working in hands with Government. The dearth of credit indebtedness and strong dominance of the modernized power looms on the Indian Textile market has posed a major threat on sustainability and profitability of the overall Indian Handloom Industry and handlooms of Madhya Pradesh are facing the brunt of same.

Handloom Production India

Year	Cloth Production	Exports
2007-08	6947	NA
2008-09	6677	NA
2009-10	6806	1252
2010-11	6907	1575
2011-12	6901	2624
2012-13	6952	2812
2013-14	7104	2233
2014-15	7203	2246

Rehwa Society - Handloom weaving dates the ancient history of some 1500 years back. Maharani AhilyabaiHolkar are said to be the one who contributed to a great extent for the rebirth of this art, she ruled at that time from 1765 to 1795, the former state Indore. By the time of India's partition in 1947, the local families who use to promote this elite art work earlier began declining and as a result quality of work and income of weavers both diminished. To cope up with the issue Holkar dynasty took initiative to establish Rehwa Society in 1978, the main founders were Richard Holkar and Sally Holkar. Central Welfare Board provided the fund grants to set up this society. The beginning of this formal society had only eight handlooms at that time, but the concrete objectives of Rehwa made what it is today. The society had their goal to provide sustainability of Handwoven tradition of Maheshwar district.

Objective Of The Study - The aim of the study is for creating an understanding that has led to declining use of handloom textiles. Thus it lays emphasis on : Studying the

*Asst. Professor, Shri Jain Diwakar Mahavidyalaya, Indore (M.P.) INDIA

Behavioral changes within the consumers of different age groups and their preference for purchasing handloom products.

To analyze the socio economic conditions along with knowledge of awareness level of weavers of various government schemes at state and central level to support the weavers and handlooms industry .It a minuscule step to ascertain the limitations and opportunities for Handlooms industry and weavers of Madhya Pradesh. Since both the Quantitative and Qualitative data was used for data analysis. Chi Square test was applied on consumer data while percentages were used on data collected from weavers to draw a broad outlook and rational conclusion to suggest relevant measures.

Loom Mahesahwari Sari - The Maheshwari sari, a favourite among women of all ages, was also designed by a woman. For making fabric for the royalty, queen Ahilyabai brought weavers from Surat and designed a unique sari, with motifs inspired by the local architecture and a striped Pallav. It was, and remains, an exemplar of graceful simplicity, yet refined and sophisticated.

The understated elegance of a Maheshwari sari is complemented by the subtle attributes that make it different. The Maheshwari sari has are versible border, so it can be worn on both sides. It also has a unique pallav with five stripes, two white and three coloured ones, alternating. The sari is usually plain, or has stripes or checks in its field, with geometric motifs decorating the borders. The motifs are usually fine abstract representations of local elements like flowers, leaves, and the local architecture. Maheshwari sarees went on to become a huge hit in the royal and aristocratic circle. Today, this beautiful textile is one of the best sellers in both national and international markets.

Special Features - Besides its understated elegance, these sarees are loved by women for its glossy finish and light weight. Though originally done only in silk, Maheshwari sarees are now available in cotton, silk cotton and even wool. With fine cotton yarns in its weft and silk in the warp, this light and airy fabric has the soft lustre of silk. The light fabric makes it a perfect choice for women all through the year, something you can't do with textiles like Kanjeevaram and Banarasi.

Colours - Originally, Maheshwari sarees were woven in earthy shades like maroon, red, green, purple and black. Weavers used only natural dyes for the yarn. Today, Maheshwari fabrics are woven in many jewel tones which are derived from chemicals rather than from flowers, roots and leaves. Popular colours today include shades of blue, mauve, pink, yellow and orange, mixed with gold or silver thread. Subtle colours and textures are created by using different shades in the warp and weft. Gold thread or zari is also used in Maheshwari sarees to weave elegant motifs on the body, border and pallu.

Motifs - Maheshwari sarees are distinguished by their vibrant colours, unusual combinations and distinctive designs that include stripes, checks and floral borders. Authentic Maheshwar is have designs that are inspired by the grand temples, palaces and forts of Madhya Pradesh. Popular designs include the mat pattern, which is also known as chattai pattern, along with Chamelikaphool - all of which may be traced back to the detailing on the walls of Maheshwar Fort. Through its evolution, the eent (brick) pattern and the heera (diamond) patterns have survived the test of time, and still have a strong presence in these sarees.

Functional Perspective Of Weaving Art

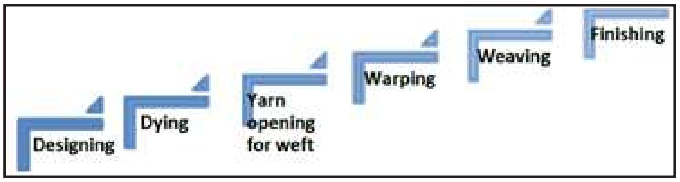

- Designing
- Dying
- Yarn opening
- Warping
- Weaving
- Finishing

Initiatives Of Indian Government - The Indian Government had initiated many schemes to uplift weavers (especially after the third census in the year 2009-10) for bringing sustainability and profitability to the sector. Few of them are -

- Loan Waivers of overdue loans and revival of handloom cooperative societies for working capital needs / Term Loans at interest rates of 6% for 3 years and margin money assistance upto Rs 10,000 per weaver for individual weavers, Self Help Groups, Joint Liability Group and Master weavers under Revival Reform Restructure Package.
- State level enforcement wing to monitor the activities to safeguard the interest of weavers ensuring infrastructure, technical and managerial aids.
- Block level Cluster development for sustainability in highly competitive market and formulating development schemes for product development, Designing, Marketing, Credit Assistance, Training and other managerial assistance.

Measures Taken By Madhya Pradesh Government -

The State government is working tirelessly to improve the socio economic life style of weavers of Madhya Pradesh by various financial and non-financial schemes. The government collaborated with banks cooperative societies for various purposes like technically upgrading the looms, credit/ marketing assistance, ensuring supplies through yarn depots, etc. It tied up with designers (NIFT and others) and developers to gain strong Market presence.

The government is persistently to provide seamless support to weavers through Marketing & distribution, Design intervention and Cluster development that adds thrust to the knowledge repository for ecological tourism and economic independence. It started with exclusive handlooms showroom “Mrignaynee” in 1961 that markets handlooms and handicraft Providing a platform to weavers. It show cases their skilled art regularly through Bhopal Haat, Exhibitions, Trade Fairs in prominent cities without any fees from weavers.

Crisp an Indo German conglomerate of MP Government also organizes periodic training programs of design and development. It started the e procurement and export oriented units to take care of design development, marketability and documentation. The Rehwa society of the Holkar dynasty is also working persistently since 1978 to protect the linage of Maheshwari sarees. They noticed the lifestyle changes owing to demographics and suggest aesthetic changes adding modernity bringing handlooms in suits, bags, bed-sheets, home accessories. It’s continuous efforts of the Rehwa society and the government has made it a global name crossing the borders of Madhya Pradesh to various domestic (Mumbai, Delhi etc) and International markets (France, UK, Germany etc).

Limitations - The study is a reflection of a small group of respondents of Madhya Pradesh which mirrors the broad problems generalizing the topic. The limitations faced due to paucity of time and resources had reserved it to a narrow scope however the scenario may be different for the other regions giving a different interpretation. Thus it has a large scope of further enrichment in the same region with different factors and other regions included.

Suggestions - The Handloom Sector being a major bread earner for the rural economy should take bring innovative measures which cater to uneducated and diversified class of people. The major setback for the government measures is unawareness about majority of the schemes among the weavers and their accessibility. The majority of weavers find difficulty in loan documentation, managerial works like marketing etc apart from limited access to modern means of communication and transportation due to limited resources .While the sheen of handlooms is declining among customers due to lack of promotions, change of taste and lifestyle.

Conclusion - Emerging trends of globalization has shaken up the roots of the traditional heritage of handlooms, that is competing with the automation and standard quality products both from domestically and international players too. This had a huge impact on employment and living standard of people dependent over it but Indian Economic Growth rate and exports too. Government had taken many measures to enhance the competitiveness of the handlooms by ensuring steady supply of raw materials and other resources at subsidized prices along with training, marketing and other assistance. However being the roots of the sector belongs to rural, uneducated and marginalized people that is still not ventured to find out the grass root problems. Thus it will some more time and persistent efforts of government along with social groups to put the things in right frame by working amongst them for them.

References :-

1. “Handloom schemes, Cluster Development, Annual Reports, Budgets”, Office of the Development Commissioner (Handlooms) Ministry of Textiles, India portal file:///C:/Users/Lenovo/Desktop/handloom%20case/ DEVELOPMENT% 20COMMISSIONER %20 (HANDL OOMS), Ministry%20of% 20Textiles. html” Mrignaynee: Textile
2. Emporium of M.P, M.P Laghu Udyog Nigam ltd” file:/// C:/Users/Lenovo/Desktop/handloom%20case/ MPLUN.html

****

Mobiling Manufacturing - A Source Of Services

Roshni Siddiqui*

Abstract - Media and telecom industry is developing speedily in India and all over the world. Its technology has affected the daily life style and change the human activities and being part of human life. Internet mobile are important need of human being. It is expected that this industry will create 86 lack job upto 2022 and only in mobile manufacturing 38 lack jobs will available. This is increasing 10% annually as per estimate mobile service market will be 37 million dollar and upto 2019. The number of smart phones will arrive 18 crore. According to data of march 2016 India is the second biggest telecom network user in the world with 1005.88 crore and internet user are in india 34.26 crore and third place of the world.

The job of this manufacturing sector are different types providing better salary and opportunities in future 86 lack in employment will create next six year and only mobile manufacturing sector will provide six lack jobs annually.

Introduction - In present era mobile instrument has influenced the each area of life. This magic minor instrument has changed the whole life style. This manufacturing sector is increasing very speedily. It has covered not only urban areas but far rural areas are also affected with this communication services. In present life internet and mobile are the undivided part of common life. Due to the expansion in all over country, Opportunity of services has also expanded in this area. It is estimated that service condition and salaries will be provided in better ways. Therefore the common life of service men of this sector will be satisfactory and more acceptable.

Research Methodology - Most of the data collection for this research are optained from secondary collection system. Interview was also organised with service men involving this field. Tabulation of data analysis performed in view to search aimed subject.

Hypothesis -

1. Mobile manufacturing is not in satisfactory stage in india.
2. Specific person may obtained job in this sector.
3. Sufficient salary and facilities perhaps will not provide to workers.
4. Employment cannot be solved satisfactory through this sector.

Objective -

1. To find out the opportunity of job in mobile manufacturing sector.
2. To find out the future development of mobile manufacturing to observe a large number of unemployed persons in this job.
3. The service of this sector may with satisfactory and sufficient salary be provided.
4. Future of this manufacturing sector be bright it will try to give suggestion.

Description - Mobile manufacturing and jobs - Mobile manufacturing is being a best source of jobs creating. The young educated persons like to survey in this sector because it service is neat and clean and beyond of any problem. Now trend professionals are being demanded in telecom sector very speedily.

Therefore telecommunication engineering is a best option for student in order to get job smoothly. Designing of Telecom device operation and manufacturing included in telecommunication education. A telecommunication engineer maintains network quality control and construct product. For getting job in mobile manufacturing (10+2) passed bachelor may inter in telecommunication engineering. He should pass maths, physics and chemistry. This selection for entrance in BE or B - Tech course have to score sufficient's mark in JEE entrance test. Beside this a student take admission diploma and B.Sc course most of institution the admission is provided on the base of entrance exam. For further education ME or M -tech course in the telecommunication are also available for admission. Engineering graduate have several possibility of services in telecom sector. As engineer, test engineer, application engineer and installer job can also achieve in telecom engineering telephone and mobile industry. Inspite of these they get job in cable and satellites network and broadcasting sector, telecommunication service provides companies.

The salary package is decided of telecommunication engineer according to industry. Experience and training, help to decide salary. The salary of engineer is more in

* Research Scholar (Commerce) A.P.S.University, Rewa (M.P.) INDIA

private companies in comparison of government companies. In this sector a fresher can get per month salary package all about 15 - 20 thousand rupess and after some year he can get 35 - 40 thousand rupees salary package per month.

Table - 1

Statement of mobile customer (in crore)

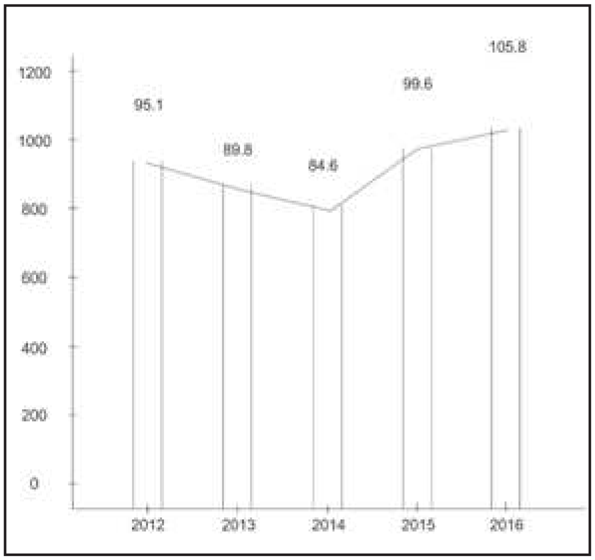

Source - Telecom regulatory authority of India

As above graph the user of mobiles in 2012 were 95.1 crore and decreased in 2013 and become 89.8 crore and also decreased in 2014 and become 84.6 crore then the customer used more mobile upto 99.6 crore in 2015 and very rapidly increased upto 10.58 crore in 2016. The overall progress of mobile customers are in increasing order and it is more expected upto end of year 2016. The double will become in comparison of 2012 and the reason of this growth is the several kind of services are provided mobile and there services and quality is being increased G- 1, G -2, G-3, G-4 and in future perhaps it will cover other services as well.

Table - 2 **(See in the next page)**

According to above piller graph there were 2.53 crore internet user in 2012 and it increased very rapidly upto 23.9 crore after only year 2013 and in 2014 internet user increased upto 26.7 crore, 30.2 crore in 2015 and in 2016 they are 34.2 crore and at the end of the year the user will also increased. Therefore the internet user increased 13 times in last four years the future of this services is very bright. Expansion of education and awareness in the society. The user will be of every age of life child to senior citizens. Due to the increasing user mobile manufacturing sector will develop and it will provide several dimensions of service to the mobile user. Technology of mobile and handling system are also improving and it is helpful to increase number of users.

Sumup - Mobile manufacturing is very developing sector. The user of mobile and internet have covered a big part of society to fillup the demand according user choice mobile manufacturing is also changing it's design operating system, durability and outlook, providing different size and shape colour, handling process etc.

It is expected that this manufacturing sector will able to provide a large number of job with attractive salary package better facilities and promotion process. The security of services and better promotion with increasing salary package will helpful to develop this manufacturing field.

References :-

1. Bhaskar laksh 21 Nov 2016 page No. 9
2. Information from telecom regulatary authority of india
3. Economic survey 2016
4. India annual book 2016.

Table - 2 - Statement of internet user (in crore)

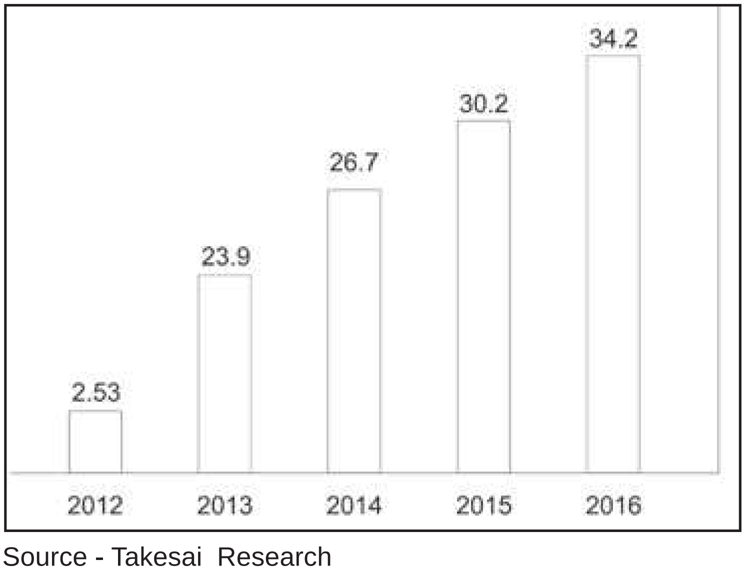

Source - Takesai Research

****

E-Waste Management And Its Effect On Environmental & Human Health A Review

Dr. Shweta Singh*

Abstract - Electronic waste or E-Waste refers to unwanted obsolete or unusable electronic and electrical products. Ever increasing usage of electronics and electrical equipments has resulted in piling up of e-waste. Waste of electrical and electronic apparatuses generated in huge amount surround the earth today, and has become a global environmental issue. The current and the future production of e-waste, the potential environmental problems associated with their disposal and management practices are discussed whereas the existing e-waste management. E-wastes are considered dangerous, or certain components of some electronic products contain materials are the harmful, depending on their condition and density. The harmful contents of these materials pose a threat to human health and environment in India encounters many challenges like the difficulty in inventorization, in effective regulations pathetic and unsafe conditions of informal recycling, poor awareness of consumers and reluctance on the part of the stakeholders to address the issues. As a result toxic materials enter the waste stream with no special precautions to avoid the known adverse impacts on the environmental and human healths as well as resources are wasted when economically valuable materials are dumped. The purpose of this paper is to find out various issues related to e-waste and suggest strategies for effective e-waste management in India.

Introduction - E-waste comprises of waste generated from used electronic devices and household appliances which are not fit for their original intended use and are destined for recovery, recycling or disposal. Such wastes encompasses wide range of electrical and electronic devices such as Computers, Hand held cellular phones, personal stereos, including large household appliances such as refrigerators, air conditioners etc. E-waste contain over 1000 different substances many of which are toxic and potentially hazardous to environment and human health, if these are not handled in an environmentally sound manner. This is largely due to increasing market penetration of products in developing countries, development of a replacement market in developed countries and a generally high product obsolescence rate, together with a decrease in price and the growth in internet use.

As per current estimates e-waste is growing almost three times the rate of municipal solid waste globally. [1] E-waste being one of the largest sources of heavy metals and the fastest growing waste streams has become a serious problem in china and other developing nations. These countries not only generated tremendous amount of domestic e-waste due to their fast consumption rates of electrical and electronic products, but also receive enormous quantities of used information Technology devices from overseas. In China e-waste largely recycled by the informal sector, Where numerous waste recycle workers are hired at extremely low wages applying crude and pollutive recycling methods for separation of reusable components and quick recovery of contained metals. These backyard practices often take place under the waste. E-waste from developed countries finds an easy way into developing countries in the name of free trade. India is a developing country from the last decades increase in population & change of lifestyle, the demand of using electronic products is increased. In India e-waste generation is growing at 15%& is expected to cross 8,000,000 tons per year in 2012. A central pollution control board (CPCB) report said 65 cities in India generate more than 60-70% of the total e-waste which comes from 10 States that's are followed by Maharashtra, Tamilnadu, Andhra Pradesh, Utter Pradesh, West Bengal, Delhi, Karnataka, Gujarat, Madhya Pradesh and Punjab in the list of e-waste generating States in India. It is an emerging problem as well as a business opportunity of increasing significance, given the volumes of e-waste being generated and the content of both toxic and valuable material in them. The fraction includes iron, copper, aluminium, gold and other metals in e-waste is over 60%, while plastic account for about 30% and the hazardous pollutants comprise only about 2.70%. Today, electrical and electronic waste is the fastest growing stream. In the last years, there is an increasing acknowledgement of our impact on the environment due to our lifestyle, while the need to adopt a more sustainable approach concerning our consumption habits emerges as of particular significance. This trend regards industrial sectors affecting the

*Asst. Professor (Commerce) S.S. Memorial Mahavidyalaya Sutiyani Mod Takha, Eawah (U.P.) INDIA

consumption habits and especially, electronic industry where the short life cycles and the rapidly developing technology have led to increased e-waste volumes. The majority of e-waste elements are led to landfills.

However, their partial recyclability due to their material composition along with the unavoidable restrictions in landfills has led to the development of retrieval techniques for their recycling and re-use, highlighting the significance of e-waste recycling not only from a waste management aspect but also from a valuable materials retrieval aspect. According to the Basel convention, wastes are substances or objects, which are disposed of or are intended to be disposed of, or are intended to be disposed of, or are required to be disposed of by the provisions of national laws.

Recently a joint inspection report by central pollution board (CPCB) union environment ministry and Utter Pradesh Pollution Control board (UPPCB) found 27 illegal e-waste industries operational in utter Pradesh These units were dumping the waste into the Rmgang causing irreparable damage to the river and its surrounding environment .

This incident highlight the silent crisis building up in India . The country's burgeoning population on mobile phones has seen stupendous growth in the last decade. From 310 million subscribers in 2001 to 1.1 billion in 2016, the number of mobile phone user in India is nearly 4 time that of united sates today and it is second only to china in the world, which has 1.3 billion subscribers .

That is just mobile phone than there are 57 million computers in use and plethora of other gadgets and consumer electronics. but mass scale use of electronic goods has a huge flip side .India is now in the global list of highest electronic waste generators posing grave threat to the envirment and public alike .electronic waste or e-waste as it is popularly known causes toxic emissions and poses several health hazards.

E-Waste In India - In 2016 India was ranked as the fifth largest generator of electronic waste in the world .a study conducted the associated chambers of commerce and industry of India (ASSOCHAM) and KPMG in 2016 ranked India among one of the top five countries in e waste generation with an estimated 1.85 million tones generated annually . Globally the number is an astounding 40to 50 million tones annually. India accounts for roughly 4 % of e waste generated annually. The United States ranked first in e waste annually. China raked second with 6.1 million tons of e-waste every years.

Effects Of E-Waste - The effects of improper disposal of this e waste on the environment are little known; these impacts nonetheless pose very real threats and dangers to the global environment at large improper disposal of these electronic wastes affect the soil, air and water components of the environment.

Effect on air - One of the most common effect of e –waste on air is through air pollution . For example a British documentary about Lagos and its inhabitants, called welcome to logos shows a number of land fills scavengers who go through numerous landfills in logos , looking for improperly disposed improperly disposed electronics which includes wires, blenders, etc., to make some income from the recycling of these wastes. These men were shown to burn wires to get the copper (a very valuable commodity) in them by open air burning which can release hydrocarbons into the air.

Effects on water - When electronics containing heavy metals such as lead, barium, mercury, lithium (found in mobile phone and computer batteries), etc., are improperly disposed, these heavy metals leach through the soil to reach groundwater channels which eventually run to the surface as streams or small ponds of water. Local communities often depend on these bodies of water and the groundwater. Apart from these chemicals resulting in the death of some of the plants and animals that exist in the water, intake of the contaminated water by humans and land animals results in lead poisoning. Some of these heavy metals are also carcinogenic.

Effects on soil - In this way, toxic heavy metals and chemicals from e-waste enter the "soil-crop-food pathway," one of the most significant routes for heavy metals' exposure to humans. These chemicals are not biodegradable—they persist in the environment for long periods of time, increasing the risk of exposure.

These dangers posed by improper disposal on the environment ultimately have impacts on human beings - human cost; the health effects of these toxins on humans include birth defects (irreversible), brain, heart, liver, kidney and skeletal system damage. They also significantly affect the nervous and reproductive systems of the human body. When computer monitors and other electronics are burned, they create cancer-producing dioxins which are released into the air we breathe. If electronics are thrown in landfills, these toxins may leach into groundwater and affect local resources. Thus improper disposal of e-waste not only has effects on the environment, it indirectly and ultimately poses grave dangers to humans and livestock.

Issues Related To E-Waste In India -

1. **Volume of E-waste generated -** India stands fifth in e-waste generation producing around 1.7 lakhs metric tonnes per annum (Thomas Reuters, 2015)
2. **Involvement of Child Labor -** In India, about 4.5 lakh child laborers in the age group of 10- 14 are observed to be engaged in various E-waste activities and that too without adequate protection and safeguards in various yards and recycling workshops.
3. **Ineffective Legislation** - There is absence of any public information on most SPCBs/PCC websites. 15 of the 35 PCBs/PCC do not have any information related to E-waste on their websites, their key public interface point. Even the basic E-waste Rules and guidelines have not been uploaded. In absence of any information on their website, specially on details of recycle rs and collectors of E-waste,

citizens and institutional generators of E- waste are totally at a loss to deal with their waste and do not know how to fulfill their responsibility. (Sinha & Rambha, 2013). So, there is failure in successful implementation of Ewaste management and handling rules, 2012.

4. Lack of infrastructure - There is huge gap between present recycling and collection facilities and quantum of E-waste that is being generated. No collection and take back mechanisms are in place. There is lack of recycling facilities.

5. Health hazards E-waste - Contains over 1,000 toxic materials, which contaminate soil and ground water. Exposure can cause headache, irritability, nausea, vomiting, and eye pain. Recyclers may suffer liver, kidney and neurological disorders. Due to lack of awareness, they are risking their health and the environment as well.

6. Lack of incentive schemes - No clear guidelines are there for the unorganized sector to handle E-waste. Also no incentives are mentioned to lure people engaged to adopt formal path for handling E-waste. Working conditions in the informal recycling sector are only slightly worse than in the formal sector. (Skinner et al., 2010). No incentive schemes for producers who are doing something to handle e-waste. (Toxicslink, 2015)

7. Poor awareness and sensitization - Limited reach out and awareness regarding disposal, after determining end of useful life. Also Only 2% of individuals think of the impact on environment while disposing off their old electrical and electronic equipment

8. Reluctance of authorities' involved - Lack of coordination between various authorities responsible for E-waste management and disposal including the non-involvement of municipalities (ASSOCHAM, 2014)

9. High cost of sourcing e-waste - The ELCINA conducted a study in 2009, where a sample calculation of capital, operating costs, revenues etc. for an e-waste recycling project indicates the cost of sourcing e-waste as the largest portion of the operating cost. (ELCINA, 2009).

10. High cost of setting up recycling facility -

11. Lack of research -

Conclusions And Recommendations - There exist many hurdles to e-waste management in India. The major one is dominance of informal sector. So the steps should be taken to formalize the informal sector by strict implementation of rules and to levy heavy penalties on defaulters. The major challenges are to reduce E-waste through reuse, recycle, recovery and reduced use of toxic substances, to invent labor intensive intermediate technology to recycle / recover E-waste safely and to distribute the responsibility of managing E-waste on one or more stakeholders. Level of awareness should be increased using advertisements and e-waste issues should be included in curriculum. There is urgent need of an effective Reverse supply chain management of E-waste. In the reverse supply chain of E-waste would be collected from all kinds of resources, and it would be delivered to a processor that can recycle valuable parts from E-waste and dispose rest hazardous components in environmentally sound manner. The producer may buy those recycled valuable parts as raw material from the processor; therefore a close loop supply chain would be formed. In the process, companies can become more environmentally efficient through reusing and reducing the amount of materials used. Some guidelines to ensure the safe and secure recyding of used electronic are as follow :-

1. There is urgent need for a detailed assessment of the E-waste including quantification, characteristics, existing disposal practices, environmental impacts and the establishment of e-waste collection, exchange and recycling centers in partnership with private entrepreneurs and manufacturers.
2. There is need of an effective take-back program providing incentives for producers to design products that are less wasteful, contain fewer toxic components, and are easier to disassemble, reuse, and recycle may help in reducing the wastes and deposit/refund schemes to encourage consumers to return electronic devices for collection and reuse/recycling.
3. There is need of more recycling facilities and development of infrastructure to handle e-waste effectively.
4. Creat a comprehenhensive zero wasteaction plan
5. Increase diversion frome landfill by increaring utilization of the SMaRT Station
6. Ban – polystyrene take-out food containers
7. Educate the public on recyclable material processing and eco-consious purchasing practices
8. Provide accessible recycle bins in public places and business
9. Partner with local school districts to creat waste reduction and recycling programs in the school including a zrero waste lunch program
10. Implement amandatory organics / yard trimming recycling ordince and addition of organics materials such as food waste to the commercial waste collection program to increase diversion

With all the above said we all can be responsible citizens by being mindful of the dangers posted by e-waste to the invirnment and do as much as we can to protect our environment because ultimately e-waste does not just affect the environment .it ultimately affect us humans too/as well .

References :-

1. Statue report on e waste management in shri lanka. central environment authority aug 2010
2. Moef guidelines for management and handling of hazardous wastes 1991
3. Vijay et al . international journal of advanced research in computer science .
4. Environmental education – K .K .Shrivastava
5. Environmental performance index(2014)
6. E-waste status and management in india journal of informantion engineering and application 41-48

Impact On Organizational Culture In Government And Private College

Sukrati Rathore*

Abstract - This study examined the perception held by administrators of Govt. and Private Colleges with above average student's satisfaction about their institutions current and preferred organizational Culture and their own management competencies. This Study identifies implication for leadership of college culture linked to effective performance. The result build on existing evidence that dominant type, strength and congruence of culture are linked with performance effectiveness.

Introduction - This Research Paper throws light on work culture and its impact on employee's affectivity and

Efficiency. It analyzes the importance of healthy work culture, improvement of employees and organizational efficiency. The Paper proposes various ways of building an innovative work culture and importance of QWL (Quality of work life). The Researcher seeks to undertake a comparative study of the impact of work culture on faculty members of selected private colleges and government colleges.

The word work culture is made up of two words "Work + Culture". Work is defined as the tasks that need to be done by use of physical strength or mental power in order to do. Culture is defined as a cumulative crystallized and quasistable shared life style of people as reflected in the preference of some Cities of life over others (values) in the response predisposition towards several significant issues and phenomena (attitudes) in the certain affairs (rituals) and in the ways of promoting desired, preventing indescribable behavior (sanctions).

Culture is the complex mixture of assumption, behaviors, myths, metaphors and other ideas that fit together to define what it mean to be a member a particular society. Organization may develop their own unique culture that differentiates them from other organization within the industry or society.

Organization culture is the set of important understandings, such as norms, values, attitudes and beliefs shared by organizational members. Culture therefore, is how an organization learned to deal with its environment.

The study is conducted based on the available data for the required analysis and interpretation of data to establish the relationship between organization culture and work condition, organization culture and leadership style.

Objective of the study -

1. To study the organization culture of private colleges and government colleges.
2. To compare the working conditions of faculty members of private colleges, and government colleges.
3. To study the improvement of employees and organizational efficiency of private colleges and government colleges.
4. To suggest improvements in organization culture private colleges and government colleges.

Review Of Literature - It is Very Important to do Literature review on a topic before we apply research work on that topic. The Researcher in this matter Presented over view on Critical study of the topic which is as follows.

1. **Saharan (1989)** in his well-known book on Organizational Behavior published at New Delhi by JMG, has operationally defined it as the sum total of healthy experiences that individuals have in various facts of their life.
2. There has been ample evidence, shown among industrial workers **by Kornhauser** as early as in **1965**, who had observed a consistent relationship between dissection and measures of mental health,
3. **Warr, P.E. Cook, J.& Wall T**. **–** While developing measure of working life – refined and developed and published it in the journal of Occupational Psychology
4. **Hofstede (2006)** on the other hand explains the organizational culture in the form of onion that contains a number of layers and values that make the core of the organizational culture.
5. The importance of the organizational culture is also highlighted by **Schein (2004)** who stated that the culture can serve as strength as well as weakness to the organization.

Methodology - The current study aims at measuring the work culture and its effect on Professors and lecturer, and offering recommendations for improving the same and thus

***Research Scholar, AISECT University, Bhopal (M.P.) INDIA**

deductive methodology would be the appropriate choice as theory obtained from published works is tested empirically during the research. The inductive methodology is not chosen for this study because generation of new theory is not the purpose of this study.

Expected outcome of the proposed work - Work Culture plays an important role to identify and examine the internal environment of any organization. Work Culture tells information of the employees working. Work culture is today's hot issue to be discussed by various famous companies to increase the productivity of employees because work culture is the major player which puts impact on the working style and art of employees.

Work Culture in some of the organization plays the role of mentor or creator but in some organization it plays the role of demolisher. Work culture has significant influence on the attitudes and behaviors complied with values on the organization members.

Conclusion - This chapter is designed to familiarize you with the concept of organizational culture of colleges. We have covered methods organizations might use to address issues related to the way people behave at work, traditions and environment of college. In addition, you should now be familiar with the large number of factors, both within a government college and within the environment of private college that may influence a person's behaviors and attitudes. In the coming years, organization culture of colleges is likely to see a major shift in the way organizations function, resulting from rapid technological advances, social awareness, and cultural blending.

References : -

1. Biswas U & Nanda Mathew R(2001) Impact of perceived empowerment on Managerial Effectiveness
2. Borg 1(1991) on the relationship between importance and satisfaction ratings on job aspects.Applied Psychological International Review vol. 40 pg 93-104
3. Dafftuar C.N.L Nair, Priya(2001)"organizational culture"vol 57
4. E. H Scein(1995) Organisation culture & Leardship Jossey Bass, San Francisco
5. Iztak, Harpez(1988) variables effecting non financial employment commitment, applied psychological International review vol 31 pg 235-248

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

म.प्र. में औषधीय फसलों के उत्पादन का एक अध्ययन- नीमच जिले के विशेष संदर्भ में

अलका शर्मा * डॉ. एल.एन. शर्मा **

शोध सारांश - नीमच जिले में औषधीय फसलों में मैथी की उत्पादन दर में 2010-11 की तुलना में 2011-12 में 24.95 प्रतिशत की कमी हुई, जबकि 2012-13 में 97.30 प्रति. उत्पादन दर में वृद्धि, वर्ष 2013-14 में 26.19 प्रति. उत्पादन दर में कमी तथा 2014-15 में 19.5 प्रतिशत उत्पादन दर में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार अलसी के उत्पादन दर में 2010-11 की तुलना में 2011-12 में 0.75 प्रतिशत, वर्ष 2012-13 में 23.65 प्रतिशत, वर्ष 2013-14 में 45.39 प्रतिशत, वर्ष 2014-15 में 549.20 प्रतिशत उत्पादन दर में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार अजवान के उत्पादन में 2010-11 की तुलना में 2011-12 में 4.25 प्रतिशत उत्पादन दर में कमी वर्ष 2012-13 में 170.03 प्रतिशत उत्पादन दर में वृद्धि, वर्ष 2013-14 में 23.98 प्रतिशत एवं वर्ष 2014-15 में 24.81 प्रतिशत की उत्पादन दर में कमी हुई है। इसी प्रकार सुवा के उत्पादन में 2010-11 की तुलना में 2011-12 में 41.43 प्रतिशत वर्ष 2013-13 में 116.24 प्रतिशत उत्पादन दर में कमी हुई है तथा 2013-14 में 437.61 प्रतिशत वृद्धि वर्ष 2014-15 में 30.21 प्रतिशत उत्पादन दर में कमी हुई है। इसी प्रकार असालिया में 2010-11 की तुलना में 2011-12 में 78.64 प्रतिशत की उत्पादन दर में कमी, वर्ष 2013-13 में 60.27 प्रतिशत की वृद्धि, वर्ष 2013-14 में 29.82 प्रतिशत की कमी तथा वर्ष 2014-15 में 65.38 प्रतिशत उत्पादन दर में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार अश्वगंधा में 2010-11 की तुलना में 2011-12 में 16.32 प्रतिशत तथा 2012-13 में 5.20 प्रतिशत उत्पादन दर में कमी हुई है जबकि 2013-14 में 19.82 प्रतिशत तथा 2014-15 में 46.45 प्रतिशत उत्पादन दर में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार लहसुन में 2010-11 की तुलना में 2011-12 में 40.22 प्रतिशत उत्पादन दर में वृद्धि हुई है। वर्ष 2012-13 में 62.02 प्रतिशत वृद्धि, वर्ष 2013-14 में 0.87 प्रतिशत तथा 2014-15 में 7.58 प्रतिशत की उत्पादन दर में कमी हुई है। इसी प्रकार तारामीरा में 2010-11 की तुलना में 2011-12 में 21.34 प्रतिशत, 2012-13 में 54.03 प्रतिशत की उत्पादन दर में कमी, 2013-14 में 6.10 प्रतिशत तथा 2014-15 में 3.20 प्रतिशत उत्पादन दर में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार कलौंजी में 2010-11 की तुलना में 2011-12 के उत्पादन दर में 25.88 प्रतिशत, 2012-13 में 214.44 प्रतिशत की उत्पादन दर में वृद्धि, 2013-14 में 15.73 प्रतिशत तथा 2014-15 में 44.17 प्रतिशत उत्पादन दर में कमी हुई है। इसी प्रकार सफेद मुसली में 2012-13 की तुलना में 2013-14 में 400 प्रतिशत उत्पादन दर में वृद्धि एवं 2014-15 में 80 प्रतिशत उत्पादन दर में कमी हुई है।
शब्द कुंजी -औषधीय फसलें, जड़ी बूटी, हर्बल, अलसी, तारामीरा, कलौंजी, इसबगोल, सुवा, असालिया सफेद मुसली।

प्रस्तावना - वर्तमान समय में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हर्बल उत्पादों एवं जड़ी बूटियों की बढ़ती मांग जिसके कारण हर्बल उत्पादों के प्रति लोगों का झुकाव तथा व्यावसायिक स्तर पर खेती के अत्यधिक लाभकारी होने से म.प्र. में विशेष कर नीमच जिले में औषधीय तत्वों के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। गत दशक में इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि नीमच में यह वृद्धि 14 प्रतिशत है और भविष्य में और अधिक बढ़ने की संभावना है। गर्व की बात यह है कि औषधीय महत्व की पाई जाने वाली अधिकांश जड़ी बूटियां भारत में पाई जाती है। इस संदर्भ में म.प्र. अपेक्षाकृत ज्यादा सौभाग्यशाली है क्योंकि ज्यादातर प्रजातियां अकेले म.प्र. में पायी जाती है, जबकि नीमच जिला औषधीय फसलों के उत्पादन में प्रदेश में अग्रणी है। यहां अफीम, मैथी, अलसी, धनिया, अजवान, इसबगोल, सुवा, असालिया, अश्वगंधा, लहसुन, तारामीरा, कलौंजी, जीरा, असगंध बीज, चिरायता, बेहडा, आंवला, ग्वार, सतावरी, असगंध पत्ती, तुलसी बीज, तुलसी पत्ता, अरीठा, चिरायता बीज, कुसुम, राई, नीम पत्ती, निम्बोली, सौंफ, डोलमी, रतनजोत, नीम ग्लोई, अरण्डी, ग्वारपाट, आंवला गुठली, शंकपुष्पी, सफेद मुसली, कटली, करंज, असभ्रुसी, धमुका आदि औषधीय फसलों का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है।

शोध का उद्देश्य :

1. म.प्र. एवं नीमच जिले में औषधीय फसलों की आवश्यकता।
2. म.प्र. एवं नीमच जिले में औषधीय फसलों के उत्पादन तरीके का ज्ञान।
3. औषधीय फसलों से होने वाले लाभ ज्ञात करना।
4. औषधीय फसलों के उत्पादन में आने वाली समस्याएं ज्ञात करना।
5. औषधीय फसलों के उत्पादन विस्तार के तरीके ज्ञात करना।

शोध प्रविधि एवं क्षेत्र - प्रस्तुत शोध पत्र में म.प्र. के नीमच जिले में औषधीय फसलों के उत्पादन से संबंधित द्वितीयक संमकों का अध्ययन किया गया है तथा वर्ष 2010-11 से 2014-15 के पाँच वर्षो के उत्पादन संमकों का ही अध्ययन किया गया है। नीमच जिले में केवल चयनित औषधीय फसलों जिसमें मैथी, अलसी, अजवान, इसबगोल, सुवा, असालिया, अश्वगंधा, लहसुन, तारामीरा, कलौंजी तथा सफेद मुसली का ही अध्ययन किया है।

* शोधार्थी (वाणिज्य) विक्रम विश्व विद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

शोध की सीमाएँ – औषधीय फसलों का उत्पादन से अभिप्राय जो फसल कृषि उपज मण्डी में विक्रय हेतु लाई गई है। उसे ही उत्पादन के रूप में शोध पत्र में सम्मिलित किया है।

तालिका 1 – (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका के निष्कर्ष इस प्रकार है :–

(01) नीमच जिले में वर्ष 2010–11 में मैथी का उत्पादन 99631 क्वि. हुआ, जो वर्ष 2011–12 में घटकर 74773 क्विं. हो गया। इस प्रकार गतवर्ष की तुलना में 24850 क्विं. मैथी का उत्पादन कम हुआ और उत्पादन दर में 24.95 प्रतिशत की कमी हुई है। वर्ष 2012–13 में मैथी का उत्पादन 147533 क्विं. हुआ, जो गतवर्ष की तुलना में 72760 क्विं. अधिक रहा तथा 97.30 प्रतिशत उत्पादन दर अधिक हुआ। वर्ष 2013–14 में मैथी का उत्पादन 108890 क्विं. हुआ जो गतवर्ष की तुला में 38643 क्विं. उत्पादन कम हुआ तथा 26.17 प्रतिशत उत्पादन में कमी हुई। इसी प्रकार 2014–15 में मैथी का उत्पादन 130176 क्विं. हुआ, जो गतवर्ष की तुलना में 21286 उत्पादन अधिक रहा एवं 19.55 प्रतिशत उत्पादन दर में वृद्धि हुई है।

(02) नीमच जिले में वर्ष 2010–11 में अलसी का उत्पादन 663 क्विं. हुआ, जो वर्ष 2011–12 में बढ़कर 268 क्विं. हो गया। इस प्रकार गतवर्ष की तुलना में 0.75 प्रतिशत उत्पादन दर में वृद्धि हुई है, जबकि 2012–13 में अलसी के उत्पादन में और वृद्धि हुई और उत्पादन बढ़कर 826 क्विं. हो गया, जो गतवर्ष की तुलना में 158 क्विं. उत्पादन अधिक रहा तथा 23.65 प्रतिशत उत्पादन दर में वृद्धि हुई। वर्ष 2013–14 में अलसी का उत्पादन बढकर 1201 क्विं. हो गया, जो गतवर्ष की तुलना में 375 क्विं. अलसी का अधिक उत्पादन हुआ तथा 45.39 प्रतिशत उत्पादन दर में वृद्धि हुई। इसी प्रकार वर्ष 2014–15 में अलसी का उत्पादन 7797 क्विं. हुआ जो गतवर्ष की तुलना में 6596 क्विं. उत्पादन अधिक रहा तथा 549.20 प्रतिशत उत्पादन दर में वृद्धि हुई।

(03) नीमच जिले में वर्ष 2010–11 में अजवान का उत्पादन 13915 क्विं. का हुआ, जो वर्ष 2011–12 में घटकर 13324 क्विं. मैथी का उत्पादन हुआ। इस प्रकार गतवर्ष की तुलना में 591 क्विं. कम उत्पादन रहा तथा 4.25 प्रतिशत उत्पादन दर में कमी हुई। वर्ष 2012–13 में अजवान का उत्पादन 36019 क्विं. हुआ, जो गतवर्ष की तुलना में 22695 क्विं. उत्पादन अधिक हुआ तथा 170.03 प्रतिशत उत्पादन दर में वृद्धि हुई। वर्ष 2013–14 में अजवान का उत्पादन 27379 क्विं. हुआ, जो गतवर्ष की तुलना में 8640 क्विं. उत्पादन कम हुआ तथा 23.98 प्रतिशत उत्पादन दर में कमी हुई। इसी प्रकार वर्ष 2014–15 में 24122 क्विं. अजवान का उत्पादन हुआ, जो गतवर्ष की तुलना में 3257 क्विं. कम उत्पादन हुआ तथा 11.89 प्रतिशत उत्पादन दर में कमी हुई है।

(04) नीमच जिले में वर्ष 2010–11 में इसबगोल का उत्पादन 86167 क्विं. हुआ, जो वर्ष 2011–12 की में घटकर 40828 क्विं. हो गया। इस प्रकार गतवर्ष की तुलना में 45339 क्विं. उत्पादन कम हुआ तथा गतवर्ष की तुलना में 52.62 प्रतिशत उत्पादन दर में कमी हुई है। इस प्रकार वर्ष 2012–13 में इसबगोल का 117423 क्विं. उत्पादन हुआ, जो गतवर्ष की तुलना में 76595 क्विं. अधिक रहा तथा 187.60 प्रतिशत उत्पादन दर में वृद्धि हुई है। वर्ष 2013–14 में इसबगोल का उत्पादन 77500 क्विं. हुआ, जो गतवर्ष की तुलना में 39923 क्विं. कम उत्पादन हुआ तथा 34 प्रतिशत उत्पादन दर कमी हुई है। वर्ष 2014–15 में इसबगोल का उत्पादन 58273 क्विं. हुआ, जो गतवर्ष की तुलना में 19227 क्विं. उत्पादन कम हुआ तथा 24.81 प्रतिशत उत्पादन दर में कमी हुई है।

(05) नीमच जिले में वर्ष 2010–11 में सुवा का उत्पादन 432 क्विं. हुआ, जो वर्ष 2011–12 में घटकर 253 क्विं. हो गया। इस प्रकार गतवर्ष की तुलना में 179 क्विं. उत्पादन कम हुआ तथा 41.43 प्रतिशत उत्पादन दर में कमी हुई है। वर्ष 2012–13 में 117 क्विं. सुवा का उत्पादन हुआ, जो गतवर्ष की तुलना में 136 क्विं. उत्पादन कम हुआ तथा 116.24 प्रतिशत उत्पादन दर में कमी हुई है। वर्ष 2013–14 में सुवा का उत्पादन 629 क्विं. हुआ, जो गतवर्ष की तुलना में 512 क्विं. उत्पादन अधिक हुआ तथा 437.61 प्रतिशत उत्पादन दर में वृद्धि हुई है। वर्ष 2014–15 में 439 क्विं. सुवा का उत्पादन हुआ, जो गतवर्ष की तुलना में 190 क्विं. उत्पादन कम हुआ तथा 30.21 प्रतिशत उत्पादन दर में गिरावट हुई है।

(06) नीमच जिले में वर्ष 2010–11 में असालिया का उत्पादन 4761 क्विं. हुआ तथा वर्ष 2011–12 में उत्पादन घटकर 1017 क्विं. रह गया, जो गतवर्ष की तुलना में 3744 क्विं. कम उत्पादन हुआ तथा 78.64 प्रतिशत उत्पादन दर में कमी हुई है। वर्ष 2012–13 में असालिया का 1630 क्विं. उत्पादन हुआ, जो गतवर्ष की तुलना में 613 क्विं. अधिक रहा तथा 60.27 प्रतिशत उत्पादन दर में वृद्धि हुई। वर्ष 2013–14 में 1144 क्विं. असालिया का उत्पादन हुआ, जो गतवर्ष की तुलना में 486 क्विं. उत्पादन कम रहा तथा 29.82 प्रतिशत उत्पादन दर में कमी हुई। वर्ष 2014–15 में असालिया का उत्पादन 1892 क्विं. हुआ, जो गतवर्ष की तुलना में 748 क्विं. अधिक उत्पादन हुआ तथा 65.38 प्रतिशत उत्पादन दर में वृद्धि हुई है।

(07) नीमच जिले में वर्ष 2010–11 में अश्वगंधा का उत्पादन 13157 क्विं. हुआ तथा वर्ष 2011–12 में उत्पादन घटकर 11009 क्विं. रह गया, जो गतवर्ष की तुलना में 2148 क्विं. उत्पादन कम हुआ तथा 16.32 प्रतिशत उत्पादन दर में कमी हुई है। वर्ष 2012–13 में 10436 क्विं. अश्वगंधा का उत्पादन हुआ, जो गतवर्ष की तुलना में 573 क्विं. उत्पादन कम हुआ तथा 5.20 प्रतिश्त उत्पादन दर में कमी हुई है। वर्ष 2013–14 में 12505 क्विं. अश्वगंधा का उत्पादन हुआ है तथा गतवर्ष की तुलना में 2069 क्विं. उत्पादन अधिक हुआ तथा 19.82 प्रतिशत उत्पादन दर में वृद्धि हुई है। वर्ष 2014–15 में अश्वगंधा का 18514 क्विं. का उत्पादन हुआ, जो गतवर्ष की तुलना में 6009 क्विं. उत्पादन अधिक हुआ तथा 48.05 प्रतिशत उत्पादन दर में वृद्धि हुई है।

(08) नीमच जिले में वर्ष 2010–11 में लहसुन का उत्पादन 517270 क्विं. हुआ तथा वर्ष 2011–12 में उत्पादन बढ़कर 725347 क्विं. हो गया, जो गतवर्ष की तुलना में 208077 क्विं. अधिक उत्पादन हुआ तथा 40.22 प्रतिशत उत्पादन दर में वृद्धि हुई है। वर्ष 2012–13 में लहसुन का उत्पादन 1175242 क्विं. हुआ, जो गतवर्ष की तुलना में 449895 क्विं. अधिक उत्पादन हुआ तथा 62.02 प्रतिशत उत्पादन दर में वृद्धि हुई है। वर्ष 2013–14 में लहसुन का उत्पादन 1164968 क्विं. हुआ, जो गतवर्ष की तुलना में 10274 क्विं. उत्पादन कम हुआ तथा 0.87 प्रतिशत उत्पादन दर में कमी हुई है। वर्ष 2014–15 में लहसुन का उत्पादन 1076612 क्विं. हुआ, जो गतवर्ष की तुलना में 88356 क्विं. उत्पादन कम हुआ है तथा 7.58 प्रतिशत उत्पादन दर में कमी हुई है।

(09) नीमच जिले में वर्ष 2010–11 में तारामीरा का उत्पादन 3584 क्विं. हुआ तथा वर्ष 2011–12 में उत्पादन घटकर 2819 क्विं. हो गया।

इस प्रकार गतवर्ष की तुलना में 765 क्विं. उत्पादन कम हुआ तथा 21.34 प्रतिशत उत्पादन दर में कमी हुई। वर्ष 2012-13 में तारामीरा का उत्पादन और घटकर 1296 क्विं. ही रह गया। इस प्रकार गतवर्ष की तुलना में 1523 क्विं. उत्पादन कम हुआ तथा 54.03 प्रतिशत उत्पादन दर में कमी हुई है। वर्ष 2013-14 में तारामीरा का उत्पादन 1375 क्विं. हुआ, जो गतवर्ष की तुलना में 79 क्विं. उत्पादन अधिक हुआ तथा 6.10 प्रतिशत उत्पादन दर में वृद्धि हुई। वर्ष 2014-15 में तारामीरा का उत्पादन 1419 क्विं. हुआ, जो गतवर्ष की तुलना में 44 क्विं. उत्पादन अधिक रहा तथा 3.20 प्रतिशत उत्पादन दर में भी वृद्धि हुई है।

(10) नीमच जिले में वर्ष 2010-11 में कलौंजी का उत्पादन 11835 क्विं. हुआ तथा वर्ष 2011-12 में कलौंजी का उत्पादन बढ़कर 14898 क्विं. हो गया, जो गतवर्ष की तुलना में 3060 क्विं. उत्पादन अधिक हुआ तथा 25.88 प्रतिशत उत्पादन दर में वृद्धि हुई है। वर्ष 2012-13 में कलौंजी का उत्पादन 46845 क्विं. हुआ, जो गतवर्ष की तुलना में 31947 क्विं. उत्पादन अधिक हुआ तथा 214.44 प्रतिशत उत्पादन दर में वृद्धि हुई। वर्ष 2013-14 में कलौंजी का उत्पादन 39477 क्विं. हुआ, जो गतवर्ष की तुलना में 7368 क्विं. उत्पादन कम हुआ तथा 15.73 प्रतिशत उत्पादन दर में कमी हुई है। वर्ष 2014-15 में कलौंजी का उत्पादन 22040 क्विं. हुआ, जो गतवर्ष की तुलना में 17437 क्विं. उत्पादन कम हुआ तथा 44.17 प्रतिशत उत्पादन दर में कमी हुई है।

(11) नीमच जिले में वर्ष 2011-12 में सफेद मुसली का उत्पादन 01 क्विं. हुआ तथा 2012-13 में भी उत्पादन 01 क्विं. ही रहा जबकि 2013-14 में सफेद मुसली का उत्पादन बढ़कर 40 क्विं. हो गया। इस प्रकार गतवर्ष की तुलना में 400 प्रतिशत उत्पादन बढ़ा। वर्ष 2014-15 में सफेद मुसली का उत्पादन घटकर 08 क्विं. रह गया। इस प्रकार गतवर्ष की तुलना में 80 प्रतिशत उत्पादन दर में कमी हुई है।

औषधीय फसलों के उत्पादन में आने वाली समस्याएँ :

1. म.प्र. में आज भी कृषकों में अंधविश्वास, जागरूकता की कमी प्रशिक्षण व कौशल के अभाव में कृषि के अधिक लागत के चलते उत्पादन का घटता अनुपात।
2. कृषकों को आधारभूत सुविधाओं जैसे-बिजली, पानी, सड़क आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
3. कृषकों को बैंक लोन सुविधा आसानी से मुहैया नहीं हो पाती, और न ही शासन स्तर पर पूंजी की कोई विशेष योजना है।
4. कृषकों में शिक्षा अभाव के कारण सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हासिल करने एवं उनका लाभ लेने में असमर्थता महसूस करता है।
5. कृषकों के परिवार का आकार अत्यधिक बड़ा होना।
6. कृषि जोतों का आकार बहुत छोटा होना।
7. कृषि जोतों के छोटे आकार होने से आधुनिक यंत्रों का प्रयोग असंभव होना।
8. कृषकों द्वारा किए जाने वाले अनुउत्पादकीय कार्य अनियंत्रित है।

औषधीय फसलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु सुझाव :

1. औषधीय फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु ब्याज मुफ्त ऋण किसानों को प्रदान किया जाना चाहिए।
2. औषधीय फसलों के उत्पादन के भण्डारण की समुचित व्यवस्था होना चाहिए।
3. देश में आयुर्वेदिक दवाईयों पर **G.S.T.** नहीं लगाया जाना चाहिए।
4. देश में आयुर्वेदिक दवाईयों के अधिक उपयोग (प्रयोग) हेतु प्रोत्साहन किया जाना चाहिए।
5. औषधीय फसलों के उत्पादन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रचारित प्रसारित होना चाहिए।
6. औषधीय फसलों के उत्पादन जो कृषि उपज मण्डी में लाया जाता है, विपणन पश्चात् शीघ्र भुगतान होना चाहिए।
7. औषधीय फसलों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होना चाहिए एवं भावान्तर योजना का लाभ औषधीय फसलों के लिए भी होना चाहिए।
8. अधिक औषधीय फसलों के उत्पादन पर शासन द्वारा प्रोत्साहन योजना लागू की जाना चाहिए।
9. औषधीय उत्पादन हेतु कृषकों को कुशलतापूर्वक आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए।
10. कृषक ऋण व्यवस्था में ऋण दलालों व फर्जी ऋण प्राप्त व्यक्तियों के लिए कठोर दण्डनीय प्रावधान हो।
11. अफीम का उचित शासकीय मूल्य निर्धारण हो परिणाम स्वरूप अवैध व्यापार नियंत्रण हो सके।
12. औषधीय फसलों के विपणन में आने वाली समस्याओं का निवारण हेतु कृषकों को कार्यशालाओं व संगोष्ठियों के माध्यम से शिक्षित किया जाए।
13. उत्पादन लागत में कमी एवं भूमि की प्राकृतिक उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने हेतु जैविक खादों को उपयोग हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए।
14. अत्यधिक सिंचाई वाली फसलों के लिए वर्षा जल संग्रहण, डबरी निर्माण, तालाब, जलाशय आदि कार्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
15. औषधी फसलों के उत्पादन से जुडे क्षेत्रों को सरकारी बजट में सर्वोपरी एवं केन्द्रीय स्थान प्रदान किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. ए.के. बनर्जी-भारत में औषधी मूल्य निर्णारण प्रकाशक सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, योजना सन् अक्टूबर 2009 ।
2. मनीच कुमार प्रकाशक-ग्रामीण विकास मंत्रालय अगस्त 2007
3. डॉ. एन.एल. अग्रवाल-भारती अर्थव्यवस्था विश्व प्रकाशक, 1966 न्यू एज इन्टरनेशनल (प्रा. लिमिटेड) का प्रभाग दरियागंज नई दिल्ली।
4. औषधीय एवं सुगंधीय पौधे-द्वितीय संस्करण-उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. (सेडमैप) भोपाल।
5. कुरूक्षेत्र, मई 2002
6. नवीन शोध संसार (अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त ISSN 2320-8767
7. दिव्य शोध समीक्षा (अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका) ISSN 2394-3807

तालिका 1 – म.प्र. के नीमच जिले में औषधीय फसलों का उत्पादन

(क्विं. में)

क्रं.	औषधीय फसल	2010-2011	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	मैथी	99631	74773	147533	108890	130176
2	अलसी	663	668	826	1201	7797
3	अजवान	13915	13324	36019	27379	24122
4	इसबगोल	86167	40828	117423	77500	58273
5	सुवा	432	253	117	629	439
6	असालिया	4761	1017	1630	1144	1892
7	अश्वगंधा	13157	11009	10436	12505	18314
8	लहसुन	517270	725347	1175242	1164968	1076612
9	तारामीरा	3584	2819	1296	1375	1419
10	कलौंजी	11835	14898	46845	39477	22040
11	सफेद मुसली	-	01	01	40	08

स्त्रोत:-कार्यालय-कृषि उपज मंडी नीमच जिला नीमच (म.प्र.)

****

भारत के विकास में कोल इण्डिया लिमिटेड की भूमिका

डॉ. दीपचंद भावरकर *

शोध सारांश – आये दिन कोल इण्डिया के श्रमिकों की हड़ताल व तालाबंदी तथा प्रबंध संघर्ष की स्थिति बनती है। इससे कोल इण्डिया लिमिटेड को अधिक से अधिक नुकसान होने की हमेशा सम्भावना बनी रहती है। प्रबंध वर्ग एवं श्रमिक वर्ग में सीधा सम्प्रेषण की स्थापना करके हड़ताल व तालाबंदी जैसी परिस्थितियों से बचा जा सकता है। तथा प्रबंध के सिद्धांतों का परिपालन करते हुये हम उद्यौगिक सम्बधों को मजबूत करते हुये। कोल इण्डिया को समय–समय पर होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। नीचे दी गई समस्याओं एवं घटनाओं की रोक थाम के लिए वेकोल इण्डिया लिमिटेड के द्वारा से अधिक से अधिक प्रयास करते हुये रोकने का प्रयास करते हुये कामगारों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करते हुये कंपनी का संचालन किया जाता है। तो कंपनी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करते हुये अपना विकास एवं विस्तार कर सकती है। जिसके साथ ही संपूर्ण भारत का विकास जुड़ा हुआ है। वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड में 5 करोड़ 80 लाख का कोयला घोटाला 22 जुलाई 2009 को उपराजधानी स्थित सी.बी.आई. की भ्रष्टाचार निर्मूलक शाखा के चन्द्रपुर जिले में स्थित वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड की दुर्गापुर रैतवारी व माना कोयला खदान से निकले 5 करोड़ 80 लाख रूपये मूल्य के कोयला घोटाला का पर्दाफाश किया है। कोयला घोटाला मामले में वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड के दुर्गापुर रैतवारी खदान के सब एरिया मैनेजर ए.के. घोषाल मैनेजर मदन कुमार पर सी.बी.आई.आई.पी.सी. की धारा 120 वी. 409 तथा भ्रष्टाचार निर्मूलन कानून की धारा 13 (2) के तहत मामला दर्ज किया है,भवानी खदान में बड़ा हादसा टला माईंस में नहीं हो सका उत्पादन 25 अगस्त 2009 को गुढ़ी अंबाड़ा भवानी खदान का एक्जास्ट पंखा मोटर जलने के कारण बंद हो गया जिसके चलते माईंस के अंदर कार्य कर रहे रात पाली के मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ा खदान के अंदर हवा के स्तर को बनाये रखने के लिए यह पंखा लगाया जाता है। पंखा चलाने के माईंस के अंदर कामगारों को जरूरी आक्सीजन की मात्रा की पूर्ति की जाती है, लेकिन पंखा बंद हो जाता है तो पाली में कार्य करने वाले श्रमिकों को जहरीली गैसों का असर पड़ने लगता है। इसके साथ ही विस्फोटक गैसों का रिसाव भी खदान से हो सकता है। जिससे कामगारों की रक्षा के लिए पंखे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गलत डायरेक्षन से हुआ हादसा दमुआ की 26–27 भूमिगत खदान मे 30 जून 2009 को भूमिगत खदान में रात पाली के दौरान काम कर रहे। एक कामगार की मौत हो गई जब वह ट्रेक से उतरी हुई गाड़ी ट्रेक पर लाने का प्रयास कर रहा था घटना समय पर भूमिगत खदान में और भी लोग थे लेकिन गाड़ी अचानक घूमकर मृतक से टकरा गई जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई,वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के रोगी वाहन खुद हैं बीमार वेस्टर्न कोल फील्ड कन्हान क्षेत्र में संचालित कालरी चिकित्सा एवं क्षेत्रीय चिकित्सालय में रोगी लाने ले जाने के लिए रोगी वाहन तो है किंतु हालत इतनी खराब हो गई है कि इस वाहन में हार्न छोड़कर सब कुछ बजता है,समय से पहले हो गये शमीम बेग सेवानिवृत्त 15 जून 2009 रानवाड़ा निवासी कोयला खदान शमीम बेग को विगत वर्ष 60 साल की आयु दशति हुये प्रबंधन द्वारा सेवा निवृत कर दिया जबकि उनकी जन्म तिथि 1955 दर्शाये है। और वे अपनी उम्र 54 साल बता रहे है,कामगार की बेबा अधिकार पाने भटक रही नहीं मिली पुत्र को नौकरी पेंच क्षेत्र की विष्णुपुरी खदान नं. 02 में कार्यरत रहा लोडर राजेन्द्र बावरिया का वर्ष 2003 में आकस्मिक निधन हो गया था। इसके बाद उसकी पत्नि शारदा ने अपने पुत्र को नौकरी दिलाने दफ्तर के चक्कर काट काट कर परेशान हो गयी जबकि उन पर 5 बच्चे आश्रित है। आशा 26 साल, उषा 22 साल, रवि 20 साल,दीपिका 19 वर्ष और मिथुन 15 साल सहित अपना जीविका पार्जन करना कठिन हो रहा है,वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड क्वाटरों पर अवैध कब्जा कामगारों को परेशानी पेंच क्षेत्र की पुरानी क्वाटरों में गैर कामगारों द्वारा अवैध कब्जा जमाकर कंपनी की सुविधा का लाभ उठाकर वहीं नियमित कामगारों को कंपनी की मूलभूत सुविधा व्यवस्थाओं के लिये भटकना पड़ रहा है। मामले को लेकर श्रमिक संगठनों ने प्रबंधन के समक्ष आवाज उठाकर कार्यवाही की मांग दोहराई है,कामगारों को क्वाटरों के आदेश मिले लेकिन क्वाटर आज तक नहीं 25 अगस्त 2009 को कोयलांचल के सभी प्रमुख श्रमिक विभिन्न अवसरों एवं विभिन्न मंचों पर कंपनी क्वाटरों पर गैर कामगारों के कब्जा की मांग उठाते हुये पिछले दिनों शिवपुरी, रावनवाड़ा,छिंदा,परासिया, कंपनी की खाली क्वाटरों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जवानों को उपलब्ध करवाने के लिए छः माह पहले मुख्य प्रबंधक कार्यालय से आदेश जारी किये गये थें तो आदेश मिले लेकिन अभी तक क्वाटर नहीं मिले।

प्रस्तावना – सभ्यता के सौपान पर चढ़ते मानव जाति के इतिहास में अग्नि का विषिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान है। अग्नि में निहित रहती है ऊर्जा,ताप और प्रकाष ईंधन के रूप में उपयोग में आने वाला कोयला पांरपरिक ईधन की श्रेणी में आता है और यह ऊर्जा का अपूर्य श्रोत है। कोयला जीवाष्म है जिसके बनने की प्रक्रिया में लाखों वर्ष लग जाते है। मानव सभ्यता के दौर में कोयले का अविभाव बहुत पहले ही हो चुका था पर उसकी ज्वलनशीलता के गुण से कितने असाध्य कार्य साधे जा सकते है। इसका अंदाजा नहीं था। कोयला को पानी से वाष्प बनाने और वाष्प से विभिन्न मशीनों को चलाने की प्रक्रिया ने यूरोप में औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। इसी तरह मानव सभ्यता में कोयला द्वारा ही विज्ञान युग का प्रांरभ हुआ। प्रांरभिक काल में कोयला खनन पूरी तरह मानव श्रम शक्ति पर निर्भर था। खान में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं था और ना ही उन्हें उनके श्रम का उचित मूल्य दिया जाता था। निजी क्षेत्र के माध्यम से उत्पादित कोयला देश के औद्योगिक आर्थिक विकास के लिए अपर्याप्त था इन बातों के मद्दे नजर

* अतिथि विद्वान (वाणिज्य) श्री.श्री ल.ना.शा.स.पेंचव्हेली. पी.जी. महाविद्यालय, परासिया, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) भारत

कोयला उद्योग में भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की पहली कंपनी नेशनल कोल डेव्हलपमेण्ट कार्पोरिशन का गठन हुआ। सहभागिता की कार्य संस्कृति और कुशल प्रबंधन द्धारा कोल इण्डिया ने विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वर्ष 2016-17 कोल इण्डिया ने 14500 करोड़ रूपये भारत सरकार को लाभांश के रूप में प्रदान किया, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। लेकिन बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने पर सिंचाई सम्बन्धी और औद्योगिक इकाई के निर्विवाद गति से चलाने के लिए बिजली का होना अति आवश्यक है। वित्त वर्ष 2016-17 में कोल इण्डिया की बिजली क्षेत्र को कोयला आपूर्ति 19.15 करोड़ टन थी। इस शोध पत्र के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते है कि हमारे यहॉं 'कोल इण्डिया लिमिटेड' जिस पर सम्पूर्ण कोयलें के उत्पादन का दायित्व है। क्या वह अपना दायित्व पूर्ण ईमानदारी के साथ निभा रहा है। क्या सरकार समय समय पर 'कोल इण्डिया लिमिटेड' में अपनी निरीक्षण टीम भेजती है। जिससे 'कोल इण्डिया लिमिटेड' के भ्रष्टचार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा जा सके तथा उनके प्रति कड़ी कार्यवाही की जा सकें। कोल इण्डिया लिमिटेड की स्थापना एक होल्डिग कंपनी के रूप में नवम्बर 1975 में भारत सरकार के अधीन कोल इण्डिया लिमिटेड 8 राज्यों में फैली 21 प्रमुख कोयला खनन क्षेत्रों के साथ 471 खाने है। जिसमें 273 भूमिगत खान तथा 163 खुली खाने और 35 मिश्रित खान शामिल है। इसमें 17 कोयला परिष्करण सुविधाओं का भी संचालन किया जाता है। जिसमें समग्र फीड स्टाक क्षमता प्रतिवर्ष 39.40 मिलियन टन की है। हमारा उद्धेष्य प्रतिवर्ष 111.10 मिलियन टन की समग्र फीड बैंक क्षमता के 20 और कोयला परिष्करण सुविधाओं का विकास करना है। इसके अतिरिक्त 85 चिकित्सालयों एवं 424 औषधालयों की सेवाए भी प्रदान किया जाता है। 8 कोयला उत्पादन कंपनियो की 200 अन्य प्रतिष्ठनों के सहयोग से कोल इण्डिया ने देश के कुल कोयला उत्पादन में 84% की भागीदारी दर्ज की है। वर्तमान में 492000 कर्मचारी अधिकारी कार्यरत है। इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोल इण्डिया लिमिटेड एक वृहद वृक्ष का नाम है के माध्यमस से सम्पूर्ण भारत में काम करती है। जो क्रमश: ई.सी.एल., बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल., एन.सी.एल., डब्ल्यू.सी.एल., एम.ई.सी.एल., एम.सी.एल, एन.ई.सी. के नाम से जानी जाती है। मध्यप्रदेश में कोल इण्डिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी डब्ल्यू.सी.एल. जो कि म.प्र., महाराष्ट्र तथा झारखंड में भी डब्ल्यू.सी.एल. ने अपना नेटवर्क बनाये रखे हुए है, कोल इण्डिया लिमिटेड का आर्थिक विकास में योगदान मानव समाज के सम्पूर्ण विकास के लिए प्राचीन से ही ऊर्जा का अपना विशेष महत्व रहा है। जिसमें सौर ऊर्जा तथा पेट्रोल,डीजल, प्राकृतिक गैस एवं कोयला विकास में अपना विशेष स्थान बनाये रखे हुये है। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में कोयला अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। हम अपना सम्पूर्ण विकास एवं ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर तभी बन सकते है जब हमारे पास उच्च किस्म का कोयला भण्डारण अधिक से अधिक रहे जिससे हम बिजली का उत्पादन में वृद्धि करने के साथ-साथ रेलगाड़ी परिवहन के क्षेत्र में भी अपना विस्तार कर सकते है,बिजली उत्पादन एवं अधिक्य विक्रय कोयला का अधिक से अधिक उत्खनन करके हम पर्याप्त मात्रा मैं कोयला संग्रहण करके बिजली का उत्पादन अधिक से अधिक करके हम अपना विकास एवं विस्तार तो कर सकते है। इसके साथ-साथ हम बिजली का आधिक्य उत्पादन का अन्य राज्यों को विक्रय करने के साथ साथ हम अपनी वित्तीय क्षमता को भी बढ़ा सकते है। जिससे अधिक कल्याणकारी कार्य किये जा सकते है और अपना अधिक से अधिक विकास कर सकते है। वर्ष 2016-17 में बिजली के क्षेत्रों में कोयला आपूर्ति 19.15 करोड़ मिलियन टन है, रोजगार का विस्तार वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड कंपनी के सफलता पूर्वक संचालन एवं विस्तार से अधिक से अधिक रोजगार एवं जीविकापार्जन के साधनों को अधिक से अधिक मात्रा में विस्तार करके अधिक से अधिक लोगों को रोजगार की सुविधा मुहैया करा सकते है। जिससे सामान्य जनता अपना जीवन स्तर का विकास करके अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठा सकते है। जिससे मृत्यु दर में कमी की जा सकती है तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों में कमी लायी जा सकती है। 19 जनवरी 2017 के लिये मैनेजमेंट ट्रेनी के 1319 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है, रेलवे परिवहन का विस्तार कोयला का अधिक उत्पादन के माध्यम से परिवहन के क्षेत्र में अपना अधिक से अधिक विस्तार करके हम सुविधाओं को उपलब्ध कराने के साथ ही अधिक से अधिक आय कमा सकते है तथा अपनी वित्तीय स्थिति को अधिक सुदृढ़ बना सकते हैं सरकारी मुद्रा कोष को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सकता है। जिसके माध्यम से अधिक से अधिक जनकल्याणकारी कार्य किये जा सकते है। जिससे कि विकास को अधिक तीव गति मिल सकेगी, कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ माना जाता है क्योंकि भारत की 80% जनसंख्या गांवों में निवास करती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जीविकोपार्जन का साधन कृषि कार्य ही माना जाता है। पर्याप्त वर्षो के अभाव में बिजली के माध्यम से हम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करते हुए कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन सकते है तथा बढ़ती हुई मंहगाई (तुअर दाल 150 रू. प्रतिकिलो एवं शक्कर 44 रू. प्रतिकिलो) से छुटकारा दिलाया जा सकता है और कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में हम सफलता प्राप्त कर सकते है,नवीन उद्यौगों की स्थापना एवं विकास नवीन उद्योगों की स्थापना तभी की जा सकती है जबकि बिजली भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो जिससे रोजगार की मात्रा में वृद्धि की जा सकेगी, वित्तीय साधनों का विकास एवं विस्तार कर सकते है। जिससे अधिक से अधिक कल्याणकारी कार्य कर सकते है। जिससे हम अपना सम्पूर्ण विकास एवं विस्तार कर सकते है। तथा उद्यौगीकरण के क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व कायम रख सकते है,आय का प्रमुख व स्थायी साधन अधिक से अधिक कोयला का उत्पादन करके हम कोयला का निर्यात के माध्यम से विदेश मुद्रा का अधिक से अधिक संचय कर सकते हैं और विदेशी मुद्रा के क्षेत्र में हम अधिक से अधिक भण्डारण करने एवं संचय में कामयाब हो सकते है, नलकूपों का विस्तार एवं पानी के साधनों का विस्तार बिजली का अधिक से अधिक उत्पादन करके हम पृथ्वी के अंदर से पानी को निकालते हुये पीने योग्य पानी की मात्रा व भण्डारण के क्षेत्र में अपना विस्तार एवं देश की जनता को अल्प वृष्टि के समय पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जा सकता है।

निष्कर्ष - उपरोक्त घटनाओं एवं खामियों का अध्ययन एवं विश्लेषण करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी उद्यौग में श्रमिक इतना जोखिम पूर्ण कार्य नहीं करता जितना कि कोल इण्डिया लिमिटेड में श्रमिकों द्धारा किया जाता है। कामगार धरती के अंदर लगभग 5 कि.मी. से 10 कि.मी. तक का सफर तय करते हुये कोयला का उत्खन्न करते है। उसके पश्चात भी कोल इण्डिया लिमिटेड एवं वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की नितियों में भारी कमियों देखने को मिली तथा श्रमिकों को आश्रित को मिलने वाली सुविधाएँ नाम मात्र की होती है। चिकित्सा के क्षेत्र में किसी कामगार के आश्रित को भरती करते है तो चिकित्सक को रिश्वत देने के उपरांत ही वह सफलता पूर्वक ईलाज करता है नहीं तो चिकित्सा व्यवस्था केवल नाम मात्र

की होती है। कामगार की कार्य के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को तत्काल रोजागर की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाती तथा वे इसके लिए 5 से 6 साल तक दफ्तर के चक्कर काटते है उसके पष्चात भी उनसे रिष्वत मांगी जाती है। तब कहीं उन्हें नौकरी मिल पाती हैं कामगारों को क्वाटर की व्यवस्था के लिए भी अधिकारियों को 10,000/- से 20,000/- रिष्वत देने के उपरांत ही उन्हें क्वाटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यदि समय रहते हुए उपरोक्त अव्यवस्थाओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारे विशेषज्ञ श्रमिकों की इसी प्रकार से कमी होती चली जायेगी और वे.को.लि. का उत्पादन स्तर कम होने लगेगा जिससे हमारे प्रदेश व देश में उद्योगों की संचालन व्यवस्था तथा रेल परिवहन से संबंधित उद्योगों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा तथा कृषि क्षेत्र भी इससे अच्छुता नहीं रहेगा तथा बिजली की कमी के कारण कृषि उत्पादन भी कम होगा। जिससे मध्यम स्तर एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या में अधिक तीव्र गति से वृद्धि होगी इसके परिणाम स्वरूप हम अपनी आर्थिक स्थिति से भी कमजोर हो जायेगे तथा कोल इण्डिया लिमिटेड से प्राप्त लाभांश में भी कमी आयेगी। जिससे जनकल्याणकारी संबंधी कार्य नहीं किये जा सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. खनिज ऊर्जा अप्रैल 2008 अंक 35 नार्दन कोल फील्ड लिमिटेड सिंगरोली।
2. वार्षिक रिपोर्ट कोल इण्डिया लिमिटेड मुख्यालय कोलकाता। (2016-17)
3. खनन भारतीय डब्ल्यू.सी.एल. (अंक 76,1999,110-2005)।
4. समन्वय सम्मेलन दिनांक 23 अगस्त 97,डब्ल्यू.सी.एल.।
5. राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता- 5 स्मृति पत्र कलकत्ता 19 जनवरी 1996।
6. अंगार - कोयला परिवार का मासिक मुख्य पत्र आई.आई.जी.एम.द्धारा प्रकाशित।
7. वार्षिक रिपोर्ट कोल इण्डिया लिमिटेड मुख्यालय कोलकाता 2012-13।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

भारत संचार निगम लिमिटेड खंडवा का वित्तीय प्रबंधन - एक अध्ययन

ऋचिका डोंगरे * डॉ. प्रतापराव कदम**

प्रस्तावना - विश्व एक गॉव हे यह कहा जाता है। इसका आधार यह कि गॉव मे बात फैलने मे जितनी देर लगती थी। आज उतनी ही देर मे पूरे विश्व मे कोई भी बात, सूचना, समाचार उत्पादन की खबर फैल जाती है। इसी कारण विश्व कौ विश्वग्राम कहा जाता है। भारत संचार निगम लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र मे भारत सरकार की दूरसंचार कंपनी है। इसका गठन अक्टूबर 2000 मे हुआ जो की दुनिया की 7वी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी है तथा भारत की 4थी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी है। जो विभिन्न प्रकार की दूरसंचार सेवाऐं भारत मे प्रदान करती है। वायर लाईन सेवाऐं सी.डी.एम, जी.एस.एम, मोबाईल ,इन्टरनेट, ब्राडबेंड,करीयर सेवाए इत्यादी कम समय मे ही भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संस्थान बन गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड इसी तरह का एक उपक्रम है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली मे है। मध्यप्रदेश के निमाड़ अंचल के प्रमुख शहर खंडवा मे भारत संचार निगम लिमिटेड का कार्यलय भंडारिया रोड़ पर स्थित है। भारत संचार निगम लिमिटेड पूरे भारत मे उत्तम स्तर के नेटवर्क के विस्तार और सुधार कि ओर अग्रसर हो रहा है। यह अपनी सेवाऐं बड़ी संख्या मे ग्रामीण क्षेत्र मे भी प्रदान कर रहा है और यहा उपभोक्ताओ का विश्वास पात्र बना हुआ है यह एक स्वदेशी कंपनी है। जिसे हर भारतवासी अपनाना चाहता है यह जम्मूकश्मीर,अरूणाचल प्रदेश,अमरनाथ जैसे पहाडी इलाको मे भी सेवा देने वाला एक मात्र संचार कंपनी है। भारत संचार निगम लिमिटेड उपभोक्ताओ को संतुष्ट एंव खुश रखना और उनकी उम्मीद से अधिक सेवा स्तर प्रदान करना यह उपभोक्ताओ को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

भारत संचार निगम लिमिटेड एक मात्र सेवा प्रदाता है जो आई.सी.टी क्षेत्र मे ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन को भरने के लिए केन्द्रीत प्रयास कर रहा है। और पहल करने की योजना बना रहा है।वास्तव मे देश मे ऐसा कोई संचार प्रदाता नही है। इसकी पहॅुच दिल्ली व मुंम्बई को छोड़कर देश के प्रत्येक कोने मे इसके व्यापक नेटर्वक के माध्यम से जानकारी दी जा रही है।

इतिहास - भारत संचार निगम लिमिटेड के नाम से जाने वाली भारत संचार निगम लिमिटेड भारत का एक सार्वजनिक क्षेत्र संचार कंपनी है। इसका गठन 19वी सदी से प्रारंभ हो गया था जो की भारत संचार निगम लिमिटेड के रूप मे 2000 से कार्य कर रहा है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली मे स्थित है। इसके पास मिनी रत्ना का दर्जा है।

- प्रकार - सरकारी कंपनी
- उद्यौग - दूरसंचार
- स्थापना - 21वी सदी मे 2000
- मुख्यालय - नई दिल्ली भारत

मध्यप्रदेश मे इसका मुख्यालय भोपाल मे स्थित है। मध्यप्रदेश के निमाड़ अंचल के प्रमुख स्तिर खंडवा मे भारत संचार निगम लिमिटेड का कार्यलय भंडारिया रोड़ पर स्थित है। भारत संचार निगम लिमिटेड के पास 4 करोड 70 लाख लेंड लाइन है। 47.3 बेसिक टेलीफोन 4 मिलियन डब्लु.एल.एल कनेक्शन प्रदान किए हुए है। इसके 37822 स्थाई दूरभाष एक्सेचेंज है। इसके 18000 बी.टी.एस है। 287 सेटेलाईट स्टेशन है। 480196 कि.मी केबल का नेटर्वक है।भारत संचार निगम लिमिटेड अपने लाईसेंस क्षेत्र मुख्य सेवा प्रदाता है। कंपनी ने प्रत्येक उपभोक्ता के लिए उपयुक्त सबसे पारदर्शी और अत्याधीक रेंज वाली टेरिफ योजनाऐं प्रस्तुत की है। भारत संचार निगम लिमिटेड के सभी 2जी कनेक्शन मे 3जी सुवीधा दी गई है। मूल सेवाए मे भारत संचार निगम लिमिटेड ने विश्व स्तरीय मल्टी प्रोटोकॉल कनेक्शन आई.पी. इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापित किया है। जो समान आधार और ब्राडबेंड एक्सेचेंज नेटर्वक के माघ्यम से वॉईस, डाटा और विडियो जैसे सभी सुवीधाऐं प्रदान करता है।

परिकल्पना -

1. विश्व मे वही देश अग्रणी होता जो संचार मे अग्रणी हो।
2. प्रोद्यौगिकी का इस्तमाल कर संचार सुविधा सस्ती की जा सकती है।
3. भारत संचार निगम लिमिटेड एक अच्छी सुविधा प्रदान कर रहा है।

उद्देश्य -

1. देश मे संचार की स्थिति का पता लगाना।
2. नगरीय,उपनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रो मे भारत संचार निगम लिमिटेड की दृश्यता का पता लगाना।
3. ग्राहक सेवा की अभिवृत्ती के साथ विक्रय एवं मार्कटिंग टिम का संबंध सार करना।
4. भारत संचार निगम लिमिटेड सेवाओ की ओर ग्राहको की प्रसन्नता बड़ाने हेतु कार्य निष्पादन पर सशक्त फोकस के साथ एक पथ प्रदर्शक कार्य वातावरण का पता लगाना।

भारत संचार निगम लिमिटेड खंडवा के अधिकारीयो का कार्य विभाजन

टी.डी.ए.म

डी.ई	सी.ए.ओ
एस.डी.ई	ए.ओ
जे.टी.ओ	ए.ए.ओ
क्लर्क	जे.ए.ओ
	क्लर्क

*शोधार्थी (वाणिज्य) माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, खंडवा (म.प्र.) भारत
** माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, खंडवा (म.प्र.) भारत

कार्य विभाजन –

1. **टी.डी.एम (Telecome District Manager)** जिले का प्रबंधक होता है। जिसके उपर पूरे कार्यालय की जिम्मेदारी होती है। सब से बड़ी जिम्मेदारी उनपर कार्यविभाजन की होती है। सभी सहकर्मीयो को उनके कार्य क्षमता अनुसार कार्यविभाजन करना होता है। इन्हे कार्य प्रणाली भी बनानी होती है।

2. **डी.ई– (Divisional Engineer)** टी.डी.एम के अंतर्गत आते है जिनका कार्य टी.डी.एम द्धारा बनाए गए कार्यप्रणाली के अनुसार कार्य करना होता है और साथ ही ध्यान रखना होता हे की कार्य कार्यप्रणाली के अनुसार हो रहा है या नही। यह कार्य की जिम्मेदारी डी.ई.की होती है।

3. **सी.ए.ओ– (Chief Accountant Officer)** वाणीज्य विभाग से होता है जो की बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है कार्यालय का। इस कार्य के अंतर्गत साल के अंत मे चिट्ठा प्रस्तुत करना होता है। जिसमे कंपनी के लाभ हानी का पता चलता है। कितना दायीत्व है तथा कितनी संम्पत्ती है। यह पूरी जानकारी साल के अंत मे मिलती है इस जानकारी को प्राप्त करने हेतु सालभर के आंकड़ो का विश्लेषण करना होता है। यह कार्य ए.ओ. अपने अंतर्गत सहकर्मी को कार्य सोपते है।

4. **एस.डी.ई. (Sub divisional Engineer)** डी.ई के निर्देशो का पालन करना एस.डी.ई. का कार्य होता है।कर्मचारीयो को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न कार्यक्रमो को आयोजित करना होता है।

5. **जे.टी.ओ– (Junior Telecom Officer)** एस.डी.ई. कार्यक्रमो के कार्यप्रणाली को बनाता है जिसे जे.टी.ओ. द्धारा निष्पादन किया जाता है।यह कार्य प्रबंधक भी होता है। जे.टी.ओ. कर्मचारीयो को नियंत्रण करता है।

6. **ए.ओ. (Accountant Officer)** की अंतर्गत जितने भी विभाग होते हे उन सभी विभाग का समय–समय पर निरिक्षण करना, पैसो को समय पर बैंक मे जमा कराना, कैशबुक बनाना, बि.आर.एस. बनाना आदी ए.ओ. के कार्य होते है।

7. **जे.ए.ओ. (Junior Accountant Officer)** इनका कार्य ट्रायल बेलेंस, बी.आर.एस.,बनाना होता है एवं रिटायर अधिकारियो के दस्तावेज तैयार करना होता है एवं इनके अंतर्गत विभाग के कार्य की जानकारी ए.ए.ओ. को भेजना होती है।

8. **ए.ए.ओ. (Assistant Accountant Officer)** ए.ओ. के अंतर्गत आते है। इनके अंतर्गत भी निम्न विभाग आते है। ए.ओ. के द्धारा दिए गए निर्देशो का पालन करते है।

9. **क्लर्क** इनका कार्य समस्त अधीकारीयो के निर्देशो का पालन करना होता है। तथा फाइल को एक जगह से दुसरी जगह पहुँचाना होता है।

अधिकारियो की मासिक आय की स्थिति

क्र.	अधिकारी	मसिक आय
1	T.D.M	80000–90000
2	D.E	70000–80000
3	S.D.E	60000–70000
4	J.T.O	40000–50000
5	C.A.O	70000–80000
6	A.O	50000–60000
7	A.A.O	40000–50000
8	J.A.O	30000–40000
9	CLERK	20000–30000

भारत संचार निगम लिमिटेड की वित्तिय स्थिति

चल दायित्व

आज हम विगत वर्षो के चिट्ठो का विश्लेषण करे तो हमे तथ्य हासिल हो सकते है। विगत पॉच वर्षो मे चल दायित्व की स्थिति को हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते है।

तालिका क्रमांक 1.1

चल दायित्व की स्थिति

Year	Current liability
2007–08	4528886
2009–10	7401824
2011–12	3884271
2013–14	3974776
2015–16	4112663

(रेखा चित्र देखे आगे पृष्ठ पर)

रेखा चित्र से ज्ञात होता हे कि वर्ष 2007–08 मे चल दायित्व 4528886,जो वर्ष 2009–10 मे बड़ कर 7401824 हो गई 2011–12 मे 3884271 कम हो गई तथा 2013–14 मे 3974776 हो गई। इसका मतलब 90505 से चल दायित्व बड़ गई एवं 2015–16 मे बड़कर 4112663 हो गई।

चल सम्पत्ति – आज हम विगत वर्षो के चिट्ठो का विश्लेषण करे तो हमे तथ्य हासिल हो सकते है। विगत पॉच वर्षो मे चल सम्पत्ति की स्थिति को हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते है।

तालिका क्रमांक 1.2

चल सम्पत्ति की स्थिति

year	Current assets
2007.08	11180613
2009.10	11272040
2011.12	4822802
2013.14	3765489
2015.16	3614135

(रेखा चित्र देखे आगे पृष्ठ पर)

रेखा चित्र में चल संपत्ति को दर्शाया है। चल संपत्ति 2007 से 2016 तक लगत घटती जा रही है। जो 2007–08 मे 11180613 से 2009–10 मे घटकर 11272040 हो गई हे तथा 2011–12 मे घटकर 4822802 हो गई है एवं वर्ष 13–14 मे चल संपत्ति 151354 घटकर 3765489 हो गई पिछले वर्ष की तुलना मे वर्ष 15–16 मे चल संपत्ति घटकर 3614135 हो गई।

अचल दायित्व – आज हम विगत वर्षो के चिट्ठो का विश्लेषण करे तो हमे तथ्य हासिल हो सकते है। विगत पॉच वर्षो मे अचल दायित्व की स्थिति को हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते है।

तालिका क्रमांक 1.3 – अचल दायित्व की स्थिति

year	Non current liability
2007.08	1148911
2009.10	571622
2011.12	2286577
2013.14	2396890
2015.16	1209595

(रेखा चित्र देखे आगे पृष्ठ पर)

रेखा चित्र के अनुसार 2007-08 मे अचल दायित्व 1148911 एवं 09-10 मे घटकर 571622 हो गई तथा फिर वर्ष 11-12 मे बड़कर 2286577 हो गया। वर्ष 13-14 मे भी बड़कर 2396890 हो गया वर्ष 15-16 मे अचल दायित्व घटकर 1209595 हो गया।

अचल संपत्ति - आज हम विगत वर्षो के चिह्नो का विश्लेषण करे तो हमे तथ्य हासिल हो सकते है। विगत पॉच वर्षो मे अचल संपत्ति की स्थिति को हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते है।

तालिका क्रमांक 1.4

अचल संपत्ति की स्थिति

year	Fixed assest
2007.08	11833494
2009.10	13962048
2011.12	16195659
2013.14	14534587
2015.16	10009537

(रेखा चित्र देखे आगे पृष्ठ पर)

रेखा चित्र अचल संपत्ति को दर्शा रहा है। 2007-08 मे 11833494 मे बड़कर 13962048 हो गई 2011-12 मे भी अचल संपत्ति बड़ी हुई आई तथा 2013-14 मे अचल संपत्ति 1661072 से घट गई एवं 2015-16 मे 4525050 से अचल संपत्ति घट गई। वित्त का महत्व वही हे जो मानव शरीर मे रक्त का है। इसके कम ज्यादा होने पर वित्त प्रबंधन गड़बडा जाता है। यही बी.एस.एन.एल में देखने में आ रहा है।

संचार का महत्व स्वयं सिद्ध है, वही देश विकास की दौड़ में आगे आता है जो अच्छी व सस्ती संचार सुविधा प्रदान करता है हमारे देश में यह होना चाहिए।

रेखा क्रमांक 1.1

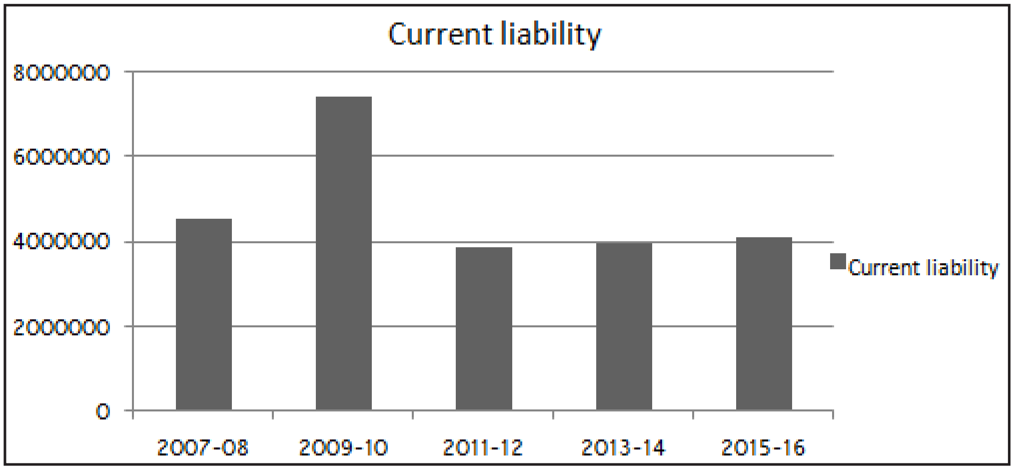

रेखा क्रमांक 1.2

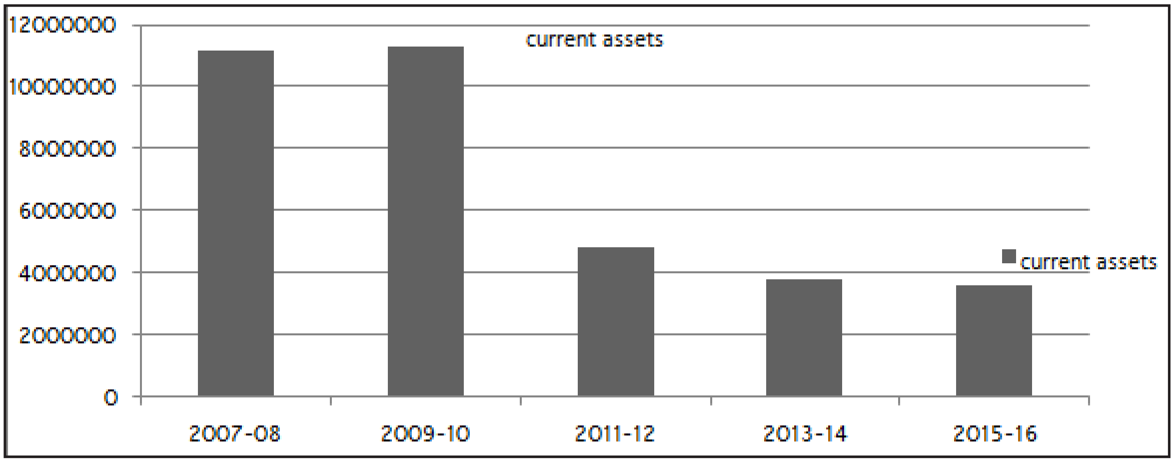

रेखा क्रमांक 1.3

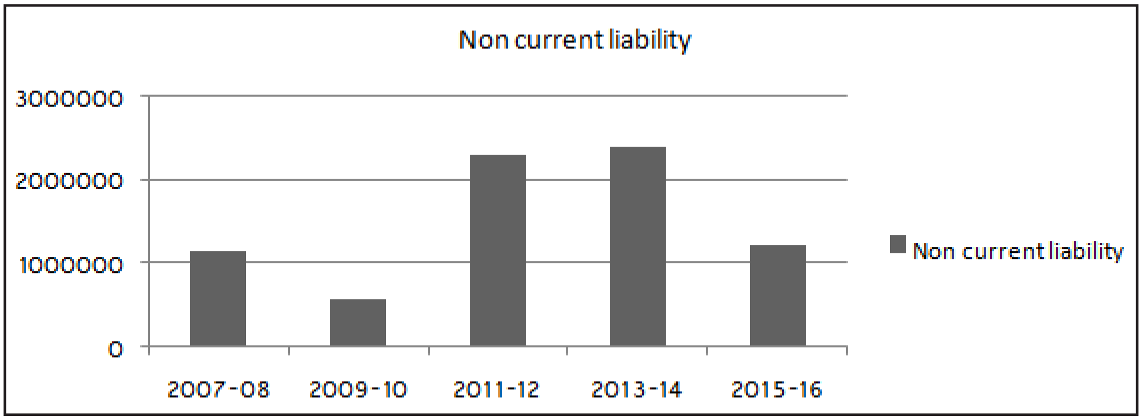

रेखा क्रमांक 1.4

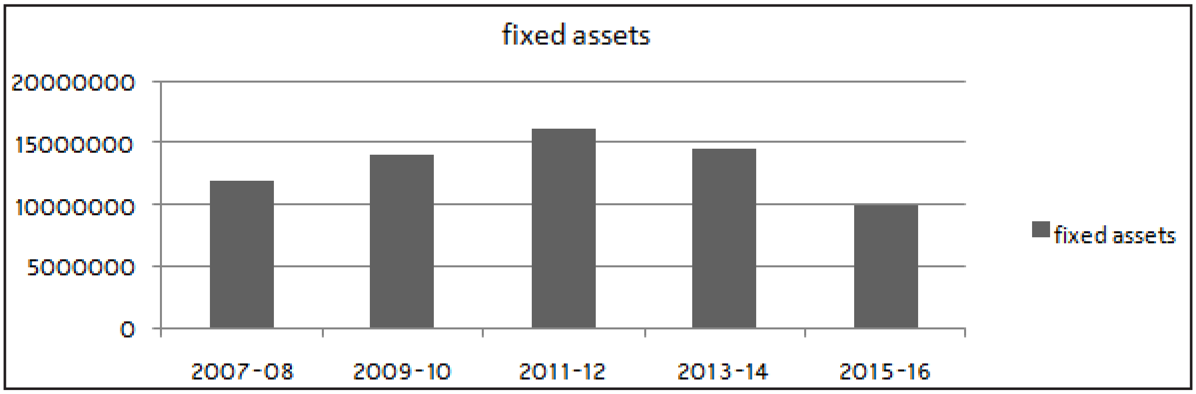

****

उद्यानिकी जैव विविधता

डॉ. दयाराम साहू *

प्रस्तावना – 'उद्यानिकी जैव विविधता से तात्पर्य ऐसी विविधता से है, जिसमें फल, फूल सब्जियाँ एवं शोभायमान वृक्षों से है। राज्य की जलवायु विविधता एवं भूमि की विविधता अनेक प्रकार के फल, सब्जियाँ एवं पुष्पों की आवश्यकता के अनुकूल है। मध्यप्रदेश, भारत के हृदय स्थल में स्थित है। उद्यानिकी जैव विविधता को तीन भागों में बाँटा गया है।' फल देने वाले वृक्ष, सब्जियाँ देने वाली वनस्पतियाँ, शोभा उत्पन्न करने वाले वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएँ तथा शाकीय वनस्पतियाँ आदि।

फल देने वाली विविधता – फल देने वाले वृक्षों को दो भागों में विभाजित किया गया है-

(अ) ऐसे फल जो व्यापारिक रूप में उत्पादन किया जाता है जैसे-आम, अमरूद, नीबू, लेमन, संतरा, मोसम्बी, केला, पपीता, अनार, लीची, चीकू, कटहल, सेव, नासपाती आदि।

(ब) ऐसे फल जो वानकीय रूप में लगाये जाते है या वनों में पाये जाते है जैसे- बेर, आँवला, बेल, कमरख, खिरनी, चिरौंची, जामुन, फालसा, महुआ, भिलवा, तेन्दू, कत्था, सीताफल, इमली आदि। ये फल भी पोषक तत्वों के दृष्टिकोण से उपयोगी होते है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इनका उपयोग सफलतापूर्वक किया जाता है।

सब्जियाँ देने वाली विविधता :- इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को शामिल किया जाता है जैसे फल, पुष्प, तना, पतियाँ तथा जड़ों को पकाकर खानें में उपयोग किया जाता है। टमाटर, बैंगन, मिर्च, आलू, प्याज, मटर, भिंडी, बरबटी, फूलगोभी, कुम्हड़ा, लौकी आदि प्रमुख सब्जियाँ है।

शोभा उत्पन्न करने वाली विविधता को चार भागों में विभाजित किया गया है।

- **शोभायमान उद्यानिकी विविधता:-** इनका उपयोग सौंदर्यीकरण के लिए किया जाता है। जैसे गुलमुहर, अमलताश, अशोक, कदम्ब, जैकरान्डा, पेल्टाफोरम, कपोक, कचनार, लाल-चम्पा, आकाशनीम आदि।
- **शोभायमान झाड़ियाँ:-** इसके अन्तर्गत गार्डीनिया, बोगेनविलिया, रात-रानी, हरी-चम्पा, जासोन, जैसमीन, रूकमणी, लाल कनेर, पीला कनेर, मधुकामनी, सुनहला चम्पक, चाँदनी आदि।
- **शोभायमान लताएँ:-** इसके अन्तर्गत एलामान्डा, माल्ती, लता, रेल्वेक्रीपर रंगूनकीपर, चमेली, कौरव-पाण्डव, माध्वीलता पोथम आदि।
- **अन्य शोभायमान विविधता:-** इसके अन्तर्गत शोभायमान पौधे गुलाब, सेवन्ती, डहलिया, कैक्टस, ऑर्किड, जल उद्यान, फर्न, पाम, शाकीय वर्षीय पौधों को षामिल किया गया।

मध्यप्रदेश में उद्यानिकी जैव विविधता – 'मध्यप्रदेश प्रकृति से सजा सवरा प्रदेश है। केन्द्रीय भारत की अनेक महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल भी हमारे प्रदेश में स्थित है, जिनके जल ग्रहण क्षेत्रों को वनाच्छादित रखने का दायित्व भी राष्ट्रीय हित में प्रदेश पर ही है। मध्यप्रदेश के वृक्ष जैव विविधता से परिपूर्ण है। जहाँ एक और ग्वालियर, भिंड, राजगढ़ आदि में झाड़ीदार वन है। वहीं दूसरी ओर मण्डला, बालाघाट, डिण्डोरी एवं शहडोल में विशाल वृक्ष वाले सागौन एवं साल वन है। देश के प्राचीनतम रहवासी आदिवासियों का प्रमुख आवास स्थल मध्यप्रदेश ही है।' वनों का संरक्षण, संवर्धन एवं विकास वन विभाग द्वारा किया जाता है। वनों के अन्दर और उसके आस-पास रहने वाले ग्रामीणों को रोजगार के अतिरिक्त लघु वनोंपज, छोटी इमारती लकड़ी जलाऊ, बांस, चारा आदि निस्तार की सुविधाएँ विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। कुछ जिलों में विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से वन क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। वृक्षों का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, उनका जीवन निर्वाह होता है जैसे किसी सज्जन के घर से कोई याचक खाली हाथ नही लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ न कुछ मिल जाता है। वृक्ष अपने शरीर से पत्ते फुल, छाया, जड़, छाल, काष्ठ, गन्ध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोयलों से भी लोगो की कामना पूरी होती है। वृक्ष प्रकृति की सर्वाधिक मूल्यवान संपदा है। मानव जीवन इस सम्पदा से घनिष्ठता से जुड़ा है। वृक्षों से प्रत्यक्ष मानव जीवन इस सम्पदा से घनिष्ठता से जुड़ा है। वृक्षों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होता है। एक बढ़ता हुआ वृक्ष देश की प्रगतिशीलता का सजीव प्रतीक माना जाता है। पारिस्थितिकीय तंत्र में वृक्ष तथा अन्य वनस्पतियाँ एवं जीव अभिन्न रूप से जुड़े है।

वृक्षों का महत्व :- वृक्षों के महत्व का विवरण वैज्ञानिक ग्रन्थों, समाज षास्त्रों तथा धर्म ग्रन्थों में विभिन्न रूपों से प्राप्त होता है। उपयोगिता के दृष्टिकोण से वृक्षों के महत्व को पाँच भागों में विभाजित किया जाता है।

- **पर्यावरण संरक्षण :-** पर्यावरण संतुलन मानव के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। मानव की प्रत्येक क्रिया पर्यावरण को प्रभावित करती है। प्रदूशित वातावरण को शुद्ध करने में वृक्षों की अहम भूमिका होती है। जैसे-ऑक्सीजन का निर्माण, कार्बन डाई-ऑक्साइड का अवशोषण, वायु प्रदूषण नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, वातावरण में नमी की वृद्धि, वातावरण अनुकूलन, सौंदर्य निर्माण, छाया प्रदान करना, पशु-पक्षियों को संरक्षण, भूमि संरक्षण, जल संरक्षण, सूखे से राहत आदि।
- **दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति:-** दैनिक आवश्यकताओं से तात्पर्य ऐसी आवश्यकताओं से है, जो वृक्षों द्वारा पूरी होती है जैसे फलों की आपूर्ति, पशुचारा, ईंधन की आपूर्ति, रेशा प्राप्त करना, कृषि औजारों के लिए ,ग्रह निर्माण के लिए लकड़ी की आपूर्ति, औषधियों की प्राप्ति आदि।
- **फसल उत्पादन में सहायक:-** फसल उत्पादन में ऐसा समझा जाता

*अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय,बरेला, जबलपुर (म.प्र.) भारत

है कि वृक्षों की कोई भूमिका नहीं होती है, जंगलों को साफ करके खेती की जाती है। ऐसी मान्यता गलत है। वृक्ष फसल उत्पादन में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनो प्रकार से लाभदायी होते है। प्रत्यक्ष रूप से फसलों को तेज गर्म हवा से सुरक्षा देना, जबकि परोक्ष रूप से सूक्ष्म जलवायु में अनुकूल परिवर्तन करना, भूमि–क्षरण को रोकना, भूमि में नाइट्रोजन की स्थिर उर्वरता बढ़ाना, जीवांश की मात्रा बढ़ाना आदि लाभ सम्मिलित है।

- **औद्योगिक उपयोगिता:–**वृक्षों का औद्योगिक उपयोग इतना अधिक विस्तृत है कि सभी औद्योगिक संस्थान किसी न किसी रूप में वृक्षों से प्राप्त होने वाली सामग्रियों का उपयोग करते है जैसे इमारती लकड़ी, बीड़ी उद्योग, खाद्य तेल, औद्योगिक तेल, गोंद तथा रेजिन, कत्था उद्योग, लाख उत्पादन उद्योग, रेषम उद्योग, शहद उत्पादन, मोम उद्योग, औषधि आदि।
- **सामाजिक – धार्मिक भावनाओं के प्रतीक :–** वृक्ष मानव की सामाजिक तथा धार्मिक भावनाओं से हमेशा जुड़े रहे है। इनकी उपयोगिता को देखते हुए अनेक ग्रन्थों में उनकी उपयोगिता का विवरण प्राप्त होता है। इनके प्रति आदर की भावना इस सीमा तक हो गई है कि उन्हें देवताओं का प्रतीक माना जाने लगा। जैसे 'गूलर' में श्री दतात्रेय जी का, 'कदम्ब' में श्री कृषण का, 'बेल' में भगवान शिव का वास मानते है। स्त्रियाँ अपने सुहाग की मंगल–कामना के लिए 'वट' के वृक्ष की पूजा करती है। रक्षा नवमी के दिन आँवला वृक्ष की पूजा की जाती है विवाह के मण्डप में 'साल' वृक्ष को साक्षी मानकर वर–वध फेरे लेते है। गांवो में अभी तक यह परम्परा है कि जो व्यक्ति फलों का बगीचा लगाता है वह तब तक उस वृक्ष का फल नहीं खाता है जब तक वह उसकी शादी न कर दे। बगीचे की शादी भी बड़े धूम–धाम से की जाती है। ईसाईयों का पूज्य वृक्ष क्रिसमस 'अरौकेरिया एक्सेलसा' है। मुसलमानों का पूज्य वृक्ष 'पीपल रैल्वेडोरा ओलियाइडी' है कितना स्नेह तथा आदर वृक्षों को प्रत्येक धर्म तथा समाज में दिया गया है।म
- **उद्यानिकी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा –** मध्यप्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ जलवायु सम्बंधी अधिक विविधताएँ पाई जाती है। यहाँ प्रत्येक प्रकार के पुष्पीय पौधे किसी न किसी ऋतु में कहीं न कहीं अवश्य उत्पन्न किये जाते है। पुष्पीय पौधों को रोपण योजना के लिए मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से किसानों को अधिक सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को उत्तम बीज देकर, तकनीकी जानकारी प्रदान करके बाजार की व्यवस्था की जाती है जिससे भारतीय किसान अधिक से अधिक पुष्पों का उत्पादन करके लाभ प्राप्त कर सके। हमारी संस्कृति, धार्मिक क्रियाकलाप साहित्य व सामाजिक जीवन में प्रत्येक स्थान में पुष्पों का समावेश है। इस कारण हमारे देश में पुष्पों के उद्योग का अलग ही महत्व है। पुष्पों का उद्योग दिनों–दिन उन्नति के शिखर पर पहुँचता जा रहा है। इससे हमारे समाज के लाखों लोगो को जीविका का साधन मिल रहा है तथा व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। पुष्प के व्यवसाय से भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक स्तर पर पुष्पोत्पादन करने के लिए अनेक सुविधाएँ प्रदान की जाती है। यदि व्यापारी या किसान पुष्पों के बीज एवं उत्तम सामग्री आयात करना चाहता है तो स्वीकृति या अनुमति की आवश्यकता नही होती है, बीज, कंद, कर्तन एवं बोने की सामग्री आदि पर आयात–निर्यात षुल्क में छूट मिलती है। 'मशीनों एवं ग्रीन हाउस बनाने के उपकरणों का आयात करने पर आयात शुल्क पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है, घरेलू बाजार में फूलों की अधिक बिक्री होने वाली परियोजनाओं पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है, किसानों को फूलों की देखभाल के लिए षीत भंडारण बनाने के लिए 4 प्रतिशत ब्याज पर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड किसानों को कर्ज देता है, विश्व स्तर पर यदि सभी उद्योग–धंधों को देखा जाए तो पुष्पीय पौधे व फूलों के उद्योग में सबसे कम व्यय होता है। इसकी खेती से हमारे पर्यावरण में सुधार होता है। उद्योग–धंधों के विकास में वृद्धि होती है। हमारे देश के पढ़े–लिखे युवक–युवतियाँ जो पुष्प कृषि में अपना कैरियर बनाना चाहते है उन्हें रोजगार प्राप्त होता है। ग्रामों में इस उद्योग की नई–नई तकनीकियों से, ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन कम होता है क्योंकि पुष्पीय पौधे एवं पुष्प द्वारा शहरों एवं विदेशों से अच्छा मूल्य प्राप्त होता है।

समस्याएँ – उद्यानिकी जैव विविधता की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उद्यान या बागबानी के बारे में लोगो को पूर्ण जानकारी न होना, बागवानी में कीटनाश्कों रासायनिक खादों का अत्यधिक प्रयोग, देशी प्रजाति के स्थान संकर प्रजाति का उपयोग, विविधता की जगह एक समानता एवं उत्पादकताओं को बढावा, वन क्षेत्रों में एक ही प्रजाति का व्यवसायिक रोपड़ करना, अनेक प्रजातियों की जगह एक बहुमूल्य प्रजाति का रोपण करना, पतझड़ एवं सदाबहार वनों में विदेशी प्रजातियों का रोपण ये सब उद्यानिकी जैव विविधता के विकास में बाधक के रूप में सबसे बड़ी समस्या है।

सुझाव – जैव विविधता बोर्ड को उद्यानिकी जैव विविधता के बारे में लोगो को जानकारी प्रदान करनी चाहिए ताकि लोग उद्यानिकी की खेती करके अधिक से अधिक लाभ कमा सके उद्यानिकी जैव विविधता में कीट नाशक दवाओं, रासायनिक खादों का प्रयोग न करते हुए जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त हो सके। उद्यानिकी में विदेशी प्रजाति के स्थान पर देशी प्रजाति का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाना चाहिए जिससे मूल प्रजाति बनी रहे उद्यानिकी कार्य करते समय विभिन्न प्रजाति का रोपण न करते हुए अधिक आर्थिक महत्व देने वाली प्रजाति का रोपड़ करना चाहिए।

निष्कर्ष – जैव विविधता के बीज मंत्र को दृष्टिगत रखते हुए हमें जैव विविधता की गवेषणा करनी चाहिए, जैव विविधता की गवेषणा से आशय उन तत्वों की खोज है जो जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है लेकिन हमनें उनकी कीमत को भुला दिया है। हमनें प्रकृति के उत्पादानों का दमन किया है जैव विविधता नष्ट हो रही है ऋतुचक्र व्यतिक्रमित हुआ है तथा मौसम रूठ रहा है। भौतिकता के अभाव में नित्य नई खोजे जारी है। सभी अन्वेषण एवं अनुसंधान हमें प्राकृतिक संसाधनों के प्रति ओर भी अधिक अनुदार बना रहे है हम प्रकृति के मूल तत्वों एवं बीज मंत्र से और अधिक दूर जा रहे है।

जैव विविधता के संदर्भ में आज गंभीर चिंतन की आवश्यकता है गवेषणात्मक संदर्शो पर दृष्टिपात जरूरी है हमारे ऋृषि मुनियों ने गंभीर चिंतन किया था उन्होने कठिन साधना की और समाधान दिए। मनीषियों के अनुसार ऋषि वह होता है जो चिंतन को विस्तृत रूप देता है और मुनि वह होता है जो चिंतन को गहराई देता है हमने भौतिक तथा लौकिक दोनो ही क्षेत्रों में प्रगति की है लेकिन अपने दिव्य आर्श ज्ञान को भुला दिया है। अपनी प्राकृतिक क्षमताओं को खो दिया है जो कुछ हमारे पास था हमने उसे खो दिया है उसी खोये हुए खोज की गवेषणा है। बदलते समय के साथ बदलती मान्यताओं का साथ जो आवश्यक है उसे हम पाना चाहते हैं उसे अन्वेषणा कहते हैं। हमें पर्यायवादी न होकर आध्यात्मवादी होकर चिंतन करना चाहिए एवं प्रकृति पर्यावरण को निरन्तर बनाये रखने के प्रयास करने होगें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पटैरिया, हरिनारायण- जैविक जननांकीय, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, बाणगंगा भोपाल (2005)
2. भार्गव, प्रभा - उद्यान कला, पुस्तक महल, दरियागंज, नई दिल्ली 21
3. तिवारी, ज्वालाप्रसाद - औषधीय पौधे कृषि एवं उपयोग, अभिनव पकाशन जबलपुर (2004)
4. श्रीवास्तव, श्यामसुन्दर - कृषि वानिकी, सेन्ट्रल बुक हाउस, सदर बाजार, रायपुर (1995)
5. शुक्ला पी.- भारत के औषधीय वृक्ष, पोइंटर पब्लिशर्स, जयपुर (2008)
6. सती, विषम्भर प्रसाद - पर्यावरण और कानून, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर, राजस्थान, (2007)
7. नवाज, आर.- कृषि वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन, पोइंटर पब्लिशर्स, जयपुर (2008)

पत्रिकाऐं :

1. वन- वृत्त- अपर वनमंडल सौंसर (छिन्दवाड़ा)
2. भारत के औषधीय वृक्ष (2008)
3. हमारी थाती हमारे बारानाजा, हमारी जैव विविधता, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, प्रथम तल किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल।
4. जैव विविधता एक साझा सरोकार, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, प्रथम तल किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल।

****

जैव विविधता विषय में शोध की आवश्यकता

डॉ. दयाराम साहू *

प्रस्तावना – आज की मानव जाति आधुनिकता के दौर में इस कदर बढ़ती जा रही है की विकास करने के लिये हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तीव्र गति से किया जा रहा है जिसकी विभिषिका हमें वर्तमान समय में देखने को मिल रही है जैसे जलवायु का बेमौसम में परिवर्तन होना, अकाल पड़ना भूखमरी बढना बेरोजगारी बढ़ना भूमण्डल का तापमान बढ़ना आदि घटनायें देखने को मिल रही है इसलिये वर्तमान समय में जैव विविधता विषय पर शोध की आवश्यकता की महत्ता बढ़ गई है हम देखते हैं जैव विविधता हमारे जीवन के हर पहलू को छूती है जैव विविधता के बिना मनुष्य ही क्या, इस वातावरण में प्रत्येक जीव-जन्तु पेड़-पौधे जीवित नहीं रह सकते। जैव विविधता से हमें जीवित रहने के लिए कपड़ा, रोटी, और मकान प्राप्त होते हैं। खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से जैव विविधता से पूरी दुनिया को अनाज प्राप्त होता है। सेहत और उत्कृष्ट स्वास्थ्य लाभ के लिए पौधों से आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में जड़ी-बूटियाँ प्राप्त होती है। जैव विविधता के कारण ही मनुष्य के जीवन में आर्थिक वृद्धि होती है जिससे उसके जीवन स्तर में सुधार होता है जैसे लघु एवं कुटीर उद्योग से कपास, जूट नारियल के रेशे से बाँस प्राप्त होते हैं, इसके साथ-साथ इनका उपयोग स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए रस्सियाँ, कागज, कपड़े बनाने में एवं पैकिंग सामग्री के लिए बोरे, गिनी बैग, गलिचों के स्तर आदि जैव विविधता से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए **जैव विविधता** विषय पर शोध की आवश्यकता की महत्ता बढ़ गई है जिससे लोगो को यह पता चल सके की जैव विविधता क्या है इसके महत्व क्या है इसे कैसे बचाया जा सकता है आदि।

यह शोध आज के समय में दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, क्योंकि जीवन अत्यधिक जटिल होता जा रहा है। इसमें धन एवं समय दोनों लगते हैं, लेकिन फिर भी अधिक से अधिक लोग शोध कार्यो में रूचि ले रहे है। इसका कारण अनुसंधान का बढ़ता महत्व है। 'शोध से बोध पनपता है और वास्तविक बोध ज्ञान का द्योतक है। शोध की भी यह प्रथम उपयोगिता है कि यह वह साधन है। जिसके द्वारा हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है साथ ही शोध नवीन वस्तुओं के सम्बंध में हमारे मन की जिज्ञासा को मिटाने का एक साधन भी है'।[1] इसके द्वारा हमारे समाज में घटित घटनाओं के अनेक अस्पष्ट या अन्धकारपूर्ण पक्षों के सम्बंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है समाज में अनेक समस्याएँ केवल इसलिए है क्योंकि उनके सम्बंध में हमें पूर्ण जानकारी नहीं है। शोध के द्वारा इन समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके उसके कारणों एवं निवारणों का समाधान किया जा सकता है शोध कार्य में समाज में घटित घटनाओं का निष्पक्ष विश्लेषण किया जाता है एवं लगातार ज्ञान में वृद्धि होती है, हम यह कह सकते हैं कि 'शोध के द्वारा मानव समाज उस प्रकार दिशा निर्देशित होता है जिस प्रकार किसी समुद्र में कोई जहाज पोल स्टार के द्वारा दिशा निर्देशित होता है'।[2]

शोध की सहायता से जैव विविधता के विकास को एक वैज्ञानिक स्तर पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है, लेकिन लोगों के मन में यह गलत धारणा बनी हुई है कि जैव विविधता का विकास कोई भी व्यक्ति या संस्था कर सकती है और सफलता भी पा सकती है लेकिन इस विकास का आधार यदि वैज्ञानिक ज्ञान व अनुभव नही है तो उसमें सफलता की प्राप्ति केवल एक संयोग ही होगा। 'शोधकर्ता समाज को सुधारना तो चाहते हैं लेकिन उनको इसके लिए सम्बंधित ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है और उसके अभाव में वे कुछ नही कर पाते। शोधकर्ता शोध के द्वारा उन्हें सम्बंधित ज्ञान देकर अपनी उपयोगिता सिद्ध कर देता है शोध समाज सुधारकों को उनके रूचि के क्षेत्रों तथा समस्याओं का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करके चाही गई सूचनाएँ प्रदान करता है इन सूचनाओं की सहायता से मनुष्य समस्या की गहनता तथा कारणों से अवगत हो जाते हैं और सुधार कार्य मे जुट जाते हैं।'[3]

राज्य की अर्थव्यवस्था में जैव विविधता के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जैव विविधता बोर्ड की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जबकि प्रस्तुत शोध प्रबंध के विषय का चयन करने के पूर्व उसके औचित्य एवं उपयोगिता की अवधारणाओं का स्वप्रेरणा से अध्ययन किया गया है। जैव विविधता के संविधान के लिए अब तक जो प्रयास किय गये है उनकी दिशा दृष्टि विकासोन्मुखी कम और विदोहन अधिक था। इस प्रकार के प्रयासों को विकास के कार्यक्रमों के रूप में न देखकर जैव विविधता के उत्थान के कार्यक्रमों के रूप में अधिक देखा जाता रहा है। आधुनिकीकरण, शहरीकरण, शिक्षा के प्रचार-प्रसार तथा व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों से पर्यावरण में जो उथल-पुथल हुई है, उससे पर्यावरण प्रदूषित हुआ है।

जैव विविधता की साख सुविधाओं का समुचित उपयोग करना एवं संरक्षण के प्रति महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को समझना। राज्य की अर्थव्यवस्था में जैव विविधता के उत्पादों के हिस्से में वृद्धि के लिए साख सुविधाओं का सक्रिय योगदान होना चाहिए। जबकि प्रदेश में प्रचुर मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध है, लेकिन उनका समुचित उपयोग नही हो रहा है। यद्यपि जैव विविधता बोर्ड द्वारा जैव विविधता की साख सुविधाओं के विकास के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे है किन्तु अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि अभी सरकार और बोर्ड के प्रयासों की आवश्यकता है।

वर्तमान समय 'जैव विविधता' के लिए अनेक संभावनाओं से भरा है। इस जैव विविधता के क्षेत्र में व्यक्तियों के लिए रोजगार के प्रचुर अवसर है जैसे स्वयं, स्वामित्व, प्रशासन, प्रबंधन, विपणन, कार्यकारी, विपणन सहायक, विक्रय कार्यकारी आदि अनेक भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त हो सकता है किन्तु जैव विविधता के क्षेत्र में अनेक बाधाएँ है जो जैव विविधता के विकास को प्रभावित कर रही है इन बाधक घटकों की पहचान एवं उन्हें

* अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, बरेला, जबलपुर (म.प्र.) भारत

दूर करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करना शोध उद्देश्य में निहित है। शोध उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित परिकल्पनाएँ परीक्षण हेतु निर्धारित की गई है।

- जैव विविधता के विकास एवं विस्तार करने के लिए चलाये जाने वाले कार्यक्रम पूर्णतया सुलभ हो रहे है।
- जैव विविधता को पहुँचाई गई क्षति को पुनर्वापसी के लिए निश्चित योजना तैयार कर समुचित क्रियान्वयन किया जाता है।
- कार्यशाला के माध्यम से जैविक सम्पदा के संग्राहकों को संकलित कर इसके सही तरीके से संग्रहण एवं विदोहन को प्रोत्साहित किया जाता है।
- जिलों में उपलब्ध जैव संसाधनों, पेड़ पौधों, फसलों, जीव-जन्तु, पालतू पशुओं इत्यादि की विभिन्न प्रजातियों की संख्या में वृद्धि करना।
- राज्य के विकास में जैव विविधता बोर्ड की कितनी सहभागिता है।
- जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम संचालित है।
- जैव विविधता बोर्ड द्वारा मध्यप्रदेश के आर्थिक विकास के लिए कौन-कौन से उपाए किए जा रहे है।
- इस शोध प्रबंध से जैव विविधता के विकास करने में नवीन तकनीक प्रशिक्षण आयोजन तथा प्रशिक्षण नीति के सम्बंध में नवीन जानकारी प्राप्त होगी।
- राज्य शासन द्वारा जैव विविधता विकास में कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित है।

समस्या ;

- आज भी वर्तमान समय में यह देखा जाता है कि जैव विविधता से सम्बधित जानकारी लगभग 60 प्रतिशत लोगो को ही नहीं है वर्तमान में जैव विविधता सरंक्षण एवं उपयोग के लिए जो अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ है वे समुचित नहीं है आज भी पचांयत स्तर पर जैव विविधता का पंजीकरण नहीं किया गया है स्थानिय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण कोष का स्थापित न होना इसलिए जैव विविधता से सम्बंधित आँकड़ो को एकत्रित करने में बहुत समस्याओं का समाना करना पड़ता है जैव विविधता से सम्बंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए जैव विविधता बोर्ड भोपाल में जाना पड़ता है लेकिन यहाँ भी प्रत्येक क्षेत्र की जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण विभिन्न संमकों से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करने में कठनाई का सामना करना पड़ता है।

सुझाव :

- जैव विविधता से सम्बंधित पूर्ण जानकारी एवं आँकडे प्रदर्शित करने के लिए राज्य सरकार को राजधानी स्तर पर जैव विविधता बोर्ड के कार्यालय के साथ-साथ राज्य के प्रत्येक जिले में जैव विविधता बोर्ड का कार्यालय खोला जाना चाहिए एवं प्रत्येक जिले के प्रत्येक विकास खंड में जैव विविधता प्रबंधन समिति गठित की जानी चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति को जैव विविधता के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके, जो आँकडे एकत्रित करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। राज्य सरकार एवं जैव विविधता बोर्ड द्वारा निम्न कार्य किया जाना चाहिए पचांयत स्तर पर जैव विविधता का पँजीकरण करना, प्रत्येक ग्राम में जैव विविधता उत्सव मनाना, जैव विविधता मुददे पर ग्राम स्तर पर लोक सुनवाई का आयोजन करना, राज्य स्तरीय कार्य शाला का आयोजन विशाल रूप में करना, ग्राम स्तरीय परामर्श शिविर लगाना, जैव विविधता कार्यक्रम तैयार करके उसे संचार साधनों से प्रचार-प्रसार करना, जैव विविधता प्रबंधक समिति के विभिन्न स्तरीय सदस्यों के प्रशिक्षण के माध्यम से कार्य कुशलता बढ़ाना, जैव विविधता से सम्बंधित समाचार पत्रों में प्रकाशित करना, स्थानिय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण कोष को स्थापित करना, इस कोष से स्थानिय युवकों को जैव विविधता सम्बंधित शोध प्रबंधन वाणिज्य उपयोग आर्थिक विकास के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
- वर्तमान समय का सबसे बड़ा बीज मंत्र है जैव विविधता संरक्षण का, जो हमें प्राप्त करना है उसे बोना आरम्भ कर देना चाहिए। आज हम जिन पेड़ों के फल खा रहे है क्या हमने उन्हें लगाया था? ये पेड़ हमारे पुरखों के द्वारा बीजारोपित किए गए, उनके द्वारा ही अभिसिचिंत किए गए और संभाले गए। हम तो उनके प्रयास को ही प्रसाद के रूप में प्राप्त कर रहे है।
- हमें भी अपनी संततियों के बारे में सोचना चाहिए और वन-वनस्पतियों एवं जड़ी-बूटियों को बोना चाहिए, ये पेड़-पौधे ही हमारे जीवन का आधार है। आज प्राकृतिक संसाधनों के नवसृजन की आवश्यकता है अन्यथा प्रयोग होते-होते शनैः-शनैः बचे भण्डार और आधार भी समाप्त हो जाएगें। हमारे पास संसाधनो के संरक्षण का बीज मंत्र है इस मंत्र को समझने की आवश्यकता है। शरीर बुद्धि और भावनाएँ, स्थूल, सूक्ष्म और कारण षरीर के साथ हम सब में ही नैसर्गिक रूप से पाई जाती है धन एवं संसाधनों को हम अर्जित भी करते हैं तथा पूर्वजों के द्वारा पूर्व संचित धन संसाधन भी हमें उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधनों के मामले में आज हम स्वउपार्जन से विमुख हुए है हम संसाधनों को उत्तराधिकार के रूप में अधिकता से प्राप्त कर रहे है किन्तु हम इनका मूल्य समझ नहीं पा रहे है। तभी तो हम अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे है और संसाधनों की बर्वादी कर रहे है यदि हम पेड़ काटते रहे, वन विनाश करते रहे है, लेकिन हमने नये पेड़-पौधे नहीं लगाये तो एक ऐसी रिक्तता आ जायेगी जिसकी भर पाई करना बहुत मुश्किल है जैव विविधता का संरक्षण करके हम संसाधनों का अंकेक्षण कर सकते हैं।
- जैव विविधता के बीज मंत्र को दृष्टिगत रखते हुए हमें जैव विविधता की गवेषणा करनी चाहिए, जैव विविधता की गवेषणा से आशय उन तत्वों की खोज है जो जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है लेकिन हमनें उनकी कीमत को भुला दिया है। हमनें प्रकृति के उत्पादानों का दमन किया है जैव विविधता नष्ट हो रही है ऋतुचक्र व्यतिकृमित हुआ है तथा मौसम रूठ रहा है। भौतिकता के अभाव में नित्य नई खोजे जारी है। सभी अन्वेषण एवं अनुसंधान हमें प्राकृतिक संसाधनों के प्रति ओर भी अधिक अनुदार बना रहे है हम प्रकृति के मूल तत्वों एवं बीज मंत्र से और अधिक दूर जा रहे है।
- जैव विविधता के संदर्भ में आज गंभीर चिंतन की आवश्यकता है गवेषणात्मक संदर्भो पर दृष्टिपात जरूरी है हमारे ऋषि मुनियों ने गंभीर चिंतन किया था उन्होने कठिन साधना की और समाधान दिए। मनीषियों के अनुसार ऋषि वह होता है जो चिंतन को विस्तृत रूप देता है और मुनि वह होता है जो चिंतन को गहराई देता है हमने भौतिक तथा लौकिक दोनो ही क्षेत्रों में प्रगति की है लेकिन अपने दिव्य आर्श ज्ञान को भुला दिया है। अपनी प्राकृतिक क्षमताओं को खो दिया है जो कुछ हमारे पास था हमने उसे खो दिया है उसी खोये हुए खोज की गवेषणा है। बदलते समय के साथ बदलती मान्यताओं का साथ जो आवश्यक है उसे हम पाना चाहते हैं उसे अन्वेषणा कहते हैं। हमें पर्यायवादी न होकर आध्यात्मवादी होकर चिंतन करना चाहिए एवं प्रकृति पर्यावरण को निरन्तर बनाये रखने के प्रयास करने होगें।

संदर्भ ग्रंथ सूची ; -

1. आहुजा, राम - सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, रावत पब्लिकेशन्स

जयपुर नई– दिल्ली (2003)

2. मुकर्जी, रवीन्द्रनाथ– सामाजिक शोध एवं सांख्यिकीय, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर दिल्ली (2005)
3. शर्मा, दीप्ती, महेन्द्र कुमार– पर्यावरण प्रबंधन एवं प्राकृतिक संसाधन, अर्जुन पब्लिषिंग हाउस प्रहलाद गली, अंसारी रोड, दरियागंज नई दिल्ली (2009)
4. साहनी के.– पर्यावरण, वन और वन्य जीव संरक्षण, पोइंटर पब्लिशर्स, जयपुर (2007)
5. त्रैमासिक पत्रिका – जैव विविधता बोर्ड, भोपाल।
6. हमारी जैव विविधता– म.प्र. शासन।
7. वनवर्धन के सिद्धांत – (1982)
8. भारत के औषधीय वृक्ष (2008)
9. जीव जन्तुओं की अनोखी दुनिया (2009)
10. खेती संसार – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वार्षिक रिपोर्ट भारत कृषक समाज मध्यप्रदेश अपेक्स बैंक भवन, भोपाल।
11. इंडियन सोसायटी और एग्रीविजनेस प्रोफेशनलस भोपाल– वनोपजों का प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण।
12. आओं जाने जीव जगत को – मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, प्रथम तल किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

Annual Publications :

1. Annual reports of Biodiversity Board, M.P., Bhopal
2. Times of India Annual Directory and Year Book
3. Manorama

****

परिवहन का आर्थिक महत्व (इन्दौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के संदर्भ में)

डॉ. धीरज शर्मा *

प्रस्तावना – 'यदि कृषि और उद्योग धंधे किसी देश के आर्थिक जीवन का शरीर और हड्डिया मानी जाए तो परिवहन को उस आर्थिक ढांचे की स्नायु प्रणाली मानना चाहिए।' किसी देश के आर्थिक विकास का आभास हमको वहां के परिवहन के साधनों से हो सकता है। आधुनिक सभ्यता वास्तव मे आधुनिक परिवहन के साधनों की शिशु है। फेयर एवं विलियम्स के शब्दों में 'सभ्यता वहा प्रगट हुई जहां परिवहन व्यवस्था प्रभावशाली उपयोग मे लाई जा सकी थी। यह कभी भी छोटे और एंकांकी समाजों मे प्रगट नहीं हुई है।'

जिस देश में मानव और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की सुविधा नहीं है उसे आज एक सभ्य राष्ट्र नही कहा जा सकता है। उन्नत परिवहन के साधन इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि तकनीकी क्षेत्र में अमुक देश ने कितनी प्रगति की है। हमारा आर्थिक जीवन ऐसा बन गया है कि परिवहन के साधनो के अभाव में सदैव आर्थिक संकट की आशंका बन रहती है।

नियोजित अर्थव्यवस्था में परिवहन की भूमिका – वर्तमान युग आर्थिक नियोजन का युग है। आज विश्व के समस्त राष्ट्र चाहे विकसित हो अथवा अविकसित या अर्द्ध विकसित, नियोजित विकास के माध्यम से ही अपनी अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में संलग्न है। योजना आयोग के अनुसार आर्थिक नियोजन आवश्यक रूप से सुनिश्चित सामाजिक उद्देश्यों के संदर्भ में अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए प्रसाधनो के संगठन एवं प्रयोग का तरीका है। किसी भी देश के आर्थिक पुनरूत्थान के लिए अनियोजित अर्थव्यवस्था की अपेक्षा नियोजित अर्थव्यवस्था केा अपनाना अधिक श्रेयस्कर है। विश्व के सभी राष्ट्रो की विकास योजनाओं मे परिवहन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। खलिहानो मे भले ही अनाज के ढेर लगे हो तथा कारखानों मे निर्मित माल से गोदाम भरे हो, किन्तु जब तक कार्य और फैक्ट्री का उत्पादन उन लोगों के पास नहीं पहुँचता जिनके यह उत्पन्न किया गया है तो उसकी क्या उपयोगिता? देश मे उत्पादन की वृद्धि के साथ-साथ उसका स्थानान्तरण भी परमआवश्यक है।

विगत घटनाओं से परिहवन विकास के संबंध में प्राप्त शिक्षाये –

1. कोयला समस्या कई बार भारत मे उत्पन्न हुआ जिसका प्रमुख कारण परिवहन साधन उपलब्ध न होना है।
2. चीन और पाक आक्रमणो ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि देश रक्षा और देश के विकास दोनों ही दृष्टियों से परिवहन का पूर्णत: विकास होना आवश्यक है।
3. रेलों की तुलना में सड़क परिवहन का भाग माल एवं यात्री परिवहन में अपेक्षाकृत बढ़ा है।
4. द्वितीय और तृतीय योजनाओं मे कई बार देश को परिवहन संकट का सामना करना पड़ा, जिससे आर्थिक विकास मे कठिनाई हुई।
5. परिवहन की योजनाएँ समय से पूर्व उपयुक्त एवं योग्य अधिकारियों द्वारा बनाई जानी चाहिए।

परिवहन का महत्व – परिवहन का महत्व निम्न तीन शीर्षको के अंतर्गत विभक्त किया जा सकता है।

1. आर्थिक महत्व
2. सामाजिक महत्व
3. राजनैतिक महत्व

परिवहन का आर्थिक महत्व – परिवहन के साधनों का मानव के आर्थिक जीवन से बहुत गहरा संबंध है। प्रो. मार्शल के मतानुसार 'अर्थशास्त्र मानव के जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है, यह व्यक्ति एवं समाज की उन क्रियाओं की परीक्षा करता है, जो भौतिक कल्याण के साधनो की प्राप्ति एवं उनके उपयोग से संबंधित होती है।' परिहवन के आर्थिक लाभ इस प्रकार है –

1. उत्पादन का विशिष्टिकरण
2. सस्ती उपभोग सामग्री
3. कच्चे माल के परिवहन की सुविधा
4. आधारभूत उद्योगो का विकास संभव
5. औद्योगिकीकरण की तीव्रगति हेतु आवश्यक
6. संतुलित विकास हेतु आवश्यक
7. व्यक्तियों के रोजगार

इन्दौर में परिवहन – इन्दौर प्राचीनकाल मे एक सीमित नगर था किन्तु धीरे-धीरे अनेक आविष्कारों और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति और जनसंख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि से इन्दौर म.प्र. की औद्योगिक राजधानी बन गया है। इन्दौर मे परिवहन के विविध साधन है जो इस प्रकार है।

1. सिटी वेन
2. तांगा
3. सिटी बस
4. टाटा मैजिक
5. रिक्शा
6. ई – रिक्शा

उपरोक्त साधनों मे रिक्शा, तांगा पुरानी व्यवस्था में से है शेष सभी 2005 में और सिटी ट्रासपोर्ट सर्विस लिमिटेड की स्थापना और परिवहन क्रांति की देन है। इसके पूर्व नगर सेवा और टेम्पो भी परिवहन साधनों मे शामिल थे जिन्हे बढ़ते प्रदूषण अधिक भाड़ा असभ्यतापूर्वक व्यवहार आदि कारणो से बंद कर दिया गया।

* शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

सिटी बस के लाभ – सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के माध्यम से परिवहन का महत्व सिटी बस और मिनी बसों के प्रयोग से बढ़ा है। इसके लाभ इस प्रकार है।

1. यात्रियों को घर पहुँच सेवा जिससे समय की बचत हो जो उत्पादक कार्यो मे लगाया जा सकता है।
2. प्रतिस्पर्धा के कारण किराया कम होना
3. सरकार द्धारा अनिवार्य व कानूनी नियमों का निर्धारण
4. सतत् संचालन और गति पर नियंत्रण
5. दुर्घटनाओं की दशा में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था
6. संचालन प्रशासकीय पद पर नियुक्त व्यक्ति द्धारा, जिससे राजनैनिक नियंत्रण मे कमी
7. लोक निजी साझेदारी(PPP Model) जुड़ा होने से सरकारी संपत्ति की सुरक्षा
8. जनता को कम किराये पर श्रेष्ठ सुविधा
9. व्यवस्था के संचालन हेतु आधारभूत संरचना का विकास सरकार द्धारा जैसे – सड़क, बी.आर.टी.एस. आदि

निष्कर्ष – उपरोक्त से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश की औद्योगिक राजधानी इन्दौर मे परिवहन के विविध साधन संचालित किये जा रहे है, जिनमें सिटी बस एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे परिवहन की अधिकाधिक सुविधा इन्दौर के नागरिको को प्राप्त हो रही है तथा इसके माध्यम से पूर्ववर्ती परिवहन के साधनों के निम्न दोषों से बचा जा सकता है।

1. यात्रियों के साथ बुरा व्यवहार
2. प्रतिस्पर्धा के कारण गाड़ियों की तेज गति
3. कंडक्टर और ड्रायवर की मनमानी
4. अधिक भाड़ा लेना
5. आर्थिक नुकसान
6. सरकारी संम्पत्तियों का नुकसान

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मनोरमा ईयर बुक 2007 – 08
2. केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950
3. रोड ट्रांसपोर्ट – डॉ. एफ.जी. आटिया
4. Urban Transport in India - Dilip Holder (2006)
5. दैनिक नई दुनिया, इन्दौर
6. https://indore.nic.in/glance.htm.

****

नार्दन कोल फील्ड लिमिटेड में मानव संसाधन की वर्तमान स्थिति

डॉ. दीपचंद भावरकर *

शोध सारांश – भारत एक विकासशील राष्ट्र है, इस नाते देश में श्रमिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम उत्पादन वृद्धि में श्रमिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। किसी उद्योग में श्रमिकों के सम्बंध तथा उत्पादन क्रिया में श्रम की स्थिति एवं भूमिका महत्वपूर्ण है।[1] वर्तमान उद्योगों में संगठित शिक्षितश्रमिकों में वृद्धि हो रही है, जिसका प्रभाव उद्योग पर प्रतिकूल या अनुकूल पड़ता है। कोल इंडिया लिमिटेड में वर्तमान में 50 प्रतिशत श्रमिक शिक्षितहै। श्रमिक संगठनों में भी श्रमिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। श्रमिक संघों के विकास एवं भूमिका के साथ श्रम बाजार की विशेषताओं में श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्योग में कार्यरत श्रमिक संगठनों की पूर्ण जिम्मेदारी है कि वे श्रमिकों को उद्योग के उत्पादन बढ़ाने व काम के प्रति निष्ठावान रहने के लिए शिक्षितकरें। श्रमिक संगठनों के गलत एवं स्वार्थी तत्वों द्वारा भ्रामक आश्वासन देने तथा गलत काम के लिए श्रमिकों को प्रोत्साहित करने से औद्योगिक क्षेत्र का वातावरण दिनोदिन दूषित होते जा रहे है, जिससे श्रमिकों का षोषण होता है। वास्तव में उद्योगों में स्वस्थ श्रमिक संगठन की आवश्यकता है जो कि श्रमिकों को उनके कर्तव्य का बोध कराए वही उद्योगों को बढ़ाने के लिए स्वस्थ वातावरण पैदा करें। श्रमिकों के रूप में श्रम अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक पाया जाने वाला साधन है श्रम पूँजी की गंभीर कमी से उदित होता है। औद्योगिक शांति स्थापित करने का तरीका यह है कि श्रमिक वर्ग के कष्ट के कारणों को ज्ञात किया जाये और उसे दूर किया जाये न कि उसे समर्पण करने और चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया जाये।

प्रस्तावना – नार्दन कोल फील्ड लिमिटेड की स्थापना 28 नवम्बर 1985 को हुई। इस का मुख्यालय सिंगरौली मध्यप्रदेश भारत में है। यह कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है। मध्यप्रदेश का 50वॉ जिला जो कि सीधी जिले से अलग हुआ है। इतिहासिक दृष्टि से सिंगरौली रीवा,बघेलखंड रियासत का एक क्षेत्र था वर्तमान में अद्यौगीकरण के रूप में जाना जाता है। कुल कर्मचारी एवं अधिकारी 15357 कार्यरत है। सर्वप्रथम 1921 में महात्मा गाँधी ने प्रबंध में श्रमिकों को भागीदार बताया। सन् 1956 को औद्योगिक नीति में श्रम भागीदारी पर बल दिया गया। सन् 1958 में शिमला में आयोजित भारतीय कर्मचारी कान्फ्रेंस द्वारा दिए गए सुझावों के अनुरूप श्रमिकों की भागीदारी सम्बंधी योजना सर्वप्रथम सन् 1960 के पूर्वार्द्ध में कोल माईन्स में लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत उत्पादन सुरक्षा एवं कल्याण कार्यो में श्रमिकों की भागीदारी का प्रयोग किया गया था। लेकिन कुछ कठिनाईयों की वजह से श्रमिकों की भागीदारी सम्बंधी योजना को वांछित गति एवं षक्ति प्रदान नहीं हो सकी। तथा किसी भी बड़े प्रतिष्ठान ने इस योजना को लागू करने में रूचि नहीं दिखाई। 'मानव का प्रबन्ध करना' बहुत ही महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके अन्तर्गत न केवल एक व्यक्ति का प्रबन्ध करना सम्मिलित है अपितु एक सामाजिक प्रणाली का प्रषासन करना सम्मिलित होता है। मानव की प्रकृति गतिशील होने के कारण उनका प्रबन्ध वर्तमान में चुनौतीपूर्ण हो गया है। संसार में कोई भी दो व्यक्ति ऐसे नहीं है जो योग्यता, क्षमता, भावनाओं, व्यवहार आदि में एक समान हो। ऐसी परिस्थिति में उन्हें मशीन की भांति प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। अत: उनके साथ व्यवहार करने और उनका प्रबन्ध करने में बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। यदि मानव का प्रबन्ध कुशलतापूर्वक कर लिया जाता है तो जहाँ एक ओर न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणामों की प्राप्ति की जा सकती है वहीं दूसरी ओर निष्पादित कार्य से व्यक्तिगत एवं सामूहिक सन्तुष्टि भी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार मानव संसाधन के प्रबन्ध का अत्यधिक महत्व है। इस सम्बन्ध में सामाजिक, पेशेवर एवं उपक्रम के दृष्टिकोण को जानना आवश्यक है।

गत पॉच वर्षो का विश्लेषणात्मक अध्ययन

वर्ष	कुल जन शक्ति	लाभ/हानि (करोड़ में)	कुल उत्पादन (मिलियन टन में)
2012-13	16073	25.05	700.21
2013-14	16741	19.57	686.39
2014-15	26226	25.04	724.84
2015-16	16078	28.48	802.24
2016-17	15357	38.82	840.96

स्त्रोत :- वार्षिक रिपोर्ट नार्दन कोल फील्ड लिमिटेड 2015-16

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सन् 2012 की तुलना में सन् 2017 में श्रम शक्ति कम है इसका मुख्य कारण नार्दन कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का प्रारंभ करने से अधिक से अधिक कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा सेवा निवृत्त होने के साथ ही अन्डरग्राउण्ड खदानों का बंद होना एवं नई नई ओपनकास्ट खदानों का खुलना है। जिसमें मशीनों की आवश्यकता अधिक पड़ती है। नार्दन कोल फील्ड लिमिटेड के कोयला क्षेत्र में श्रमिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के महत्वपूर्ण साधनों में कोयले की सर्वश्रेष्ठ भूमिका है। देश में व्यवसायिक ऊर्जा की कुल माँग लगभग 65 प्रतिशत पूर्ति कोयला से होती है। भारत की ईधन नीति समिति ने सन् 1974 में ऊर्जा के साधनों में कोयले को प्रमुख साधन स्वीकार किया है। अत: इस महत्वपूर्ण खनिज के उत्खनन हेतु लगे श्रमिकों का आज भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आज प्रत्येक राष्ट्र तीव्र गति से औद्योगिकीकरण के लिए प्रयत्नशील है। अत: सभी उत्पादन के घटकों में श्रम महत्वपूर्ण घटक है। श्रम जीवियों के सहयोग के बिना पूँजी, यंत्र व उपकरण व्यर्थ है। प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी भी आवश्यक है।

निष्कर्ष – अध्ययन की दृष्टि से मानव संसाधन प्रबंध जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं अधिक वह व्यावहारिक दृष्टि में उपयोगी है। क्योकि सम्पूर्ण

* अतिथि विद्वान (वाणिज्य) श्री.श्री ल.ना.शा.स.पेंचव्हेली. पी.जी. महाविद्यालय, परासिया, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) भारत

उत्पादन प्रक्रिया में कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विज्ञान व तकनीकी चाहे कितनी ही विकसित हो जाये। मनुष्य का विकल्प कोई भी उपकरण नहीं बन सकता। निश्चय ही मनुष्य प्रबंध प्रणाली का केन्द्र बिन्दु है और उसके उचित प्रबंध से ही उचित संगठनात्मक व्यवहार व प्रभावोंत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। कर्मचारियों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना ही प्रबंधक का मूल कार्य है। प्रमुख रूप से मानव संसाधन को संगठित करने कार्य के प्रति उन्हें प्रोत्साहित करने, कार्य करने के लिए प्रेरणा देने, उनका मार्गदर्शन करने, उन्हें योग्य नेतृत्व प्रदान करने, प्रशिक्षण देने, उस पर नियंत्रण रखकर, सभी कार्यो में समन्वय स्थापित करने तथा अन्य व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित करने से संबंधित कार्य करने पड़ते है। एक सफल प्रबंधक वह है जो केवल अपने पद के कारण ही नहीं बल्कि अपनी बहुमुखी कार्यक्षमता द्वारा मानव संसाधनों को प्रभावित करने में सफल हो। प्रबंधक मानवीय व्यवहार को उचित प्रकार से न समझने के कारण संगठन में अच्छे मानवीय सम्बंध स्थापित करने में असफल रहते हैं जिससे उपक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा आती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रूद्रदत्त, के.पी.एम.सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था एंव वित्त, एस.चंद एंड कम्पनी लि., नई दिल्ली।
2. वार्षिक रिपोर्ट नार्दन कोल फील्ड लिमिटेड सिंगरौली (म.प्र.)। (2014-15)
3. खनन भारतीय डब्ल्यू.सी.एल. (अंक 76,1999,110-2005)।
4. समन्वय सम्मेलन दिनांक 23 अगस्त 97,डब्ल्यू.सी.एल.।
5. अंगार - कोयला परिवार का मासिक मुख्य पत्र आई.आई.जी.एम.द्वारा प्रकाशित।
6. उद्यौग एवं व्यापार पत्रिका - ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इण्डिया प्रगति मैदान नई दिल्ली।

****

मध्यप्रदेश के आर्थिक विकास में पर्यटन उद्योग का महत्व (बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. डी.सी.कुमरावत *

प्रस्तावना – भारत की हृदयस्थली के रूप में स्थापित मध्यप्रदेश अपने विस्तृत क्षेत्र में स्थापित पर्यटन की असीम सम्भावनाऐं है। सतपुडा और विन्ध्यांचल पर्वत श्रृंखलाओं से आच्छादित इस प्रदेश में विभिन्न रूचि और धर्म के पर्यटकों के लिये सांस्कृतिक विरासत, नैसर्गिक सौन्दर्य, कलात्मक मंदिर एवम् पुरातात्विक महत्व के स्मारक मौजूद है। देश और प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की अनन्त सम्भावनाऐं छुपी हुई है। अविभाजित मध्यप्रदेश में लगभग 453 पर्यटन केन्द्र स्थित थे, जिनमें से 71 पर्यटन केन्द्र पृथक छत्तीसगढ़ राज्य स्थानान्तरित हो गये है।

बडवानी जिला भी पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जिला है। इस जिले अनेक ऐसे स्थान है, जहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक आते है। इन्दौर संभाग में बडवानी जिला एक जनजातीय बहुल जिला है और ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को समेटे हुऐं है, जो पर्यटन की दृष्टि से न केवल बड़वानी जिले के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, वरन् मध्यप्रदेश के आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। बड़वानी जिले प्रमुख पर्यटन स्थलों में निम्नलिखि को शामिल किया जा सकता है :-

1 बावनगजा पैन सिध्द क्षेत्र – बड़वानी जिला मुख्यालय से 07 किलोमीटर दूर बावनगजा जैन सिध्द क्षेत्र स्थित है। यहाँ एक ही पाषण शिला में उकेरी गई भगवान आदिनाथ की 52 गज ऊँची प्रतिमा है। यह जैन धर्म के अनुयायियों के लिये एक पावन तीर्थ है। यहाँ कुम्भ और सिहस्थ मेले की तरह ही हर 12 वर्ष में मेले का आयोजन किया जाता है, लाखों की संख्या में पर्यटक आते है। इसके अलावा इस क्षेत्र में वार्षिक मेले का भी आयोजन किया जाता है। पौराणिक कथा अनुसार बावनगजा सतयुग में मेघनाथ और कुम्भकर्ण की तपस्या स्थली के रूप में जाना जाता है। यहाँ भगवान आदिनाथ की मुख्य प्रतिमा के अतिरिक्त अनेक जिनालय है, जो जैन सम्प्रदाय के लोगों की आस्था के केन्द्र है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के ठहरने के लिये लिये धर्मषाला और भाजनालय की भी समुचित व्यवस्थ है।

2 शहीद भीमानायक स्मारक, धाबा बावड़ी – बड़वानी जिले का यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह स्मारक बड़वानी जिला मुख्यालय से 2 किलोमीटर दक्षिण में धाबा बावड़ी में स्थित है। शहीद भीमानायक का कार्य क्षेत्र बड़वानी रियासत से वर्तमान महाराष्ट्र के खान देश तक रहा है। भीमानायक ने सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अग्रेजों के विरूध्द संघर्ष किया था। अग्रेज सरकार द्वारा पर उन पर दोष सिद्ध होने पर किसी करीबी व्यक्ति की मुखबिरी पर गिरफ्तार कर पोर्ट ब्लेयर और निकोबार में रखा गया था। 29 दिसम्बर 1876 को पोर्ट ब्लेयर में उनकी मृत्यु हो गयी थी।

शहीद भीमानायक की स्मृति में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा धाबा बावड़ी में एक स्मारक का निर्माण करवाया गया है, जिसका प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिह चौहान द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2017 को लोकार्पण किया गया था। साथ ही , जनजातीय क्षेत्र के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भीमानायक के क्रान्तिकारी जीवन वृत्तको दर्शाने वाले 52 चित्रों के संग्रहालय का भी उद्घाटन किया था। वर्तमान में शहीद भीमानायक का यह स्मारक पर्यटकों एवम् इतिहासकारों के लिये प्रेरणादायक स्थल बन गया है।

3 तीर–गोला स्मारक बड़वानी – बड़वानी रियासत के महाराजाओं द्वारा भव्य इमारतों का निर्माण किया गया था, जिसमे 'तीर–गोला स्मारक ' आज भी बड़वानी की खास पहचान बना हुआ है। इस स्मारक का निर्माण बड़वानी रियासत के महाराजा राणा देवीसिह द्वारा अपने भाई स्व. राणा उदयसिह जी की स्मृति में किया गया था। यह स्मारक बड़वानी आने वाले पर्यटकों के लिये आकर्षण का केन्द्र है।

4 बिजासनी माता मंदिर, सेन्धवा – बड़वानी जिला मुख्यालय से 77 किलोमीटर दूर स्थित सेन्धवा में माता बिजासनी देवी का प्रसिध्द मंदिर है। नवरात्री के समय यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचते है। पर्यटन की दृष्टि से यह मंदिर काफी महत्व रखता है।इस मंदिर का इतिहास 1000 साल पुराना है। यहाँ माँ दुर्गा के नौ स्वरूप विद्यमान है। अतीत में यह इलाका काले हिरणों और मंत्र मंत्र सिद्धी के लिये विशेष रूप से जाना जाता था। इस मंदिर का निर्माण इंदौर के महाराजा श्री शिवाजीराव होल्कर द्वारा सन 1760 में किया गया था। पूर्व में इस मंदिर का निर्माण मराठा शैली में किया गया था। यह मंदिर वास्तुकला का एक नायाब नमूना है। इन्दौर रेल्वे स्टेषन से इस मंदिर की दूरी 9.8 किलोमीटर है तथा यहाँ पहुँचने मे करीब 27 मिनट का समय लगता है।

5 नागेश्वर शिखर धाम मंदिर, नागलवाड़ी – सतपुड़ा की हरी भरी वादियों में बड़वानी जिले की राजपुर तहसील के ग्राम नागलवाड़ी में भीलटदेव का शिखर धाम मंदिर स्थित है। शिखरधाम नागलवाड़ी बड़वानी जिला मुख्यालय से 74 किलोमीटर, खरगोन से 50 किलोमीटर तथा सेंघवा से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिखर धाम तक पहुँचनें के लिये आवागमन के पर्याप्त साधन माजूद है।

नागलवाड़ी शिखरधाम संस्थान के अनुसार सावन की नागपंचमी पर यहाँ लाखों श्रद्धालुगण भीलट बाबा के दर्शन के आते है। जिला प्रशासन बड़वानी के सहयोग से नागपंचमी पर प्रतिवर्ष 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भीलटदेव का जन्म लगभग 853

* एसोसिएट प्राध्यापक (वाणिज्य) शहीद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

वर्ष पूर्व म.प्र. के हरदा जिले के ग्राम रोलगाँव पाटन में हुआ था। उनकी माता का नाम मेदाबाई और पिता का नाम रेलन राणा था। गवली परिवार के श्री रेलन भगवान शिव के परम भक्त थे। संतान नही होने के कारण भीलट देव के माता पिता ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके यहाँ एक सुन्दर बालक को जन्म दिया जिसका नाम भीलटदेव था। भगवान शिव ने भीलट देव के माता पिता से यह वचन लिया था कि वे एक दिन उनसे दूध दही की माँग करने उनके यहाँ आयेगें। यदि भीलट देव के माता पिता उन्हे नही पहचान पाये तो वे भीलटदेव को उठाकर ले जायेगें। अपने बच्चें के लालन पालन में भीलटदेव के माता पिता भगवान शिव को दिया वचन भूल जाते है और जब एक दिन भगवान शिव पार्वती संग दूध दही माँगने आते है तो वे उन्हे नही पहचान पाते है। तब भगवान शिव बालक को पालने से उठाकर उसकी जगह अपने गले के नाग को रख देते है और बालक को लेकर चौरागढ़ (वर्तमान में पंचमढ़ी) चले जाते है। पालने मे अपने बालक की जगह नरग को देखकर भीलटदेव के माता पिता बेहोश हो जाते है और उनके द्वारा पुन: भगवान शिव की तपस्या किये जाने पर भगवान शिव द्वारा यह आशीर्वाद दिया जाता है कि हमने आपके यहाँ पालने में जो नाग रखा था उसकी पूजा नाग और भीलटदेव दोनों ही रूपों में की जायेगी, लेकिन भीलटदेव की शिक्षा हमारे द्वारा ही पूर्ण की जायेगी।

भगवान शिव से शिक्षा दिक्षा प्राप्त किये जाने के बाद भीलटदेव को भगवान शिव द्वारा नागलवाड़ी के पास शिखर चोटी पर विराजित होकर जनकल्याण करने का आशीर्वाद दिया जाता है। तब से भीलट बाबा नागलवाड़ी से चार किलोमीटर दूर शिखरधाम पर विराजित है। यद्यपि भीलटदेव का मंदिर 700 वर्ष पुराना है किन्तु वर्ष 2004 में गुलाबी पत्थरों से भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है। इस प्रकार शिखरधाम बड़वानी जिले का पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है।

निष्कर्ष – उपर्युक्त पर्यटन स्थलों के अतिरिक्त बड़वानी जिला मुख्यालय पर सागर विलास, सुख विलास, इन्द्रभवन (पूर्व महाराजा का दरबार), म.गा. मार्ग पर मोठी माता मंदिर के सामनें स्थित शाही बावड़ी, बंधान का झरना , बावनगजा का झरना, माँ वैष्णों देवी का मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है, जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण केन्द्र है। आवश्यकता है, उन्हे सँजाने, सँवारने और संरक्षित करने की। बड़वानी जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये शासन एवम् प्रशासन स्तर पर प्रभावी प्रयास किये जाने चाहिये ताकि बड़वानी जिले के इन पर्यटन केन्द्रों को म.प्र. के पर्यटन मानचित्र में जगह प्राप्त हो सकें। यदि ऐसा किया जा सका तो बड़वानी जिले के पर्यटन स्थल राजस्व उपार्जन के महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते है और बड़वानी जिले के आर्थिक विकास के साथ साथ मध्यप्रदेश के आर्थिक विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगें – इसमें कोई संदेह नही है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. भारत के पर्यटन स्थल–श्री मधुसूदन शर्मा, नई सदी पब्लिकेशन
2. भारतीय पर्यटन के नये आयाम–श्री सुभाष सेतिया, नई दिल्ली
3. म.प्र. ट्रेवल्स गाईड, भोपाल
4. समाचार पत्र–नई दुनिया, दैनिक भास्कर
5. पत्र–पत्रिकाऐं।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

धार जिले में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की स्थिति एक अध्ययन (वर्ष 2002-2011)

डॉ. बी. एस. सिसोदिया *

प्रस्तावना - भारत एक ग्रामीण बाहुल्य देश है। ग्रामों के सुधार एवं पुनउद्धार के लिए स्वास्थ्य एवं सफाई की अत्यधिक आवश्यकता है। अधिकांश गांवों में पेयजल की अपर्याप्त, खाद्य पदार्थों में मिश्रण तथा गंदगी होने के कारण अनेक प्रकार की बिमारियों का प्रकोप गांवों में हा जाता है, जिससे श्रम की कुशलता नष्ट हो जाती है एवं मृत्यु दर में अधिकता पाई जाती है।

धार जिले में स्वास्थ्य कार्यक्रमके अंतर्गत परिवार कल्याण कार्यक्रम, मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम, क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किये गए है। अध्यापन की दृष्टि से जिले में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की स्थिति को स्पष्ट किया गया है।

मलेरिया एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी को सर्दी और सिरदर्द के साथ बार-बार बुखार आता है। गंभीर मामलों में रोगी कोमा में चला जाता है या उसकी मृत्यु तक हो जाती हैं

मलेरिया प्लाज्मोडियम (PAISMOIUM) नाम परजीवी के कारण होता है। मलेरिया मादा एनोफेलीज मच्छर (ANOPHELES MOSQUITO) के काटने से शुरू होता है जो इस परजीवी को शरीर में छोडता है।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य मलेरिया रोग की रोकथाम एवं उससे प्रभावित लोगों का उपचार करना है। इसमें रोग का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। संभावित रोगी के खुन की जांच कर लक्षण पाये जाने पर चिकित्सा उपाय किये जाते है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला मलेरिया कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

अध्ययन का उद्देश्य - धार जिले में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किस प्रकार किया गया यह देखना इस शोध पत्र का महत्वपूर्ण भाग है।

समंक संकलन - प्रस्तुत शोध-पत्र धार जिले में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की स्थिति पर आधारित है। यह द्वितीय स्त्रोतों से प्राप्त समंकों पर आधारित है उक्त अध्ययन हेतु वर्ष 2002 से 2011 के समंकों का संकलन कार्यालय जिला चिकित्सालय जिला धार से किया है।

जिले में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की स्थिति को तालिका 1 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1 (देखे अगले पृष्ठ पर)

विश्लेषण - तालिका 1 से स्पष्ट है कि वर्ष 2002 में 224797 रक्त पट्टियों के एकत्रीकरण का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरूद्ध 278442 रक्त पट्टियों का एकत्रीकरण किया गया जो कि लक्ष्य का 123.86 प्रतिशत रहा जिसमें 515 केसेस पॉजिटीव थे। वर्ष 2003, 2004, 2005 एवं 2006 में क्रमश: 286761 रक्त पट्टियाँ, 354863 रक्त पट्टियाँ, 282049 रक्त पट्टियाँ एवं 292945 रक्त पट्टियाँ एकत्रित की गयी, जो लक्ष्य की क्रमश: 124.45 प्रतिशत, 150.25 प्रतिशत, 116.57 प्रतिशत एवं 118.05 प्रतिशत रही। वर्ष 207 में 248230 रक्त पट्टियों के एकत्रीकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरूद्ध 247402 रक्त पट्टियों का एकत्रीकरण किया जो 99.66 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2008 में 254595 रक्त पट्टियों के एकत्रीकरण का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरूद्ध 239465 रक्त पट्टियों का एकत्रीकरण किया गया, जो लक्ष्य का 94.05 प्रतिशत रहा। वर्ष 2009 एवं 2010 में एकत्रित की गयी रक्त पट्टियों में पॉजिटीव केसेस क्रमश: 1355 एवं 5946 रहें। वर्ष 2011 में 274686 रक्त पट्टियों के एकीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरूद्ध 318866 रक्त पट्टियाँ एकत्रित की गयी जिसमें 4532 पॉजिटीव केसेस रहें।

निष्कर्ष - इस प्रकार वर्ष 2002 से 2011 तक की अवधि में 2489058 रक्त पट्टियॉ एकत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरूद्ध 2838150 रक्त पट्टियों का एकत्रीकरण किया गया जो कि लक्ष्य का 114.02 प्रतिशत रहा। रक्त पट्टियों की जांच के दौरान 33685 पॉजिटीव केसेस पाये गये जिसमें 19616 पी.व्ही. केसेस तथा 14069 पी.एफ. केसेस सम्मिलित है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 33630 रोगियों को मेडिकल ट्रिटमेंट दिया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के शासकीय प्रयास सफल रहे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. वी.आर. कुमार - जनांकिकी।
2. गुप्ता, सुरेश - आगे आए लाभ उठाए (एल.के. जोशी) आयुक्त, जनसंपर्क, भोपाल (म.प्र.)
3. कार्यालय, जिला चिकित्सालय, धार (म.प्र.)
4. दैनिक पत्र - पत्रिकाएं

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

तालिका 1 – धार जिला राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना की स्थिति

वर्ष	रक्त पट्टियों के एकत्रीकरण का लक्ष्य	रक्त पट्टियों के एकत्रीकरण की उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत	रक्त पट्टियों जिनकी जांच की गई	पॉजिटीव केसे संख्या	पी.वी. केसेस संख्या	पी.एफ. संख्या	मेडिकल ट्रिटमेंट रोगी
2002	224797	248442	123.86	278442	515	380	135	509
2003	230417	286761	124.45	286761	2107	1385	722	2100
2004	236177	354863	150.25	354863	9739	4680	5059	9725
2005	242081	282049	116.57	282049	3809	2703	1106	3802
2006	248133	292945	118.05	292945	2300	1582	718	2300
2007	248230	247402	99.66	247402	2108	1164	944	2103
2008	254595	239465	94.05	239465	1274	816	458	1270
2009	261123	261444	100.12	261444	155	797	558	1351
2010	268819	275913	103.02	275913	5946	3192	2754	5940
2011	274686	318866	116.88	318866	4532	2917	1615	4530
योग	2489058	2838150	114.02	2838150	33685	19616	14069	33630

स्त्रोत– कार्यालय जिला चिकित्सालय धार (म.प्र.)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

बचत एवं विनियोग को प्रोत्साहित करने में वित्तीय संस्थाएँ: डाकघर एवं बैंक

डॉ. एन.एल.गुप्ता * ऊँकार सिंह रावत **

प्रस्तावना – यद्यपि भारत के शिक्षित व दूरदर्शी जन – समूहो द्वारा बचत व विनियोग की प्रक्रिया में सहर्ष प्रतिभाग लिया जाता है किन्तु शेष समुदाय की संस्कृति व उपयोग प्रधान व्यय प्रवृत्ति के कारण प्राय: बचत की प्रवृत्ति से लोग विमुख रहते है। ऐसी परिस्थितियों का निपटान करने के लिए शासन द्वारा अग्रणी भूमिका का निर्वहन करते हुए बचतों को पल्लवित कर पूँजी निर्माण की दर में वृद्धि करता है। अपने इस ध्येय की पूर्ति में शासन कभी-कभी जन- जागरण, प्रचार- प्रसार एवं प्रोत्साहन के माध्यम से बचत करवाता है तथा कभी आवश्यकता होने पर अनुशासनात्मक आदेशों के आधार पर बचत करवाता है।

यह स्पष्ट है कि सुविधाओं के अभाव में किसी भी निवेशक या निवेशक संस्थाओं द्वारा धन की बचत होती ही नहीं या बचतों को इस तरह से रखा जाता है जिससे धन की उत्पादकता शक्ति नष्ट हो जाती है। देश में हो रहे शनै:-शनै: आर्थिक व सामाजिक विकास से देश में पूँजी निर्माण की संकल्पना दृष्टिगत हो रही है। राष्ट्र में पूँजी निर्माण व बचत को प्रोत्साहित करने में शासन अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता रहा है। सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ निवेशको को उपलब्ध करवाई जाती है। इन सुविधाओं में मुख्य रूप से सरकार वित्तीय संस्थाओं की सुविधा, निवेश संरक्षण कार्यक्रम एवं शिक्षा, निक्षेपगारो की सुविधा के साथ कर छूट संबंधी सुविधाएँ भी शामिल है। इस सुविधा के अंतर्गत सरकार द्वारा विविध कानूनी रूपी रेखाओं व अधिनियमों के अधीन विभिन्न वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की जाती है जिसका मुख्य कार्य बचतों का संग्रहण करना है। शासन इस श्रृंखला में डाकघर बैंक, विनियोग बैंक, म्युच्युअल फण्ड, जीवन बीमा निगम जैसी विभिन्न संस्थाओं को स्थापित करने में तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संचालित करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है।

इन महत्वपूर्ण संस्थाओं का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है:-

डाकघर – यद्यपि डाकघर का मुख्य कार्य डाक संबंधी सेवाओं को संपादित करना है। बढ़ती हुई बैंकिंग आवश्यकताओं के समाधान के लिए 'बचत बैंक अधिनियम 1873' के आधार पर डाकघर बचत बैंक की स्थापना की गई। इस योजना की सफलता के पश्चात् वर्ष 1884 में पोस्टल लाईफ इन्श्युरेंस सेवाएँ भी डाकघर द्वारा प्रारम्भ की गई जिसमें विनियोग के साथ जीवन सुरक्षा का दोहरा लाभ प्रदान किया जाता है। डाकघर की सम्पूर्ण गतिविधियों पर सरकार द्वारा अपने दो केंद्रीय मंत्रालय क्रमष: दूर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण रखा जाता है। डाकघर 'बैंक' के कार्य वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में संचालित करता है।

सम्पूर्ण डाक व्यवस्था को 22 सर्कल व 37 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिसमें 442 विभागीय कार्यालय है। भारत में कुल 155035 डाकघर है जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 139173 डाकघर व शहरी क्षेत्रों में 15862 डाकघर है। कुछ विशेष क्षेत्रों में 163 रात्रीकालीन डाकघर भी कार्यरत् है जो अपने ग्राहको को सेवाएँ दे रहे है।

डाकघर की सफलता का मुख्य कारण डाकघर द्वारा तकनीकी रूप से सर्कल व क्षेत्रीय विभागीय कार्यालयों के माध्यम से देश के कोने – कोने में योजनाएँ पहुँच बनाना एवं सेवाओं के माध्यम से जनविश्वास हासिल करना रहा है। इसके साथ ही डाकघर में बदलते हुए परिवेश के अनुसार अपनी प्रतिस्पर्धी वित्तीय संस्थाओं में होने वाले नवोन्मेशी परिवर्तनों को भी आत्मसात करता है। इसी कारण से बैंकिंग संस्थाओं की तर्ज पर एक छत के नीचे एक स्थल पर वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध करवाने हेतु य डाक वित मार्ट य स्थापित किए है। वर्तमान में 313 'डाकवित्त मार्ट' कार्यरत है। डाकघर स्वयं तो प्रत्यक्ष रूप से बचत एवं विनियोग करने में सलग्न है किन्तु 22 जनवरी 2001 से 1000 डाकघर अपनी योजनाओं के साथ एस.बी.आय.एम.एफ., यू.टी.आय. आदि म्युच्युअल फण्ड की योजनाएँ भी जनता को सुलभ करवा रहा है। इसी प्रकार से डाकघर जीवन बीमा एवं गैर-जीवन बीमा कम्पनियों के उत्पादों को ग्राहक तक पहुँचाने का कार्य सफलतापूर्वक कर रहा है। विविध जीवन बीमा योजनाएँ जो डाकघर स्वयं संचालित करता है उसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारी अग्रणी रूप से सहभागी है।

डाकघर पुरे देश में जाल की तरह बिछी अपनी शाखाओं एवं उपशाखाओं के माध्यम से शहरों के अतिरिक्त छोटे-छोटे गॉवों में अपनी विभिन्न योजनाओं के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाता है एवं बचतों को प्रोत्साहन देता है।

बैंक – भारतीय वित्त बैंकिंग संस्थाओं में राष्ट्रीय बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक एवं भूमी विकास बैंक को सम्मिलित किया जाता है। एक सामान्य बचतकर्ता जो नियमित रूप से बचत कर , उस पर सुरक्षित व सुनिश्चित प्रतिफल अर्जित करना चाहते है वो बैंकों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं में धन विनियोजित करते है। भारत में प्रथम बैंक 1786 में 'द जनरल बैंक ऑफ इण्डिया' व 'द हिन्दुस्तान' के रूप में स्थापित किये गये थे। भारत में सबसे पुराना बैंक भारतीय स्टैट बैंक जिसकी स्थापना

* प्राध्यापक (वाणिज्य) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (वाणिज्य) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

1806 में की गई थी जिसे बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से जाना जाता था। सन् 1935 में केन्द्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित किया गया जिसका मुख्य कार्य भारत में बैंकिंग उद्योगों का नियमन, संर्वधन व नियंत्रण करना था। सरकार ने 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों व 15 अप्रेल 1980 को 6 बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसे बैंको के लिये उसके गाहको व निवेशको के विश्वास में बढ़ौतरी हुई है। बैंको के राष्ट्रीयकरण के परिणाम स्वरूप देश की बैंकिंग व्यवस्था में कॉफी बदलाव आया है। आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगो को भी बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं का लाभ मिलने लगा। जो बैंक पहले अपने लाभों पर ध्यान देते थे, वे अब जनहित पर ध्यान देकर सरकारी योजनाओं के अनुसार कार्य करने लगे। अपनी योजनाओं को आम लोगों तक पहुॅचाने के लिये सन्1975 से वाणिज्यिक बैंको द्धारा 'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' का प्रर्वतन प्रारम्भ हुआ ताकि उसी क्षेत्र के लोग अपने अनुभव के आधार पर अपने ही क्षेत्र के लोगों की अच्छी सेवा कर सके।

सरकार द्धारा बैकिंग क्षेत्र में किये गये सुधारों के उपरान्त देश में नीजी एवं विदेशी बैंको ने बैंकिंग क्षेत्र के परिदृष्य को परिवर्तित कर अधिक तकनीकीपूर्वक व विश्वसनीय बनाया है, साथ ही बैंकिंग संबंधी किसी भी शिकायत के निवारण हेतु एवं ग्राहको व निवेशको के संरक्षण हेतु वर्ष 2006 में 'बैंकिंग लोकपाल योजना' का सुभारंभ किया गया है।

वास्तव में आधुनिक बैंको के कार्य व उनकी जनसमुदाय के प्रति उपयोगिता इतनी विशाल है कि यदि एक दिन के लिये भी बैंक कर्मचारी हड़ताल कर दे तो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ता है और यदि ये हड़ताल कुछ लम्बे समय तक हो जाये तो सम्पूर्ण व्यापार जगत अस्त-व्यस्त हो जायेगा, क्योंकि समस्त व्यापार प्रत्येक्ष या अप्रत्येक्ष रूप से बैंकों पर ही आश्रित रहता है। यह सत्य की कहा गया है कि बैंक साख के निर्माता तथा विनिमय को सुविधाजनक बनाने वाला यंत्र है।

सभी वित्तीय संस्थान एवं विकास बैंको की स्थापना में केन्द्र व राज्य शासन की महत्वपूर्ण भुमिका होने से निवेशको के विश्वास को जीतना इन संस्थाओं को सुलभ हो जाता है इस संस्थाओं के द्धारा ही बचतों को एकत्र कर विशाल पूँजी निर्माण करते हुए देश के बुनियादी उद्योगो के विकास के लिये धन उपलब्ध करवाया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. 'बैंकिंग विधि एवं व्यवहार' , ओझा बी.एल., रमेश बुक डिपो, जयपुर, 2011
2. 'भारत में अधिकोषण' , प्रो. अग्रवाल वी.पी., साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा-03,2010
3. 'वित्तीय परामर्श', श्री शिवरामन बी., इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, मुंबई, 2013
4. भारतीय डॉकघर की वार्षिक रिपोर्ट
5. www.indianpostoffice.com.
6. wwww.indiapost.gov.in

****

भारत में महिला उद्यमियों के विकास हेतु - सरकारी प्रयास

डॉ. अनिल तौहेल *

प्रस्तावना - एक उद्यमी का आशय ऐसे व्यक्ति से है, जो व्यापारिक अवसर की पहचान करता है, नये व्यवसाय की स्थापना हेतु आवश्यक कदम उठाता है, व्यवसाय उपक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न संसाधनों जेसे व्यक्ति, सामग्री और पूंजी को एकत्र करता है, और निहित जोखिम व अनिश्चिताओं को वहन करता है। उद्यमी द्वारा किये गये कार्य ही उद्यमिता है अत: उद्यमिता को एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जा सकता है जिसमें निम्नलिखित क्रियाए सम्मिलित हो -

1. बाजार में उपस्थित अवसरों को पहचानना एवं प्रयोग करना।
2. विचारों को क्रिया में परिवर्तित करना।
3. किसी नये उद्यम को प्रांरभ करने के लिए प्रवर्तन कार्य करना।
4. अपने कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठतम प्रदर्शन का प्रयत्न करना।
5. निहित जोखिम एवं अनिश्चिताओं को वहन करना।
6. समरूपता लाना।

अत: उद्यमिता का आशय उस कौशल दृष्टिकोण, चिंतन, तकनीक एवं कार्यप्रणाली से है जिसके द्वारा व्यवसाय में निहित अनेक प्रकार के जोखिम एवं अनिश्चिताओं का सामना किया जाता है, एवं व्यवसाय को संचालित किया जाता है। किसी भी राष्ट्र के आर्थिक-सामाजिक विकास के लिये उपलब्ध संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है मानव/मानव संसाधन ही सजीव है जो अन्य संसाधनों को अपने कल्पनाओं एवं योजनाओं विकास को एक गति और दिशा प्रदान करता है औद्योगीकरण एवं उसका स्तर उद्यमी चिंतन, सकारात्मक प्रयास और मानव संसाधन के उपयोग पर निर्भर करता है। भारतीय आधुनिक समाज के विकास की आज सबसे बड़ी जरूरत है उद्यमिता का विकास और पूर्ण ओद्योगीकरण। चूंकि महिलाए शुरू से ही अपने आस पास के परिवेश में कार्य करते हुए उचित प्रबंध कौशल का परिचय देती है इसलिए यदि इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हुए उन्हे एक व्यावसायिक/आद्योगिक ईकाई चलाने का अवसर मिलता है तो संभव है कि वे उसे भी इतनी सक्षमता से चला सकें। कम से कम संसधनों में कार्य करने की प्रवृत्ति तथा अपने घर व बाहर के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं में सुव्यवास्थित ढंग से कार्य करने में निपुण रखने के कारण वे उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में भी काफी अच्छा काम कर सकती है लेकिन इस सब कार्यो के लिये जहां एक तरफ सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं की अहम भूमिका है वहीं दसरी तरफ सामाजक स्तर पर कार्य रकने वाले संस्थानों ओर समाज के विभिन्न वर्गो से जुड़े हुए लोगों में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे विभागों और संस्थाओं को तो इस क्षेत्र में और अधिक अवश्यक हो जाता है। कि वे अपने सभी कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने में अधिक से अधिक संख्या में महिला वर्ग के प्रतिनिधियों को अमित्रित करे जिससे आशानुरूप सफलताओं को देखते हुए अन्य महिलाए आगे आ सकें।

उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश ने पिछले पांच वर्षो से इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए न केवल इस वर्ग के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये है बल्कि इनको और अच्छी तरह से आगे लाने के लिए जागरूकता शिविर और संचार के अन्य माध्यमों से उद्योग और व्यवसाय से संबंधित सभी जानकारी पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इस क्षेत्र मे जहां एक तरफ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने कार्य किया है वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कार्यरत महिला आर्थिक विकास निगम, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं तकनीकी परिषद, महिला बाल विकास विभाग तथा ग्रामोद्योग विभाग ने भी अपना योगदान प्रदान किया है। आने वाले दिनों में अधिक से अधिक महिलाए इस क्षेत्र में पदार्पण करेंगी ओर अपने को सफल उद्यमी के रूप में समाज में स्थापित कर पायेंगी।

चुनौतियां/समस्याए -

1. भारतीय महिलाओं में आज भी आर्थिक एवं व्यावसायिक जोखिमों को वहन करने की क्षमताओं का नितांत अभव बना हुआ है।
2. भारतीय महिलाओं को अपने परिवार की परंपराओं और कैरियर के मध्य समन्वय स्थापित करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
3. भारतीय महिला उद्यमियों को लिंग भेद का सामना करना पड़ता है।
4. भारतीय महिला उद्यमी आज भी सामाजिक परम्पराओं में जकड़ी जुई महसूस करती है।
5. पुरूष प्रधान समाज महिलाओं की कार्य एवं निर्णयन क्षमता को सदैव संशय की दृष्टि से देखता है।
6. निवेशको द्वारा भी महिलाओं द्वारा संचालित उद्योगो को संशय की दृष्टि से देखा जाता है।
7. हमारे देश में आज भी महिला उद्यमियों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव है।
8. भारतीय महिलाओं की कोई निजी सम्पत्ति नही होती है कई बार उनका बैंक में खाता तक भी नही होता है।

भारतीय सामाजिक संरचना में महिला उधमियों के प्रति सकारात्मक परिवर्तन आने तथा सरकारी नितियों में महिला उधमियों को विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित करने के कारण आज हमारे देश में महिला उधमिता का निरन्तर विकास हो रहा है, सरकार और समाज के सभी प्रयासों के कारण आज भारतीय महिलाये फुटकर व्यापार रेस्टेरेन्ट, होटल, ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजाईनिंग, कम्प्यूटर सॉफटवेयर, हस्तशिल्प, कृषि कूटीर

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय तिलक पी.जी. महाविद्यालय, कटनी (म.प्र.) भारत

उधोग आदि क्षेत्रों में नये कीर्तिमान स्थापित कर रही है।

सरकारी प्रयास – केन्द्र सरकार द्धारा महिलस उधमियों के लिये विशिष्ट योजनाये तो संचालित की जा रही है,साथ ही सरकारी बैंको द्धारा रियायती ब्याज दरों पर एवं आसान ऋण शर्तो पर पूँजी उपलब्ध कराई जा रही है, इन विशिष्ट योजनाओं मे प्रमुख्य निम्नानुसार है –

1. **भारतीय महिला बैंक व्यवसाय ऋण –** उन महिला उधमियों के लिये जो सूक्ष्म ऋण या सम्पत्ती के विरुध ऋण फुटकर करोबार के लिये ऋण तथा अन्य नवाचार गतिविधियों आदि के लिये ऋण तथा व्यवसाय से जुडना चाहती है, अधिकतम 20 करोड रु. तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
2. **सेंट कल्याण योजना –** सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया द्धारा संचालित इस योजनार्तगत उन महिला उधमियों को 1 करोड रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्रो में नवीन लघू एवं कुटीर उधोग एवं स्वरोजगार हेतु कार्यरत है।
3. **मुद्रा योजना –** भारत सरकार द्धारा व्यक्तिगत रुप से अथवा संयुक्त रुप से टेलरिंग युनिट्स, ब्यूटी पार्लर, टयूशन सेर्न्टस आदि क्षेत्रों मे नवीन लघू उपक्रम प्रराभ करने हेतु बिन प्रतिभूति के ऋिण उपलब्ध कराया जाता है, इस योजना के अन्तर्गत तीन प्रकार के लोन उपलब्ध कराये जाते है।

अ. शिशू इकाईयॉ– नवीन उपक्रम प्रारम्भ करने हेतु अधिनियम 50000 रु.तक।

ब. किशोर इकाईया– पूर्व से स्थापित उपक्रमों हेतु 50000 से 5 लाख रु.तक।

स. तरुण इकाईयॅा– कारोबार का भावी विकास एवं विस्तार हेतु 10 लाख रु.।

4. **अन्नपूर्णना योजना –** डिब्बा बन्द भोजन, स्नेक्स एवं फूटकेटरिंग उधोंग हेतु महिला उधमियो को 50000रु. तक का ऋण उपलब्ध करायो जाता है।
5. **स्त्री शक्ति पैकेज योजना–** किसी फर्म या व्यवसाय के 50 प्रतिशत अंशों पर स्वमित्व रखने वाली महिलाओं कों सरकारो द्धारा आयोजित उधमिता विकास कार्यक्रमों में भागीदारी हेतु भारतीय स्टेट बैंक द्धारा ऋण प्रदान किया जाता है।
6. **उधोगिनी योजना–** देश में लघु महिला उपक्रमो को प्रोत्साहित करने तथा युवा महिला उधमियो को कृषि क्षेत्र से संबंध रखने के उद्देश्य से पंजाब एंव सिंघ बैंक द्धार संचालित इस योजनार्तगत 18 से 45 साल की महिलाओं को 1 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
7. **देना शक्ति योजना–** रिटेल कृषि कार्यो, सूक्ष्म साख तथा लधू उपक्रमों को संचालित करने के लिये देना बैंक द्धारा 50000 रु. से 20 लाख रु. तक का ऋण उपलब्ध करायो जाता है।
8. **ओरिएण्टल महिला विकास योजना–** ओरिएण्टल बेंक ऑ कॉमर्स द्धारा उन महिलाओ को ऋण सहायता प्रदान की जाती है, जो व्यक्तिक व संयुक्त रुप से किसी उपक्रम की 50 प्रतिशत अंशपूजी पर मलिकाना हक रखती है, इस योजनार्तगत 10 से 25 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।
9. **महिला उद्यम निधि योजना –** पंजाब नेशनल बैंक द्धारा संचालित इस योजनार्तत 10 साल की पुर्नभुगतान अवधि के साथ उदार एवं आटो रिक्शा, टूव्हिलर्स, कार आदि का क्रय करने अथवा डे केयर सेन्टर, ब्यूटी पालर्र अथवा अन्य लघु स्तरीय उपक्रम संचालित करने हेतु 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. शर्मा राजीव, डॉ. शर्मा राजेन्द्र, डॉ. चंदेल योगिता, उद्यमिता विकास यशराज प्रकाशन, इंदौर।
2. रिसर्च लिंक जनवरी 2006
3. प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2018

****

धार जिले में मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम की स्थिति - एक अध्ययन (वर्ष 2002-03 से 2010-11)

डॉ. बी.एस. सिसोदिया *

प्रस्तावना - देश की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही हैं वहीं दूसरी तरफ 70 प्रतिशत आदिवासियों में अशिक्षा, गरीबी एवं अज्ञानता विद्यमान है। उनमें रूढिवादिता व्याप्त है इन्हीं परिस्थितियों ध्यान में रखकर सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ किये है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य केवल जनसंख्या वृद्धि को रोकना ही नहीं वरन् असमय प्रसूति के दुष्परिणामों से मातृत्व की रक्षा करना वांछित समय पर संतान के उत्तम पालन पोषण की व्यवस्था भी कराना है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाता है।

मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य नवजात शिशुओं और गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना है इसके अंतर्गत टीकाकरण, श्वास रोग नियंत्रण, दस्त रोग नियंत्रण, अंधतव से बचाव नवजात शिशु तथा गर्भवती महिलाओं की देखभाल की जाती है।

उद्देश्य - धार जिले में मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम का क्रियान्यन विभाग द्वारा किस प्रकार किया गया है यह देखना इस शोधपत्र का महत्वपूर्ण भाग है।

समंक संकलन - प्रस्तुत शोध-पत्र धार जिले में मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम की स्थिति पर आधारित है। यह द्वितीय स्त्रोतों से प्राप्त समंकों पर आधारित है उक्त अध्ययन हेतु वर्ष 2002-03 से 2010-11 के समंकों का संकलन कार्यालय, जिला चिकित्सालय जिला, धार से किया है।

जिले में मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम की स्थिति को अग्रतालिका में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका क्रमांक - 01 (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका क्रमांक - 1 (अ) (देखे आगे पृष्ठ पर)

विश्लेषण - तालिका क्रमांक 1 एवं 1(अ) का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि धार जिले में मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2002-03 से 2010-11 तक की अवधि में एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों में टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बी.सी.जी. टीकों का कुल लक्ष्य 502784 रखा गया था जिसके विरूद्ध496636 टीके लगाये गये। डी.पी.टी. बुस्टर एवं ओ.पि.वि. बुस्टर की उपलब्धि हेतु निर्धारित लक्ष्य क्रमश: 475578 एवं 475538 के विरूद्ध क्रमश: 463380 एवं 463710 रही जबकि इसी अवधि में लक्ष्य 439001 के विरूद्ध 472707 मिजल्स के टीके भी लगाये गए और 477522 बच्चों को विटामिन - ए की खुराक दी गई वहीं निर्धारित लक्ष्य 490902 के विरूद्ध 488355 बच्चों को पोलियो की खुराक दी गयी इस अवधि में 5 वर्ष के कुल 534913 बच्चों को डी.टी. (खुराक प्रथम एवं द्वितीय) देने के लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरूद्ध 490164 बच्चों को खुराक दी गयी। इस प्रकार उपलब्धि 91.63 प्रतिशत रही।

गर्भवती महिलाओं को 452897 टी.टी. के टीक लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरूद्ध 499008 टीके लगाकर 110.18 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गयी। 10 वर्ष एवं 16 वर्ष के बच्चों को टी.टी. के टीके निर्धारित लक्ष्य क्रमश: 527388 एवं 504044 के विरूद्ध क्रमश: 488715 एवं 467307 टीके लगाकर क्रमश: 92.67 प्रतिशत एवं 92.71 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की। आयरन की बडी गोलियाँ जो कि गर्भवती महिलाओं को दी जाती है, के वितरण का लक्ष्य 526051 रखा गया था, जिसके विरूद्ध 643504 बडी गोलियाँ वितरित कर 122.33 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की।

निष्कर्ष- इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि अध्ययन अवधि में स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार स्वास्थ्य शिक्षा एवं जन - शिक्षण के माध्यमों से आदिवासियों की मानसिकता में बदलाव आया है और मातृत्व एवं शिशु कल्याण कार्यक्रमों का लाभ लेने के लिये आकर्षण बडा है। इसका श्रेय विभाग द्वारा आयोजित शिविरों एवं प्रचार-प्रसार को जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गुप्ता, सुरेश आगे आये लाभ उठाये (एल.के. जोशी) आयुक्त जनसंपर्क, भोपाल।
2. डॉ. व्ही. कुमार - जनांकिकी।
3. भारत की जनगणना 2011 घटनाचक्र (समसामयिक)
4. भारतीय जनांकिकी।
5. कार्यालय, जिला चिकित्सालय, धार (म.प्र.)
6. दैनिक पत्र-पत्रिका।

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

तालिका क्रमांक - 01

धार जिले में मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम की स्थिति

वर्ष	बी.सी.जी.		डी.पी.टी. बुस्टर		मिजल्स		आ.पि.वि.बुस्टर		विटामिन -ए		DT (Does I & II) 10 वर्ष	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2002-03	50260	51660	51040	47555	51663	52074	51040	47668	50040	52045	64320	63683
2003-04	56388	51747	49758	45007	57128	50787	49714	44966	55306	50472	57010	55522
2004-05	48672	48502	44267	44139	50875	49568	44267	44139	51067	49796	64220	60210
2005-06	51920	52164	51920	52118	51919	51198	51920	52118	51919	51166	59311	56891
2006-07	55890	59803	50826	51030	56421	52204	50826	51288	55721	55721	61440	59864
2007-08	66156	59919	54269	54546	54273	53567	54269	54546	54271	53669	60110	57703
2008-09	56780	61221	56780	58109	56780	54655	56780	58109	56780	54553	57808	54403
2009-10	57265	57064	57265	57099	57269	55797	57269	57099	57265	55840	54353	51723
2010-11	59453	54560	59453	53777	59453	52857	59453	53777	59453	54260	56341	30165
योग	**502784**	**496636**	**475578**	**463380**	**439001**	**472707**	**475538**	**463710**	**491822**	**477522**	**534913**	**490164**

स्त्रोत- कार्यालय जिला चिकित्सालय धार (म.प्र.)

तालिका क्रमांक - 1 (अ)

धार जिले में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की स्थिति

वर्ष	पोलियों		टी.टी. (गर्भवती महिला)		टी.टी.(Does I & II) 10 वर्ष		टी.टी. (Does I & II) 16 वर्ष		आयरन बडी गोली गर्भवती महिला हेतु	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2002-03	50260	50755	52603	49543	65120	61330	56310	54395	59730	74573
2003-04	56388	56867	51730	50889	60405	58052	52320	50452	58940	69915
2004-05	48672	49381	52340	53570	56340	45451	58482	54289	56310	74292
2005-06	51920	52118	57112	55151	57412	54760	59410	57359	57110	87928
2006-07	55890	56117	55447	54549	63210	60737	55430	50704	56520	83738
2007-08	54271	54569	59697	60479	58120	56103	56311	54607	59695	64244
2008-09	56781	57651	60975	58872	55353	5345	5435	51356	55432	60975
2009-10	57267	57106	62993	57115	55090	51027	55091	47169	60621	62440
2010-11	59453	53791	65399	58840	56338	47820	56340	46976	61693	65399
योग	**490902**	**488355**	**452897**	**499008**	**527388**	**488715**	**504044**	**467307**	**526051**	**643504**

स्त्रोत- कार्यालय जिला चिकित्सालय धार (म.प्र.)

****

भारत में महिला सशक्तिकरण हेतु - सरकारी प्रयास

डॉ. अनिल तौहेल *

प्रस्तावना – भारत प्राचीन समय से ही अपनी सभ्यता, संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, परंपरा, धर्म और भौगोलिक विशेषताओं के लिये जाना जाता रहा है। वहीं दूसरी ओर यह पुरूषवादी राष्ट्र के रूप में भी जाना जाता रहा है क्योंकि भारतीय महिला घरों की चारदीवारी तक ही सीमित रहती थी उनको सिर्फ पारिवारिक जिम्मेदारियां ही दी जाती थी उन्हे अपने अधिकारों और विकास से बिलकुल अनभिज्ञ रखा जाता था। इस देश में आधी आबादी महिलाओं की है, इस लिए देश को शक्तिशाली बनाने के लिये महिला सशक्तिकरण जरूरी है। इस लिए समाज में जागरूकता लाने के लिये मातृदिवस अंर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसे कई कार्यक्रम संस्कार द्वारा चलाए जाते रहे है। भारत में असाक्षरों की संख्या में महिलाओं का अनुपात ज्यादा है, महिला सशक्तिकरण वास्तव में तब होगा जब इन्हे अच्छी शिक्षा दी जाएगी और इन्हे काबिल बनाया जाएगा कि वो हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसले ले सकें।

भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली राक्षसी सोच को मारना जरूरी है, जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, वैश्यावृत्ति, मानव तस्करी आदि। भारत के संविधान में उल्लिखित समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना आवश्यक है। सरकार को महिलाओं के वास्तविक विकास के लिय पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में जाना होगा और वहां की महिलाओं को सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं और उनके अधिकारों से अवगत कराना होगा। सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है, जिससे उसमें योग्यता आ जाती है, जिससे वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके।

विकास की मुख्यधारा में महिलाओं को लाने के लिये सरकार के द्वारा कई योजनाओं को निरूपित किया गया है भारतीय सरकार के इन प्रयासों के कारण देश में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया है। (राष्ट्रीय मिशन 2011 जनगणना)

'यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता:'

अर्थात् जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते है। यहां नारी को देवी के रूप में देखा गया है, भारत में नारी की दशा सदैव एक जैसी नही रही अपितु समय एवं काल के साथ परिवर्तित होती रही है।

किसी भी राष्ट्र का विकास उसकी उपलब्ध मानव शक्ति की गुणवत्ता व शिक्षा पर निर्भर होता है चूंकि किसी भी राष्ट्र की आबादी का लगभग आधा भाग महिलाएं होती है। अत: महिलाओं की स्थिति ही देश के विकास की स्थिति का सूचक भी होती है। पुरूषों के बराबर महिलाओं को वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में स्वायत्तता व निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करना ही महिला सशक्तिकरण है। सरकार द्वारा महिला उत्थान की दिशा में विभिन्न प्रयास किये गये है इनमें से कुछ प्रमुख प्रयास इस प्रकार है –

1. **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना –** युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने की इस योजना का 50% महिलाएं है – युवाओं की योग्यता के अनुरूप 6,9 व 12 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रमो के द्वारा 'रोशनी योजना' के माध्यम से तीन वर्षो में 50 हजार युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है इनमें से 40% महिलाएं होंगी।
2. **महिला किसान सशक्तिकरण योजना –** यह योजना वर्ष 2010 – 11 में शुरू की गई इसके तहत 18 राज्यो में 71 परियोजनाएं (आंध्रप्रदेश, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तारप्रदेश व तेलंगाना) राज्यों में संचालित की जा रही है, जिससे 119 जिलों की 30 से 65 लाख से भी अधिक महिला किसान लाभंवित हो रही है।
3. **दीनदयाल अंत्योदय योजना –** इस योजना के तहत सूक्ष्म ऋण के माध्यम से कृषि, पशुपालन, डेयरी उद्योग, चारा विकास, बागवानी, बैंकिंग सेवा के साथ एकाउन्ट के क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है।
4. **सुकन्या समृद्धि योजना –** यह योजना बेटी – बचाओं, बेटी पढ़ाओं की विस्तार योजना है इसका उद्देश्य भी बालिकाओं की सुरक्षा के साथ उन्हे मुख्यधारा में लाने के लिए शिक्षा का समान अधिकार और पढ़ने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
5. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं –** 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई इस महत्वाकांछी योजना का उद्देश्य बालिकाओं के लिए सकारात्मक माहौल के साथ-साथ उन्हे शिक्षा के द्वारा सामाजिक व वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है।
6. महिला ई-डॉट-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में 7 मार्च 2016 में आरंभ की गई इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय कार्यक्रम मेक इन इण्डिया में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना है।
7. **मुद्रा योजना व स्टैण्डअप इण्डिया योजना –** वर्ष 2016 में वंचित एवं पिछड़ी महिलाओं को आर्थिक सम्बलता प्रदान कर 16000 नए उद्यम स्थापित किये गये। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 70: ऋणों का लाभ महिला उद्यामियो को प्राप्त हुआ।
8. **प्रधानमंत्री उज्जवला योजना –** इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करने वाली महिलाओं को एल.पी.जी. गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गये है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दैनिक भास्कर 27 दिसंबर 2016
2. डॉ. सिन्हा वी.सी., अर्थशास्त्र लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद।
3. प्रतियोगिता दर्पण, मार्च 2018
4. रिसर्च लिंक, फरवरी 2006

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय तिलक पी.जी. महाविद्यालय, कटनी (म.प्र.) भारत

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

A Comparative Study Of Capital Adequacy Ratio Of Indian Public And Private Sector Banks With Special Emphasis On Basel II Norms

Rishi Vaidya* Dr. Kamalijeet Bhatia Dr. N. K. Totala*****

Abstract - In India, there is dominance of Government ownership coupled with significant private shareholding in the public sector banks, which in turn continue to have a dominant share in the total banking system. Basel II mandates Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) of 8% and Tier 1 capital of 6%. Further, the Government of India has stated that public sector banks must have a capital cushion with a CRAR of at least 12%, higher than the threshold of 9% prescribed by the RBI. The present study attempts to compare the CRAR of all the 26 public sector banks and 20 private sector banks for the period from 2008-09 to 2012-13. The study found that the public sector banks have gone in for further issue of equity shares to enhance their capital adequacy ratio.
Key Words - Bassel II, Capital Adequacy Ratio, Public Sector Banks, Private Sector Banks.

Introduction - Originally named the Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices, the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) was created in 1974 as a forum for member countries to discuss global banking supervision. Its goal is to advance the quality and know-how of banking supervisors worldwide and to be a global standard setter for financial institutions. It aims to facilitate global economic stability through common banking standards. Many of these standards focus on capital adequacy requirements.

Basel II considers that the key element of capital on which the main emphasis should be placed is equity capital and disclosed reserves, as this key element of capital is the only element common to all countries' banking systems. As this item is wholly visible in the published accounts, is the basis on which most market judgments of capital adequacy are made, it has a crucial bearing on profit margins and a bank's ability to compete. (Swamy, 2013).

Capital adequacy is an indicator of the financial health of the banking system. It is measured by the Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR), defined as the ratio of a bank's capital to its total risk weighted Assets. Higher value of CRAR indicates the lower need of external funding and therefore higher profitability. CRAR reflects the optimum amount of capital that it would require to ensure the confidence of all stakeholders, investors, depositors, creditors and regulators.

Two types of capital are measured: tier 1 capital, which can absorb losses without a bank being required to cease trading, and tier 2 capital, which can absorb losses in the event of a winding-up and so provides a lesser degree of protection to depositors. Tier 1 capital is the capital that is permanently and easily available to cushion losses suffered by a bank without it being required to stop operating. A good example of a bank's tier one capital is its ordinary share capital. Tier 2 capital is the one that cushions losses in case the bank is winding up, so it provides a lesser degree of protection to depositors and creditors. It is used to absorb losses if a bank loses all its tier one capital.

Literature Review -

Nachane et al. (2000) examined the impact of capital adequacy requirements on public sector banks in India on a sample of 27 banks for the period 1997 to 1999. The study concluded that Capital remains a useful tool in the hands of policy makers for influencing bank behaviour over and above the influence of the banks' own internally generated capital targets and there is no conclusive evidence to support a shift from high risk towards to low risk asset category by banks. It also found that banks increase Tier I and Tier II capital to increase the capital ratio.

Nag & Das (2002) studied the impact of imposition of capital requirement norms on flow of credit to the business sector by the Indian public sector banks for the period 1996-2000. The study concluded that in the post reform period public sector banks did shift their portfolio in a way that reduced their capital requirements and adoption of stricter risk management practice in respect of bank lending in post reform period and its interplay with minimum capital requirements (regulatory pressure) have had a dampening effect on overall credit supply.

Kaur & Kapoor (2014) attempted to analyse the

*Research Scholar, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore (M.P.) INDIA
**Principal, SDPS Women's College of Commerce & Management, Indore (M.P.) INDIA
***Reader, Institute of Management Studies, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore (M.P.) INDIA

changes in Capital Adequacy Ratio of public and private sector banks from 2001 to 2013 in the light of Basel Capital adequacy requirements. The data was analysed using Compound Annual Growth Rate (CAGR) and was found that most of the public and private sector banks have shown sign of growth of Capital Adequacy ratio and all of them have crossed the minimum CAR requirement of 9% stipulated by RBI under Basel II.

Objectives of the Study -

- To examine the various aspects of regulatory capital.
- To analyze the trend in CAR values of the Indian public and private sector banks as per Basel II norms.

Research Methodology - For the purpose of the research study, secondary data has been collected from the various research books, journals, newspapers, periodicals, articles, internet, annual reports of banks, bulletins, RBI circulars. For the collection of secondary data, 26 public sector banks and 20 private sector banks were selected to study the CAR values of the Indian public and private sector banks.

Data Analysis and Interpretation

Table 1 - Capital to Risk Weighted Assets Ratio of Public Sector Banks (2008-09 to 2012-13) (See in the last page)

Figure 1 - Capital to Risk Weighted Assets Ratio of Public Sector Banks (2008-09 to 2012-13) (See in the last page)

Table 1 and Figure 1 depicts the CRAR of public sector banks for sample period. The result reveals that maximum banks are working on more than the minimum prescribed limit of capital adequacy ratio of 9% by RBI. The average value of CRAR for five years reveals that Bank of Baroda has maintained the highest average CRAR of 14.18% while Dena Bank has maintained the least CRAR of 12.16%. Canara Bank, Corporation Bank, Indian Overseas Bank and Indian Bank are ranked 2nd, 3rd, 4th and 5th rank respectively in terms of average CRAR.

Table 2 - Capital to Risk Weighted Assets Ratio of Private Sector Banks (2008-09 to 2012-13) (See in the last page)

Figure 2 - Capital to Risk Weighted Assets Ratio of Private Sector Banks (2008-09 to 2012-13) (See in the last page)

Table 2 and Figure 2 exhibits the data for CRAR of private sector banks for five years, i.e., from 2008-09 to 2012-13. Bank with the maximum average CRAR are ranked first and then subsequent ranks are provided. Ratnakar Bank has average CRAR of 34.62% in the five years and is ranked first while Catholic Syrian Bank has average CRAR of 11.54% in the five years and is ranked least.

Kotak Mahindra Bank, ICICI Bank, Yes Bank and Federal Bank are ranked 2nd, 3rd, 4th and 5th rank respectively in terms of average CRAR. From the above data it can be concluded that the private sector banks have maintained highest CRAR as compared to the government owned banks.

Conclusion - The study found that the public sector banks have gone in for further issue of equity shares to enhance their capital adequacy ratio. Several banks running on the brink of very low or sometimes even negative profitability have been permitted by the government to write-off their losses against their paid-up capital. This has further worsened their capital adequacy position. Inspite of all this and some bailout packages by the government, all the banks today have reached the stipulated ratio of 9% CRAR or even more. The main reason for this is also the internally generated funds by way of increased profits and augmentation of their reserves and surplus. In any cases due to further issue of equity shares capital, the shareholding of the government in the public sector banks also stands reduced.

References :-

1. Kaur, M., & Kapoor, S. (2014). Capital adequacy growth in banks: An Indian scenario. *Amity Business Review*, 15(1), 31-38.
2. Nachane, D. M., Narain, A., Ghosh, S., & Sahoo, S. (2000). *Capital adequacy requirements and the behaviour of commercial banks in India: An analytical and empirical study*. Development Research Group Study No. 22, Department of Economic Analysis and Policy, Reserve Bank of India: Mumbai.
3. Nag, A. K., & Das, A. (2002). Credit growth and response to capital requirements: Evidence from Indian public sector banks. *Economic and Political Weekly*, 37(32), 3361-3368.
4. Swamy, V. (2013). *Basel III: Implications for Indian banking*. Research Report, Indian Institute of Banking and Finance: Mumbai. Retrieved from www.iibf.org.in/documents/reseach-report/Report-25.pdf, accessed on 15th December 2015.

Table 1 - Capital to Risk Weighted Assets Ratio of Public Sector Banks (2008-09 to 2012-13)

Data Analysis and Interpretation

S. No.	Banks	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR)					Average	Rank
		2009	2010	2011	2012	2013		
1	Allahabad Bank	13.11	13.62	12.96	12.83	11.03	12.71	18
2	Andhra Bank	13.22	13.93	14.38	13.18	11.76	13.29	8
3	Bank of Baroda	14.05	14.36	14.52	14.67	13.30	14.18	1
4	Bank of India	13.01	12.94	12.17	11.95	11.02	12.22	24
5	Bank of Maharashtra	12.05	12.78	13.35	12.43	12.59	12.64	21
6	Canara Bank	14.10	13.43	15.38	13.76	12.40	13.81	2
7	Central Bank of India	13.12	12.23	11.64	12.40	11.49	12.18	25
8	Corporation Bank	13.61	15.37	14.11	13.00	12.33	13.68	3
9	Dena Bank	12.07	12.77	13.41	11.51	11.03	12.16	26
10	IDBI Bank Ltd.	11.57	11.31	13.64	14.58	13.13	12.85	15
11	Indian Bank	13.98	12.71	13.56	13.47	13.08	13.36	5
12	Indian Overseas Bank	13.20	14.78	14.55	13.32	11.85	13.54	4
13	Oriental Bank of Commerce	12.98	12.54	14.23	12.69	12.04	12.90	14
14	Punjab & Sind Bank	14.35	13.10	12.94	13.26	12.91	13.31	7
15	Punjab National Bank	14.03	14.16	12.42	12.63	12.72	13.19	10
16	State Bank of Bikaner & Jaipur	14.52	13.30	11.68	13.76	12.16	13.08	12
17	State Bank of Hyderabad	11.53	14.90	14.25	13.56	12.36	13.32	6
18	State Bank of India	14.25	13.39	11.98	13.86	12.92	13.28	9
19	State Bank of Mysore	13.38	12.42	13.76	12.55	11.79	12.78	17
20	State Bank of Patiala	12.60	13.26	13.41	12.30	11.12	12.54	22
21	State Bank of Travancore	14.03	13.74	12.54	13.55	11.70	13.11	11
22	Syndicate Bank	12.68	12.70	13.04	12.24	12.59	12.65	20
23	UCO Bank	11.93	13.21	13.71	12.35	14.15	13.07	13
24	Union Bank of India	13.27	12.51	12.95	11.85	11.45	12.41	23
25	United Bank of India	13.28	12.80	13.05	12.69	11.66	12.70	19
26	Vijaya Bank	13.15	12.50	13.88	13.06	11.32	12.78	16
Average Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR)		**13.20**	**13.26**	**13.37**	**12.98**	**12.15**		

Figure 1 - Capital to Risk Weighted Assets Ratio of Public Sector Banks (2008-09 to 2012-13)

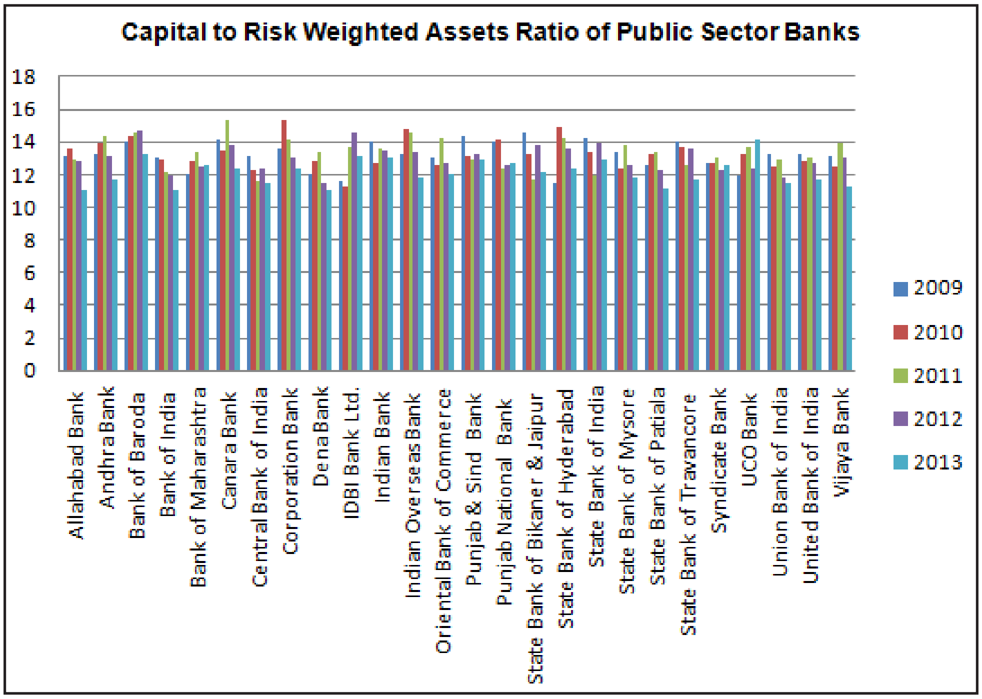

Table 2 - Capital to Risk Weighted Assets Ratio of Private Sector Banks (2008-09 to 2012-13)

S.No.	Banks	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR)					Average	Rank
		2009	2010	2011	2012	2013		
1	Axis Bank Ltd.	13.69	15.80	12.65	13.66	17.00	14.56	10
2	City Union Bank Ltd.	12.69	13.46	12.75	12.57	13.98	13.09	16
3	Development Credit Bank Ltd.	13.30	14.85	13.25	15.41	13.61	14.08	13
4	Dhanlaxmi Bank Ltd.	15.38	12.99	11.80	9.49	11.06	12.14	19
5	HDFC Bank Ltd.	15.69	17.44	16.22	16.52	16.80	16.53	6
6	ICICI Bank Ltd.	15.53	19.41	19.54	18.52	18.74	18.35	3
7	IndusInd Bank Ltd.	12.55	15.33	15.89	13.85	15.36	14.60	9
8	ING Vysya Bank Ltd.	11.65	14.91	12.94	14.00	13.24	13.35	15
9	Kotak Mahindra Bank Ltd.	20.01	18.35	19.92	17.52	16.05	18.37	2
10	Tamilnad Mercantile Bank Ltd.	16.05	15.54	15.13	14.69	15.01	15.28	7
11	The Catholic Syrian Bank Ltd.	12.29	10.82	11.22	11.08	12.29	11.54	20
12	The Federal Bank Ltd.	20.22	18.36	16.79	16.64	14.73	17.35	5
13	The Jammu & Kashmir Bank Ltd.	14.48	15.89	13.72	13.36	12.83	14.06	14
14	The Karnataka Bank Ltd.	13.48	12.37	13.33	12.84	13.22	13.05	17
15	The Karur Vysya Bank Ltd.	14.92	14.49	14.41	14.33	14.41	14.51	11
16	The Lakshmi Vilas Bank Ltd.	10.29	14.82	13.19	13.10	12.32	12.74	18
17	The Nainital Bank Ltd.	13.10	15.68	16.35	15.09	14.43	14.93	8
18	The Ratnakar Bank Ltd.	42.30	34.07	56.41	23.20	17.11	34.62	1
19	The South Indian Bank Ltd.	14.76	15.39	14.01	14.00	13.91	14.41	12
20	Yes Bank Ltd.	16.60	20.60	16.50	17.90	18.30	17.98	4
Average Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR)		**15.95**	**16.53**	**16.80**	**14.89**	**14.72**		

Figure 2 - Capital to Risk Weighted Assets Ratio of Private Sector Banks (2008-09 to 2012-13)

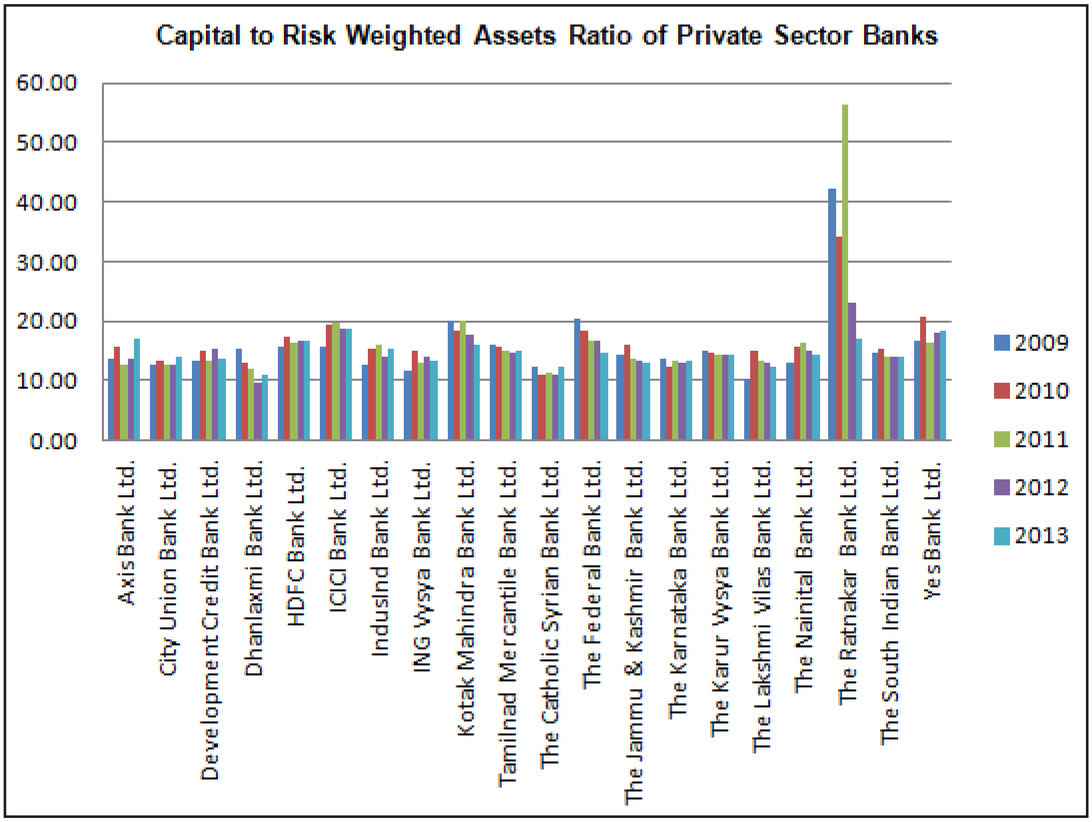

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

छ.ग. के बिलासपुर संभाग में फसल चक्र का प्रभाव

नोर्बेलता एक्का *

शोध सारांश– बिलासपुर संभाग की उपजाऊ भूमि के उपरान्त भी कृषकों की कमजोर आर्थिक स्थिति, जल के लिए मानसून पर निर्भरता तथा पुराने परम्परागत साधनों एवं रासायनिक उर्वरकों से फसल पर निर्भरता बनी हुई है। फसल चक्र का प्रयोग कर भूमि की उर्वरा–शक्ति में निरन्तरा बनाये रखकर उत्पादन में वृद्धि के साथ ही साथ लागत में भी कमी परिलच्छित हुई है। संभाग में फसल चक्र की वर्तमान स्थिति ज्ञात कर इसके उपयोग से उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने हेतु सुझाव देना इस शोध का उद्देश्य है।

शब्द कुंजी – फसल चक्र, उर्वराशक्ति, उत्पादकता, लागत, संवर्धन।

प्रस्तावना – विभिन्न फसलों को किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित क्रम से, किसी निश्चित समय में बोने को शस्यचक्र या फसल चक्र कहते हैं। इसका उद्देश्य पौधों के भोज्य तत्वों का सदुपयोग तथा भूमि की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशाओं में संतुलन स्थापित करना है।

सभ्यता के प्रारंभ से ही किसी खेत में एक निश्चित फसल न उगाकर फसलों को अदल–बदल कर उगाने की परंपरा चली आ रही है। फसल उत्पादन की इसी परम्परा को फसल चक्र कहते है। अर्थात् किसी निश्चित क्षेत्र पर निश्चित अवधि के लिए भूमि की उर्वरकता को बनाये रखने के उद्देश्य से फसलों को अदल–बदल कर उगाने की क्रिया को फसल चक्र कहते हैं।

आदिकाल से ही मानव अपने भरण–पोषण हेतु अनेक प्रकार की फसले उगाता चला आ रहा है। फसलें मौसम के अनुसार भिन्न–भिन्न होती है। अधिक मूल्यावान फसलों के साथ चुने गये फसल चक्रों में मुख्य दलहनी फसलें, चना, मटर, मसूर, अरहर, उर्द, मूंग, लोबिया, राजमा आदि का समावेश जरूरी है।

अध्ययन का उद्देश्य – बिलासपुर संभाग में फसल चक्र से कृषि उत्पादकता, लागत एवं रोजगार पर प्रभावों का अध्ययन करना, आंकड़े संकलित करके वास्तविकता ज्ञात करना तथा फसल चक्र का उपयोग करने हेतु सुझाव देना मेरे इस शोध का उद्देश्य है।

परिकल्पना –प्रस्तुत अध्ययन हेतु निम्न शून्य परिकल्पनाओं की जांच की जाएगी –

1. कृषकों के द्वारा फसल चक्र में सुधार किया गया है।
2. कृषि यन्त्रीकरण एवं रासायनिक उर्वरकों का फसल चक्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध मुख्यत: द्वितीयक समंकों पर आधारित है। द्वितीयक समंक संग्रहण हेतु पत्र–पत्रिकाओं, विभागों के प्रतिवेदन तथा वेब साइट से प्राप्त सूचानाओं का प्रयोग का प्रयोग कर विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग किया गया है।

अध्ययन की सीमाएँ – प्रस्तुत शोध अध्ययन सन् 2009–10 से 2014–15 के प्राप्त आंकड़ों एवं जानकारियों तक सीमित है।

फसल चक्र से आशय – सभ्यता के प्रारंभ से ही किसी खेत में एक निश्चित फसल न उगाकर फसलों को अदल–बदल कर उगाने की परंपरा चली आ रही है। फसल उत्पादन की इसी परम्परा को फसल चक्र कहते है। अर्थात् किसी निश्चित क्षेत्र पर निश्चित अवधि के लिए भूमि की उर्वरकता को बनाये रखने के उद्देश्य से फसलों को अदल–बदल कर उगाने की क्रिया को फसल चक्र कहते हैं।

फसल चक्र से लाभ –

अ. पोषक तत्वों का समान व्यय– फसलों की जडे गहराई तथा फैलाव में विभिन्न प्रकार की होती है, अत: गहरी तथा उथली जड वाली फसलों के क्रमश: बोने से पोषक तत्वों का व्यय विभिन्न गहराइयों पर समान होता है। जैसे गेहूँ ,कपास।

ब. पोषक तत्वों का संतुलन – विभिन्न पौधे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तथा अन्य पोषक तत्व भिन्न–भिन्न मात्राओं में लेते रहते है। इससें परस्पर संतुलन बना रहता है। एक ही फसल निरन्तर बोने से अधिक प्रयुक्त होने वाले पोषक तत्वों की भूमि में शून्यता हो जाती है।

स. हानिकारक कीटाणु रोग तथा घासपात की रोकथाम–एक फसल अथवा उसी जाति की अन्य फसलें लगातार बोने से उनके हानिकारक कीड़े, रोग तथा साथ उगने वाली घासपात उस खेत में बनी रहती है।

द. श्रम, आय तथा व्यय का संतुलन– एक बार किसी फसल के लिए अच्छी तैयारी करने पर, दूसरी फसल बिना विशेष तैयारी के ली जा सकती है और अधिक खाद चाहने वाली फसल को पर्याप्त मात्रा में खाद को देकर, शेष खाद पर अन्य फसलें लाभ के साथ ली जा सकती है, जैसे आलू के पश्चात् तम्बाकू, प्याज या कद्धू आदि।

क. भूमि में कार्बनिक पदार्थों की पूर्ति –निराई, गुड़ाई चाहने वाली फसलें, जैसे आलू प्याज आदि बोने से, भूमि में जैव पदार्थों की कमी हो जाती है। इनकी पूर्ति दलहन वर्ग की फसलों तथा हरी खाद के प्रयोग से ही जाती है।

ख. अल्पकालिन फसलें बोना – मुख्य फसलों के बीच अल्पकालीन फसलें बोई जा सकती हैं, जैसे मूली, पालक, मूँग आदि।

ग. भूमि में नाइट्रोजन की पूर्ति – दलहन वर्ग की फसलों को जैसे

*शोधार्थी, डॉ.सी.व्ही.रमन विश्वविद्यालय, करगीरोड़, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

सनई, ढेंचा, मूँग इत्यादि, भूमि में तीन या चार वर्ष में एक बार जोत देने से, न केवल कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं अपितु नाइट्रोजन भी मिलता है, क्योंकि इनकी जड़ की छोटी-छोटी गाँठों में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणु होते हैं।

घ. भूमि की अच्छी भौतिक दशा - गहरी जड़वाली तथा अधिक गुड़ाई चाहने वाली फसलों को शस्यचक्र में सम्मिश्रित करने से भूमि की भौतिक दशा अच्छी रहती है।

ड. घास पात की सफाई -निराई, गुड़ाई चाहने वाली फसलों के बोने से घास पात की सफाई स्वयं हो जाती है।

च. कटाव से बचत - उचित शस्यचक्र से वर्षा के जल से भूमि का कटाव रूक जाता है तथा खाद्य पदार्थ बहने से बच जाते हैं।

छ. समय का सदुपयोग - इससे कृषि कार्य उत्तम ढंग से होता है। खेत एवं किसान व्यर्थ खाली नहीं रहते।

ज. भूमि के विषैले पदार्थों से बचाव - फसले जड़ों से कुछ विषैला पदार्थ भूमि में छोड़ती हैं। एक ही फसल बोने से भूमि में विषैले पदार्थ अधिक मात्रा में एकत्रित होने के कारण हानि पहुँचाते हैं।

झ. उर्वरा शक्ति की रक्षा- भूमि की उर्वरा शक्ति मितव्ययिता से ठीक रखी जा सकती है।

फसल चक्र निर्धारण के मूल सिद्धान्त - फसल चक्र के निर्धारण में कुछ मूलभूत सिद्धान्तों को ध्यान में रखना जरूरी होता है जैसे-

1. अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों का उत्पादन।
2. अधिक पानी वाली फसलों के बाद कम पानी वाली फसल लगाना।
3. अधिक निराई, गुड़ाई वाली फसल के बाद कम निराई, गुड़ाई वाली फसल लगाना।
4. दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलों का उत्पादन।
5. अधिक मात्रा में पोषक तत्व शोषण करने वाली फसल के बाद खेत को परती रखना।
6. एक ही नाशी जीवों से प्रभावित होने वाली फसलों को लगातार नहीं उगाना।
7. उथली जड़ वाली फसल के बाद गहरी जड़ वाली फसल को उगाना।
8. फसलों का समावेश स्थानीय बाजार की माँग के अनुरूप रखना।
9. फसल का समावेश जलवायु तथा किसान की आर्थिक क्षमता के अनुरूप करना चाहिए।

कुछ उपयोगी फसल चक्र -

1. दलहनी फसलों पर आधारित फसल चक्र-धान-तिवरा, धान-चना, मटर-गेहूँ, ज्वार-चना, बजरा-चना, धान-मटर-गन्ना, मूँगफली-अरहर-गन्ना, मूँग गेहूँ, कपास-मटर-गेहूँ आदि।

2. अन्न की फसलों पर आधारित फसल चक्र-धान-गेहूँ, मक्का-गेहूँ, ज्वार-गेहूँ, बाजरा-गेहूँ, गन्ना-गेहूँ, धान-गन्ना, मक्का-जौ, धान-बरसीम, मक्का-गेहूँ, चना-गेहूँ, आदि।

3. सब्जी आधारित फसल चक्र -भिण्डी-मटर, पालक-टमाटर, फूलगोभी-मूली, बन्दगोभी-मूली, बैंगन-लौकी, टिण्डा-आलू-मूली, घुईयाँ-शलजम-भिण्डी-गाजार, आलू-टमाटर लहसून-मिर्च, आलू-लौकी आदि।

बिलासपुर संभाग में फसल चक्र का प्रयोग **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

सारणी क्रमांक 01 के अनुसार कृषक परिवारों को भूमि धारिता के आधार पर 03 भागों में बांट कर 303 परिवारों को अध्ययन किया गया। कृषि में यंत्रीकरण एवं रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के पूर्व 01 से 02 हेक्टेयर कृषि भूमि धारित करने वाले 28.7 प्रतिशत कृषक परिवार फसल चक्र का उपयोग कर रहे थे। वहीं 02 से 05 हेक्टेयर भू धारित करने वाले 53.5 प्रतिशत परिवार फसल चक्र का उपयोग कर रहे थे। 05 हेक्टेयर से अधिक भू धारित करने वाले 60.4 प्रतिशत परिवार फसल चक्र का उपयोग कर रहे थे। इससे स्पष्ट होता है कि छोटे कृषक परिवारों की तुलना में मध्यम एवं बडे कृषक परिवारों के द्धारा फसल चक्र का उपयोग अधिक किया जा रहा है। कृषि यंत्रीकरण एवं रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के बाद छोटे, मध्यम एवं बडे तीनों स्तर के कृषक परिवारों ने फसल चक्र का उपयोग अधिक मात्रा में करने लगे। छोटे कृषक परिवार जो पूर्व में 28.7 प्रतिशत फसल चक्र का उपयोग कर रहे थे वे यंत्रीकरण एवं रासायनिक उर्वरकों के बाद 38.6 प्रतिशत फसल चक्र का उपयोग करने लगे। इस तरह 9.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। उसी तरह मध्यम कृषक परिवारों में 12.9 प्रतिशत एवं बडे कृषक परिवारों में 13.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अगर सम्पूर्ण कृषक परिवारों पर विचार करे तो यंत्रीकरण एवं रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के पूर्व 47.9 प्रतिशत कृषक परिवार फसल चक्र का उपयोग कर रहे थे जो कि बाद में इनकी संख्या 11.9 प्रतिशत वृद्धि के साथ 59.7 प्रतिशत कृषक परिवार फसल चक्र का उपयोग करने लगे हैं। इस तरह कृषि यंत्रीकरण एवं रासायनिक उर्वरकों के उपयोग का फसल चक्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

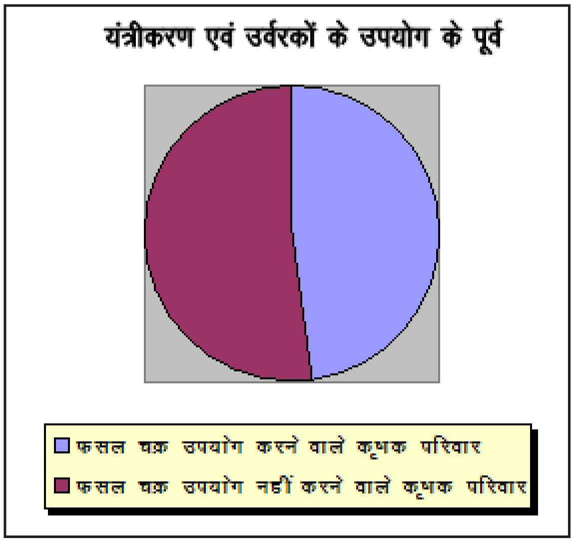

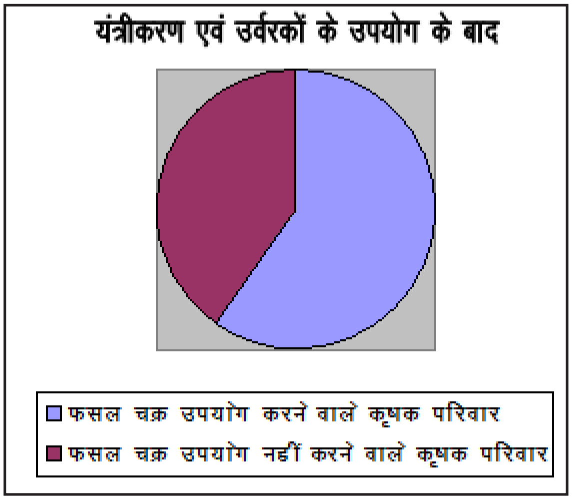

सारणी क्रमांक-02 **(देखे)**

सारणी क्रमांक 2 में फसल चक्र का उपयोग न करने वाले कृषक परिवारों को दिखाया गया है। कृषि यंत्रीकरण एवं रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के बाद नकरात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। पूर्व में 52.1 प्रतिशत कृषक परिवार फसल चक्र का उपयोग नहीं करते थे वे बाद में घटकर 40.3 प्रतिशत हो गया है। इस तरह 11.9 प्रतिशत की कमी आयी है। मध्यम वर्ग के कृषक परिवारों में इसका प्रभाव अधिक दिखा है। छोटे और बडे कृषक 9.9 प्रतिशत की कमी जबकि मध्यम कृषकों में यह कमी 12.9 प्रतिशत की देखी गई है। इससे स्पष्ट है कि मध्यम कृषक परिवारों में लोच अधिक है।

निष्कर्ष – कृषि यंत्रीकरण एवं रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के फलस्वरूप फसल चक्र के उपयोग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है फलस्वरूप कृषक परिवारों ने कृषि में फसल चक्र के उपयोग में लगातार सुधार किया है और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। अतः शून्य परिकल्पना परीक्षण उपरान्त सत्य सिद्ध हुई।

सुझाव– बिलासपुर संभाग में जोत का आकार छोटा है और कृषि कार्य में लगी जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है। भूमि एक दुर्लभ साधन है जबकि श्रम एक प्रचुर साधन है। अतः भूमि उत्पादकता को उन्नत करने की नीतियों का ग्राम-जनशक्ति के प्रयोग के साथ सामन्जस्य करना होगा। कृषि यन्त्रीकरण की नीति ऐसी हो जो कि श्रम विस्थापन के प्रभाव को कम कर सके। इस दिशा में फसल चक्र का अधिकाधिक उपयोग कर भूमि की उर्वरा शक्ति को प्राकृतिक रूप से बनाये रखना या उसमें वृद्धि करना उचित होगा। फसल चक्र के उपयोग से एक साथ तीन लाभ प्राप्त होगा। फसल उत्पादन में वृद्धि, लागत में कमी और भूमि की उर्वरा शक्ति में प्रचूरता।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मिश्र, डॉ0 जय प्रकाश, कृषि अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स: आगरा।
2. आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर
3. वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन, छ0ग0 शासन, कृषि विभाग, रायपुर
4. छत्तीसगढ़ कृषक सहयोगी पुस्तिका, कृषि वातावरणीय विभाग-7 एवं 8, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षक एवं परीक्षण संस्थान, ट्रैक्टर नगर, बुदनी (म0प्र0)
5. http://cg.nic.in/revenue/Table Of Agriculture Statistics 2013-14

सारणी क्रमांक - 01

बिलासपुर संभाग में फसल चक्र का प्रयोग

बिलासपुर संभाग में फसल चक्र उपयोग करने वाले कृषक परिवार

कृषकों की श्रेणी	सर्वेक्षित कृषक	कृषि में यंत्रीकरण एवं रासायनिक उर्वरक उपयोग के पूर्व		कृषि में यंत्रीकरण एवं रासायनिक उर्वरक उपयोग के बाद		कमी /वृद्धि
	परिवारों की संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
01 से 02 हेक्टेयर	101	29	28.7	39	38.6	9.9
02 से 05 हेक्टेयर	101	54	53.5	67	66.3	12.9
05 हेक्टेयर से अधिक	101	61	60.4	75	74.3	13.9
योग	303	145	47.9	181	59.7	11.9

स्रोत- सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक आंकडे।

क्रमांक-02

बिलासपुर संभाग में फसल चक्र उपयोग नहीं करने वाले कृषक परिवार

कृषकों की श्रेणी	सर्वेक्षित कृषक	कृषि में यंत्रीकरण एवं रासायनिक उर्वरक उपयोग के पूर्व		कृषि में यंत्रीकरण एवं रासायनिक उर्वरक उपयोग के बाद		कमी /वृद्धि
	परिवारों की संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
01 से 02 हेक्टेयर	101	72	71.3	60	61.4	-9.9
02 से 05 हेक्टेयर	101	46	46.5	32	33.7	-12.9
05 हेक्टेयर से अधिक	101	40	39.6	30	29.7	-9.9
योग	303	158	52.1	122	40.3	-11.9

स्रोत- सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक आंकडे।

****

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के विभिन्न पहलु - एक सिंहावलोकन

डॉ. ललिता सोलंकी * प्रो. तपन चौरे **

शोध सारांश – महिलाएँ मानव संसाधनों की आधी फीसदी जनसंख्या है अत: मानव पूँजी निर्माण की दृष्टि से महिलाओं का विकास महत्वपूर्ण है। कुल आबादी के आधे हिस्से को समानता की श्रेणी में लाकर उसके द्वारा समाज विकास में अदा की जा रही भूमिका, योग्यता एवं क्षमता को पहचाना साथ ही महिलाओं द्वारा किये जा रहे कार्यो को सही मान्यता प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। इसी कारण महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही हैं। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भता व आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक उत्थान से हैं। वैसे तो सशक्तिकरण को कई स्तरों पर देखा जा सकता है किन्तु प्रमुख लक्ष्य आर्थिक सशक्तिकरण के स्वरूप को समझना है।

प्रस्तावना – देश के समग्र विकास के लिए महिला व पुरुष दोनों का समान गति से निर्बोध रूप से उन्नति के पथ पर अग्रसर होना आवश्यक है। महिलाएँ समाज की अभिन्न अंग है अत: सामाजिक व आर्थिक विकास की संकल्पना महिलाओं के विकास व सशक्तिकरण के बिना अधूरी है। देश के **प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू** ने भी महिलाओं के विकास को प्राथमिकता देते हुए कहा था कि, 'यदि विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वत: ही हो जाएगा तथा समाज से राज्य और राज्य से राष्ट्र का विकास होगा।'

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ है महिला संबंधी समस्याओं की पूरी जानकारी के लिए उनकी योग्यता व कौशल में वृद्धि कर सामाजिक एवं संस्थागत अवरोधों को दूर करने का अवसर प्रदान करना, साथ ही आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ावा देना, ताकि वे अपने जीवन की गुणवत्ता में व्यापक सुधाार ला सकें। महिलाओं के सशक्तिकरण से संबधित नीतियों का क्रियान्वयन इस प्रकार से करना कि वंचित महिलाओं को आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त हो तथा इसमें आने वाली दैनिक समस्याओं को दूर किया जा सके। आर्थिक सशक्तिकरण प्रगति व सुधार का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। महिलाओं को समसामयिक सामाजिक कुप्रथाओं से मुक्त करने के लिए आवष्यक है महिलाओं में विवेकजन्यता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, धर्म निरपेक्षता एवं आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न की जाए तभी वे सामन्ती एवं रूढ़िवादी शोषण का सशक्त विरोध कर सकेंगी।

मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना – योजना 1 अगस्त, 2014 को युवाओं को स्वयं के उद्योग, व्यवसाय शुरू करने और सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विकसित करने के लिए बिना बैंक गारंटी के ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक वित्तीय सहायता योजना है। शासन द्वारा मार्जिन मनी सहायता, ब्याज सब्सिडी, ऋण गारंटी और लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। योजना का मुख्य उद्देश्य collateral security की आवश्यकता के बिना उद्यमिता (entrepreneurship) को बढ़ावा देना है। आवेदक प्रदेश का मूल निवासी, न्यूनतम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो तथा आय सीमा में कोई बंधन नहीं है। एवं उसका परिवार किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

परियोजना लागत न्यूनतम 20 हजार एवं अधिकतम 10 लाख तक हैं। मार्जिन मनी सहायता सामान्य वर्ग के लिए 15 प्रतिशत अधिकतम 01 लाख होगी। बी.पी.एल., अजा, अजजा, पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक, नि:शक्तजन के लिये 30 प्रतिशत अधिकतम रुपये 02 लाख की मार्जिन मनी सहायता का प्रावधान है। ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत की दर (अधिकतम 25 हजार रुपये) योजना में गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगी। विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति के उद्यमियों को परियोजना लागत में 2 लाख रूपये की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 3 लाख तक किया गया है। योजनान्तर्गत कुल परियोजना लागत 9,99,999 है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना – अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित युवा/युवतियों के लिए युवा उद्यमी योजना प्रारम्भ की गई। योजना का उद्देश्य समाज के अजा वर्ग के लिए स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजनान्तर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी, ब्याज अनुदान, ऋण गारण्टी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाता है। योजना का क्रियान्वयन आयुक्त अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अन्तर्गत म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल द्वारा एवं जिला अन्त्य व्यवसाय सहकारी विकास समिति मर्यादित के माध्यम से किया जाता है। प्रदेश के 18 से 40 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए 10 लाख से लेकर 01 करोड़ तक के ऋण बैंकों के माध्यम से मिलता है। हितग्राहियों को 15 प्रतिशत पूँजी लागत सहायता, अधिकतम 12 लाख रूपये की मार्जिन मनी सहायता तथा 5 प्रतिशत सालाना की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान दिया जाता है।

महिला उद्यमियों को पूँजी लागत का 01 प्रतिशत अधिक अर्थात् ब्याज अनुदान मिलता है। नवीन उद्योग के लिए न्यूनतम दसवीं परीक्षा पास होना जरूरी है। योजना के प्रथम दो वर्षो में मध्यप्रदेश में 2,500 युवाओं को

* ICSSR, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो (अर्थशास्त्र) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** (अर्थशास्त्र) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

लाभान्वित कर औसतन रुपये 35 लाख का ऋण प्रदान किया गया है। योजना में केन्द्र सरकार द्वारा कोई अनुदान, सब्सिडी नहीं दी जाती है। योजनान्तर्गत कुल परियोजना लागत 2 करोड़ रूपए तक है।

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना – योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों हो तथा मध्यप्रदेश का मूल निवासी व बी.पी.एल. होना आवश्यक है। इसमें शैक्षणिक योग्यता का बंधन नहीं हैं हितग्राही की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो एवं उसका परिवार किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी, स्व–रोजगार योजना में सहायता ले चुका है, तो वह योजना का पात्र नहीं होगा। योजना में सबसे गरीब वर्ग को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूँजी उपलब्ध करवायी जाती है। परियोजना की लागत अधिकतम 20 हजार रूपये एवं लागत का 50 प्रतिशत मार्जिन मनी एवं अधिकतम सहायता 10 हजार रूपये तक शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

पिछले वर्ष इन तीनों योजनाओं में एक लाख से ज्यादा हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। भारत सरकार की स्व–रोजगार योजनाओं को मिलाकर प्रदेश के 5 लाख 40 हजार हितग्राहियों को ऋण सहायता उपलब्ध करवाई गई है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से युवाओं को मिलने वाला रोजगार इन तीन महत्वपूर्ण योजना में वर्ष 2015–16 में 72 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2016–17 में 01 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य के साथ ही भारत सरकार की संचालित मुद्रा योजना को मिलाकर 5 लाख युवा स्वरोजगार स्थापित किया गया।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम – शिक्षित बेरोजगार को स्वरोजगार प्रेरित करने के लिए भारत सरकार ने 02 अक्टूबर, 1993 को प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की थी। कुछ ही समय पश्चात् बन्द कर दी गई थी। तथा योजना को पुन: शुरू किया गया। बेरोजगारो को स्वयं का उद्योग, सेवा, व्यवसाय स्थापित करवाकर स्वरोजगार उपलब्ध करवाना है तथा आर्थिक रूप से योग्य गतिविधियों, जिसमें कृषि और सहायक गतिविधियाँ भी शामिल हैं, उनके लिए ऋण स्वीकृत किया जाता है। निषिद्ध कार्यो को छोड़कर अन्य स्वरोजगार योजनाओं को चयन आवेदक को करना होता है। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष हो तथा अजा/अजजा, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग और महिलाओं के लिए उम्र में 10 वर्ष की छूट अर्थात् 45 वर्ष की आयु तक लाभ दिया जाता है।

योजना के तहत् रोजगार के लिए दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर तुलनात्मक रूप से काफी कम है और ऋण को आसान किश्तों में विभाजित कर 7 किश्तों में भुगतान किया जाता है तथा ऋण से निर्मित उत्पादकों को ही बंधक माना जाता है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रूपए तक का ऋण दिया जाता है। सामान्य वर्ग के आवेदक को 10 प्रतिशत मार्जिन मनी और शहरी क्षेत्र के निवासी को 15 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के निवासी को 25 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। तथा अजा/अजजा/अपिव/अल्प संख्यक, महिला, पूर्व सैनिक, शारीरिक विकलांग और पूर्वोत्तर, पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्रों सहित हितग्राहियों को 5 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा करनी होगी और शहरी क्षेत्र के निवासी होने पर 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के निवासी को 35 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कि जाती है। योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक 3737500 हितग्राहियों को रोजगार दिया गया तथा 4485.00 राशि (करोड़ में) सब्सिडी प्रदान की गई।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

आर्थिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित कराने हेतु केन्द्र सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के रूप में वर्ष 2012 में पुनर्गठित किया गया। आजीविका मिशन के तहत उन्हें दीर्घकालिक तथा गरीबी दूर करने के उनके प्रयासों में सहायता देना और गरीबों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का भी लक्ष्य है। युवाओं को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिलाकर नियोजन की उपलब्धता कराई जाती है।

स्व–सहायता समूह, समूहों, व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए पूंजीगत अनुदान की उच्चतम सीमा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को प्रति लाभार्थी परियोजना लागत का 30 प्रतिशत अथवा 15,000 रूपए तक, अजा/अजजा वर्ग के लाभार्थियों को 50 प्रतिशत 20,000 रूपए तक के अधीन रहते हुए और स्व–सहायता समूहों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 2.50 लाख रूपए निर्धारित है। आजिविका मिशन के लिए 12वीं योजना में 29 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया हैं।

दीनदयाल रोजगार योजना – प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को उद्योग, सेवा, व्यवसाय के क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों, वित्त संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋण में अपेक्षित मार्जिन मनी को जमा कराने में सहायता देने के लिए उद्योग विभाग द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, उम्र 18 से 40 वर्ष हो व परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम हो।

परियोजना लागत का उद्योग में 10 प्रतिशत अधिकतम 40.000 रूपए, सेवा क्षेत्र में 7.5 प्रतिशत अधिकतम 15,000 रूपए एवं व्यवसाय क्षेत्र में 5 प्रतिशत अधिकतम 7,500 रूपए मार्जिन मनी स्वीकृत की जाती है। आवेदक जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक या अधिक है उन्हें उद्योग या सेवा गतिविधि के लिए उपरोक्त निर्धारित प्रतिशत अनुसार अधिकतम सीमा क्रमश: 50,000 रूपए एवं 25,000 रूपए तक मार्जिन मनी सहायता की पात्रता होगी। मार्जिन मनी सहायता हितग्राही द्वारा लगाई जा रही योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। योजनान्तर्गत वर्ष 2014 तक 610 हितग्राहियों को 69,10,000 की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/जनजाति स्वरोजगार योजना – प्रदेश के अजा/अजजा वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्वयं के रोजगार स्थापित करने लिए उद्योग विभाग द्वारा उद्योग, सेवा, व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से सहायता उपलब्ध कराना जिसमें उद्यम के चयन से लेकर प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, विपणन, स्थापना आदि सभी चरणों में सहयता व सघन अनुसरण भी सम्मिलित हैं। योजनान्तर्गत ऐसे हितग्राही जिनके पास राजस्व अनुभाग स्तर के अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र हो तथा म.प्र. का मूल निवासी हो, उम्र 18 से 50 वर्ष के मध्य हो, शैक्षणिक योग्यता 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हो तथा परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपए से अधिक हो। योजना का लाभ दो या दो से अधिक शिक्षित बेरोजगारों को साझेदारी या कम्पनी के रूप में दिया जा सकता है। कम्पनी या साझेदारी अनुसूचित जाति या जनजाति किसी एक वर्ग के होना चाहिए। वर्ष 2014 तक 1012 हितग्राहियों को 19 करोड़ 60 लाख से अधिक तथा जनजाति के 79.5 व्यक्तियों को 13 करोड़ 98 लाख से अधिक राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

महिलाओं को रोजगार प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा महिलाओं के विकास के लिए रोजगार योजनाओं के द्वारा महिला उद्यमियों

में सूक्ष्म आर्थिक सशक्तिकरण संभव है। एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करने में महिला उद्यमी की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाएँ अनेक विषम परिस्थितियों तथा कठिन चुनौतियों का सामना करके अपने उद्यमों द्वारा न केवल अपने परिवार के आर्थिक स्वावलम्बन में सहयोगी बनी हैं वरन् प्रकाशंतर से विकास में भी योगदान दे रही हैं।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण का प्रमुख आधार आर्थिक सशक्तिकरण है। यदि महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्म निर्भर होगी तो उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो सकेगा, जो जीवन में गुणवत्ता सम्बन्धी तत्वों पर ध्यान देकर आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। ऐसे में योजना आर्थिक सशक्तिकरण का सफल माध्यम हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. म.प्र. माध्यम, 2011, म.प्र. में अनुसूचित जाति वर्गो के चहुँमुखी विकास की विशेष पहल। www.mpmadhyam.in
2. आगे आये लाभ उठाये मई 2016, जनसम्पर्क विभाग भोपाल म.प्र. पेज न. 65, 118, 219, 222। www.mpinfo.org.
3. मध्यप्रदेश में अनुसूचित जातियों के उत्थान की सार्थक कोशिशें, 12 अप्रैल, 2016, भोपाल।
4. युवाओं को रोजगार के लिये तेजी से काम करती म.प्र. सरकार, 19 अगस्त, 2017, भोपाल।
5. अगस्त, 2013 ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, कुरूक्षेत्र, अरावली पब्लिशर्स प्रा.लि., नई दिल्ली, पेज 16, 23।

****

गांवो के बदलते स्वरूप में भारत निर्माण योजना

डॉ. आर.एस. मण्डलोई *

शोध सारांश – भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु प्रारम्भ की गई भारत निर्माण योजना के माध्यम से वर्तमान में गांव के प्रत्येक क्षेत्र में विकास हुआ है। इस कार्यक्रम के जरिये ग्रामीण नवीनीकरण के कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पहल की गई। परिणाम स्परूप गांवो के विकास को नया आयाम मिला है गांवो में नयापन का एहसास होने लगा। आज प्रत्येक गांव पक्की सडक, बिजली की 24 घण्टे उपलब्धता, डिजिटल इण्डिया, टेलिफोन, टि.वी., मोबाईल, कच्चे मकानों से पक्के मकानों का निर्माण, डाकघर की सुविधाओं से जुड चुके है। हर गांव मे विकास की किरण दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में गांवो में भी शहरों जैसा माहोल है। भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों की स्थिति एवं स्वरूप में परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है।

शब्द कुंजी – उत्पादकीय व्यय, अनुत्पादकीय व्यय।

प्रस्तावना – भारत देश गांवों का देश है, गांवो के विकास के बिना हम भारत के विकास की कल्पना नही कर सकते है। 'महात्मा गांधी के इस सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार द्वारा ग्रामीणों को शहरी लोगो जैसी सुविधाऍं उपलब्ध कराने के लिए भारत निर्माण योजना का क्रियान्वयन किया।

वर्तमान परिदृश्य में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास न होने से शहरी क्षेत्र पर दबाव बडता है जिससे शहरी क्षैत्र में आधारभूत व्यवस्था एवं प्रबंधन अव्यवस्थित हो जाते है। ग्रामीण लोग शहरो की और पलायन कर जाते है। इन्ही समस्याओं के निराकरण हेतु इस योजना को लागू किया गया।

ग्रामीण को शहरी क्षेत्रों में विद्यमान जल, सडक भवन, विद्युतिकरण और दूरसंचार कनेक्टिविटी आदि सुविधाऍं आकर्षित करती है यदि यही सुविधाऍं गांवों में उपलब्ध हो जाये तों सारी समस्याओं का हल हो जायेगा, इसी कारण यह योजना अस्तित्व में आई। योजना के माध्यम से गांवो में उद्योगों की स्थापना होगी तथा गांव के लोगो के रहन-सहन में सुधार होगा तथा वे शहरो से सीधे से जुड सकेंगे।

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है विशाल निर्धन जनसंख्या को गरीबी रेखा से उपर उठाया जाए। इसके लिए गांवों में आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है।

भारत निर्माण योजना का आधार –

ग्रामीण आवास – भारत में सबसे बडी समस्या आवास की रही है। ग्रामीण क्षैत्रों में यह समस्या बहुत विकराल है। 2011 की जनगणना के अनुसार अभी भी ग्रामीण क्षैत्रों में लगभग 02 करोड मकानों की कमी है। गरीब ग्रामीण को यदि मकान दे दिया जाए तो उससे उनके जीवन में सामाजिक परिवर्तन आ जाता है। उसमें आत्मविश्वास बढता है। इन्ही उद्धेश्यों को लेकर केन्द्र सरकार ने सन 1996 में इंदिरा गांधी आवास योजना प्रारम्भ की थी। इस योजना के पश्चात मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना भी चलाई जा रही है। जिसमें ग्रामीण लोगो को पक्का आवास निर्माण हेतु सम्पूर्ण वित्तीय सहायता शासन द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

पेयजल – 'जल ही जीवन है' जल के बिना मानव जीवन की कल्पना व्यर्थ है। ग्रामीण भारत के विकास में पेयजल की आपूर्ति अति महत्वपूर्ण है। भारत निर्माण में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को एक घटक के रूप में शामिल किया गया। ग्रामीण क्षैत्रों में पेयजल की आपूर्ति हेतु 1972-73 केन्द्र सरकार द्वारा शतप्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन प्रारम्भ किया जिसका 1991 में नाम बदलकर राजीव गांधी पेयजल मिशन तथा 1999 में पेयजल आपूर्ति बनाया गया। पेयजल और स्वछता मंत्रालय अगस्त 2011 में अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल के लिए वित्त वर्ष 2011-12 9000 करोड रू., 2012-13 में 110000 करोड रू. 2014-15 में 16 हजार करोड रू. तथा 2015-16 में 19000 करोड रू. आवंटित किये गये।

दूरसंचार – वर्तमान में दूरसंचार में विशेषकर मोबाईल क्रान्ति आम आदमी के साथ-साथ ग्रामीण परिदृश्य में बहुत अधिक बदलाव ला दिया है। यह हमारा सामाजिक आर्थिक जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। अब तो स्थिति यह है कि दूरसंचार के बिना जीवन की कल्पना करना भी कठिन सा हो गया है। देश में 66822 गावों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलिफोन सुविधाऍं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रख गया है।

सडक – सडके किसी देश की जीवन रेखा होती है। सडक अच्छी होने पर ही ग्रामीण कृषि पदार्थो को शहरी क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है जब तक गांवो में सडको का विस्तार नही हो सकता है तब तक ग्रामीण भारत का विकास सम्भव नही है। इसलिए शासन ने प्रत्येक गांव में पक्की सडकों का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2012-13 में 43 हजार बस्तियों को 2014-15 में 48 हजार एवं 2015-16 में 51 हजार बस्तियों को पक्की सडकों से जोडा जा चुका है।

विद्युतीकरण – आज के युग में बिजली मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता का एक हिस्सा बन गयी है। हर क्षेत्र में जैसे- उद्योग, कृषि, सिंचाई, सूचना, संचार, रात्रि का प्रकाश, तकनीकी, घर, दुकान बाजार आदि सभी क्षेत्रों में बिजली का महत्व दिन प्रतिदिन बढ रहा है। ग्रामीण क्षैत्रों में बिजली प्रमुख आधार बन गई है। गांवों में विद्युतीकरण की नीति अप्रेल 2006 में लागू करते हुए 2009 तक सभी परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। तत्पश्चात देश में विद्युत व्यवस्था सुधार कर वर्तमान में 24 घण्टे ग्रामीणों में विद्युत उपलबधता की व्यवस्था की जा रही

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

है।

सिंचाई – भारत की लगभग 56 प्रतिशत जनसंख्या पुरी तरह कृषि पर निर्भर है। भारत में कृषि अभी भी पुरानी तकनीक से की जाती है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ है। कृषि का आधार सिंचाई है चुकि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार द्धारा निर्णय लिया गया है कि भारत निर्माण योजना में सिंचाई को प्राथमिकता से लिया गया है। सिंचाई कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य 2009 तक एक करोड हैक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई की क्षमता का निर्माण करना।

ग्रामीण भारत की तस्वीर बयां करती है कि भारत में विकास की गति प्रारम्भ हो चुकी है। ग्रामीण विकास में आर्थिक सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनैतिक, परिवहन, व्यापार, उद्योग, कृषि, सिंचाई, बैकिंग, नेट, मिडिया, मोबाईल आदि की भूमिका बढ रही है। आज ग्रामीण भारत 21 वी सदी में जी रहा है। भारता विषमता वाला देश है जो ग्रामीण भारत को प्रभावित करता है। विषमताओं को दूर कर ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है अनेको योजना द्धारा तथा देश की लगभग 68 प्रतिशत युवा जनसंख्या द्धारा ग्रामीण भारत को बदलने का प्रयास किया जा रहा है।

विभिन्न योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिलने से ग्रामीण जीवन में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आज हर ग्रामीण अपने जीवन स्तर में सुधार चाहता है। ग्रामीणों की क्रयशक्ति धीरे-धीरे बढने लगी है। लोग आज अनुत्पादकीय व्यय कम कर उत्पादकीय कार्यो में अपनी आय खर्च रहे है। ग्रामीण युवा देश के विकास की बात समझने लगे है। परिणामत: ग्रामीण क्षेत्रों के हालातों में निरन्तर परिवर्तन आ रहा है।

भारत निर्माण योजना के कारण गांवों में आधारभूत सुविधाओं को जाल बिछ रहा है। गांवों की तस्वीर में आमूलचूल पविर्तन दिखाई देने लग रहे है। गांव एवं शहरों की खाई दूर हो रही है। ग्रामीणजनों की आय में वृद्धि हो रही है क्रयशक्ति बढने से बाजार तंत्र का विस्तार होने लगा है शहरों की तुलना में गांवों में अतिरिक्त खर्च बडा है। साख निर्धारण ऐजेन्सी क्रिसिल के अध्ययन के अनुसार ग्रामीण भारत में खपत में वृद्धि का मूल कारण गैर कृषि रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने से आय में वृद्धि हो रही है। अत: स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में भारत निर्माण जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास बढा है। ग्रामीण लोग गैर-कृषि रोजगार की ओर पलायन कर रहे है। जिससे उनके जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन परिलक्षित हो रहे है।

आज ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूबवेल, सडके, ट्रेक्टर, पक्के मकानो से शहरो जैसी चमक- दमक गांव के लोगो के चेहरे बयां कर रहे है। एक हरित क्रान्ति ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया तो इसकी और श्वेत क्रान्ति दुग्ध उत्पादन में दूनिया में देश को नम्बर एक बना दिया।

शासन द्धासरा ग्रामीण विकास को बढावा देने की पहल करते हुए किसान क्रडिट कार्ड के माध्यम से किसानो को ऋण उपलब्ध कराकर साहूकारों के चुंगल से मुक्त किया जा रहा है। संचार क्रान्ति ने भी गांव की तस्वीर ही बदल दी है जो लोग शिक्षा से वंचित है उन्है भी मोबाईल क्रान्ति से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मण्डी बाजार एवं अन्य घटनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त हो रही है। आज गांव के स्कूल, सडक, मोबाईल, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएँ तथा रोजगार सुविधाएँ उपलब्ध है। जो ग्रामीणों एवं स्वयं सेवी संगठन तथा शासन के मिलेजुले प्रयासों का परिणाम है। आज भारतीय ग्रामीणों की तस्वीर एवं तकदीर दोनो ही बदलती नजर आ रही है।

वर्तमान समय में हमारे ग्रामीण भारत में मीडिया तंत्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण विकास में मीडिया एक कडी के रूप में कार्य कर रही है। आज ग्रामीण इलाकों में मासिक, दैनिक समाचार पत्र, मैगजीन, रेडियो, टी.वी., टेलीफोन, इन्टरनेट का प्रयोग बहुतायत हो रहा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ग्रामीण लोगो में शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो रहा है एवं लोग शिक्षा का महत्व समझ रहे है। जिससे उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने की क्षमता आ गई है।

अंत में कहा जा सकता है कि भारत निर्माण योजना से ग्रामीण भारत का विकास हो रहा है, गांवो में पलायन रूका है। आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से लोगो की आय बढी एवं क्रयशक्ति बढने से बाजार विकसित हुए है। आज लोगो का जीवन स्तर सुधरा है। ग्रामीण लोगो में साहस एवं आत्मविश्वास जागा है।

समस्याएँ एवं सुक्षाव –

समस्या –

1. ग्रामीण विकास की भारत निर्माण योजना के क्रियान्वयन में वास्तविक हितग्राहियों को लाभ नही मिल पा रहा है। जिस कारण योजना की मोटी रकम उचित व्यक्तियों का नही मिला है।
2. व्यापक भ्रष्टाचार पनपने लगा है।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएँ ही उपलब्ध नही हुआ है।
4. यातायात साधनों का सही विकास नही हुआ है।
5. आवास योजना का पूर्ण लाभ न देकर थोड़ी-थोड़ी राशि ही हितग्राहीयों को प्राप्त हुई है जिससे वे नही अपना नया आसियाना बना पा रहे है और न ही पुराने को सही कर पा रहे है।
6. जन जागृति की कमी होना।

सुक्षाव –

1. भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त होना चाहिए, लोगो में लोक कल्याण की भावना विकसित होना चाहिए।
2. ग्रामीण विकास हेतु पर्याप्त आवंटन उपलब्ध होना चाहिए।
3. ग्रामीण आवास योजना का लाभ उचित हितग्राही को तथा पूर्ण रूप से दिया जाना चाहिए।
4. ग्रामों में ग्राम सभा हर महिने आयोजित होना चाहिए।
5. शिक्षा एवं स्वास्थ्य का प्रचार-प्रसार होना चाहिए।
6. गैर कृषि रोजगार भारी मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सुन्दरम रूद्रदत्त, (2005)'भारतीय अर्थव्यवस्था' उपकार प्रकाशन, नई दिल्ली
2. मिश्र एवं पुरी, (2003)'भारतीय अर्थव्यवस्था' दिल्ली
3. माथुर बी.एल., (2009)'ग्रामीण अर्थव्यवस्था' अर्जुन पॉलिशिंग दिल्ली
4. रामकृष्ण रूचिका, 'सरल मार्केटिंग इन इण्डिया' सेन्च्युरी पाब्लिकेशन नई दिल्ली
5. गुप्ता शिवभुषण, (2003)'कृषि अर्थव्यवस्था' पी.सी. पब्लिकेशिंग हाउस आगरा।
6. योजना, प्रकाशन, विभाग दिल्ली।
7. कुरूक्षेत्र, प्रकाशन, विभाग दिल्ली।
8. www.oruraldevelopment.com
9. आर्थिक सर्वेक्षण 2016 भारत सरकार।

Naxalbari Movemnet In India

Dr. Indira Barman*

Abstract - The naxalbari movement was a agrarian revolt which began in 1967 and was led by the local tribal people and communist leaders of the Siliguri district of West Bengal. It is in the air that the movement got support from China and Nepal. The main leader who pushed the people forward was Charu Majumdar. Charu was inspired by Mao Zedong was a very popular leader of China. Mao was an extra ordinary leader with extra ordinary skills which helped him gain a lot of success. Charu used the same tactics and strategies in the naxalbari movement. The naxal ideologies are basically the ideologies which Mao Zedong used and the people of Indian liked the ideologies at once. When Rajnath Singh was the Union Home Minister he said that 68 districts were under the maoist influence but later in 2009 that number rose to 223. The peasant revolt was initiated by using the gorilla tactics against the enemies which helped them a lot later the movement was strategized and the people were divided into squads which did underground operations. Tribal people from Bihar had migrated to Darjeeling in search of work and they started working in the tea gardens of Darjeeling. They were treated so badly and exploited so much that agitation led to this revolt. In the second phase, groups were formed where they seized the lands of the rich zamindaars and cultivated on them. They kept the produce and did not give anything to the landlords. Initially the movement was for the upliftment of the poor peasants but later it tuned into an anti-national slant. The Chinese people only wanted to capture the land of India. The exchange of produce between the landlord and peasant could have been done mutually but greed led the people towards destruction.

Introduction - The motive of the Naxalbari movement was started off with the well being of the people but as soon as it proceeded forward the motive remained same but the way changed to ill ways. It was the fight for the right cause with wrong means. A police team was ambushed in the first naxal attack on 25th May 1967. A sub- inspector was killed in the attack led by Jangal Santhal near Naxalbari village in West Bengal. The movement began in the beautiful Darjeeling district which is in West Bengal. At present around 68 districts are influenced by Naxalism.

People of the old era understand that naxalism owes its origin in a West Bengal village called Naxalbari in Siliguri but the young people join it with terrorism and Maoism. As per the government of India naxalism and maosim is left as it uses extremism and is tackled by a separate part of the Ministry of Home Affairs. The Maoist carried out two main attacks in the year 2017 in March and April. In March, naxals killed 12 CRPF jawans at Sukma and then again attacked on the paramilitary forces on April 24 in the same district killing more than 24 jawans again. The biggest attack on security forces occurred in April 2010 in Dantewada of Chattisgarh when 72 CRPF jawans were killed.

In 1967, the small farmers reached the level of satiety and launched their own meovement. They formed their own group and thegroup was led by Eharu Mazumdar, Kanu Sanyal, and Jangal Santhal. Their aim was to snatch the lands from the greedy and big zamindars and redistribute it to the farmers.

Then Jangal Santhal again led a group and attacked a team of policemen who had come to investigate the previous matters and they too were attacked by bows and arrows. As the incident happened in Naxalbari this movement was named as the naxalbari movement.

One of the main reason behind this movement is the incomplete agrarian reform. The rich became richer day by day and poor became more poor. The aggression with burnt the people from inside led to this. The farmers were exploited till they committed suicide. The tribal people and the dalit people were denied social justice and were treated like animals.

Even though the government abolished the zamindari system after independence the distribution of land was not proper and again the poor people suffered. In many areas the poverty level reached as high as ninety five percent. This was socio-economic anger.

After the first attack the movement spread across the whole state of West Bengal. Many similar groups popped up in Madhya Pardesh and Andra Pradesh as well. Many previous groups reunited and formed the Communist Party of India.

The government which in power then did not take this

*Associate Professor, Institute For Excellence In Higher Education, Barkatullah University Bhopal (M.P.) INDIA

movement seriously and thus lost all control over the naxalites. Then in 2008, prime minister Manmohan Singh said that movements like these are the biggest threat to the internal security of the country. Since then the government started working actively to reduce the effect of the naxalism on India. More than 68 districts are influenced by Maosim and around six by maoist violence.

Viewpoints

- The involvement of political parties increased in this movement as soon as it gained a status.
- The movement functioned at both macro and micro level.
- The social structure played a very important role in this movement.
- This agrarian movement was also highly influenced by the green revolution which helped the people to opt for the contemporary techniques of farming.

Discussion and Findings - This was not only a movement which was initiated to fight for the rights of the people but this later turned into a political movement. The movement has completed more than fifty years now but still the problem is same. The armed forces is also not able to tackle this problem. The areas which are under naxal influence are the places where the government is least interested in doing any kind of progressive work. Thirty two percent are below poverty line, only sixty four percent people are getting safe drinking water, only forty three percent women get medical help during pregnancy, etc. These results are devastating. The movement has spread widely and has instilled deeply in the roots of the Indian system,

This problem cannot be solved till the government does not understand the nature of the movement and what these people actually want. If the military forces are not able to find any solution then the government has to step forward and settle down things with them. If this movement is posing as a threat to the internal security of then it is a serious challenge for the authorities of India.

The first step towards settlement has to be taken by the government otherwise this will go on like this for ever.

References:-

1. Rabindra Ray, The naxalits and their ideology
2. Asian centre for human research
3. India Today
4. BBC, 2010
5. Walking with the comrade, Arundhati Roy
6. Sudeep Chakravarty
7. Outlook.com

****

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान - नीति आयोग (विकास के परिप्रेक्ष्य में)

डॉ. कान्ता अलावा *

प्रस्तावना - नेहरू युगीन अत्यन्त प्रभावशाली 'योजना आयोग' का अंत हो गया और अब उसकी जगह 'नीति आयोग' ने ले ली हैं। नीति आयोग मोदी-युग में आर्थिक विकास के एजेन्डे के लिए नीति-थिंक टैंक की भूमिका निभाएगा। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च, 1950 में तत्कालिन केन्द्र सरकार द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू उसके प्रथम अध्यक्ष थे। आयोग का उद्देश्य था देश के संसाधनों का उचित दोहन करते हुए लोगों के जीवन स्तर में तेजी से सुधार, उत्पादन में वृद्धि और रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का निर्माण करना। तब योजना आयोग ने देश के प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन करते हुए एवं उनके उचित और संतुलित दोहन का दक्षतापूर्ण नियोजन करते हुए राष्ट्रीय वित्तीय संसाधनों के समूहीकरण की योजना बनाई थी, जिसके बाद क्षेत्र और प्रान्तवार आवंटन किए गए थे। लेकिन 1965 के बाद सरकारी थिंक टैंक की कमजोरी उजागर होने लगी, क्योंकि उसके पास बाढ़, सूखा, मुद्रा और वित्तीय स्त्रोतों के अवमूल्यन जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए कोई वैकल्पिक योजना नहीं थी। बाद में इसे एक-वर्षीय योजना तक सीमित कर दिया गया था। सच तो यह है कि 1992 के बाद से ही योजना आयोग ने अपनी प्रासंगिकता खो दी थी। जब मोदी-युग आरंभ हुआ तो 15 अगस्त, 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग के रूप में एक नई संस्था स्थापित करने की घोषणा कर दी गई।

परिचय - नीति आयोग (नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया-NITI Aayog) भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है, जो 1 जनवरी, 2015 को बनाया गया। नीति आयोग देश के सामाजिक-आर्थिक विकास का नीति नियन्ता बनेगा। नीति का अर्थ है इस बात को निर्णल लेना कि क्या किया जाए, कब किया जाय तथा कहाँ, कैसे किया जाय। नीति वस्तुत: कार्य की योजना है। बिना नीति के बनी हुई कोई योजना भी सफल नहीं होती है। नीति में लचीलापन होने से परिवर्तन भी किया जा सकता है। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएँ प्रदान करेगा एवं उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। केन्द्र व राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श व अन्तर्राष्ट्रीय आयात, देश के भीतर एवं अन्य देशों की बेहतर पद्धतियों का प्रसार, नए नीतिगत विचारों का समावेश होगा। नीति आयोग ग्राम स्तर पर भी विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा व इसे उच्च स्तर पर पहुँचाएगा। नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व के सकारात्मक प्रभावों को अपनाते हुए संस्थान को इस नीति का पालन करना होगा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में एक ही मॉडल प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता है। विकास के लिए हमें अपनी नीति स्वयं निर्धारित करनी होगी। देश में और देश के लिए क्या हितकारी है, संस्थान को इस पर ध्यान केन्द्रित करना होगा जो विकास के लिए भारतीय दृष्टिकोण पर आधारित होगा। इन आशाओं को जीवन्त बनाने के लिए है - नीति आयोग।

रक्षा, वित्त, गृह और विदेश मंत्रालय को नीति आयोग के दायरे में बाहर रखा गया है। इन चार महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा सीधे पीएमओ करेगा। नीति आयोग का काम योजनाओं की सक्रिय निगरानी और उनका आकलन, समस्याओं व संसाधनों की भी पड़ताल करना है, ताकि योजनाओं को प्रभावी बनाया जा सके।

संरचना - नीति आयोग आठ सदस्यीय एक थिंक टैंक हैं। आठ सदस्यीय थिंक टैंक में एक अध्यक्ष और सात सदस्य रहेंगे जैसे -

1. **अध्यक्ष -** भारत का प्रधानमंत्री
2. **शासी परिषद -** सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व केन्द्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल सदस्य होंगे।
3. क्षेत्रीय परिषद् (जरूरत के आधार पर गठित)-

- विशिष्ट मुद्दों, आकस्मिक मामले, जिनका संबंध एक से अधिक राज्य/क्षेत्र से हो को देखने के लिए गठित की जाएगी। जिसका विशिष्ट कार्यकाल होगा। प्रधानमंत्री के निर्देश पर बैठक होगी, जिसमें संबंधित क्षेत्र के मुख्यमंत्री व केन्द्र शासित क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल होंगे। इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष करेंगे।

4. संबंधित कार्यक्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ व कार्यरत् लोग, विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानंत्री द्वारा नामित होंगे।

पूर्णकालिक संगठनात्मक ढ़ांचे में निम्न होंगे -

- उपाध्यक्ष - पूर्णकालिक, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त।
- 5 सदस्य - पूर्णकालिक, सरकार द्वारा नियुक्त।
- 2 अंशकालिक सदस्य - अग्रणी विश्वविद्यालय शोध संस्थानों और संबंधित संस्थाओं से होंगे (रोटेशनल) पदेन ।
- पदेन सदस्य - 4 केन्द्रीय मंत्री इसके पदेन सदस्य होंगे, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त।
- सचिवालय- आवश्यकतानुसार ।

इस प्रकार प्रधानमंत्री इस आयोग के प्रमुख होंगे और सीधे इसके कार्यों पर नजर रखेंगे।

विशेषताएँ -

*प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

1. नीति आयोग के क्रियाकलापों में मुख्यमंत्रियों तथा निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ की अहम भूमिका होगी।
2. देशभर के विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों से व्यापक स्तर पर परामर्श लेना।
3. राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर केन्द्र व राज्य सरकार को जरूरी रणनीतिक व तकनीकी परामर्श देना।
4. मोदी के टीम इंडिया और सहकारी संघवाद के विचार को मूर्तरूप देना।

उद्देश्य – नीति आयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए कार्य करेगा –

- राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करेगा।
- राज्यों के साथ सतत् आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देगा।
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर पर पहुँचाएगा।
- आयोग को जो क्षेत्र विशेष रूप से सौंपे गये है, उनकी आर्थिक कार्य नीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया गया है।
- विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अन्तर-क्षेत्रीय और अन्तर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
- आवश्यक संसाधनों की पहचान करने सहित मूल्यांकन और सक्रिय निगरानी की जाएगी। ताकि सेवाएँ प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके।

अपेक्षाएँ –

1. हमारे उद्योग और सेवा क्षेत्रों का विकास हुआ है। अब उनका वैश्विक स्तर पर संचालन हो रहा है। इस नींव पर निर्माण करने के लिए नये भारत को एक प्रशासनिक बदलाव की जरूरत है, जिसमें सरकार सक्षम हो, सरकार को कानून बनाने, नीति निर्माण करने तथा विनियमन पर ध्यान केन्द्रित करना होगा।
2. कृषि व शुद्ध खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर कृषि उत्पादन के मिश्रण तथा किसानों को उनकी उपज से मिलने वाले वास्तविक लाभ पर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा।
3. हम एक वैश्विक गांव में रहते हैं, भारत को समान विचार वाले वैश्विक मुद्दों, विशेषकर जिन क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया है, इस पर बहस और विचार-विमर्श में सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए।
4. मध्यम वर्ग अपने आकार और क्रय शक्ति दोनों में ही अनुठा है। विकास का महत्वपूर्ण वाहक है। यह चुनौती है कि आर्थिक रूप से जीवंत इस मध्यम वर्ग की भागीदारी बनी रहे और इनकी क्षमता का पूर्ण दोहन किया जाना चाहिए।
5. उद्यमशीलता, वैज्ञानिक व बैद्धिक मानव पूँजी भारत की शक्ति का स्त्रोत है, अभी तक देश के विकास में बड़ा योगदान करता रहा है और इसलिए इसका उपयुक्त नीतिगत पहल के माध्यम से लाभ उठाये जाने की जरूरत है।
6. प्रवासी भारतीय समुदाय 200 से अधिक देशों में फैला है। भविष्य की राष्ट्रीय नीतियों में इस ताकत को निश्चित रूप से शामिल किया जाना चाहिए, जिससे वित्तीय समर्थन की आशा के अतिरिक्त नये भारत में उनकी भागीदारी को भी व्यापक बनाया जा सके।

परामर्श – नीति आयोग की सलाहकारी भूमिका –

- नीति आयोग की उप समूह की भोपाल बैठक में 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। जिसमें केन्द्र सरकार की योजनाओं में केन्द्र-राज्य की फंडिंग को लेकर दिए गए 50:50 के सुझाव पर मुख्यमंत्री सहमत नहीं थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर का कहना था कि राशि की हिस्सेदारी का यह अनुपात 80:20 का होना चाहिए। केन्द्र सरकार 80 फीसदी राशि दे। इससे राज्य पर 20 फीसदी भार आएगा। नागालैण्ड के मुख्यमंत्री झेलियांग ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष मानते हुए अलग से फण्ड दिया जाए। उल्लेखनिय है कि फंडिंग पैटर्न को आधा करने की केन्द्र सरकार की मंशा को लेकर ही यह उप समूह बनाया गया था, ताकि राज्यों के सुझाव लिए जा सकें।
- नीति आयोग ने वर्ष 2024 से लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने का सुझाव दिया है, ताकि चुनाव प्रचार के कारण शासन व्यवस्था में पड़ने वाले व्यवधान को कम किया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रहित में इसे लागू करने के लिए संविधान और इस मामले पर विशेषज्ञों, थिंक टैंक, सरकारी अधिकारियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित विशेष समूह गठित किया जाना चाहिए, जो इसे लागू करने से संबंधित सिफारिशे करेगा। यह सिफारिश इसलिए अहम है, क्योंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी चुनाव एक साथ करवाने के पक्षधर है।
- नीति आयोग ने डीजल ओर पेट्रोल वाहनों के पंजीयन पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक और साझा वाहनों की स्वीकार्यता बढ़ने से देश में 2030 तक डीजल और पेट्रोल की लागत 60 अरब डालर (3.9 लाख करोड़ रूपए) बचाए जा सकते है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे सालाना 15.6 करोड़ टन डीजल और पेट्रोल के बराबर ईंधन की बचत की जा सकेगी।

सुझाव –

1. आने वाले वर्षो में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था के मार्चो पर कार्य करने एवं हमें अपने युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कार्य करना होगा।
2. लैंगिक असमानता के साथ-साथ आर्थिक विषमता की ओर विशेष ध्यान देना होगा। ऐसा वातावरण और सहायता प्रणाली की स्थापना करने की जरूरत है, जिसमें महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में अपनी अधिकारपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहन मिले।
3. गाँव हमारे लोकाचार, संस्कृति और जीविका के सुदृढ़ आधार है। इन्हें विकास प्रक्रिया में पूर्ण रूप से संस्थागत बनाये जाने की जरूरत हैं।
4. हमारे पर्यावरण और संसाधनों का प्रत्येक तत्व जैसे जल, जमीन, जंगल की सुरक्षा की जानी चाहिए। हमारे विकास के एजेंडे में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि विकास, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता को दूषित न करें।

उपसंहार – नियोजित एवं नियंत्रित विकास के प्रतीक योजना आयोग की विदाई के फैसले का संदेश यही था कि देश अब नई आर्थिक दिशा में जाएगा। इस बड़े परिवर्तन की जड़े असल में प्रधानंत्री के विकास मॉडल में निहित है। पूँजीवाद के नए दौर में नीति आयोग जैसी संस्था बनाकर विकास का नया खाका खींचा जा रहा है। पीएमओ ने कहा है कि नीति आयोग का काम योजनाओं की सक्रिय निगरानी और उनका आंकलन करना है, साथ ही समस्याओं और संसाधनों की पड़ताल भी करना है।

गत वर्षों में विकास दर का स्तर सात प्रतिशत के ऊपर रहने के बावजूद

रोजगार के अवसरों में अपेक्षानुरूप वृद्धि नहीं हुई है। देश का असली रूपान्तरण तभी होगा जब हर युवा को रोजगार मिलेगा। कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को भी प्रभावी बनाने की रणनीति की जरूरत हैं सरकारी योजनाओं की निगरानी हेतु सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिससे 2022 तक 'न्यू इंडिया' का सपना वास्तव में साकार किया जा सकें। फिलहाल ज्यादा ध्यान इस पर दिए जाने की जरूरत है कि देश में गरीबी उन्मूलन कैसे हो? लैंगिक विभेद कैसे समाप्त हो और शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय का स्तर कैसे सुधरे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. एल.डी. गुप्ता-लोक प्रशासन के प्रमुख विचार एवं मुद्दे मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
2. नंटू बनर्जी - नाम तो बदला, नीति भी बदलेगी, नई दुनिया 8.01.215 पेज-6
3. मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया।
4. दैनिक भास्कर- 2015, 2016, 2017
5. नई दुनिया - 2015, 2016, 2017 समाचार संकलन।

****

महिला सशक्तिकरण चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

डॉ. हर्षा चचाने * डॉ. राजू रैदास **

प्रस्तावना – भारत वर्ष द्धारा सन् 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें महिलाओं के लिए कई कानून विकास नीतियॉ, योजनाओं एवं कार्यक्रमों से संबंधित अधिनियम बनाये गये जिससे महिलाओं के हितों की रक्षा हो सके एवं उनका उन्नयन हो। समााजिक संदर्भ में शक्ति का अभिप्राय नियंत्रण करने की क्षमता, निर्देशन की क्षमता, रक्षा करने की क्षमता एवं किसी को सहारा प्रदान करने की क्षमता से जाना जाता है। समाज में उसको शक्तिशाली माना जाता है, जो स्वयं को एवं साथ वाले को ऊपर उठा सके तथा बिना सहारे के समाज में स्वयं को स्थापित कर सके।[1] काडरवेल संगठन के प्रंबंध निदेशक रिचर्ड कार्वर ने सशक्तिकरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए बताया है कि सशक्तिकरण में व्यक्ति स्वयं अपने लिए कार्य करने के सर्वश्रेष्ठ तरीके की खोज करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि, व्यक्ति द्धारा स्वयं अपनी सहायता करना ही सशक्तिकरण है। सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जो व्यक्तियों में जागरूकता एवं साहस पैदा कर आत्मविश्वास के भाव पैदा करती है तथा उसमें अन्तनिर्हित क्षमताओं और कौशल के लिए प्रेरणा स्त्रोत का काम करती है। महिलाओं की प्रस्थितियों के बदलते स्वरूप– नारी पर जब भी कहीं चर्चा होती है तो व्यक्ति किसी भी स्तर का हो शिक्षित हो, अशिक्षित हो धार्मिक हो अधार्मिक हो नेता, कवि, लेखक, साहित्यकार समाज सुधारक, आलोचक नारी पर अपने दृष्टिकोण व्यक्त करते है। नारी की संवेदना के बिना जीवन ही नही जग भी अधूरा है। नारी का अस्तित्व वस्तुत: आधी आबादी तक सिमटा नहीं है बल्कि संपूर्ण आबादी उसी के गर्भ में से जन्म लेती है, उसी के हाथों उसका पालन–पोषण होता है इसलिए माता बालक की प्रथम गुरू है।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: भुनस्मृति में उल्लेखित वाक्य का अर्थ जहाँ स्त्रियों की पूजा एवं सम्मान होता वहाँ देवता निवास करते है। नारी सम्मान के इसी भाव के कारण संभवत: समृद्धि सम्पन्नता व शक्ति की उपासना स्त्री उपासना का प्रतीक है। वैदिक युग में घोषा, गार्गो, मैत्रेयी आदि विदुषी महिलांए हुई है जो पठन–पाठन में लगी रहती थी, उन्हे 'ब्रह्मवादिनी' कहा जाता था। नारी की स्थिति में देश–काल परिस्थिति के अनुसार सशक्त स्परूप को देखा जा सकता है। लेकिन मनुस्मृति में जिस सामाजिक संरचना का वर्णन हुआ है वहीं से नारी के शक्ति के क्षरण का वातावरण भी तैयार होने लगा। वैदिक युग में नारी को समान शिक्षा व शास्त्रार्थ का अवसर मिलता था वहीं मनुस्मृति मे नारी की पूजा एवं सम्मान की बात की जाती है। इसके साथ ही उसकी स्वतंत्रता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए 'मनु' ने यह व्यवस्था दी कि स्त्री को बाल्यावस्था में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के आधीन एवं वृद्धावस्था में पुत्र की अधीन रहना चाहिए। शायद दसी दशा में द्रवित होकर मैथिलीशरण गुप्त की पंक्तियाँ, अबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी, ऑचन में दूध और आँखों में पानी निकल पड़ी।

कौटिल्य ने भी नारी का अविश्वसनीय चंचल, बुद्धिवाली माना है। कौटिल्य ने तो पत्नी को पिता के परिवार से तथा अन्य सगे संबंधियो से भी वंचित कर दिया। पुत्र–विहीन विधवा को पिता की संपत्ति से भी कर दिया। मध्यकाल में नारी की स्थिती और गिर गई जब लोग आक्रमणकारियों के भय से नारी सुरक्षा में असमर्थ हुए तो, कन्या को जन्म के बाद मार देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। आठवीं से अठारहवीं शताब्दी के बीच मुगल साम्राज्य के पतन तक भारतीय नारी पर अधिक बंधन लगाये गये। विधवा को अशुभ व अमंगलकारी माना जाने लगा। सती प्रथा, जौहर प्रथा, पर्दाप्रथा विधवा की नियति बन गयी। बौ (काल में नारी की स्थिति मे कुछ सुधार हुआ। शिक्षा विवाह तथा धार्मिक अनुष्ठानों में उन्हें भागीदारी मिलने लगी। मुगल काल में उन्हें फिर स्वतंत्रता से वंचित रखा गया तथा पुरूषों की संपत्ति माना जाने लगा। इसके बावजूद रज़िया बेगम, तारामती, जीजाबाई, अहिल्याबाई जैसी सशक्त राजनीतिज्ञ तथा दूरदर्शी नारियों का आभाव नहीं रहा। धार्मिक क्षेत्र में भक्ति की प्रतीक मीराबाई नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। किन्तु तुलसीदास के सुन्दरकाण्ड में जड़ समुद्र के मुख से 'ढोर गॅवार शूद्र पशु नारी' सकल ताड़ना के अधिकारी पंक्तियॉ नारी स्वतंत्रता पर प्रश्नचिन्ह लगाकर विवादों को जन्म देती है।

अंग्रेजी शासन काल में एक नये युग की शुरूआत हुई। नारी स्वतंत्रता में प्रगति हुई और नारी सशक्तिकरण का नया अध्याय शुरू हुआ। रमाबाई राणाडे, आनन्दी बाई जोशी जैसी जागरूक महिलाओं ने 19वीं सदी में नारी समाज में नारी मुक्ति के लिए प्रयास किया। मुगल काल में नारी को शक्तिहीन बनानें में बहुविवाह प्रथा के विरू(ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानन्द सरस्वती, टैगोर आदि समाज सुधारक सामने आये। महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 1970 में महिला विद्यालय की स्थापना तथा 1911 में डॉ. डी.के. कर्वे ने महिला विद्यालय की नींव डाली। 1872 में सिविल मैरिज एक्ट बना तथा 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। महात्मा गांधी ने नारी स्वतंत्रता में बहुत योगदान दिया। श्रीमती नायडू, अमृत कौर, कमला देवी चटोपाध्याय, कस्तूरबा गांधी आदि के सशक्त नारियों के नाम है। राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की स्थिति स्वतंत्रता के बाद अस्तित्व में आयी। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपनी योग्यता से देश की प्रधानमंत्री बनी और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शताब्दी की महानतम महिला होने का गौरव प्राप्त किया। बछेन्द्री पाल प्रथम एवरेस्ट महिला विजेता बनी तो किरन बेदी देशी की पहली महिला आई.पी.एस. ऑफिसर बनी। भारत

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, उमरिया (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, उमरिया (म.प्र.) भारत

की प्रथम महिला राष्ट्रपति पद पर आसीन होने का गौरव श्रीमती प्रतिभा पाटिल को प्राप्त हुआ। महिलाओं हेतु बच्चों के समुचित विकास के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1985 में महिला और बाल-विकास विभाग की स्थापना की गई। इसी विभाग की सिफारिश पर 'राष्ट्रीय महिला आयोग' व 'राष्ट्रीय महिला कोष' की स्थापना हुई। वर्ष 2000-2001 को वार्षिक बजट में 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' घोषित किया गया जिसके तहत महिलाओं को राजनैतिक क्षेत्र में बराबरी की भागीदारी हेतु 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था अब इसे बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का यह प्रावधान सीधे चुनाव के जरिए भरी जाने वाली सीटों पर लागू होता है। पंचायतों में भी महिलाओं का आरक्षण 50 प्रतिशत हो गया है। महिलाओं के हितों में विधेयक लाना तथा सरकार द्वारा उनके विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ बनाने के प्रयास उचित है इसे एक सामाजिक आन्दोलन बनाया जाना चाहिए।

आज के इस तथाकथित सभ्य समाज में भी स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। देश का शायद ही ऐसा कोई जिला है, जहॉ प्रतिदिन बलात्कार, यौन शोषण या दहेज हत्या की घटनायें न घटती हों। आज के भौतिकवादी चकाचौंध में नारी ने स्वयं को फंसाकर बाजार वादी संस्कृति का एक प्रमुख एवं आकर्षक माध्यम बना लिया है। जिसमें उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करने के लिए मीडियाई चैनल के माध्यम से स्वयं को अपने अधनंगें बदन के साथ प्रस्तुत कर रही है। नारी दुनिया के सामने पूरा जोर लगाकर खुद को भोग्या और बुरि(से रहित खूबसूरत देह सि(करने में लगी हुई है। इस संदर्भ खालिद अंसारी का कथन है- बेचारी स्त्री। इक्कीसवीं सदी चल रही है, लेकिन उसकी नादानी जस की तस। पहले पुरूष प्रधान समाज की उपेक्षा का पात्र रही और अब आधुनिकता के नाम पर इसी पुरूष प्रधान समाज के द्वारा छली जा रही है। पुरूष ने बड़े दोस्ताना अन्दाज में सुझाया कि नाचो आधुनिक और प्रगतिशील समझी जाओंगी। अंधे को क्या चाहिए दो आसमान पर महसूस करने लगी। अब मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं, न सारे नियम कायदे की, न कपड़ो की अब मै आज़ाद और खुद मुख्तार हूँ। बेरहम से बेरहम मर्दो से भी हजारों गुना आगे बढ़ गई हूँ। जब बेहयाई पर उतरती हूँ तो मर्द मुझे देखते रह जाते है। वह झूम रही है मर्द उसे तन्मय होकर देख रहे है आपस में बातें कर रहे है, अरे यार कितना बढ़िया तरीका निकाला है।

दुनिया में छा जाने के लिए एक-दूसरे को धमियाते हुए शॉर्टकट का यह रास्ता चुनना अत्यंत आत्मघाती होगा। यदि पुरूषों ने स्त्रियों के साथ अत्याचार या इमोशनल ब्लैकमेलिंग की है तो नारी के प्रति स्वयं नारी ने भी कुछ कम नहीं किया। इस संबंध में मृदुला गर्ग कहती है- 'जब भी स्त्री पर चर्चा होती है तो कुछ लोग यह आक्षेप अवश्य लगाते है कि, स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी शत्रु होती है मॉ और सास का बेटी और बहू पर निष्ठुर अत्याचार संवेदन ही निष्ठुर व्यवहार इसके परिणाम स्वरूप पेश किये जाते है। लड़कियों के कमाने लायक होने पर खुद मॉ-बाप आर्थिक शोषण करते है। और उसमें मॉ की भूमिका बाप से कम नहीं होती। आज के भारतीय समाज का यह एक भयानक सत्य है। पुरूषों के साथ-साथ स्त्री स्वयं स्त्री के विकास एवं खुशहाल जीवन में सदियों से जहर घोलने का काम करती चली आ रही है। जब वह अपनी बेटी या बहू को प्रताड़ित करती है तो भूल जाती है कि, वह भी कभी बहू-बेटी रही है।

मीडिया के क्षेत्र में स्त्री की स्थिति भावुक उत्तोजक रूप में सामने आती है। नारी आज के उपभोक्तावादी युग में इस्तेमालवादी संस्कृति का एक अंग बन चुकी है। वस्तुओं के विज्ञापन के साथ-साथ नारी देह का भी बड़ा चित्ताकर्षक विज्ञापन हो रहा है। फिल्मों में नारी का कैसा रूप सामने आता है इस पर मंजूररानी सिंह कहती है - 'स्त्रियों की ताकत दिखाते है उसके अधनंगेपन में। टाईवाले नायक को रिझाने के लिए मिनी स्कर्ट या मिनी पहनने का निर्देश होता है। गीत गाते या डांस करते हुए नायक का वस्त्र नहीं खुलता न कही से खिसकता है पर नायिका का ऑचल या दुपट्टा हमेशा गिरता-पड़ता-उड़ता है, वे अपने कपड़े सम्हाल नहीं सकती या सम्हालती नहीं।

आज की विज्ञापनीय औरतें यह भूल जाती है कि सुन्दर होना तो अच्छी बात है लेकिन सुन्दरता को उभारकर प्रस्तुत करना कितना घातक है। कामकाजी महिलाओं की जिंदगी आज के संदर्भ में कुछ हद तक संतोषजनक मानी जा सकती है। लेकिन सर्विस-पेशे के दौरान किन-किन परिस्थितियों से दो-चार होना पड़ता है इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस संबंध में प्रभा खेतान का वक्तव्य है- 'बाहरी दुनिया में काम करते हुए अधिकतर स्त्रियां की मुख्य समस्या है गृहिणी और बच्चों के साथ स्वयं का सामंजस्य बैठाना। स्वाभाविक है कि किसी भी भूमिका का सही तरह से पालन न कर पाने के कारण ये अपराध बोध में ग्रस्त होती है। न वे अच्छी मॉ बन पाती है और न कार्य जगत में एक कुशल कामकाजी। उसकी इस कमजोरी का फायदा व्यवस्था उठाती है। वास्तविक तो यह है कि किसी भी राष्ट्र का विकास बिना आधी आबादी को साथ लिये सम्भव ही नहीं है। स्त्री और पुरूष दोनों विकास के दो पहिये है और जब तक दोनों पहिये समान रूप से आगे नहीं बढेंगे तब तक किसी देश का राष्ट्र के विकास की कल्पना करना महज कोरी कल्पना सिद्ध होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महिला सशक्तिकरण आवश्यकताएँ सम्भावना पुस्तक महिला सशक्तिकरण दशा एवं दिशा।
2. महिलाओं की स्थिति- क्रॉनिकल।
3. डॉ. राजकुमार- नारी के बदलते आयाम।
4. विनोद पाण्डेय- भारतीय समाज में नारी की भूमिका।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

रीवा जिला की प्रमुख सरायें एवं धर्मशालाओं का ऐतिहासिक महत्व

डॉ. मो. स्वालकीन खान *

प्रस्तावना – मध्यप्रदेश के अंतर्गत रीवा बघेलखण्ड का एक प्रमुख जिला है। स्वतंत्रता के पश्चात जब विन्ध्य क्षेत्र का विलीनीकरण हुआ तब रीवा को जिले का दर्जा दिया गया। रीवा, शहडोल से इलाहाबाद मार्ग पर 165 कि.मी. छुहिया घाटी के नीचे और गोविंदगढ़ से 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है तथा ट्रेन मार्ग पर कटनी से सतना होते हुए सतना से 40 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

स्थापत्य एवं ऐतिहासिक्ता की दृष्टि से रीवा में प्राचीन सरायें, एवम् धर्मशालाओं का अपना महत्व है ।यहॉ प्रमुख सरायों, धर्मशालाओं का वर्णन करना प्रासंगिक होगा –

प्रमुख सरायें – सरायें एक प्रकार का वह भवन है। जिसे विविध ग्रामों एवं नगरों में मार्ग के किनारे उन स्थानों पर बनाया जाता था, जहां पेयजल की व्यवस्था हो। बघेल वंश के राजाओं के द्वारा रीवा के आस-पास के ग्रामों एवं कस्बों में यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्थानों पर सरायों का निर्माण मध्यकालमें करवाया गया था। किन्तु दुर्भाग्यवश ये पुरातत्व सामग्रियाँ विखंडित होकर ढह चुकी हैं। कहीं-कहीं इनके अवशेष भी दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि उन स्थानों पर या तो लोगों का कब्जा हो चुका है, या फिर कोई दूसरी नई इमारत बन चुकी है।

रीवा जिले की यात्रा एवं सर्वेक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण स्थानों पर सरायों के निर्माण की बात जनश्रुति के आधार पर मिली। उनमें से कुछ प्रमुख स्थान, सरिया, रामपुर नैकिन, गोविन्दगढ़, ताला मुकुन्दपुर, बिछिया, गुढ़, सेमरिया, डहोरा, चाकघाट, सोहागी, मऊगंज, हनुमना, मनगंवा, गंगेय आदि वे प्रमुख स्थान हैं, जहां सरायों का निर्माण कार्य हुआ था। परंतु दुर्भाग्यवश कहीं भी सरायों का निर्माण अच्छी हालत में उपयोगी एवं सुरक्षित नजर नहीं आया।

जनश्रुति एवं साक्षात्कार में इन स्थानों पर पुरानी सरायें होने की जानकारी उपलब्ध हो सकी किन्तु जब वहां का भ्रमण एवं सर्वेक्षण कार्य मेरे द्वारा किया गया तो मुझे निराशा ही हाथ लगी, इतनी महत्वपूर्ण धरोहरों का नष्ट होना एक दु:खद बात है। फिर भी मैंने अपने अथक परिश्रम से निष्ठापूर्वक उन स्थानों तक पहुंचने की कोशिश जहां सरायों का निर्माण कराया गया था।

कुछ स्थानों पर सरायों के अवशेष मिले जिनका आगे के पृष्ठों पर विवरण सहित मुद्रित है।

बिछिया रीवा की सराय – बिछिया, रीवा मुख्यालय बस मार्ग पर बिछिया नदी में मुख्य मार्ग के बांई ओर नदी के किनारे बसा हुआ है। ये मोहल्ला किला की ओर जाता है किला रोड पर नदी के किनारे राजा गुलाब सिंह के समय में एक सराय का निर्माण कराया गया था, जो वर्तमान समय में खण्डित हो चुकी है। इसके अवशेष अभी बाकी हैं। इसे लगभग 40 फिट लंबाई में एवं 20 फिट चौडे आकार में बनाया गया था। इस सराय के बगल में अखाड़घाट स्थित है, जहां लोगों के निस्तार के लिए पेयजल की व्यवस्था थी।

अलाबक्स की सराय – इस सराय का निर्माण अलाबक्स ने लगभग 100 वर्ष पहले करवाया था। सराय अमहिया में सिरमौर चौराहा के पास फैजुल्ला धर्मशाला के बगल में स्थित है। यहाँ गरीब मुसाफिरों के विश्राम की व्यवस्था थी एवं उन्हें मुफ्त भोजन भी दिया जाता था। ईंट एवं लकड़ी से बनी हुई इस सराय में वर्तमान समय पर कहीं छत है तो कहीं टीने से ही छत को ढंका गया है। छत गिर चुकी है। लकड़ी के कड़ी के सहारे छत का निर्माण किया गया था। ये सरायें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में देखने को मिलीं, जनश्रुति के अनुसार इसी से लगा हुआ धर्मशाला उनके पुत्र हाजी फैजुल्ला द्वारा बनवाया गया था। देखरेख के अभाव के कारण ये इमारत पूरी तरह असुरक्षित हैं। यद्यपि आज भी इस सराय में बेसहारा एवं भिखारी वगैरह रात्रि में विश्राम करते हैं।

गोविन्दगढ़ की सराय – गोविन्दगढ़, रीवा-शहडोल बस मार्ग पर छुहिया घाटी से लगभग 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। गोविन्दगढ़ का किला गोविन्दगढ़-ताला मार्ग पर 1 कि.मी. की दूरी पर बांई ओर स्थित है। यहां महाराजा गुलाब सिंह द्वारा राहगीरों के विश्राम के लिए तालाब के निकट एक सराय का निर्माण करवाया था जिसका आकार लगभग 30 फिट लंबा एवम् 20 फिट चौड़ा था। इस सराय का निर्माण ईंट एवम् पत्थरों से करवाया गया था। जिसके अवशेष विद्यमान है किन्तु सराय अनुपयोगी है। इसकी छत ढह चुकी है। सर्वेक्षण के दौरान ही किले में स्थित सेवकों एवं कर्मचारियों से इस सराय के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई।

मनगवाँ की सरायें – मनगवाँ, रीवा से 20 मील की दूरी पर रीवा-इलाहाबाद मार्ग पर स्थित है। 'मनगवाँ एवं मऊ' के शासक सेंगर वंश के थे। ये जालौन (उ.प्र.) से स्थानान्तरित होकर मऊगंज तहसील में आबाद हुए थे। मऊगंज तहसील रीवा जिले के अंतर्गत आता है। मनगवाँ में सेंगरों का शासनकाल उसी समय का है, जब रीवा में बघेलों का था। मनगवाँ में पेयजल की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, सेंगर राजा धंकदेव ने जो यहाँ की गढ़ी भरों से छीनी थी, उसी के समय एक सराय यात्रियों के विश्राम के लिए इस गांव में बनवाई थी, जो वर्तमान में ध्वस्त हो चुकी है एवं उसके अवशेष नजर नहीं आ रहे है। जनश्रुति के अनुसार मनगवाँ में तालाब के किनारे मार्ग की दांयीओर राहगीरों के लिए एक बड़ी सराय राजाओं द्वारा निर्मित कराई गई थी, जिसका आकार लगभग 800 वर्गफिट का था जिसमें दो बड़े हाल और दो छोटे कमरे थे, एक रसोई भी थी, ये सराय ईंट पत्थर से बनाई गई थी, छत पूरी तरह से ढह चुकी है, दीवारें गिर चुकी है। ऐसे में ठीक-ठीक पता कर पाना कठिन कार्य है कि इसका आकार एवं निर्माण शैली क्या थी, प्राय: सराय सामान्य आकार की

* (इतिहास) पं.शम्भूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत

ही होती थीं।'

त्यौंथर की सराय – त्यौंथर, रीवा–इलाहाबाद मार्ग पर स्थित रीवा जिले की तहसील है, जो लगभग 60 मील उत्तर में स्थित है। त्यौंथर में मुख्य मार्ग पर तालाब के निकट परिहार राजाओं के द्वारा एक बड़ी सराय का निर्माण कराया गया था। बाद में 19 वीं शताब्दी में जब त्यौंथर के परिहारराजा ने जब बघेलों की अधीनता स्वीकार कर ली उस समय भी वहां सरायों का निर्माण कराया गया था, किन्तु इस बात की जानकारी नहीं हो सकी कि किस राजा के समय सरायें बनीं थीं। वर्तमान समय में ये सरायें खण्डहर हो चुकीं हैं। ईंटों एवं पत्थरों की बनी सरायें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। स्वतंत्रता के पश्चात इन भवनों की ओर लेशमात्र भी ध्यान नहीं दिया गया इस कारण सारी सरायें नष्ट हो चुकी हैं।

क्योंटी की सराय – क्योंटी, त्यौंथर से लगभग 30 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो वर्तमान में रीवा जिला की सिरमौर तहसील के अंतर्गत आता है, जहां प्रसिद्ध जल प्रपात भी है। क्योंटी प्रवेश करने पर लगभग 1 कि.मी. की दूरी पर दांये ओर एक सराय पत्थरों की बनी हुई देखने को मिली जो लगभग 200 वर्ष पुरानी थी, किन्तु वर्तमान समय में पूरी तरह से ढह चुकी है, और मात्र उसकी दीवारों के अवशेष ही बचे हुए हैं। देखने से लगता है कि ये सराय लगभग 30 फिट लंबी और 20 फिट चौड़ी अर्थात् 600 वर्गफिट की बनी होगी। यहाँ गरीब राहगीर, मुसाफिर ठहरते भी थे और कुछ समय आराम करके अपनी यात्रा पर निकल जाया करते थे। यह जानकारी साक्षात्कार में क्योंटी के कुछ लोगों से प्राप्त हुई।

सेमरिया की सराय – सेमरिया रीवा जिला मुख्यालय से 15 कि.मी. दूर बस मार्ग पर उत्तर पश्चिम में स्थित है। सेमरिया में एक प्राचीन सराय के अवशेष कस्बे में प्रवेश करने से पहले लगभग 1 कि.मी. मार्ग की दांयी ओर देखने को मिला जनश्रुति के अनुसार यह एक सराय थी जो लगभग 150 वर्ष पहले निर्मित की गई थी किन्तु वर्तमान समय में ये जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पूरी तरह खंडहर बन चुकी है। इसका आकार लगभग 30x20 वर्गफिट का था, देख–रेख के अभाव के कारण इसकी सुरक्षा नहीं हो सकी। इस सराय में एक हाल एवं 2 कमरे थे पूरी सराय वर्तमान में जीर्ण–शीर्ण हो चुकी है।

प्रमुख धर्मशालाएं –

बैजू धर्मशाला रीवा – बैजू धर्मशाला तक पहुंच मार्ग नेशनल हाईवे मार्ग 07 पर पुराना बस स्टैण्ड के बगल में व्यंकट मार्ग के पश्चिमी भाग पर बैजू धर्मशाला स्थित है। इस धर्मशाला का निर्माण कार्य महाराजा गुलाब सिंह सा. के संरक्षण में हुआ। इस धर्मशाला का निर्माण कार्य सेठ बैजनाथ रामसहाय अग्रवाल द्वारा 1941 ई. में पूरा कराया गया। 100x100 वर्गफिट के क्षेत्रफल में इस धर्मशाला का निर्माण गरीब जनता के आश्रय देने एवं उनके विश्राम करने के उद्देश्य से किया गया था। इस धर्मशाला का मुख पूर्व दिशा में है, प्रवेश द्वार से लगा हुआ बाहर की ओर पाँच सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर बाराण्डा 10x100 वर्गफिट का बना हुआ है, इसका मुख्य द्वार मेहराबदार अति सुंदर है जहाँ से 10 फिट का रास्ता धर्मशाला के अंदर की ओर जाता है। ये धर्मशाला दो मंजिल की बनी हुई है, इस धर्मशाला में 10ग10 वर्गफिट के कुल 55 पचपन कमरे बने हुए हैं, कमरों के चारों ओर मंजिलों में मेहराबदार वर्गाकार बराण्डा बना हुआ है, कुल 38 मेहराब अंदर की ओर बने हुए हैं। प्रवेश मार्ग धर्मशाला के आंगन में खुलता है।

भू–स्थल से 51 फिट की ऊंचाई में बने इस धर्मशाला की ऊंचाई लगभग 40 फिट है। धर्मशाला का मुख्य दरवाजा मोटे स्तंभों से सुसज्जित है, जिसके ऊपर की ओर बीच में 3 मेहराब बने हुए है, मुखाग्र में दो बड़े स्तंभ काफी मजबूत पत्थरों से युक्त गोल आकार में ऊपर की ओर 60 फिट की ऊंचाई तक गया है, जो मेहराबदार खिड़कियों से युक्त है, दोनों मंजिलों में प्रवेश मार्ग पर बनी इन दोनों मीनारों के बीच में नीचे से ऊपर तक 6 मेहराबनुमा खिड़कियाँ बनी हुई हैं, धर्मशाला के बाहरी भाग में दोनों ओर मेहराबनुमा बराण्डा बना हुआ है; दोनों मीनारों के ऊपरी भाग पर एक खूबसूरत गुम्बद जिसके ऊपर तीन छोटी मीनारें इसकी सुन्दरता को चार चाँद लगा रही हैं। पत्थरों को काट कर अत्यंत सुंदर कलाकृतियों को उभारा गया है। दोनों मंजिलों में कमरों के बाहर बराण्डा मेहराबदार है। प्रत्येक मेहराब के बीच में पत्थरों का स्तंभ है। मध्य भाग की तरह धर्मशाला के चारों कोनों पर चार–चार मोटी पत्थर की बनी हुई गोलाकार मीनारें इसकीसुंदरता को और भी बढ़ा देती हैं। चारों कोने पर चारों मीनारों के बीच एक–एक गुम्बद गोलाकार बना हुआ है। इस प्रकार इस धर्मशाला के पूर्व दिशा में मुख्य द्वार के तरफ 10 मीनारें, 03 गुम्बद एवं पीछे भाग पर 8 मीनार एवं 02 गुम्बद बने हुए हैं। ये मीनारें सीढ़ीनुमा हैं। नीचे से ऊपर तक सीढ़ियों से जाया जा सकता है, उसकी कलाकृति में मुगल स्थापत्य कला का स्पष्ट निखार आता है।

धर्मशाला के बीचों–बीच मध्य भाग में आंगन है, जहाँ से धर्मशाला के अंदर के भाग को देखा जा सकता है। इस आँगन का आकार 50 फिट चौड़ा एवं 50 फिट लम्बा है। मेहराबदार बराण्डा चारों तरफ बना हुआ है। बराण्डे का आकार 10 फिट चौड़ा है। धर्मशाला के अंदर पहली मंजिल पर पश्चिमी भाग पर बीचों–बीच एक मंदिर है जिसमें राधाजी एवं भगवान कृष्णजी की मूर्ति है, ठहरने वाले लोगों के पूजा–आराधनाकेलिए मंदिर का निर्माण धर्मशाला में करवाया गया था। ये धर्मशाला पूरी तरह भूरे एवं गुलाबी पत्थरों से युक्त है। धर्मशाला में कार्यरत मैनेजर से साक्षात्कार पर जानकारी मिली कि अधिकांश मिस्त्री मुस्लिम थे एवम् राजस्थान से बुलवाए गए थे। आर्किटेक्ट इंजीनियर भी मुस्लिम था जो राजस्थान से आया था। इसकी नक्काशी पत्थरों को काटकर उभारी गई है जो अत्यंत खूबसूरत है, जिसे पूरी तरह ताजमहल के बाहरी भाग की तरह निखारने का प्रयास किया गया है।

इसकी मोटी दीवारें जो पत्थरों की हैं, इसकी मजबूती के लिए काम कर रही हैं। गुम्बद, मीनार एवं मेहराब इसकी सुंदरता को और भी अधिक बढ़ाती हुई नजर आती हैं। इस बावली का प्रांगण लगभग 40,000 वर्गफिटका है। चारों ओर दीवार एवं एक लोहे का दरवाजा इसके प्रांगण में लगा हुआ है। प्रांगण में किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है। बारिश के मौसम में यहाँ कीचड़ हो जाता है। इस धर्मशाला के पीछे पश्चिम दिशा में प्रांगण के दोनों ओर खूबसूरत गुम्बदनुमा एक–एक स्तूप बना हुआ हैं, जो इसकी सुंदरता को बढ़ाता है।

ये धर्मशाला आज भी दानवीर सेठ रामसहाय जी अग्रवाल ट्रस्ट द्वारा संचालित है। यहाँ नाममात्र के लिए 20 रू. से 50 रू. तक शुल्क ठहरने वालों से लिया जाता हैं, जो दीन–हीन लोग यहाँ आते हैं उन्हें निःशुल्क सुविधाएँ दी जातीं हैं। इसके बाहरी हिस्से में साफ–सफाई का अभाव है। जानवर बिना रोक–टोक के यहाँ घूमते रहते हैं, यह विशाल धर्मशाला बघेल खण्ड का ताज महल है। इसकी साफ–सफाई का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। अगर प्रांगण के मैदानी भाग पर यदि पक्का प्लास्टर कर दिया जाए तो यहाँ का कूड़ा कचरा हट सकता है।

इस अनमोल धरोहर को बचाये रखना एवं इसकी साफ–सफाई की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सेठ वैजनाथ, रामसहाय अग्रवाल जी की दानशीलता की यह धर्मशाला बेमिसाल उदाहरण प्रस्तुत करती है।

हाजी फैजुल्ला धर्मशाला – रीवा जिले का दूसरा पुराना एवम् महत्वपूर्ण धर्मशाला हाजी फैजुल्ला धर्मशाला है। जो रीवा अमहिया में सिरमौर चौराहा के दायीं ओर स्थित है। इस धर्मशाला का निर्माण दीन-हीन गरीब जनता के विश्राम करने एवं ठहरने के उद्देश्य से हाजी फैजुल्लाद्वारा 19-19में करवाया गया था। इस धर्मशाला के ऊपरी हिस्से में फैजुल्ला व अलाबक्श धर्मशाला अंकित है। इस प्राचीन धर्मशाला का आकार काफी विस्तृत था। लगभग 100 फिट लम्बी एवं 40 फिट चौड़ी अर्थात 4 हजार वर्गफिट में ये धर्मशाला बनी थी, जिसमें बाहरी गली की ओर 10 कमरे 10x10 वर्गफिट के बने हुए हैं। अंदर की ओर भी कुछ बड़े हाल एवं कमरों का निर्माण हुआ था, इस धर्मशाला में ईंट एवं पत्थर से दीवारों का निर्माण कराया गया था, ऊपर लकड़ी की सिल्ली के ऊपर छत का निर्माण किया गया था।

इसका मुख्य द्वार मध्य भाग में निर्मित है, जो मेहराबनुमा बना हुआ है। अंदर चारों ओर कमरे बने हुए हैं, बीच में आँगन है। इस धर्मशाला में मीनार एवं गुम्बदों का अभाव हैं। सादगीपूर्ण यह धर्मशाला गरीबों, भिखारियों एवं दीन-हीन लोगों का सहारा देने के उद्देश्य से हाजी फैजुल्ला खान द्वारा बनवाया गया था। कहीं-कहीं मिट्टी के गारे से भी ईंट-पत्थरों की जुड़ाई का काम हुआ है, जो स्पष्ट नजर आता है।

धर्मशाला के बाहरी भाग में बराण्डा एवं छोटे-छोटे आठ-दस कमरों का भी निर्माण कार्य बाद में हुआ, जिनकी छत ढह जाने के बाद उनमें टीने एवं खपरे की छत बनाई गई है। यह धर्मशाला जीर्ण-शीर्ण अवस्था में स्थितहैं तथा बुरी तरह खण्डित एवं अपनी जर्जर अवस्था में सिसकियाँ लेती हुई नजर आती है।

फिर भी इस जर्जर स्थिति के होते हुए भी अभी इस धर्मशाला में थके-माँदे, दीन-हीन, गरीब, भिखारी प्रवृत्ति के लोग आकर आराम करते हैं एवं रात्रि विश्राम करते हैं।

धर्मशाला के कुछ हिस्सों पर लोगों ने अपना अधिकार जमा लिया है और अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। इस पुराने जीर्ण-शीर्ण धर्मशाला में साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है, न ही इसमें कोई पुननिर्माण का कार्य हुआ। यह पुरानी धरोहर धीरे-धीरे खण्डित होकर खण्डहर का रूप ले रही है, जो खेद का विषय है।

पूसू धर्मशाला रीवा – पूसू धर्मशाला रीवा जिले की तीसरी पुरानी धर्मशालाहै। पूसू धर्मशाला फोर्ट मार्ग रीवा में ए. के. स्कूल के पास अशोक बाबा के मजार के निकट अशोक के वृक्ष के सामने रोड के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस धर्मशाला का निर्माण कार्य 1940 से 1950 के बीच हुआ। इस धर्मशाला का निर्माण दानवीर श्री पूसू वर्मा ने करवाया था। गरीब, दीन-हीन, भिखारी एवं जनता के हितार्थ इस धर्मशाला का निर्माण किया गया था। जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने वाले गरीबों को श्री पूसू वर्मा द्वारा मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी की जाती थी, वे जब तक जीवित थे गरीबों कापूरा ध्यान रखते थे, उनकी मृत्यु के पश्चात नि:शुल्क भोजन देने की व्यवस्था भी बंद हो गई।

इस धर्मशाला का निर्माण पत्थरों से किया गया था। यह धर्मशाला लगभग 100x100 वर्गफिट में निर्मित है, सामना 40 फिट चौड़ा एवं गहराई लगभग 100 फिट की है।

प्रवेश मार्ग में एक कमरा 20ग15 वर्गफिट का बना हुआ है, जिसमें आस्ताना हजरत लम्बशाह रह अलैह का बना हुआ है। अंदर 40ग20 अर्थात 500 वर्गफिट का बड़ा हाल हैं एवं 15x20 अर्थात 300 वर्गफिट के 4 कमरे बने हुए है, यह दो भागों में बना हुआ है। इसके एक भाग पर वर्तमान में आर.एस.एस. का मुख्यालय (कार्यालय) बना हुआ है। ये धर्मशाला अभी सुरक्षित अवस्था में है किन्तु अब यहाँ यदा-कदा ही कोई गरीब भिखारी आकर विश्राम करता है, वैसे ज्यादातर ये बंद ही पड़ा रहता है। इसमें एक आंगन भी है। ऐसा माना जाता है कि भोजन व्यवस्था बंद हो जाने के कारण यहाँ ठहरने वालों का आना बंद हो गया है।

गोविंदगढ़ का त्रिडंडी धर्मशाला एवम् मठ – गोविंदगढ़, रीवा-शहडोल बस मार्ग पर रीवा से 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। गोविंदगढ़ पहुंचने पर गोविंदगढ़ से ताला मुकुन्दपुर रोड पर तिराहे से लगभग 1 कि.मी. पश्चिमी दिशा में मार्ग के बांई ओर गोविंदगढ़ तालाब के पश्चिमी तट पर गोविंदगढ़ का एक विशाल किला बना हुआ है।किले के प्रांगण में एक त्रिडंडी धर्मशाला भी है साथ ही एक व्यंकटेश भगवान का मंदिर भी है।

महाराजा रघुराज सिंह के द्वारा इस धर्मशाला का निर्माण 1887 ई. में करवाया गया था। जब महाराजा रघुराज सिंह दक्षिण भारत की यात्रा के लिए तिरुपति बालाजी का आर्शीवाद लेकर वापस लौटे और उन्हें एक पुत्र व्यंकटरमन सिंह की प्राप्ति हुई, तब पुत्ररत्न की प्राप्ति के पश्चात् स्वामी त्रिडंडी सम्पत कुमारजी के मार्गदर्शन में इस धर्मशाला एवं मठ का निर्माण करवाया और अपने इलाकेदारों को कई एकड़ भूमि दान में दिया।

इस धर्मशाला में उत्तर एवं दक्षिण भारत के साधु-संत आकर रुकते थे, यह एक धार्मिक धर्मशाला है, जहाँ रामानुज सम्प्रदाय से जुड़े साधु-संतों के रुकने की विशेष व्यवस्था है। वैसे हिन्दू सम्प्रदाय के साधु-महात्मा जो मंदिर एवं मठ में दर्शन के लिए जाते हैं, उन संतों को रुकने की स्वीकृति है। जगतगुरू रामानुजाचार्य की चरण पादुका इस स्थान पर होने के कारण प्रतिवर्ष उत्तर एवं दक्षिण भारत के साधू-महात्मा आते हैं, और यहाँ रूककर अपने आपको धन्य महसूस करते हैं।

इस धर्मशाला में मंदिर के बगल में पांच कमरे बने हुए हैं, जो 10x15 वर्गफिट के हैं। इनका निर्माण पत्थरों से करवाया गया है जो आज भी सुरक्षित हैं, रुकने की सारी सुविधाओं से युक्त इस धर्मशाला में आज भी साफ-सफाई देखने को मिलती है। समय-समयपर इस मंदिर में विविधधार्मिक आयोजन होते रहते हैं, इन आयोजनों केसमय धर्मशाला में अत्यधिक लोग विश्राम करते हैं, जिनके भोजन की व्यवस्था रामानुजाचार्य जी स्वामी शेषमणि दास जी द्वारा संचालित होती है। इस बात की जानकारी साक्षात्कार के समय स्वामी शेषमणिदास द्वारा दी गई, जो यहां स्थित मठ के मठाधीश हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. साक्षात्कार - श्री मकबूल खान, मैनेजर (उम्र 55 वर्ष) बैजूधर्मशाला घोघर रीवा। दिनांक 13.12.2010
2. साक्षात्कार - आबाद खान, लेक्चरर, (उम्र - 52 वर्ष) हा.से. स्कूल क्रं. 2, बिछिया। दिनांक 13.12.2013
3. साक्षात्कार - अब्दुल वाहिद (उम्र -80 वर्ष) फोर्ट रोड अशोक वृक्ष के पास रीवा, दिनांक 13.12.2010
4. साक्षात्कार - स्वामी शेष मणिदास (उम्र - 55 वर्ष) मठाधीश व्यंकट धर्मशाला गोविंदगढ़। दिनांक 13.12.2010
5. शोधकर्ता द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर।

****

संस्कृति तथा सभ्यता

डॉ. सुनीता शुक्ला *

प्रस्तावना – किसी देश की संस्कृति उसकी सम्पूर्ण मानसिक निधि को सूचित करती है। यह किसी खास व्यक्ति के पुरूषार्थ का फल नहीं, अपितु असंख्य ज्ञात तथा अज्ञात व्यक्तियों के भागीरथ प्रयत्न का परिणाम होती है। सब व्यक्ति अपनी सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार संस्कृति के निर्माण में सहयोग देते हैं। संस्कृति की तुलना आस्ट्रेलिया के निकट समुद्र में पाई जाने वाली मूँगे की भीमकाय चट्टानों से की जा सकती हैं मूँगे के असंख्य कीड़े अपने छोटे घर बनाकर समाप्त हो गए, फिर नए कीड़ों ने घर बनाए, उनका भी अन्त हो गया। इसके बाद अगली पीढ़ी ने भी यही किया और यह क्रम हजारों वर्ष तक निरन्तर चलता रहा। आज उन सब मूँगों के नन्हें-नन्हें घरों ने परस्पर जुड़ते हुए विशाल चट्टान का रूप धारण कर लिया है। संस्कृति का भी इसी प्रकार धीरे-धीरे निर्माण होता है और उसके निर्माण में हजारों वर्ष लगते हैं। मनुष्य विभिन्न स्थानों पर रहते हुए विशेष प्रकार के सामाजिक वातावरण, संस्थाओं, प्रथाओं, धर्म, दर्शन, लिपि, भाषा तथा कलाओं का विकास करके अपनी विशिष्ट संस्कृति का निर्माण करते है।

अतः हम कह सकते हैं कि संस्कृति व्यक्ति निष्ठ न होकर अनेक व्यक्तियों द्वारा किया गया एक बौद्धिक प्रयास है। इसीलिए किसी राष्ट्र की संस्कृति का निर्माण अचानक न होकर उस राष्ट्र के निवासियों के जीवन की शताब्दियों का परिणाम होता है।

संस्कृति के प्रमुख विशेषताएँ –

1. संस्कृति एक आंतरिक अवस्था है।
2. व्यक्ति के द्वारा संस्कृति का निर्माण होता है और हर व्यक्ति में संस्कृति के गुण पाये जाते है।
3. किसी व्यक्ति विशेष के गुणों को संस्कृति नहीं कहा जा सकता है, संस्कृति तो सामाजिक गुणों का नाम है।
4. संस्कृति की तुलना मानव समाज की उस विरासत से की जा सकती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है तथा मानव जीवन की क्रियाओं को निर्धारित करती है।

संस्कृति का समानांतर एक शब्द सभ्यता है। भ्रमवश अनेक व्यक्ति संस्कृति एवं सभ्यता को एक ही मान लेते है। वस्तुतः सभ्यता मानव की भौतिक विचारधारा की सूचक है तथा संस्कृति आध्यात्मिक एवं मानसिक क्षेत्र के विकास की एक सूचक है।[1] दूसरे शब्दों मे हम कह सकते हैं कि मनुष्य के भौतिक क्षेत्र मे की गई उन्नति का नाम ही सभ्यता है। सभ्यता समाज में रहन-सहन, वेशभूषा, व्यवहार का पर्याय है।

मेकाइवर और पेज के अनुसार 'मनुष्य ने अपने जीवन की दिशाओं को नियंत्रित करने के प्रयत्न में जिस सम्पूर्ण कला-विन्यास और संगठन की रचना की है, उसे सभ्यता कहते है।'[2] मनुष्य का समाज में मानवीयकरण ही सभ्यता है।[3]

सभ्यता आदिम बनैली स्थिति से सामाजिक जीवन की ओर मनुष्य की प्रगति का नाम है, संस्कृति उसी प्रगति की सत्य, शिव सुन्दर और रूचिकर परम्परा का।[4] हम इस संस्कृति के इतिहास मे सभ्यता का समावेश करते है।

गिसबर्ट का विचार है कि सभ्यता यह बतलाती है कि हमारे पास क्या है, संस्कृति यह बतलाती है कि हम क्या है।[5] संस्कृति किसी समाज मे निहित चरम मूल्यों की सामंजस्यपूर्ण चेतना है जिसकी अभिव्यक्ति उसने अपनी सामूहिक संस्थाओं में की है, जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति सदस्यों ने अपने भाव-स्वभाव, अपनी प्रवृत्तियों, अपने आचरण मे और भौतिक वस्तुओं को दिये गये महत्वपूर्ण रूपों में की हो।[6] संस्कृति एक प्रयत्न ही नहीं, किन्तु एक विशिष्ट स्थिति हुई और सभ्यता का ज्ञान परक अंश नहीं किन्तु सभ्यता उसके ज्ञान-परक अंश से उद्‌भूत हुई।[7] बेग्गी ने सभ्यता को वह संस्कृति माना है जिसमें नगरों का संस्थापना होता है।[8]

सभ्यता एवं संस्कृति का मौलिक अंतर यह है कि सभ्यता का संबन्ध जीवन-यापन या सुख-सुविधा की बाह्य वस्तुओं से है, जबकि संस्कृति का संबंध आंतरिक वस्तुओं से है।[9]

संस्कृति आभ्यन्तर है, सभ्यता बाह्य है, संस्कृति को अपनाने मे देर लगती है पर सभ्यता का अनुकरण सरलता से किया जा सकता है। संस्कृति का सम्बन्ध निश्चय ही धार्मिक विश्वास से हैं सभ्यता सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से बंधी हुई है।

सभ्यता और संस्कृति एक ही मानव विकास के दो पहलु हैं। एक सभ्यता-उसकी स्थूल और अविष्कार की दिशा की और संकेत करता है, दूसरा, संस्कृति उस विकास के चिन्तित, सुन्दर, शालीन, सूक्ष्म तत्वों की ओर।[10]

अतः सभ्यता मनुष्य के मनोविकारों की द्योतक है, संस्कृति आत्मा के अभ्युत्थान की प्रदर्शिका है। सभ्यता मनुष्य को प्रगतिवाद की ओर ले जाने का संकेत करती है। संस्कृति उसकी आंतरिक और मानसिक कठिनाइयों पर काबू पाने में सहायक सिद्ध होती है।

निष्कर्ष –

1. संस्कृति साध्य है, सभ्यता साधन।
2. संस्कृति तथा सभ्यता दोनो ही मानव-विकास के दो पहलू हैं।
3. संस्कृति का काम मूल्यांकन है, अपना नहीं अपने स्तर की सभ्यता का।
4. सभ्यता का अपना स्वतंत्र मूल्य नहीं होता। उसकी उपयोगिता होती है, उपयोगिता के आधार पर ही उसका मूल्यांकन होता है।

* प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

5. संस्कृति जीवन का आंतरिक सौन्दर्य है, सभ्यता उसके बाह्य साधनों की सुविधा।
6. संस्कृति का सम्बन्ध आत्मा से है तथा सभ्यता का सम्बन्ध कार्यकलापों से है।
7. सभ्यता का सम्बन्ध सामाजिक विरासत के मूर्त पक्ष से है और संस्कृति का अमूर्त पक्ष से।
8. सभ्यता मे सुधार किया जा सकता है, परंतु संस्कृति मे नहीं।
9. सांस्कृतिक वस्तुएँ प्रतियोगिता रहित होती है, किन्तु सभ्यता का आधार प्रतियोगिता से है।
10. संस्कृति अन्त: चेतना, सौन्दर्यानुभूति एवं आनन्दोल्लास आदि अभ्यान्तरित तत्वों से सम्बन्धित है, परन्तु सभ्यता स्थूल तथा भौतिक के संयोजन और उसके लिये आवश्यक संगठित प्रयत्नों की और संकेत करती है।
11. सभ्यता संस्कृति का ही एक अंग है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. राजकिशोर सिंह-भारतीय कला और संस्कृति, संस्करण-1971, पृ. -193.
2. Society, Page-498.
3. Mathew Arnald- Culture and Anarchy, Ed.1950.
4. डॉ. भगवत शरण उपाध्याय-सांस्कृतिक भारत, पृ. 6.
5. डॉ. डी.पाल. बघेल-समाजशास्त्र के सिद्धांत, संस्करण 1982-83, शीर्षक-सभ्यता एवं संस्कृति, पृ.-240
6. डॉ. आविद हुसैन-भारत की राष्ट्रीय संस्कृति, भूमिका, पृ. 6 शीर्षक-संस्कृति, अनुवाद- महेन्द्र चतुर्वेदी.
7. डॉ. बल्देव प्रसाद मिश्र-भारतीय संस्कृति का गोस्वामी तुलसी का योगदान संस्करण-1953, अध्याय-1, पृ.-3-4, शीर्षक-भारतीय संस्कृति का अर्थ
8. फिलिप बेग्गी-कल्चर एण्ड हिस्ट्री, पृ. 60. संस्करण 1951 अध्याय-7
9. डॉ. राजकिशोर सिंह-भारतीय कला और संस्कृति, संस्करण-1971 पृ. 193.
10. डॉ. भगवत शरण उपाध्याय-सांस्कृतिक भारत- पृ. 6.

****

प्रत्येक भारतीय को समानता व गरिमामय जीवन जीने का संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए

प्रीति राठौर * डॉ. मदनलाल पँवार **

शोध सारांश – यह लोकतंत्र एवं समानता का युग है। आज किसी भी व्यक्ति की भावनाओ को ठेस नही पहुँचाई जानी चाहिए, अपमान नही किया जाना चाहिए और नीचा नही दिखाना चाहिए। यही संविधान का मूल तत्व व भावना है।

प्रस्तावना – भारत की आजादी के लिए अंग्रेजो के विरूद्ध दलितो ने भी बढ़–चढ़ कर भाग लिया था। दलित नेता अंग्रेजो से मुक्ति के साथ ही रूढ़िवादिता व जातिवाद से भी मुक्ति चाहते थे। राष्ट्रवादी नेताओं का मानना था कि हम पहले आजादी हासिल करें। आजादी के बाद दलित मुक्ति के प्रश्न को हल कर लिया जाएगा। 15 अगस्त, 1947 को देश आजाद हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। लेकिन संविधान लागू होने के 65 वर्ष बाद भी हम रूढ़िवादियों से मुक्त नही हो पाए है। हम आज भी उपेक्षित और घृणित जीवन जीने पर मजबूर है। हमें छोटा व नीचा समझा जाता है। चाहे हम अपने परिश्रम से कितने ही बड़े अधिकारी बन जाएं, बुद्धि में हम कितने ही कुशाग्र हो, शरीर से हम कितने ही बलिष्ठ हो, कितने ही साधन सम्पन्न हो, तथाकथित उच्च जाति के लोगो की भावनाओं में कोई भी बदलाव नही आया है। भारतीय संविधान की मूल भावना 'समानता एवं सम्मानपूर्वक व गरिमामय जीवन जीने की अवधारणा' का मखौल उड़ाया जाता है। हमें पग–पग पर लज्जित व अपमानित किया जाता है। आज भी हमें 'चमार' कहकर गाली दी जाती है। 'चमार' शब्द अपमानजनक होने के बावजूद सभी मेघवंशिय जातियों को लज्जित करने के लिए इसी नाम से जोडा गया है, चाहे चमड़े के काम से वे वर्षो से कोसो दूर हों। ऐसे ही ढेढ़, ढेर, देढ़ा, चर्मकार, मेंगु, मुचि आदि शब्द तिरस्कृत, असम्मानीय व असंवैधानिक हैं, जो मनुवादियों (रूढ़िवादिया) द्वारा गढे गए हैं।

मानव स्वभाव की एक सच्ची विडम्बना यह है कि जिस वस्तु की उसे आवश्यकता होती हैं, उसे पाने के लिए वह उस वस्तु के निर्माता की खुशामन्द करता हैं। अंग्रेजो के भारत में आने से पूर्व भारत की लगभग 40 प्रतिशत आबादी भिन्न–भिन्न प्रकार के लघु घरेलु उद्योगों में लिप्त थी। आमजन द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय कारीकरों द्वारा निर्मित वस्तुओं से कर ली जाती थी। चूंकि बाकी 60 प्रतिशत आबादी को उनके उत्पादों की आवश्यकता होती थी, इसलिए वे इनके कारीगारों की खुशामद करते थे। इनमें चमड़े से बनी रोजमर्रा उपयोग में आने वाली वस्तुओं (जूते, चड़स, बाल्टी, मस्क, दीवडा, नाडी, लगाम, जीन, कवच, ढ़ाल, नकेल, रस्सी इत्यादि) और कपड़ों (पहनने, ओढ़ने, बिछाने, तिरपाल, बोरी इत्यादि) का सबसे अधिक उपयोग होता था। इसलिए चर्मकारों और बुनकरों की अधिक खुशामद की जाती थी।

अंग्रेजो के भारत में आगमन के बाद भारत में बड़े–बड़े उद्योग स्थापित किए गए और यूरोप में स्थापित उद्योगो में भारत से कच्चा माल जाने लगा तो भारत की स्थानीय घरेलु उद्योगो में लिप्त 30 प्रतिशत आबादी बेरोजगारी व भुखमरी के कगार पर पहूँच गई। बाटा जैसे अनेक उद्योगो ने चमड़े केा काम करने वाले लोगो को और मान्चेस्टर (इंग्लैण्ड) में पावरलूम से बनने वाले वस्त्रो के उद्योगो ने भारतीय बुनकरों को भी दरिद्रता की ओर धकेल दिया। जब अंग्रेजो द्वारा स्थापित उद्योगो से उत्पादित वस्तुओं से आमजन की आवश्यकताओं की पूर्ति होना शुरू हुई और चर्मकारों व बुनकरें की सम्पन्नता समाप्त हो गई, तो उनकी खुशामद भी बन्द हो गई। कुछ लोग बडे उद्योगे में नौकरी पर चले गए, लेकिन अधिंकाश लोग गॉवों में संभ्रांत लोगो की दया पर ही निर्भर रह गए। दरिद्रता से घृणा की शुरूआत होती हैं। यहॉ से हुई उनके दोहन की शुरूआत। पेशवा सामंतशाही ने सभी शूद्रों को मरे जानवरों की खाल उतारने व जूता गांठने के काम से जोड दिया। उन्होने प्रचार–प्रसार द्वारा यह काम उन लोगो से भी जबरन करवाया जो चमडे का काम नही करते थे। शब्दकोशकारों ने भी चमारों को सामाजिक रूप से अपमानित करने के लिए कुछ नए शब्द अन्वेषित किए। उन्होंने इस जाति को अति नीच व अस्पृष्य घोषित कर दिया। संस्कृत के शब्द–कोश ग्रंथों में 'चर्मकार' को नीच जाति नही कहा गया था, लेकिन हिन्दी शब्द–कोशों (हिन्दी शब्द–सागर–1915) में 'चमार' शब्द का अर्थ दिया गया, एक नीच जाति, जो चमडें का काम करती हैं।' इस जाति को गाली के तौर पर समझा जाने लगा तथा 'चमार' कहकर अपमानित किया जाने लगा।

सन् 1920 में प्रकाशित मि.जी.डब्ल्यू. ब्रिग्स ने अपनी 'द चमार' नाम की पुस्तक में चमार, जटिया, चामड़, चामडिया, रैहगर, रायगर, रामदासी, रविदासी, जुलाहा, कबीरपंथी, मेघ, भगत, कोली, कोरी, पासी, मेघवाल आदि समकक्ष 1156 मेंघवंशिय उपजातियों को 'चमार' बताया। जिस तरह से भारत में एक भी शूद्र न होते हुए भी मनुवाद के तहत् भारत की 85 प्रतिशत जनता को 'शुद्र' घोषित कर दिया गया था और जिस तरह मुस्लिम शासको ने भारत की हजारों गैर–मुस्लिम जातियों की चकबन्दी करने के लिए फारसी शब्द 'हिन्दू' प्रयुक्त किया था, उसी प्रकार 'चमार' शब्द भी अनजाने में प्रयुक्त हो गया। अंग्रेजो द्वारा दिए गए नाम को 'हिन्दू' की तरह प्रतिष्ठा सूचक समझकर सभी मेघवंशिय जातियॉ अपने के 'चमार' कहने में गर्व महसूस करने लगी।

समय बदला, लोगो में जागृति आई और चेतना लौटी तब यह आभास

* शोधार्थी (इतिहास) पेसिफिक विश्वविद्यालय,उदयपुर (राज.) भारत
** रिटा. प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, मन्दसौर (म.प्र.) भारत

हुआ कि रूढ़िवादियों द्वारा 'चमार' जाति को सम्मान सूचक नही, बल्कि अति शूद्र, घृणित और नीच जाति घोषित कर दिया गया है। मि.जी.डब्ल्यू. ब्रिग्स द्वारा इस सूचि में उन जातियों को भी डाल दिया गया जिनका चमडे के काम से कोई लेना-देना नही था।

इस बात का आभास होते ही सम्पूर्ण भारत में जागरण का शंख बज उठा। सुधारवादी आन्दोलनों में यह निर्णय लिया गया कि यचमार' शब्द से समाज को पग-पग पर अपमान झेलना पड़ता हैं, इसलिए 'चमार' जैसे अपमानजनक जाति सूचक शब्द से छुटकारा दिलाया जाए तथा उन लोगो से भी यह काम छुडवाया जावे जो दलितो की आबादी के पॉच प्रतिशत से भी कम है और चमडे का गन्दा काम करते हैं तथा जिनके कारण इस जाति की हीन दृष्टि से देखा जाता है, ताकि जाति अपना सिर ऊॅचा उठाकर चल सके। इन सुधारवादी आंदोलनों में निम्न घटनाएं उल्लेखनीय हैं -

1. दल्ली में सन् 1922 में मंत्री देवीदास, जानकीदास, चौधरी टेकचंद इत्यादि के प्रयासों से जाति सुधार सम्मेलन के बैनर तले पुराने किले के मैदान में एक विशाल सम्मेलन आयोजित हुआ। वहॉ 'बलाई', 'कोरी' या 'मेघवाल' नाम लगाकर अपमानित नाम 'चमार' से पीछा छुडाया।
2. पंजाब (बृहत पंजाब जिसमें पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र, भारत का वर्तमान पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश शामिल थे।) में सभी मेंघवंशिय उपजातियों को बाबू मंगूराम मुगोवालिया ने 'आदिधर्म' नाम के नीचे जोड़ा और 'आदिधर्म मण्डल' की स्थापना की। सन् 1928 में जग साईमन कमीशन भारत आया तो लाहौर में साईमन कमीशन के सामने बाबू मंगूराम मुगोवालिया ने लाखों आदिधर्मियों के साथ कहा कि हम भारत के मूलनिवासी हैं। हमारा एक अलग र्धम 'आदिधर्म' हैं। सर ज्योकरें 12 अक्टूबर, 1929 को जालन्धर (पंजाब) में आए तो आदिधर्म मण्डल के प्रतिनिधि उनसे मिले और अपने अलग धर्म के विषय में बातचीत की। पंजाब तथा भारत सरकार ने तत्काल 'आदिधर्म' को मान्यता प्रदान कर दी जिसके परिणामस्वरूप 1931 में सभी आदिधर्मियों ने अपना धर्म 'आदिधर्म' लिखाकर अपने संगठन का परिचय दिया और अपमानजनक नाम से पीछा छुडाया।
3. उत्तर प्रदेश में स्वामी अछूतानन्द जी ने डॉ. माणिकचन्द्र और सहयोगियों से मिलकर 'चमार' नाम से कलंक को दूर करने के लिए जाट, यादव आदि जातियों की तर्ज पर चमारों को सम्मानजनक नाम देने का विचार किया तथा उसके स्थान पर 'जाटव' शब्द का विकल्प दिया। कुछ सुधारवादी नेताओं ने दूसरा नाम 'यादव' सुझाया। बाद में यही 'जाटव' कहे जाने लगें। डॉ. माणिकचन्द्र की अध्यक्षा में 1920 में 'भारतवर्षीय जाटववीर युवा परिषद' का गठन हुआ। उन्होने 26 अक्टूबर, 938 को इंग्लैण्ड में भारत के मामलो के तत्कालीक मंत्री लॉर्ड जटलैण्ड को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें यह मॉग की गई कि आगरा के चमारों को सरकारी रिकार्ड में 'चमार' के स्थान पर 'जाटव' लिखा जाए, क्योंकि 'चमार' अपमानजनक शब्द है। उस समय की संयुक्त प्रांत सरकार ने लार्ड जटलैंड के आदेश पर कार्यवाही की। सरकार के निर्देश पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, लखनऊ के एडीशनल डिप्टी सैक्रेट्री ने अपने पत्रांक संख्या 78 (3) 3-1938 दिनांक 8 नवम्बर, 1939 के द्वारा आदेश दिया कि सरकारी रिकार्ड में आगरे की 'चमार' जाति को आज से 'जाटव' लिखा जाएगा। बहुत से चमारों ने यह परिवर्तन मानकर अपमानित नाम 'चमार' से पीछा छुडाया।
4. राजस्थान और गुजरात में स्वामी गोकुलदास जी 'मेघवंश' नाम से समाज को एक सूत्र में संगठित कर रहे थे। वे डूमाड़ा (अजमेर) के रहने वाले थे। इन्होने 1935 में दौराई ग्राम में 290 गॉवों की आम सभा बुलाई तथा 'राजस्थान मेंघवंश महासभा' का गठन किया। महासभा का एक अधिवेशन 1935 में अहमदाबाद में हुआ। उन्होने समाज को 'मेघवाल' नाम देकर अपमानित नाम 'चमार' से पीछा छुडाया।
5. राजस्थान और दिल्ली में आचार्य स्वामी गरीबदास जी, जो भोजपुरा (जयपुर) के बलाई थे, ने मेघवाल, बलाई, भांबी आदि मूलतः कपडे बनाने का कार्य करने वाली जाति को 'सूत्रकार' नाम से संगठित किया तथा अपमानित नाम 'चमार' से पीछा छुडाया।
6. राजस्थान के किशनगढ़-मदनगंज के स्वामी कल्याण भारती जी ने राजस्थान और मध्यप्रदेश में चमडे के कार्य को तिलांजलि देना आरम्भ कराया और 'चमार' कहलाना बन्द करवाया और चमार समाज को 'बैरवा' नाम देकर अपमानित नाम 'चमार' से पीछा छुडाया।
7. उतरांचल (गढ़वाल) में बाबू हरिप्रसाद जी टमटा ने दलितों में शिल्पकार आन्दोलन चलाया की समस्याओं से अवगत रहने वाले श्री बबनराव घोपल ने समाज के नेतृत्व का भार संभाला। इसी प्रकार सम्पूर्ण भारत में अपमानित नाम से पीछा छुडाने की मुहीम चली।
8. इसी मुहीम के अंतर्गत महात्मा गांधी ने भी 'चमार' शब्द को अपमानजनक मानकर दलित जातियों को सम्मानजनक नाम देने के लिए 'हरिजन' नाम का सुझाव दिया। 19 जुलाई, 1937 को मुम्बई प्रांत में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना। महात्मा गांधी के सुझाव के अनुसार एक सरकारी बिल में 'चमार' के स्थान पर 'हरिजन' शब्द प्रयुक्त किए जाने की सिफारिश की गई तथा 'हरिजन' शब्द को सरकारी मान्यता दे दी गई।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मेघवंश इतिहास - स्वामी गोकुलदास जी।
2. जाति भास्कर - मित्र पं. ज्वालाप्रसाद।
3. आर.पी.सिंह - राजस्थान मेंघवाल समाज जयपुर।
4. पत्रिका - राष्ट्रीय सर्व मेघवाल महासभा इण्डिका स्मारिका।
5. मालवा और राजसथान इतिहास - मनोहरसिंह राणावत के।
6. कतिपय पहलू श्री नहनागर, शोध संस्थान सीतामऊ 1983 ई.।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

20वीं शताब्दी से पूर्व डूँगरपुर राज्य में शिक्षा

निमेश कुमार चौबीसा *

प्रस्तावना – प्रस्तुत शोध लेख में 20वीं शताब्दी से पूर्व डूँगरपुर राज्य में शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। उपलब्ध साहित्यों के सारांश के आधार पर तथ्यों को संकलित कर क्रमबद्ध किया गया है। 20वीं शताब्दी से पूर्व डूँगरपुर राज्य में शिक्षा का अर्थ धर्म का ज्ञान एवं धर्मशास्त्रों की नैतिकता के पालन से सम्बन्धित था। शिक्षा का रूप वैश्विक नहीं लेकिन प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली से संगत रखता था। उस समय की शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेज अपने हितों के लिए परिवर्तन करना चाहते थे और अंतत: वे महारावलों को भी विभिन्न्ना तर्कों से अपने पक्ष में करने में सफल रहे।

भौगोलिक सरंचना – पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से पाठशालाओं और शिक्षण संस्थाओं की स्थापनाएँ समय पर नहीं हो पायी थी। गाँवों की बसावट भी बिखरी हुई थी जिसमें आवास अलग-अलग पहाड़ियों पर थे। वर्षाकाल में नदि-नाले पगडण्डियों और मार्गो का अवरूद्ध हो जाना सामान्य था और राज्य में जहाँ परम्परागत शिक्षा थी वहाँ से राज्य में अन्य स्थल तक उसका आदान-प्रदान नहीं था। अत: एक जैसी शिक्षा का विस्तार की योजना बनाना उस समय असंभव था।[1]

पाठशालाएँ – डूँगरपुर राज्य में परंपरागत पाठशालाओं का ही चलन था। सैद्धान्तिक ज्ञान प्रदान करने में इनका विशेष महत्व था। शिक्षा के केन्द्र प्राय: धाार्मिक- स्थल जैसे उपासरा, मठ, मंदिर, मस्जिद आदि एवं धार्माधिकारियों के घर होते थे। उपासरों व मठों के छात्रों व आशार्थियों को साधाू-साधिवयों व यतियों द्वारा धर्म, दर्शन तथा नैतिक ज्ञान के अलावा प्रारंभिक गणित व भाषा ज्ञान की शिक्षा भी दी जाती थी। साधाुओं के चार्तुमासों के प्रवचन की श्रवण-परंपरा का लाभ प्रौढ़ लोग भी उठाते थे। वैसे तो उपासरों से विशेष रुप में जैन संप्रदाय सम्बद्ध था, लेकिन उनकी शिक्षा का लाभ सभी द्विज जातियाँ प्राप्त करती थी। इसके अतिरिक्त साधाुजन प्राचीन व उपयोगी हस्तलिखित ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ तैयार करते थे, जो उस समय की पुस्तक-लेखन परंपरा की तरफ हमारा धयान इंगित करती है। उस समय शिक्षा का आधार धर्म का पालन एवं जिविकोपार्जन ही था। अंग्रेजी शिक्षा राजाओं और राजघरानों तक ही सीमित थी।[2]

शिक्षा और जिविकोपार्जन – राज्य की सभी जातियाँ अपने जिविकोपार्जन के कौशल को सीखने को ही शिक्षा मानते थे। यह तथ्य सत्य है कि उस समय की कौशल आधारित परिवारिक शिक्षा रोजगारपरक थी। उस शिक्षा का एक ही ध्येय था कि किसी न किसी प्रकार से जिविकोपार्जन हो जावे। किसान की खेती, ब्राम्हण की जजमानी, लौहार और सुनार की कला और चर्म और निर्माण कार्य की जातियों के कौशल शिक्षा के पैमाने माने जाते थे। इसके अतिरिक्त भाषाओं की जानकारी नए आविष्कार संसार के देश और जनसंख्या और विशिष्ट विज्ञान का ज्ञान आधुनिक पाठशालाओं की उपलब्धता नहीं होने के कारण नहीं था।[3]

शासन के सहयोग का आभाव – महारावल फतेहसिंह (1790-1808) और महारावल जसवंत सिंह (1808-1845) परम्परागत शिक्षा प्रणाली के पक्षधर थे। महारावल दलपत सिंह ने भी इसी को आगे बढ़ाया। जब 1835 ई. में गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य लार्ड मैकाले ने आंग्ल-दल का समर्थन किया। 2 फरवरी, 1835 ई. को अपने महत्वपूर्ण स्मरण-पत्र में उसने लिखा कि 'सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिये, माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है।' मैकाले ने कहा कि 'भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है'। उपर्युक्त महारावलों ने इस तथ्य को अस्वीकार कर दिया। वे राज्य में चल रही परम्परागत शिक्षा प्रणाली से संतुष्ट थे। उनके अनुसार आधुनिक शिक्षा उनके शास्त्रों और उपनिषदों से पृथक और धार्मिक क्रियाओं से विमुख कर देने वाली थी। राज्य के सलाहकारों ने भी महारावलों को आधुनिक शिक्षा व्यवस्था और अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने के लिए उपयोगी सुझाव नहीं दिए और महारावलों की इच्छाशक्ति भी नहीं थी। वहीं उस समय उदयपुर में सज्जनसिंह और बड़ौदा के महाराजा ने 1881 से 1892 ई. तक प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया था।[4]

अंग्रेजों की शिक्षा नीतियाँ – बीसवीं शताब्दी के पूर्व अंग्रेजों की शिक्षा नीतियाँ कौशल और रोजगार परक नहीं थी। वे सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धी हेतु अपनी शिक्षा से उनके लिए अंग्रेजी भाषा को समझने वाले कर्मचारी बनाना नाहते थे। ब्रिटिश काल में शिक्षा में मिशनरियों का प्रवेश हुआ, इस काल में महत्वपूर्ण शिक्षा दस्तावेज में मैकाले का घोषणा पत्र 1835, वुड का घोषणा पत्र 1854, हण्टर आयोग 1882 सम्मिलित हैं। इस काल में शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजों के राज्य के शासन सम्बन्धी हितों को धयान में रखकर बनाया गया था।[5]

प्राय: लोग इसे मैकाले की शिक्षा प्रणाली के नाम से पुकारते हैं। लार्ड मैकाले ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के ऊपरी सदन (हाउस आफ लार्ड्स) का सदस्य था। 1857 ई. की क्रान्ति के बाद जब 1860 ई. में भारत के शासन को ईस्ट इण्डिया कम्पनी से छीनकर रानी विक्टोरिया के अधीन किया गया तब मैकाले को भारत में अंग्रेजों के शासन को मजबूत बनाने के लिये आवश्यक नीतियां सुझाने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। उसने सारे देश का भ्रमण किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यहां झाड़ू देने वाला, चमड़ा उतारने वाला, करघा चलाने वाला, कृषक, व्यापारी (वैश्य), मंत्र पढ़ने वाला आदि सभी वर्ण के लोग अपने-अपने कर्म को बड़ी श्रद्धा से हंसते-गाते कर रहे थे। सारा समाज संबंधाों की डोर से बंधा हुआ था। शूद्र भी समाज में किसी का भाई, चाचा या दादा था तथा ब्राहमण भी ऐसे ही रिश्तों से बंधाा था। बेटी

* शोधार्थी (इतिहास एवं संस्कृति) जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड -टू-बी) विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

गाँव की हुआ करती थी तथा दामाद, मामा आदि रिश्ते गांव के हुआ करते थे। इस प्रकार भारतीय समाज भिन्नता के बीच भी एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। इस समय धार्मिक सम्प्रदायों के बीच भी सौहार्दपूर्ण संबंधा था। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि 1857 ई. की क्रान्ति में हिन्दू–मुसलमान दोनों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया था। मैकाले को लगा कि जब तक हिन्दू–मुसलमानों के बीच वैमनस्यता नहीं होगी तथा वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित समाज की एकता नहीं टूटेगी तब तक भारत पर अंग्रेजों का शासन मजबूत नहीं होगा। भारतीय समाज की एकता को नष्ट करने तथा वर्णाश्रित कर्म के प्रति घृणा उत्पन्न करने के लिए मैकाले ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली को बनाया।

अंग्रेजों की इस शिक्षा नीति का लक्ष्य था – संस्कृत, फारसी तथा लोक भाषाओं के वर्चस्व को तोड़कर अंग्रेजी का वर्चस्व कायम करना। साथ ही सरकार चलाने के लिए देशी अंग्रेजों को तैयार करना। इस प्रणाली के जरिए वंशानुगत कर्म के प्रति घृणा पैदा करने और परस्पर विद्वेष फैलाने की भी कोशिश की गई थी। इसके अलावा पश्चिमी सभ्यता एवं जीवन पद्धति के प्रति आकर्षण पैदा करना भी मैकाले का लक्ष्य था। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में ईसाई मिशनरियों ने भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईसाई मिशनरियों ने ही सर्वप्रथम मैकाले की शिक्षा–नीति को लागू किया।[6] मिशनरियों ने प्रमुखता से डूँगरपुर राज्य के आदिवासियों को भी धर्म परिवर्तन करने पर विवश कर दिया था। अंग्रेजों की इस प्रकार की नीति भी डूँगरपुर राज्य में शिक्षा के पीछड़ेपन का कारण बनी।

अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली – डूँगरपुर राज्य अंग्रेजी शिक्षा में इस काल में पिछड़ा था। यदि समीपस्थ राज्य मेवाड़ में अंग्रेजी शिक्षा की स्थिति की तुलना करे तो मेवाड़ी सामंतों व जन–साधारण के विरोधा के बावजूद भी यहाँ के राणाओं ने व्यक्तिगत प्रयास किये जो डूँगरपुर के रावल नहीं कर सके। फलत: उदयपुर नगर में स्थित कई धार्मार्थ पाठशालाओं को मिलाकर राणा शंभुसिंह व उनके गुरु रत्नेश्वर के नाम पर शंभु–रत्न पाठशाला की नींव रखी गई। इस पाठशाला में प्रारंभिक गणित, हिंदी, उर्दू, फारसी तथा संस्कृत की शिक्षा प्रदान की जाने लगी। 1864 ई. में यहाँ अंग्रेजी भाषा का विषय पढ़ाना प्रारंभ किया गया। बाद में 1873 ई. में इसमें दो विभाग स्थापित किये गये। अंग्रेजी प्राइमरी स्कूल को अलग कर, हिंदी प्राइमरी स्कूल को इसका ब्रांच बना दिया गया। 1885 ई. में इसका नाम महाराणा हाई–स्कूल रख दिया गया तथा इसी साल संस्कृत का अलग से विभाग भी खोला गया।

1873 ई. में भीलवाड़ा तथा चित्तौड़ में हिंदी–प्राथमिक पाठशाला प्रारंभ की गई। इसके अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्र में जैसे कोटड़ा (1875 ई.) जावर (1883 ई.) ऋषभदेव (1883 ई.) के भी स्कूल खोले गये। इसी प्रकार 1900 ई. तक राज्य के खालसा प्रदेश में प्रत्येक बृहत–ग्राम में प्राथमिक पाठशालाएँ राज्य द्वारा चलाई जाती थी और अजमेर में मेयो कॉलेज और महिला शिक्षा हेतु सोफिया कॉलेज की स्थापना हो चुकी थी।

सामाजिक कुरीतियाँ – डूँगरपुर राज्य की सामाजिक व्यवस्था दयनीय थी। समाज में सबसे निम्न स्थिति स्त्रियों की थी। बालिका का जन्म अपशकुन, उसका विवाह बोझ एवं वैधाव्य श्राप समझा जाता था। विशेषकर राजपूतों में जन्म के पश्चात बालिकाओं की हत्या कर दी जाती थी। कालांतर में रावल उदयसिंह ने बालिका वध पर रोक लगाई। स्त्रियों का वैवाहिक जीवन अत्यंत दयनीय एवं संघर्षपूर्ण था। यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे बलपूर्वक पति की चिता में जलने को बाधय किया जाता था। इसे 'सती प्रथा' के नाम से जाना जाता था। राजा राममोहन राय ने इसे शास्त्र की आड़ में हत्या की संज्ञा दी। सौभाग्यवश यदि कोई स्त्री इस क्रूर प्रथा से बच जाती थी तो उसे शेष जीवन अपमान, तिरस्कार, उत्पीड़न एवं दुख में बिताने पर बाधय होना पड़ता था। इस प्रकार की महिलाओं को शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं था। अत: आम स्त्री हेतु शिक्षा व्यवस्था न होने से परिवार में भी शिक्षा का वातावरण नहीं बन पाता था जिससे बींसवीं शताब्दी से पूर्व डूँगरपुर राज्य शिक्षा में अन्य राज्यों से पिछड़ा था।

वर्णव्यवस्था – डूँगरपुर राज्य में भी चतुवर्ण व्यवस्था के अनुसार, जाति ही किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती थी। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं शुद्धता की पुष्टि उसकी जाति के द्वारा होती थी। जाति ही निर्धारित करती थी कि किसे शिक्षा ग्रहण करने एवं सम्पत्ति रखने का अधिकार है, किसे, कौन सा व्यवसाय अपनाना चाहिये तथा किसे, किस से वैवाहिक संबंधा स्थापित करने चाहिए। किसी व्यक्ति के पूर्वजन्म के कर्मो का आकलन भी इसी बात से किया जाता था कि इस जन्म में वह किस जाति में पैदा हुआ है। परिधाान, खान–पान, वास स्थान, कृषि एवं पीने के पानी का स्रोत तथा मंदिर में प्रवेश के अधिकार जैसे मुद्दों का निर्धारण भी जाति के द्वारा ही होते थे। इस चतुर्वर्ण व्यवस्था का सबसे निंदनीय पहलू था समाज में अश्पृश्यता या छुआछूत की भावना का जन्म। जो लोग निम्न जाति में पैदा होते थे उन्हें अछूत समझा जाता था। उन्हें सामान्यत: गाँवों से दूर बसाया जाता था तथा उनके मंदिरों में प्रवेश करने पर पाबंदी थी। इस वर्ग के लोग अनेक प्रकार के उत्पीड़न एवं भेदभाव के शिकार थे। अत: बीसवीं शताब्दी में डूँगरपुर राज्य में शिक्षा के पिछड़ेपन का कारण वर्णव्यवस्था भी थी।

उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि 20वीं शताब्दी से पूर्व डूँगरपुर राज्य में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का धर्म एवं परम्पराओं से सामाजीकरण करना, जीवन–धर्म समझाना, मानव–व्यवहार सिखलाना तथा आर्थिकोपार्जन था। आंग्ल शिक्षा पद्धति ने शिक्षा द्वारा अंग्रेजी में कुशल कार्मिक पैदा करने का काम प्रारम्भ कर दिया था। अंग्रेजों द्वारा इस प्रक्रिया को डूँगरपुर में शासन और प्रशासन के साधान के रुप में विकसित करने का असफल प्रयास किया। बीसवीं शताब्दी से पूर्व शिक्षा के विकसित होने और पिछड़ेपन को स्पष्ट कर पाना आसान कार्य नहीं है। शिक्षा के बेहतर होने एवं पिछड़े होने के कोई शोधित मापक उपलब्ध नहीं है। मात्र तर्क एवं तुलना के आधार पर डूँगरपुर राज्य में बीसवीं शताब्दी से पूर्व शिक्षा की स्थिति को बताने का प्रयास किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. एल.आर. भल्ला – राजस्थान का भूगोल, कुलदीप पब्लिकेशन्स, 1998, पृ. 93
2. नरूला एण्ड नायक – भारत में शिक्षा का इतिहास, 1951, पृ.स.43
3. डूँगरपुर एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1888 पैरा–5
4. डूँगरपुर एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1891 पैरा–3
5. शर्मा गिरिजाशंकर – राजस्थान में शिक्षा का इतिहास, कलासन प्रकाशन, अजमेर
6. शर्मा दशरथ – राजस्थान थ्रूदी एजेज पार्ट(फर्स्ट), पृ.स. 73

****

गौतम बुद्ध के दार्शनिक व शैक्षिक विचारों की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता

सुरेन्द्र प्रताप सिंह खरे *

शोध सारांश – शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है कोई समाज इसकी व्यवस्था अपने उद्देशों की प्राप्ति के लिए करता है जिससे यह पता चलता है कि किसी समाज की शिक्षा उसकी तात्कालीन परिस्थितियों एवं उसके भविष्य की आकांक्षाओं के अनुकूल होती है वौद्ध कालीन शिक्षा संसार की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली में से थी महात्मा बुद्ध के दार्शनिक व शैक्षिक विचारों की प्रासंगिता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है महात्मा बुद्ध द्धारा दिये गये विचारों का यदि सच्ची निष्ठा से पालन किया जाये तो हम सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते है। महात्मा बुद्ध के सत्य, अहिंसा, अष्टांगिक मार्ग तथा मध्यम मार्ग के सिद्धान्त वर्तमान समय में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गये है इनका अनुपालन करके समाज, देश तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शान्ति, सामाजिक सद्भाव व विश्व बन्धुत्व लाया जा सकता है।

प्रस्तावना – बौद्ध धर्म के दार्शनिक एवं शैक्षिक विचार आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक व नैतिक, राजनीतिक, शैक्षिक, पर्यावरणीय सभी दृष्ठिकोणों को बौद्ध धर्म के दार्शनिक व शैक्षिक विचारों ने प्रभावित किया। महात्मा बुद्ध के अनुसार शिक्षा के प्रसार से व्यक्ति को आत्म ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा अविद्या या अज्ञान का नाश हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति से व्यक्ति आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है।

बौद्ध धर्म के दार्शनिक व शैक्षिक विचारों की प्रांसगिकता तत्कालीन समाज से लेकर वर्तमान समय के समाज तक निर्विवाद रूप से स्पष्ट है। सामाजिक रूप से विभक्त तत्कालीन समाज को बौद्ध धर्म ने एकता के सूत्र में बाँधने का काम किया। तत्कालीन समाज परम्परागत रूप से चार वर्णो यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभक्त था। समाज में ऊँच–नीच, छुआ–छूत जाति प्रथा स्पृश्यता, पशुबलि, आदि कुप्रथायें व्याप्त थी। भगवान बुद्ध ने उपरोक्त कुप्रथाओं का विरोध किया तथा मानव मात्र की समानता का संदेश दिया उन्होंने वर्णव्यवस्था का खण्डन किया तथा कहा कि यथार्थ जीवन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र इन चारों वर्णो की सृष्टि मानव निर्मित है। भगवान बुद्ध का कहना था कि– 'केवल ब्राह्मण ही स्वर्ग भोग के पात्र नहीं होते वरन् अपने पवित्र कर्मो द्धारा अन्य वर्णो के लोग भी स्वर्ग–सुख के सुयोग्य पात्र हो सकते है।' महात्मा बुद्ध मानव जाति की समानता के अनन्य पोषक थे। यही कारण था कि संघ का द्धार सभी जातियों के लिए खुला रखा था। महात्मा बुद्ध के उपरोक्त विचारों को वर्तमान समय में भी महत्व दिया जाता है। सम्राट अशोक से लेकर महात्मा गाँधी, डॉ0 अम्बेडकर, श्री नारायण गुरू आदि महापुरूषों ने बौद्ध दर्शन से प्रभावित होकर मानव मात्र की समानता के लिए विभिन्न आन्दोलन किया तथा भारतीय संविधान में समानता का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया साथ ही अस्पृश्यता का अंत किया गया। बौद्ध धर्म के सामाजिक पहलू की प्रासंगिकता आगे आने वाले समय में भी बनी रहेगी। बौद्ध धर्म के विचारों का अनुशीलन कर सामाजिक समरसता स्थापित की जा सकती है।

धार्मिक दृष्टि से बौद्ध धर्म का योगदान अविस्मरणीय है। गौतम बुद्ध ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया उसका आदर्श **'मानवता का कल्याण'** था। महात्मा बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया वह भिक्षु धर्म से भिन्न उपासक धर्म था। बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म के प्रमुख लक्षण अहिंसा, प्राणियों पर दया, सत्यवचन, माता–पिता की सेवा, गुरूजनों की सेवा व सम्मान, ब्राह्मणों–श्रमणों को दान, मित्रों परिचितों सम्बन्धियों आदि के साथ अच्छा वर्ताव करना, इत्यादि बताये गये है। ये बाते सभी धर्मो में समान रूप से श्रद्धेय मानी जाती है। महात्मा बुद्ध द्धारा बताये गये धर्म के प्रमुख लक्षण वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है तथा ये लक्षण सभी धर्मों में व्याप्त है, परन्तु वर्तमान भौतिकतावादी युग में अपनी स्वार्थवादी नीतियें के चलते व्यक्ति धर्म से विमुख हो गये है या कहें कि धर्म भी अपने लक्ष्य की पूर्ति करने में असफल हो रहा है। वर्तमान समय में व्याप्त धार्मिक व साम्प्रदायिक भेदभाव, तनाव, वैमनस्य आदि इसी धार्मिक भटकाव के परिणाम है। महात्मा बुद्ध ने जिस मानवतावादी धर्म का प्रतिपादन कर बौद्ध धर्म को कालान्तर में विश्वधर्म बने का गौरव प्रदान किया, आज यदि हम धार्मिक मतभेदों को भुलाकर इस मानवतावादी धर्म के सिद्धान्तों पर अमल करें तो विश्व में धार्मिक समरसता तथा विश्व बंधुत्व की भावना स्थापित की जा सकती है।

आध्यात्मिक तथा नैतिक दृष्टि से बौद्ध धर्म के दार्शनिक तथा शैक्षिक विचार आज भी प्रासंगिक है। महात्मा बुद्ध जटिल दार्शनिक समस्याओं में कभी उलझे नहीं तथा एक नैतिक दार्शनिक के रूप में उन्होंने मनुष्य के नैतिक व सामाजिक गुणों के विकास पर ही बल दिया उनकी दृष्टि में ज्ञान तथा नैतिकता (शील) दोनों ही महत्वपूर्ण है, परन्तु नैतिकता ज्ञान से सर्वोच्च है क्योंकि वही ज्ञान प्राप्ति का साधन है। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सदाचार, सत्य वचन, निर्व्यसन आदि ऐसे तत्व है जिनका अनुपालन करने से व्यक्ति आध्यात्मिक व नैतिक दृष्टि से सृदढ़ बना है। महात्मा बुद्ध द्धारा बताये गये नैतिकता के नियम व आष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके मनुष्य न केवल दु:खों से निवृत्ति पा सकता है, समाज में चतुर्दिक सुख शान्ति समृद्धि तथा सदाचार की स्थापना की जा सकती है। बौद्ध धर्म में प्रतिपादित नैतिकता (शील) के सिद्धान्त वर्तमान समय में अत्यधिक प्रासंगिक है। आज का समाज तथा मानव चोरी, लालच, व्यभिचार, घृणा, द्धेष, ईर्ष्या, व्यसन, मिथ्यावचन, भौतिकतावाद व पाश्चात्य संस्कृति से इस तरह घिर गया है

* शोधार्थी (इतिहास) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

कि समाज व व्यक्ति नैतिक पतन की दिशा में अग्रसर होता जा रहा है। व्यक्ति, व्यक्ति का ही दुश्मन बना हुआ है। अत: आज आवश्यकता है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिये गये शील सम्बन्धी नियमों का छात्रों तथा समाज के लोगों को बोध कराया जाय ताकि इससे सीख लेकर अपना तथा समाज का नैतिक उत्थान करने में सक्षम हो सकें, और एक ऐसे समाज का निर्माण हो जो सभी तरह के दुर्गुणों से मुक्त नैतिक समाज हो।

बौद्ध धर्म के दार्शनिक व शैक्षिक विचार राजनीतिक क्षेत्र को भी प्रभावित करते आये है तथा इसकी प्रासंगिकता आने वाले समय में भी रहेगी। बौद्ध धर्म का उदय ऐसे समय में हुआ है जब तलवार ही शक्ति का निर्धारण करती थी देश अनकों छोटे-छोटे राज्य में विभक्त था। एक राजा दूसरे राज्य से अपनी सीमा विस्तार हेतु संघर्षरत था। ऐसे समय में महात्मा बुद्ध द्वारा मानवता के लिए दिया गया संदेश कि **'जिओं और जीने दो' 'अहिंसा परमो धर्म:'** विश्वबंधुत्व की भावना आदि राजनीतिक रूप से विभक्त देश को एकता के सूत्र में बाँधने का काम किया। महात्मा बुद्ध के अहिंसा तथा विश्वबंधुत्व की अवधारणा को अशोक जैसा महत्वकांक्षी सम्राट अपनाकर इतिहास में अशोक महान् के नाम से जाना गया। सम्राट अशोक ने भेरीधोष के स्थान पर धम्मघोष के मार्ग का अनुसरण किया तथा अपने साम्राज्य में पशुबलि, युद्ध अभियान आदि को त्याग कर अपना बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में लगाया तथा इसे विश्व धर्म बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान प्रणेता महात्मा गाँधी ने **बौद्ध धर्म के सत्य व अहिंसा का प्रयोग करके** अंग्रेजों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। **पं0 जवाहर लाल नेहरू** ने बौद्ध के **पंचशील सिद्धान्त** को अपनाकर चीन के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार की स्थापना की। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध धर्म के अहिंसा व सहअस्तित्व की भावना से प्रभावित होकर अन्तराष्ट्रीय शांति-समझौते हो रहे है। यदि बौद्ध धर्म के आदर्शो, मूल्यों सिद्धान्तों का सच्ची निष्ठा से पालन किया जाय तो विश्व आतंकवाद रूपी दानव से मुक्ति पा सकता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव व विश्व बन्धुत्व की कल्पना साकार हो सकती है।

शिक्षा के सम्बन्ध में भी बौद्ध धर्म के विचार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में आधुनिक शिक्षा के लक्षण दिखायी देते है। बौद्ध शिक्षा का द्वार सभी जाति वर्ग के लिए खुला था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली जनतंत्रीय शिक्षा व्यवस्था पर आधारित थी। जहाँ प्राचीन शिक्षा व्यवस्था केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित थी वहीं बौद्ध शिक्षा सर्वसाधारण के लिए सुलभ थी। शिक्षा व्यवस्था नि:शुल्क थी। विद्यार्थियों को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी ताकि छात्र भावी जीवन के लिए अपने को तैयार कर सके। बौद्ध धर्म की उपरोक्त शैक्षिक विशेषता वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में भी दृष्टिगत होती है। आज सरकार की तरफ से नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी संचालित किये जा रहे है। शैक्षिक पाठ्यक्रम में विभिन्न महापुरूषों, क्रान्तिकारियों आदि को शामिल कर विद्यार्थी में तद्रूप गुणों के विकास पर बल दिया जा रहा है। शिक्षा में योग को शामिल कर विद्यार्थियों के सर्वागीण विकास पर बल दिया जा रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है के बौद्ध शिक्षा व्यवस्था की झलक वर्तमान समय की शिक्षा व्यवस्था में भी दिखायी देती है।

उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध के दार्शनिक व शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिये गये विचारों का यदि सच्ची निष्ठा से पालन किया जाय तो सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते है। महात्मा बुद्ध के सत्य, अहिंसा, आष्टांगिक मार्ग तथा मध्य मार्ग के सिद्धान्त वर्तमान समय में अत्यधिक महात्वपूर्ण हो गये है। इनका अनुपालन करके समाज देश तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, सामाजिक सदभाव व विश्व बंधुत्व लाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मिश्र डॉ0 जयशंकर- प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास- बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी पटना पृष्ठ 841
2. पाण्डेय डॉ0 राजवली- प्राचीन भारत- विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी 2010, पृष्ठ 125
3. झा द्विजेन्द्रनारायण, श्रीमाली- कृष्णमोहन- प्राचीन भारत का इतिहास- हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय 2006, पृष्ठ 156
4. दिनकर रामाधारी सिंह- संस्कृति के चार अध्याय- लोकभारती प्रकाशन पटना 2008, पृष्ठ 205
5. पाण्डेय विमल चन्द्र- प्राचीन भारत का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास भाग 1- सेन्ट्रल पब्लिशिंग हाउस इलाहाबाद 2011, पृष्ठ 201
6. श्रीवास्तव डॉ0 कृष्णचन्द्र- प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति- यूनाइटेड बुक डिपो इलाहाबाद 2012, पृष्ठ 795
7. पाण्डेय, गोविन्दचन्द्र- बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास- उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 2004 पृष्ठ 120
8. वाशम डॉ0 ऐ0एल0- अद्भुद भारत- शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी आगरा
9. सिंह डॉ0 मदन मोहन- बुद्धकालीन समाज और धर्म- हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय 1999 पृष्ठ 121

****

मुगलकालीन भारतीय सांस्कृतिक परिवेश को जानने के स्त्रोत

डॉ. सुनीता शुक्ला *

प्रस्तावना – विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था कि'इतिहास ग्रन्थों मे प्राप्त भारतवर्ष का इतिहास एक दु:स्वप्न मात्र है जो निरंतर बदलते रहने वाले रक्तरंजित स्वप्न के दृश्य पर से ढका हुआ है। उसमें भारत के यथार्थ इतिहास के दर्शन नहीं मिलतें।' सुप्रसिद्ध विद्वान डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल ने भी लिखा है कि 'सारे मध्यकाल मे हिन्दू संस्कृति का तेजस्वी सूर्य इस्लामी घटाटोप के बावजूद तपता हुआ दिखाई पड़ता है।

'भारत मे मुगल साम्राज्य का इतिहास हमारा परिश्रमसाध्य किन्तु प्रामाणिक रहा है। तत्कालीन इतिहासज्ञों के ग्रन्थों के पन्नों की छान-बीन करके हमने ऐसी घटनाओं का संग्रह किया है जिनके आधार पर हम उचित व्यापक कथनों का प्रतिपादन कर सकते हैं।'[1]

घटनाऍ एक प्रकार की ईटें है जिन पर तर्क के द्धारा ज्ञान रूपी भवन खड़ा किया जा सकता है।[2] संक्षेप मे यह माना जाता है कि इतिहास अध्ययन का कोई अलग विषय नहीं है बल्कि समाज के सामान्य विज्ञान की रचना करने वाले परस्पर सम्बन्धित अध्ययनों में से एक है।[3]

मुगलकाल मे अनेक ऐतिहासिक ग्रन्थ लिखे गये है। परन्तु इन ग्रन्थों मे सबसे अधिक न्यूनता सांस्कृतिक दशा के वर्णन की है। अब प्रश्न उठता है कि वे कौन से साधन हैं जिनके द्धारा हम 'मुगलकालीन भारत का सांस्कृतिक परिवेश' का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

1. **ऐतिहासिक अभिलेख –** मुगलकाल मे अनेक ऐतिहासिक ग्रन्थों की रचना की गई है। इन ग्रन्थों मे बाबर द्धारा रचित 'तुजुक-ए-बाबरी' का नाम विशेष उल्लेखनीय है। तुर्क मे लिखी गई बाबर की आत्मकथा का अब्दुल रहीम खानखाना ने फारसी मे अनुवाद किया है। इस ग्रन्थ का श्रेष्ठतम अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती बेवरीज का है। इसमें बाबर ने भारत की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक दशा का वर्णन किया है। डॉ. आशीवार्दी लाल श्रीवास्तव लिखते हैं कि 'बाबरनामा पढ़ने से पता चलता है कि प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति उसका कितना अगाध प्रेम और विकट आकर्षण था, तथा मानवीय गुण-गरिमा और दोष दुर्बलता से उसका चरित्र निर्मित था। यह पुस्तक का युग के इतिहास का प्रमाणिक ग्रन्थ है।'[4]

हुमायूँनामा – हुमायू (1530-40), (1545-56) की बहन गुलबदन बेगम ने 'हुमायूँनामा' नामक ग्रन्थ की रचना की है। इसमें हुमायू के शासनकाल की गतिविधियों का वर्णन है। अभिलेखों मे से ख्वामादीर का 'हुमायूँनामा' भी एक मनोरंजक दस्तावेज है। अपने इस अन्तिम ग्रन्थ को उस प्रसिद्ध इतिहासकार ने मुगल सम्राट हुमायूॅ के विशेष आग्रह पर 1534 ई. (941 हि.) के प्रारंभ मे लिखा था। सम्राट द्धारा प्रवर्तित नवीन युक्तियों और अनूठे रचना कौशल का उल्लेख इसकी विशेषताऍ हैं।[5]

तारीख-ए-शेरशाही – 'तारीख-ए-शेरशाही', 'तारीख-ए-दाउदी' और 'वाकयात-ए-मुश्ताकी' मे सामाजिक एवं आर्थिक दशा का पर्याप्त चित्रण है। 'तारीख-ए-शेरशाही' ऐसे अनेक लोगों की जीवनियों के सतर्क संकलन के लिए प्रसिद्ध है जो उस समय जीवित थे और जो उन दृश्यों के सक्रिय भागीदार थे और तदन्तर जिन्होने अपने अनुभव लेखक को सुनाए, जिसने आवश्यक सावधानी और परीक्षण के पश्चात् उन्हें संकलित किया।[6] 'तारीख-ए-दाउदी' खण्डित और बिजरी है और असम्बद्ध संस्मरणों से कुछ अधिक नहीं है। इसी तरह' वाकयात-ए-मुश्ताकी' क्रमबद्ध नहीं है और उसमें लम्बे विषयान्तर हैं। दोनो ग्रन्थ कौतुकों तथा अन्धविश्वासों से परिपूर्ण हैं, विशेषत: वाक्यात में तत्कालीन प्रसिद्ध सरदारों और सन्तों के उपाख्यानों, चमत्कारों, प्रेतों, दानवों जादू और बाजीगरी की मुर्खतापूर्ण कहानियों की खिचड़ी कृति को कुरूप कर देती है और इन सबसे लेखक की ओर उसके काल के अन्धविश्वास की प्रवृत्ति प्रकट होती है।[7]

आइन-ए-अकबरी – मुगलकाल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ अबुलफजल कृत्तआइन-ए-अकबरी' है। 'ब्लोचमैन' तथा जेरटे ने इसका अनुवाद किया है। 'आइन-ए-अकबरी' सामाजिक इतिहास का स्मारक है किन्तु उसका महत्व मुख्यत: उन विभिन्न विकासों को लेख बंद करने मे है जो अकबर के शासनकाल तक सम्पन्न हुये थे, जबकि महान मुगल सम्राट ने सूत्र अपने हाथ मे लेकर सामाजिक प्रगति के कार्य को एक कदम आगे बढ़ाया लेखक ने दावा किया है कि उसने कृति का संकलन विश्वकोष के तरीके पर किया है, जहॉ सब तरह की उपयोगी सूचना मिलेगी और जिसकी सहायता लोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सन्दर्भ, अनुदेश और मनोरंजन के लिए लेगें।[8]

'प्रथम वार सजीव लोग हमारे समक्ष चलते-फिरते दिखाई देते हैं और उस समय के महान प्रश्न, बहुविश्वसनीय तत्कालीन स्वयंसिद्ध तथ्य, अनुकरणीय सिद्धांत, और बहुविश्वासनीय प्रेत हमारी ऑखों के सम्मुख सच्चे और सजीव रंगों मे प्रस्तुत किये गये हैं।'[9] आइन-ए-अकबरी के विषय मे अबुल फजल लिखते हैं कि 'अपनी पुस्तक मे वर्णित ऐसे प्रत्येक विषय के लिये उसने पूर्ण सर्तकता से बीस ज्ञापन तैयार किये और सावधानी पूर्ण तुलना और परीक्षण के पश्चात् अपनी पुस्तकों में उन तथ्यों का संकलन किया।[10]

आएन-ए-अकबरी की आलोचना – श्री डब्ल्यु कुक लिखते हैं 'जो कोई भी अकबर के शासन के विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रन्थ आइन-ए-अकबरी को पढ़ता है, उनमें से किसी भी विभागीय स्वरूप के किसी अभाव को समझने मे असफल नहीं हो सकता है। अकबर विस्तार का स्वामी था, किन्तु यहॉ इस विस्तार को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा दिया गया है। इसमें हमें शिविर एवं राज्य परिवार, अस्तबल तथा बंदीखानों, शस्त्र और आखेट विभाग के संगठन का वास्तविक विवरण मिलता है। दूसरी और जैसा कि हम समझते है, शासन

* प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

की आवश्यक बातें अर्थात् पुलिस तथा न्याय कार्य, राष्ट्रीय साधनों, अकाल के समय की सहायता, शिक्षा तथा चिकित्सीय सहायता के सम्बन्ध मे कुछ भी जानकारी नहीं हो पाती है।[11]

आइन-ए-अकबरी मे दिये हुये अंकों पर कितना विश्वास किया जाये, कहना कठिन है............। आइन-ए-अकबरी मे उल्लिखित मालगुजारी के सम्बन्ध मे यह प्रश्न हो सकता है कि क्या यह एक प्राक्कलन न था और क्या यह कभी भी राज्य के लिये वसूल की गई थी।[12]

मुगल कालीन अन्य ग्रन्थ - मुगल काल के सांस्कृतिक परिवेश क विशद अध्ययन के लिए निम्न अन्य ग्रन्थ भी महत्वपूर्ण है -

1. मुल्ला दाउद कृत-तारीखे अल्खी
2. अब्दुल बकी कृत- मासीर-ए-रहीमी
3. अब्दुल कादिर बदायूनी का मुन्तखन-उत-तवारीख
4. निजामुद्दीन अहमद कृत-तत्कात-ए-नासिरी
5. मिर्जा मोहम्मद कासिम का-आलमगीरनामा
6. अब्दुल हमीद का-पादशाहनामा
7. हनायत खॉ का शाहजहॉनामा
8. इलियट और डाउसन का भारत का इतिहास

निष्कर्ष -

1. मुगलकालीन भारत के सांस्कृतिक परिवेश को जानने के साधन अति अल्प मात्रा मे है।
2. अधिकांश लेखक मुगल बादशाहों के जीवन विलासिता, दरबारी वातावरण का वर्णन करते है।
3. प्राप्त साधनों से सबसे न्यून जानकारी सांस्कृतिक इतिहास की है।
4. मुगल काल के सांस्कृतिक परिवेश की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का स्त्रोत अबुल फजल कृत-आइन-ए-अकबरी है।
5. अन्य स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी अत्यधिक न्यून है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. एस.आर.शर्मा-भारत मे मुगल साम्राज्य, द्वितीय संस्करण 1965, पृ. 767.
2. पीगू-मेमोरियल्स ऑफ आल्फ्रैड मार्शल, पृ.86, मैकमिलन, सन् 1925.
3. हर्नशा, आर्ट-'साइंस ऑफ हिस्ट्री' आउट लाइन ऑफ मार्डन नोलेज, पृ.809
4. आर्शीवादी लाल श्रीवास्तव-भारत का इतिहास -चतुर्थ संस्करण, पृ. 325.
5. संवाद, 125.
6. अब्बास खॉ शेरवानी कृत- तारीख-ए-शेरशाही, 3.
7. इलियट और डाउसन, चतुर्थ संस्करण-537 अफगानों का और अधिक सम्बद्ध वर्णन 1613 मे नियामतुल्ला द्वारा संकलित ग्रन्थ 'मखजन-ए-अफगानी' में मिलता है।
8. के.एम.अशरफ-हिन्दुस्तान के निवासियों का जीवन और उनकी परिस्थितियॉ अनुवादक डॉ.के.एस. लाल. पृ. 12-13.
9. आइन-ए-अकबरी-अबुल फजल कृत, तृतीय संस्करण, पृ.282 'यह विभिन्न तरह के ज्ञान का भण्डार है। चतुर और कुशल विद्वान इसकी सहायता ले सकते है, और यहॉ तक कि विदूषक और ढॉगी जन भी इससे लाभ उठा सकते है, बालवन्द के लिए यह मनोरंजन का श्रोत हो सकता है और प्रौढ़ तथा परिपक्व लोगों के लिए सूचना भण्डार का काम दे सकता है। बुजुर्ग इसमें युगयुगीन परिपर्व ज्ञान और आभिजात्य पायेगें और सद्गुणी लोग इसमें सद्व्यवहार की संहिता पायेगें।
10. आइन-ए-अकबरी, अंग्रेजी-अनुवाद, प्रथम, भूमिका, पंचम।
11. आइन-ए-अकबरी, द्वितीय, 252.
12. एन.डब्ल्यू.पी. पृ.101-102.
13. जे.आर.रीड

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

Impact Of Tea Production On The Economic And Geographical Scenario Of Kumaon Mandal (Uttarakhand) 'A Brief Study From Kausani (Bageshwar)'

Manoj Kumar Tamta* Dr. Jyoti Joshi**

Abstract - Himalyala region is the very sensitive for the agricultural and land use activities. Increasement of waste land and degradiation are the biggest problem in these Himalayan region. While the other hand there are much unemployment and migration of developing hill areas. Natural hazards of Himalayan region also take important place where the landforms are having agriculture land as the land use. The some modern technology to rural and hill area development specifically plantation of commercial crop such as tea, development of cultivable waste land, the groundwater use etc. after the half of the nineteenth century plantations have been adopted by Indian sub contitant such humans as crawling out of the agricultural place. For the reduce of wasteland and unemployment in himalyan region Tea plantation can be the batter choice. Tea plantation is suitable for the hill state due to its particular climatic conditions. Tea is the most demandable liquid after water. Therefore the tea is known as a national liquid of India.

Introduction - Migration from rural areas (particularly hills) to urban areas inside the country, the rate of migration has been a lot of higher. In Uttarakhand hill state inside the nine hill districts and is growing hastily. Population in Pauri Garhwal and Almora districts has declined due to migration. Between 2001 and 2011, the districts registered decadal populace boom charges of -1.41 percent and -1.28 percent respectively (senses 2011). Inadequate education and fitness centers and shortage of employment alternatives to farming. Uttarakhand is commonly an agricultural state although its share within the total region and manufacturing may be very small. Lack of employment opportunities, no innovation in agriculture, absence of right training and clinical facilities, and developing water shortage have robbed the mountains in their citizens. Every day, busloads of human beings lock up their houses inside the Garhwal, Kumaon and Johar regions, in the low hills and the high mountains, and are available to the cities inside the plains searching for an less complicated lifestyles. According to the 2011 Census, nearly 1,100 villages in Uttarakhand have seen a decline in population, a few to a degree that their inhabitants can be counted on one hand. Waste land in Uttarakhand is 16097.46, 30% of total vicinity. More than 1,000 villages have been deserted for the seeking of job. Of the 13 districts of Uttarakhand, migration has hit nine hill districts over the last decade. According to latest census reports, two hill districts, Pauri and Almora, show a negative growth in population (In the case of Pauri 6,97,078 in 2001 to 6,86,527 in 2011 and in case of Almora 6,32,866 in 2001 to 6,21,927 in 2011). This type of terrible condition shown every hill district.

According to Census 2011, of Uttarakhand's 16,793 villages, 1,053 haven't any inhabitants and any other 405 have a population of much less than 10 faimilies. The range of such ghost villages has reportedly raised specially after affect the problem of employment, unproductivity of land and hazards. Hills and high mountains are the biggest part of this region. The state government's Annual Plan shows that the per capita income in the villages specially in hills is much lower than inside the plains. This does not mean that the employment generation and production capacity of the hill areas is low, but the production capacity of these areas is very high especially commercial plantation and fruits. Untended land turns barren or is protected with by means of resilient weeds and shrubs (such as Lantana and Parthenium) which might be very tough to clear. Such factors have triggered a perceptible decline in agriculture, productivity and wasteland. According to the Union Ministry of Agriculture, the net sown in area in the state has declined by using round 10 percent, from 769,944 (ha.) in 2000-01 to 701,030 (ha.) in 2013-14. Experts cite a few different purpose for the decline of farming within the region, extremely effective implementation of welfare schemes similar to the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) it works good in Himalayan areas but such works are not enough for the development of hill state.

In Uttarakhand, agricultural activities are mostly depends on rain, especially in hill areas. Irrigation facilities are very hard to find in hill and mountain areas. There may be very little in terms of irrigation infrastructure within the higher altitudes. Changing climatic conditions may also accelerate growing stages of migration. In Himalaya vicinity there are large trouble of migration, herbal disaster, waste land and unemployment. Tea production is a better option for the

*Research Scholar (Geography) S.S.J. campus Almora, Kumaoun University, Nainital (Uttarakhand) INDIA
**Asst. Professor (Geography) S.S.J. campus Almora, Kumaoun University, Nainital (Uttarakhand) INDIA

problem of employment and diversion. Especially for mountain areas such as Uttarakhand.

The study area - After the formation of Uttarakhand on 9th November 2000, the state is divided into two divisions: Garhwal and Kumaun mandal, 6 districts in Kumaon division, out of which 3 districts are 100% hilly, 2 districts Nainital and Champawat partly plain and 1 district Udham Singh Nagar 100% is plain. Kumaun division lies between 28° 51'N to 30° 49'N latitude and 77° 43'E to 81° 31'E longitude. Area of entire Kumaon division is about 21035 sq km. In kumaon mandal of uttarakhand Kausani is the most beautiful town, situated at the border of Bageshwar and Almora district, the total area of 5.2 sq. km, its altitude is 1890 meter above from the mean sea level, located 51 km north from Almora district headquarter, Kausani is the birthplace of famous Hindi poet Sumitra Nandan Pant also. The ***Latitude and Longitude of Kausani*** is 29.8431N and 79.6033E. (figure in last page, figure 3)

Methodology - The study has included both primary and secondary data collection. Detailed information has been collected through different sources (govt., non- govt. and personal contacts) and detailed field study.

Result and Disscussion - Like the other parts of India, there is a lot of problem of migrating and degradation in Kumaon area, Consequently, out-migration from Uttarakhand is one of the highest in the country. It has also been cited by researchers that almost every household in the villages of Kumaun districts have at least one family member leaving the state in search of work. Kumaon area is surrounded by the middle Himalayas and Shivalik ranges. There is immense potential for employment and production in this area. Tea is one of the most famous and lowest value crop inside the world and consumed via a huge variety of people. Owing to its increasing call for, tea is considered to be one of the primary additives of global beverage marketplace. Tea plant life are propagated from seed and slicing; it takes about 4 to twelve years for a tea plant to bear seed and approximately 3 years earlier than a brand new plant is ready for harvesting. Tea vegetation requires as a maximum 127 cm (50 inches) of rainfall a 12 months and prefer acidic soils (4.5-five.Five ph). Many excessive- pleasant tea plants are cultivated at elevations of up to at least one,500 m (4,900 ft) above sea degree. While at those heights the plants develop greater slowly, they gather a higher flavour. Today, India is certainly one of the most important tea manufacturers within the global, even though over 70 in step with cent of its tea is ate up inside India itself. In India tea become particularly increasing and traumatic crop. India is the biggest manufacturer and purchaser country of the world it will likely be proper to mention that tea is the National Drink of this kingdom. India has 11 % mountain of total landmass which has suitable atmospheric conditions to grown tea plants. There are three countries which can be producers of a number of the excellent best tea in the global. Tea from India, China and Sri Lanka are known world over for his or her flavour and taste in addition to their liquor. Kumaun Mandal is a very favorable area for the production of tea. There are immense possibilities of tea production in many areas like Champawat, Bageshwar, Almora, Nainital and Pithoragarh districts. The Kumaon division has immense potential for tea production. The capacity of production under various programs is given in the following tables. The first table 1.0 shows that Tea is being produced in different areas of Kumaon through Uttarakhand Tea Vikash Board, out of which there is a possibility of more production in Kausani and Garur region. Wherever average average production is 211 quintals per Kausani, its capacity can be more than 300 quintals. Similarly, there is the possibility of producing 375 qwintals in Garur. Which is more than 100% of the actual production. Similarly, Munasari and Dhauldevi area also have zero production While there is also the possibility of production in these areas. Table number 2 shows the features under MNERGA tea production where it is clear that the potential production is much higher than actual production. Many places like Kapkot, Nainital, dholadevi, Dhari, Ramnagar are 50 to 100% less in actual production.

Project under uttarakhand tea development board

Region	Actual Pro. In (kw.)	Potaintail Pro (kw.)
Champawat	160	200
Ghorakhal	191	200
Jaorasi	1.8	200
Kausani	211	375
Garur	141	375
Munsyari	00	100
Dhauladevi	00	100

Source- Uttarakhand tea Development board Almora Table 1

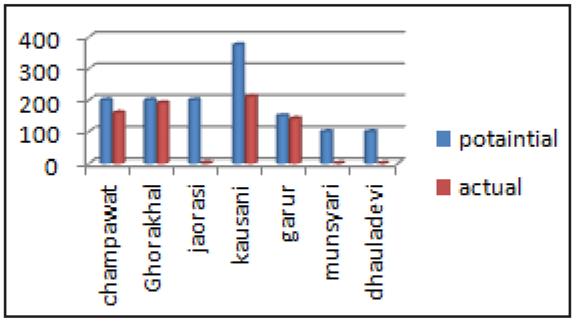

Figure- 1. tea production under Uttarakhand tea board

Project under the Mahatma Gandhai National Rural employment guaranty scheme in kumaun

Region	Actual Pro.	Potaintial Pro
Dhauladevi	32	60
Takula	18	60
Garur	25	100
Didihat	20	60
Nainital	6	100
Kapkot	0	60
Ramgarh	1	60
Dhari	1	60

Source- Uttarakhand tea development board Table-2

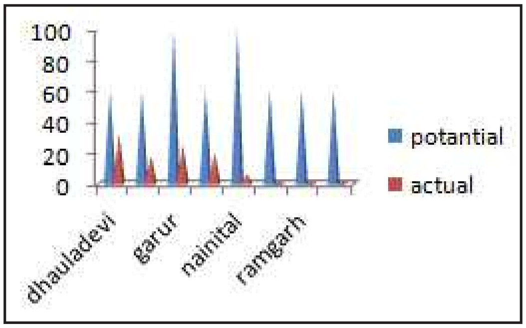

Figure- 2 Production under MNREGA

A Study from kausani - kausani is the world famous tourist place not only its natural beauty also in tea production. In kausani the first plant of tea bring was in 1836, nursery was established 1993 and plantation was begin 1995. The present day it become speard to 211 hectare. The factory was established with the help of combined unit of Banglore Co. giriyas Pvt with 89 and 11 % share. Kausani tea state produce world level tea with many verities and qualities. Here are many species of tea plant which are very expensive, healthy and familiar with ecosystem. Main species are SEAT- 379,449,520, CLONE-AB2,T78,P312,RR144, UPASI9 and UPASI3 (this verity from South India), KANGDAJAT (himanchal species). Kausani tea state produce 265000 kg green leaves in a year. 5 kg green leaves makes one kg tea in winter season and 4 kg green leaves makes 1 kg tea in summer season so that's mean in summer season tea production is more than winter. Tea plantation can gives a large quantity of employment 1000 workers are involve in tea production in kausani they are also getting facilities many life insurance policy and funding policies. However the tea agriculture gives women employment in mountain regions more than 60% women are involve in tea agriculture all over India. Among working staff in kausani tea state,65% are women.

Tea plantation is very useful to environment and it can help to reduce wasteland with the of proper plan and government policies. In the time of developing age we can see that many problems are rapidly increasing like environmental degreadiation,soil pollution (erosion), deforestation they are the cause of increasing wasteland in uttarakhand as well as in india also. In uttarakhand 12790 km² (23.91%) land area is wasteland area in this area only 2.67% is plain most of the wasteland area is suitable for the plantation of tea. There is no way to change this soil and natural process takes many hundred years. The speed of tree destruction is 30 times more than the plantation. Tea production is the ideal plan for soil and moisture conservation in india with the help of biotic fertilizers. Tea is a perennial crop grown on sloping terrain and high rainfall areas. Though the soil under a perennial crop like tea is believed to be protected adequately by canopy and surface litter.

Bright prospect of Indian rural scene forecast in the course of Green Revolution', the progress in the agricultural production is still left behind the population explosion, and unemployment problem remains to be critical. The three main sources of rural development namely reclamation of cultivable waste land, utilization of groundwater, and promotion of intensive agriculture based on 'modern' technology, have been already exploited and the future of the villagers mainly depends on joh opportunities offered by the economic activist's outside rural, areas.

Tea plantation can reduce the environmental issues with the help of reforstration.

Migration to plane area is the emerging problem for the all hill states m

Tea plantation can appreciate the echo tourism. *Over a decade after the state was founded, nine of its 13 districts are facing a crisis of migration.* In uttarakhand production of tea can become the source of employment. Tea is the second most popular drink in the world, after water. For a number of developing countries it is an important commodity in terms of jobs and export earnings. Tea production is labour intensive and the industry provides jobs in remote rural areas. Kausani tea state gives employment and life security to employee. The amount of salary is 108rs per day 3240rs monthly with funding and LIC. Thease type of policies can reduce the migration and give support to rural peoples.**(See in the next page)**

References :-

1. Haridas P, An ideal plant for soil and moisture conservation in Tea Plantations In India.
2. The hindu, feb 14, 2016
3. Uttarakhand Tea Development Board.

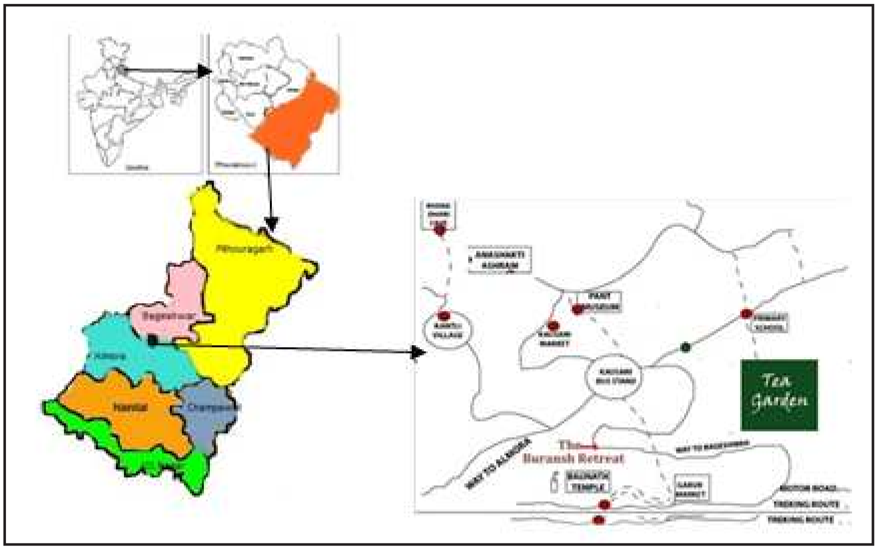

Kumaun Division — Kausani

Source- Modified from the "buransh.com"

Figure-3 Location of Kausani

****

A Trend Analysis Of Rural Population Dependency In A City Region

Dr. Prabhakar Mishra*

Introduction - Population Dependency is a characteristic of population that introduces and determines the ratio between the Working and dependent population. It is an important factor to represent the salient feature of the population potential of that particular region which comes under an influence of a City. This trend of population plays vital role among the developmental aspects and potential of productivity of population. High dependency ratio of population decreases the pace of development due to liability of nourishing of dependent population. On the other hand low dependency ratio of population spares more potential to the developmental works of the region. Therefore, the trend of investment of population potential provides the foundation to the specialization of population structureand the changes of regional phenomenon.

In the global scenario to achieve High developmental growth rate meant as a sign of progress. Productivity of populationcan play an important role to determine the dimensions for the effective planning and execution of policies.It is obstinate to achieve and maintain the goal of regional development without high progressive growth rateand increase in population productivity.

Therefore, it is also important to evaluate the population productivity in the context of the status of dependency ratio of population. Here is a presentation of trend analysis of population dependency in accordance with the effect of distance from the core region of the city.

Study Area - Ujjain and its' environs is selected as the study area to performthe present study. It is an area that extends between 23^{0}04' 44'' to 23^{0}17' 43'' north latitudes and 75^{0}17' 42'' to 75^{0}54' 02'' east longitudes. The study area compriseswith the area of 111.32 sq. kilometer of core region that is Ujjain city and the area of 406.08 sq. kilometer of its' rural countryside.

The study area consists of 90 villages around the Ujjain city up to the peripheral distance of 15km. from the outer boundary of Ujjain municipal corporation service area. It is because of the fact that is the intensity of influence of urban services decreases as the spatial distance increases and the impacts of other nearest urban service centers are observed which influence the accuracy of the research study.

Objective of the Study - Of all the characteristics of population structure population Dependency ratio is an important factor to study the qualitative merits of population of an area. Present study deals with the changes in distribution of Population Dependency Ratio as a structural characteristicsof rural population due to the proximity and the intensity of the urban services to the villages which are located inIntensive zone, and Extensive zone of its city region.

Methodology - Distance from core to the city region is a geographical factor. It determines the intensity of impact of urban facilities rendered to the city region. Therefore, the villages located in the nearest and fartherest zone are taken to compare the factors pertaining to the population of study area.The villages of Intensive zone and Extensive zone of city region are inclusiveto the analysis of statistical data. On the basis of primary and secondary data of sample villages are collected to analys the Population Dependency Ratio. As the values are minor to compare. So, the ratio of dependency is computed on per thousand person in lieu of per cent person to better representation of data analysis.

Population Dependency Ratio - Population Dependency Ratio is depend on the Age Structure and the level of contribution of population to the production. It is the ratio of producers and consumers sector of population. To evaluate the total workforce of population or the population potential, Population Dependency Ratio is an important tool to be used as an statistical indicator. High dependency ratio increases the pressure on the productive population groups and minimise the workforce to the developmental works within the area of occupancy and affects the economy.

Ujjain and City Region : Population Dependency Ratio(See in the next page)

Data Analysis - Here is a tabular representation of collection of number of Dependents per thousand persons of sample families of sample villages. Table shows the six groups of dependents of family members of selected sample families. In this table Lower dependency group represents <400 persons and Highest dependency group represents >2000 persons per thousand working persons.

Under the closure distance, Intensive zone has 44.12 percent families under 800-1200 dependents group per thousand working persons. It is highest dependency rate of this group where as 26.47 percent families have <400

*Associate Professor (Geography) Govt. College, Mahidpur (M.P.) INDIA

dependents per thousand working persons. It is second highest dependency group. 1200-1600 and 1600-2000 both groups of dependents reported null. But group of >2000dependents reported 17.65 percent families under the group. Therefore, it is clear that one fourth of the families of this group have less dependency ratio where the lowest dependency ratio falls under the group of 400-800 dependents with 11.76 percent families.

Extensive Zone that is the farthest category of distance in study area has the highest percent of families i.e. 47.62 percent under <400 dependents that is the lowest dependency ratio group. The highest dependency group shows the lowest only 01.19percent of families. In this zone , there is a reverse relation between dependency and number of family, which is the uniquetrend of dependency ratio of population. In this regard Intensive zone represents the uneven variance with the aspects.

To evaluate the effect of distance from city on the dependency ratio among ruralpopulation of villages located in Intensive zone and Extensive Zone of the study area the result of Chi square test achieved by the computation of dependency datashows its value 28.65 at level of significance 01 and Degree of freedom 05 where table value 15.08 is lesser. Therefore, the result shows the significance and intimated the fact that the dependency ratio and the distance from the city are interrelated geographical variables.

Results - Thus, analysis of the study reflects the fact that distance from the city has a remarkable effect on the dependency ratio of rural population of countryside. The trend of dependency ratio of population and the location of rural population are correlated geographical aspects. But in this regard the other geographical factors are also need to be examined which affect the dependency of population in a city region.

References :-

1. Demko G.J:Population Geography : A Reader; Mac Grow Hill Company, 1970
2. Bansal S.C.: Town – Country Relationship in Saharanpur City –Region: A Study in Rural – Urban Interdependence Problems, Sanjeev Pub. Saharanpur,1975
3. Chandna R.C.: Introduction to Population Geography, Kalyani Publisher, New Delhi, 1980
4. Deshpande C.D., Arunachalam B. and Bhatt L.S. : Impact of a Metropolitan City on the surrounding Region, Concept Publishing Co. New Delhi, 1980
5. Lal H. : Population Geography, Radha Publication, New Delhi, 2000
6. Mishra Prabhakar : Gramin Jansnkhya Sanrachna par nagriya prabhav (in hindi) unpublished Ph.D. thesis, Vikram Univrsity, Ujjain,2006

Ujjain and City Region - Population Dependency Ratio

Number of dependents per thousand working person

	<400 -800	**400- -1200**	**800- -1600**	**1200- -2000**	**1600-**	**>2000**	**total**
Intensive Zone	09 (26.47)	04 (11.76)	15 (44.12)	00 (0.00)	00 (0.00)	06 (17.65)	34
Extensive Zone	40 (47.62)	15 (17.86)	13 (15.48)	09 (10.71)	06 (07.14)	01 (01.19)	84

Degree of freedom = 05Level of significance 01percent

Computed value of Chi sq = 28.65

Source : Based on personal interviews.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

Nutritional Iron Deficiency Among Women In Betul District

Smt. Kaneez Fatima*

Abstract - Iron Deficiency among women in Betul district have been investigated, anaemic women both rural and urban in Betul were interviewed to participate in this study. The diet survey has been conducted through oral questionnaire method in rural as well as urban areas of the study region. Information have been collected from women of rural and urban population. In the present survey oral questionnaire method has been adopted. Selected families of different communities were interviewed. To collect the required information a detailed schedule was prepared regarding dietary habits. Consumption of nutritional iron in rural women is 16.10 per cent and urban women is 2.35 percent, which is less than the standard requirement.
Key Words - Nutrition, Health, Iron, Deficiency, Anaemia.

Introduction - Iron deficiency, which is the main cause of anaemia, is the most common nutrition disorder worldwide (WHO 1998). WHO recognized anaemia as a world spread public health problems having major consequences on health as well as on social and economical development (WHO, 2001). Anaemia is a condition characterized by a reduction in the total circulating haemoglobin. Iron deficiency anaemia is insufficient production of haemoglobin, which contains, iron (Brady. 2007). It is also a major health problem in menstruating women particularly pregnant women are most frequently affected (Herchberg, 1992). The iron deficiency often co-exist with other conditions such as malnutrition, Vitamin A deficiency, Folate deficiency and infections. Limited health care, poor hygiene, sanitation and low literacy rate are the main problems leading to various nutritional deficiencies including iron deficiency. Iron deficiency is a major health problem for health professionals and a challenge for policy makers in India. It is a very common and nutritional deficiency and a serious hematological problem in pregnancy. It is a major contributing factor to maternal and fatal morbidity and mortality.

The Study Area - The Betul district is a study region which is situated in the mid-southern most part of Madhya Pradesh. The area under study lies between 21º22' north to 22º24' north latitudes and 77º4' east to 78º33' east longitudes. For administration, the region is divided into 08 tehsils and 10 development blocks. The development blocks and villages are basic units of the present study which comprise an area of 10,043 square kilometers and a population of 1,575,362 persons. The study area contributes 3.25 per cent of total geographical area of the Madhya Pradesh. The sex ratio of the study region as a whole was 971 females per 1000 males during study period. The average density of population was 157 persons per sq. kms. Agriculture is the main source of food and the majority of rural people of the area is engaged in agriculture and allied activities. The total net sown area of the region is 42.27 per cent. Food crops overwhelm the agriculture land use and account for nearly 56.34 per cent of the total cropped area. A food habit of the people varies from place to place according to the culture of the inhabitants.

Data Collection And Methodology- The diet survey has been conducted through oral questionnaire method in rural as well as urban areas of the study region. Information have been collected from women of rural and urban population. In the present survey oral questionnaire method has been adopted. Selected families of different communities were interviewed. To collect the required information a detailed schedule was prepared regarding dietary habits. Survey of rural centres were made during October 2014 to March 2015, while the survey of urban centres were made from April 2015 to September 2015. To conduct the diet survey a schedule was filled in ten selected rural centres and eight urban centres of the region. The total 500 families were surveyed out of which 260 families were from rural areas and 240 families from urban areas. Diet calculations of each family was carried out on the basis of various guidelines and recommendations given by ICMR. The average diet of each member has to be resolved for different nutrient, the daily per capita consumption of food stuff has been considered.

Data Analysis - Iron is a mineral that works with other substances to create haemoglobin, the compound that carries oxygen in the blood. Men need around 8 mg of iron in their diet, while women need up to 18 mg (27 mg if

*Research Scholar (Geography) Govt. M.G.M. P.G. College, Itarsi (M.P.) INDIA

pregnant). Rich sources of iron are cereals, millets, meat, fish, eggs, pulses and green leafy vegetables. Of the cereals grains and millets, bajra and ragi are very good source of iron. Most of the iron in the body is found in the blood, and some are present in every cells, bound to iron containing enzymes. Iron within metalloprotein, haemoglobin and myoglobin can bind to oxygen molecules and transport them through the blood or store them within muscles. Myoglobin is found only in muscles, where it serves as a reservoir of oxygen. Iron deficiency is the most common nutrient deficiency in women. Insufficient iron can lead to anaemia. Common symptoms include tiredness and breathlessness. Iron deficiency in pregnant women increases the risk of having a premature birth or weight baby, which can have a negative impact on the short and long-term health of the baby.

The average consumption of iron in the rural area is 23.49 mg per capita per day against the standard requirement of 30 mg per capita per day. The all India average consumption of iron is 28 mg per capita per day. Thus, in the study area, it is 21.66 per cent and 16.10 per cent less than the standard requirement and the all India average consumption respectively. Further, in the urban centres the average consumption of iron is 29.29 mg per capita per day, which is 2.35 per cent less than the standard requirement and 4.60 per cent more than the all India average consumption of iron. The regional average consumption of iron is 26.39 mg per capita per day, which is 12.03 per cent more than the standard requirement and 5.75 per cent less than the all India average consumption of iron.

In the rural centres all the ten villages have recorded deficit and none of the villages are recorded surplus. The quantity of iron consumption varies from village to village. It is highest in Umariya 29.61 mg per capita per day, and it is the lowest in Bijadehi 17.15 mg per capita per day. The NIN recommended 30 mg of iron per capita per day. Iron consumption of all the ten villages is below this recommended level in the Betul district i.e. Bijadehi 17.15 mg, Chillore 19.71 mg, Dunava 22.71 mg, Heerapur 25.76 mg, Hidli 23.10 mg, Khandara 20.43 mg, Kothalkund 24.55 mg, Malajpur 23.06 mg, Masod 28.83 mg, Umariya 29.61 mg per capita per day.

In the urban centres only two centres have recorded surplus i.e. Betul 44.88 mg and Chicholi 33.15 mg per capita per day and the other six centres are recorded deficit. The quantity of iron consumption varies from village to village. It is highest in Betul 44.88 mg per capita per day, and it is the lowest in Multai 22.07 mg per capita per day. The NIN recommended 30 mg of iron per capita per day. Iron consumption of six centres is below this recommended level in the Betul district i.e. Athner 25.08 mg, Multai 22.07 mg, Dhodaramohar 29.04 mg, Bhainsdehi 29.85 mg, Sarni 26.28 mg and Amla 24.00 mg per capita per day.

Conclusion - Iron deficiency anaemia is found to be a common problem in women both rural and urban areas of Betul district. The majority of iron deficient anaemic women are rural, thus it is concluded that iron deficiency anaemia is much more among rural female than urban especially in the child bearing age. The risk factors include multiple pregnancies, nutritional inadequacy. Iron deficiency anaemia is mostly a problem of the poor class as the majority of the women had a very low socio-economic status. Thus it can be concluded from this study that iron deficiency anaemia is the most common type anaemia among the anaemic women of Betul district.

References :-

1. Brady (2007) - Iron Deficiency Anaemia : A Call for Aggregation Diagnostic Evaluation, Southern Medical Journal, 100, 966-967.
2. Herchberg. S, et. al. (1992) - Nutritional Anemia's, Baillier's Clinical Hematology, 5, 143-168.
3. World Health Organisation (1988) - The World Health Report 1998- Life in the 21st Century, A Vission for All., Geneva, Switzerland.
4. World Health Organisation (2001) - Iron Deficiency Anaemia Assessment Prevention and Control : A Guide for Programme Managers, WHO/NHD.01.30Ref Type., Serial (Book, Monograph).

****

डिण्डौरी जिले की बैगा जनजातीय के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का शिक्षा पर प्रभाव

एकता मथनियाँ * डॉ. ए.एल. महोबिया **

प्रस्तावना - शिक्षा व्यक्ति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बैगा जनजातीय समुदाय को विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित करने में शिक्षा एक शक्तिशाली हथियार हो सकता है। इस हेतु भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् से ही प्रयास किये जा रहे है। इसके बावजूद भी यदि अन्य समुदायों की तुलना में बैगा जनजातीय साक्षरता को देखते है, तो इस समुदाय में साक्षरता की बहुत ही धुंधली तस्वीर हमारे सामने आती है। शिक्षा के मौलिक अधिकार, सर्वाशिक्षा अभियान और विभिन्न जनजातीय विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बाद भी इन क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति में बहुत बदलाव दिखायी नहीं पड़ते है। अशिक्षा के कारण ही कई दशको से इस समुदाय का शोषण होता आया है। तथा विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाना है। यह शोध पत्र बैगा जनजाति के सामाजिक, आर्थिक स्थिति का शिक्षा पर प्रभाव के अध्ययन पर आधारित है। बैगा जनजातीय क्षेत्रो में शिक्षा की वास्तविक स्थिति की दशा एवं दिशा पर आधारित है।

प्रस्तावना - साक्षरता मानव विकास की एक ऐसी चाबी है जो लोगों की आजीविका का साधनों तथा क्षमता कुशलता निर्माण के साथ उनकी सूचनाओं तथा संसाधनों की पहुँच बढाने में कुशल तरीके से परिवर्तन लाती है।

वर्तमान परिदृश्य में विकास का एक महत्वपूर्ण प्रतिमान शिक्षित समाज का होना है। शिक्षित समाज ही सभ्य समाज की स्थापना कर सकता है। जबकि बैगा जनजातीय समुदायो में शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय है, जिसके कारण ये आज भी आधारभूत सुविधाओं से वंचित है। बैगा जनजाति सामाजिक, आर्थिक स्थिति का शिक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जब तक बैगा समाज की शिक्षा स्तर नहीं पढ़ती तब तक उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार का परिदृश्य नहीं देखा जा सकता है। बैग समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना बहुत ही जरूरी है ताकि वो आज की दुनिया से कदम से कदम मिलाकर चल सके।

बैगा जनजातीय समुदायो में शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय है जिसके कारण ये आज भी आधारभूत सुविधाओं से वंचित है। 2001 के अनुसार म.प्र. में बैगाओं को मात्र 26.2 प्रतिशत ही साक्षर है। जिनमें पुरूष 32.3 प्रतिशत साक्षर है एवं महिलाएँ 20.1 प्रतिशत साक्षर है।

शोध विधि - प्रस्तुत शोध प्रपत्र हेतु प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ो का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आकड़ो का संकलन हेतु साक्षात्कार अवलोकन प्रविधियों का प्रयोग किया गया है। द्वितीय आकड़े जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, 2011 आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था म.प्र. आदि का प्रयोग किया है।

अध्ययन क्षेत्र - सतपुडा पर्वतमाला के अंचल में तथा सलिल पावन नर्मदा की गोद में डिण्डौरी जिला जबलपुर संभाग के अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य जिला है। यह जिला भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अक्षांश $22^{0}17'$ से $23^{0}12'$ तक एवं पूर्वी देशांतर $80^{0}35'$ से $80^{0}58'$ के बीच स्थित है। जिले के उत्तरी सीमा जिला, उमरिया, उत्तर पश्चिम जिला जबलपुर दक्षिण पश्चिम सीमा जिला मण्डला उत्तर पूर्वी जिला शहडोल एवं दक्षिणी पूर्वी सीमा बिलासपुर से घिरा हुआ है। यह जिला समुद्रतल से 1100 मीटर ऊँचाई पर स्थित है। जिले की भौगोलिक क्षेत्रफल 6128 वर्ग कि.मी. है।

जिले की मुख्य नदी नर्मदा हैं इसके अतिरिक्त तुडार, सिवनी, चकरार मचरार, कुतरार, बुडनेर, खरमेर, बिजाखन, सिलगी, नदियाँ है जो नर्मदा की सहायक नदी है। इस जिले में काली दोमट, सेहरा, रेतीली, तथा मुरूम युक्त मिट्टी पाई जाती है। **(मेप देखे आगे पृष्ठ पर)**

अध्ययन का उद्देश्य -

1. बैगा जनजाति में शिक्षा प्रगति का अध्ययन करना।
2. बैगा जनजाति की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना।
3. उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
4. साक्षरता दर में वृद्धि एवं कमी के कारणो का अध्ययन करना।

(ग्राफ देखे आगे पृष्ठ पर)

बैगा छात्र-छात्राओं की सामाजिक स्थिति (सारणी देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

सारणी क्रमांक के अंतर्गत बैगा छात्र-छात्राओं से उनकी सामाजिक स्थिति संबंधी जानकारी एकत्र करते हुए यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि क्या उनकी सामाजिक स्थिति उनके शैक्षिक विकास में सहयोग प्रदा करती है अथवा नहीं। प्राप्त आकंड़ो से निम्न तथ्य दृष्टिगोचर हुए है-

1. छात्र-छात्राओं से यह प्रश्न पूछने पर कि क्या आपका विवाह हो चुका है प्राप्त उत्तर में 8.8 प्रतिशत छात्रो तथा 87.8 प्रतिशत छात्राओं ने अपनी असहमति व्यक्त की है।
2. घर में प्रकाश, हवा की उचित व्यवस्था संबंधी प्रश्न पूछने पर 73.3 प्रतिशत छात्रो तथा 79.1 प्रतिशत छात्राओं ने असहमति व्यक्त की है।
3. शाला जाने के लिए आवागमन के साधन की उपलब्धा के संबंध में 60.1 प्रतिशत छात्र तथा 66.3 प्रतिशत छात्राओं के अनुसार शाला जाने के लिए साधन उपलब्ध नहीं है जिसके कारण कई कठिनाईया

* शोधार्थी (भूगोल) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत
** प्राचार्य, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

का सामना करना पड़ता है। यह परेशानी बरसात के दिनों में और बढ़ जाती है।

4. माता-पिता द्वारा नशा करने के संबंध में 75.6 प्रतिशत छात्र तथा 77.9 प्रतिशत छात्राओं ने अपनी सहमति व्यक्त की है।
5. नशे के कारण झगड़ा होने के संबंध में 65.9 प्रतिशत छात्रो तथा 76.7 प्रतिशत छात्राओं ने अपनी सहमति व्यक्त की है।
6. क्या झगड़े के कारण पढ़ाई नहीं हो पाती है इस प्रश्न के उत्तार में 54.7 प्रतिशत छात्र तथा 65.1 प्रतिशत छात्राओं से सहमति व्यक्त की है।
7. स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न पूछने पर कि क्या आपके माता-पिता का स्वास्थ्य ठीक रहता है इस संबंध में 67.6 प्रतिशत छात्र तथा 68.6 प्रतिष्ता छात्राओं ने सहमति व्यक्त की है।
8. बहुत अधिक खेलने से थकान के संबंध में 65.9 प्रतिशत छात्र तथा 62.8 प्रतिशत छात्राओं ने सहमति व्यक्त की है।
9. थकान के कारण आपके पढ़न-पाठन में बाधा उत्पन्न होती है, इस संबंध में 60.1 प्रतिशत छात्र तथा 76.2 प्रतिशत छात्राओं ने सहमति व्यक्त की है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि वह विदित है कि सामाजिक कारक शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते है। यदि सामाजिक परिवेश शैक्षणिक दशा के अनुरूप न हो तो शिक्षा रूपी कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। प्राप्त आंकड़ो के विश्लेषण से यह विदित है कि सभी प्रकार के लैंगिक और सामाजिक भेदभाव शिक्षा को प्रभावित करते है। बाल्यावस्था में छात्र-छात्राओं का विवाह उनके शिक्षा मार्ग में बाधक है जो कानूनी दृष्टि से भी अनुचित है किंतु वर्तमान समय में भी जनजातीय क्षेत्रो में यह स्थिति दृष्टिगोचर होती रहती है। अधिकांश परिवार गरीब होने के कारण उनके घरो में प्रकाश व हवा की उचित व्यवस्था का अभाव है। माता-पिता द्वारा नशे के सेवन से पारिवारिक वातावरण अशांत रहता है। झगडे होते हैं जिसका प्रभाव बच्चो की शिक्षा पर पड़ता है। घरेलू कामकाज में बच्चों की संलग्नता से उन्हें खेलने का पर्याप्त समय नही मिल पाता, जिस समय का उपयोग खेलने में करते है उससे पाठन कार्य भी प्रभावित होता है तथा अधिक थकान से पढाई के प्रति रूचि नहीं रह पाती है।

आदिवासी क्षेत्रो में शाला आने-जाने के साधनो का भी अभाव दृष्ट्रिगोचर हुआ है। ये सभी कारक शिक्षा के मार्ग में चुनौती पूर्व माहोल की ओर इषारा करते है। अर्थात् इन सभी अवरोधो का पर्याप्त समाधान निकाले बिना सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इन तथ्यों की पुष्टि सांख्यिकी गणना के द्वारा भी स्पष्ट है।

बैगा जनजाति की आर्थिक स्थिति (सारणी देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

सारणी क्रमांक 2 के अतंर्गत बैगा छात्र-छात्राओं से उनकी आर्थिक स्थिति संबंधी जानकारियाँ एकत्र करते हुए यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि क्या उनकी आर्थिक स्थिति का प्रभाव उनकी शिक्षा पर पड़ता है। प्राप्त जानकारियो को निम्नवत् दर्शाया जाता है।

1. छात्र-छात्राओं से यह प्रश्न पूछने पर कि क्या आपके परिवार में केवल पिता ही कमाते है, इन प्रश्न के उत्तर में 71.7 प्रतिशत छात्र तथा 75.5 प्रतिशत छात्राओं ने सहमति व्यक्त की है।
2. क्या पिता की आय में घर का खर्च चल जाता है। इस संबंध में 51.2 प्रतिशत छात्र 53.5 तथा छात्राओं ने असहमति व्यक्त की है।
3. घर का खर्च पूरा न होने पर छात्र-छात्राओं से यह पूछने पर कि क्या आपको भी काम करना पड़ता है, इस संबंध में 58 प्रतिशत छात्र तथा 61.5 प्रतिशत छात्राओं ने सहमति व्यक्त की है।
4. आपकी मां भी काम करती है, यह पूछने पर 53.9 प्रतिशत छात्रो तथा 529 प्रतिशत छात्राओं ने अपनी सहमति व्यक्त की है।
5. क्या आपके परिवार में कर्ज का बोझ है, इस संबंध में 54.7 प्रतिशत छात्र तथा 52.3 प्रतिशत छात्राओं ने स्वीकार किया कि उनके परिवार में कर्ज का बोझ है।
6. आर्थिक कठिनाई के संबंध में पूछने पर 79.8 प्रतिशत छात्र तथा 69.8 प्रतिशत छात्राओं ने बताया कि उनके यहां आर्थिक समस्यायें बनी ही रहती है।
7. क्या आपका अपना घर है यह पूछने पर 80.6 प्रतिशत छात्रो तथा 54.9 प्रतिशत छात्राओं के अनुसार उनके अपने निजी घर है।
8. क्या घर में पर्याप्त जगह/कमरे है यह पूछने पर 62 प्रतिशत छात्रो तथा 62.8 प्रतिशत छात्राओं ने स्वीकृत किया है। उनके घर में पर्याप्त जगह कमरे नहीं है।
9. क्या घर की आवश्यक सभी वस्तुएं है। इस संबंध में 68.2 प्रतिशत छात्रो तथा 69.8 प्रतिशत छात्राओं ने असहमति व्यक्त की है।

उपरोक्त आंकड़ो के विश्लेषण से यह विदित है कि आदिवासी क्षेत्र के अधिकांश परिवारों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। क्षेत्र में रोजगार के अवसरो की अनुपलब्धता से परिवार के पुरूषों के साथ-साथ समय विशेष पर महिलाओं को भी कार्य करने हेतु विवश होना पड़ता है, क्योंकि घर की आर्थिक कठिनाई तथा कर्ज का बोझ परिवार के सदस्यों को कार्य करने हेतु विवश करता है। आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को भी मजदूरी कार्य में सलंग्न होना पड़ता है। आर्थिक कठिनाईयो के कारण बहुत घरो में कमरो की संख्या भी कम है। यह सभी आर्थिक कारक शिक्षा की प्रगति में बाधक है। इन सभी तथ्यों की पुष्टि सांख्यिकी गणना से भी होती है।

निष्कर्ष – सामाजिक कारक शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते है यदि सामाजिक परिवेश शैक्षणिक दशा के अनुरूप न हो तो शिक्षा रूपी कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, आर्थिक कारक शिक्षा की प्रगति में बाधक है बैगाओं में साक्षरता दर को बढ़ाने के लिये उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार से ही शिक्षा विकास हो सकता है। इस समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना बहुत आवश्यक है। तभी इस समाज का शैक्षणिक सामाजिक और आर्थिक विकास होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राजू एस. सुपारा (2010) डेवलपमेंट थूर लिटरेसी: अस्टडी फिशरिंग कम्यूनिटी इन आन्ध्रप्रदेश जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट एन. आई. आर. डी. अक्टूबर-दिसम्बर, वोल्यूम 29, नं 4
2. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका प्रकाशन वर्ष 2011, जिला योजना एवं सांख्यिकीय कार्यालय मण्डला (म.प्र.)
3. डॉ. विजय चौरसिया 'प्रकृति पुत्र बैगा' मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल (2009)
4. मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 2011 आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था म.प्र. शासन 35, श्यामला हिल्स भोपाल-462002

District Umariya
North
District Dindori
Blockwise
Shahpura
Dindori
District Sahdol
Mehadwani
Amarpur
Samnapur
District Mandla
Karanjiya
Bajag
District Bilaspur
District Kaverdha

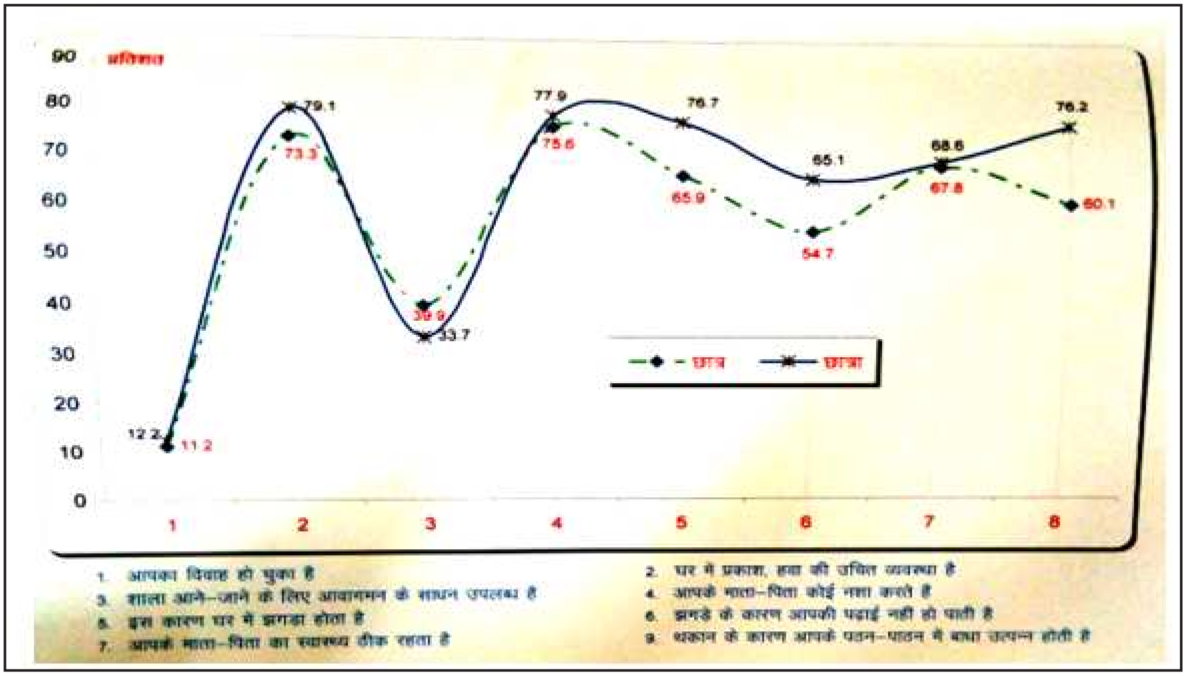
प्रतिशत
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
12.2
11.2
79.1
73.3
39.9
33.7
77.9
75.6
76.7
65.9
65.1
54.7
68.6
67.8
76.2
60.1
छात्र
छात्रा
1. आपका विवाह हो चुका है
3. शाला आने–जाने के लिए आवागमन के साधन उपलब्ध है
5. इस कारण घर में झगड़ा होता है
7. आपके माता–पिता का स्वास्थ्य ठीक रहता है
2. घर में प्रकाश, हवा की उचित व्यवस्था है
4. आपके माता–पिता कोई नशा करते है
6. झगड़े के कारण आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है
9. थकान के कारण आपके पठन–पाठन में बाधा उत्पन्न होती है

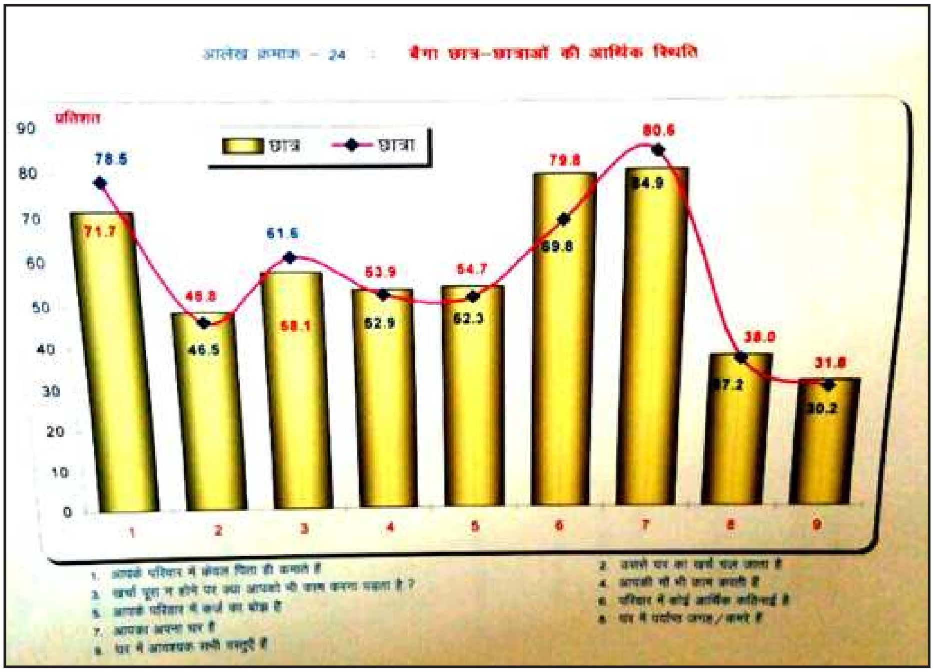

बैगा छात्र-छात्राओं की सामाजिक स्थिति

क्र.	कथन	छात्र			छात्रा			सार्थकता	
		हाँ	नहीं	योग	हाँ	नहीं	योग		
1	आपका विवाह हो चुका है।	11.2	88.8	100	12.2	87.8	100	0.094	असार्थक
2	घर में प्रकाश, हवा की उचित व्यवस्था है।	73.3	26.7	100	79.1	20.9	100	1.89	असार्थक
3	शाला आने-जाने के लिए आवागमन के साधन उपलब्ध।	39.9	60.1	100	33.7	66.3	100	1.694	असार्थक
4	आपके माता-पिता कोई नशा करते है।	75.6	24.4	100	77.9	22.1	100	0.311	असार्थक
5	इस कारण घर में झगड़ा होता है।	65.9	34.1	100	76.7	23.3	100	5.814	सार्थक
6	झगडे के कारण आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है।	54.7	45.3	100	65.1	34.9	100	4.667	सार्थक
7	आपके माता-पिता का स्वास्थ्य ठीक रहता है।	67.8	32.2	100	68.6	31.4	100	0.029	असार्थक
8	थकान के कारण आपके पढ़न-पाठन में बाधा उत्पन्न होती है।	60.1	39.9	100	76.2	23.8	100	11.988	सार्थक
	योग	**57.1**	**42.9**	**100**	**51.4**	**38.6**	**100**	**24.024**	**सार्थक**

बैगा जनजाति की आर्थिक स्थिति

क्र.	कथन	छात्र (N=258)			छात्रा (N=172)			काई वर्ग	सार्थकता
		हाँ	नहीं	योग	हाँ	नहीं	योग		
1	आपके परिवार में केवल पिता ही कमाते है।	71.7	28.3	100	78.5	21.5	100	2.494	असार्थक
2	उससे घर का खर्च चल जाता है।	48.8	51.2	100	46.5	53.5	100	0.224	असार्थक
3	खर्चा पूरा न होने पर क्या आपको भी काम करना पड़ता है।	58.1	41.9	100	61.6	38.4	100	0.521	असार्थक
4	आपकी माँ भी काम करती है।	53.9	46.1	100	52.9	47.1	100	0.224	असार्थक
5	आपके परिवार में कर्ज का बोझ है।	54.7	45.3	100	52.3	47.1	100	2.224	असार्थक
6	परिवार में कोई आर्थिक कठिनाई है।	79.8	20.2	100	39.8	30.2	100	5.00	सार्थक
7	आपका अपना घर है।	80.6	19.4	100	84.9	15.1	100	1.269	असार्थक
8	घर में पर्याप्त जगह/कमरे है।	38.0	62.0	100	37.2	62.8	100	0.026	सार्थक
9	घर में आवश्यक सभी वस्तुएं है।	31.8	68.2	100	30.2	69.8	100	0.116	असार्थक
	योग	**57.5**	**42.5**	**100**	**57.1**	**42.9**	**100**	**0.43**	**सार्थक**

****

बालाघाट जिले में लिंगानुपात का क्षेत्रीय अध्ययन

दीपिका दोहरे* डॉ.जे.एल.बरमैया **

शोध सारांश – लिंगानुपात किसी प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सूचक होती है, अर्थात किसी अर्थव्यवस्था के विकास में स्त्री-पुरूष अनुपात का विशिष्ट स्थान होता है। किसी जनसंख्या में सभी आयु वर्ग के कुल पुरूषों व स्त्रियों के अनुपात को लिंगानुपात कहते है। किसी समुदाय का लिंगानुपात उसकी सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं पर भारी प्रभार डालता है। भारत में निंगानुपात लगातार घट रहा है अर्थात प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या कम हो रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति हजार पुरूषों पर 943 स्त्रियाँ है। स्पष्ट है कि भारत में स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरूष शिशुजन्म लेते है।

क्लार्क ने माना है कि विश्व के सभी समाजों में परिवार को तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक कि उनके परिवार में लड़के का जन्म नहीं होता है। यद्यापि जन्म के समय पुरूष शिशुओं की संख्या स्त्री शिशुओं से अधिक पायी जाती है परन्तु संसार के सभी देशों में लिंगानुपात एक जैसा नही है। प्राकृतिक लिंगानुपात में भारी क्षेत्रीय भिन्नतायें मिलती है।

लिंगानुपात का प्रभाव जनसंख्या की वृद्धि, विवाह दर तथा व्यावसायिक संरचना, जैसे अन्य जनांकिकी गुणों पर भी पड़ता है। किसी जनसंख्या में रोजगार व उपभोग के प्रतिरूप सामाजिक आवश्यकतायें और उसके मनोवैज्ञानिक विशेषताओं कों समझने में लिंगानुपात का अध्ययन उपयोगी होता है। प्रस्तुत शोध पत्र बालाघाट जिले में लिंगानुपात को प्रदर्शित करता है।

प्रस्तावना – लिंगानुपात समाज में विस्थापित पुरूष तथा स्त्रियों के अनुपात को निकालकर उसमें प्रतिहजार पुरूषों में स्त्रियों की संख्या के प्रभाव को दर्शाता है लिंगानुपात में क्षेत्र एवं समय के अनुसार भिन्नता पायी जाती है , जो मानव जीवन के विभिन्न आयु-वर्गो में स्त्री एवं पुरूषों की मृत्यु दर एवं स्थानान्तरण के कारण होती है।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राष्ट्रीय लिंगानुपात में 7 अंको की वृद्धि हुई है। 2001 की जनगण्ना में प्रति 1000 पुरूष पर 933 स्त्री थी, जो 2011 की जनगणना में बढ़कर 943 पर पहुँच गया है। राष्ट्रीय लिंगानुपात में यह वृद्धि देश के लिए अच्छा संकेत है। क्योंकि आंकड़ो के हिसाब से यह 1971 की जनगणना के बाद से दर्ज सबसे उँचा लिंगानुपात है। वहीं 1961 की जनगणना की तुलना में थोड़ा कम है। 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों में लिंगानुपात 914 है। 2001 की जनगणना में जंहा बच्चों का लिंगानुपात 927 था वही 2011 के आंकड़ो के अनुसार बच्चों का लिंगानुपात 914 है यानी बच्चों के लिंगानुपात में 13 अंको की कमी आयी है।

अध्ययन क्षेत्र –भारत के ह्रदय क्षेत्र एवं दक्कन के पठार के उत्त्र में मध्यप्रदेश राज्य स्थित है। इस राज्य के दक्षिण पूर्व में बालाघाट जिला वसा है। भौगोलिक दृष्टि से यह जिला सतपुड़ा-मैकल पठारी प्रदेश का एक महत्वपूर्ण भूखण्ड है। इस पठारी प्रदेश का अधिकांश भूभाग सतपुड़ा पर्वत श्रेणी प्रदेश तथा शेष उत्तरी-पूर्वी भाग मैकल पठारी प्रदेश के अन्तर्गत आता है। इस जिले में सतपुड़ा का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र तथा मध्य बैनगंगा घाटी सम्मिलित है। यह जिला $21^{0}19'$ उत्तरी अक्षांश तथा $79^{0}31'$-$81^{0}3'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 9229 वर्ग किलोमीटर तथा समुद्र सतह से इसकी उचांई 303,33 मीटर है। प्रशासनिक दृष्टि से यह जिला 11 तहसीलों, 10 विकासखण्डों एवं 1390 ग्रामों मे विभक्त है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 17,01,156 व्यक्ति है जो मध्यप्रदेश की सम्पूर्ण जनसंख्या का 2.3 प्रतिशत , जनसंख्या घनत्व 184 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा सक्षरता दर 78.9 प्रतिशत है। इस जिले का लिंगानुपात 1021 है। यह मध्यप्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है।

उद्देश्य :–प्रस्तुत शोध पत्र अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य बालाघाट जिलें में लिंगानुपात की स्थिति का अध्ययन करना तथा लिंगानुपात में संतुलन के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना है।

सारणी क्रमांक -01 - बालाघाट जिले में विकासखण्ड अनुसार लिंगानुपात वर्ष 2011

क्र.	विकास खण्ड का नाम	लिंगानुपात
1	कटंगी	1026
2	खैरलांझी	1027
3	लालबर्रा	1015
4	वारासिवनी	1021
5	बरघाट	1031
6	किरनापुर	1019
7	परसवाड़ा	1036
8	वैय्हर	1034
9	विरसा	1028
10	लांझी	1014
बालाघाट जिले का कुल लिंगानुपात		1024

*शोधार्थी (भूगोल) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत
** शासकीय महाविद्यालय, जैतहरी, जिला-अनुपपुर (म.प्र.) भारत

स्त्रोत – जिला सांख्यिकीय पुस्तिका

उपरोक्त सारणी क्र. 01 बालाघाट जिले में विकास खण्ड अनुसार लिंगानुपात को प्रदर्शित करती है। आंकड़ो के अनुसार जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात 1036 पारसवाड़ा विकास खण्ड में तथा सबसे कम 1014 लांझी में है इस जिलें में लिंगानुपात 1021 है। जोकि मध्यप्रदेश में सवसे अधिक है।

सारणी क्रमांक – 02 : बालाघाट जिले में विकासखण्ड अनुसार लिंगानुपात (0–6) आयु वर्ग में वर्ष 2011

क्र.	**विकास खण्ड का नाम**	**कुल जनसंख्या (0–6) आयु वर्ग में**			**लिंगानुपात (0–6)आयु वर्ग में**
		बालक	**बालिका**	**योग**	
1	कटंगी	9476	9373	**18849**	989
2	खैरलांझी	9021	8872	**17893**	983
3	लालबर्रा	10230	9609	**19839**	939
4	वारासिवनी	9011	8672	**17683**	962
5	बरघाट	10331	10058	**20389**	974
6	किरनापुर	10688	10094	**20782**	944
7	परसवाड़ा	7130	6996	**14106**	981
8	वैय्हर	8196	7965	**16161**	972
9	विरसा	9446	9339	**18785**	989
10	लांझी	11161	11015	**22176**	987
बालाघाट जिले का कुल(0–6) आयु वर्ग में लिंगानुपात		**94690**	**91993**	**186683**	**972**

उपरोक्त सारणी क्रमांक 02 में बालाघाट जिले के सभी 10 विकासखण्डों में (0–6) आयु वर्ग में लिंगानुपात को प्रदर्शित किया गया है। आंकड़ो से स्पष्ट होता है कि जिले में बाल लिंगानुपात 972 है तथा सबसे अधिक कटंगी विकासखण्ड में 989 एवं सबसे कम बिरसा विकासखण्ड में 944 बाल लिंगानुपात है।

निष्कर्ष एवं सुझाव – लिंगानुपात एक अति संवेदनशील सूचक है जो महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है। बच्चों में लिंगानुपात निरंतर कम होता जा रहा है। निरंतर कम होते लिंगानुपात के कारण जनसंख्या में असंतुलन पैदा होता है जिससे महिलाओं के विरूद्ध अपराध बढ़ने जैसी अनेक सामाजिक समस्याएँ पैदा होती है।

पश्चिमी विकसित देशों में लिंगानुपात की प्रकृति स्त्री जनसंख्या के पक्ष में है जबकि भारत में विशेष रूप से इसकी प्रवृति पुरूष जनसंख्या के पक्ष में मिलती है। भारत में 2001 की जनगणना में प्रति हजार पुरूषों के पीछे 933 स्त्रियां है जबकि रूस में स्त्रिओं का अनुपात 1140, जपान में 1041 व संयुक्त राज्य अमेरिका में 1129 था। राष्ट्रीय स्तर पर शिशु लिंगानुपात वर्ष 2011 के आंकड़ो को देखे तो वह 1000 पर 914 है जबकि 2001 की जनगणना में 1000 पर 927 था। इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर भी शिशु लिंगानुपात में भी गिरावत दर्ज की गई है। इस मामले में राज्यों की स्थिति राष्ट्र की तुलना में भी खराब है।

बालाघाट जिले में परूषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक है तथा (0–6) आयु वर्ग में भी अधिक असमानता दृष्टिकोचर होती है। जिले में बलिकाओं की संख्या अधिक होने के कारण भविष्य में प्रजन्नता में वृद्धि होने से जनसंख्या में भी वृद्धि होगी। जनसंख्या वृद्धि होने से आवास समस्या, खाद्यान्न की कमी , बेरोजगारी में वृद्धि, गंदगी, भुखमरी, अशांति एवं पर्यावरण प्रदूषण जैसे अनगिनत समस्यांए उत्पन्न होती है। समस्याओं के विकराल रूप से जिले की अर्थव्यवस्था, अव्यवस्थित होकर विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे। इन समस्याओं के समाधान के लिये साक्षारता दर को उँचा उठाया जायें ताकी जन जागरूकता में वृद्धि होने से परिवार नियोजन की विभिन्न योजनाओं से लाभांवित होकर लिंगानुपात असमानता की दर में गिरावट लाया जा सके।

लड़को की चाहत में लोग कन्याभ्रूण को गर्भ में ही मरवा देते है। ऐसे परीक्षणों पर सख्ती से रोक लगनी चाहिये। लिंग परीक्षण के लिए कानून बनना ही पर्याप्त नही है ,उसके लिए कड़े व मजबूत प्रबंधन एवं उसकी अनिवार्यता को भी लागू करने की आवश्यकता है तभी लिंगानुपात असमानता को कम किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. मिश्रा डॉ. जे.पी. (2008) 'जनांकिकी ' साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा (उ.प्र.)।
2. पंडा, डॉ. बी.पी. (2007) 'जनसंख्या भूगोल' मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल।
3. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका प्रकाशन वर्ष 2011 जिला योजना एवं सांख्यिकीय कार्यालय बालाघाट (म.प्र.)।
4. शोधपत्रिका – रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर विद्यालय मण्डला।
5. त्रिपाठी रामदेव (2005) 'जनसंख्या भूगोल' वसुन्धारा प्रकाशन गोरखपुर।
6. बराडे जितेन्द्र लाल (1998) – 'नगरीय प्रजननता रायपुर नगर तथा उसके उपान्त का प्रतीक अध्ययन' पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

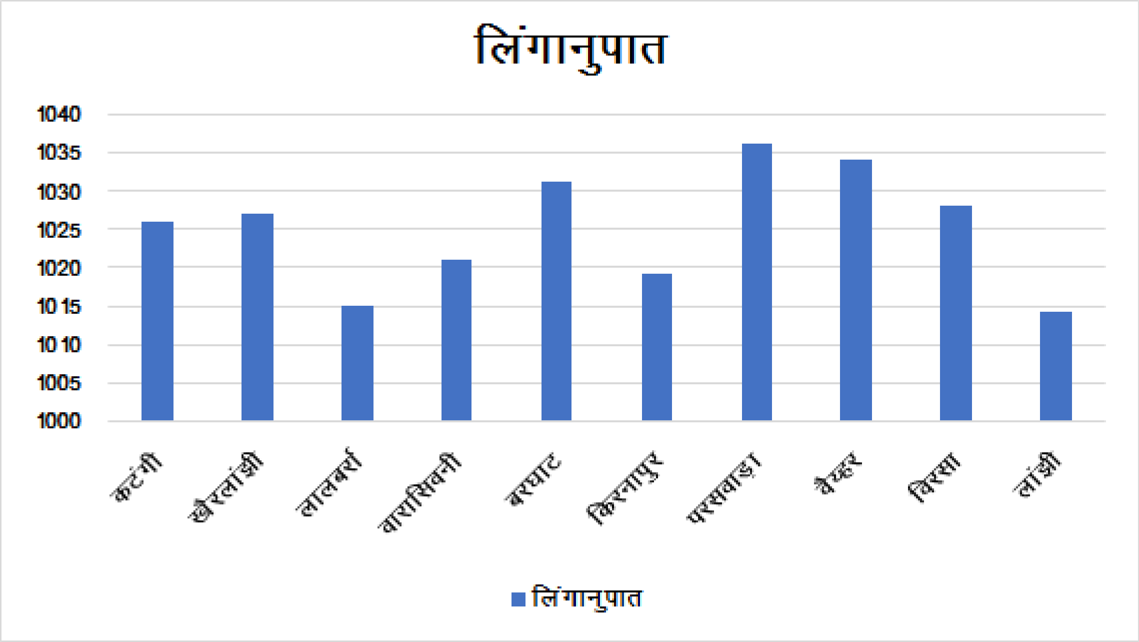

तहसील अनुसार मानचित्र

****

मैक्स वेबर की नौकरशाही की अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण

मनोज कुमार चंदोलिया *

शोध सारांश – मैक्स वेबर ने सत्ता द्वारा निर्धारित अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नौकरशाही को अब तक सर्वाधिक परिष्कृत साधन माना एवं नौकरशाही का एक आदर्श प्रारूप विकसित किया हालाँकि अनेक विद्वानों ने इसकी अनेक आधारों पर आलोचना करते हुए इसके आदर्श होने पर प्रश्न किया लेकिन फिर भी प्रशासन एवं संगठन के प्रबन्धन के क्षेत्र में वेबर के योगदान को नकारा नही जा सकता। प्रस्तुत शोध पत्र में मैक्स वेबर की नौकरशाही की अवधारणा का द्वितीयक तथ्यों के आधार पर आलोचनात्मक विश्लेषण किया किया गया जिसके आधार पर निकलकर सामने आता है कि नौकरशाही, लोकतंत्र एवं जनता के परिवर्तित सम्बन्धों के सन्दर्भ मे नए अध्ययनों की आवश्यकता है ताकि वर्तमान परिदृश्य में नौकरशाही और अधिक लोक कल्याणकारी बन सके।

शब्द कुंजी – नौकरशाही, आदर्श प्रारूप, लोकतंत्र एवं प्रबन्धन।

प्रस्तावना – मैक्स वेबर की नौकरशाही समाज में तार्किक सत्ता एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया से सम्बन्धित है। अब तक के अनुवर्ती सिद्धांतों ने नौकरशाही की तार्किकता पर प्रश्न किया है। आधुनिक समय में लोक नौकरशाही की कौन सी विशेषता तार्किक है ? कौन सी नही ? को अपने तर्को से संगठन एवं लोक–प्रशासन के सिद्धांतों के उद्धरणों से सिद्ध करने का प्रयास किया है।

ब्यरोक्रेसी (Bureaucracy) शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों Bureau एवं Kraots से हुई है जहां Bureau का अर्थ कार्यालय या मेज एवं Kraots or Kratia का अर्थ शक्ति या शासन होता है अर्थात Bureaucracy शब्द का उपयोग कार्यालय के शासन या शक्ति के लिए किया जाता है। (Hummel 1998, 307)

नौकरशाही कागजी एवं इलेक्ट्रानिक दस्तावेजो के प्रेषण द्वारा मेज या कार्यालय से शासन का संचालन करती है। वेबर (1946) ने नौकरशाही के वैज्ञानिक एवं साधारण प्रारूप को प्रस्तुत किया जो सार्वजनिक एवं निजि क्षेत्र दोनों के लिए उपयोगी हो सकता है। विज्ञान में विश्वास मैक्स वेबर की तार्किक–कानूनी सत्ता में निहित है, जो विशेष रूप से शासकीय नौकरशाही की संगठनात्मक संरचना की परिभाषिक विशेषता बन गई।

यह शोध–पत्र वेबर की नौकरशाही की प्रकृति एवं लोक–प्रशासन पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करेगा। यह वेबर की नौकरशाही की अवधारणा और पूंजीवादी एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इसके संघर्ष की प्रतिक्रिया की व्याख्या करता है। इसके अतिरिक्त यह शोध–पत्र लोक–प्रशासन के साहित्य एवं सिद्धांतों में खोजे जा सकने वाले तार्किक एवं अतार्किक क्षेत्रों को प्रतिबिम्वित कर लोकतांत्रिक समाज में नौकरशाही के वस्तुनिष्ठ दृश्य एवं इसकी व्यवहारिक उलझने को प्रस्तुत कर यह निष्कर्ष निकालता है।

मैक्स वेबर की नौकरशाही में तार्किकता – वेबर ने नौकरशाही को सामुदायिक क्रिया को, तार्किकता से आदेशित सामाजिक क्रिया के ऊपर ले जाने वाले साधन के रूप में परिभाषित किया है, शक्ति संबंधों के समाजीकरण के साधन के रूप में, नौकरशाही सबसे प्रमुख उपकरण रही है। कुछ विद्वानों (Friedrich, 1940; Finer, 1941; Simon, 1947; Shafritz and Hyde,1997; and Marshall in Ventriss, 2000) तर्क करते हुए कहते है कि लोक– प्रशासन नियंत्रण का क्षेत्र है, लोक–प्रशासन का नियंत्रण, लोगों का नियंत्रण, निवेश या निगत का नियंत्रण, उत्पाद का नियंत्रण, ये सभी प्रकार के नियंत्रण जनता की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के लक्ष्य को दक्षता अर्जित करने का प्रयास करते है। वेबर (1946) के अनुसार– नौकरशाही विशुद्ध रूप से तकनीकि दक्षता की अधिकतम सीमा को प्राप्त करने में सक्षम है और इस अर्थ में नौकरशाही मानव जाति पर नियंत्रण रखने के लिए औपचारिक रूप से ज्ञात सबसे तर्कसंगत साधन है (337)।

वेबर का मानना है कि मानव सभ्यता, आदिम और रहस्मय से तार्किक एवं जटिल चरणों और संबंधों में विकसित हुई है एवं समाज आदिम अवस्था से सैद्धान्तिक और तकनीकी विषयों तक आगे बढ़ते है। वेबर के अनुसार समाज के विकास को तीन प्रकार के प्राधिकारों/सत्ता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जिसे वह पारंपरिक, करिश्माई और वैधानिक–तार्किक सत्ता के रूप में पहचानते हैं(Fry, 1989)। यह वैधानिक–तार्किक प्रकार की सत्ता है जो कि वेबर की नौकरशाही की अवधारणा का आधार है और आधुनिक सभ्यता की नींव के रूप में यह 'मानक नियमों के स्वरूप की वैद्यता और उन नियमों के तहत प्राधिकार को ऊपर उठाने वाले अधिकारों के आदेशों को पर आधारित है(Stillman, 2000, 51)। चूंकि वेबर का तर्क है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, एवं सामाजिक सेवाओं के प्रावधान, अनेक प्रकार के करो का संग्रह करने और कार्य के विभाजन एवं विशेषीकरण द्वारा आवश्यक सेवाओं की आपूर्ती करने की समाज की जरूरतों के कारण नौकरशाही बढ़ती है। इस सन्दर्भ में Stillman ने वेबर को उद्धत करते हुए कहा है कि 'प्रशासनिक कार्यो का विकास नौकरशहीकरण के लिए हमेशा उचित पृष्ठभूमि रहा है (Stillman, 2000, 52)।

वेबर ने नौकरशाही का जो आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किया है उसकी मुख्य विशेषताए है– श्रम–विभाजन, लिखित दस्तावेज, प्रशिक्षित स्टॉफ एवं

* शोधार्थी (समाजशास्त्र एवं समाजकार्य) डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

विशेषज्ञ, अधिकारियों की पूर्ण कार्य क्षमता एवं औपचारिक नियमों का प्रयोग(Hummel, 1998, 307)।

परंतु नौकरशाही के ये अवयव संभवत: हमेशा संगठन में आदर्श कार्यो एवं दक्ष प्रदर्शन में सहयोग नही करते है। Michel Crozier (1964) तर्कपूर्वक कहते है कि 'नौकरशाही की कुछ विशेषताएं औपचारिक नियम, संस्तरण और निर्णय लेने के अधिकार के केन्द्रीयकरण के कारण यह संगठन समाज में अपनी सेवाए देने के दौरान अपनी गलतियों से सीख लेने में असमर्थ होता है।'

नौकरशाही में उच्च अधिकारियों को निम्न अधिकारियों से पृथक रखने के लिए संस्तराणात्मक व्यवस्था आवश्यक है क्योंकि औपचारिक नियमों का उद्देश्य नौकरशाहों को नियत व्यवहार प्रतिमानों तक सीमित रखना है। नियम अधीनस्थों पर उनके वरिष्ठो के व्यवस्थित नियंत्रण के साधन है जो 'मनमानी और निजी पक्षपात के अवसरों को सीमित करते है'(Stillman, 2000, 52)। अतएव पूर्वगामी विश्लेषण से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 'वेबर का विश्वास है कि प्रशासन का एक विज्ञान है जिसके द्वारा तथ्यों को मूल्यों से पृथक करके संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रकार नौकरशाही मनुष्य द्वारा तैयार किया गया अब तक का सबसे तर्कसंगत एवं दक्ष संगठनात्मक स्वरूप है।

वेबर दक्षता और नौकरशाही के बारे में बताता है कि – 'सार्वभौमिक अनुभव है कि विशुद्धरूप से नौकरशाही प्रारूप का प्रशासनिक संगठन का तानाशाही प्रकार है। लेकिन नौकरशाही तकनीकी दृष्टि से, उच्चतम दक्षता प्राप्त करने में सक्षम है और इस अर्थ में यह मनुष्य पर आवश्यक नियंत्रण रखने के लिए ज्ञात, औपचारिक रूप से सबसे तर्कसंगत साधन है, यह स्थिरता, अनुशासन और विश्वसनीयता में किसी भी अन्य स्वरूप से श्रेष्ठतर है'(Weber, 1947, 337)।

हम नौकरशाही व्यवस्था का संगठन के रूप में आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकते है। Foucault,(1975) ने अपनी पुस्तक– **डिसीप्लिन एण्ड पनिशमेन्ट – द बर्थ ऑफ द प्रिजन** में इससे मिलते जुलते तत्वों की व्याख्या की है। क्या सार्वजनिक संगठनों के कर्मचारी कुछ तरीकों और नियमों को नही सीखते है ? क्या वे विशिष्ट नियमों, प्रक्रियाओं और उनके कार्य करने के तरीको का पालन नही करते है ? हम सामाजिक संस्थानों की संरचना देखते है जो हमे **पनपटीकॉन** (Foucault,1975) की याद दिलाते है। कार्यकर्ताओ का लगातार निगरानी, विश्लेषण, परीक्षण होता रहता है जिसके परिणामस्वरूप कार्यकताओं के जीवन के हर क्षेत्र में लोगों का नौकरशाही शामिल हो जाती है।

नौकरशाही, पूंजीवाद एवं लोकतंत्र – वेबर का मानना है कि पूंजीवादी समाज में हर जगह नौकरशाही मौजूद है। वेबर के पूंजीवाद एवं नौकरशाही के अवधारणाकरण के अनुसार दोनो पारस्परिक सहायक संरचनाएं है(Fry, 1998, 33)। पूंजीवाद एवं नौकरशाही को एक ही प्रकार के औपचारिक संचार की आवश्यकता होती है, एक तरफ यह लेन–देन पर आधारित होता है जिसे सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए कानूनी एवं नैतिक आधार की आवश्यकता होती है तो दूसरी ओर नौकरशाही एवं लोकतंत्र का एक अलग प्रकार का सम्बन्ध है, यह ऐसा संबंध है जो वेबर के संगठन सिद्धांत के नियमों के एकीकरण के लिए सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र द्वारा बौद्धिक प्रतिक्रिया में मुख्य रूप से मदद करता हैं। यह ऐसा सम्बन्ध है जिसे वेबर ने प्रभावशाली वक्तव्यों के आधार पर बनाया है, जिसका विद्वानों द्वारा लोकप्रशासन के क्षेत्र में विश्लेषण भी किया गया है। नौकरशाही तार्किक रूप से निर्देशित सामाजिक क्रिया को प्राप्त करने का साधन है। लोक प्रशासकों के लिए प्रश्न उठता है कि क्या होगा यदि नौकरशाही अपनी सीमाओं को लांघ दे ? सबसे पहले हम उस प्रश्न का उत्तर देना चाहेगें जो प्रश्न वेबर के लोकतंत्र पर दिए हुए विचारों में पाया जा सकता लोकतंत्र पर वेबर लिखते है– 'लोकतंत्र मे लोग उस नेता को चुनतें हैं जिस पर वे भरोसा करते है, लेकिन नेता चुने जाने के बाद नेता कहता है कि **अब चुप रहो और मेरी आज्ञा मानों**, लोग, नेता एवं पार्टी के कार्य में हस्तक्षेप के लिए स्वतंत्र नही होते है लेकिन जब नेता गलती करते है तो बाद मे लोग निर्णय लेकर बैठ जाते है और सजा के तौर पर उसका बहिष्कार करते है(Gerth & Mills, 1946, 6)।

नौकरशाही पर राजनीति की सर्वोच्चता के लिए एक लोकतांत्रिक ढांचे में राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक है। यह केन्द्रीय मुद्दा वेबर और लोक प्रशासन के विद्वानों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। निष्क्रिय 'लोकतंत्रीकरण' एक ऐसी प्रक्रिया जिसके पर वेबर कहमे है है कि नौकरशाही कार्य पूर्णता को नियंत्रित करके अपने लोकतांत्रिक प्रतिभागियों को नियंत्रित करते है। जब बहुत कम नियंत्रण परिणाम होते है तो अभिजात वर्ग की स्थिति या नियंत्रण समूहों को खतरा हो सकता है जिसे हटाना मुश्किल हो जाता है। Thompson (1961) बताते है कि नौकरशाह कभी–कभी अपने अधिकारों का उपयोग करके लोगों पर नियंत्रण रखने वाले व्यवहार के तरीके को अपनाने की कोशिश करते हैं।

शासन स्तर पर और कठोर वैज्ञानिक, तर्कसंगत विचार के छत्र के नीचे, नौकरशाही लोकतंत्र के साथ संघर्ष क्यो करती है ? प्रशासन (नौकरशाही) विशिष्ट नियमों, प्रक्रियाओं और चीजों को पूरा करने के बारे में है, जबकि लोकतंत्र इच्छा, अभिव्यक्ति, अनुनय और प्रत्येक नागरिक की आवाजों पर विचार करने के बारे में है। लेकिन लोकतांत्रिक प्रशासन के साथ आने के लिए एक आसान मिशन नही है क्योंकि नौकरशाही ही वह उपकरण है जो प्रशासन में कार्य करने के लिए लागू किया जाता है। नौकरशाही ही लोकतांत्रिक नही है क्योंकि यह पदानुक्रम पर आधारित है।

नौकरशाही की अतार्किकता/सीमाएं – राबर्ट किंग मर्टन (1952) ने वेबर की नौकरशाही की आलोचना करते हुए कहा कि नौकरशाही की विशेषताओं, जिसे वेबर ने तर्कसंगतता एवं दक्षता बढ़ाने में आवश्यक माना, वास्तव में तर्कहीनता और अक्षमता के साथ जुड़ा हो सकता है। मर्टन ने निष्कर्ष निकाला कि नौकरशाही मे अपने स्वयं के विनाश के बीज होते है। इस हिस्से मे मैक्स वेबर के नौकरशाही प्रारूप की एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से चर्चा की गई है। यह चार मुख्य तर्कहीन सीमाओं पर ध्यान केन्द्रित करता है, जहां नौकरशाही अपने आदर्श प्रारूप में, अनौपचारिक संगठन की उपेक्षा और इसके अमानवीयकरण के साथ–साथ लोकतंत्र के साथ तनाव का सम्बन्ध है।

विशेष रूप से, वेबर की नौकरशाही किसी भी मानवीय संगठनों में मौजूद अनौपचारिक सम्बन्धों की महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार नही करती है। इसके अलावा, सार्वजनिक प्रशासन में कई लोग तर्क देते है कि नौकरशाही विवेकशीलता वास्तविकता लोकतांत्रिक मानदण्डों और प्रथाओं के लिए खतरा है।

पहली सीमा के बारे मे और वेबर की नौकरशाही की सावधानीपूर्वक जांज के माध्यम से, वेगर नौकरशाही का एक आदर्शवादी और निष्काम प्रारूप प्रस्तुत करता है जो किसी भी स्थान और किसी भी समय सार्वजनिक व्यवस्था को नियंत्रित एवं संचालित कर सकता है।

वेबर (1946) ने इसके लिए 'पूर्ण विकसित, शुद्ध प्रकार, सर्वाधिक विकसित या विशुद्ध विचारों का प्रयोग करते है, जो दर्शाते है कि नौकरशाही का उनका प्रारूप सही और पूर्ण है और यह हमेशा प्रभावी और कुशलतापूर्वक कार्य करता है। सार्वजनिक प्रदर्शन में समस्याएं होने और किसी भी देश में पूरे नागरिकों की सामाजिक आवश्यकताओं और राजनीतिक अधिकारों को पूरा करने में उसकी अक्षमता इस दावे को नकारती है कि नौकरशाही प्रारूप एक आदर्शवादी और प्लोटोनिक प्रणाली है। वेबर की नौकरशाही ने यह नही दर्शाया है कि वास्तविकता में नियमित परिस्थितियों में यह 'पूरी तरह से विकसित' संरचना है। Blau, and Marshall (1987) का तर्क है कि 'चूंकि पूर्ण नौकरशाही पूरी तरह से महसूस नही हुई है, इसलिए कोई भी मौजूदा संगठन निश्चित रूप से आदर्श प्रारूप में फिट नही होता है.......जो ठोस नौकरशाही संरचना की समझ प्रदान करता है(25)। दूसरे शब्दों में संगठनों के लिए एक ऐसे आदर्श प्रारूप का पालन करना सही नही लगता है जो लागू होने पर कभी भी निर्धारित लक्ष्यों को नही पा सकता या कुशलतापूर्वक कार्य नही कर सकता हो।

वेबर के नौकरशाही प्रारूप के संबन्ध में कह सकते है कि इसकी दूसरी सीमा, संगठनों के प्रदर्शन में दक्षता को प्रभावित करने की अनौपचारिक संगठन की भूमिका से अनभिज्ञता है। वेबर ने मुख्य रूप से औपचारिक तत्वों पर ध्यान केन्द्रित किया है जैसे विशेषीकरण, नियम, पदानुक्रम आदि। दूसरी ओर मानव रिस्तों, नेतृत्व, संचार नेटवर्क, प्रेरणा आदि अनौपचारिक तत्वो पर ध्यान नही दिया गया है जबकि ये भी सार्वजनिक और निजी संगठनों के कार्यो में भी उतना ही महत्व रखते हैं।

अनौपचारिक संगठन का अस्तित्व और महत्व जिसे 'व्यक्तिगत सम्पर्क, अन्त:क्रिया और लोगों के संबद्ध समूह के रूप में परिभाषित किया गया है' प्रबन्धन के क्षेत्र में अत्यधिक स्वीकार्य है(बरनार्ड, 1966, 115)। बरनार्ड (1966) ने पुष्टि की कि 'औपचारिक संगठन में अनौपचारिक सम्बन्ध संगठन के संचालन के लिए संचार के एक साधन, एकीकरण और व्यक्तियों की अखण्डता की रक्षा के लिए आवश्यक है'(123)। अनौपचारिक सम्बन्धां के इस महत्व को वेबर के नौकरशाही प्रारूप में नही देखा गया है, जो औपचारिक संरचनाओं पर केन्द्रित है। हॉलाकि वह संगठन मे व्यक्तियों के कुछ सामाजिक, राजनीतिक या व्यवहार संबंधी परिस्थितियों के बारे में बात करते है, उनके परिप्रेक्ष्य मुख्य रूप से औपचारिक संगठन के रूपरेखा से निकल जाते है।

तीसरा Hummel **(2007)** अपनी पुस्तक **ब्यूरोक्रैटिक एक्सपीरियंस** में तर्क देते है कि गुणवत्ता प्रबन्धन, कॉर्पोरेट पुन: अभियांत्रिकी और नए सार्वजनिक सिद्धांतकारों द्वारा उत्पन्न सभी प्रयासों के बावजूद नौकरशाही खराब हो रही है क्योंकि प्रबन्धन अभी भी नौकरियों के लिए 'हमेशा की तरह व्यापार' है। वह बताते है कि नौकरशाही केवल एक यांत्रिक तकनीशियन बन जाता है जो उसकी मानवता, भावनाओं, समाज और यहां तक कि उनकी व्यक्तिगत सोच से अलग है, जो इसे 'मानवता को धमकी देने वाले बम' के रूप में वर्णित करता है। उन्होंने कहा कि नौकरशाही संगठन मानव पहचान, चरित्र एवं स्वायत्त इच्छा को बदलता है(Bodley, 2002, 75)।

इसके अलावा नौकरशाही मानव को उसके दैनिक कार्यो को निर्णय, नियम और उच्च पर्यविक्षकों द्वारा लगाए गए निर्देशों के द्वारा सही और गलत तरीके से अपने प्रतिस्थापन के स्थान पर ले जाने के लिए मजबूर करता है जो वास्तविक सामाजिक सन्दर्भ और इसकी जरूरतों से दूर हो सकते हैं। हम्मेल कहते हैं कि नौकरशाही मनुष्य के मुकाबले इंसानों के साथ सौदा करती है। हम्मेल ने घोषणा की कि समाज और नौकरशाही के बीच एक संघर्ष है और 'नौकरशाही और समाज के बीच संबन्धों को मानवीकृत करने के वे सभी प्रयास आत्मघातक जो नौकरशाही के भीतर ही आते है।

लोकतांत्रिक समाज में नौकरशाही के अनुप्रयोग – waldo (1948) की दृष्टि से वास्तव में राजनीति एवं प्रशासन को अलग करने की असंभाव्यता के बारे में लोक प्रशासन के विद्वान इसका अनुमान लगा सकते है कि नौकरशाही एवं लोकतंत्र के मध्य साहित्य में कितना तनाव है। चौथी सीमा के संबंध में कई विद्वानों ने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है कि वास्तव में निरंकुश नौकरशाही, लोकतांत्रिक मानदण्डों और प्रथाओं के लिए खतरा है। ब्लॉ और मेयर ने यह तर्क दिया कि 'नौकरशाही की क्षमता का लाभ उठाने के दौरान नौकरशाही प्रभुत्व के खतरे से खुद को बचाने के लिए हमे पहले यह समझाना चाहिए कि नौकरशाही कैसे कार्य करती है। (Blau and Meyer quoted in Lane, 1999, 8)

ब्लॉ एवं मेयर ने व्याख्या कि है कि वेबर ने स्वीकार किया है कि नौकरशाही की स्थापना लोकतंत्र की दिशा में दोहरे मनोभाव वाली है।' एक तरफ नौकरशाहीकरण की प्रवत्ति वृहत पैमाने पर लोकतंत्र की ओर अग्रसर होती है तो दूसरी ओर नौकरशाही जनता की राय के प्रति उत्तरदायी नही होती है।'(Blau and Meyer quoted in Lane, 1999, 12)

Meyer & Tool (2006) ने पाया कि नौकरशाह शक्तिशाली है और अपने स्वयं के मूल्यों को प्रदर्शित करने के लिए राजनीतिक कार्यक्रमों में बदलाव कर सकते है– वे सामरिक एजेंट हैं। Wilson (1989) का तर्क है कि लोकतांत्रिक समाजो की नौकरशाही नियमों से भरी है, यह एक निश्चित संकेत है कि नौकरशाही लोगों से अलग है, उनकी चिंताओं से दूर है और नौकरशाहों की शक्ति और विशेषाधिकारों के साथ व्यस्त एक व्यापक पीसने वाली मशीन जो किसी का विरोध करने एवं भावना को कुचलने की हिम्मत कर सकता है(Wilson, 1989, quoted in Stillman, 2000, 484)। प्रशासनिक परम्पराओं और नौकरशाही के बिना एक आधुनिक समाज के प्रबन्धन की असम्भवता के बीच असंतुष्ट मतभेदों के कारण, आश्चर्य की बात नही है कि विद्वानों को नौकरशाही और प्रतिनिधि सरकार के बीच के संबन्ध को समझने में कठिनाई होती है, नौकरशाहों की समस्याएं हमेशा पदानुक्रम और प्राधिकरण आधारित संरचनाओं में फिट नही होती है।

नौकरशाही अब एक बंद प्रणाली नही मानी जाती है क्योंकि नागरिक–सलाहकार बोर्डो, परिषदों और आदि अन्य माध्यमो से निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इस आधार पर विल्सन (1989) का तर्क है कि यह प्रणाली अमान्य एवं अक्षम हो गई है।उन्होंने कहा कि 'इस लोकप्रिय भागीदारी को साक्ष्य के रूप मे लिया जाएगा कि प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल भी प्रणाली नही है, बल्कि एक घृणित, भ्रष्टाचार और पक्षपात के साथ प्रहार करती है'(Wilson quoted in Stillman, 2000, 484)।

नौकरशाही पर वस्तुनिष्ट दृष्टिकोण – यदि निष्पक्ष होकर कहा जाए तो न तो लोकतंत्र न ही समाज, नौकरशाही के बिना जीवित रह सकता है क्योंकि लोकतंत्र नौकरशाही के बिना चुने गए नेताओं के कार्यक्रम सम्बन्धी वायदों को पूरा करने मे सक्षम नही होगा। (Goodsell, 1994, 152)

Waldo के लिए नौकरशाही का मतलब बड़े पैमाने पर, औपचारिक, जटिल, विशेषीकरण और लक्ष्य उन्मुख संगठन से है। लोकतंत्र मूल्यों और नैतिकता की विशेषता है और यह नौकरशाही के साथ पूरी तरह से असंगत नही है। एक ओर नौकरशाही लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करती है और

दूसरी तरफ पदानुक्रम, अनुशासन और पर्यवेक्षण जैसी विरोधाभासी विशेषताएं भी हैं जो समानता और स्वतंत्रता के साथ संघर्ष करती है। वाल्डो का कहना है कि हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि नौकरशाही और लोकतंत्र दोनों वांछनीय एवं आवश्यक है और हमें दोनों के बीच इष्टतम मिश्रण की तलाश करना चाहिए।

अनेक शोधकर्त्ता इस धारणा की जांच करते है कि लोकतंत्र और नौकरशाही असंगत है। हालाकि वे यह निष्कर्ष निकालते है कि नौकरशाही चुनाव राजनीति को उस तरीके से जबाव देती ह जो लोकतांत्रिक नियंत्रण को मजबूत करती है एवं सुधारती है। (Scholz & Headrick, 1991, 829–850) पारंपरिक दृष्टिकोण यह है कि नौकरशाह जो व्यवसाय के सदस्य है, विशेषकर उनके विशेष कौशल और सरकार क बाहर पेशेवर समूहों के संबन्धों क कारण बाहरी नियंत्रणो को दूरकरने में विशेष रूप से कुशल है। हालाकि नौकरशाही पेशेवरों को अक्सर कौशल या जानकारी का कोई एकाधिकार नही होताहै, कोई समरूप मूल्य नही रखता है और कई जांचों के अधीन है।

इसके अलावा हमे यह याद रखना होगा कि कुछ विद्धानो तर्क देते है कि नौकरशाही को निम्नलिखित तर्कसंगत औचित्यों के आधार पर शासन करने की वैद्यता है –

1. वे सक्षम, सुशिक्षित और प्रशिक्षित है और वे चीजों को जानते है।
2. उनके पास दीर्घकालिक कार्यकाल है, जो उन लोगों के लिए विशिष्ट पीएफ के विशेषज्ञ है जिनके पास निश्चित अवधि है।
3. नौकरशाह लोग है और वे मूल्यों का आनन्द लेते है और लोगों और समाज की सेवा करने के लिए उनकी अच्छी इच्छा है इसीलिए उन्हें शासन करने का मौका दिया जाना चाहिए और लोगों को चिंता नही करनी चाहिए।

निष्कर्ष – नौकरशाही के द्वारा तर्कसंगतता और दक्षता प्राप्त की जा सकती है,वेबर की इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए लेकिन नौकरशाही अपनी कमियों के कारण 'एक दमनकारी दिनचर्या जो स्वतंत्रता के प्रतिकूल है'भी सिद्ध हो जाती है(Fry, 1998, 33)। क्योंकि नौकरशाही व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करती है और संगठन के सम्बन्ध में सदस्यों की गतिविधियों को समझने में पूरी तरह असफल तो नही है, लेकिन मुश्किल बना देती है। (Fry, 1998, 33)

संस्थापकों द्वारा प्रस्तुत प्रशासनिक परम्पराओं मेंमतभेदों एवं नौकरशाही के बिना आधुनिक समाज के प्रबन्धन की असंभाविता के कारण यह आश्चर्यजनक घटना नही है कि विद्वान अब सार्वजनिक प्रशसन के क्षेत्र में नौकरशाही और प्रतिनिधि सरकार के बीच सम्बन्धों की व्याख्या के लिए सैद्धान्तिक आधारों को समझने की कोशिश कर रहे है(Warner, 2001)

वर्तमान समाजों में हुए परिवर्तनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासकों, जनप्रतिनिधियों एवं जनता के मध्य आपस में संघर्ष होता रहता पड़ता है।चूंकि पदानुक्रम और प्राधिकरण आधारित संरचना मौजूदा संरचना में आसानी से फिट नही हो पा रही है इसलिए अधिक जटिल समस्याओ के अनुकूल होने के लिए नौकरशाही के पुनर्गठन या सुधार की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है दुर्भाग्य से इस बारे में कोई आम सहमति नही है कि पुनर्गठन कैस किया जा सकता है और यह मुद्दा आने वाले दशकों के लिए लोकप्रशासन के क्षेत्र में गर्म बहस में से एक रहेगा

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Barnard, Chester I. (1966). *The Functions of Executive*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
2. Blau, Peter M. and Meyer, Marshall W. (1987). *Bureaucracy in Modern Society*. New York, NY: Random House.
3. Bodley, John H. (2002). The Power of Scale: A Global History Approach.
4. M.E. SharpeCrozier, Michel. (1964). *The Bureaucratic Phenomenon*. Chicago: University of Chicago Press.
5. Finer, Herman. (1941). **Administrative responsibility in democratic government.** *Public Administration Review*, Vol. 1: 335-350
6. Foucault, Michel. (1975). *Discipline and Punish: the Birth of the Prison*. New York: Random House.
7. Friedrich, C. (1940). *Public policy and the nature of administrative responsibility*. In C. J. Friedrich (Ed.), Public Policy: 3-24. Cambridge: Harvard University Press.
8. Fry, Brian. (1989). *Mastering Public Administration*. Chatham, NJ: Chatham House Publishers, Inc.
9. Gerth, H, and G. Wright Mills. (1946). *From Max Weber: Essays in Sociology*. New York: Oxford University Press.
10. Goodsell, Charles. (1994). *The Case For Bureaucracy*. Chatham House Publishers, Inc., New Jersey, 152-159.
11. Kearney, Richard & Sinha, Chandan. (1988). Professionalism and Bureaucratic Responsiveness: Conflict or Compatibility? *Public Administration Review*, January-February 11988, 571-579
12. Hummel, R. (2007). *The Bureaucratic Experience: The Post-modern Challenge*. The 5th edition. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
13. Lane, Frederick. (1999). *Current Issues in Public Administration*. Bedford St.Martin's, Sixth Edition, Boston: 103
14. Merton, Robert. (1952). *Bureaucratic Structure and Personality in Reader in Bureaucracy*. New York: Free Press
15. Scholz, John & Hedrick, Barbara; Twombly, Jim. (1991). Street-Level Political Controls over Federal Bureaucracy. *American Political Science Review:*.529-850
16. Shafritz J. & Hyde A.C. (1997) Classics of Public Administration. Orlando: Harcourt Brace College Publishers.
17. Simon H. (1946). *Administrative Behavior*. New York, NY: Free Press.
18. Thompson, Victor. (1961). *Modern Organization*. New York: Alfred A. Knopf.
19. Waldo, D. (1948). *The Administrative State.* New York: Holmes and Meier Publishing.
20. Weber, Max (1946). *Bureaucracy.* Oxford Press
21. Wilson, J. Q. (1989). Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It. Basic Books

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

शिक्षित महिलाओं में धर्म के साथ सामंजस्य

लक्ष्मी मेहरा *

प्रस्तावना – धर्म का अर्थ होता है, धारण, अर्थात जिसे धारण किया जा सके, धर्म, कर्म प्रधान है। गुणों को जो प्रदर्शित करे वह धर्म है। धर्म को गुण भी कह सकते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि धर्म शब्द में गुण अर्थ केवल मानव से संबंधित नहीं। पदार्थ के लिए भी धर्म शब्द प्रयुक्त होता है यथा पानी का धर्म है बहना, अग्नि का धर्म है प्रकाश, उष्मा देना और संपर्क में आने वाली वस्तु को जलाना। व्यापकता के दृष्टिकोण से धर्म को गुण कहना सजीव, निर्जीव दोनों के अर्थ में नितांत ही उपयुक्त है। धर्म सार्वभौमिक होता है। पदार्थ हो या मानव पूरी पृथ्वी के किसी भी कोने में बैठे मानव या पदार्थ का धर्म एक ही होता है। उसके देश, रंग रूप की कोई बाधा नहीं है। धर्म सार्वकालिक होता है यानी कि प्रत्येक काल में युग में धर्म का स्वरूप वही रहता है। धर्म कभी बदलता नहीं है। उदाहरण के लिए पानी, अग्नि आदि पदार्थ का धर्म सृष्टि निर्माण से आज पर्यन्त समान है। धर्म और सम्प्रदाय में मूलभूत अंतर है। धर्म का अर्थ जब गुण और जीवन में धारण करने योग्य होता है तो वह प्रत्येक मानव के लिए समान होना चाहिए। जब पदार्थ का धर्म सार्वभौमिक है तो मानव जाति के लिए भी तो इसकी सार्वभौमिकता होनी चाहिए। अत: मानव के सन्दर्भ में धर्म की बात करें तो वह केवल मानव धर्म है। हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, जैन या बौद्ध आदि धर्म न होकर सम्प्रदाय या समुदाय मात्र हैं। 'सम्प्रदाय' एक परम्परा के मानने वालों का समूह है।

समाज में धर्म की भूमिका

दुर्खीम ने समाज में धर्म के प्रारम्भिक स्वरूप और उसके सामाजिक लक्षणों के अध्ययन के आधार पर जो योगदान किया उससे समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक विश्लेषण को असाधारण प्रोत्साहन प्राप्त हुआ यह सर्वविदित है। सही अर्थ में कहे तो समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मवाद के उत्तम उपयोग का उदाहरण धार्मिक उत्सवारों और विधि विधानों के विश्लेषण में इमाईल दुर्खीम के योगदान मध्य आस्टेलिया की अरुन्टा आदिम से प्राप्त तथ्यों पर आधारित था।

अध्ययन के उद्देश्य –

1. समाज में हिन्दू, मुस्लिम व जैन धर्म की शिक्षित महिलाओं का समाज के साथ व्यवहार को जानना।
2. शिक्षित महिलाओं के समाजीकरण के लिए मिलने वाले वातावरण एवं सुविधाओं के बारें में जानकारी प्राप्त करना।

प्रमुख प्राकल्पनाएँ – प्रस्तुत अध्ययन में निम्न प्राक्कल्पनाओं का निर्माण किया गया है–

1. शिक्षित महिलाओं को अपने बच्चों को धर्म के संस्कार देने में बहुत कम सामन्जस्य करना होता है।
2. शिक्षित महिलाओं को अन्य धर्म को मानने वाले से सम्बन्धों में बहुत अधिक सामन्जस्य करना होता है।

निदर्शन पद्धति – बून्दी जिले की दो पंचायत समितियों बून्दी और केशोराय पाटन से 240 उत्तरदाताओं का अध्ययन किया गया है। बून्दी पंचायत समिति से 40 हिन्दू, मुस्लिम 40 और 40 जैन शिक्षित महिलाओं को मिलाकर कुल 120 महिलाओं का चयन किया गया है और इसी प्रकार केशोरायपाटन पंचायत समिति से भी 40 हिन्दू, मुस्लिम 40 और 40 जैन शिक्षित महिलाओं को मिलाकर कुल 120 महिलाओं का चयन किया गया है। कुल इस अनुसंधान में 240 उतरदाताओं का चयन किया गया है। 15 शिक्षित महिलाओं का वैयक्तिक अध्ययन किया गया है। जिसमें 5 हिन्दू, 5 मुस्लिम, 5 जैन धर्म की शिक्षित महिलाओं का अध्ययन किया गया है।

सामग्री एंव प्रविधियाँ – प्रस्तुत अध्ययन के लिए साक्षात्कार अनुसूची को प्रयोग में किया गया है। द्वितीयक तथ्यों के लिए पूर्व में किए अनुसंधान, विविध जरनल,पत्र-पत्रिकाएँ एंव समाचार पत्र प्रमुख आधार है। तथ्यों के एकत्रीकरण के पश्चात् उनका सम्पादन, संकेतन, वर्गीकरण व सारणीयन के माध्यम से विश्लेषण किया गया है। तथ्यों को प्रदर्शित करने के लिए यथा संभव पाई चार्ट, बार डाइग्राम और मानचित्रों का प्रयोग किया गया है।

बच्चों को धर्म के संस्कार देने में सामन्जस्य

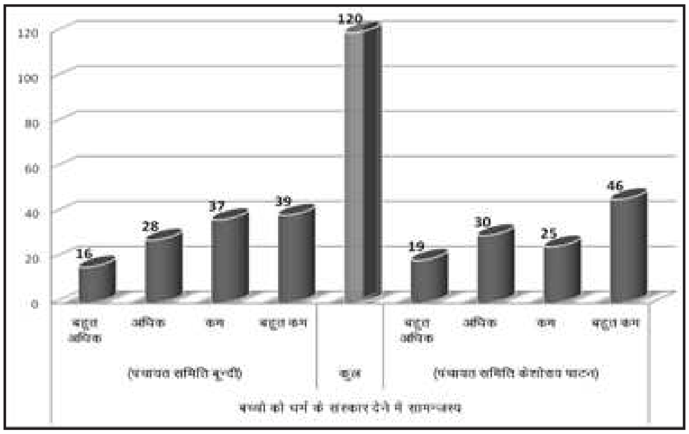

पंचायत समिति बून्दी से 120 शिक्षित महिलाओं में से 16 महिलाओं को बच्चों को धर्म के संस्कार देने में बहुत अधिक प्रयास करना होता है एवं 28 महिलाओं को बच्चों को धर्म के संस्कार देने में अधिक मेहनत करनी होती है और 37 महिलाओं को बच्चों को धर्म के संस्कार देने में आसानी होती है तथा 39 महिलाओं को बच्चों को धर्म के संस्कार देने में बहुत कम कठिनाईयों का सामना करना होता है। पंचायत समिति केशोराय पाटन से 120 शिक्षित महिलाओं में से 19 महिलाओं को बच्चों को धर्म के संस्कार

* शोधार्थी (समाजशास्त्र) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय,उदयपुर (राज.) भारत

देने में बहुत अधिक प्रयास करना होता है एवं 30 महिलाओं को बच्चों को धर्म के संस्कार देने में अधिक मेहनत करनी होती है और 25 महिलाओं को बच्चों को धर्म के संस्कार देने में आसानी होती है तथा 46 महिलाओं को बच्चों को धर्म के संस्कार देने में बहुत कम कठिनाईयों का सामना करना होता है।

अन्य धर्म को मानने वालों से सम्बन्ध

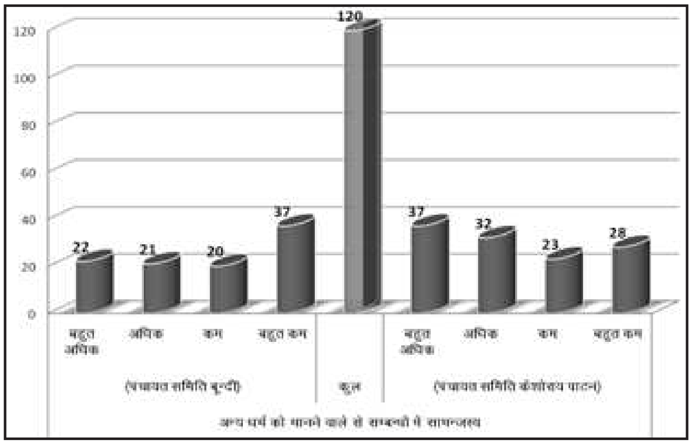

पंचायत समिति बून्दी से 120 शिक्षित महिलाओं में से 42 महिलाओं को अन्य धर्म को मानने वाले से सम्बन्धों में बहुत अधिक अवरोध आते है एवं 21 महिलाओं को अन्य धर्म को मानने वाले से सम्बन्धों में अधिक प्रयास करना होता है और 20 महिलाओं को अन्य धर्म को मानने वाले से सम्बन्धों में कम समस्याएँ आती है तथा 37 महिलाओं को अन्य धर्म को मानने वाले से सम्बन्धों में बहुत कम संघर्ष करना होता है। पंचायत समिति केशोराय पाटन से 120 शिक्षित महिलाओं में से 37 महिलाओं को अन्य धर्म को मानने वाले से सम्बन्धों में बहुत अधिक अवरोध आते है एवं 32 महिलाओं को अन्य धर्म को मानने वाले से सम्बन्धों में अधिक प्रयास करना होता है और 23 महिलाओं को अन्य धर्म को मानने वाले से सम्बन्धों में कम समस्याएँ आती है तथा 28 महिलाओं को अन्य धर्म को मानने वाले से सम्बन्धों में बहुत कम संघर्ष करना होता है। **साईमन** के अनुसार 'किसी न किसी प्रकार की अतिमानवीय एवं अलौकिक शक्ति में विश्वास है जिसका आधार विश्वास और श्रद्धा माना जा सकता है और जिसकी अभिव्यक्ति पूजा अथवा आराधना द्वारा होती है।'

सामान्यीकरण – प्रस्तुत अध्ययन के अनुसार दूर्खिम के सिद्धान्त को देखने का प्रयास किया गया है जिसमें यह ज्ञात होता है कि, हिन्दू ,मुस्लिम और जैन धर्म में अपने-अपने पवित्र कर्मकान्ड और वस्तुएँ होती है जैसे हिन्दू और जैन धर्म में मूर्तीयाँ और प्रतीक चिन्ह पवित्र होते है। मुस्लिमों में मूर्ती पूजा को अपवित्र और बूत परस्ती माना जाता है। हिन्दूओं और मुस्लिमों में कन्द-मूल भोज्य पदार्थ है और पवित्र भी माने जाते है जबकि जैन धर्म में ये अपवित्र और निषेध है। हिन्दू,मुस्लिम और जैन तीनों का समूह जीवन है एवं पृथक-पृथक है। तीनों धर्मो में पवित्र और अपवित्र वस्तुओं का अपना अलग से कोई धर्म से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। तीनों धर्मो को मानने वाले व्यक्ति मन में धर्म के बारे में कुछ भी मंथन करते हो सामूहिक अवस्था में उन्हे पवित्र एवं अपवित्र धारणाएँ एवं वस्तुओं में विश्वास दिखाना ही होता है।

निष्कर्ष –

- 29.9 प्रतिशत महिलाओं को धर्म एवं परम्पराओं के साथ बहुत अधिक सामन्जस्य करना होता है।
- 15 प्रतिशत महिलाओं को बच्चों को धर्म के संस्कार देने में बहुत अधिक सामन्जस्य करना होता है।
- 33 प्रतिशत महिलाओं को अन्य धर्म को मानने वाले से सम्बन्धों में बहुत अधिक सामन्जस्य करना होता है।
- 27.1 प्रतिशत महिलाओं को अन्य धर्म को मानने वाले से सम्बन्धों में बहुत कम सामन्जस्य करना होता है।

सुझाव –

- धर्म पर आधारित भेदों का सम्मान करना अन्य धर्मो के प्रति राज्य द्वारा तटस्थता बरतना ही धर्म निरपेक्षता है मुस्लिम महिलाओं के समाजीकरण में सम्मिलित किया जा सकता है।
- धर्म, पंथ और संविधान की शिक्षा विद्यालयों में दी जा सकती जिससे उक्त तीन शब्दों में अन्तर किया जा सके।
- सभी धर्मों में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा सकता है।
- महिला अधिकारों को मझबूत करके धर्म को मझाबूत किया जा सकता है।
- सभी धर्म के लोग आपस में विवाह कर प्राथमिक समूह का निर्माण कर सकते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. McKinnon, A. (2014). `Elementary Forms of the Metaphorical Life: Tropes at Work in Durkheim's Theory of the Religious'. Journal of Classical Sociology, vol 14, no. 2, pp. 203-221
2. Arvind Sharma (2002), On Hindu, Hindustân, Hinduism and Hindutva. Numen Vol. 49, Fasc. 1 (2002), pp. 1-36.
3. A Bhattacharya (2009), Applied Ethics, Center for Applied Ethics and Philosophy, Hokkaido University, ISBN 978-4990404611, pages 63-64

****

दिव्यांगता एवं सामाजिक पुनर्वास (सशक्तिकरण का माध्यम)

डॉ. ज्योति मेहता *

प्रस्तावना – दिव्यांगों के लिए पहले भी कई नाम दिए जाते रहे हैं बीच में इन्हें नि:षक्तजन कहां जाने लगा था। लेकिन चलन में नहीं आ पाया इसका कारण भी यही रहा कि किसी ने न तो इसे गंभीरता से लिया और नहीं कोई पहल हुई। नि:शक्तता के स्थान पर विशेष योग्यता वाले सम्बोधन शब्द की समाज से अपेक्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27.12.2015 में विकलांग की जगह पर एक सम्मान सूचक दिव्यांग शब्द के प्रयोग के निर्देष दिए थे। ये वे लोग हैं जिनके पास एक ऐसा अंग है या एक से अधिक अंग है जिनमें दिव्यता है। इन्हें समाज में दया नहीं बराबरी का मौका दिया जाना चाहिए।

इसमें पहले तो दिव्यांगो की समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक कर इमोशनल पहलू पर काम करना होगा कि दुनिया ऐसे लोगों को उनकी खूबियो (विशेष योग्यता) के आधार पर स्वीकार करें। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। दूसरे हमें समानता पर आधारित समाज बनाना हैं तो इसमें सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराने होगें। वर्ष 2011 की जनगणना में भारत में दिव्यांगो की संख्या 2.19 करोड़ है। जो देश की कुल आबादी का 20 प्रतिशत है। यह आबादी के लगभग 2.50 करोड़ है। इनमें पुरूषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। 75 फीसदी आबादी गाँवों में निवास करती है।

2011 की जनगणना में 8 प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी का उल्लेख है जिनमें दृष्टि असमर्यता से पीड़ितो की संख्या सर्वाधिक यानि 48.5 प्रतिशत है। जबकि पैरो से संबंधित असमर्थता 27.9 प्रतिशत मानसिक विक्षिप्तता 10.3 प्रतिशत बोलने में असमर्थ 7.5 प्रतिशत व श्रवण बाधित 5.8 प्रतिशत है।

दिव्यांगजनों के प्रति समाज का ध्यानाकर्षण करने उनकी समस्याओं की पहचान और उनके निराकरण हेतु समाज के प्रत्येक वर्ग का सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष 3 दिसम्बर को विश्व विकलांग दिवस का आयोजन किया जाता है। वैधानिक प्रावधान : भारत के संविधान में सभी व्यक्तियों की समानता स्वतंत्रता न्याय तथा गरिमा सुनिश्चित करता है तथा वह एक ऐसे समाज की स्थापना पर जोर देता है जिसमें दिव्यांग सहित सभी लोग रह सकें। संविधान इस विषय से जुड़ी अनुसूची में सीधे तौर से दिव्यांग व्यक्ति के सशक्तिकरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारो को देता है। संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत् केन्द्रीय सूची में इस बात का उल्लेख है कि भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम 1995 (समान अवसर अधिकारों की सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी बनाया। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है।) जम्मू कश्मीर सरकार ने विकलांगता अधिनियम 1998 (समान अधिकार, अधिकारों की सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) का गठन किया। बहुक्षेत्रीय समग्र प्रयासों के तहत् सभी संबंधित सरकारें जैसे केन्द्र सरकार के मंत्रालय राज्य सरकार केन्द्र शासित प्रदेश के केन्द्रीय तथा राज्य निकाय स्थानीय अधिकारी तथा अन्य समुचित अधिकारी इस अधिनियम के कई प्रावधानों का अनुपालन कर रहे है। भारत के फुल पार्टिसिपेशन एण्ड क्वलिटी ऑफ पीपल विद डिसैबलिटि इन द एशिया पेसिफिकरीजन घोषणा-पत्र का हस्ताक्षरकर्ता सदस्य है। यह विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन एण्ड प्रमोशन ऑफ राइटस एण्ड डिग्नेटी ऑफ परसंस विद डिसैबलिटी का भी 30 मार्च 2007 से ही इसका हस्ताक्षरकर्ता सदस्य है। भारत इस मुद्दे पर 1 अक्टूबर 2008 को हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का भी समर्थन करता है।

विभिन्न मंत्रालयोप विभागो में दिव्यांग लोगों के लिए उत्तरक्षण की स्थिति इस प्रकार है: समुह ए,बी,सी,डी, के लिए सरकार ने क्रमश: 3.07, 4.41, 3.76, प्रतिशत तथा 3.18 प्रतिशत आरक्षण दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में यह स्थिति इस प्रकार है – ए-समूह 2.78 प्रतिशत बी-8.54, सी-5.04 और डी-6.75 प्रतिशत है।

दिव्यांगजनो के सशक्तिकरण के लिए दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 उन्नीस अप्रैल 2017 से लागू किया गया। इस अधिनियम के अंर्तगत केन्द्रीय नियमों को 15 जून 2017 को अधिसूचित किया गया इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ : दिव्यांगता के प्रकारो की संख्या वर्तमान में 7 से बढ़ाकर 21 की गई है –

दिव्यांगता के प्रकार – 1. कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति 2. स्वलीनता स्पैक्ट्रम प्रकार 3. विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता 4. अभिवाक और भाषा दिव्यांगता 5. चिरंकालिक तंत्रिका स्थितियाँ 6. श्रव्य श्रीणता (बधिरता एवं सुनने में परेशानी) 7. बधिर नेत्रहीनता सहित बहुदिव्यांगता 8. बहु स्केलेरोसिस 9. सिक्कल कोशिका रोग 10. पर्किसंस रोग 11. बौद्धिक दिव्यांगता 12. मांस पेशिय दुर्विकास 13. ऐसिड़ हमले का शिकार 14. गति विषयक दिव्यांगता 15. नेत्रहीनता 16. बौनापन 17. निम्न दृष्टि 18. थेलेसीमिया 19. हेमोफीलिया 20. मानसिक रूग्णता 21. सेरेब्रल पल्सी।

दिव्यांगो का सामाजिक पुर्नवास – भारत में अब दिव्यांगों के चिकित्सकीय पुर्नवास के बदले सामाजिक पुर्नवास की नीति अपनाई जाती है। दिव्यांगो के लिए एपन.एच.एफ.डी.सी. नेशनल हेंडिकेप्ड़ फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने 1500 दिव्यांग स्टुडेंट्स के लिए स्कालरशिव की घोषणा की है। स्कालरशीप की मदद से ऐसे स्टुडेंट देश भर के किसी भी मान्यता प्राप्त एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से प्रोफेशनल या टेक्नीकल कोर्स कर सकेगें। इसका उद्देश्य ऐसे स्टुडेंटस को कौशल सीखना है जिससे उनकी रोजगार की संभावना बेहतर हो सकें कुल 1500 स्कालरशीप में से 30 प्रतिशत लड़कियों

* शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नाकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

के लिए रिजर्व रखी गई है इस प्रोग्राम में ट्यूशनस फीस और मेंटनेंस अलाउस भी कवर किया गया है। इसके तहत् स्क्रीन रीडिंग, साफ्टवेयर, बेक्र टाइप राइटर, हियरिंग एंड और मोबाईल फोन जैसी सहायक चीजें भी दी जाऐगी।

योग्यता – पर्सन्सविद, डिसएबेलिटिज (इक्वल अपार्च्यूनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फूल पार्टिसिपेशन) एक्ट 1995 और नेशनल ट्रस्ट फार टू वेलफेयर ऑफ पर्सनल विद आटिज्म, वेलफेयर सेरेब्रलपल्सी, मेंटल रिटाडेषन एण्ड मल्टीपल डिस ऐबे लिटिज एक्ट, 1999 के तहत् आने वाले भारतीय छात्र इस स्कालरशीप के पात्र होगें।

दिव्यांगो के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 – 1. नीति में कुछ विकलांगता जिन्हें रोकने का प्रयास किया जा सकता है रोकने के प्रयास पर बल दिया गया है। 2. नीति 3. प्रकार के पुर्नवास शारीरिक, शैक्षिक और आर्थिक पुर्नवास का उल्लेख करती है। आर्थिक पुर्नवास में उन्हें दिए जाने वाले आरक्षण का पूर्ण पालन करने का उल्लेख है। 4. निजि क्षेत्र रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनके कौशल विकास पर बल दिए जाने का उल्लेख है। 5. सरकार यह निश्चित करेगी की जिन पारियोजनाओं में महिलाएँ हो। 6. दिव्यांग बच्चों एवं युवाओं के खेलो एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ाने के प्रयास सरकार करेगी। 7. बंधन मुक्त माहौल के विकास पर बद दिया जाएगा। 8. दिव्यांगों को प्रमाण–पत्र अल्प अवधि में बिना किसी परेशानी के उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाऐगें। 9. दिव्यांगों के कल्याण में गैर सरकारी संठनों की भूमिका को बढ़ाने के प्रयास किए जाऐगें। 10. दिव्यांगजनों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का नियमित तौर पर आकलन करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

भारतीय पुर्नवास परिषद् – उसकी स्थापना 1992 में की गई थी उसके निम्ननिखित कार्य है – 1. पूरे देश में विभिन्न स्तरो पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का मानकीकरण और नियमन 2. दिव्यांगो के पुर्नवास के संदर्भ में देश के बाहर और देश में संस्थानों को विश्वविद्यालयों को उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए मान्यता देना। उनके पुर्नवास और विशिष्ट शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना। 4. पुर्नवास के क्षेत्र में मान्य योग्यता रखने वाले व्यवसायिक लोगों का एक केंद्रिय रजिस्टर रखना 6. पुर्नवास शिक्षा कार्यक्रम को जारी रखने को प्रोत्साहन देना।

राष्ट्रीय दिव्यांग पुर्नवास कार्यक्रम – ग्रामीण तथा दूरदराज के इलाकों में रहने वाले दिव्यांग तथा उनके परिवार के लोगों के पुर्नवास तथा सलाह सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय दिव्यांग पुर्नवास कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस योजना पर कार्य करने के लिए 82 जिलों को चुनाव किया गया है। इस योजना को राज्यों को सौंप दिया गया है क्योंकि ये राज्य क्षेत्र की योजना है।

दिव्यांगों के लिए कई योजनाएँ और छूट के प्रावधान भी किए गए है। इनके लिए सहायक उपकरण, छात्रवृत्ति, आर्थिक सहायता व अन्य कदम है। ए.डी.आई.पी.योजना के तहत् सहायक उपकरण खरीदने के लिए उन्हें सहायता दी जाती है। स्वैच्छिक सेवा के लिए दीनदयाल दिव्यांग पुर्नवास योजना भी है। दिव्यांगों के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरूस्कार भी दिया जाता है। निजी क्षेत्रों में भी उसके लिए रोजगार योजनाएँ है। उन्हें नौकरी व ट्रेनिंग के लिए नियक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाता है। उनके लिए यात्रा भत्ता तथा समान बीमा लाभ की भी व्यवस्थाएँ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. समाज कल्याण, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, 2010 भारत का संविधान , डॉ.जे.एन., पाण्डेय ।
2. नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का सरंक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995
3. विष्णुदत्त शर्मा, नारी और न्याय राम आहुजा, भारतीय सामाजिक व्यवस्था ।

****

आतंकवाद एक सामाजिक विश्लेषण

डॉ. रश्मि दुबे *

प्रस्तावना – आज विश्व रंगमंच पर जिस भयावह प्रसंग का अवतरण हुआ है वह है– 'आतंकवाद' जिसमें आज संपूर्ण विश्व को अपने आगोश में ले लिया है। इससे दुनिया के देश त्रस्त है सम्पूर्ण मानवता का अस्तित्व खतरे में है और यह खतरा लगातार बढ़ेगा क्योंकि हम तकनीक का इस्तेमाल मनुष्य की सृजनात्मक उर्जा को जागृत करने की बजाए उसको विकृत करने में लगे हुये हैं। यही कारण है कि नस्ली, मजहबी और सांस्कृतिक बर्चस्ववादी आंतकवाद बढ़ रहा है।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में आतंकवाद साम्राज्यवाद से सम्बद्ध दिखता है यदि राजनैतिक दृष्टि से विचार करके देखा जाय तो अमेरिका की दादागीरी आतंकवादियों के लिए प्रेरक सिद्ध हो रही हैं क्योकि इतिहास साक्षी है। अमेरिका ने स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए अन्य देशो को कमजोर बनाया है। सोवियत संघ, ईराक आदि इसके ज्वलंत प्रमाण है। आज भी अमेरिकी नीतियाँ शेष विश्व को कमजोर करने पर ही अधिक अवलम्बित है। आतंकवाद की अभी तक सर्वमान्य परिभाषा नही दी जा सकी है। समस्त राष्ट्रों का नेतृत्व करने वाला 'संयुक्त राष्ट्र संघ' भी आतंकवाद की सर्वमान्य परिभाषा स्थिर नही कर सका है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि आतंकवाद प्रजातंत्रीय समाजो को अस्थिर करने का मौका है। और यह ये प्रदर्शित करता है कि सरकारे शक्तिहीन है। सामान्य रूप से आतंकवाद का सम्बन्ध कतिपय स्वार्थी, बर्बर संकुचित मानसिकता वाले व्यक्तियों द्वारा निर्दोश व्यक्ति या जनसमूह को भय के वातावरण मे घेरकर वाधित करना, शान्त परिसर को उग्रवादी विस्फोटो के द्वारा निरपराध व्यक्तियों की हत्या करना बेगुनाहों को डराना, मारना, असुरक्षा की भावना का निर्माण करना जनसंहार साम्प्रदायिकता एवं क्षेत्रवाद पर आधारित है। इसका उद्देश्य राजनीति से प्रेरित तीव्र हिंसा का प्रयोग है। जिसके द्वारा निरपराध लोगो और सम्पत्तियों को नुकसान पहुँचाना है। अर्थात वह व्यक्ति या संगठन जो अपने किसी लक्ष्य पर लोगो का ध्यानाकर्षण के लिए हिंसक तरीको का इस्तेमाल करता है आतंकवादी है।

भारत के लिए यह उचित समय है जब आतंकी बर्बरता के खिलाफ सम्पूर्ण राष्ट्र को एकजुट किया जाए। एकजुटता ऐसी हो जिससे आतंकवादी को ही नही वरन उनके समर्थको एवं संरक्षणदाताओं को भी बेपर्दा किया जा सके। आतंकवाद मुख्यत: कुछ व्यक्तियों के एक समूह द्वारा लोगो निजी या सर्वजनिक सम्पति, सुविधाओ के खिलाफ किया गया अपराधिक कार्य है। आतंकवाद का लक्ष्य दहशत फैलाना है। ताकि आम जनता मे इतना भय पैदा हो जाये कि वह सरकार की क्षमता पर शक करने लगे। वर्तमान समय मे आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है। जिसके समाधान में मजबूत राष्ट्र अमेरिका से लेकर एक कमजोर राष्ट्र तक अक्षम है। आतंकवादी दहशत फैलाकर अपनी सफलताओं से उत्साहित होकर पहले से भी ज्यादा आक्रामक होकर कार्यवाही करते है। व्यापक अर्थो में आतंकवाद की व्याख्या अच्छी तरह प्रशिक्षित, हथियार बन्द व जबरदस्त प्रेरणा वाली आदृश्य सेनाओं द्वारा किया जाने वाले विध्वंसकारी कृत्य के रूप मे की जा सकती है। जिसका अत्याधिक शक्तिशाली व प्रभावशाली होना एक चौकाने वाला पहलू है। देश चाहे जो भी हो आतंकवादी वही एक जैसा गति, कार्यप्रणाली का प्रायोग करतें हैं। जैसे विमान अपहरण राजनेताओ का अपहरण सार्वजनिक मुख्य इमारतों व धार्मिक स्थल पर बम ब्लास्ट इत्यादी आतंक और हिंसा कमजोर लोगो के अस्त्र है ये संख्या मे कम होते है। और उन केन्द्रो को शिकार बनाते है। जो देश की राजसत्ता या गौरव के प्रतीक होते है। जैसे अमेरिका मे विश्व व्यापार संगठन, भारत मे होटल ताज, ओबराय इत्यादि। आतंकवाद वर्तमान समय मे राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाने वाली नियोजित हिसा का एक विशेष रूप है।

समाज विज्ञान विश्वकोष में 'आतंकवाद' को एक ऐसा तरीका बताया गया है। जिसके द्वारा कोई संगठित समूह अथवा दल अपने उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए हिंसा का योजनाबंद्ध रूप से प्रयोग करता है। जबकि 'नोएल ओ सलीवन' नें आतंकवाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि– 'राजनीतिक आतंकवाद उस समय जन्म लेता है जब कोई समूह चाहे वह सत्ता मे हो या सत्ता के बाहर बैचारिक उद्देश्यो को मनवाने के लिए ऐसे तरीको को अपनाता है। जो न केवल अमानवीय होते है अपितु घरेलु एवं अन्तराष्ट्रीय कानूनो की भी अनदेखी करते है। तथा जो अपनी सफलता हेतु प्राथमिक तौर पर धमकी या हिंसा के प्रयोग पर निर्भर रहते है। इसके अतिरिक्त आतंकवाद एक ऐसा तरीका है। जिसके द्वारा एक संगठित समूह अथवा दल अपने प्रकट उद्देश्यो की प्राप्ति मुख्य रूप से हिसा के योजनाबद्ध उपयोग से करता है।

आतंकवाद आज समूचे विश्व मे एक बहुत गंभीर समस्या के अतिरिक्त यह एक कड़ी चुनौती भी है। आतंकवाद जैसी अमानवीय एवं कूट घटनाओ से आज विश्व का कोई भी देश अछूता नही है। धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक भाषायी ऐसी कई प्रकार के या इनमे से कुछ भी कारण हो सकतें है। जिससे व्यक्ति विशेष प्रकार का दल या समूह बनाकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है। जिससे कई प्रकार की हानियाँ होती है। आंकडो से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है।

कुछ महत्वपूर्ण आंतकवादी घटनाएं **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

पिछले सालो मे घटी आतंकवादी घटनाओ से यह तो स्पष्ट है कि देश का कोई भी कोना इन घटनाओं से अछूता नही है लेंकिन हमे इसको कम करने और समाप्त करने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए।

* प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोतर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है इसलिए इसका निदान भी वैश्विक होना चाहिए। इस सन्दर्भ में त्रि–स्तरीय रणनीति बनाई जाना समीचीन है–प्रथम, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ एक सुरक्षा प्रहरी की भूमिका निभाए तथा आतंकवाद की रोकथाम हेतु सकारात्मक निर्णय लिए जाएं तथा आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले देशो का अन्तार्राष्ट्रीय समुदाय से पूर्णतया वायकॉट किया जाये दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राष्ट्र यह प्रतिज्ञा करें कि वह आंतकवाद से लड़ने के लिए कटिबद्ध है तथा अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए न तो आंतकवाद को बढ़ावा देगा और न ही आश्रय–स्थल बनने देगा, अगर कोइ देश जानबूझकर ऐसा करता है, तो उसके विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रीय मोर्चाबन्दी की जाए तीसरे स्तर पर व्यक्ति की भूमिका नहीं होगा इसका समाधान सम्भव नहीं है इसलिए हर व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने आस–पास की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे। और आत्मसंतुष्टि की नीति त्यागकर बिना कुर्सी मोह के देश हित मे राष्ट्रीय भावना के साथ कार्य किया जाए। और आतंकवाद उन्मूलन जैसे बलो का गठन किया जाना चाहिए। अपने देश मे ही जनता का दिल जीता जाना चाहिए। बिना इसके दुश्मन पर विजय नही पायी जा सकती। अर्थात सर्वप्रथम सार्थक निष्पक्ष नीतियाँ बनाकर देश मे बिना किसी पक्षपात के लागू कर उनका लाभ जनता को पहुचाया जाना चाहिए जिससे उनके अन्दर असन्तोष न पनपे और विदेशी ताकतें अपने मन्सूबो को पूरा ना कर सके। जब हमारे नागरिक सन्तुष्ट होगे तो वे दुश्मनो का साथ नही देगे। और उन्हे हमारी सीमाओ मे रहते हुए फलने–फूलने की परिस्थितियाँ उनलब्ध न हो सकेगीं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव – आतंकवाद का समकालीन परिदृश्य, ओमेगा पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2011
2. इंडिया टुडे – दिसंबंर –2008
3. सिंह नौनिहाल – द वर्ल्ड टैररिज्म, साउथ एशिया पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1989
4. मधु सूदन त्रिपाठी – राष्ट्रीय एकता और आतंकवाद, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008
5. मानचंद खंडेला – अन्तराष्ट्रीय आतंकवाद, अविष्कार पब्लिशर, जयपुर, 2002

कुछ महत्वपूर्ण आंतकवादी घटनाएं –

1	1 January 2008	Rampur UP lashkar-e- Taiba	Uattar Pradesh
2	May 13 2008	Jaipur bombings 9l bomb blasts along 6 areas in JaIpur Jaipur (Rj.)	
3	July 25 2008	2008 Bangalore serial blasts 8 low intensity bomb blasts in banglore	Bangalore
4	July 26 2008	Ahmedabad Bombings 17 serial bomb blasts in Ahmedabad	Gujrat
5	Septamber 13 2008	Delhi bombings 5 bomb blast in Delhi markets	Delhi
6	Sep 27 2008	Delhi Bombing : Bombing at mehrauli area , 2 bomb blasts in Delhi flower market	Delhi
7	sep 29 2008	Western india bombing: 10 killed and 80 injured in bombings in maharashtra (Including malegaon and Gujrat bomb blasts)	Maharastra
8	Oct 1 2008	Agartala Bombings	Agartala
9	Oct 21 2008	Imphal bombing	Imphal (Madupur)
10	Oct 30 2008	Assam bombings	Assam
11	Nov 26	Mumbai Attacks	Mumbai
12	January 1 2009	Guwahati Bombings	Assam
13	6 April 2009	Assam Bombings	Assam
14	Ferbruary 13 2010	Pune bombing	Pune
15	7 Dec 2010	Varanasi bombing	Varansi
16	July 13 2011	Mumbai bombings	Mumbai
17	Septa 7 2011	Delhi bombing	Delhi
18	February 13 2012	Attacks on israeli diplomats	Delhi
19	Feb 21 2013	Hyderabad blasts	Hyderabad
20	March 13 2013	Shrinagar Attack	Jammu and Kasmir
21	Oct 27 2013	Patna bombing	Patna
22	April 25 2014	Blast in jharkhand	Jharkhand
23	March 20 2015	Jammu attack	Jammu and kasmir
24	July 27 2015	Gurdaspur attack in dina nagar gurdaspur district	
25	January 2 2016	Pathankot attack in pathankot air force station pthankot	Punjab
26	Aug 5 2016	Terrorist attack in the market area Bulajan Tinali of the city of kokrajhar by three terrorists suspected to be bodo militants using ak-47 and used a grenude	
27	Sep 18 2016	Uri attack	Uri J&k
28	Oct 3 2016	Baramulla attack	Baramulla J&K
29	Oct 6 2016	Handwara attack at rashtyriya rittles camp	Handwara J&K
30	Nov 29 2016	Nagrota attack	Nagrota J&K

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

गन्दी बस्ती में स्थित आवासों में उपलब्ध सुविधाओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (होशंगाबाद जिले के संदर्भ में)

कंचन ठाकुर *

प्रस्तावना – नगरीय और औद्योगीकरण ने जहाँ व्यक्ति को विज्ञान, शिक्षा, तकनीकी ज्ञान और एक अच्छी वैज्ञानिक समझ दी है, वहीं करोड़ों व्यक्तियों को नारकीय जीवन व्यतीत करने के लिये भी विवश किया है। नारकीय जीवन को मलिन बस्तियों मे देखा जा सकता है। एक छोटी-सी झोपड़ी, कच्चे मकान अथवा कोठरी में 10 से 15 व्यक्ति तक रहते हैं। इन बस्तियों में एक झुग्गीवासी को इतना भी स्थान नहीं मिलता कि वह वहाँ खाना बना सके रात में सो सके और अपना खाली समय व्यतीत कर सके। जल के निकास का यहां कोई प्रबंध नहीं होता है। पानी यहां सड़ता रहता है। कूड़े-कचरे का ढेर यहां लगा रहता है। शौच आदि जाने के लिये यहां कोई स्थान नहीं होता है। बैठने के लिये इनके पास कोई खुला स्थान नही होता हैं। तंग-संकरी मलिन बस्तियां जहां जीवन कम और बीमारियां अधिक पाई जाती हैं। पीले, मुरझाये चेहरे, चिपके गाल, उभरती हड्डियां, फटे-गन्दे कपड़े यहां की पहचान होती है। इन्हें पता नहीं कि ये कब जवान हुए और कब बूढ़े हो गए। ये टी.बी. व कैंसर से ग्रस्त होते है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो मौत के मुंह में जन्म लेते हैं। इनका जिन्दा रहना और मरना जैसे समाज के लिये कोई मायने नहीं रखता।

आवास की समस्या ने नई मलिन बस्तियों के स्थापित होने में जहां सहायता की है वहीं असंख्य जर्जर मकान जिन्हें छोड़कर व्यक्ति अच्छे मकानों मे चला गया है, ये जर्जर छोड़े हुये घरों में दोबारा असंख्य निर्धन-व्यक्ति रहने लगे हैं जिसने मलिन बस्ती का रूप धारण कर लिया है। इस तरह नई मलिन बस्तियां स्थापित होती जा रही है। और पुरानी मलिन बस्तियों के निर्धन व्यक्ति इसलिए उसे नही छोड़ते कि इससे सस्ता घर नगर मे कही उसे उपलब्ध नहीं होता है।

भारत में ऐसी मलिन बस्तियां नाले, नदी, रेलवे लाइन की पटरियों आदि स्थानों पर सरलता से देखी जा सकती है। मलिन बस्तियों के लिये कोई निश्चित पर्यावरण निर्धारित करना कठिन है। ये कहीं भी विकसित हो सकती है।

प्रत्येक देश की मलिन बस्तियों का अपना-अपना स्वरूप है, किन्तु उसका पर्यावरण और रहने की दशायें लगभग एक समान हैं। इनमें निवास करने वाले व्यक्ति निर्धन, बेरोजगार, नशाखोर, बीमार, विभिन्न छोटे-बड़े अपराधों में लिप्त और कम आय वाले व्यक्ति हैं जिनका न कोई मकान है और न मकान होने की आशा हैं।

उपकल्पना –

- गन्दी बस्तियों के आवासों मे सुविधाओं का आभाव पाया गया है।
- अधिकांशता: गन्दी बस्ती में निम्न आर्थिक जीवन स्तर के तथा श्रमिक वर्ग निवास करते है।
- गन्दी बस्तियों के आवासों के स्वरूपों में भिन्नता दिखाई देती है।

उद्देश्य – प्रस्तुत शोध अध्ययन होशंगाबाद जिले की गंदी बस्तियों में स्थित आवासों में उपलब्ध सुविधाओं के सामाजशास्त्रीय अध्ययन पर आधारित है। जिसके अंतर्गत –

हाशंगाबाद जिले में आवासों में उपलब्ध सुविधाओं को ज्ञात करना उक्त शोध का मुख्य उद्देश्य है।

गन्दी बस्ती मे रहने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।

गन्दी बस्ती में निवासित परिवारों को शासन द्वारा मिलने वाली प्राप्त सुविधाओं का पता लगाना उक्त शोध का उद्देश्य है।

अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन प्रविधि – प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिये होशंगाबाद नगर की गंदी बस्तियों का चयन किया गया है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित होशंगाबाद नगर एक धार्मिक स्थल के रूप में विख्यात है जहां धार्मिक पर्वो पर भारी संख्या में अधिकांश दर्शानार्थी यहां आते है। तथा स्नान करते है। यह स्थल धार्मिक रूप से ही प्रसिद्ध नही बल्कि कृषि के क्षेत्र मे भी काफी विकसित है। इसके आसपास के ग्रामों एवं जिलों में निवास करने वाले भूमि हीन श्रमिक रोजगार एवं मजदूरी की तलाश मे यहां गेहू, धान, सोयाबीन आदि की कटाई के लिये आते है। यहां कुछ श्रमिक स्थाई रूप से रहने लगते है। तथा कुछ अपने निवास स्थान पर वापस लोट जाते है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। परंतु जो यहां स्थाई रूप से रोजगार शिक्षा एवं मजदूरी के लिये संयुक्त रह रहे है। उनके आवास पूर्ण सुविधाओं से वंचित है। क्योंकि बाहर से आने के कारण उन्हें असुविधाओं गन्दी बस्तियों मे छोटे-छोटे कमरों में रहना पड़ता है।

होशंगाबाद जिले मे ऐसे क्षेत्र ग्वालटोली, आनंद नगर वस्ती, पिचिन बस्तियां आदि है। जहां होशंगाबाद जिले के लगभग 150000 परिवार इस नरकीय वातावरण मे जीवन व्यतीत कर रहा है। यहां अधिकांश निम्न आय प्राप्त परिवारों की संख्या अधिक है जो दैनिक मजदूरी श्रम आदि करते है। इनका आर्थिक स्तर भी निम्न है।

प्रस्तुत शोध मे प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों के संकलन के लिये अवलोकन साक्षात्कार देव-निदर्षन विधि का प्रयोग कर प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया है। देवनिदर्शन विधि द्वारा होशंगाबाद जिले की तीन गन्दी बस्तियां ग्वालटोली, पिचिन बस्ती, एवं आनंद नगर बस्तियों मे से 100-100 इकाईयों को चयन कर कुल 300 इकाईयों द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया है।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष – प्रस्तुत अध्ययन में प्राप्त तथ्यों के आधार पर जो विष्लेषण किये गये है, उनके आधार पर गन्दी बस्तियों में सुविधाओं का

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय गृह विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.) भारत

आभाव पाया गया है। क्योंकि अधिकांश परिवार के लोगों की मासिक आय 101-200 रूपये प्रतिदिन है जो पूरे परिवार के लिये न काफी है। प्राप्त आय केवल भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है।

इन परिवारों की व्याप्त सुविधा संबंधी तथ्य यह दर्शाते है कि यहां रसोई घर एवं नहाने की व्यवस्था सभी घरों में है परंतु शौचालय की सुविधा शून्य मात्र है। पानी की पर्याप्त सुविधा है परंतु गन्दे पानी की निकासी के लिये नालियों की व्यवस्था नही पाई गई। जिससे गंदगी का प्रभाव बना रहता है। एवं अनेक बिमारियां मलेरिया, टायफाइड, डेंगू, टी.बी. आदि बिमारियां पाई गई है। बरसात मे यहां जीवन व्यतीत करना अंसभव है। फिर भी ये जीवन जीने के लिये मजबूर है।

इन्हें इस नरकीय जीवन से छुटकारा दिलाने के लिये शासन का ध्यान इनकी तरफ आकर्षित करना पड़ेगा इनके लिये सर्वप्रथम रोजगार के साधन एवं शिक्षा तथा प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाये ताकि इनका आर्थिक जीवन ऊँचा उठ सके।

इस गंभीर आवासीय समस्याओं से निपटने के लिये कम लागत के मकान बनाकर दिये जाये ताकि वे अपना शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास कर सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आहुजा राम 'सामाजिक समस्याएं', बावत् पब्लीकेशन जयपुर, 2009।
2. गुप्ता एम.एल., शर्मा, डी.डी., 'ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र, साहित्य भवन, पब्लिकेशन आगरा 2012।
3. मुखर्जी रविन्द्रनाथ, 'सामाजिक शोध एवं सांख्यकीय' विवके प्रकाशन, दिल्ली 2009

****

Effect Of Examination Anxiety And Hypnotherapy On Students

Dr. Bharti Joshi* Dr. Nitendra Singh Rajput**

Abstract - Most students are afraid of examinations, but examinations are very important today. They are also very interesting. Examinations are important because they compel students to learn without them most students would not learn. So they would know very little about the world. They would teach only subjects in which they are interested and ignore the other subjects which are thought to be difficult, though they are very important in the modern age. Exam anxiety is a psychological condition in which a person experiences distress before, during, or after a test or other assessment to such an extent that this anxiety causes poor performance or interferes with normal learning. Hypnosis is a mental state (state theory) or set of attitudes and beliefs (non-state theory) usually induced by a procedure known as a hypnotic induction, which is commonly composed of a series of preliminary instructions and suggestions.

Key Words - Anxiety, Examination, Hypnosis, Learning, Performance.

Introduction - The most exciting day in the life of a student is the day during the final examination for class promotion. He prepares himself well for about a month before the examination and still he has fears and hopes on the day of the examination. Even a student who neglects his lessons sits up to make his eleventh hour preparation. A student who studies hard may feel confident once inside the examination hall for the first paper. Every student is anxious to know whether the question papers would be difficult or not, except a few who do not take their question papers would be difficult or not, except a few who do not take their lessons seriously. Most of the students eagerly look forward to the examination day. Unlike the other days, examination days are usually quiet. Everyone seems to browse his notes for the last time before going into the hall. Every minute seems precious before the bell goes as it provides the last chance to check the facts properly. Sometimes the last minute reading may help you to score marks. It is indeed a day of excitement to every child who takes his or her lessons seriously. Life today has become so complex that examinations have come to play an important part in one's educational career. Examinations are considered so important that most students are afraid of them.

An examination, commonly known as exam, is a test to see how good somebody is at something . In its widest sense, to examine somebody or something is to look at it very carefully, perhaps to find out why something is not working properly. Someone who is ill may need to go to a doctor to have a medical examination. In education examination is a test to show the ability and knowledge of a student. In examination there are two important thing first candidate and second examiner.

A student who takes an examination is a candidate. The person who decides how well the student has performed is the examiner. An examination could be a written test, an on-screen test or a practical test. Examples of a practical test may be: playing a musical instrument, driving a car, speaking a language, & doing a scientific experiment. An on-screen test is a test which uses the computer.

Examination Anxiety - Terms like anxiety, intelligence, and motivation are abstract constructs which have been advanced to make various facets of performance, comprehensible. For example, we may attribute a student's excellent performance in classroom examination to his superior intelligence or we may interpret their poor performance in terms of motivation concept such as anxiety, which interferes or facilitates with academic achievement. Exam anxiety is a psychological condition in which a person experiences distress before, during, or after a test or other assessment to such an extent that this anxiety causes poor performance or interferes with normal learning.

Definitions of Examination anxiety - According to Lali (1997), Examination anxiety is a factor that is for more harmful than general anxiety, Hence it is ideal that when classroom tests are conducted there must be clear attempt to

*Associate Professor (Lifelong Learning) Devi Ahilya University, Takshshila Parisar, Kahandwa Road, Indore (M.P.) INDIA
**Corporate Trainer, Pandit Ventures PVT Ltd. , 9th Floor, Sambhav House, Premchand Nagar, Bodakdev, Ahmadabad (Gujrat) INDIA

minimize this form of anxiety.

According to Dickson, ken(2009), Exam anxiety is excessive worry about upcoming exams, fear of being evaluated, apprehension about the consequences, experienced by many normal students, not mysterious or difficult to understand, manageable by following a plan of helpful suggestions. There are four main areas which can contribute to exam anxiety: lifestyle issues, information needs, studying styles, psychological Factors . Lifestyle issues that can contribute to exam anxiety are inadequate rest, poor nutrition, too many stimulants, Insufficient exercise, not scheduling available time, not prioritizing commitments**.**

Test anxiety has been overwhelmingly identified as a two-factor construct, consisting of the cognitive (often referred to as "worry") and emotional (or affective) components (Morris, Davis, & Hutchings 1981, Schwarzer 1986). Test anxiety is an important predictor of academic achievements. Sgoutas-Emch , et al. (2007)

Symptoms of Examination Anxiety - Some students may experience symptoms of test anxiety. They believe that the knowledge they bring to a test (resources) will be inadequate to perform to their desired level. This generates added stress and anxiety, which may become overwhelming for some students. When anxiety begins to affect exam performance it has become a problem.Prior to, or during an exam, as in any stressful situation, a student may experience any of the following changes -

Physiological	Emotional	Cognitive
Perspiration	Fear of failure	Decreased ability to make decisions
Indigestion, vomiting	Helplessness	Memory loss
Headache	Frustration/ anger	Limited attention span
Trembling/Dizziness	Shame/guilt	Inability to concentrate
Rapid heart beat	Doubt/ hopelessness	Mental distraction
Tense muscles, tics	Anxiety/panic	Procrastination
Poor sleeping habits	Tearfulness	Catastrophizing

Causes of the examination anxiety - Exam anxiety can develop for a number of reasons. There may be some prior negative experience with test taking that serves as the activating event. Students who have experienced, or have a fear of, blanking out on tests or the inability to perform in testing situations can develop anticipatory anxiety. Worrying about how anxiety may affect oneself can be as debilitating as the anxiety itself. There are many reasons which can trigger the examination anxiety.

- Lack of preparation can contribute to test anxiety. Poor time management, poor study habits, and lack of organization can lead to a student feeling overwhelmed.
- Lack of confidence, fear of failure, and other negative thought processes may also contribute to test anxiety. The pressure to perform well on exams is a great motivator unless it is so extreme that it becomes irrational.
- Perfectionism, low self-esteem, and feelings of unworthiness provide unreasonable goals to achieve through testing situations. When a student's self-esteem is too closely tied to the outcome of any one academic task, the results can be devastating. In these situations, students may actually spend more time worrying about the test than actually studying for it.
- Psychological Factors- Feeling no control over the exam situation (rather than knowing and applying exam strategies), Negative thinking and self-criticism (rather than being one's own best friend), Irrational thinking about exams and outcomes, Irrational beliefs "If I don't pass my (parents/partner/boss) will kill me!" Irrational demands "I have to get 100% or I am worthless." Catastrophic predictions "I'll fail no matter what I do."
- Biological Causes of exam anxiety in stressful situations, such as before and during an exam, the body releases a hormone called adrenaline. This helps prepare the body to deal with what is about to happen and is commonly referred to as the "fight-or-flight" response. Essentially, this response prepares you to either stay and deal with the stress or escape the situation entirely. In a lot of cases, this adrenaline rush is actually a good thing. It helps prepare you to deal effectively with stressful situations, ensuring that you are alert and ready. Symptoms such as nausea, sweating and shaking hands can actually make people feel even more nervous, especially if they become preoccupied with test anxiety symptoms.

Hypnotherapy - When a hypnotist use the hypnotism for therapeutic purposes is referred to as "hypnotherapy". Induction of hypnosis and its deepening consist of facilitating an inward focusing of attention, which largely depends upon the motivation, hypnotisability and emotional state of the subject himself rather that the ability of hypnotist. The real skill of therapy through hypnosis is in proper understanding of the psychopathology of the patient's or client's symptoms and his personality, developing immediate and long tern goals and then presenting proper ideas (suggestions) and images to achieve therapeutic gains. When used with the total management approach to a patient, hypnosis establishes a climate for the healing precisely because

Hypnotherapy as a Psychotherapy - Hypnotherapy is the use of hypnosis in psychotherapy. It is used by licensed physicians, psychologists, and others. Physicians and psychiatrists may use hypnosis to treat depression, anxiety, eating disorders, sleep disorders, compulsive

Hypnosis has been defined as the altered state of consciousness and heightened responsiveness to suggestions. During the hypnotic sessions positive suggestions are given to build confidence and eliminate the exam fear. Through hypnosis they can learn that how they can relax themselves before or during examination period and how they can increase their self-concept positively and emotional strength. These positive changes

will also be helpful to increase their intelligence. The present study is an humble attempt to understand the effectiveness of the hypnotherapy as a method to effectively deal with teenager's mental health issues. Our sense of self, our intelligence, and the mental and social health of our nation, suffer when person miss any of the required steps of emotional experience. Greenspan disagrees with the theories of Kant and Piaget, but amplifies Freud's, to show the overriding importance of emotions ("lived experience") in the development of intelligence.

Hypnosis is a powerful state for facilitating emotional and physiological change. Self-hypnosis session can have health benefits and an ongoing influence on self-trust and emotional balance, Saltz (2008). A poor self-image is by far the most damaging set of beliefs that any person can hold. Holding onto a negative self-image can damage person's life in immeasurable ways. However it can be changed through the specific auto suggestions with the help of hypnotherapy and transform into a positive, strong self image like a person is capable, loving, and strong and destined to succeed, Palan (2003). Person can literally achieve anything which he set in his mind with the help of hypnosis. In the present research researcher will find whether specific designed hypnotherapy session will influence the mental health and reduce the level of examination anxiety of the students or not.

Studies related to Examination Anxiety and Hypnosis - Zhao et al, (2015) studied effect of hypnosis on psychological stress and anxiety. The study revealed a significant improvement due to hypnotherapy in anxiety and stress of students. The study utilized a 2 (gender: male vs. female) × 2 (hypnosis mode: AR hypnosis vs. ordinary hypnosis) between-groups experimental design. Taqavi & Pourasghar, (2015) studied on to assess the effectiveness of hypnotherapy on self concept, self efficacy and exam anxiety. Exam anxiety is associated with interferences with the educational exam, leading to poor results and even school abandon. Hypnotherapy could increase the quality self concept, self efficacy and decrease exam anxiety in students. Random sampling method was used and a 20 subjects sample resulted, which was evenly split into two groups, experiment ($n = 10$) and control group ($n = 10$). The experiment group was placed under hypnotherapy treatment for 6 sessions. The Delavar self-concept, Bandora self-efficacy, and exam anxiety Inventory were used, in order to obtain data from participants. The post - test results between the experimental and control group showed statistically significant differences for self-concept ($F = 6.944$, $P<0.05$), self-efficacy ($F=11.25$, $P<0.05$) and anxiety ($F=23{,}002$, $P<0.05$), respectively. The results indicate that hypnotherapy has positive effects on self-concept, self-efficacy and exam anxiety, in guidance school students.

Kumar and Jena (2013) studied on effect of Clinical Hypnotherapy on Anxiety Symptoms. Studied aim to use Clinical Hypnotherapy as an intervention strategy to help patients diagnosed with Anxiety symptoms. This study was conducted with 7 college students, pursuing Ph.D. from University of Delhi, South Campus of the age group 20 to 30 years who scored 14 and above on the Hamilton Anxiety Rating Inventory. Clinical hypnosis was used as an intervention strategy. Results were that the t-test score of 6.3454 revealed that the pre and post intervention scores attained by the intervention subjects on the toll were significant at 95% level of significance. This study demonstrated how the use of Clinical hypnotherapy is an effective intervention strategy to help patients diagnosed with anxiety symptoms.

Mathur and Khan (2011) found in their study of 10 children age 13 and 14, anxiety and scholastic achievement scores were obtained before and after hypnotherapy intervention. Where pre-test anxiety scores ranged from 80-92% while post-test anxiety scores dropped to 60-68%. **Pre-test academic scores** ranged 50-57% while post intervention scores increased by 10-15%.which indicated that hypnotherapy as treatment intervention proved to be effective in reducing exam anxiety and improving scholastic performance among children.

Hypnotherapy is used to treat a range of anxiety disorders. A systematic review by Baker, Ainsworth, Torgerson and Torgerson (2009) showed that hypnotherapy is effective in reducing exam anxiety; however it was only able to locate five small randomized controlled trials. A full scale randomized trial is therefore needed to assess whether hypnosis is effective in both reducing exam anxiety and in increasing exam performance. The purpose of this pilot trial was, therefore, to investigate the acceptability of such a trial to both participants and examination providers, and the feasibility of conducting a full scale trial.Participants, all first year nursing students, were randomized to receive hypnotherapy sessions preceding a numeracy test or to a control group which did not receive hypnotherapy. Results were that two thirds of participants approached to take part in the pilot trial agreed to take part and remained in the trial until completion. The two main reasons expressed for not taking part included not wanting to be hypnotised and not feeling anxious about the exam. Attendance at the hypnotherapy sessions was high and almost all those who received hypnotherapy reported that they found it helpful and useful. Olatoye and Afuwape (2003), Hurlock (1972), test anxiety is the psychological state of mind of a candidate about a test as expressed by the level of worry, fear, uncertainty, concern and helplessness expressed before, during or even after a test.

Although theories of test anxiety provide important insights regarding the process like interference model, deficits model, or information processing model by which test anxiety affects performance, much of the research on test anxiety has focused on the differential impact of emotionality and worry factors of test anxiety on performance (Cassady, & Johnson, 2002; Hembree, 1988) Gail Brown et al. (1997) found that hypnosis is a therapeutic

procedure that is appropriate for some school-age clients. Clinical applications of hypnosis in the school setting include treatment of test anxiety, problems with studying and concentration, phobias, sleep disorders, social skills training, anxiety, pain, bulimia, enuresis, etc. Through the use of hypnosis that utilizes metaphors and imagery, children can be empowered to find unique solutions to their problems.

A study by Stanton (1993) on effect of hypnotherapy session on examination anxiety revealed similar results. In this study, they were seen individually for two, 40-50-minute sessions of hypnotherapeutic training designed to engender an increased confidence in their ability to overcome examination anxiety. Two outcome measures were used: the actual examination result and a face-valid attitude scale, the Examination Anxiety Thermometer. On the first of these, 10 of the 11 practitioners recorded passes, whereas on the second, 9 indicated an attitude change toward lower levels of test anxiety. Attention is drawn to the minimal expenditure of time involved in the treatment and the generalizability of the hypnotherapeutic technique to other areas of the practitioners' lives.

Palan & Chandwani (1987) studied "Coping with Examination Stress through Hypnosis: An Experimental Study". Fifty-six volunteer medical students participated in three groups balanced for number of subjects, performance at last examination, and hypnotizability. The hypnosis and waking groups attended eight group sessions once a week with general ego-strengthening and specific suggestions for study habits, with a ninth session of age progression and mental rehearsal. Subjects in these two groups practiced self-suggestions (in self-hypnosis or waking respectively) daily for the study period of 9 weeks. The control group experienced sessions of passive relaxation induced by light reading for the same period of time. The hypnosis group improved significantly in coping with examination stress.

Recommendation - India has various kind of structure in school education as private schools and public schools. Hypnotherapy can be compared to other traditional methods prevalent in the Indian schools, for example counseling method is one the prior method which is used to deal with these kinds of problems. So counseling method can be compare with the hypnotherapy method to see the effectiveness of the method in school settings.

Benefits for Students - Hypnosis can help to reduce exam anxiety in students .Exam anxiety can cause serious illness in students like, high blood pressure, obesity and sleep disorders. If students have a lot of exam anxiety and pressure in their life, then there will be constantly in a high alert state then one of the benefits of hypnotherapy would be learning some simple relaxation and self hypnosis techniques that can reduce this exam anxiety or stress because hypnosis involves putting you in a deep state of relaxation it gives your mind and body a chance to recuperate, repair and heal itself by experiencing the relaxation that it desperately needs in present social context and environment.

Benefits for Parents - Present time parents also take interest in the problems of their children. This kind of research gives an extra advantage to see the other alternative solutions of their children's problem. Self Hypnosis can help parents to reduce their worry related to their children's exam performance, and parents can use the positive affirmation for their children to improve their performance.

Benefits for Administration and Teachers - School administration can involve hypnotherapy in their school schedule and provide the session to all the students before the examination so they can get the better performance from the students. Generally, teachers in the day to day classroom interaction find many students who are facing mental health problems. Teacher in the light of present research can understand the problems of the students and can further try to guide students and parents to solve their problems. The results of the present study can be guiding line for teachers who are pillars of a school system.

Benefits for Policy Makers - Hypnotherapy are a part of alternative therapy which generate harmony in mind, body and behavior and there is no side effect of it. When policy maker is considering about the society welfare then they can involve hypnosis as a very good tool for improving the mental health of the society.

a. School counselor should learn the hypnotherapy so they can use it as a therapy tool instead of doing just counseling.

b. Govt. school should appoint the certified hypnotherapist in the school so they can improve the mental health of the students through the hypnosis techniques. It will improve the job opportunities also in the society.

c. Govt. should open hypnotherapy one year diploma courses in Govt. Universities so many people can learn and take the benefits from it. It will generate the Govt. source of income from these courses.

d. Govt. should involve hypnosis course in the syllabus of these subjects: Psychology , M.B.B.S, Counseling, MSW ,Child psychology, Clinical Psychology ,M. Phil in Clinical Psychology, Social Psychology etc. so society will get the benefits in all these area through its services.

References :-

1. Cassady, J. C., & Johnson, R. E. (2002). Cognitive test anxiety and academic performance. Contemporary Educational Psychology,27, 270-295.
2. Gail W. Brown, David Summers, Brent Coffman, Rodney Riddell & Bruce Poulsen (1997) . The Use of Hypnotherapy with School-Age Children": Volume 15, Issue 3, pages 53-65.
3. Hembree, R. (1988). Correlates, causes, effects, and treatment of test anxiety. Review of Educational Research, 58, 47-77
4. Hurlock E.N. (1972). Child Development (5th Ed) New York: Hill Book Company.
5. Kumar, Akshay., Jena, SPK. (2013). "Effect of Clinical

Hypnotherapy on Anxiety Symptoms". Delhi Psychiatry Journal, Vol. 16 No.1

6. Lali, S (1997). "Influence of Anxiety on Science Achievement of Secondary School Pupils ." Asian Journal of Psychology and Education, 30 (7-8), 29-32.
7. Mathur, S. and Khan, W. (2011) Impact of Hypnotherapy on Examination Anxiety and Scholastic Performance among School Age Children. Delhi Psychiatry Journal, 14(2), 337-342.
8. Morris, L. W., Davis, M. A., & Hutchings, C. H. (1981). Cognitive and emotional components of anxiety: Literature review and a revised worry-emotionality scale. Journal of Educational Psychology, 73, 541-555.
9. Olatoye RA, Afuwape MO (2003). Test anxiety as a determinant of examination misdemeanor among some Nigerian Secondary School Students. Ibadan J. Educ. Stud. 3(182): 32-39.
10. Palan,B.M. (2003). A holistic stress management & self-development programme with self-Hypnosis: Transformation.
11. Palan, B.M. & Chandwani, S.(1987). Coping with Examination Stress Through Hypnosis : An Experimental Study. American Journal of Clinical Hypnosis, Volume 31-issue 3 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00029157.1989.10402886
12. Saltz, Wendy Lapidus, (2008). Can Hypnosis make me rich, thin, brilliant and happy? The Hypnosis Alliance network.
13. Schwarzer, R. (1986). Self-related cognitions in anxiety and motivation: An introduction. In R. Schwarzer (Ed.), Self-related cognitions in anxiety and motivation (pp. 1- 18). Hillsdale, NJ: LEA.
14. Sgoutas-Emch SA, Naget E, Flynn S (2007). Correlates of Performance in Biological Psychology: How can We Help? J. Instr. Psychol. 34(1): 46-53.
15. Stanton E. Harry, (1993). Using Hypnotherapy to Overcome Examination Anxiety American Journal of Clinical Hypnosis , Vol. 35, (3).
16. Taqavi, Somayeh & Poursghar, Mehdi (2015) International Journal of Basic Sciences & Applied Research. Vol., 4 (11), 661-666.
17. Zhao Xiaojun, You Xuqun , Shi Changxiu and Gan Shuoqiu (2015). Hypnosis therapy using augmented reality technology: treatment for psychological stress and anxiety. Behaviour & Information Technology , Vol. 34, (6).

****

Study Of Relationship Of Bullying With Academic Performance Of Adolescents

Dr. Saroj Kothari* Richa Mandovra**

Abstract - Bullying is a widely prevelant problem that is spreading far and wide and having severe adverse effects on school children, especially in adolescents. Teachers, parents and other caregivers are faced with many cases of students suffering emotional, physical and mental trauma because of being constantly bullied by classmates or seniors students. The present study aimed to find the relationship, if any, between bullying and academic performance of adolescents. A sample of 248 students of class 8th from schools of Indore was taken for the study. ***Illionis Bully Scale*** developed by Espelage & Holt (2001) was used to measure bullying and ***Academic performance of students*** was measured by using the marks obtained by students in Summative Assessment-1(that is equivalent to the half yearly examination). The results showed a negative relationship between bullying and Academic Performance that shows the adverse effect of bullying on the grades of students.
Key Words- Bullying, Adolescents, Academic Performance.

Introduction - What is Bullying? - World Health Organization defines bullying as a threat or physical use of force, aiming at the individual, another person, a specific community or group which can result in injury, death, physical damage, some development disorders or deficiency. A single student who bullies can have far-reaching effects in the school and create a climate of fear and intimidation not only in his or her victims but in fellow students as well. Students who bully, their victims, and bystanders are all affected. Despite the common assumption that bullying is a normal part of childhood and encompasses minor teasing and harassment (Laursen et al, 1998), researchers increasingly find that bullying is a problem that can be detrimental to students' well-being (Nansel TR et al, 2003, Kshirsagar VY et al, 2007).

Bullying can be undertaken in several different methods (e.g., face-to-face, group, or cyberbullying). During face-to-face bullying one student directly bullies another student. Group bullying occurs when multiple aggressors engage in bullying a student. Cyberbullying occurs when a student is bullied through social media, text-message, or other means of technologically based communication.

Bullies often come from families that use physical forms of discipline(Prod. Debra Chasnof et al.,2003).This somewhat turns the tables on the bully, making them the victim. Unfortunately, this leads to a strategy of bully or be bullied.(Beaty, LA; Alexeyev, EB (2008))

School Bullying - School bullying is a type of bullying that occurs in an educational setting. School bullying may be more specifically characterized by:

- An intention to harm: intention suggests that the harm caused by bullying is deliberate, not accidental.
- Victimisation distress: bullying causes the victim to suffer mild to severe psychological, social or physical trauma.
- Repetition: bullying is persistent; it happens more than once or has the potential to occur multiple times.
- Power inequity: real or perceived imbalance of power between the bully and the victim.
- Provocation: bullying is proposed to be a part of progressive aggression: motivated by perceived benefits of their aggressive behaviours.

Types of bullying- Direct bullying is a relatively open attack on a victim that is physical and/or verbal in nature. Indirect bullying is more subtle and harder to direct, but involves one or more forms of relational aggression, including social isolation, intentional exclusion, rumor-spreading, damaging someone's reputation, making faces or obscene gestures behind someone's back, and manipulating friendships and other relationships.(Hirsch, L. & Lowen, C, 2012)

Another classification of types of bullying is into three categories:

a) Physical
b) Verbal
c) Relationship (Langevin, 2000).

Physical bullying is based on anger and asserted through physical acts. Verbal bullying uses words to hurt and humiliate victims. Lastly, relationship bullying occurs when rumors are spread about the victim.

Bullying occurs in and away from schools; however, the majority of bullying takes place in educational institutions. Bullying locations vary by context. For example,

*Professor & Head (Psychology) Government MLB Girls P. G. College, Indore (M.P.) INDIA
**Research Scholar (Psychology) Government MLB Girls P. G. College, Indore (M.P.) INDIA

the playground is the most dangerous area on the elementary level, followed by the outdoor recess area, hallways, indoor recess, and classrooms. In middle school, hallways were the most perilous location, followed by the lunchroom, outdoor recess areas, classrooms, indoor recess, and the front of the school. The common denominator in almost all of these locations is inadequate or no supervision and unstructured time.

Why is bullying harmful? - When bullying pervades a school, victims are not the only ones to suffer. Bullying creates an atmosphere of fear, self-doubt and worry that affects the instigators, the victims and onlookers. The emotional turmoil can cause a child to neglect his academics, leading to failing grades. Students who are victims of bullying encounter difficulty with social development. Olwues (1993) found bullying victims often lack friends in the class and at school. Students exposed to long-term bullying perceive the school environment as unfriendly, frightening, and often experience a major part of their school career feeling anxiety and insecurity.

The obvious physical harm exhibited by physical bullying is bruises, cuts, or other unexplained injuries or damaged possessions. The elevated levels of anxiety, stress, and depression exhibited from the other forms of bullying can lead to physiological responses. A meta-analysis of bullying research found that victims of all types of bullying are more likely to exhibit bouts of headaches, stomachaches, dizziness, bedwetting, and sleeping problems (Gini & Pozzoli, 2009).

Declining Grades - Low achievement in school and bullying are frequently linked. It is seen that students who are repeatedly bullied receive poorer grades and participate less in class discussions. Some students may get mislabeled as low achievers because they do not want to speak up in class for fear of getting bullied.

Roles kids play - There are some roles in bullying that take place. “McNamee and Mercurio” have identified the people involved in bullying as: the person doing the bullying, the person getting bullied and the bystander as the “bullying triangle”. (Dr. Mark Dombeck -2012)

- **Bully -** Students with power (social and/or physical) who repeatedly picks on another student or group of students with the intent to inflict harm or discomfort.
- **Victim -** Students who are the target of the bullying.
- **Bystander -** Student who observes bullying – may ignore bullying, encourage bullying, or take a stand against bullying.(Miller et al., 2014)

What is Adolescence? - The most longstanding definition of the onset of adolescence links it to puberty, when hormone activity produces the development of secondary sex characteristics.

WHO identifies adolescence as the period in human growth and development that occurs after childhood and before adulthood, from ages 10 to19. The transition from childhood to adolescence can cause stress that might promote bullying behavior, as students attempt to define their place in the new social structure. A short-term investigation of over 500 middle school students (grades 6-8) found an increase in bullying behavior among sixth-graders over a 4-month period (Espelage et al., 2001).

Bullying Appears to Affect Students’ Academic Performance - When students feel sick, depressed, worried, and/or isolated and alone, it is hard for them to perform to their potential in school (Juvonen, J. et al., (2000)). Feeling sick and thinking about or anticipating bullying may interfere with students’ ability to concentrate, which can reduce their ability to learn new material. In turn, students who felt down and sick as a function of bullying were absent from school more often and obtained lower grades.

Methodology -

Sample - Random Sampling method was used to select three schools where both the tools would be administered. The tests were administered on all students of class 8th. The sample consisted of 248 students. The constitution of the sample is as follows -

No. of Boys	120
No. of Girls	128

*Names of the schools and students cannot be disclosed because of confidentiality.

Tools to be used -

- **Illionis Bully Scale** developed by Espelage & Holt (2001) was used to measure bullying.
- **Academic performance of students** was measured by using the marks obtained by students in Summative Assessment-1(that is equivalent to the half yearly examination).

Findings -

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Bullying	4.8306	3.54662	248
Marks Percentage	43.3940	16.62193	248

The high deviation in bullying can be attributed to the following two reasons:

- There is a selected group of students that is being bullied much more than others
- The survey was conducted in school settings, so a few students might not have reported the correct level of bullying.

Pearson Correlation	Bullying	1.000
	Marks Percentage	-.207
N	Bullying	248
	Marks Percentage	248

The correlation between Bullying and Marks Percentage is -.207 which is low degree negative correlation which indicates that as bullying increases, there is a decrease in academic performance.

This negative correlation is also supported by a meta-analysis of 33 studies which concluded that students who are bullied are more likely to earn lower grades and scores on standardized achievement tests (Nakamoto & Schwartz, 2009). The few studies that have examined the causal

effects over time indicate that peer victimization increases the risk of lower achievement (Schwartzet al., 2005). The connection between harassment and low academic achievement has also been observed with school level data, as reported in California Healthy Students Research Project (CHSRP) Brief No. 1. CHKS data show that schools with high Academic Performance Index (API) scores had significantly lower rates of harassment than schools with low API scores, even after adjusting for socioeconomic and other school characteristics. Depending on the grade level examined, the number of students reporting rates of harassment was 22-33 percentage points higher at the schools in the bottom API quintile than it was at schools in the top API quintile (Hanson et al., 2010). In one study, emotional problems associated with being bullied compromised academic performance as early as elementary school (Schwartz et al., 2005).

Conclusion - There is a negative correlation between bullying and academic performance. Hence as the student gets increasingly bullied, the academic performance shows a steady decline. Hence when a student shows a decline in grades, instead of blaming, scolding him, the teacher and parents should talk to him, counsel him and try to ascertain the reason for this sudden change because it is highly possible that he /she is getting bullied at school. Bullying should be considered a major problem by schools, parents and authorities so that measures to address it can be taken. Frequent physical complaints may be warning signs that a child is being bullied. Especially when such complaints take place during certain classes or activities, it is important to find out if bullying is happening in these classes or by certain students.

Teachers and other adults in children's lives at school can help by limiting students' exposure to bullying. Adult involvement includes discretely intervening in bullying incidents both inside and outside (e.g., during lunch, recess, passing period) of the classroom. Public intervention may also be warranted when the bullying is public and observed by other students. Teachers and school staff should consistently intervene whenever a bullying incident comes to their attention because the events that adults observe are a fraction of what students encounter on a daily basis. Timely and prompt intervention and punishment for bullies will give a strong positive message to other students that bullying is not going to be tolerated.

Suggestions for future work -

- More schools, including government schools can be included in the survey to get better sample.
- The study can be conducted over longer duration to assess long term effect of bullying on academic performance.
- The role of other factors like gender of the victim, socioeconomic status etc can also be assessed.

References :-

1. Beaty, LA; Alexeyev, EB (2008). "The problem of school bullies: What the research tells us". Adolescence (169): 1–11. PMID 18447077.
2. Dr. Mark Dombeck. Mentalhelp.net. Retrieved on 2012-12-30.
3. Espelage, D. L., & Holt, M. K. (2001). BULLYING AND VICTIMIZATION DURING EARLY ADOLESCENCE: PEER INFLUENCES AND PSYCHOSOCIAL CORRELATES (pp. 123-142). Binghamton, NY: Haworth Press
4. Gianluca Gini, PhD, Tiziana Pozzoli, MA, Association Between Bullying and Psychosomatic Problems: A Meta-analysis, PEDIATRICS Vol. 123 No. 3 March 1, 2009 pp. 1059 -1065
5. Hanson, T., Austin, G., & Zheng, H. (2010). Academic performance and school well-being in California. California Healthy Students Research Project Research Brief. No. 1. San Francisco: WestEd
6. Hirsch, L. & Lowen, C. Bully. New York: Weinstein Books, 2012. Print.
7. Juvonen, J., Nishina, A., & Graham, S. (2000). Peer harassment, psychological adjustment, and school functioning in early adolescence. Journal of Educational Psychology, 92, 349-359.
8. Kshirsagar VY, Agarmal R, Bavdekar SB. Bullying in Schools: Prevalence and Short-Term Impact.Indian Pediatr. 2007;44:25–8.
9. Langevin, M. (2000). Teasing and Bullying: Unacceptable Behaviour. Available from the Institute for Stuttering Treatment & Research, 3rd Floor, 8220 — 114 Street, Edmonton, Alberta, T6G 2P4.
10. Laursen, B., Coy, K. C., & Collins, W. A. (1998). Reconsidering changes in parent–child conflict across adolescence: A meta-analysis. Child Development, 69, 817–832.
11. Let's Get Real. Prod. Debra Chasnof, Helen S. Cohen, and Kate Stilley. New Day Films: Women's Educational Media, 2003. Videocassette
12. Miller, Holly Ventura, and J. Mitchell Miller. "School-Based Bullying Prevention." Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention. Ed. Bonnie S. Fisher, and Steven P. Lab. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc., 2010. 818–20. SAGE knowledge. Web. 20 Feb. 2014.
13. Nakamoto, J. & Schwartz, D. (2009). Is peer victimization associated with academic achievement? A meta-analytic review. Social Development, 19, 221-242.
14. Olweus, D. (1993). BULLYING AT SCHOOL: WHAT WE KNOW AND WHAT WE CAN DO. Cambridge, MA: Blackwell. ED 384 437.
15. Schwartz, D. Gorman, A. H., Nakamoto, J. & Toblin, R. L. (2005). Victimization in the peer group and children's academic functioning. Journal of Educational Psychology, 97, 425-435.

****

Hybridity & Alienation in the works of Ruskin Bond

Dr. Shailendra Kumar Chourasia*

Abstract - The paper examines how one culture accepts, absorbs, adapts, or resists the onset of hybridity. The comparative analysis of culture and society provides a complex picture of contested versions of hybridity. This reveals both the contradictions that sharpen and the overlap that blurs the distinctions between West and East. The paper revisits the culture of Ruskin Bond, not in the usual terms of the influence of west on the East, but as a set of relationships between both of them. This shift in emphasis provides new insights into how the peoples of different culture sought to discover new ways to negotiate the problems of cultural difference.

Introduction - Hybridity and multiculturalism are the two different forms though both are the products of East West encounters. The interaction between two cultures gives an overlapping of ideas and tradition with each other. Hybridity explores the flexibility of thoughts and multidimensional approach to the society. This flexibility trends up into the form of a gradual advancement. Indian culture is supposed to have age long tradition and customs. And this process still is going on so that is has become the most noteworthy example of multicultural ocean. The induction of new culture and its established tradition merged with Indian culture has given acceleration. This acceleration has been turned up into the form of human comfort. Men have sought their own ways to be identified in the society. And this has gripped them a sort of separation or what we may call it as alienation. This alienation is also the product of East West encounter that is plenty in the works of Ruskin Bond. So all these terms are the reflection of East- West encounters and gradual cultural interaction.

The important point to recognize is that cultures are always *retrospective* constructions, meaning that they are consequences of historical process. Bhabha argues throughout *The Location of Culture* the narrative construction of new mixed race that arise from the 'hybrid' interaction. What Bhabha states about the hybridization of two culture is high standards of two cultures.

It is the emergence of the interstices- the overlap and displacement of domains of difference that the inter-subjective and collective experiences of nations, are negotiated…. Terms of cultural engagement, whether antagonistic or affinitive are produced per formatively. The representation of difference must not be hastily read as the reflection of pre- given ethnic or cultural traits set in the fixed tablet of tradition. The social articulation of difference from the minority perspective is a complex, on- going negotiation that seeks to authorize cultural hybridites that emerge in moments of historical transformation. (LC-2).

Cultural hybridity is a medium through which one culture enacts another. The themes, patters & ideologies many a times seem parallel to each other. The writers borne in one country and writing about another inevitably seek pleasance to evoke the universalism of conscious cross-culturalism. Bapshi Shidhwa, Salman Rushide, V.S. Naipul, Amitav Ghose and other eminent writers have elaborated the theme of 'hybridization' in their works. E.M. Foster's *A passage to India* is a monumental study of the clash and reunion between two cultures. Aziz a representative of upper class Indian society fails to set an equilibrium between the Indian cultural values and colonized one. Fielding at Aziz's house while encounters Aziz's wife; Aziz speaks out of his cultural values:

"Of course not, but the word exists and is convenient. All men are my brother, and as soon as one behaves as such he may see my wife" (A Passage to India- 128).

And further he speaks in a conversation to Miss Quested, Aziz admits that Eat and West are two "you keep your religion I mine" (A passage To India - 156)

Ruskin Bond, an offspring writer with the basic tissues of hybridity gives a harmonious blending of East and West in his works. He rejected the superiority of white man and introduced the permanent nature of writing. The nature trails, wild flowers,trees, birds and other nature's wonder became a permanent part of his writing. *His Room on the Roof* portrays of his new learning and affection of Indian culture where he was born. The hybridity of two cultures of East and West has been spelled out clearly in *The Room of the Roof* and nowhere is the resolution so unambiguous and simple. Here the protagonist, Rusty, borne in India, a product of mixed hybridity repairs his conflict of being a British. Soon he concentrates his problem which is or regaining his roots, of belongingness. He concludes that I don't belong to British as my upbringing, sense of values, affections all combine to make me Indian. He finds physically nothing common in him with his countryman. His self-pity arising out of a sense of alienation and rootlessness come out with his character. From the beginning we see the protagonist Rusty learning

*PGT (English) KV No-1, Indore (M.P.) INDIA

about diverse Indian ways through his intimacy with Indian soil. Bond having British ancestry couldn't help to keep alone himself very much close to the Indian rituals. The rituats embed and accustomed with strangeness, the western and the acquaintance the, eastern. While he speaks of the European soldiers, the man of colourful fortune, he closely understand the manners morals and values of Europeans and Asians during the period of colonial expansion. The mixed race understanding developed with his senses helped him to interpret such unpredicted, unpolished instincts to portray.

The Theme of alienation also depicts the literature of Ruskin Bond. Alienation is a natural instinct present in every living creatures on the earth.

In a mystical conception while we go through the two great Indian epics, *Ramayana* by Valmiki and *Mahabharata* by Ved Vyas, we see a long chain of alienation. The epic in relation to man present all types of character who suffer from alienation. Being drifted from father and wandering in search of beloved Sita we see a touch of alienation in Rama. Sita being away from Rama herself alienated where . Hanumana waiting for Rama in the dense forest himself is alienated. Laxman younger brother to Rama, alienated himself and his wife Urmila. Sabari, Sugriva and his group, Bharat, and Satrugan are alienated themselves in one kind. On the other hand Ravana, Mandodari (Ravana's wife), Kumbhakarna, all are conflicted of the very purpose of their existence. In the *Mahabharata* charaters like Devabrata, Kunti, Pandvas, Ghatotakachha, Ashwatthama had been alienated is some way. According to the Oxford English Dictionary, alienation means the action of estranging or state of estrangement in feeling or action". The *Encyclopedia Britannica* describes it as:

term used with various meanings in philosophy, theology, psychology, and social sciences, usually with emphasis on personal powerlessness, meaninglessness, normlessness, cultural estrangement, social isolation, or self estrangement.

Thus alienation can be only from *other* things. It can be from man's own self, it can be intense and minute, no matter what is source or degree, that one fact is that alienation is man's inevitable fate.

Ruskin Bond visualizes the problem of alienation with full aspects in his fiction. He sees this alienation because of the conflict in having intimacy with others. According to him, the meaning of the feeling of loneliness is the loss of significant relations with others and this loss results in social isolationship. He thinks that the decay in creative meaningful relation between man and man and the separation of a man living in the society from the culture of his society cause alienation.

Bond's first novel, *The Room on the Roof* deals with the very life of Anglo- Indian boy Rusty and the incidents that take around him. Living in the custody of his English guardians, Rusty, feels himself alienated. He himself does not know about his parents and always searches them into void. Somi, an Indian Panjabi boy while accompanies him, Rusty finds himself attached with him. Dehra was a place of curiosity to him. The restrictions imposed by Mr. Harrison, his English guardian and mal description of missionary's wife puts him always around fear. But these all fail to freeze his steps as he himself decides to overcome his alienation.

This community why did not move to England always comes or question in his mind. The community consisted mostly of elderly, people, the others had left soon often independence. These few stayed because they were too old to start life again in another country, where there would be no servants and very little sunlight and, though they complained of their lot and criticized the government, they knew their money could buy them their comforts: servants, good food, whisky almost anything- except the dignity they cherished most…. (*The Room on the Roof.* 10).

Being suppressed with loneliness, Rusty determines to search for the bazaar even after the restriction imposed over him. This shows the quest of being identified he was suffering from in the tight custody of his guardians.

In the view of Heidegger man lives in this world in authentic existence; that means existence which is determined in the present, only in terms of impersonal social requirements. Thus man's freedom of decision and choice is interrupted and he feels alienated. In the view of Sartre, a person feels the loss of touch with the inner core of his being and therefore all his actions become empty, flat and devoid of meaning .This search for inner core enforces Rusty to accept invitation for *holi* even because of the fear of his guardians. While Rusty thinks about it.

Holi, the Festival of Colours, the Arrival of spring, the rebirth of The new year, the awakening of love, what were these things to him, they did not concern his life, he could not start a new life, not for one day….and besides, it all sounded very primitive, this throwing of colour and beating drums….(The Room on the Roof-28)

While he escapes from his guardians' custody, Rusty's alienation feels consolation Kishen, Suri and Somi introduce him the affection, love, family manners he has been deserted for.

In *Delhi is not Far* Bond; through the narrator, speaks of his intense desire that shows his suffering and escape of alienation.

A few things reassure me …the desire to love and to be loved. The beauty and ugliness of human body, the intricacy of its design….love takes me to distant, happier places. (Delhi is not far 26).

In the next novel *Delhi is not Far* Bond; through the narrator, speaks of his intense desire that shows his suffering and escape of alienation.

A few things reassure me …the desire to love and to be loved. The beauty and ugliness of human body, the intricacy of its design….love takes me to distant, happier places. (Delhi is not far 26).

Living alone in his house, the narrator brings an orphan boy Suraj and finds his deep affections with him. Kamla, a

girl whom the narrator loved is left behind in the ups and downs of life and struggle to become a writer. Finally the narrator moves to Delhi with Suraj.

Bond's entire writing is an out product of his close association with the soil of India and its people. The hybridity has given him a new meaning in this country of diverse and colourful cultures and people. The alienation didn't put him down in fact he made the everyman of the society his family. This is clearly portrayed in the characters and the incidents of his writing.

References :-

1. Bhabha, Homi K. "Introduction: Narrating the Nation." Nation and Narration.Ed. Bhabha. London and New York: Routledge, 1990. 1-7.
2. Our Trees Still Grow in Dehra. New Delhi: Penguin, 1991.
3. The Room on the Roof. London: Andre Deutsch, 1956.
4. Ruskin Bond's Treasury of Stories for Children. New Delhi: Viking, 2000.
5. Scenes from a Writer's Life: A Memoir. New Delhi: Penguin, 1997.
6. Time Stops at Shamli and Other Stories. New Delhi: Penguin, 1989.
7. E.M.Foster."*A passage To India",New Delhi, Penguine,1964 Ed.*
8. *Khorana, Meena. The life and works of Ruskin Bond. Praeger Publishers, Westport. United States.2003*
9. *Soma Banerjee, "Ruskin Bond," in Reference Guide to Short Fiction, ed. by Noille Watson (Detroit: St. James Press, 1994),*
10. *"Delhi Is Not Far." Delhi Is Not Far: The Best of Ruskin Bond. New Delhi: Penguin, 1994.*
11. *The Lamp Is Lit: Leaves from a Journal. New Delhi: Penguin, 1998.*
12. *Time Stops at Shamli and Other Stories. New Delhi: Penguin, 1989.*
13. *Our Trees Still Grow in Dehra. New Delhi: Penguin, 1991.*
14. *Scenes from a Writer's Life: A Memoir. New Delhi: Penguin, 1997.*
15. *"The Room on the Roof" and "Vagrants in the Valley": Two Novels of Adolescence. New Delhi: Penguin, 1993.*
16. *Khorana, Meena. Introduction. The Indian Subcontinent in Literature for Children and Young Adults: An Annotated Bibliography of English-Language Books. Westport, CT: Greenwood, 1991.*

****

The Problem Of Modern Wasteland In K.A. Porter's Flowering Judas

Dr. Anita Tripathi *

Introduction - In ***Flowering Judas,*** Porter traces astutely the failure of the revolution through fictional characterization. Porter shows the vestiges of great hopes and dearest faiths that have nearly run out. She describes to Thompson the genesis of the story. She walks past a window and sees her friend Mary sitting with a big fat man. She says that Mary was not able "to face her own nature" then but that she herself was "more skeptical". Like Laura, Mary Doherty taught Indian children in Zochimilco and participated in the revolution. Laura represents the alien why came to Mexico "uninvited" to participate in the revolution. In so doing the ostensibly had to abandon her own Catholicism and take on the "religion" of revolution because the church was an emeny of the revolution in Mexico. Laura has become disillusioned like Porter with the hypocrisy of the movement, which has bogged down in petty factionalism and corruptive struggle for power among the leaders of the various groups. Her idealistic view of the revolution has not been borne out.

Braggioni is the symbol of Laura's disillusions, for she had thought of a revolutionist as "lean, animated by heroic faith, a vessel of abstract virtues" (CS, 91),[1] essentially a Christ figure, Braggoni 's distance from this standard is implied in all the descriptions of him. He is a symbol of that corruption as is Mr. Hatch in Noon Wine, He is the professional revolutionist. He wages war for gain and not for idealistic commitment. But he acts the part of the idealist well. When "crafty men" whisper in his ear, "Hungry men... wait for hours outside his office for a word with him", or "emaciated men with wild faces waylay.. him at the street gate with a timid, 'Comrade, let me tell you... " (CS, 98), he is always seemingly sympathetic. He gives them handfuls of small coins from his own pocket and tells them :

There will be demonstrations, they must join the unions and attend the meetings, above all they must be on the watch for spies. They are closer to him than his own brothers, without them he can do nothing — until tomorrow, Comrade ! (CS, 98).

Tomorrow, of course, will never come, for Braggioni is in fact cruel and unsympathetic, and says to Laura : "They are stupid, they are lazy, they are treacherous, they would cut my throat for nothing." He says of Eugenio which has taken all the drugs that Laura brought him because he was bored : "He is a fool, and his death is his own business.... We are well rid of him" (CS, 100-101). He also tells her that he himself is rich, "not in money ... but in power, and this power brings with it the blameless ownership of things and the right to indulge his love of small luxuries" (CS, 93). Braggioni is so far removed from the original revolutionary zeal that he cannot understand why Laura is involved in the revolution at all, "unless she loves some man who is in it" (CS, 100). This, then, is the death that was in the revolution. The heroic faith and dedication for the cause of welfare of Mexicans is not present in the revolutionaries who are left to fight. Braggioni does not have idealistic commitment and is responsible for the failure of the revolution. Laura is equally "corrupt, callous and incomplete, and adds to the betrayal of faith and hope. She must identify herself with Judas rather than with any liberator of mankind.

Flowering Judas is almost always interpreted as a link between Porters concern with primitivism and her childhood experiences that created the Miranda cycle. Flowering Judas leads to a climax of self revelation. Laura's betrayal is the crux of the story. She draws her strength from denying everything. In her dream Laura feels guilty of betrayal. She is frustrated because her ideals are shattered. Her mind is troubled, and in her dream she is summoned by Eugenie who is dead :

Get up, Laura, and follow me. Come out of your sleep, out of your bad, out of this strange house. What are you doing in this house ? Without a word, without fear she rose and reached for Eugenie's hand (CS, 102).

Like a Hemingway hero, she "was afraid to sleep" after this dream of self-realization. Laura is firmly grounded in Catholic belief of Christianity. In her dream she gets moral guidance a suggestion of salvation or redemption so that, through right action, self control and realization of the guilt, she may go beyond the sterile, senseless world. She eats the flowers of Judas tree with an earnest desire to purify herself. Deep down her ego, she feels her remorse might lead her to purgation. Laura "cannot help feeling that she has been betrayed irreparably by the disunion between her way of living and her feeling what her life should be" (CS, 91). Later, Laura betrays the revolution's ideal by stepping into a church to pray knowing that the discovery will cause scandal, and by rejecting the machine which is sacred to

*Associate Prof. (English) Govt. Girls College, Satna (M.P.) INDIA

the movement and "will be the salvation of the workers" (CS, 92). Her "private heresy" is that she refuses to wear lace made on machines. Then, she also betrays her religion, as "she was born Roman Catholic", which promises spiritual life, by replacing it with the revolution that practices death. Finally, Laura betrays Eugenio by providing excessive narcotic drugs that make his suicide possible. By doing this, Laura betrays herself too, in a way that includes her responsibility towards Eugenio.

In Flowering Judas, Porter has achieved more than a mere definition of modern man's condition; she has embodied an attitude that demonstrated the necessity for the application of the ancient qualities of love and faith as fructifying elements in any human existence, whether of the old order or the new. Without love and faith the world is a wasteland. Laura's world becomes the symbol wasteland.

Flowering Judas is a "highly figurative composition", a "mood piece", the "open ended" story.[30] The Judas tree is seen quite simply as "a symbol for the betrayer of Christ". Laura's eating the buds is a "sacrament.. of betrayal".[31] Flower is the symbol of love. Without love one cannot survive. Laura instinctively feels this when she rationalizes that it is monstrous to confuse "love with revolution, night with day, life with death" (CS, 101). She eats the flower greedily presumably with the hope that she would be able to survive as flowers "satisfy both hunger and thirst" (CS, 102). Her eating of flowers may be seen in the light of her instinctive need of love for survival. Porter consistently thought of machinery as life negating as observed in "The Flower of Flowers", "...the world of evil is mechanistic furnished with the wheel, but not the rose" (DB, 147).[2]

The problem of the modern wasteland, as displayed in Flowering Judas, is the pathetic inability of man to live according to his dreams. Porter presents an ironic tension between two powerful competing forces: Christian faith and revolutionary hope. Caught between these two is the heroine, Laura, whose predicament is that she cannot free herself from her religious training and beliefs and so cannot give herself wholly to the revolutionary cause. Although a beautiful woman, she clothes herself like a nun and can respond to none of the would-be lovers who woo her. She rejects Braggioni, the revolutionary general; she outwits the young army captain who takes her riding; she unknowingly teases a young man from the Typographers Union by throwing him a rose (the symbol of love), when she can feel nothing for him. She even fails to react to the children whom she teaches, when they bring her flowers and scribble on the blackboard, "We love ar ticher". Her principal contribution to the cause is to carry narcotics to the prisoners in jail, so that may sleep away their imprisonment.

The story is one of Laura's inability to love. She cannot love erotically as a woman, humanely as a dedicated revolutionary, or divinely as a communicant in the church. Without love, the story says, the world is a wasteland. The moral of the story is as translated into the language of Christian theology: "Man cannot live by bread alone." We might say the theme is: Man cannot live only by materialistic values: but "only in faith and love can man live".[3]

References :-

1. Collected stories of Katherine Anne Porter.
2. The Days Before.
3. West-Stallman : The Art of Modern Fiction, New York, Rinehart, 1949, 287-91
4. J.E. Hardy : Katherine Anne Porter, New York, Frederick Ungar, 1973, 63.
5. M.G. Krishnamurthi : Katherine Anne Porter : A Study, Mysore, Rao and Raghvan,1971, 135.

****

Socio-Economic Aspects In The Novels Of Ruth Prawer Jhabvala

Dr. Kehkashan Khan*

Introduction - "Social life in a country of the size of India, says Srinivasa Iyengar, is so full of vagaries and varieties that the novelist with an observant eye and an understanding heart will find the material spread out before him to be literally inexhaustible.[1]" When the Indian masses became more resentful of the foreign government because of the humiliation they suffered at their hands, Indian writing became more vocal about justice, cruelty & exploitation. Ruth Prawer Jhabvala having chosen to write about people of North India, particularly Delhi, could not ignore the influence of the British & ill fated partition which they carried with them into a free India. Delhi was swarmed by refugees from a partitional Punjab when India attained freedom. Survivors of the holocaust had lost everything and were engaged in building their fortunes anew in Delhi. The ways and means they adopted provided her an opportunity to assess the prevailing socio-cultural and economic conditions in free India.

Ruth Prawer Jhabvala also brings to bear upon her novels her own expatriate position in India. Born in one country, brought up in another and living in a third, her cosmopolitanism provides her a striking objectivity. In her first novel 'To whom she will' Mrs. Jhabvala makes fun of the young Indian generation, who while thinking themselves to be modern and westernized try to do things which the traditional. Hindu society would not accept, i.e. falling in love with a boy or girl outside one's own caste, community and social strata. They face vehement opposition and tradition wins over modernization.

Amrita's grand father Tarachand prides himself in his pseudo-advanced ideas of female emancipation but his duality is exposed in the course of the novel. He affects a distaste for arranged marriages and holds forth his respect for individual preference in matrimony. Yet his liberal outlook falls short indeed when he is up against Amrita's preference for Hari Sahani, He says, "I have enquired into the young man's family.... the result was not satisfactory .... you know that I myself am not hidebound in this way; that indeed I have allowed two of my own daughters to marry outside their immediate community .... But in your case .... the margin, the discrepancy between the two families, the young man's and yours, is too wide."[2] Even Hari, who declares his love for Amrita, has no courage to face the opposition of his family, for a Bengali girl cannot fit into their Punjabi family, because the food habits, language and social customs of two communities are very different.

In her novel 'Esmond in India', Jhabvala shows how freedom fighters like Ramnath are out of date and their places are being taken by others like Har Dayal who did not have to sacrifice much to get the freedom, but are enjoying all the comforts in free India. Har Dayal has stopped wearing imported suits and wears only Khadi & Jodhpurs. He owns a big bungalow and a fleet of cars and holds committee meetings in his house. When Har Dayal's daughter Shakuntala praises her father and his achievements, Amrit, her brother, cuts her short and remarks, "Daddyji's Committees and all this art and culture and fuddle .... are very nice to keep old gentleman busy but, why do we pretend they serve any useful purpose."[3] Ruth Jhabvala displays a characteristic sensitivity to the social condition of the nameless and faceless domestic servants of India. Har Dayal's wife Madhuri takes unquestioned possession of the lives of her well trained servants and her daughter Shakuntala, despite her high idealism, is not above venting her feelings viciously on an occasion, on her chauffeur.

Esmond still wood, a master of Indian art and culture, husband of an Indian wife is Indian only outwardly. It is ironical that he has come to India to teach Indians about their own art and culture. He has furnished his apartment as a typical European would do. He never develops any taste for Indian food. He dislikes the Indian ways of bringing up children and Indian customs & traditions.

Mrs. Ruth Prawer Jhabvala has taken the title of her novel 'Get Ready for the Battle' from the advice given by the Lord Krishna to the heroic prince Arjuna on the field of Kurukshetra; "Treating alike pleasure and pain, gain & loss, victory & defeat, then get ready for battle". In this scripture Lord Krishna tells Arjuna that a Kshatriya's duty is to fight against all evils. In Jhabvala's novel it is Sarla Devi who gets herself against evil, mainly social injustice and oppression of the poor. The world revealed in the novel is characterized not only by the press of poverty and the socio-cultural gulfs but also existing patterns of living which are changing fast & drastically.

Ruth Jhabvala has also depicted social workers like

*Associate Professor (English) Govt. M.L.B. P.G. Girls College, Fort, Indore (M.P.) INDIA

Mrs. Bhatnagar and Mrs. Dass who, though apparently selfless are only irrelevant to India's real problems. Having uprooted a colony of slum-dwellers and pushed them out far beyond the city limits, these ladies ironically busy themselves in organizing jeeps which will take them out to new colony every day for they are engaged in the selfless task of educating the slum dwellers. Though none of them has given a thought to the squatters' problems of commuting to the city and making a living.

In 'A Backward Place' Ruth Jhabvala exposes sterility of cultural Dais and of its endeavours in the sphere of art. This association is supposed to dispense culture to a small minority of Delhi society. Ironically, the Dais functions only as Mrs. Kaul's compensation for a husband who is too busy to give her any attention and a pattern of life in which her role has become indistinct. In the public eye the "Cultural Dai stands, for social advancement – a place where you can meet nice and interesting people and be in touch and be important, also an opportunity perhaps to wangle a trip abroad[4]. The difference between the rich and the poor is shown through materialists like Mr. Gupta and Mrs. Kaul on one hand and idealists like Mr. Jaykar and Sudhir on the other. It is through Jaykar that she points out the evils of Indian Society and government. "What we as a nation want is not words but deeds, not promises but plans, not sentiments but bread"[5]. Sudhir finally decides to quit Delhi and cultural Dais to their empty intellectual and aesthetic pretensions to devote his considerable intelligence to assist Indian education at its lowest level in a part of India remote from the fashionable capital.

Jhabvala very skillfully and faithfully portrays the changing society which was, struggling between the old and the new values, trying to evolve a new way of life.

Delhi, a meeting place of people and their cultures from all parts of the country and abroad, is the locale of her writing. This offered a great scope for ironical dissection of morals, manners and attitudes of people for a novelist who was endowed with a keen power of observation and awareness of the subtle nuances of the new aspect of the social & cultural life of the city. With her comic and ironic vision, she lays bare the follies, foibles, vanities, frivolities and pretences of the sophisticated and not so sophisticated upper-middle class people of the society. She depicts very clearly that in India of Independence and freedom, Gandhi is honoured like a god but his ideals are largely ignored. In free India the young are trying to free themselves not politically but in private life, in family life, rebelling against parents, resenting having their marriages arranged, falling in love with unsuitable people. She also finds it difficult to accept the deplorable sights of the sick and the poor with equanimity or as sins of a past life. She does not falsify or idealize life but is human enough to feel the heartache at the heart of humanity and it is this that finally refines the quality of her engagingly entertaining art as the consummate portrait of socio-economic life in India.

References :-

1. K.R. Srinivasaa Iyengar, Indian writing in English (New Delhi : Sterling Publishers Pvt. Ltd., 1989), P. 327.
2. Ruth Prawer Jhabvala. To whom she will, (London : Penguin Books, 1985), P. 7
3. R.P. Jhabvala, Esmond in India, (London : Penguin Books, 1980), P. 44
4. R.P. Jhabvala, A Backward Place, (London : Penguin Books, 1980), P. 47
5. Ibid; P. 56

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

व्यंग्य का विकास एवं परिभाषा

डॉ. रश्मि सिलारपुरिया *

शोध सारांश – हिन्दी साहित्य में व्यंग्य का क्षेत्र न केवल भारत में अपितु पाश्चात्य जगत में भी समादर्णीय स्थान पर रहा है। व्यंग्य के महत्व व उपयोग को विद्वानों ने सर्वाधिक स्वीकार्य किया है। हिन्दी साहित्य की प्रमुख विधाओं में व्यंग्य अपनी प्रखर एवं समर्थ उपस्थिति प्रदान कर रहा है। समाज की संलग्तता के कारण व्यंग्य साहित्य विद्धानों के अध्ययन एवं विचार का महत्वपूर्ण बिन्दु बन गया है समाज में व्याप्त विषमताओं, विसंगतियों और बुराईयों की ओर व्यंग्यकार अपनी कहानी अथवा निबंध के माध्यम से हमारा ध्यान रोचक ढंग से आकर्षित कराता है। व्यंग्य को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है। व्यंग्य क्रोध की अभिव्यक्ति का एक उपकरण है। उसकी सफलता अभिव्यक्ति के सौष्ठव पर आधारित है। व्यंग्य का विकास हिन्दी साहित्य में बहुत ही पुराना है। वीरगाथा काल में व्यंग्य राजा और महाराजाओं के लिए हुआ करता था फिर इसका धीरे धीरे आगे विकास क्रम बढ़ता गया और वह वर्तमान में अपनी चरम सीमा को लॉघ कर सबसे आगे खड़ा हुआ है। व्यंगयकारों ने भरसक प्रयास किया तथा उसे इस वर्तमान युग में लाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहे।

प्रस्तावना – हिन्दी साहित्य का इतिहास हास्य एवं व्यंग्य चेतना से नहीं के बराबर रहा है और जो भी हास्य-व्यंग्यात्मक मिलता है, वह साहित्य की श्रेणी में नहीं आता है वह निम्नस्तरीय कहा जा सकता है। भारतीय साहित्य एवं व्यंग्य की कमी का सबसे बड़ा ढोष जीवन को परखने की शक्ति का रहा है। इस सम्बन्ध में डॉ. नागेन्द्र ने लिखा है – 'भारतीय दृष्टि सदैव भेद को देखती रही है। द्वैत को मिटाकर अद्वैत की स्थिति को प्राप्त करना ही इसका लक्ष्य रहा है।' वास्तव में अनेकता में एकता की प्रतीति के बिना पूर्ण आस्तिकता की स्थिति सम्भव नहीं, परन्तु आप देखेंगे कि यह जीवन दृष्टि हास्य के एकान्त में प्रतिकूल पड़ती है।' [1] इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय जीवन की मूलदृष्टि हमेशा द्वैत को समूल नष्ट कर अद्वैत को प्राप्त करना रही है। इस प्रकार की स्थिति हास्य के विपरीत है, अनुकूल नहीं है।

संस्कृत और प्राकृत साहित्य में भी व्यंग्य लेखन की परंपरा विकसित नहीं रही है। भारत दीर्घकाल से पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा रहा है और कहा भी गया है कि 'पराधीन सुख सपनेहु ना ही इससे मानसिक विकास न होकर हास्य-व्यंग्य के अभाव का कारण माना है, ऐसे वातावरण में हिन्दी साहित्य का उद्‌भव और विकास बड़ा संघर्षमय एवं गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा रहा है। उसे व्यंग्य, विनोद की रचना लिखने का अवकाश ही नहीं मिला है। जैसा कि राजबहादुर लमगोड़ा के अनुसार-'हास्य की कमी का कारण मुझे यह प्रतीत होता है कि जिन हजार वर्षो में हिन्दी भाषा का विकास हुआ है, वे हमारी गुलामी के रहे हैं। हमारे उस हजार वर्ष के इतिहास में लड़ाई, झगड़े, परेशानी और उनके छुटकारे के प्रयत्न ही प्रधान रहे। तात्कालिक स्थिति में न हमें हंसने का अवकाष मिला और न समय।'[2] अत: व्यंग्य हास्य का अभाव स्पष्ट होता है। प्रत्येक युग में परिस्थितियों गम्भीर और विपरीत रही हैं। हास्य और व्यंग्य सामाजिक विकृतियों को सुधारने की वृत्तियां हैं, किन्तु भारतीय शास्त्र में इसे आचार्यों ने ग्रहण किया। अत: उपेक्षित व्यंग्यकार एवं हास्य कवियों को सामाजिक स्तर पर कोई उंचा महत्व नहीं दिया गया, जैसा कि आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी जी ने सत्य ही कहा कि 'जिस प्रकार सामाजिक जीवन में हंसोड़ व्यक्ति के प्रति सम्मान का भाव कठिनाई से उत्पन्न होता है और उसके गम्भीर वक्तव्य भी लोगों द्वारा उपेक्षित होने लगते हैं, उसी प्रकार के मात्र हास्य और व्यंग्य के लेखन से साहित्य में ऊंची प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त की जा सकती।'[3] इस प्रकार की प्रवृत्तियों ने व्यंग्य की परम्परा एवं विकास पर अवरोध डाला है। हिन्दी साहित्य के इतिहास में अधिकांषत: अल्पकालिक हास्य-व्यंग्यकारों की रचनाएं देखने मिलती हैं। इसमें लेखन की क्लिष्ठिता एवं रूचि न होना ही रही है। व्यंग्य, परिहास, हास्य विनोद में लड़ाई-झगड़े, दुष्मनी के अलावा उसका उच्च स्तर महत्व को नहीं समझा गया।

हिन्दी हास्य-व्यंग्य में आदि कवि, वीरगाथा काल धर्माश्रित एवं राज्याश्रित कवियों से ओत-प्रोत रहा है। सिद्धों, नाथों के धर्माश्रित काब्यों में सरहपा जैसे सिद्धों ने वैदिक विधानों पर व्यंग्य प्रहार किए हैं। आदिकाल के अन्तिम समय में अमीर ख़ुसरो ने सं. 1340 के आसपास ठेठ खड़ी बोली में जनता के अनुकूल पहाड़ियों, मुकरियों की रचना की। इस आधार पर अमीर खुसरों को हिन्दी का आदि हास्य कवि कहा जा सकता है। सरोज खन्ना के अनुसार – 'आदिकाल की सन्ध्या में जब साहित्याकाष पर अमीर खुसरो देदीप्यमान नक्षत्र की भांति उदित हुए, तब हिन्दी कविता में विनोद और मनोरंजन की प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होने लगी। हास्य को स्वतंत्र सत्ता प्रदान करने वाले अमीर खुसरों ही हिन्दी के प्रथम कवि हैं।'[4]

व्यंग्य की परिभाषा – व्यंग्य-हास्य के गर्भ से पैदा हुआ है, अत: इसे हास्य की जननी कहा जाता है। कभी-कभी आष्चर्यचकित घटनाओं को देखकर हमें उन पर हंसी आ जाती है।

'व्यंग्य शब्द वि + अंग से बना है, जिसका अर्थ विफल अथवा विकलांग होता है, वस्तुत: विफल का अर्थ है खण्डित अंगों वाला। इसलिए विकलांग शब्द अनुपयुक्त है। 'विललांगा।' शब्द उसी पकार चल पड़ा, जैसे सनलाईट साबुन, ए.सी. करेण्ट, विंध्याचल पर्वन इत्यादि। इस प्रकार व्यंग्य अंगहीन अथवा खण्डित अंगों वाले व्यक्ति, प्राणी अथवा पदार्थो का बोध

* क्राइस मेमोरियल कोऐड हायर सेकेण्डरी स्कूल, बैरागढ़, भोपाल (म.प्र.) भारत

कराता है। मूलत: किसी व्यक्ति या समाज बुराई या न्यूवता को सीधे शब्दों में न कहकर उल्टे या टेढ़े शब्दों में व्यक्त करना व्यंग्य है। सामान्य भाषा में इसे ताना बोली या चुटकी भी कह सकते हैं। व्यंग्य वह विद्या है, जिसमें वाक्य को सीधा न कहकर उसे थोड़ा घुमा-फिराकर भी बोल सकते हैं।

'व्यंग्य शब्द अंग्रजी के Satire का हिन्दी पर्याय है। होरेस (65 ई.पू.) के समकालीन रोम में अमर्यादित नाटकों के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता था- 'Saturege'। परवर्तीकाल में लातिन में यह 'Sature' बनकर आया और अंग्रेजी में 'Satire' शब्द बना। इस 'डरींळीश शब्द के पर्याय स्वरूप हिन्दी में व्यंग्य, व्यंग, विकृति, उपहास चार शब्द प्रचलित संज्ञा है।'[5]

व्यंग्य हमेशा कड़वा तथा पैना होता है।
लेकिन इसमें सुधार हमेशा होता रहता है।।

लेटिन में व्यंग्य के प्रमुख व्याख्यानकर्ता रहे हैं-होरेस, पर्सियंस और जुबेनल जिनका अनुकरण यूरोप के 'रिनेसा' (निवोत्थान) के अंतर और उपरांत किया गया था। इंग्लैण्ड में यहीं आदर्श स्वरूप एलिजाबेथीन, अगस्तीय समय में अपनाया गया था, कविता के विशिष्टीकरण के लिए व्यंग्य का प्रयोग किया गया। यहीं से व्यंग्य की व्युत्पत्ति मान्य हुई। साहित्यिक स्वरूप में इसे परिभाषित करना हो तो यह कह सकते हैं कि सामाजिक दोषों, दुर्बलताओं और बिडम्बनाओं पर तीक्षण प्रहार करने वाली रचनाएं साहित्यिक व्यंग्य श्रेणी में आती हैं।

व्यंग्य को साहित्य स्वरूप में परिभाषित किया जाये, तो कहेंगे कि इसमें पर्याप्त मनोरंजन की संभावनाओं के साथ-साथ तिक्तता की प्रेरणा से उत्तेजित जुगुप्सा भी हैं, इसमें हास्य की प्रतीति अलग प्रकार की होती है और उक्तियों का उपयोग साहित्य शिल्प के तौर पर होता है। हास्य के अभाव में व्यंग्य गाली का रूप धारण कर लेता है तथा साहित्यिकता के अभाव में वह विदूषक की ठिठोली मात्र बनकर रह जाता है।

व्यंग्य - व्यंग्य 'Satire' क्रोध की अभिव्यक्ति का एक उपकरण है। उसकी सफलता अभिव्यक्ति के सौष्ठव पर आधारित है। व्यंग्यकार, व्यंग्य-पात्र और आस्वाद; इन तीनों का सक्रिय योग व्यंग्य की पूर्णता के लिए अपेक्षित है और उसकी परिणति हास्य में होती है। व्यंग्य का लक्ष्य लोकहित है। मात्र आत्मतुष्टि के लिए प्रयुक्त समाज की आनन्पूर्ण स्वीकृति के अभाव में सफल नहीं हो पाता।

व्यंग्य की भाषा में तिक्तता अधिक होती है। इसके लिए तीन बातें आवश्यक हैं-निन्दा, सामाजिक हित, वर्तमान या जीवित लक्ष्य की सीमा।

व्यंग्य समझदारी और विवेकपूर्ण चिन्तन पर आधारित होना चाहिए। व्यंग्य का लक्ष्य सामाजिक कुरीतियों, व्यवहारों तथा रूढ़िमुक्त परम्पराओं को हेय और हास्यास्पद रूप में रखकर सुधारने का होता है। व्यंग्यकार समाज के एक अंग अथवा व्यक्ति विशेष पर ही व्यंग्य करता है, समष्टि पर नहीं। क्योंकि वह जानता है कि व्यंग्य की पूर्णता के लिए समाज का आनन्दपूर्ण योगदान आवश्यक है और यह तभी संभव हो सकता है, जब आघात समष्टि पर न हो। व्यंग्यकार का शिकार समर्थ, योग्य और शक्तिशाली होता है, परंतु वह उस रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता, केवल उसकी ओर संकेत किया जाता है। व्यंग्यकार का मूलभाव अनुदान है और उससे संपन्न कर्म सृजनात्मक न होकर ध्वंसात्मक होता है, इसलिए समाज में उसकी गणना कवि, कलाकार, महात्मा तथा संत के सदृश नहीं होती।

व्यंग्य वह पद्यमय अथवा गद्यमय रचना है, जिसमें तत्कालीन विषमताओं तथा विद्रूपताओं का मजाक उड़ाया जाता है। इसका अभीष्ट किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह का उपहास करना होता है अथवा जो एक व्यक्तिगत आक्षेप लेख समान होता है।'[6]

'व्यंग्यकार अपनी मर्ममेदनी दृष्टि से समाज के प्रत्येक पहलू पर पैनी नजर रखता है और तत्पश्चात् अपनी रचना में अपनी तीखी आलोचना करता है।'[7] पाठकों को गुदगुदाते हुए वह सामाजिक विकृतियों के प्रति नफरत उत्पन्न करता है। 'व्यंग्य रचना लेखकों की कल्पना की अपेक्षा उनकी प्रतिभा की परीक्षा है। व्यंग्यकार की विनोदशील प्रकृति के बीच एक क्रूर आलोचक छिपा होता है। जब आलोचना पर हास्य हावी होता है, तब रचनाकार विनोदशील की, शालीनता की रक्षा करते हुए मनुष्य की दुर्बलताओं की स्वीकृति प्रदान करता है।'[8]

पश्चिम के व्यंग्कार स्वीकार करते हैं कि व्यंग्य का प्रभाव एक तीर की भांति होना चाहिए, जो पलक झपकते ही लक्ष्य भेद करता हो, इसलिए इसका आकार जितना संक्षिप्त होगा, प्रभावान्विति उतनी ही श्रेष्ठ होगी। विस्तृत विवरण इसकी प्रभनिष्ठता को क्षींण कर देता है। 'व्यंग्यकार के लिए सामाजिक विकृतियां पीड़ादायक होती हैं। आत्मसंतुष्टि के लिए यह उसकी तींखी आलोचना करता है। अंग्रेजी व्यंग्य का उत्स रोमन साहित्य के प्रभावस्वरूप भी स्वीकार किया जा सकता है।'[9] जुबेनल और होरेस रोमन साहित्य के प्रतिष्ठित व्यंग्यकार हैं, जिनका अनुकरण अंग्रेजी साहित्य के व्यंग्य के प्रारम्भिक चरणों में किया गया है। स्विपर यहां का श्रेष्ठ लेंगलैण्ड रिचर्ड स्टील, जानसन, गोल्डस्मिथ आदि महत्वपूर्ण व्यंग्यकार है।

भारतीय आलोचकों की परिभाषाएं निम्नलिखित है-

1. **आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी -** 'व्यंग्य वह है, जहां कहने वाला अधरोष्ठ में हंस रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठा हो और फिर भी कहने वाले को जबाव देना अपने को और भी हास्यास्पद बना लेना आता हो।'[10]

2. **हरिशंकर परसाई -** 'व्यंग्य जीवन से साक्षात्कार करता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, मिथ्याचारों और पाखण्डों का पर्दाफाश करता है 'यह नारा नहीं है। मैं यह कर रहा हूं कि जीवन के प्रति व्यंग्यकार की उतनी ही ही निष्ठा होती है, जितनी किसी गंभीर रचनाकार की, बल्कि ज्यादा ही वह जीवन के प्रति दायित्व का अनुभव करता है। जिन्दगी बहुत जटिल चीज है। इसमें खालिस हंसना या खालिस रोना जैसी चीज नहीं होती, बहुत सी हास्य रचनाओं में करूणा की धारा होती है।'अच्छा व्यंग्य सहानुभूति का सबसे उत्कृष्ट रूप होता है।'[11]

3. **शरद जोशी -** 'अब यदि उन्हीं मूल्यों, विश्वासों और आस्थाओं से जुड़ा साहित्य सामान्य जिन्दगी से भी जुड़ा है, तो वह 'सेंस ऑफ ह्यूमर' साहित्य में आयेगा ही जो अन्याय, अत्याचार और निराषा के विरूद्ध होते व्यंग्य में अभिव्यक्त होगा। व्यंग्य की पहचान है कि साहित्य कष्ट सहती जिन्दगी के करीब है या जुड़ा हुआ है, नहीं हो सकता तो कहीं गड़बड़ी है।'[12]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विचार और विवेचन - डॉ. नगेन्द्र, नई दिल्ली (संस्करण 1949), प्र.सं.74।
2. विश्व साहित्य में रामरचित - राजबहादुर लमगोड़ा, वाराणसी (1948), प्र.सं. 152।
3. प्रकीर्णिका - आचार्य नन्दुलारे वाजपेयी, कानपुर (1965) प्र.सं. 152।
4. हिन्दी कविता में हास्य रस - रसेज सन्ना, इलाहाबाद (संस्करण 1969), प्र.सं. 50।
5. हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, वाराणसी

(संस्करण 1968), प्र.सं. 57।

6. हिन्दी व्यंग्य साहित्य – लेखक–डॉ. ए. एन. चन्द्रशेखर रेड्डी, शबरी संस्थान, नई दिल्ली (प्रथम संस्करण 1989), पृ. सं. 37।
7. हिन्दी का स्वातन्त्रयोत्तर हास्य और व्यंग्य – डॉ. बालेन्दु शेखर तिवारी, अन्नपूर्णा प्रकाशन, कानुपर (प्रथम संस्करण 1978), पृ. सं. 51।
8. कबीर – हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ. सं. 164।
9. सदाचार का ताबीज – हरिशंकर परसाई, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली (चौथा संस्करण 1981), पृ. सं. 3,91।
10. मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं – शरद जोशी, ज्ञान भारतीय प्रकाशन, नई दिल्ली (भूमिका सन् 1980)।
11. स्वातन्त्रोत्तर हिन्दी कविता में व्यंग्य – डॉ. शेरजंग गर्ग, पृ. सं. 27–28।
12. हिन्दी का स्वातन्त्रोत्तर हास्य और व्यंग्य – डॉ. बालेन्दु शेखर तिवारी, अन्नपूर्णा प्रकाशन, कानपुर (प्रथम संस्करण 1978), पृ. सं. 56।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

हिन्दी के समकालीन ऐतिहासिक उपन्यासों में जनचेतना के विविध आयाम

डॉ. लक्ष्मी गोयल *

प्रस्तावना – विश्व उपन्यास साहित्य का जन्म,विकास एवं समृद्धी जनचेतना के समानान्तर हुई है। उपन्यास जनचेतना का संवाहक ही नहीं, अपितु युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर गतिशील जन–जीवन का चितेरा है। यही कारण है कि उपन्यास जनचेतना की गोद में जन्म लेता है और युग जीवन की खाद से पोषित होकर नूतनता से सिंचित होता है। आज के जीवन की उथल–पुथल एवं भावगत अंतर्द्वंद्व की अभिव्यक्ति की सर्वोत्तम विधा उपन्यास ही है।[1]

मनुष्य की जीवन धारा चीर, प्रवाहशील, प्रगतिशील है। देश और काल के अनुसार इसमें सदैव परिवर्तन हुए है। उपन्यास उस प्रगतिशील मानव को यथार्थ परिवेश में चित्रित करने का प्रयत्न करता है, यही कारण है कि उपन्यास भी निरन्तर प्रगतिशील रहा है।[2] कभी वह सामाजिक जीवन से संबंधित समस्याओं का चित्रण करता है, कभी मानव–मन के द्वंद्वों की अभिव्यक्ति करता है, तो कभी वह इतिहास की छानबीन कर युग–विशेष को प्रत्यक्ष कर देता है या किसी ऐतिहासिक पात्र–विशेष को लेकर उसके सम्पूर्ण जीवन को प्रत्यक्ष कर देता है। इस प्रकार मानव–जीवन की प्रस्तावित रूपरेखा का विधान करने वाली विधा उपन्यास है, जिसका प्रगाढ़ सम्बन्ध व्यक्ति के जीवन एवं उसके युग से होता है।[3] समाज अधोगति और पतनावस्था की विविध प्रतिकूल परिस्थितियों में जो प्रतिभा आकर्षक दीप्ति बनकर चमक उठे और जिसके प्रभाव से समस्त समाज में जन–जागरण की लहर व्याप्त हो जाए, उसी को चेतना का वाहक समझा जाता है। रूढ़िगत विचारों को त्यागकर किसी नई दिशा में जब समाज प्रवृत्त होता है, और अपनी उन्नति की ओर अग्रसर होता है, तो यह कहा जाता है कि उस समाज में जागृति उत्पन्न हुई है।[5]

ऐतिहासिक चेतना परंपराओं से जुड़ी है। रूढ़ि का अर्थ–जड़ता है और परंपरा का अर्थ–निरन्तरता। रूढ़ि की साधना परंपरा के प्रति जागरूकता का मुख्य उपकरण है एक ऐतिहासिक चेतना अर्थात् जो कालानुक्रम में बीत गया है, अतीत है उसे बीतेपन की ही नहीं उसकी वर्तमानता की भी तीखी और चीर–जागृत अनुभूति। अज्ञेय के मतानुसार–आधुनिक हिन्दी लेखकों में यदि यह ऐतिहासिक चेतना होगी तो उसकी रचना में न केवल अपने युग, अपनी पीढ़ी से उसका संबंध बोल रहा होगा, बल्कि उससे पहले की अनगिनत पीढ़ियों की और उनके साथ अपनी पीढ़ी की संलग्नता और एक सूत्रता की भी तीव्र अनुभूति स्पंदित हो रही होगी जो 'है' उसके साधना में ऐसा साहित्यकार उसे एक ओर हटाकर नहीं फेंक सकेगा जो 'था' वह अनुभव करेगा कि 'अतीत' उसी का नाम है जो पहले से वर्तमान है, जबकि आज वह है जो वर्तमान होना आरंभ हुआ है। अतीत और वर्तमान के इस दोहरे अस्तित्व की उनकी पृथक वर्तमानता और उनकी एक सूत्रता का निरन्तर अनुभूति हो ऐतिहासिक चेतना है और इस चेतना का अनवरत स्पंदनशील विकास ही परंपरा का ज्ञान।[6] मनुष्य की सम्पूर्ण क्रियाओं एवं गतिशील प्रवृत्तियों का मूल कारण जन चेतना ही है। जन चेतना का विकास सामाजिक वातावरण के सम्पर्क से होता है। वातावरण के प्रभाव से मनुष्य नैतिकता, औचित्य और व्यवहार कुशलता प्राप्त करता है। यह चेतना का विकास कहा जाता है। विकास की चरम–सीमा में चेतना निज स्वतंत्रता की अनुभूति कराती है। ऐतिहासिक उपन्यास सामाजिक जनचेतना का प्रतीक है। ऐतिहासिक उपन्यास तो एक ऐसी कथा है, जो यथार्थ की प्रतिच्छाया होती है।[7] डॉ. त्रिभुवन के शब्दों में ऐतिहासिक उपन्यासकार का उद्देश्य मनोरंजन नहीं होता इतिहास का ज्ञान प्राप्त करना, भ्रांतियों का निवारण करना अथवा वर्तमान से संबंधित किसी चेतना को ऐतिहासिक आधार देना होता है। त्याग एवं बलिदान के प्रसंगों को यथास्थान रखकर पाठकों के हृदय को द्रवित करना लेखक का प्रतिपाद्य होता है, तथ्यों, नामों, तिथियों आदि पर ऐतिहासिक उपन्यासकार का विशेष ध्यान रहता है। इसमें लेखक कल्पना का सहारा लेता है, कल्पना के द्वारा वह लेखक के मानवीय गुणों को सजीवता प्रदान करता है।[8] इस प्रकार साहित्य में जनचेतना का महत्वपूर्ण स्थान है। जन प्रतिनिधि कलाकार के साहित्य में सामाजिक चेतना आवश्यक नहीं, अनिवार्य होती है, क्योंकि इसके बिना वह न मनुष्य की वास्तविक समस्याओं को पहचान सकता है न यथार्थ समस्याओं से समाज को अवगत करा सकता है और न ही उसे उचित दिशा प्रदान कर सकता है। साहित्यकार यह कर देता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वाह कर दिया। साहित्यकार को हर युग में यह ध्यान रखना पड़ता है कि– सृष्टि सम्पूर्ण पशुवत नहीं और न मानव ही पशुवत है मानव यदि देवत्व के गुणों से परिपूर्ण है तो उसमें पाशविक प्रवृत्तियॉं भी है। अतएव वह न देवता है, न पशु है, वह केवल मानव है, जिसमें दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ का विशिष्ट अनुपात है। उसकी समस्याएँ, कुँठाएँ, विवशताएँ तथा वञ्जनाएँ आदि बहुमुखी है, जो व्यक्तिगत न होकर समष्टिगत है। साहित्यकार का यह कर्तव्य है कि उसे व्यक्ति के दृष्टिकोण से नहीं, अपितु सामाजिक दृष्टिकोण से देखे व परखें। साहित्य जो समष्टिगत चेतना की उपज होता है, उसमें संशिलष्ट होती है।[9]

जनचेतना उपन्यासकार का एक ऐसा कारगर अस्त्र है तथा ऐसी पैनी दृष्टि है, जो साहित्य के भावपक्ष और प्रतिपाद्य में ही परिवर्तन नहीं लाती, अपितु उपन्यास के प्रस्तुतीकरण शिल्प में भी नूतन परिवर्तन प्रस्तुत करती है। समकालीन ऐतिहासिक उपन्यासों के अध्ययन से ज्ञान होता है कि– उपन्यास साहित्य तो यथार्थ की अनुकृति है तथा युगचेतना का अनुगायी है क्योंकि इसका जन्म ही परिवर्तन से और जन–चेतना की पृष्ठभूमि में हुआ

*अतिथि सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, गंधवानी, जिला–धार (म.प्र.) भारत

है। जन की गतिशील पृष्ठभूमि में जन-चेतना में परिवर्तन होता है, जिससे उपन्यास अछूता नहीं रह सकता है। ऐतिहासिक उपन्यास स्वयं इसका प्रमाण है। कुणाल की आँखे, बेगमात के आँसू, गुलारा बेगम, गंधर्वसेन, निष्कृति, सुहाग के नूपुर, बेकसी का मज़ार, शिल्पगत, भावगत एवं विचारगत परिवर्तनशील जनचेतना के मील स्तम्भ है।[10]

इनकी भाषा-शैली उत्तरोत्तर यथार्थवादी, चित्रात्मक तथा नाटकीय है। यही कारण है कि जनचेतना का वाणी-विधान करना इनका धर्म है और जन परिवर्तनशील है। फलत: उपन्यासों में भाव भी परिवर्तित होते जाते है। साथ ही वे किसी पूर्व योजना के अनुसार उपन्यास नहीं लिखते है। समकालीन उपन्यासों की प्रेरणा-भूमि युगपटल पर जैसे-जैसे परिवर्तन नर्तन करते है ठीक उसी के अनुरूप इनके साहित्य के प्रतिपाद्य भी बदल जाते हैं। यही कारण है कि इनके साहित्य में स्वर-खंडन की प्रवृत्ति भी मिल जाती है। किन्तु यह उपन्यासकारों का जीवन-दर्शन है जो साहित्यिक-दर्शन बन गया है।[11] समकालीन उपन्यासों पर तात्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक तथा शिल्पगत जन-चेतना का व्यापक प्रभाव पड़ा है। उनकी सांस्कृतिक चेतना में बौद्धिकता का आग्रह है, जिससे सांस्कृतिक धरातल पर अराजकता की स्थिति दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि सांस्कृतिक विरासत में गतिरोध की स्थिति आ गई है। विगत जीवन मूल्यों की आदर्श भावधारा का निषेध तो अवश्य किया गया है, लेकिन स्वस्थ जीवन-मूल्यों की स्थापना नहीं हो सकी है।[12]

1900 राजपुतों का पतन काल से लेकर स्वतंत्रता आन्दोलन के युग तक रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी रूचि के अनुकूल गुप्तकाल तक सीमित रहे। अपेक्षतया नए उपन्यासकारों आनंद प्रकाश जैन तथा अमृतलाल नागर अपने उपन्यासों में भारतीय इतिहास के विभिन्न काल क्षेत्रों का चुनाव ही कर सके है। इन उपन्यासों में वैयक्तिक समस्याओं के साथ सामाजिक और उससे भी अधिक राष्ट्रीय समस्याओं का विशेष विनियोग किया गया है। नारी की स्वतंत्रता एवं सत्ता-महत्ता की स्थापना, बहु-विवाह विरोध, पर्दा-प्रथा निवारण, विशिष्ट परिस्थितियों में तलाक के समर्थन, विवाहों में कुल एवं जात्याभियानों की विगर्हणा, विवाह में नारी की इच्छा-स्वीकृति के सम्मान, सास-बहू-ननंद की गृह-कलह में नारी के अपने अपराध अनौचित्य के अनावरण तथा विधवा, पतिता, वैश्या, दासी, देवदासी आदि के आधार पर नारी के पीड़ित-शोषित, अपमानित रूपों के प्रति संवेदना जगाने और चिंतन बाध्य करने में ऐतिहासिक उपन्यास पीछे नहीं रहे है।[13]

अत्याचारियों-आक्रांताओं से लोहा लेने वाली वीरांगनाओं को उभारा और प्रसिद्ध पुरूषों की महानता के मूल में नारी प्रेरणा एवं नारी-शक्ति के संधान से युग-युग की नारी के लिए उज्जवल आदर्श एवं क्रांति के कंगन प्रस्तुत किए है।[14]

डॉ. कृष्णा अग्निहोत्री ने निष्कृति के माध्यम से ऐतिहासिक कथा को नए रूप व नए-विचारों में प्रकट किया है और आज के जीवन की सच्चाईयों को प्रकट करने का प्रयास किया है। उन्होंने व्यक्तिगत समस्याओं और अंतर्द्वंद्वों के साथ-साथ सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष किया है।[15]

गंधर्वसेन क्षिप्रा के दर्द को विचलित करने वाली मर्मकथा है, इसमें दूसरी सदी की नायिका सरस्वती और उज्जयिनी नरेश गंधर्वसेन की ऐसी प्रणय-गाथा है, जिसमें नारी-मन का सच्चा संताप और शोकाकुल शब्दों में लिखी उसकी व्यथा अंतस को झकझोर देती है।[16]

गुलारा बेगम पगारे जी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास है। यह उपन्यासों में एक नई परंपरा का निर्धारण करता है। यह अपनी लींक से हटकर लिखा गया उपन्यास है। यह केवल गुलार और खुर्रम की प्रेमकथा नहीं बल्कि आम आदमी की कहानी है। इसमें मुगल दरबार की सत्ता-संघर्ष की कुटिल चालों का चित्रण है तो कोठे पर सजधज कर अपमान का जीवन जीने वाली नारियों की गहरी वेदना भी है।

दास्तान-ए-औरंगजेबी मुहब्बत की इतिहास को चौंकाने और स्तब्ध करने वाली घटना है, क्योंकि इतिहास औरंगजेब के जीवन के गोपनीय रहस्यों को उजागर करने में असफल रहा है। बेगम जैनाबादी के लिए उसकी तड़प और बेकसी उसकी शख्सियत का दूसरा अनछुआ पहलू है। हीरा की मोहब्बत में इस फकीर ने नृत्य, गीत संगीत, शराब, शबाब का आनंद उठाया। हीरा उनकी जिंदगी की तवारीख का रूमानी अध्याय है। हीरा की अचानक मौत ने न केवल औरंगजेब को बदला इतिहास की धारा बदल दी। काश! हीराबाई जिंदा होती तो मुगल इतिहास शायद दूसरी तरह से लिखा जाता।[17]

राजस्थान की पावन-भूमि पर जोधकुँवर का जन्म हुआ जहाँ शौर्य-स्वाभिमान एवं निडरता रही, वहाँ नारी का सदा भोग्या ही माना गया। कई क्षत्राणियाँ लड़कर शहीद हो गई, सीमित धारणाओं व पुरूषों के अधीन रह अपना अस्तित्व उनके इशारों पर निखारना पड़ा।

नीला चाँद – इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश के लिए छात्र-क्रांति, अंग्रेजी हटाओं आन्दोलन और 1961 की अभूतपूर्व बाढ़ को चुना है,

कुणाल संदर्भ – मौर्यकाल में उपन्यासकारों के सार्थक आकर्षण का केन्द्र तीन विभूतियाँ रही है- चाणक्य, चंद्रगुप्त और अशोक। इसमें वृद्ध अशोक की युवा रानी निश्यरक्षिता राजकुमार कुणाल के प्रति अपनी आसक्ति में असफल होकर उसकी आँखें निकलवानें के षड्यंत्र में सफल होती है। उधर कुणाल अपने अधिकार-रक्षा के लिए ललकारता है कि सम्राट अशोक की आज्ञा के बिना किसी को उसे अंधा करने का अधिकार नहीं और पिंजरे में बंद शेर की आँखें फोड़ना वीरता भी नहीं।[18]

शतरंज की मोहरे- इसमें अवध राज्य के कुछ सामाजिक व राजनैतिक घटना चक्र के माध्यम से उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वाध के काल का सजीव चित्रण है। गाजीउद्दीन हैदर अवध का बादशाह था उसकी बेगम धार्मिक ढकोसलेबाज थी और अपने जिद्दी एवं दम्भी स्वभाव के कारण अपने पति से झगड़कर अलग रहती थी स्वयं नि:संतान होने के कारण उसने अपनी प्रभुत्वकामना की सिद्धी के लिए एक दासी पुत्र नसीरूद्दीन को अपना पुत्र बनाकर उसे खेल के मोहरें की तरह इस्तेमाल करती है। और राजमातृत्व के स्नेह का जाल फैलाती है।

सुहाग के नूपुर – इस उपन्यास की नायिका माधवी उन वैश्याओं का प्रतीक है, जो जन्म से वैश्या नहीं होती और किसी-न-किसी बड़े कुलीन एवं धनाधीश की पुत्री भी हो सकती है, किन्तु दुर्भाग्यवश लूटी-चुराई और बेची जाकर परिस्थितिवश वैश्या बनती है। इसलिए माधवी में जहाँ एक वैश्या-सा सौंदर्य, हाव-भाव, कुशलता, प्रेम का नाटक या जादू करने की प्रवीणता है वहीं एक कुलवधु का एक प्रेम और धर्म-निरपेक्ष समर्पणशीलता भी है।

प्रेमचंद के सेवासदन में वैश्या सुमन का उद्धार हो जाता है, किन्तु वैश्या-बालाओं को समाज अपनाएगा या नहीं यह समस्या टेढ़ी खीर बनी रहती है। यही सोच माधवी की है कि-कहीं उसकी पुत्री को समाज की विगर्हणा से वैश्या-जीवन अपनाने पर बाध्य न होना पड़े। सुहाग के नूपुर की तार्किकता तथा वैचारिकता इस युग के वैश्या-जीवन पर लिखे उपन्यासों से बहुत आगे बढ़ी हुई है, अतएव यह आधुनिक है।[19]

इस प्रकार हम कह सकते है कि चेतना जो अनुभूतियों की जननी है, वह साहित्यात्मा है तो युगचेतना उसके अलोकमय नेत्र हैं, जिनसे वह सारे संसार का सौंदर्य आत्मसात करता है। साहित्य 'चेतना' के बिना निष्प्राण होता है तथा युगचेतना के अभाव में अंधा जो न वर्तमान के बारे में कुछ कह सकता है और न स्वर्णिम उषाकालीन भविष्याशा के पथ को देख सकता है। युग के गतिशील धरातल पर युग-चेतना परिवर्तनशील होती है, प्रत्येक भावी युग की युग-चेतना वर्तमान से भिन्न नए रंग में होती है। युग-चेतना का क्षेत्र इतना व्यापक होता है कि उसे सर्वांगीण रूप से साहित्य में बाँध पाना किसी साहित्यकार के लिए कठिन है। फिर भी काव्य की अपेक्षा गद्य में औपन्यासिक विधा में युग चेतना की अभिव्यंजना सरलतापूर्वक हो सकती है, क्योंकि कवि स्वप्नदृष्टा होता है और भावानुरूप शब्द शिल्पी भी, जबकि उपन्यासकार यथार्थ होता है।[20]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. महावीर- हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचन, पृष्ठ-4
2. डॉ. त्रिभुवन सिंह - हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद, पृष्ठ-1
3. डॉ. भगीरथ मिश्र- काव्य-शास्त्र, पृष्ठ-3
4. डॉ. लक्ष्मी सागर वाष्णेय- बीसंवी शताब्दी हिन्दी साहित्य नए संदर्भ, पृष्ठ-252
5. डॉ. लक्ष्मी सागर वाष्णेय- बीसंवी शताब्दी हिन्दी साहित्य नए संदर्भ, पृष्ठ-255-56
6. सर्जना और संदर्भ- त्रिशंकु, पृष्ठ-21
7. सर्जना और संदर्भ- त्रिशंकु, पृष्ठ-22
8. डॉ. बेचेन- आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य और चरित्र विकास, पृष्ठ-69
9. प्रताप नारायण टण्डन- हिन्दी उपन्यास कला, पृष्ठ-181
10. सर्जना और संदर्भ- त्रिशंकु, पृष्ठ-46
11. डॉ.त्रिभुवनसिंह- हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद, पृष्ठ-48-49
12. भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों में युग-चेतना, पृष्ठ-22-23 डॉ. बैजनाथ प्रसाद शुक्ल
13. हिन्दी उपन्यास सुरेश-सिन्हा- पृष्ठ-153
14. हिन्दी उपन्यास सुरेश-सिन्हा- पृष्ठ-169
15. निष्कृति- डॉ.कृष्णा अग्निहोत्री
16. गंधर्वसेन- डॉ.शरद पगारे
17. बेगम जैनाबादी- डॉ.शरद पगारे
18. कुणाल-संदर्भ- डॉ.आनंद प्रकाश जैन
19. शतरंज के मोहरे- अमृतलाल नागर
20. डॉ. सुरेश सिन्हा- उपन्यास शिल्प और प्रवृत्तियाँ, पृष्ठ-77
21. सुहाग के नूपुर- अमृतलाल नागर

****

हिन्दी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप

डॉ. अमित शुक्ल *

शोध सारांश – हिन्दी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली–समझी और पढ़ी–लिखी जाने वाली भाषा मानी जाती है। भारत में हिन्दी भषियों की संख्या अरबों में है जिसमें तीस करोड़ लगभग ऐसे है जिसकी मातृभाषा हिन्दी न होते हुए भी उसी तरह व्यवहार में लाने की क्षमता रखते हैं, जैसे–हिन्दी भाषा–भाषीलोग विश्व के 200 देशों में चार करोड़ बीस लाख भारतीय मूल के लोग बिखरे हुए है जिनमें आधे से अधिक हिन्दी बोलते और समझते हैं। इस दृष्टि से देखें तो 21वीं सदी के वर्तमान समय में संसार में हिन्दी जानने वाले अंग्रेजी से अधिक हैं।

शब्द कुंजी –हिन्दी भाषा, विश्व, भाषा संसार, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, भारतवंशीय, विश्वविद्यालयों, हिंदी व्याकरण।

प्रस्तावना – यदि किंचित् गहराई से विचार करें तो और भी विस्मयकारी तथ्य उजागर होंगे। चीनी भाषा संसार में सबसे बड़ी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। कहा जाता है कि राट्रभाषा होते हुए भी चीनी जानने वाले लोग समूचे चीन में उपलब्ध नहीं है। जिस प्रकार हिन्दी के भारत देश की राट्रभाषा होते हुए भी सभी भारतीय हिन्दी नहीं जानते, वही स्थिति चीन में चीनी की और इंग्लैण्ड में अंग्रेजी की है। इसीलिए भाषा के विशेषज्ञों का मानना है कि कुल मिलाकर हिन्दी ही विश्व की सर्वाधिक समझी और पढ़ी जाने वाली भाषा है। यह भी निश्चित है कि विगत 64 वर्षों में हिन्दी की शब्द संख्या में जितना विस्तार हुआ है, उतना विश्व की शायद ही किसी भाषा में हुआ हो।'शब्द–संख्या की दृष्टि से यह संसार की सबसे समृद्ध भाषाओं में से एकमानी जाती है। अंग्रेजी–जिसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा का गौरव प्राप्त है,उसके मूल शब्द जहाँ मात्र दस हजार हैं, वहाँ हिन्दी के ढाई लाख से भी अधिक हैं।'

हिन्दी सारे विश्व में नई दिशा–दृष्टि से आगे बढ़ रही है। विश्व में नए अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में हिन्दी जानने वालों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक वे देश जहाँ हिन्दी भाषा– भाषी क्षेत्र के भारतीय श्रमिक दासों के रूप में, लगभग सौ डेढ़ सौ वर्ष पहले गए थे और आज वहाँ के प्रमुख नागरिकों के रूप में, जिनकी गणना होती है– फीजी, मारिशिस, गियाना, सूरीनाम आदि। ये भोजपुरी, अवधी, मिश्रित हिन्दी बोलते हैं। बहुत बड़ी संख्या में ये हैं। दूसरे, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, नार्वे, के आप्रवासी भारतीय हैं। इनमें दक्षिण पूर्व एशिया के – म्यामार, थाईलैण्ड, सिंगापुर, मलेशिया तथा दक्षिण अफ्रीका, केन्या आदि देशों में बसे आप्रवासियों को भी शामिल किया जा सकता है। नेपाल की आधी से अधिक जन संख्या हिन्दी से परिचित है, थाईलैण्ड में हिन्दी जानने वालों की जन संख्या लगभग दो लाख है। बर्मा में भारतीय मूल के हिन्दी जानने वालों की संख्या लाखों में हैं।

विदेशों में बसे भारतवंशीय लोगों में हिन्दी को जीवित रखने में आर्य समाज, सनातन धर्म तथा अन्य धार्मिक संगठनों का योगदान है। अपने घर की भाषाभोजपुरी, अवधी आदि को उन्होने अपनी अस्मिता से जोड़े रखने में सहायता की है। मारिशस में हिन्दी को विशेष महत्व प्राप्त है। सन् 1910 से आर्य समाज की मारिशस में स्थापना के बाद वह निरंतर गतिशील रही है। यह स्मरणीय है कि सन् 1935 में जब भारतीय मूल के लोगों ने यहाँ अपने आगमन की शताब्दी मनाई तो हिन्दी के शिक्षण को अपनी अस्मिता और अस्तित्व से जोड़ने पर बल दिया। परिणाम यह हुआ कि आज वहाँ हिन्दी की अनेक संस्थाएँ सक्रिय है और हिन्दी को नए दृष्टि बोध से आगे बढ़ रही है। इस द्वीप ने हिन्दी को अनेक प्रतिभाशाली लेखक दिए– सोमदत्त लाखोरी, अभिमन्यु अनंत, रामदेव आदि। इन्होने फ्रान्सीसी और अंग्रेजी के प्रबल प्रभाव के बीच हिन्दी के वर्चस्व को बनाए रखने में ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह किया। आस्ट्रेलिया के निकट एक छोटा सा द्वीप 'फीजी' है, जहाँ हिन्दी को सदैव प्रतिष्ठा मिली। अनेक पत्र पत्रिकाएँ यहाँ से प्रकाशित होती रही हैं। सन् 1916 में स्थापित हिन्दी पाठशाला का आज भी गौरवपूर्ण स्थान है। वहाँ हिन्दी शिक्षण का कार्य एक धार्मिक अनुशठान की तरह चल रहा है। मिनीडाड की कुल आबादी के आधे लोग भारतवंशीय है, उनके बीच हिन्दी सम्मानित भाषाहै। भारतीयों के सम्पर्क में आने के कारण वहाँ रह रहे अफ्रीकी मूल के लोग भी हिन्दी शब्दों को ग्रहण कर रहे हैं। सूरीनाम में देवनागरी के साथ रोमन लिपि में हिन्दी लिखी जा रही है जिसे सरनामी हिन्दी, कहते हैं। सूरीनाम में एक विचित्र बात देखने को मिलती है कि जो आदमी हिन्दी नहीं जानता, उसका मंत्री बनना कठिन होता है। न्यूजीलैण्ड में हिन्दी के चल चित्र विशेष लोकप्रिय है। हिन्दी के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए भारतीय मूल के लोग वहाँ अलग से अपना दूरदर्शन और आकाषवाणी केन्द्र स्थापित किए हुए हैं। इंडोनेशिया में तो भाषा 'इंडोनेशिया' ही प्रचलित है जिसमें 18 प्रतिशत शब्द संस्कृत अथवा हिन्दी के हैं। वहाँ की तीनों सेनाओं के समाचार पत्र के नाम 'त्रिशक्ति' है। इंडोनेशिया भी मॉरिशस की भाँति हिन्दीमय है। दक्षिण अफ्रीका में हिन्दी के पठन–पाठन तथा पूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था है। अफ्रीका महाद्वीप के केन्या, उगान्डा, जैम्बिया आदि देशों में स्वाहिली भाषा के माध्यम से हिन्दी, गुजराती, पंजाबी आदि भारतीय भाषाएँ पढ़ाई जाती है। कम्पाला, नाइजीरिया, तंजानिया आदि में लाखों की संख्या में भारतीय हैं जो हिन्दी को उसकी पूर्ण आस्था के साथ जीवित किये हुए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी के विकास में विद्यालयों–विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागो का विशेष योगदान है। इस समय विदेशों में लगभग 200 विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है। इनके अतिरिक्त विदेशों के छोटे–बड़े उनके स्तरीय संस्थान हैं। जो वर्षो से हिंदी सेवा के कार्य में संलग्न

* एसोसिएट प्रोफेसर (हिन्दी) शा. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

हैं अकेले जापान में 12 के लगभग विश्वविद्यालय एवं संस्थान हिंदी की पढ़ाई में जुटे हैं, लगभग 700 जापानी छात्र हिंदी सीख रहे हैं। 'गोदान' का मूल हिंदी से जापानी में अनुवाद पेथोमो दोई ने किया जिसकी पांच लाख प्रतियां बिकी थीं। जापानी में आकाशवाणी के हिंदी समाचार नियमित रूप से प्रसारित होते हैं। अनेक वर्षो से जापान में 'सर्वोदय' नाम की पत्रिका प्रकाशित होती रही हैं। जापान में अप्रवासी भारतीयो ने अपने ही प्रयास से जापान भारतीय हिंदी पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया था। इसके अतिरिक्त अनेक हिंदी पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही है। प्रो. ची-थ्येन ने पेइचिंग में हिंदी-विभाग खोला था। प्रो. चिन्तिन डॉन, प्रो. ल्यू को नान आदि विद्वान भारत विद्या-विभाग में हिंदी पाठ्यक्रम का कोर्स पूरा कर चुके हैं। यह कार्य किये उन्हें अनेको वर्ष हो गए हैं। प्रेमचंद की निर्मला तथा रामचरित मानस का पद्यानुवाद उन्होंने ही किया था। 'यशपाल' के 'झूठ सच' का अनुवाद भी इन्होने किया। 'चित्र लेखा' मैला आंच के अनुवाद भी चीनी पाठको तक पहुंचाए गए थे। श्रीलंका के तीनो विश्वविद्यालयों में उच्च स्तर तक हिंदी पढ़ाई जाती है। पाकिस्तान में पंजाब विश्वविद्यालय के साथ-साथ करांची विश्वविद्यालय में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। संपूर्ण पश्चिमी दुनिया में हिंदी के प्रचार-प्रसार में विश्वविद्यालयों का महत्वपूर्ण योगदान है। यूरोप अमेरिका, आस्ट्रेलिया का शायद ही कोई स्तरीय विश्वविद्यालय हो जहां आज हिंदी के पठन पाठन की समुचित व्यवस्था न हो।

फिनलैंड के हेलसिंकी विश्वविद्यालय में गत अनेके वर्षो से हिंदी पढ़ाई जा रही है। वहां के प्राध्यापक प्रो बातिन तिम्बे ने गोदान का फिनिस भाषा में रूपांतर किया है। स्वीडन में सन 1968 से हिंदी विभाग प्रारंभ हुआ। इसी तरह नार्वे के ओस्लो विश्वविद्यालय में भी हिंदी पढ़ाने की विशेष व्यवस्था है। बुल्गारिया, हंगरी में भी हिंदी का कार्य और भी बडे पैमाने पर है। पोलैंड इस दिशा में और भी आगे है। पोलैंड के भारत स्थित वर्तमान राजदूत प्रो. मारिया क्रिस्तोक बृस्की संस्कृत और हिंदी के जाने माने विद्वान हैं। चेक गणराज्य का भारतीय साहित्य के प्रति विशेष मोह रहा है। चार्ल्स विश्वविद्यालय में हिंदी के पूर्व प्राध्यापक डॉ. ओदोलेन स्मैकेल हिंदी के विद्वान ही नही सुप्रतिष्ठित कवि भी रहे है। उनके हिंदी में लिखे आठ काव्य संग्रह प्रकाशित हुए है। रोमानिया के बुखारेस्ट विश्वविद्यालय में हिंदी का स्वतंत्र विभाग है जहां स्नातक स्तर तक हिंदी का पाठ्यक्रम है। बेलजियम और फ्रांस में भी हिंदी के अध्ययन की व्यवस्था है, इटली में भारतीय साहित्य एवं दर्षन के प्रति विशेष आकर्षण रहा है। वहां के नेपल्स और वेनिस विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागो में अनेक इटालियन छात्र हिंदी अध्ययन में संलग्न है। इंग्लैंड में कैम्ब्रिज, यार्क तथा लंदन विश्वविद्यालयों में उच्चतम स्तर तक हिंदी के पढ़ाए जाने की पूर्ण व्यवस्था है। डॉ. रूपर्ट स्नैल हिंदी के ही नहीं ब्रज भाषा के अनन्य भक्त हैं। आधुनिक यूरोपीय भाषाओ में जर्मन में संस्कृत, हिंदी का वैज्ञानिक स्वरूप प्राप्त है। कभी सोवियत संघ में हिंदी का विशिष्ट स्थान था। 34 से भी अधिक संस्थानों में हिंदी पाठ्यक्रम चलते थे। सोवियत संघ के विघटन के साथ सब कुछ अस्त-व्यस्त हो गया था। रूसी में हिंदी पुस्तकों का जितना अनुवाद प्रकाशित हुआ उतना शायद ही संसार की किसी भाषा में हुआ हो। अमेरिका में 28 विश्वविद्यालय तथा अनेक स्वयं सेवी संस्थाएं हिंदी के प्रति समर्पित भाव से जुटी हैं। वहां 1975 में हिंदी व्याकरण भी तैयार किया गया था।

निष्कर्ष यह है कि भारत की स्वाधीनता के पष्चात विश्वभर में हिंदी को जो मान्यता मिली वह विश्व की अनेके भाषाओ के लिए दुर्लभ है। हिंदी के इस जगतव्यापी प्रचार-प्रसार में चल-चित्रों की भी अहम भूमिका है। जो लोग हिंदी नही जानते किसी भारतीय भाषा से परिचित नहीं उन्हें भी हिंदी फिल्में रिझाती रही हैं हिंदी फिल्में विश्व को जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी है। वी.वी.सी. दूरदर्शन पर महाभारत इतना लोकप्रिय हुआ कि भारतीय ही नहीं, अन्य देशो के अप्रवासी ही नहीं स्वयं ब्रिटेन के तरूण वृद्ध सभी अतीत के भारत की शौर्य गाथा पर मुग्ध हो गए थे। सूरीनाम दूरदर्शन तुर्की, इराक, सउदी अरब, मिश्र आदि में इसे चाव से देखा गया। सारी दुनिया में जितनी फिल्में आज हिंदी की देखी जा रही हैं उतनी शायद ही किसी भाषा की हों। यह 21वीं सदी की महत्वपूर्ण देन है जो हिंदी के विकास का एक दृढ़ माध्यम है, कम्प्यूटर, इंटरनेट, ई-मेल, फैक्स आदि संचार माध्यमों में हिंदी को दृढ़ किया है। यह सब तो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के विकास का दूरगामी प्रभाव पड़ा है। पर हमारे देश में हमारी राष्ट्र भाषा को उचित मान्यता क्या अभी तक मिल पाई है यह एक सवाल है। हमारे राजनेता विदेश यात्राओं पर अपनी राष्ट्र भाषा की अपेक्षा अंग्रेजी में बोलना अधिक पसंद करते है, क्यों? इससे वहां के लोगो पर प्रतिकूल असर पड़ता है लोग प्राय: सोचते हैं कि क्या इस देश की कोई अपनी राष्ट्र भाषा नही। हमारे राजदूत हिंदी में बोलना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल मानते हैं। नेताओं की इस मानसिकता को बदलना होगा। हम हिंदी को राष्ट्र संघ की भाषा बना सकते थे पर अरबी भाषा की तरह अनुदान देकर। हमारी प्राथमिकता में हिंदी ही कब है? हिंदी भाषियों का ही हिंदी के प्रति उपेक्षा भाव है तब औरों की क्या कहें? हम हिंदी भाषा भाषी ही यदि हिंदी को सही ढंग से अपनाते तो हिंदी राज भाषा राष्ट्रीय भाषाऔर अंतर्राष्ट्रीय भाषा स्वत: हो जाती, जिस पर लोग संदेह करते है कि यह राज भाषा है कि नहीं। पर यह निषिचित है, ऐसा विश्वास है कि हिंदी अपने अस्तित्व की लड़ाई अवश्य जीतेगी। हर मोर्चे पर जीतेगी। धीरे धीरे एक परिवर्तन आ रहा है। देश भर में और विश्व भर में हिंदी अपनी पहचान बनाती जा रही है। हिंदी की गरिमा बढ रही है। हम हिंदी वालो में धीरे-धीरे आत्म गौरव भी आ रहा है। अब हिंदी बोलने लिखने वालो में हीन भावना नही दिखलाई देती। हिंदी का प्रचार प्रसार अनेके विघ्न-बाधाओ के बावजूद निरंतर हो रहा है। यह विश्वास है कि 21वीं शताब्दी हिंदी की है और भविष्य में भी रहेगी। निष्चित ही मीडिया और जनसंचार ने इसे अंतराष्ट्रीय स्तर तक दृढ़ता प्रदान की है। राष्ट्रभाषा हिंदी को नए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में देखने समझने और मान्यता देने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दीक्षित सूर्य प्रसाद, विदेशों में व्याप्त रूमानी हिन्दी, अक्षरा साहित्य की द्विमास की म.प्र. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हिन्दी भवन, भोपाल अंक 105 पृष्ठ 32
2. पांचाल परमान्द हिन्दी के प्रति बढ़ती उदारसीनता अक्षरा साहित्य की द्विमास की म0प्र0 राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हिन्दी भवन, भोपाल अंक 105 पृठ 29,
3. रचना द्विमास की पत्रिका हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल द्वारा प्रकाशित अंक 66 अगस्त 2007 पृष्ठ 25,
4. साहित्य अमृत मासिक पत्रिका आशफ अली रोड नई दिल्ली, अक्टूबर 2010 पृष्ठ 25
5. स्वयं का सर्वेक्षण एवं निष्कर्ष

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

जयप्रकाश कर्दम रचित 'मोहरे' कहानी की प्रमुख समस्याएँ

डॉ. मजीद कुरैशी *

प्रस्तावना – किसी भी कहानी, उपन्यास, नाटक या एकांकी लेखन के पीछे लेखक का एक विशेष उद्देश्य होता है। जिसकी पूर्ति व अपनी लेखन क्षमता की माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत करता है। कोई भी कहानी पात्रो के आपसी संवादो के माध्यम से आगे बढ़ती है। और उसकी विशेषताओ से पाठक को परिचित कराती है। ऐसी एक कहानी जयप्रकाश कर्दम द्धारा लिखी गई है। जिसका नाम 'मोहरे' है। इस कहानी के माध्यम से श्री कर्दम जी ने शिक्षा व्यवस्था के दूषित रूप को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उन्होने कहानी में यह बताया है कि किस प्रकार आज का शिक्षक अपने कर्तव्य से विमुख होकर केवल अपने हित के बारे में सोचता है। और इसके लिये वह अपने सहयोगी शिक्षक जो उसके जैसे नही है। बल्कि शिक्षक ही नही है। इनसे जुडे उच्च अधिकारी भी जिम्मेदार है। जो बिना बात ही सही जानकारी लिये चापलूस लोगो की बातो में आ जाते है। कहानी में ऐसी कुछ समस्याएँ कर्दमा जी ने हमारे समक्ष रही है। कहानी में यह बाताया गया है कि किसी प्रकार एक ईमानदार शिक्षक इस भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार होता है।

कहानी का संक्षिप्त कथा सार – कहानी आरंभ होती है एक स्कूल से जिसके प्रथम अंक में यह दिखया गया है। कि छुट्टी के बाद कैसे अध्यापक हाजरी लगाने के लिये प्रधानाचार्य के कमरे में टुट पडते है, लेकिन उन्ही अध्यापको में से एक अध्यापक है जो सत्य प्रकाश सबसे दूर खडा अपने साथी अध्यापको को रजिस्टर को छिना झपडी करते हुए देख रहा है। सत्य प्रकार एक इमानदार एवं अपने कर्तव्य का अच्छे से निर्वह करने वाला शिक्षक है बच्चे उसे बहुत पसंद करते है। यहा तक कि हर साल जब 'बेस्ट टीचर्स' पुरस्कार के लिये सूचि जाती तो सत्य प्रकाश का नाम सबसे उपर रहता था। लेकिन किन्ही कारणो वश उसे यह अवार्ड नही मिलता था।

कहानी में मोड तब आता जब प्रधानाचार्य उसे बताते है कि कक्षा सात का छात्र है मनोज उसके पिता ने तुन्हारे खिलाफ कम्पलेन्ट करता है। सत्यप्रकाश ने उन्हे समझाने की बहुत कोशिश की मगर वे सत्यप्रकाश की एक भी सुनने को तैयार नही हुए और कहा कि जो कुछ भी कहना है। डिप्टी डायरेक्टर साहब से कहना कम्पलेन्ट का कारण यह बताया गया है कि सत्यप्रकाश ने कक्षा सात के मनोज नाम के एक लडके की इतनी बेहरमी से पिटाई की जिसके कारण उसके नाक से खून निकलने लगी और उसके हाथ को इस तरह मरोडा की उसके हड्डी में फ्रेक्चर आ गया। जबकि सत्य सह नही था बल्कि आपसी जलन के कारण सत्यप्रकाश के ही एक सहयोगी अध्यापक रामदेव त्रिपाठी ने उस लडके के घर जाकर उसके पिता को सत्यप्रकाश के खिलाफ भडकाया और उसके खिलाफ कम्पलेन्ट करने को कहा। पहले तो मनोज के पिता तैयार नही हुए लेकिन त्रिपाठी के सामने उनकी एक नही चली। अन्त में स्यंम त्रिपाठी ने सम्यप्रकाश की कम्पलेन्ट अपने हाथो से लिखी जिसके कारण सत्यप्रकाश की बदनामी हुई इसके पश्चात् जब एक दिन यह सूचना मिलती है। कि डिप्टी डायरेक्टर साहब आ रहे है। सभी अध्यापको के चाल चलन बदल जाते है। जल पान के बाद इन्क्वारी शुरू होती है। मनोज से प्रश्न पूछा जाता है। मनोज कुछ नही बोलता है तो उसकी चुप्पी को सहमति मान लेते है। फिर सत्यप्रकाश का ब्यान दर्ज किया जाता है। लेकिन गवाहो के झुठे बयानो के समक्ष उसकी सच्चाई दब जाती है अन्त में सत्यप्रकाश को दोषी पाया जाता है। और उसका तबादला ऐसी जगह किया जाता है। जहा आने जाने का कोई साधन नही होता सत्यप्रकाश तबादले का आदेश लिये स्कूल से बाह हनकलता है और सोचता है कि आखिर मेरे समाज के लोग कब तक दुसरो के हाथ के मोहरे बनते रहेगें। इस प्रकार कहानी का अंत होता है।

उपर्यक्त कहानी में लेखक ने हमारे सामने शिक्षा व्यवस्था से संबंधित अनैक समस्याओ को प्रस्तुत किया है। इस काहनी के आधार पर हम उन समस्याओ का विवरण नीचे दे रहे है–

1. **नैतिक पतन –** प्रस्तुत कहानी के आधार में हमें जिस परिवेश से परिचित कराया गया है। उस परिवेश को देखते हुए हमे यह प्रतित होता है कि कुछ अध्यापको को अगर छोड दिया जाये तो अधिक्तर शिक्षको का नैतिक पतन हो चुका है। और इसमें छात्र भी शामिल है। नैतिक पतन से तात्पर्य यह है कि कोई भी अपने पद की गरिमा एवं कर्तव्य निष्ठा को नही समझता है। कि वह भूल गये है। कि अध्यापक का काम छात्रो को अच्छी शिक्षा को देकर उन्हे आदर्श नागरिक बनाये ताकि वह भविष्य में अपने लिये तथा देश के लिये कुछ कर सके। लेकिन इसके लिये केवल अध्यापक ही जिम्मेदार नही है। बदली परिस्थितियां एवं शिक्षा के व्यवसायी करण के कारण व मिडिया के प्रभाव भी छात्रो के नैतिक पतन के लिये जिम्मेदार है। पहले छात्र गुरूकुल में शिक्षा प्राप्त करता था। आज का छात्र ज्ञान को प्राप्त करने के साथ–साथ उसे खरीदना भी चाहता है। और वो भी अत्यंत कम समय में इस नैतिक पतन का कारण समाज का हर वह व्यक्ति है। जो स्यंम के हित के लिये दुसरो को हानि पहुँचाता है।
2. **उत्तर दायित्व की कमी –** कोई भी कार्य अच्छे से तब तक पुरा हनी हो सकता जब तक की हम उस कार्य को पूर्ण उत्तर दायित्व की भवना से न करे। प्रस्तुत कहानी में यह दिखया गया है कि अध्यापको में अपने कार्य प्रति उत्तर दायित्य की भवना की कमी है। वे अपना काम उत्तर दायित्व समझकर नही बल्कि औपचारिता समझकर करते है। कहानी में जिस प्रकार अध्यापक का चित्रण किया गया है। उह अध्यापन कार्य के अलावा सब कुछ करता है। या फिर कक्षा में जाकर एक छात्र को

* अतिथि सहायक प्राध्यापक, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, चौरई, जिला – छिन्दवाडा (म.प्र.) भारत

खडा करके पढने को कहता है और सब सुनेगे, यह कहकर कक्षा से बाहर आ जाता है। इस कारण छात्रो का मनोबल गिरता है। वे भी अपनी पढाई के प्रति लापवाह हो जाते है। इस का नतीजा यह होता ह, कि छात्र अपनी परीक्षाओ के दौरा असफलता प्राप्त करते है। इसके लिये अध्यापक को जिम्मेदार ठहराया जाता है। यह सत्य की कुछ अध्यापक अपने कार्य के प्रति लापरवाही करते है। जैसा कि इस कहानी में दिखया गया है। जहा एक तरफ अच्छे अध्यापको में सत्यप्रकाश है वही उनके विपरीत में त्रिपाठी जैसे अध्यपक भी है। जो अपनी जवाबदारी को नही समझते है।

3. **व्यवस्था का दूषित होना –** समाज की प्रत्येक बुराई के लिये सदा शिक्षा व्यवस्था को दोष दिया जाता रहा है। शिक्षा समाज की आधार षिला होती है लेकिन यह व्यवस्था दूषित हो चूकि है। प्रस्तुत कहानी 'मोहरे' में इसके बारे में बताया गया है। इसके कारण कुछ बुरे परिणामो की तरफ लेखक ने संकेत दिया है।
4. **पारस्परिक वैमनस्य –** प्रस्तुत काहानी में हमे पारस्परिक वैमनस्य की भावना भी देखने को मिलती है जिसके कारण सत्यप्रकाश के सहयोगी अध्यापक, जो सत्यप्रकाश से उसकी छात्रो के बीच में लोकप्रियता से जलते थे। इसका उदाहरण इस कथन के माध्यम से देख सकते हे– **'कहना तो नही चाहिए क्योकि मै भी एक मास्टर हूँ पर अन्याय नही देख सकता आज सत्यप्रकाश मास्टर ने आपके बेटे की इतनी बेहरमी से पिटाई की है कि उसकी नाक से खून आ गया और इतनी जोर से बाह ऐंठी की लडका बिलख कर रह गया।'**[1]

निष्कर्ष – प्रस्तुत कहानी के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहॅुचते है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली दूषित हो चूकि है शिक्षको एवं छात्रो अनेक बुराईयो का समावेश हो चूका है। जिसके कारण दोनो में उत्तर दायित्व की भावना में कमी आ गई है । और जो इमानदारी से अपने कर्त्वयो का निर्वाह करने वाले अध्यापक बचे है वे इस दूषित एवं भ्रष्ट व्यवस्था के शिकार होते है। जैसा कि कहानी मे सत्यप्रकाश के साथ हुआ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. वसुधा 58 जुलाई – सितम्बर संपादक प्रो.कमला प्रसाद , वाणी प्रकाशन , नई दिल्ली पृ.क्र. 203

****

केदारनाथ अग्रवाल की कविता में लोक सौन्दर्य दृष्टि

डॉ. कुमुद कला मेहता *

प्रस्तावना – ज्ञान, संवेदना, विचार, विवेक, लगन, आस्था से परिपूर्ण केदारनाथ अग्रवाल को महज एक कवि, लेखक, आलोचक, विचारक जैसी पारिभाषिक शब्दावलियों की सीमा में बाँधा नहीं जा सकता। विचारों की जितनी व्यापकता और सघनता केदार जी की कविताओं में देखने को मिलती है, अन्यत्र कहीं नहीं। प्रकृति, लोक जीवन के दु:ख-सुख, आशा-निराशा संघर्ष और जिन्दगी से गहरा लगाव – केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं को विशिष्ट बनाते हैं। विशिष्ट इस अर्थ में कि ये अपनी कविताओं में युग की सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं।बकौल केदार जी के शब्दों में 'मैं आदमी की महत्ता इसमें समझता हूँ कि वह अपनी चेतना को मानव बोधी बनाता चले, लोक में लीन रहे; स्वयं, जग और जीवन से, प्रकृति और परिवेश से, लोक व्यवहार से द्वन्द और संघर्ष करता रहे और सत्य से सम्बद्ध होते-होते भ्रम और मिथ्या का परित्याग करता रहे। जो ऐसा नहीं करता, वह अविकसित बना रहता है; असंबद्ध होकर, व्यक्ति सबसे कटकर, अकेले में मर जाता है। यह प्रवृत्ति का संवदेन रूप है। इसलिए वह शिल्प या प्रणाली भी है। यह स्थिति सौन्दर्यानुभूति की है। सौन्दर्य मानवीय चेतना की क्षमता है। इनमें एक तरफ छायावादियों की तरह प्रकृति से गहरा लगाव दिखलाई पड़ता है तो दूसरी ओर प्रगतिशील काव्य आंदोलन के दौर की वैचारिक प्रखरता भी। पर न तो प्रकृति के प्रति लगाव इन्हें छायावादियों की वायवीय कल्पनाशीलता से बाँधाता है न ही वैचारिक प्रखरता इनकी कविताओं के गहरे भाव-बोधा को उथला बना पाती है – इसके पीछे कारण है लोक जीवन में इनकी गहरी पैठ और भाषा में विडंबना, विसगंतियों के गहरे अर्थपूर्ण प्रयोग। यह गौर करने की बात है कि आजादी के आंदोलन के दिनों में अनेक कवियों ने राष्ट्रीयता बोधा और देशभक्ति की कविताएँ, पर जिस तरह विडंबनाओं का प्रयोग केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी कविताओं में किया है, वह दुर्लभ है। एक चित्र प्रस्तुत है –

देश को आजाद कर लें
वीर नर है इस फिकर में
चैन से है भैंस सर में

इन पंक्तियों में बिम्ब के प्रयोग में अद्‌भुत कौशल है। भाषा सीधाी और सपाट है। मगर बिंब चौंकाने वाले हैं। एक बिंब उभरता है उन देशभक्तों का, जो देश को आजाद करने की चिंता में घुल रहे हैं, अंग्रेजों की बंदूकों के सामने सीना खोले खड़े हैं, दूसरी तरफ भैंस का बिंब है, वह तालाब में लोट रही है। डॉ. रामविलास शर्मा ने अपने एक भाषण में इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि यह केदार की राजनीति कविताओं का अपना विशिष्ट अंदाज है। इस विशिष्ट अंदाज को हम इसके बिंब की विशिष्टता में देख सकते हैं। पहले देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वालों का बिंब सामने आता है, पर तुरंत तालाब में लोट रही भैंस का चित्र सामने आ जाता है। दोनों बिंबों में कोई तुलना नहीं है। यही वह बिन्दु है जब पाठक झटके में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुँचता है और तब कविता के अर्थ खुलने लगते हैं। तालाब में 'लोट रही भैंस' का बिंब देश के उन सामंतों, पूँजीपतियों की ओर संकेत करते हैं जो अंग्रेजों की दलाली करते थे। डॉ. रामविलास शर्मा इनकी कविताओं में राजनीतिक रंग देखते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पर राजनीतिक विचार इनकी कविताओं में सीधो नहीं आते, वे जीवन की गहराई से उभरकर सामने आते हैं। जीवन के प्रति अटूट आस्था ही इनकी कविताओं का मूल स्वर है। राजनीतिक, सामयिक जीवन के संकट इस जीवन से बाहर नहीं हैं, इसलिए केदार की कविताओं में संघर्ष है, मेहनतकशों के पसीने बहाने के चित्र हैं, किसानों, मजदूरों के श्रम के प्रति गहरा आत्म-विश्वास है। निस्संदेह केदार जनवादी थे, पर जनवादी चेतना उनकी कविता के सौंदर्य बोधा के ऊपर-ऊपर नहीं तैरती दिखलाई देती, वह बिंबों, विडंबनाओं में रची-बसी है। इसीलिए वे भाषा में एक से बढ़कर एक अनूठे चित्र प्रस्तुत करते हैं।

'कंधो पर लिए नदी
मूँड पर धारे नाव'

यह बिंब अद्‌भुत है, कलात्मक है, मगर स्पष्ट रूप से जीवन के संघर्ष को, मेहनतका किसान और मजदूर की पीड़ा को व्यक्त करता है। भाषा के साथ केदार जिस प्रकार खेलते हैं वह कौशल सिर्फ अज्ञेय में दिखलाई पड़ता है, मगर वे अज्ञेय की तरह व्यक्ति के अवसाद के चित्रण में विश्वास नहीं करते। उनमें वर्गीय चेतना की समझ स्पष्ट है।

जीवन के प्रति गहरा लगाव, और उनकी वर्गीय चेतना इनकी कविताओं में लोक सौंदर्य दृष्टि का सृजन करती है। यह वही लोक सौंदर्य दृष्टि है जिसका प्रारंभ निराला की कविता वह 'तोड़ती पत्थर' से होता है। छायावादियों की तरह इनमें भी प्रकृति के प्रति लगाव है, लेकिन यह जीवन की वास्तविकताओं से दूर नहीं है। डॉ. बच्चन सिंह कहते हैं कि इनका प्रकृति प्रेम जीवन के व्यापारों से जुड़ा हुआ है। इसमें भावुकता नहीं है, कवि प्रकृति के सुंदर दृश्यों में खो नहीं जाता। बच्चन सिंह के अनुसार इसमें गाँव के किसानी प्राकृतिक परिवेश से एकतान कर दिया गया मालूम पड़ता है-

'रोक बीते के बराबर
यह हरा ठिगना चना
बांधो मुरैठा शीश पर
छोटे गुलाबी फूल का'

इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने निजी जीवन में केदारनाथ अग्रवाल अकेलेपन की पीड़ा महसूस करते थे। बाँदा जैसी छोटी जगह में रहकर वे व्यापक जीवन से अलगाव महसूस करते थे, पर यह अलगाव उन्हें प्रयोगवादी कुंठा या अवसाद का शिकार नहीं बना पाता तो इसका कारण

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) राँची कॉलेज, राँची (झारखण्ड) भारत

लोक जीवन से उनका गहरा लगाव ही था।

यह धयातव्य है कि केदारनाथ अग्रवाल लोक सौंदर्य बोधा की दृष्टि से निराला और नागार्जुन के करीब ठहरते हैं। निराला ने अपनी कविताओं में जगह–जगह व्यंग्य, विडंबना के प्रयोग किए हैं। उदाहरण के लिए उनकी 'कुकुरमुत्ता' कविता को देखा जा सकता है। इसी प्रकार नागार्जुन की कविताओं में भी व्यंग्य और विडंबना के प्रयोग हैं। आजादी के आंदोलन को लेकर निराला का दृष्टिकोण आम स्वतंत्रता समर्थकों से भिन्न था। उन्होंने लिखा था कि 'भेद वह खुल जाय जो तुम्हारे दिल में है। देश को मिल जाय जो पूँजी तुम्हारे मिल में है' – जाहिर है कि निराला के लिए आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को देश से निकालना नहीं था, बल्कि देशी पूँजी का विकेन्द्रीकरण हो, यह भी उनका दृष्टिकोण था क्योंकि इसके बिना जनता की समस्याओं का खात्मा संभव नहीं था। केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में भी इसी आम आदमी के प्रति चिंता है। इनके लिए भी आजादी का मतलब यही था कि देश के मेहनतकश किसान मजदूरों की जिन्दगी बेहतर हो। यह गौर करने योग्य है कि निराला की तरह ही प्रेमचंद भी महसूस कर रहे थे कि जबतक आजादी का आंदोलन किसानों मजदूरों के शोषण से मुक्ति के आंदोलन से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक आजादी का कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आयेगा। उनके 'गबन' उपन्यास का एक पात्र देवीदीन गांधी जी के अनुयार्यिों से पूछता है कि साहब, सच बताओं, तुम जो सुराज लाने जा रहे हो, वह कैसा होगा? तुम भी साहबों की तरह बंगलों में रहोगे, मोटरों में सैर करोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, तो देश का भला क्या खाक होगा? इसी प्रकार निराला पूँजीपतियों के हाथों में केन्द्रित पूँजी के विकेन्द्रीकरण की बात कहते हैं और केदार तालाब में लोट रही भैंस के चित्र के माधयम से सामंतों–पूँजीपतियों पर सीधाा व्यंग्य करते हैं –

आग लगे इस राम–राज में
ढोलक मढ़ती है अमीर की
चमड़ी बजती है गरीब की
खून बहा है राम–राज में

पूँजीपतियों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं –

मिल मालिक का बड़ पेट है
बड़े पेट में बड़ी भूख है
बड़ी भूख में बड़ा जोर है
बड़े जोर में जुलुम घोर है

केदारजी के अनुभव लोकजीवन में इसी एकात्मकता से मिलता है। कवि आत्मलोप की क्षमता से काल और देश के इतिहास में व्याप्त हो जाता है। खुद निराकार होकर सबमें व्याप्त हो जाता है। स्रष्टा का यही लक्षण है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. गूँज (स्मृति अंक) सं0 – अकिंचन, वर्ष–8, अंक 9–11
2. हिन्दी का गद्य साहित्य – रामचन्द्र तिवारी
3. वाद–विवाद–संवाद–नामवर सिंह
4. कविता का उत्तर जीवन– परमानन्द श्रीवास्तव

****

राष्ट्रकवि 'दिनकर' के काव्य का अनुशीलन – राजनीति के विशेष संदर्भ में

डॉ. इला द्विवेदी *

प्रस्तावना – राजनीति अर्थात् राज्य की नीति। यहाँ राज्य के अन्तर्गत राज्य के प्रबन्धक स्वयमेव ही आ जाते हैं। आज पूरे विश्व में राजनीति का बोलबाला है। उसके बिना मानव जाति के कल्याण की कल्पना ही असम्भव है। आज का मानव इस दृष्टि से बहुत सजग भी हो गया है। राजनीति में वह सक्रिय भूमिका निभाता है क्योंकि आज प्रजातंत्रीय राजनीति प्रभावशील है। आज राजनीति के समक्ष विकराल स्थितियाँ खड़ी हैं – प्रथम तो जिनके कल्याणार्थ उसने अस्तित्व पाया, उनके प्रति अपने दायित्व की पूर्ति वह नहीं कर पा रही है, दूसरे वह निरंकुशता की ओर बढ़ रही है और तीसरे उसके कारण संसार में युद्ध की विभीषिका आ पनपी है तथा शान्ति का नामोनिशान मिटता जा रहा है।

साहित्यकार समाज का दिग्दर्शक एवं पथ-प्रदर्शक होता है इसलिए वह अपने तरीकों से राजनैतिक क्षेत्र में व्याप्त बुराइयों और लोक विरोधी प्रवृत्तियों को मिटाने पर तुल जाता है। समाज की अपेक्षा भी साहित्यकारों से यही होती है। इसी अभियान के तहत कवि दिनकर ने जनसमुदाय में यह चेतना जागृत करने की चेष्टा अपने काव्य द्वारा की है कि साम्राज्यवाद का जो रोग आज जड़ पकड़ रहा है उसे समूल मिटाने का प्रयत्न हो। निरंकुश शासकों का विरोध किया जाये तथा युद्ध एवं शान्ति सम्बन्धी दृष्टिकोण पर सन्तुलित ढंग से विचार किया जाये।

साम्राज्यवाद अर्थात् एक देश द्वारा अन्य देशों को जीतकर वहाँ की जनता पर अपना शासन चलाना। साम्राज्यवाद की यह प्रक्रिया अति भयानक है क्योंकि इसमें शक्तिशाली देश के सैनिक एवं जनता कमजोर देशों की जनता पर आक्रमण कर उसकी स्वतन्त्रता को हरण करने का प्रयास करते हैं। उनको शोषण और अत्याचारों से बिल्कुल शक्तिहीन बना देते हैं।

आज हमारा भारत देश साम्राज्यवाद की ऐसी ही अन्यायपरक नीतियों का शिकार होने की कगार पर है। अमेरिका जैसा अपने आपको सर्व शक्ति सम्पन्न मानने वाला देश उसे कभी भी आँखे दिखाने लगता है। चीन और पाकिस्तान हमारी सीमाओं का अतिक्रमण कर हमारी भूमि पर अपना कब्जा करने की जुगत में तत्पर रहते हैं। दूसरी ओर इन स्थितियों में विडम्बना यह है कि हमारे देश के राजनीतिज्ञों को राष्ट्र की तनिक भी परवाह नहीं है। वे स्वस्थ राजनीति नहीं करते। सत्तासीन होने की महत्वाकांक्षा में वे शासन द्वारा किये गये अच्छे कार्यों को भी गलत साबित करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाने से बाज नहीं आते। अपितु निन्दनीय षड्यन्त्र भी रचते रहते हैं। वे एक दूसरे को मात देने वाले आपसी दाँव-पेंचों में ही उलझे रहते हैं। उन्हें चिन्ता है बस अपना खजाना भरने की। वे पूरी तरह भ्रष्ट हो चुके है। जनता को गुमराह करते रहते हैं। बेचारी जनता बस पिसती रहती है। इन स्थितियों में कवि दिनकर की कवितायें जनता की आँखें खोलने में पूर्णतया समर्थ हैं। उदाहरणार्थ वे लिखते हैं –

'युगों से हम अनय का भार ढोते आ रहे हैं,
न तू बोली मगर हम रोज मिटते आ रहे हैं,
पिलाने को कहाँ से रक्त लायें दानवों को,
नहीं क्या स्वत्व है प्रतिशोध का हम मानवों को।' (1)

कवि दिनकर अपनी कविताओं के माध्यम से जनमानस को सदैव उद्बुद्ध करने का प्रयास करते रहे। वे उसे अपनी शक्ति पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं और गलत नीतियों का विरोध करने का साहस भरते हैं। वे लिखते हैं –

'अन्ध विषमता के विरूद्ध, सारा संसार उठा है।
अपना बल पहचान, लहरकर पारावार उठा है।
छिन्न-भिन्न हो रहीं, मनुजता के बन्धन की कड़ियाँ।
देश-देश में बरस रहीं, आजादी की फुलझड़ियाँ।' (2)

दिनकर जी जनता के सामने संघ-शक्ति के महत्व को उजागर करते हैं। उनका मानना है कि एक होकर बड़े से बड़े कूटनीतिज्ञों के भी पैर उखाड़े जा सकते हैं। बस आवश्यकता है एक होकर उनका विरोध करने की। वे लिखते हैं –

मत खेलो यो बेखबरी में, जन समुद्र यह नहीं,
सिन्धु है यह अमोघ ज्वाला का।
जिसमें पड़कर बड़े-बड़े कंगूरे पिघल चुके हैं।
लील चुका है यह समुद्र, जाने कितने देशों में,
राजाओं के मुकुट और सपने नेताओं के भी।
सावधान! जनभूमि किसी का चारागाह नहीं है,
घास यहाँ की पहुँच पैर में, काँटा बन जाती है। (3)

संसार में राजतंत्र की परम्परा बहुत समय से प्रचलित है। इसके पूर्व मानव जीवन के हर क्षेत्र में समानता दृष्टिगत होती है। कवि दिनकर ने राजनैतिक दृष्टि से फैली इस असमानता को चित्रित करते हुए सामान्य जन को समझाया है कि यह पृथ्वी सबकी है। इस पर सबका समान अधिकार हैं कुरूक्षेत्र में भीष्म पितामह स्पष्ट शब्दों में युधिष्ठिर से कहते हैं –

धर्मराज! यह भूमि किसी की नहीं क्रीत है दासी,
है जन्मना समान परस्पर, इसके सभी निवासी,
जो कुछ प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है,
धर्मराज! उसके कण-कण का अधिकारी जन-जन है। (4)

इस असमान एवं अनर्थकारी प्रवृत्ति को दूर करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य व्यक्तिगत सुखों-स्वार्थों की पूर्ति की लालसा छोड़ दे। समाज में सब कुछ, सबको समान रूप से प्राप्त होने की व्यवस्था है। कवि दिनकर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब तक यह स्थिति नहीं आयेगी तब तक राष्ट्र में

* एसोसियेट प्रोफेसर (हिन्दी) शासकीय पी.जी. कॉलेज, दतिया (म.प्र.) भारत

पूर्णरूपेण शान्ति व्याप्त नहीं हो सकती।

'न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव-मानव को।
चैन कहाँ धरती पर तब तक, शान्ति कहाँ इस भव को। (5)

शासक, नेता, मंत्री – इनकी क्रूरताओं अनाधिकर चेष्टाओं को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि जनता द्वारा इनका पुरजोर विरोध किया जावे। व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति के लिए ये लोग समाज में न्यायोचित सुख प्रदायक व्यवस्था लागू नहीं होने देते, अतएव जनता को संगठित होकर इनके विरोध में खड़ा होना चाहिए। इन्हें यह अहसास कराना होगा कि यदि शासन समर्थ है तो जनता भी कमजोर नहीं है। वह अधिकारों को समझती भी है और उसको प्राप्त करने के लिए जूझने का सामर्थ्य भी रखती है। दिनकर जी लिखते हैं कि अपने अधिकारों के लिए की गई जनता की लड़ाई को रोकने की शक्ति किसी में भी नहीं होती। अन्यायी शासक को उस शक्ति के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं।

'हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है।
साँसों के बल से ताज हवा में उड़ता है।
जनता की रोके राह, समय में ताब कहाँ?
वह जिधर चाहती, काल उधर ही मुड़ता है।' (6)

इस प्रकार दिनकर जी की कृतियों में राजनैतिक चेतना अपने प्रखरतम रूप में दिखाई देती हैं। दिनकर जी राजनीतिज्ञों की बखिया ही नहीं उधेड़ते उन्हें आगाह भी करते हैं कि जनशक्ति बहुत विराट होती है। यदि एक बार वह जागृत हो गई तो बड़े-बड़े कूटनीतिज्ञों के मुकुट सहज ही उतर जाते हैं। अतः शासकों को जनता के हितों का ध्यान रखकर, देश के विकास में अपना सक्रिय योगदान देना चाहिए। उन्हें विश्व राजनीति से भी बेखबर नहीं होना चाहिए क्योंकि विश्व स्तर पर भी उन्हें अपना स्थान बनाये रखना है। अतः अपने देश अपने राष्ट्र की साख किसी भी कीमत पर गिरनी नहीं चाहिए। यह ध्यान रखना राजनेताओं का प्रथम कर्तव्य है।

निष्कर्ष रूप में वर्तमान राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए यदि उनकी कविताओं का अनुशीलन किया जाये तो उनकी काव्य-कृतियाँ कालजयी हैं। वे हर काल में लोक का रक्षण करने वाली हैं। आज राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, धर्म, अध्यात्म, अर्थ, समाज, साहित्य और विशेष रूप से राजनैतिक स्तर पर जो विसंगतियाँ आ चुकी हैं, दिनकर जी का काव्य उन प्रश्नों को उठाता भी है और उनके प्रखर तथा सटीक समाधान भी प्रस्तुत करता है। यह कहा जा सकता है कि दिनकर जी की कविता समाज के हर सुख-दुख को बहुत करीब से पहचानती है। लोगों को विवश करती है उस दिशा में सोचने के लिए। वास्तव में एक साहित्यकार का यही तो दायित्व होता है। बांग्ला कवि श्री अरूण मित्र के शब्दों में -'जो हृदय को स्पर्श मात्र न करे, भीतर उथल-पुथल भी मचा दे। मन को मुक्त कर दे। कुछ ऊपर उठा दे। जो मनुष्य को मुक्ति का मार्ग दिखाये। कविता हमेशा हर तरह के मनुष्य की पीड़ा, उसके दुख का खात्मा चाहती है। जो मनुष्य के अस्तित्व व यथार्थ की उपेक्षा करता है, वह बड़ा कवि नहीं हो सकता। दूसरी कलाओं की तरह कविता का भी महत्व बहुत कम होता है, जब वह मनुष्य, उसके जीवन, उसके दुख-सुख और उसकी मनः स्थितियों से नहीं जुड़ी होती। सिर्फ जादुई भाषा और शिल्प से कविता महान नहीं होती।'

श्री अरूण मित्र जी की कविता विषयक यह धारणा दिनकर जी के काव्य पर पूर्णतः खरी उतरती है। उन्हें एक युगकवि घोषित करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रामधारी सिंह दिनकर, हुंकार, पृ0सं0 23
2. रामधारी सिंह दिनकर, सामधेनी, पृ0सं0 60
3. रामधारी सिंह दिनकर, नीम के पत्ते, पृ0सं0 05
4. रामधारी सिंह दिनकर, कुरूक्षेत्र, पृ0सं0 51
5. रामधारी सिंह दिनकर, कुरूक्षेत्र, पृ0सं0 141
6. रामधारी सिंह दिनकर, धूप और धुँआ, पृ0सं0 70

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

लोक साहित्य में होली गीतों मे श्रंगारिकता

डॉ. एस. एस. राठौर *

प्रस्तावना - लोक में प्रचलित मान्यताओ एवं विश्वासो के आधार पर वसंत ऋतु का वर्णन हमारी भारतीय संस्कृति की अपनी एक परंपरा रही है। वैसे तो होली का त्यौहार हमारे देश में हर जगह अपने अपने ढंग से मनाया जाता है। लोक शब्द के उच्चारण मात्र से ही जन- जीवन का चित्र एवं उसकी झॉकी हमारी आखों के समाने उपस्थित हो जाती है। कुछ विद्धान कहतें हैं कि लोक संस्कृति (फोक कल्चर) का पर्याय हैं। प्रयाग मे अखिल भारतीय लोक संस्कृति सम्मेलन मे भी फोक लोर के पर्याय के रूप मे लोक संस्कृति के औचित्य को ही माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस शब्द के अर्थ को लोक संस्कृति के रूप मे ग्रहण करने का सुझाव भी दिया हैं लोक भाषा एवं लोक विश्वासों के संबल के विना जिस प्रकार गीत् कथा अथवा लोक गाथा अर्थहीन एवं खोखले साविद होते है। लोक गीत एवं गीत में तत्वत: जो भी भेद हो किन्तु दोनो के मूल स्वरूप मे एक ही प्रकार की सृजन प्रवृत्ति काम करती हैं। मानव जब अपने सुख दुख की अभिव्यक्ति को विवस होकर शब्द का आश्रय लेता हैं तो गीत फूट ही पडतें है। इससे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि मानव ने अपनी इच्क्षा आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करने का सर्वोत्कृष्ट साधन माना होगा। लोक साहित्य में बहुत कुछ लिखा हुआ आज भी प्रकाशित नही है। उस पर काम करने की अभी भी बहुंत संभावनाऐं हैं।

बसंत ऋतु में होली गीतो का आनंद ग्रामीण अंचलों मे आज भी देखा जा सकता है एवं उसकी अनुभूति भी की जा सकती है। बुन्देल खण्ड मे एक बहुत ही प्रसिद्ध बुन्देली कवि हुऐं हैं ईसुरी जिनकी चौकडियॉ ग्रामीण क्षेत्रो मे ढोलक, नगडियॉ, झांझ, मंजीर के साथ इतनी तन्मयता से गायी जाती हैं कि लोग झूम उठते हैं इन होली गीतों में प्राय: राधा कृष्ण के प्रेममय स्वरूप को दर्शाया जाता है। जैसें-

'श्याम सुन्दर के संग मा।
राधा माती फिरैं रस रग मा।।'

रंगो के त्यौहार होली का अपना अलग ही महत्व है। वैसे भी बसंत ऋतु बहुत ही मादक मानी जाती है क्यौकि कामदेव अपने पंच बाणों का प्रयोग इसी ऋतु के माध्यम से करते हैं फूलो का खिलना, आमों में बौरो की सुगंध, कोमल पत्तियों का फूटना, भौरों का गुंजार, कोयल का बोलना ये सब इसी ऋतु मे होता हैं।

'इनमे फाग रची अनमोली, राग रंग रस घोली।
ऐसहि रूप सुहावे सुन्दर, ऐंसहि मधुरी बोली।।
ऐंसहि राग तान के ज्ञाता, पिगंल गैल टटोली।
ऐंसहि चलत लक्ष के उपर ,चलत अचूका गोली।।'

इनकी पुस्तक 'सुन्दर सुमन' में ये चौकड़िया देखने को मिलती हैं जिनका वर्णन बहुत ही सहज एवं सरल ढंग से किया गया है। हमारे लोक जीवन में अनेक पर्व एवं परंपरायें ऐसी हैं कि जिनका सीधा संवंध लोक जीवन से ही हैं बृज का रसिया, बुन्देलखण्ड मे दादरें के तर्ज पर गायी जाने वाली चौकड़िया फाग में अद्‌भुत श्रंगारिक वर्णन मिलता है। रसिया का एक उदाहरण प्रस्तुत है-

'परदेसी दिन डूबे न जाव
आज घरै मोरे कोउ नईयाँ।।
सास ननदिया गई हैं बजरिया
सैयां गये देवरा का लेबो चलाव ....'

फाग गाने वाले वैसे तो बहुत ज्यादा गीत एवं संगीत के जानकार नहीं होते किन्तु जब होली का त्योहार आने को होता है तो उसके पहले से ही उनमें एक खुमारी चढ़ जाती है तथा वह एकान्त में ही गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। फागों के संदर्भ में यदि यह कहा जाय कि बुन्देलखण्ड में जो सरस एवं श्रंगारिक होली गीत गाये जाते हैं वह अत्यन्त ही रसपूर्ण एवं सहज रसानुभूति से सराबोर करते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी जैसे-

'सांवरिया तोरे रंग संग मै कैसे खेलूं होरी
क्कारे-क्कारे घड़ा मंगाये उनमें घोरो रंग
भरि पिचकारी सन्मुख मारी
भींज गयो सब अंग रंग मै कैसे खेलूं होरी ....'

होली गीतों के चित्रण में स्थानीय रहन-सहन एवं वहां की ग्रामीण परम्पराओं का भी प्रभाव देखने को मिलता है। बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी आदि जिलों में जो बुन्देखण्ड में आते हैं यहां होली गीतों का चलन पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, ललितपुर आदि से थोड़ा सा भिन्न है। मुख्यत: यह भी देखा जाता है कि इन क्षेत्रों में जो मशहूर नृत्यांगनायें हैं जो लोक संगीत एवं लोक नृत्य से ताल्लुक रखतीं हैं जैसे छतरपुर जिले में बिजावर का राई नृत्य होली गीतों पर मुख्य माना जाता है। वह बहुत ही भावनात्मक दृष्टिकोण से अपनी कला का प्रदर्शन करतीं हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की पुरानी परम्परायें इन्हीं त्योहारों के माध्यम से जीवंत हो जातीं हैं। इसी का एक उदाहरण है कि मां कीरत अपनी बेटी राधा को होली के दिन ढूढते ढूढते परेशान हो जातीं हैं तब अचानक कन्हैया होली खेलते हुए मिल जाते हैं। वो पूंछतीं हैं कि कन्हैया तुमने मेरी राधा को कहीं देखा है, तब उनके द्वारा मना करने पर वह कन्हैया से अनुनय विनय करतीं हैं।

'सांवरिया जरा बंशी बजाव
मोरी राधा हेराय गई कुंजन में ।।'

अंतरा - कोउ मोरी राधा का ढूंढि लै आवै । सखी ढूंढि लै आवै
दईहौं मै मोहरैंयां लुटाय ।। मोरी राधा हैराय गई कुंजन में ....

* प्राध्यापक (हिन्दी) छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना (म.प्र.) भारत

ब्रज में होली के आनंद का रस कुछ और है, राधा और कृष्ण अपनी–अपनी टोलियों के साथ होली खेलते हैं। बसंत का मौसम ही बहुत अधिक सुहाना होता है तभी उसको ऋतुराज कहा जाता है। कृष्ण राधा की एक प्यारी सखी को पिचकारी मारकर भिगो देते हैं तो वो दौड़कर राधा के पास उलाहना देने आती है, वो कहती है –

'मोरी चुनरी मा परिगौ दाग
अनारी ऐसो चटक रंग डारि गयो।
औरन से मुखहू न बोलै
वाकी मोही से लागी लाग ।। अनारी ऐसो ....
सास ननद मोरी गारी देंहैं।
ऐसी होरी मा लग जाय आग ।। अनारी ऐसो ....'

इन होली गीतों को समझकर सुनकर तथा गाकर ये कहा जा सकता है कि बसंत के इस मौसम में होली में निःसंदेह मादकता की सुगंध भरी होती है और ये आनन्द बिना श्रृंगारिक लोक रचनाओं के अधूरा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. बुन्देली बसंत 2015 पृष्ठ 93
2. लोक जनश्रुतियों एवं लोक गायन के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

आचार्य श्रीराम शर्मा के साहित्य में जीवन-मूल्य की सार्थकता

डॉ. वर्षा ठाकरे *

शोध सारांश - मूल्य एक मानक है, जिनके आधार पर मानव सामाजिक व्यवहार की श्रेष्ठता का अनुमान लगाता है। किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार और संस्था से किसी व्यक्ति का कैसा संबंध है यह उसके जीवन मूल्य पर आधारित है। वैदिक युग के साहित्य मे जीवन मूल्य की स्थापना का महान कार्य ऋषियो द्वारा सम्पन्न हुआ। उन्होने ही यह अनुभव किया कि मनुष्य की श्रेष्ठता कायम रखने के लिए उसे जीवन मूल्यो का आश्रय लेना होगा यदि वह ऐसा नही करता तो वह मूल्यहीन जीवन जीता है। प्राचीनकाल से लेकर आज तक जीवन मूल्यो का विघटन हुआ है इसका प्रमुख कारण कथनी-करनी मे अंतर आचार्य श्रीराम शर्मा ने कथनी-करनी के एकत्व पर बल दिया और अपने साहित्य मे जीवन-मूल्यो की पूर्न स्थापना की।

प्रस्तावना - आचार्य श्रीराम शर्मा का प्रादुर्भाव इस सदी के दूसरे दशक के प्रारंभ मे हुआ। जब देश विषम परिस्थितियो से गुजर रहा था। इनका आरंभिक जीवन अध्यात्म चर्चा एवं सत्संग मे व्यतीत हुआ। तदनंतर स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका अदा की। देश प्रेम मे मस्त होने के कारण वे 'मत्तजी' या 'श्रीराम मत्त' के नाम से जाने जाते थे। [1] संतो एवं ऋषियो से भी आचार्यजी का संपर्क लगातार बना रहा। उन्ही की प्रेरणा एवं प्रकाश मे उन्होने साहित्य सृजन किया। वे सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर थे। इसी क्रम मे आचार्यजी ने अपने जीवन साहित्य मे मानवीय जीवन-मूल्य को स्थापित किया। और इसी तरह का जीवन स्वयं भी जिया।

जीवन का एक निश्चित क्रम ही जीवन-मूल्य है। प्राचीन साहित्य मे मूल्य के भाववाची शब्द पुरूषार्थ, प्रयोजन एवं मान मिलते है। आधुनिक युग मे 'मूल्य' और 'प्रतिमान' शब्द समान अर्थो मे प्रयोग किये जाते है। मूल्य के सम्बन्ध मे **श्री रोहित मेहता** के विचार अधिक समीचीन प्रतीत होते है- 'मूल्य न तो किसी मशीन द्वारा उत्पादित वस्तु है और न किसी सरकार द्वारा निर्मित कानून। मूल्य तो जीवन के प्रति एक गुण है, एक अन्तदृष्टि है, एक अवधारणा है, एक दृष्टिकोण है।' [2] जीवन-मूल्यो का निर्धारण मानव की विकासषील प्रवृत्ति का द्योतक है। मानवीय विकास हेतु निर्धारित आदर्श एवं मान्यताओ का दूसरा नाम जीवन-मूल्य है। प्रत्येक देश एवं समाज के विकसित व्यक्ति आदर्श मानव के पद पर प्रतिष्ठित है। वे जनसामान्य के प्रेरणा स्त्रोत भी है।

मानव इस सृष्टि मे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इस श्रेष्ठत्व का कारण है कि मनुष्य स्वकर्म ज्ञान और बुद्धि के द्वारा प्रायोजित होती है। वह पहले मनन कर कर्म मे प्रवृत्त होता है। इसीलिए **शास्त्रो** मे वर्णित है - **'मत्वा कर्माणि सीव्यापि इति मनुष्य:।'** प्रश्न यह उठता है कि मूल्यात्मक स्थिति क्या है? आज मानव कितना नियंत्रित और मर्यादित है। वर्तमान युग की परिवर्तनशील प्रक्रिया के कारण चिरंतर मानवीय मूल्य संदेहास्पद हो गये है।

'मूल्यो का मानव-जीवन मे विशिष्ट स्थान है। उनका अर्थ व्यक्तियो को सामंजिक जीवन के लिए आदर्श रूप मे प्रस्तुत करना है। वस्तुत: मूल्य एक मानव है' जिनके आधार पर व्यक्ति सामाजिक व्यवहार की श्रेष्ठता का अनुमान लगा सकता है। किसी वस्तु व्यक्ति विचार व संस्था से किसी व्यक्ति का कैसा संबंध है यह उसके जीवन मूल्य पर आधृत है। **डॉ. मैत्र** ने कहा है- 'हमारी परम्परा मूल्य केन्द्रित होना है. न कि अस्तित्व केन्द्रित होना है।' [3]

'इस चराचर जगत मे मानव सृष्टि कर्ता की सर्वोत्तम कृति है जिसकी स्वतंत्रता की महत्ता सभी धर्मो' विश्वासो एवं विचारधाराओ मे स्वीकृत है। वह देश 'काल प्रकृति' व्यक्तिगत सम्बन्धो. सूक्ष्म मनोभावो एवं संवेगो मे अवस्थित है। [4]

वैदिक साहित्य मे 'ऋत' एवं 'सत्य' की भावनाओं का विस्तार ही नैतिक मूल्य का आधार है। वेद मे निहित 'ऋत' की भावना ही पापों को विनष्ट करती है। [5] वैदिक ऋचाओं मे सभी के लिए स्वस्ति वाचन करने का विधान है। [6] इसी तरह मानव जीवन को सार्थक उपयोगी बनाने भावो की तरह विचारों की पवित्रता अनिवार्य है। शुभ विचार जीवन को पवित्र और उत्कृष्ट बनाते है। [7] यही जीवन के नैतिक मूल्य है जिसको आधार बनाकर वैदिक युग सम्पन्न समृध्द एवं विकसित रहा है।

वर्तमान समय मे संघर्ष परिव्याप्त है। मान्यताएँ एवं धारणाएँ बदल रही है। मानवीय मूल्यो मे वर्तमान विघटन को स्वीकार करते हुए **डॉ धर्मवीर भारती** का विचार है कि 'सम्पूर्ण सभ्यता जिन मूल्यो पर आधारित थी वे झूठे पड गये है। परिणाम यह है कि एक भयानक विघटन उपस्थित है।'[8]

निष्कर्षत: मानव की वर्तमान स्थिति अत्यंत संघर्षशील है। मानव के इस खोए हुए अस्तित्व को पुन: महत्व प्रदान करने के लिए आचार्य श्रीराम शर्मा ने पुरामूल्यो की पुनर्व्याख्या प्रस्तुत कर उनके स्वीकरण की प्रेरणा को बल दिया।

जीवन मूल्यो के पोषक एवं संरक्षक के रूप मे सृजनशीलता के कई आयाम विकसित किए। **आचार्य श्रीराम शर्मा** ने जीवन मूल्यो को परिभाषित करते हुए लिखा है-'मानव जीवन मूल्यो का आगार एवं भण्डार है लेकिन इसके सारे मूल्य जीवन के केन्द्र से उपजते है। यह केन्द्र ही जीवन का सार है। जीवन के इस सार तत्व को संवेदना कह सकते है। यही शास्वत जीवन मूल्य है। इसी का सहारा पाकर जीवन-मूल्य अंकुरित होते है। इसी का रस पाकर वे पुष्पित. पल्लवित एवं अभिवृध्दित होते है।'[9]

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि मानव जीवन मे कल्याणकारी मूल्यो

* गेस्ट फेकेल्टी (हिन्दी) पोस्ट - पीपला नारायण वार, जिला - छिंदवाड़ा (म.प्र.) भारत

का विशिष्ट स्थान है। ये मूल्य व्यक्तिगत या सामाजिक धरातल पर ही नही, आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर भी मानव को उच्चादर्श की ओर अग्रगामी बनाते है। आचार्य श्रीराम शर्मा ने जीवन मूल्यो का विकास शाश्वत जीवन मूल्य से माना है। उन्होने 'संवेदना' को जीवन मूल्य का आधार माना है। उन्ही के शब्दो मे 'संवेदन सूत्रो का सीधा सम्बन्ध जीवन-मूल्यो के विकास एवं प्रशिक्षण से है।' [10]

1. आगरा संभाग के स्वतंत्रता सेनानी-सूचना विभाग लखनउ (उ. प्र.) पृ. 13
2. The Intutive Philosophy, P. 30
3. Contemporary Indian Philosophy P. 386
4. The Image (Introduction) P.3-5
5. ऋतस्य हीषुरूध: सन्ति पुर्वी ऋतस्य धीति वृजिनानि हन्ति। ऋग्वेद 4/23/8-9
6. ऋग्वेद 10/63/15-16
7. अथर्ववेद - 6/19/1-3
8. मानव मूल्य और साहित्य पृ. 134-135
9. अखण्ड ज्योती वर्ष 60 अंक 3 पृ. 30 आचार्य श्रीराम शर्मा, जीवन मूल्यो का यक्ष प्रष्न और उसका हल
10. अखण्ड ज्योती वर्ष 59 अंक 9 पृ. 13 आचार्य श्रीराम शर्मा, परिवार संस्था की धुरी नारी

****

गुलेरी जी की कहानी 'उसने कहा था' में आदर्श प्रेम - विश्लेषण

डॉ. मजीद कुरैशी *

प्रस्तावना - गुलेरी जी ही एकमात्र ऐसे कहानीकार हैं जिन्होने हिन्दी कहानी जगत में मुख्य रूप से मात्र चार कहानियॉं लिखकर जो स्थान बनाया है। उस स्थान को आज तक कोई काहानीकार प्राप्त नही कर पाया है। अपनी विशिष्ठ शैली के कारण ही वे हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। जब गुलेरी जी कहानीकार के रूप में पाठकों के समक्ष आए तब हिन्दी कथा साहित्य में रहस्य , रोमांच एवं तिलस्मी दौर का बोलबाला था। ऐसे समय में गुलेरी जी की 'उसने कहा था' जून 1915 में 'सास्वती' में छपकर अपनी शैली की विशिष्टता से सभी को परिचित कराया। इस काहानी की बात करें तो कहानी का जो मूल वाक्य है, जिसे पर सम्पूर्ण कहानी का भार है वह वाक्य है 'उसने कहा था' जो पाठकों के मन में एक जिज्ञासा भी उत्पन्न करती है कि किसने कहा था, क्यों कहा था, जिसका उत्तर पाठक कहानी के शुरू से ही सोचता है। और इसका जबाब उसे कहानी के अंत में जाकर मिलता है कि किसने कहा था, क्यों कहा था, किससे कहा था। इस कहानी में गुलेरी जी ने यथार्थ और कल्पना तथा प्रेम और त्याग विषयक घटनाओ का ताना-बाना बडे ही कौषल से बुना है कि किस प्रकार एक सात-आठ साल के बालक एवं बालिका अमृतसर के बाजार में मिलते हैं और कैसे दोनों में निर्मल प्रेम के बीज पनपते हैं जो इस इस एहसास को समझते भी नहीं है लेकिन कोई तो ऐसा अपनापन दोनों में हो जो रोज मिलते हैं और वह बालक बालिका से पूछता है तेरी कुड़माई हो गई क्या ? और बालिका धत् कहकर चली जाती है। कुछ दिन तक यही क्रम चला फिर एक दिन बालक हमेशा की तरह यही प्रष्न करता है तो उसे आषा के विपरीत उत्तर मिलता है-

'हाँ, हो गई।'

'कब'

'कल, देखते नही यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू।'[1]

यह सुनते ही उस बालक के हृदय में फूटते प्रेमांकुरो पर मानो तुशारपात हो गया। मगर प्रथम प्रेम की यह मधुर स्मृति एक कसक जरूर दे दी और इस उत्तर बालक पर जो प्रभाव पडा उसका गुलेरी ने बडा ही मनोवेज्ञानिक चित्रण किया हैं-

'रास्ते में एक लडके को मोरी में ढकेल दिया, एक छावडी वाले की दिनभर खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दुध उंडेल दिया। सामने नाहकर आती किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधी पाई तब कई घर पहुंचा।' [2]

बालक की यह स्थिति क्यो हुई पाठक उसे खुब समझते है क्योंकि बालक को यह लगा अब वह बालिका से नही मिल पायेगा। यहॉं पर गुलेरी जी ने किशोरावस्था के इस प्रथम प्रेम का चित्रण बडे ही मर्यादापूर्ण एवं सहज ढंग से प्रस्तुत किया है। इस प्रथम परिचय में जो सहज आकर्षण से पवित्र प्रेम का जन्म हुआ वह कभी भुलने से नही भुला जा सकता है। जैसा की मैने पहले कहा कि कहानी की जो मूल संवेदना 'उसने कहा था' यह वाक्य है। इसके सहारे ही संपूर्ण कहानी का विकास हुआ है। इस वाक्य की सार्थकता को अंत में लहनासिंह सिध्द करता है कि किसने कहा था और किससे कहा था-

'मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। ———— एक बेटा है। फोज में भर्ती हुए इसे एक ही बरस हुआ। इसके पीछे चार और हुए, पर एक भी नही जिया। सूबेदारनी रोने लगी, 'अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग! तुम्हे याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही की दुकान के पास बिगड गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोडे की लातों में चले गये थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़े कर दिया था। ऐसे इन दोनों को बाचाना। यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं ऑचल पसारती हूँ।'[3]

इस प्रकार स्पष्ठ होता है कि लहनासिंह की वह बाल सखी जिसे वह 25 साल पहले मिला था। उससे कुछ मॉग रही थी जिसको लाहनासिंह निस्वार्थ भावना से वचन निभाते हुए अपने प्राणो को त्याग यह कहते हुए करता है कि जो उसने कहा था। वो मैंने पूरा किया इस बात की पुष्टि उसके इस वाक्य से होती है जब वह घायल होते हुए भी हजारासिंह और बोधा को गाड़ी पर बिठाते यह कहता है कि-

'सूबेदारनी होरां को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो यह कह देना कि जो उनने कहा था वह मैंने कर दिया।'[4]

'उसने कहा था' किशोरावस्था के भावनात्मक प्रेम को कर्तव्य भावना और उत्सर्ग की पराकाष्ठा तक ले जाने वाली प्रेम कहानी है। उसमें प्रथम मिलन के प्रति आकर्षण से पवित्र प्रेम के उदर तथा निस्वार्थ भावना से प्रण निभाते हुए आत्म बलिदान कर देने की उदात्त भावना है। दस कहानी का मुख्य पात्र लहनसिंह प्रेम, ज्याग तथा कर्तव्य भावना का जीवंत पात्र है जो अपनी बाल सखी से किए गए वचन का निभाते हुए अपने प्राणों का न्यौछावर कर देता है, केवल इसलिए कि 'उसके प्रेम में कहीं भी कोई लोभ, कोई स्वार्थ नहीं हैं बल्कि इस समर्पण में उत्सर्ग के अलावा कुछ और नही झलकता है। इस कहानी में हमें यथार्थ, मर्यादा, प्रण, निष्ठा, भावुकता एवं प्रेम का स्वर्गीय रूप देखने को मिलता है, जो कि कहानी का मुख्य बिन्दु है। जिसके कारण ही कहानी पाठकों का बांधे रखती है। 'उसने कहा था' कहानी के माध्यम से गुलेरी जी ने स्वर्गीय प्रेम, कर्तव्य परायणता, त्याग, प्रण,-पालन, साहस और वीरोचित उत्सर्ग की भावना की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। इस कहानी में कहीं भी प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की वीभत्स

* अतिथि सहायक प्राध्यापक, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, चौरई, जिला - छिन्दवाडा (म.प्र.) भारत

विकुति नहीं है। और न ही किसी के हृदय को कोई आघात पहुंचाने वाली बात है। बल्कि इस काहानी में तो लोगो और समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया गया है। जो अन्य व्यक्तियों में भी किसी के लिए समर्पण एवं त्याग की भावना को जागुत करने में सहायक होता है। 'उसने कहा था' कहानी का नायक लहनसिंह कुछ इसी प्रकार की भावना रखता है जो अपनी बाल सखी के लिण अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसके पति एवं पुत्र की रक्षा करता है। खुद घायल होते हुए भी पहले हजारासिंह एवं बोधासिंह को अस्पताल पहुंचाता है। यह प्रेम को उच्च शिखर तक पहॅुचाने वाला प्रेमी है। जो अपनी बाल सखी को दिया हुआ वचन का निर्वाह करने में खुद के प्राणों का न्यौछावर कर देता है। केवल इसलिए कि ' उसने कहा था' । प्रेम का ऐसा रूप हमें दुर्लभ ही देखने को मिलता है। जहॉ कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपेक्षा नही, कोई शिकायत नहीं है और षिकायत होगी भी कैसे क्योंकि सच्चा प्रेमी कभी शिकायत नहीं करता है। वह जानता ही नहीं कि षिकायत क्या है ? इस बारे में रजनीश ओशो कहते हैं–

'शिकायत आशिक जनता ही नहीं, धन्यवाद ही जानता है। भूलकर भी उसके भीतर शिकायत नहीं उठती, कोई शिकायत नहीं उठती। जैसे है बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिये। तैसा है ठीक है, तथाता– भाव होता है। दर्द भी होता है, पीडा होती है, तो वह कहता है, धन्य भाग मेरे।'[5]

निष्कर्ष – कहानी का विश्लेषण करने से यही बात स्पष्ट होती है कि गुलेरी जी ने जिस आदर्श प्रेम के औदात्त स्वरूप का चित्रण किया है। वह हम सबको प्रेरित करने वाला है। आज के समाज में प्रेम की ऐसी स्थिति की कहां देखने को मिलती है। वास्तविक रूप में आज न ऐसी कहानियां लिखी जा रही है। और न ही प्रेम का आदर्श रूप देखते को मिल रहा है। आज के समाज में जो दिखावा एवं बाहरी आकर्षण को प्रेम का नाम दिया जाता है। वह तो प्रेम है ही नही।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. उसने कहा था और अन्य कहानियां,चंद्रधर शर्मा गुलेरी सं. मनोहर लाल पृ.क्र. 112
2. वही पृ.क्र. 112
3. वही पृ.क्र. 113
4. वही पृ.क्र. 121
5. ओशो टाइम्स, मासिक पत्रिका नव. 2003 सं. अमृत साधना पृ.क्र. 60

****

रघुवीर सहाय की कविताओं का भावबोध, भाषा और शिल्प

डॉ. कुमुद कला मेहता*

प्रस्तावना – रघुवीर सहाय स्वतंत्र भारत के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं। कविता को जनमानस तक पहुँचाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। जिस समय रघुवीर सहाय कवि के रूप में सामने आए, वह नई कविता का काल था। इनकी कविताओं को अज्ञेय ने 'दूसरा सप्तक' में संकलित किया था। नई कविता में व्यक्ति चेतना, अस्तित्ववादी दृष्टिकोण मौजूद है। रघुवीर सहाय वैचारिक रूप से समाजवादी चेतना के कवि थे। व्यक्ति चेतना और सामाजिक सरोकारों के बीच एक द्वन्द अक्सर चलता रहा है। लेकिन रघुवीर सहाय की कविता का मुख्य स्वर व्यक्ति चेतना नहीं बना, हालांकि कतिपय आलोचक यह मानते हैं कि इनकी व्यक्ति चेतना अक्सर सामाजिक चेतना पर हावी हो जाती है। पर मेरे विचार से ऐसा कहना रघुवीर सहाय की कविताओं के प्रति न्याय नहीं होगा। कविता के सामाजिक सरोकार के प्रति इनका दृष्टिकोण इतना मजबूत था कि ये कविता में कला के प्रश्न की उपेक्षा कर देते हैं। जिस समय इन्होंने लिखना शुरू किया, उस समय कविता अपने समकालीन समय के संकटों से उदासीन हो गई थी। नई कविता के कवियों का आधुनिकता बोध व्यक्ति के अवसाद, घुटन, कुंठा, पहचान खो जाने से उत्पन्न पीड़ा, यौन कुंठा तक सीमित रह गया था। आधुनिकता ने कवियों के भीतर निस्संगता उत्पन्न की और यह निस्संगता आगे बढ़कर तटस्थता में बदल गई। इस तटस्थता के कारण उस समय के रचनाकार अपने परिवेश, राजनीतिक वातावरण आदि के प्रति उदासीन भाव अख्तियार किए हुए थे। स्वातंत्र्योत्तर भारत का जो रूप बन रहा था, उसमें शासक वर्ग भी रचनाकारों को तटस्थ बनाए रखने में ही अपनी भलाई देखता था। यही कारण है कि नई कविता के कवि जनतांत्रिक मूल्यों और मानवीय सरोकारों से विच्छिन्न होकर अपने भीतर की दुनिया में निजी संवेदना का अन्वेषण कर रहे थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ ही समय बाद आम लोगों में किस तरह का मोहभंग घटित हुआ और लोगों ने स्वातंत्र्योत्तर भारत में खुशहाली का जो स्वप्न देखा था, वह किस प्रकार टूट कर बिखर गया था? जाहिर है कि इस समय की नई कविता में जनतांत्रिक मूल्यों, आदर्शों आदि के टूटने की कोई झलक नहीं मिलती। रघुवीर सहाय उस समय अकेले ऐसे कवि थे जिन्होंने समय की जड़ता को तोड़ा और कविता को मनोजगत की रहस्यमता से बाहर निकालकर यथार्थ की भूमि पर खड़ा किया।

रघुवीर सहाय कविता में कला के बजाय, उसके सामाजिक-मानवीय परिप्रेक्ष्यों को महत्व देते थे। इसलिए वे कविता में सीधे तौर पर अपने संकटों पर बात करते हैं। उन्होंने स्वाधीन भारत में 'हिन्दी' की उपेक्षा को केन्द्र बनाकर एक कविता लिखी थी जिसमें हिन्दी को 'दुहाजू की बीबी' कहा है। जाहिर है कि इसके कारण खूब बावेला मचा। पर इनके सामाजिक सरोकार इतने स्पष्ट थे कि इन्होंने अपने समय के परे जाकर कविता में जनतांत्रिक मूल्यों का पक्ष लिया। इस पक्षधरता का आभास इनके काव्य-संग्रह 'सीढ़ियों पर धूपय में ही मिलने लगता है, बाद में 'आत्महत्या के विरूद्ध' संग्रह की कविताओं में इनकी जनपक्षधरता पूरे स्पष्ट रूप में सामने आ गई।

जैसा कि पूर्व में कहा गया है, रघुवीर सहाय की कविता व्यक्ति चेतना से मुक्त नहीं है आडंबर और पाखण्डपूर्ण जीवन-शैली के बढ़ते प्रभाव के कारण उसकी मानवीय संबंध चेतना में भी ह्रास हुआ है। इनकी 'दुनिया' शीर्षक कविता इन्हीं ह्रासोन्मुख प्रवृत्तियों से उत्पन्न अर्थहीनता को अभिव्यक्त करती है। जाहिर है कि कवि अस्तित्ववाद के प्रभाव में है। मगर मानवीय संबंध में ह्रास देखने तक ही कवि सीमित नहीं रहता। वह इसका अतिक्रमण करके सामाजिक सरोकारों से जुड़ता है और सीधे-सीधे कविता में राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संकटों पर बात करने लगता है। यहीं अस्तित्ववादी प्रभाव से कवि मुक्त होने लगता है। राजनैतिक राजनीति की विसंगतियों को इन्होंने अपनी कविताओं में केन्द्रीय महत्त्व दिया है। इनकी राजनीतिक सरोकार वाली कविताएँ सीधे-सपाट रूप में अपने समय की राजनीति के अंतर्विरोधों, असंगतियों और जनविरोधी रूख को सामने लाती हैं। 'हँसो-हँसो जल्दी हँसोय शीर्षक कविता 1974 के छात्र आंदोलन और उसके बाद देश पर लादे गए आपातकाल के पूर्वानुमान को अभिव्यक्त करती है। उस समय सत्ता, धन और शक्ति का उन्मादपूर्ण दौर चल रहा था और शासक वर्ग जनता को आतंक के नए-नए रूपों से सामना करा रहा था। इन्हीं युगीन लक्षणों को देखकर और इनका तार्किक विश्लेषण करके रघुवीर सहाय ने अपनी कविता में आपातकाल का पूर्वानुमान किया था। इस दौर की राजनीति रघुवीर सहाय की कविताओं का मुख्य विषय है। साथ-साथ बौद्धिकों की निष्क्रिय बहसों को भी इन्होंने व्यंग्य का विषय बनाया। राजनीतिक विडम्बनाओं की आलोचना करते हुए जो कविताएँ इन्होंने लिखीं उनमें भ्रष्ट राजनीति की व्यंग्यपूर्ण आलोचना है। ये मानते थे कि जो कविता युगीन सच को अभिव्यंजित नहीं करती, वह भाषा का अर्थहीन कौतुक बनकर रह जाती है। 'आत्महत्या के विरूद्ध' कविता में उनकी इस धारणा की पुष्टि होती है। यह बता देना आवश्यक है कि रघुवीर सहाय व्यवस्था के आतंक से घबरा कर निष्क्रिय होकर नहीं बैठ जाते, बल्कि अपनी कविताओं में यह व्यंजित करते हैं कि व्यवस्था का जितना आतंक बढ़ता है, उतना ही प्रतिरोधा भी बढ़ता है। 'रामदास' शीर्षक कविता इस प्रसंग में बहुत महत्वपूर्ण है। रामदास मरते हुए समाज की ठोस वास्तविकता के रूप में सामने आता है।

स्त्री के प्रति भी रघुवीर सहाय प्रगतिशील दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए स्त्री जीवन की विडंबना और स्त्रियों के संघर्षों को उजागर करते है। उन्होंने भारतीय समाज के मधयवर्ग और निम्नवर्ग की त्रासदी, उसका आर्थिक

* सहायक प्राधयापक (हिन्दी) राँची कॉलेज, राँची (झारखण्ड) भारत

पक्ष पूँजीवादी मूल्यों और सामाजिक पक्ष, सामंती मूल्यों का भी वर्णन किया है। 'लुभाना', 'भय' आदि कविताओं में कवि पुरुष वर्चस्ववादी समाज में स्त्री की बेचारगी, दयनीयता और असहायता का चित्रण करता है। इनकी कविताओं में स्त्री सामाजिक असुरक्षा के कारण आतंक महसूस करती है। इसी प्रकार प्रकृति सौंदर्य के प्रति भी रघुवीर सहाय वास्तविकता का ही पक्ष लेते हैं। प्रकृति के विविध रूप दृश्य इनकी कविताओं में आते हैं, मगर वे सौन्दर्य–बोध तक ही नहीं ठहरते। साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि रघुवीर सहाय प्रकृति के सहज सौंदर्यबोध के कवि नहीं है। प्रकृति इनकी कविता में संश्लिष्ट मानवीय अनुभव बनकर आती है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि रघुवीर सहाय बौद्धिक आत्मसंतोष के लिए कविता नहीं लिखते बल्कि सामाजिक परिवर्तन शोषण और दमन से मुक्ति की चेतना से लैस होकर लिखते हैं।

पूर्व में कहा गया है कि कविता में मानवीय सरोकारों को रघुवीर सहाय कला के प्रश्न से ज्यादा महत्त्व देते हैं। भाषा और शिल्प की दृष्टि से इनकी कविताएँ प्रायः स्पष्ट हैं। इस कारण इनकी कविता में साधारणता दृष्टिगोचर होती है पर कविता में नाटकीय कौशल का प्रयोग करके कवि साधारण कविता को असाधारण बना देता है। इसी प्रसंग में नामवर सिंह ने इनकी कविताओं में साधारणता में असाधारणता देखी है। इनकी भाषा पर अखबारी प्रभाव है, फिर भी वह बेधाक है, सीधो मर्म पर चोट करती है। नई कविता के कवियों के लिए प्रतीक, बिम्ब और मिथक जिस प्रकार महत्वपूर्ण थे, रघुवीर सहाय की कविताओं में उस प्रकार से इनको महत्त्व कम मिला। इनकी कविता की बनावट में शुद्ध गद्यात्मक वाक्य महत्वपूर्ण है। पर नाटकीयता, लयात्मकता तथा वर्णनात्मकता के कारण इनकी कविता सादगी में भी विशिष्ट नजर आती है। रघुवीर सहाय का काव्य–व्यक्तित्व, उनके सामाजिक और निजी जीवन के तनाव, सामाजिक, राजनैतिक संघर्ष, साहित्य–पत्रकारिता के बीच के द्वन्द, सम्प्रेषणीयता और स्तरीयता के तनाव से मिल के बना–बुना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. कविता के नए प्रतिमान – नामवर सिंह।
2. रघुवीर सहाय का कवि कर्म – सुरेश शर्मा।
3. नई कविता और अस्तित्ववाद – रामविलास सिंह।
4. आजकल (मासिक पत्रिका) 2015 रघुवीर सहाय विशेषांक।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

शैलेश मटियानी का उपन्यास रामकली के सन्दर्भ में

मनीषा टैगोर *

प्रस्तावना - शैलेश मटियानी जी द्धारा लिखित उपन्यास रामकली हिन्दी साहित्य की एक प्रसिध्द रचना हैं। जिसमे दाम्पत्य जीवन का अनोखा चित्रण हैं । जिसमें एक अद्‌भूत नारी सघर्ष की कथा और एक असीम सहनशील पुरूष की ह्रदय मर्मस्पर्शी कथा हैं।

'रामकली' ही रामकली उपन्यास की नायिक हैं । इसका चरित्र ही उपन्यास की जान हैं। पूरे उपन्यास मे रामकली का चित्रणन ही दर्शनीय हैं। कथा का आकर्षण भी यही हैं। रामकली का चरित्र ऐसा हैं। जो जिन्दादिल हैं। वह आजीवन ताजगी लाने वाला सुन्दर सपने सजोने वाला और पत्नी के रूप में होकर भी वह किसी का मन रिझाने वाली नारी हैं। तन मन के सूखो तलाशना मस्ती में रहना उसका स्वभाव हैं। उसका पति होते हुए भी उसे किसी दूसरे की तलाश रहती हैं।

रामकली का विवाह हुआा तब वह 15 वर्ष की थी और उसका पति लगभग 32 साल का था । उम्र की खाई रामकली की निरंतर निखरती तरूणाई और उसकी जिम्मेदारियों से बोझिल होती जाती हैं। तब वहां दुबली ,पतली और सुन्दर दिखती थी। जब भी वह दूध लेने जाती हैं तब वह ठीक से धोती पहनती और बालों पर कंघी करती । बडे प्यार से माथे पर लाल बिंदिया लगा लेने के बाद काजल भी आंखों में वह लगाकर कमला पहलवान के घर दूध लेने जाती हैं। बसंतलाल के साथ की गृहस्थी के अभाव रामकली को अब धीरे-धीरे ज्यादा चुभने लगी हैं । शादी के 10 वर्ष हो चुके थे । अब तो दो बच्चे की मां बन चुकी हैं । फिर भी बसंतलाल की उम्र और अपने जिस्म के साथ अपनी उम्र को तोलकर देखने लगती हैं। रामकली को हरगुन पंडित अपने पति से ज्यादा अच्छा लगता हैं । वह गंगा स्नान को नहाने जाता हैं तब रामकली भी उसके साथ चल पडती हैं। तब वह अपने साथ अगरबत्ती और कंकू की पुडिया झोले में डालती हैं और हरगुन पंडित के हिस्से की दक्षिणा भी अपने साथ रख लेती हैं। पीतल का लोटा अपने दाएं हाथ की उंगलियों में रखकर मंदिर जाने की मुद्रा में निकलती हैं। तब दोनों स्त्री पुरूष के बीच से होते हुए काफी दूर तक चुपचाप चलते रहते हैं। रात बीतने तक रामकली को केवल हरगुन पंडित दिखई देता हैं। लेकिन सवेरा होते ही एक औरत का मन जाग उठता हैं। उसे अपने बच्चों और पति की याद आने लगती हैं।

रामकली अपने इच्छाओ को पूर्ण करने के लिए हरगुन पंडित ना मिले तो वह कमला पहलवान के घर चली जाती हैं। विजयादशमी के दिन कमला पहलवान के द्धारा मारे और प्रताडित किये जाने पर वह बच्चों के बहाने बसंतलाल के घर चली जाती हैं। जब वह कमला पहलवान को छोडकर अमोलकचंद ठेकेदार के साथ जाने का फैसला लेने के पहले मन में जरूर आया था कि बसंतलाल के मन में क्या ख्याल हैं। अब बसंतलाल के घर से बाहर निकलने के बाद रामकली का बडे घरो कि सी बहूओ का रूप निखर आया हैं। रामकली मे ज्यादा आकर्षक आ जाता हैं। पहले वह पुरानी मैली धोती पेटीकोट और ब्लाउज पहनती थी , लेकिन अब वह सफेद रंग की छोटी बाहो का ब्लाउज , पेटीकोट और बैंगनी रंग की साडी पहनती थी। उसकी शारीरिक गठन और उसके साफ -सुथरे पहनावे से यह कल्पना करना किसी के लिए भी कठिन हो सकता हैं कि वह बसंतलाल जैसे सामान्य मजदूर या फिर रिक्शा वाले की पत्नी हो सकती हैं।

एक दिन अमोलकचंद ठेकेदार मिर्जापुर जाता हैं तब रामकली बाजार जाती हैं। एक दुकान से बाहर निकलते ही बसंतलाल उसे देख लेता हैं। और बच्चो को देख आने को कहता हैं। तब वह बसंतलाल के हाथ में एक दस रूपये का नोट आगे बढाते हुए कहती हैं-'एक पैकेट बढिया वाले बिस्कुट का और रख देना थोडी टाफीया भी । '[1] तब रामकली का चरित्र मातृत्व का रूप धारण करता दिखाई देता हैं। अमोलकचंद ठेकेदार मिर्जापुर रूकता नही और अपने दोस्त के साथ घर वापस आ जाता हैं। वह अपने दोस्त के साथ रामकली की प्रतिक्षा करता हैं। बसंतलाल के घर से रामकली के लौट आने पर उसको अमोलकचंद ठेकेदार के साथ आए दोस्त उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। अमोलकचंद ठेकेदार उसे अपने दोस्त के साथ बेठने को कहता हैं। उसके सामने बेइज्जत करता हैं। रामकली हडबडाहट में जान नही पाई कि अमोलकचंद ठेकेदार के इस पागलपन की उन लोगो पर क्या प्रतिक्रिया हुई। रामकली को देखकर अमोलकचंद ठेकेदार को उसके दोस्त किस्मत वाले समझ रहे थे। अमोलकचंद ठेकेदार उसे भी छुकर देखने को कहता हैं। तब रामकली को इस बात का एहसास हो गया कि इन सब की हवस मिटाने या अपनी पूरी ताकत से विद्रोह करने के अलावा और कोई रास्ता उसके पास रहा नही गया तब अमोलकचंद ठेकेदार और उसके साथी जब तक कोई निर्णय ले रामकली अपने आप को बचाती हुए कहती हैं- 'हरामी , तू ससुरा कौन होता हैं साले।'[2] रामकली प्रचंड आक्रमण करके शेरनी की तरह चिल्ला उठी हैं और उनके तीनो दोस्तो को घर से बाहर निकाल देती हैं। बसंतलाल के साथ के आत्मीयता और सम्मान भरे वातावरण में से वापस लौटते ही इस तरह का अपमानजनक व्यवहार वह सहन नही कर पाती हैं।

रामकली का अमोलकचंद ठेकेदार से झगडे के बाद से अब तक निरंतर पश्चाताप हताश और आक्रोश में झूलसती हुई अब वह दो साल के बाद बसंतलाल के घर हमेशा के लिए वापस लौटती हैं। वह बसंतलाल को गले लगाती हैं। अपने दोनो बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। बच्चों वाली औरत को सिर्फ पत्नी ही नहीं होना पडता हैं। रामकली को बसंतलाल ने पहले आत्मालाप

* शोधार्थी , माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला,इन्दौर,
सम्बद्व-देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

की सी मुद्रा में धीमें शब्द मे कहा था कि – 'तेरे मेरे बीच उम्र का इतना फासला ना रहा होता रामकली तो हम लोग की गृहस्थी में दरार ना पड़ी होती।'[3]

उपन्यास के आरंभ से अंत तक रामकली को कई बार में निष्फलता मिलती हैं। फिर भी उसको अपने जीवन से अब नही। आती बल्कि उसकी जीने की जिजीविषा यथावत रहती हैं। आज के कई पढे– लिखे शिक्षित लोग जिन्दगी में पहली बार में निष्फलता मिलने पर खुदखुशी कर लेते हैं। पर रामकली इन सबसे भी अनपढ़ स्त्री होते हुए भी ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नही सकती हैं। ऐसा लगता हैं कि किसी भी स्थिति में वह भगवान की देन मानकर जीना चाहती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. शैलेश मटियानी : रामकली के पृ.क्र. 80
2. वही पृ.क्र. 82
3. वही पृ.क्र.110

****

बाणभट्ट की आत्मकथा - सांस्कृतिक आख्यान

डॉ. रंजना मिश्रा *

प्रस्तावना – संस्कृति जीवन के उन उदात्त मूल्यों का समुच्चय है, जो हमारे समग्र क्रिया-व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिन्दी के ऐसे ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, जिनके उपन्यास इतिहास के तथ्यों पर उतने आधारित नहीं है, जितने ऐतिहासिक वातावरण एवं देशकाल पर आधारित हैं, जिसकी सृष्टि उन्होंने अपनी अद्‌भुत कल्पना शक्ति से की है। उनके चारों उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचन्द्र लेख, पुनर्नवा एवं अनामदास का पोथा इसी श्रेणी के हैं।

'बाणभट्ट की आत्मकथा' में सातवीं शती के भारत की राजनीतिक स्थिति का निरुपण हुआ है। उस समय उत्तर भारत पर हूणों का आक्रमण हुआ था और कोई भी बड़ी शक्ति उनका प्रतिरोध कर सकने में सक्षम नहीं थी। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। द्विवेदी जी ने इस उपन्यास के कथानक में इतिहास की पृष्ठभूमि ही ली है, शेष सब कुछ उन्होंने कल्पना के आधार पर गढ़ा है। इसके साथ ही द्विवेदी जी ने 'हर्षचरित' नामक संस्कृत ग्रंथ को उपजीव्य ग्रंथ बनाया है। सातवीं-आठवीं शताब्दी के भारतीय समाज में जो दूषित प्रवृत्तियाँ पनप रहीं थीं, उनका यथार्थ चित्रण उपन्यासकार ने किया है।

तत्कालीन भारतीय समाज में जाति प्रथा का वर्चस्व था। ब्राम्हण को सम्मान तो मिलता था, किन्तु अपने कर्मो के कारण वह अपने देवत्व से गिर गया था। निम्न वर्ण ब्राम्हण को देवतुल्य समझता था। इस काल में लोग कर्मफल एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितनी भाग्यवाद पर रखते थे। धर्म का स्वरूप विकृत हो गया था। उसमें बाह्याचार एवं पाखण्ड बढ़ रहा था।

धर्म की आड़ में अनेक अनैतिक कार्य हो रहे थे। नारी के प्रति लोगों का दृष्टिकोण विशुद्ध भोगवादी था। लुटेरे उनका अपहरण कर लेते थे और उन्हें राजाओं के अन्त:पुर में बेच दिया जाता था। लेखक ने इस अधोपतन का चित्रण बाणभट्ट की आत्मकथा में किया है। भट्टिनी का अपहरण कर उसे 'छोटा राजकुल' के अंत:पुर में पहुँचाना और बाणभट्ट का निपुणिका के सहयोग से उसे मुक्ति प्रदान करना ऐसा ही घटनाक्रम है। बाणभट्ट नारी के प्रति अत्यंत उदार दृष्टिकोण रखता है। वह कहता है- 'मैं नारी सौंदर्य को संसार की सबसे अधिक प्रभावोत्पादिनी शक्ति मानता रहा हूँ। नारी शरीर मेरे लिए देवमंदिर की भाँति पवित्र है।'

द्विवेदी जी लोककल्याण को विशेष महत्व देते हैं। उन्होंने सम्पूर्ण उपन्यास में सर्वत्र नैतिकता पर बल दिया है। वे कहते हैं कि व्यक्ति को उचित-अनुचित का निर्णय अपनी विवेक बुद्धि से करना चाहिये। विवेक को वे लोक, शास्त्र, गुरू से भी अधिक प्रामाणिक मानते हैं। लेखक की यह भी धारणा रही है कि निवृत्ति मार्ग या वैराग्य वस्तुत: जीवन से पलायन ही तो है। व्यक्ति को इस योग्य बनना चाहिये कि वह संसार में रहते हुए भी समस्त कामनाओं एवं भोगों के आकर्षण पर विजय प्राप्त कर सके।

हर्षकालीन भारत का सांस्कृतिक रूप इस उपन्यास में प्रमुखता से उभारा गया है। उस समय कला के सभी रूप अपने उत्कर्ष पर थे। समाज में कवियों, कलाकारों का सम्मान था। नाट्य, काव्य, संगीत, चित्र एवं मूर्तिकला उन्नत अवस्था में थी। अभिनय के लिए प्रेक्षाग्रह बने हुए थे। काव्य की भाषा संस्कृत और प्राकृत थी। आचार्यों के साथ-साथ कवियों और कलाकारों को भी विशेष सम्मान प्राप्त था। 'बाणभट्ट की आत्मकथा' में सरस्वती मंदिर में प्रतिवर्ष मनाये जाने वाले मदनोत्सव का वर्णन किया गया है। इस उत्सव में गणिका चारुस्मिता का नृत्य होता था तथा अनेक देशों के कवि, कलाकार और नर्तक अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। व्यक्ति को विवेक, साहस, करुणा जैसे गुण अपने भीतर विकसित करने चाहिये। बाणभट्ट और निपुणिका दोनों इन गुणों से विभूषित हैं। निपुणिका और बाणभट्ट द्वारा भट्टिनी का उद्धार तथा विलासी समाज के बीच रोजी-रोटी कमाते हुए अपने सतीत्व की रक्षा करना निपुणिका के इन्हीं गुणों का परिचायक है। वह बड़ी से बड़ी विपत्ति के समक्ष भी किं कर्त्तव्य विमूढ़ नहीं होती अपितु उसका विवेकपूर्ण समाधान भी खोज लेती है।

इस उपन्यास में द्विवेदी जी ने साहित्यकारों को एक महत संदेश प्रेषित किया है, कि वे पुरानी परम्पराओं के मोह को छोड़, नये विषय, नये काव्य रूप एवं नई परम्पराओं को रचनाओं में स्थान दें। दूसरी ओर सामान्य जनता को उनका यह सन्देश है कि नारी के प्रति सम्मान का भाव रखें, उसे केवल वासना पूर्ति का साधन मात्र न मानकर उसके प्रति पवित्र एवं उदात्त भाव अपने मन में रखें। राज्य में व्यवस्थाओं और सुधार का जिम्मा केवल राजा का नहीं है, वरन् जनसाधारण को भी अपनी शक्ति और साधनों का उपयोग जनहित में करना चाहिये। शैव दर्शन के प्रभाववश लेखक मानते हैं कि सारा विश्व त्रिपुर भैरवी की लीला है। शैव दर्शन के अनुसार प्रकृति क्रियाशील है, जो पुरुष को प्रेरित और आकर्षित करती है। प्रकृति नारी स्परूप है। बाणभट्ट की आत्मकथा के प्रेम प्रसंग इसी धारणा के अनुरूप हैं। भट्टिनी और निपुणिका दोनों ही बाणभट्ट से प्रेम करतीं हैं, किन्तु उनके प्रेम में कहीं भी ईर्ष्या भाव नहीं है। यह प्रेम उनमें कर्त्तव्य भाव जगाता है, उनकी वृत्तियों को उदात्त बनाता है, इसलिए श्लाध्य है। मोह पर कर्त्तव्य की विजय ही प्रेम का उदात्त स्वरूप है और प्रेम के इसी उदात्त स्वरूप का चित्रण करते हुए द्विवेदी जी ने अपनी सांस्कृतिक चेतना का परिचय इस उपन्यास में दिया है।

'बाणभट्ट की आत्मकथा' तत्कालीन युग को जीवन्त रूप में प्रस्तुत करने के साथ ही वर्तमान समाज की समस्याओं को स्पष्ट चित्रित करती है। लेखक ने मध्यकालीन जड़ता पर प्रहार करते हुए उसे आधुनिक चेतना से जोड़ने का प्रयास भी किया है। तत्कालीन समाज में अनेक प्रकार की विरोधी धर्मसाधनायें प्रचलित थीं, जिनके कारण समाज विश्रृंखलित हो रहा था, राजनीतिक स्थिति अस्थिर एवं चंचल थी। इसी अस्थिरता के बीच उन्होंने बाणभट्ट के माध्यम से नवीन मूल्यों की खोज की है।

* एसोसिएट प्रोफेसर, शासकीय कला एवं वाणिज्य 'अग्रणी' महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

वैदिक पुराण साहित्य में प्रतिपादित ऋषभ तथा भरत के चरित्र

डॉ. सावित्री मिश्रा *

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य विषय वैदिक पुराण साहित्य में प्रतिपादित ऋषभ तथा भरत के चरित्र इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य जनता जनार्दन के समक्ष वैदिक पुराण साहित्य में प्रतिपादित ऋषभ एवं भरत के चरित्र प्रस्तुत करना है। उक्त दोनों विभूतियों के चरित्र आज के युग में चरित्र सारभौमिक है तथा जनता उनके चरित्रो का पालन कर नवीन समाज की स्थापना करें साथ–साथ ही आदर्श समाज की परिकल्पना को साकार रूप में प्रकट करें।

प्रस्तावना – भगवान ऋषभ देव और चक्रवर्ती भरत की आदिपुराण के प्रमुख कथानायक है भगवान ऋषभ देव और चक्रवर्ती भरत इतने अधिक प्रभाव शाली पुण्य पुरूष हुये थे कि उनका जैन ग्रंथो में तो उल्लेख आता ही है उसके सिवा वेद मंत्रो पुराणों आदि मे उल्लेख मिलता है। भागवत् में भी मरूदेवी, नाभिराय, वृषभदेव और उनके पुत्र भरत का विस्तृत वर्णन दिया है। यह दूसरी बात है कि वह कितने ही अंशो में भिन्न भिन्न प्रकार से दिया गया है। इस देश का भारत नाम भी भरत चक्रवर्ती के नाम से प्रसिद्ध हुआ है।

वैदिक पुराण साहित्य में ऋषभ का वर्णन – भगवान ऋषभदेव का व्यक्तित्व अत्यन्त सशक्त और तेजस्वी था उनकी मान्यता देश और काल की सीमाओं का अतिक्रमण करके देश–देशान्तरों में फैल गई वे किसी एक सम्प्रदाय, जाति धर्म के नेता नही थे। वे तो कर्म और धर्म दोनो के ही आद्य प्रेरक थे। मानव की आद्य सभ्यता को एक दिशा देने का महानकार्य उन्होने किया था, सारा मानव समाज उनके अनुग्रहों और उपकारों के लिये चिर ऋणी था वर्ग, जाति और वर्ण के भेदभाव के बिना सारी मानव जाति उन्हे अपना उपास्य मानती थी। उनके विधि कर्यकलापों और रूपों को लेकर विभिन्न देशें और कालों में उनके विविध नाम प्रचलित हो गये। शिव महापुराण में उन्हे अट्ठाइस योगावतारों मे एक अवतार भगवान ऋषभ देव का माना है। श्रीमद्भागवत में उनका अष्ठ्म अवतार (श्रीकृष्ण) स्वीकार किया।

वेदों मे प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभ देव के लिये अनेक आहुतियों, स्तुतियाँ, विभिन्न नामो से की गई है। उनकी ऋचाओं में उनकी स्तुति, अग्नि, मित्र, यम आदि नामों से की गई है। ताण्ड्य[1], तैत्तिरीय[2], और शतपथ[3], ब्राह्मण में अग्नि के नाम से उन्हे आद्य (आदिपुरूष) मिथुनकर्ता (विवाह प्रथा के प्रचलन कर्ता, ब्रह्म, पृथ्वी पति, धाता, ब्रह्मा, सर्वविद्, सर्वज्ञ) कहा गया है। वेदों उन्हें जातवेदस (जन्म से ज्ञान सम्पन्न) रत्नधाता, विश्ववेदस् (विश्व को जानने वाला) मोक्षवेता और ऋत्विज (धर्मसंस्थापक) बताया गया है। वेदों में अनेक स्थानों पर ऋषभदेव की स्तुति की गई है। इनके देवता ऋषभदेव है।

त्वं रथं प्रभसे योधमृष्वमावो युध्यन्तं वृषभं दशद्युम।
त्वं तुग्रं वेतसवे स चाहन्त्वं तुजिं गृणन्तभिन्द्र तू तो।।[4]

इसका आशय यह है कि युद्ध करते हुये ऋषभ को इन्द्र ने युद्ध सामग्री और रथ प्रदान किया।

अतिसृष्टो अपां वृषभोऽतिसृष्टा अग्नयो दिव्या:।।[5]

इन्द्र ने राज्य में वर्षा नही होने दी। तब वृषभदेव ने जल बरसाया।

अहो मुंचं वृषभ याज्ञिमानां विराजन्तं प्रथममध्वराणाम्।
अपां न पातमश्विना हुवे धिय इन्द्रियेण इन्द्रियंदत्तभोज:।।[6]

सम्पूर्ण पापो से मुक्त तथा अहिंसक वृत्तियों के प्रथम राजा आदित्य स्वरूप श्री ऋषभदेव का में आव्हान करता हूँ। वे मुझे बुद्धि एवं इन्द्रियों के साथ बल प्रदान करें।

विष्णुपुराण – पुराण साहित्य के इतिहास में विष्णुपुराण का सातिशय महनीय है। इसके द्वतीय अंश के प्रथम अध्याय में भगवान ऋषभ देव का चरित्र मिलता है।

'महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था, उनकी मेरूदेवी नाम की भार्या से अतिशय कान्तिमान, ऋषभ नाम पुत्र उत्पन्न हुआ।'[7]

वायुपुराण – यह पुराण अत्यंत प्राचीन है। वाणभट्ट ने अपनी कादम्बरी में इसका उल्लेख पुराणे वायुप्रलयितम् लिखकर किया है। इस पुराण के 33 वें अध्याय में प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव का चरित्र चित्रण दृष्टिगोचर होता है। नाभि ने मेरूदेवी से ऋषभ नामक एक पुत्र उत्पन्न किया जो अत्यन्त तेजस्वी और नृपतियों में श्रेष्ठ और सभी क्षत्रियो का पूर्वज था।[8] ऋषभ से भरत की उत्पत्ति हुई जो अपने भाइयों में श्रेष्ठ था। ऋषभ अपने पुत्र भरत को राजलक्ष्मी देकर सन्यासी हो गये।[9]

भरत का वैदिक पुराण साहित्य में वर्णन – भरत चक्रवर्ती का व्यक्तित्व अत्यधिक उत्कृष्ट एंव प्रवाहमय था। वे अत्यधिक प्रवाहशील एवं पुण्यमानव थे। उन्होंने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की तथा असंख्य मानवों को कल्याणमयी उपदेश दिया। उन्होंने वर्ण, जाति, धर्म, ऊँच, नीच आदि में समान संस्कृति का स्त्रोत प्रवाहित किया। वे प्रजा का पुत्रतुल्य व्यवहार करते थे।

विष्णुपुराण – पुराण साहित्य में विष्णु पुराण का महान स्थान है। इस पुराण के 13 वें अध्याय में ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत का चरित्र मिलता है। मैत्रेय ऋषि पराशर जी से कहते है वे नरेश भरत निरंतर योगयुक्त होकर भगवान कृष्ण में चित लगाये शालग्राम क्षेत्र में निवास करते थे इस प्रकार पुण्यदेश के प्रभाव और ईश्वर चिंतन से भी उनकी मुक्ति क्यों नही हुई जिससे उन्हे फिर ब्राह्मण का जन्म लेना पड़ा।[10]

श्रीमद्भागवत् – यह पुराण संस्कृत– साहित्य का एक अनुपम रत्न हैं।

*भू.पू. अतिथि विद्वान (संस्कृत) शासकीय गांधी महाविद्यालय, बालाजी मिहोना, जिला - भिण्ड (म.प्र.) भारत

भक्तिशास्त्र का तो यह सर्वस्य हैं। यह निगम कल्पतरू का स्वयं गलित अमृतमय फल है। वैष्णव आचार्यो ने प्रस्थानत्रयी के समान भागवत को भी अपना उपजीव्य मानते है। भगवान आदिनाथ के चक्रवर्ती पुत्र भरत जी का वर्णन भागवत के पाँचवे स्कंध में मिलता है।

भगवान ऋषभदेव का जैनेतर पुराण जैसे– विष्णु, अग्नि, लिंग, मार्कण्डेय, शिव नारद, वायु, गरूण, ब्राह्मण्ड, बाराह आदि पुराणों मे उनका अल्प में वर्णन मिलता परंतु श्रीमद्भागवत् में उनका विशद् वर्णन मिलता है।

चक्रवर्ती भरत का वैदिक पुराण जैसे– लिंग, अग्नि, मार्कण्डेय, शिव, वायु, गरूण, ब्राह्मण्ड, बाराह आदि पुराणों मे वर्णन अल्प मिलता है। श्रीमतद्भागवत्, विष्णु, नारद, आदिपुराणो में उनका विदश् वर्णन मिलता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. ताण्ड्य ब्राह्मण– 25/9/3
2. तैतिरीय ब्राह्मण– 1/7/2/3/.33/11/4/1,3/3/10/2
3. शतपथ ब्राह्मण– 10/4/1/5
4. ऋग्वेद – 4/6/26/4
5. अथर्ववेद – 16 काण्ड प्रजापतिसूक्त।
6. अथर्ववेद – 19/42/4
7. हिमायंम तु वै वर्ष नाभेसीनमहात्मनः। विष्णुपुराण द्वितीय अंश 1/27/107
8. नाभेहि सर्ग वक्ष्यामि हिमाह ताह्नबोधत। वायुपुराण पूर्वार्ध 33/50/257

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

चाणक्य-माणिक्य में शिक्षा नीति

डॉ. भावना श्रीवास्तव *

प्रस्तावना - साहितं विहितं दत्तं ज्ञातं तद्यन्न केनचित्।
किमन्यत् कविराजस्य श्रीभोजस्य प्रशस्यते।।

महाराजा भोज भारतीय परम्परा के संक्रान्ति काल के ऐसे आलोकपुंज है जिनके प्रभामण्डल सेढूरी सहस्त्राब्दी भीतर बाहर आलोकित होती रही। भारतीय राजाओं में परमार राजा भोज अद्धितीय है। उनकी राजधानी धाननगरी (धार) होने से धारेश्वर और राय का केन्द्र मालवा होने से मालवाधीश भी कहलाते हैं। राजा भोज का विरुद्ध नाम भूपाल था। इस नाम पर भूपाल (भोपाल) और भूपालपुर (भोपावर) बसाया। परम्परानुसार राजा भोज के भोजपाल नाम के आधारी पर बस्ती का नाम भोजपाल हुआ जो आजकल भोपाल कहलाता है।

राजा भोज के व्यक्तित्व तथा कृतित्व के ज्ञान में इतिहास और अनुश्रुतियाँ ढोनों परस्पर पूरक हो जाती है। ढोनों मिलकर हमें राजा भोज के विषय में अधिक जानकारी दे सकते है। जून 1056 ई. का एक ताम्रपत्र राजा भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह का प्राप्त हुआ है। 1065 ई. का एक ग्रंथ राजा भोज के रायकाल में लिखा गया है। इससे स्पष्ट है कि 1055 तक राजा भोज विद्यमान थे। आइने-अकबरी के अनुसार राजा भोज की आयु 90 वर्ष थी। अनेक तथ्यों के आधार 1001 ई. से पूर्व ही राजाभोज हो गये थे।

राजा भोज के ताम्रपत्रों में अनेक बार-बार भोज देव के नाम उल्लेख ही प्राप्त होते हैं और इसी नाम उन्होंने अपने हाथ से सभी ताम्रपत्र जारी किये-

'स्वहस्तोऽयं श्री भोजदेवस्य'

राजाभोज के ग्रंथों, भवन तथा विरूदों के नाम बहुधा एक ही रहे।

प्रबन्धचिन्तामणि के अनुसार राजाओं के 104 विरूद, 104 भवन, 104 गीतप्रबंध रहे और उनके सबके नाम एक ही थे। अजड़ के अनुसार यह संख्या 84 थी। उनमें सरस्वतीकण्ठाभरण, चाणक्य-माणिक्य, श्रृंगार प्रकाश, चपरूपर आदि ग्रंथ सर्वप्रसिद्ध है।

राजाभोज का 'चाणक्य -माणिक्य' चाणक्यनीति प्रकार का आठ अध्यायों का ग्रंथ है। राजनीति, लोकनीति ओर सदाचार का इसमें अनोखा समन्वय है। रातवर्ग के लिए तथा आदर्श समाज के लिए मार्गदर्शन सिद्ध हो सकता है इसमें जगत को लोकशिक्षा मिलती है।

येन सम्यग्-अधीतेन प्रज्ञा संबर्धते नृणाम्।
सत्य-शौच-रतो नित्य हिंसा-क्रोध विवर्जित:।। चाणक्य-माणिक्य 3।।

राजभोज ने जन मानस को नीति शिक्षा देते हुए कहा है-

रहस्य- भेदंपैशुन्य पर-दोषाऽनुकीर्तनम।
कलह पर-कृत्यं च दूरत: परिवर्जयेत।। चाणक्य-माणिक्य 6।।

राजा भोज मनुष्य को कुछ कार्य न करने की शिक्षा देते हुए कहते हैं-

पर-वादं पर-स्वेच्छा पर-हास्यं पर-स्त्रियाम्।
पर-वेश्यनि वासं च न कुर्वीत कदाचन्।। चाणक्य-माणिक्य 8 ।।

राजाभोज शिक्षाप्रद बातों से जनमानस के लिए प्रेरणस्त्रोत बन जाते हैं-

स बन्धुऽयो हिते स पिता यस् तु पोषक:।
तन मित्रं यत्र सद्भाव: स देशो यत्र जीवित ।। चाण.-माणि. 21।।

जो गुणवान है और धर्मपराण है वही जीवित है। जो गुण से रहित और धर्म से च्युत है उसका जीना तो व्यर्थ ही है। चाण.-माणि. 22।।

राजा भोज कहते हैं-

येन जीवेन जीवन्ति मित्राणों ष्टा: स: - बान्धवा: ।
सफलं जीवितं तस्य स्वाऽऽत्मादर्श को न जीवति।। चाण.-माणि. 23।।

राजा भोज चाणक्य-माणिक्य में शिक्षा देते हुए कहते हैं-

व्यजदुर्जन-संसर्ग भज साधु-समागयम्।
कुरू पुण्यम् अहो-रात्रं स्मर नित्यम् अनित्यताम्।। 211

दुष्ट व्यक्तियों का साथ छोड़कर सानों का संग करो, दिन-रात पुष्य-(शुभ) कार्यों को करते रहो और क्षणभंगुरनश्वर) को छोड़कर शाश्वत का स्मरण किया करो।

आपत्सु मित्रं जानीयाद् रणे सूरं रह: सुचिम्।
आर्या च विभवे क्षीणे दुर्भिक्षे च प्रियाऽतिथिम् ।। 214

विपत्ति आने पर मित्र की परीक्षा होती हैं, युद्ध में वीर की और एकान्त में (मनुष्य की) पवित्रतासच्चरित्र) की परीक्षा होती हैं। तब धन-वैभव नष्ट हो जाता है तब पत्नी की और अकाल के समय अतिथि-सत्कार की परीक्षा हो जाती है।

शाश्वतं विधिवद् दानं शाश्वतं सत्य-भाषणम्।
शाश्वती प्रगुणा विद्या ह्रधं मित्रं च शाश्वतम् ।। 255

विधिवत दान शाश्वत होता हैं, सत्य बोलना शाश्वत हैं। विशेष गुण वाली विद्या शाश्वत होती हैं। मन के लायक मित्र शाश्वत होता है।

दुर्जनै: सह संगेन सानोऽपि विनश्यति।
जलं प्रसन्नम् अप्या हु: पकङ: कलुषतां नयेत्।। चाण.-माणि. 330।।

दुर्जन की संगति से सान भी नष्ट हो जाता है। कितना ही स्वच्छ जल होने पर भी कीचड़ उसे मलिन या कलंकित कर देता है।

तनुर्उपकार: साधुषु।
विकसित परम् अप्सु तैल-बिन्दुर इव।
उदमेषु तु बाधते महान अपिं
संकुचितं यथा धृत तुहिने।। चाण.-माणि. 337 ।।

सानों पर थोड़ा भी उपकार ऐसे फैल जाता है जैसे जल में तैल की बूँद। पर नीचे लोगों पर बड़ा उपकार भी उसी प्रकार सिकुड़ जाता हैं। जिस प्रकार ठंड में घी।

राजा के लक्षण बताते हुए राजाभोज कहते हैं-

स्वं राष्ट्रं पालयेत् नित्यं सत्य-धर्म-परायण:।

* विभागाध्यक्ष (संस्कृत) शास.म.ल.बा. स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

निर्जित्य पर-सैन्यानिं क्षिति धर्मेण पालयेत् ।। चाण.-माणि. 52।।

राजा इनकी सावधानीपूर्वक रक्षा करे-

गान्धर्वं नृत्यम् आलेख्यं वाद्यं च गणितां कला:।

अर्थशास्त्र धनुर्वेद यात्नद् रक्षेन् महो-प्रति:।। चाण.-माणि.422।।

कर्म की प्रधानता बताते हुए कहते हैं-

लग्न वशिष्ठ ने दिया फिर भी सीता को दु:ख ही मिला,,

न पितु: कर्मणा पुत्रों न पिता पुत्र कर्मणा।

स्व-कृतेनै व सम्पत्तिं विपत्ति चोप भुञ्(जते।। चाण. माणि. 622।

न कश्चित् कस्यचित् मित्र न कश्चित् कस्यचिद् रिपु:।

अवस्थात. प्रजायन्ते मित्राणि रिपवस् तथा । चाण.-माणि. 71।।

मित्र के बारे में कहते हैं-

न विश्वसेद् अभित्रस्य मित्रस्याऽपि न विश्वसेत्।

कदाचित् कुपितं मित्रं सर्वं गुश्त प्रकाशयेत। चाण.-माणि. 728।।

जो मित्र न हो उस पर विश्वास न करें। मित्र पर भी विश्वास न करें। कभी मित्र नाराज हो जाए तो सब गोपनीय उजाकर कर दें।

पराऽन्नं पर-वस्त्रं च पर शय्यां पर-स्त्रियं:।

पर-स्वादं पर-द्रव्य दूरत: परिवर्जयेत।। चाण.-माणि. 84।।

इस प्रकार उनकी कृतियों में जनमानस के लिये नीति शिक्षा के अनेक श्लोक दिखाई पड़ते हैं जिनमें जनमानस पर उसका प्रभाव पड़ता है।

इस प्रकार शास्त्र एवं शास्त्र के अप्रतिम समन्वयक, शास्त्र के अनवरत, प्रयोक्ता स्थापत्य के चतुर्दिक्, क्रियान्वयन में निरत राजाभोज अपने अन्य वंशज तथा अन्य परवर्ती राजाओं के आदर्श बन गये थे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्राचीन मालती गाथाएँ- डॉ. पूरन सहगल, महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ स्वराज संस्थान संचालनालय, म.प्र. 2011
2. राजा भोज- डॉ. भवगतीलाल राजपुरोहित-स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग म.प्र. 2011
3. चाणक्य-माणिक्य- डॉ. भगवतीलाल राजपुरोहित-स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग म.प्र. 2012

****

आदिपुराण के आधार पर ऋषभ एवं भरत का चरित्र चित्रण

डॉ. सावित्री मिश्रा *

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से आदिपुराण के आधार पर ऋषभ एवं भरत चरित्र चित्रण का मनोहारी वर्णन किया गया है जो समाज में आदर्श स्थापित करता है। श्रषभ देव तथ भरत दोनो का चरित्र सार्वभौम रहा है उनके जीवन में दिव्य और अलोकिक गुण विद्यमान थे। यह सर्वमान सत्य है कि आदिनाथ इस श्रृष्टि के आदिपुरूष थे उनकी सर्वोपरिता, सर्वव्यापक्ता, जैन एवं वैदिक दोनो संस्कृतियों में स्वीकार किया है। आदिपुराण में भगवान श्रषभ देव प्रमुख नायिक है उनके जीवन में दिव्यता तेजस्विता विभिन्नरूपों में समन्वय आदेश समन्वय आदि उच्चत्यागी वैराग की प्रतिमूर्ति आदि है।

प्रस्तावना – आदिपुराण में प्रतिपादित ऋषभ का चरित्र – वर्तमान अवसर्पिणी के कालचक्र में भगवान ऋषभदेव जैन-धर्म के संस्थापक हुये। वे एक मनुष्य थे किन्तु उन्होनें अमरपद पाया और तीर्थकर हुये। साथ ही उन्होंने दूसरो को पूर्णपद प्राप्त करने का मार्ग भी बताया उनकी लोकोपरी शिक्षाओं से असंख्यात जीवो का कल्याण हुआ। उनके उत्तरगामी 23 तीर्थकर और हुयें जिन्होंने उनकी शिक्षाओं और सिद्धांतो का पुनर्गठन एवं पुन: प्रचार किया।

जैन पुराण साहित्य के अध्यन के प्राप्त होता है कि जैनधर्म के 24 तीर्थकर हुये है और बताया गया है कि तीर्थकरों के जन्म से पूर्व उनकी मातायें 16 स्वप्न देखती है। ठीक इसी प्रकार भगवान ऋषभ देव के जन्म से पूर्व उनकी माता मरूदेवी ने 16 स्वप्न देखे।

सोलह स्पप्न– स्वस्छ और सफेद शरीर धारण करने वाला ऐरावत हाथी, दुन्दभि के समान शब्द करता हुआ बैल, पहाडी को चोटी को उल्घन करने वाला सिंह, देवों के हथियारो द्वारा नहलायी गयी लक्ष्मी आकाश में लटकती हुई दो मालायें आकश को प्राकाशमान करता हुआ चन्द्रमा पुन: उदय होता हुये सूर्य, मनोहर मछिलीयों का युगल, जल से भरे हुए दो कलश, स्वच्छ जल और कमलों से सहित सरोवर, क्षुभित ओर भँवन से युक्त समुद्र, देदीप्यमान सिंहाशन, स्वर्ग से आता हुआ विमान सरोवर, पृथ्वी से प्रगट होता हुआ नागेन्द्र का भवन, प्रकाशमान किरणों से शोभित रत्नों की राशि और जलती हुई देदीप्यमान अग्नि। सोलह स्वप्नो को देखेने के बाद एक स्वर्ण के समान पीला बैल मुख मे प्रवेश करते हुये देखा।

तभी प्रभात– जागरण के मंगल वाद्य बजने लगे और बन्दी मंगल गान करने लगे मरूदेवी स्वप्न के स्मरण से आनन्दित होती हुई उठी। उन्होंने मंगल स्नान करके वस्त्राभूषण धारण किये और प्रमुदित मन से अपने प्रति नागराज के पास पहुँची। वहाँ समुचित विनय के साथ नाभिराज के बाई और सिंहासन पर बैठ गई। नाभिराज ने पत्नी की समुचित अभ्यर्थना की। तब मरूदेवी ने रात में देखे हुये स्वप्नो का वार्णन करते हुये राजा नागराज से उनका फल पूँछा।

आदिपुराण में प्रतिपादित भरत का चरित्र – आचार्य जिनसेन (900ई.) का आदिपुराण भारत तथा भारतीय जीवन का विश्वकोष हे। इसमे भगवान ऋषभदेव के सुयोग्य पुत्र भरत का अद्धितीय चित्ररण हैं भरत महाप्रतापी एवं आत्म सम्मान जीवी थे। उनके पास अतुल सम्पदा थी। उनके देवांगनाओं को लज्जित करने वाली छियानवे हजार रानियाँ थी किन्तु उन्हें किसी के प्रति मोह नही था। वे सदैव आत्मा में रमण करते थे। वे अपने प्रजा का विशेष ख्याल रखते थे। प्रजा भी उन्हें धर्मात्मा राजा कहती थी। थोडा सा अवकाश मिलते ही वे आत्म स्वरूप के चिन्तन में लीन हो जाते थे। उन्हें आत्मानुभव भोगों में नही आती थी। वे सदैव आत्मनोन्मुखता का अभ्यास करते रहते थे। सभी को उसी की प्रेरणा देते थे।

जैन साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि चक्रवर्ती के जन्म से पूर्व उनकी माता पाँच स्वप्न देखती है ठीक उसी प्रकार उनकी यशस्वी माता ने भरत के जन्म से पहले 5 शुभ स्वप्न देखे। वे स्वप्न जन्म लेने वाला बालक चक्रवर्ती होगा यह प्रगट करते थे इसके साथ ही साथ वह बालक कितना सुन्दर एवं उज्जवल व्यक्तित्व वाला होगा यह भी सूचित करते थे।

भरत का जीवन भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से समृद्ध था। काला एवं कला-गोष्ठियों के प्रति समाज के सभी वर्गो के व्यक्तियों को उनमें आस्था थी। संवेदनशीलता, मानसिक द्धन्द्ध एवं मनोविकार सामाजिक घात-प्रतिघातों का अंकन करने में सक्षम थे। इसी कारण व्यक्तित्व निर्माण और सामाजिक विकास हेतु वर्ण व्यवस्था, संस्कार, दिव्य भोजनपान, सुन्दर वस्त्राभूषण, सौन्दर्य चेतना की तृप्ति के लिये कलाओं के प्रति अनुराग एवं व्यक्तित्व उत्थान के लिये शिक्षा-साहित्य पर विशेष बल दिया।

इस प्रकार हम देखते है कि आदिपुराण में प्रतिपादित भगवान ऋषभदेव और उनके जेष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भरत दोनो का चरित्र-चित्रण बडा ही अनुपम है। उनके चरित्रो का प्रत्येक कालखण्ड अपार अर्थ गरिमा से व्याप्त है। इनका चरित्र जैनपुराणों मे ही निहित नही है अपितु श्रीमद्‌भागवत में भगवान ऋषभदेव को भगवान के 24 अवतारों मे अष्टम अवतार में श्रीकृष्ण सिद्ध किया है और चक्रवर्ती भरत को जड भरत के नाम से पुकारा है। दोनों का ही चरित्र भौतिक एवं अध्यात्मिक दृष्टि से परिपूर्ण है। तीर्थकर ऋषभदेव मोक्षमार्ग के जगतगुरू है। उनके नाम स्मरण मात्र से मनुष्य पाप से विमुक्त हो जाता है। तीर्थकर ऋषभदेव और चक्रवर्ती भरत दोनो मनुष्य थे किन्तु उन्होने अमर पद को प्राप्त कर लिया था। उनकी लोकोपकारी शिक्षाओं से असंख्यात जीवों को कल्याण हुआ है। इसके साथ ही साथ लोगो ने उनके उपदेशों को ग्रहण किया तथा उनके उपदेशों पर चलने का प्रयास किया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. गजेन्द्रभवदाताडग्वृषभं दुन्दुभिस्वनम्। आदिपुराण – 12/148/263
2. आदिपुराण – 12/149-153/263

*भू.पू. अतिथि विद्वान (संस्कृत) शासकीय गांधी महाविद्यालय, बालाजी मिहोना, जिला - भिण्ड (म.प्र.) भारत

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

Judicial Review - A Study In Indian Perspective

Dr. Vijay Srivastava* Devender Goel**

Abstract - The conception of judicial review is the touchstone and repository of the supreme law of the land. It is a vital principle of our constitution which cannot be abrogated without affecting the basic structure of the Constitution. It is too considered the basic feature of our Constitution. It is the most potent weapon in the hands of the judiciary for the maintenance of the rule of law. it is also the touchstone of the Constitution. The search work consists of introduction, historical perspective of England and United States, judicial review in India and at the end conclusion.
Key Words - Judicial review, constitution of India, law, separation of power, etc.

Introduction - The conception of judicial review is founded on the principles of Rule of law which is the proud heritage of the traditional Indian culture and traditions. Only in the method of working of judicial review and in its type of application, there have been characteristic changes, but the basic philosophy upon which the doctrine of judicial review hinges is the same. The main consideration of judicial review is that to assure the protection of rights, avoid violation of laws, socio-economic uplifts and to alert the other organ i.e. legislature to be in conformity with the Constitution. In ancient India , such type of spirit was prevalent. As per words of Manu: "Law in fact, is the sovereign and leader and regulator of the society. The whole race of mankind is kept in order by law".[3] Judicial review, the power of courts to review statutes and the governmental action to determine whether or not they confirm to rules and principles laid down in constitution. Judicial review is based on the idea that a constitution which dictates the nature, functions and limits of a government- is the supreme law. Consequently, any action by a government that violates the principles of its constitution is invalid. The system of judicial review of administrative action has been inherited from Britain. It is on this foundation that the Indian Courts have built a superstructure of control mechanism. The whole law of judicial review of administrative action has been developed by judges on case to case basis. Consequently, a thicket of technicalities and inconsistencies surrounds it. However, the present trend of judicial decisions is to widen the scope of judicial review of administrative actions and to restrict the immunity from judicial review to a class of cases, which relate to deployment of troops and entering into international treaties, etc.

Indian Railway Construction Co. Ltd. v. Ajay Kumar[4] - Judicial review means review by courts of administrative actions with a view to ensure their legality. Review is different from appeal. In appeal the appellate authority can go into the merits of the decisions of the authority appealed against. In judicial review, the court does not go into merits of the administrative action; court's function is restricted to ensuring that such authority does not act in excess of its power.

Object - The underlying object of judicial review is to ensure that the authority does not abuse its power and the individual receives just and fair treatment and not to ensure that the concerned authorities reach a conclusion which is correct in the eyes of the law.

Minerva Mills Ltd. v. Union of India[5] - The SC observed that the constitution has created an independent judiciary which is vested with the power of judicial review to determine the legality of administrative action and the validity of legislation. Thus, judicial review focuses to protect the citizens of the country from any abuse or misuse of power by any of the branch of the State. Judicial quest in administrative matters is to strike the just balance between the administrative discretion to decide matters as per government policy, and the need of fairness. Any unfair action must be set right by administrative review. Judicial review provides time for 'sober second thought'.

Historical Perspective -

Judicial Review in England - Judicial review is a procedure in English administrative law by which the courts supervise the exercise of public power on the application of an individual. The Britain constitutional theory as expounded by the Prof. A.V.Dicey does not recognize a separate system of administrative courts that would review the decision of public bodies. The constitutional theory of judicial review has long been dominated by the Doctrine of Ultravires, under which a decision of public authority can

*Asst. Professor, Law College, Uttaranchal University, Dehradun (Uttaranchal) INDIA
**LLM Student, Uttaranchal University, Dehradun (Uttaranchal) INDIA

only be set aside if it exceeds the powers granted to it by the parliament. Therefore, it seems that today the constitutional position of judicial review is dictated by the need to prevent the abuse of power by the executive as well as to protect individual rights.

After two decisions of the House of Lords in Board of Education v. Rice[6] and Local Government v. Arlidge[7] Dicey in his article "The Development of Administrative Law in England" observed that legislation had conferred a considerable amount of quasi-judicial authority on the administration which was a considerable step towards the introduction of administrative law in England.

Judicial review in United States - In USA, the doctrine of judicial review has been accepted. The doctrine of separation of powers has been recognised by the framers of the American Constitution. The legislative powers are vested in the Congress, the executive powers in the President and the judicial power in the Supreme Court and the courts subordinate thereto. Under the power of judicial review, the Supreme Court can set aside any order passed or action taken by an administrative authority or agency if it is not in consonance with law.

Marbury v. Madison 1803

Chief Justice Marshall observed that the Constitution is Supreme and it is the duty of the court to declare what the law is.

In the United States, the doctrine of judicial review is a gloss put upon the constitution by the judges themselves. Chief Justice Marshall, was modest enough to say that if it was the duty of the court to apply the law, it was no less its duty to enforce the Constitution which was the 'superior paramount law' of the land, and if unfortunately, there was a conflict between the fundamental law and the ordinary law, the Court would be bound to brush aside the law laid down by the legislature, in order to give effect to the paramount law.

Judicial Review and Constitution - The Constitution of India expressly establishes the Doctrine of judicial Review through several Articles viz..13,32,131-136,143,226&246. The expression of judicial review is firmly rooted in India, and has the express sanction of the constitution. It is the basic feature of our Constitution. It is the most potent weapon in the hands of the judiciary for the maintenance of the rule of law. it is also the touchstone of the Constitution. The Supreme Court and high Courts are the ultimate interpreters of the Constitution. 'This is indeed a delicate task assigned to the judiciary by the Constitution. The doctrine of judicial review is thus to be considered as the touchstone and essence of the rule of law'. R.K Jain v. Union of India[8] As per Article 13 declares that any law which contravenes any of the provisions of the part of fundamental Rights shall be void. As per the Art.372 Clause1 establishes the judicial review of the pre-constitution legislation. Article 32 and 226 entrusts the roles of the guardian and guarantor of fundamental rights to the Supreme and High Courts.

Kesavananda Bharati v. State of Kerala AIR 1973 SC The Court held that judicial review is not only an integral a part of the constitution but also a basic structure of the Constitution, which cannot be abolished or whittled down even by an amendment of the Constitution.

Minerva Mills Ltd. v. Union of India (1980) 3 SCC 625 - The Court held that in democratic society, judicial review is the soul of the system because without it democracy and the rule of law cannot be maintained.

D.K. Basu v. State of West Bengal AIR 1997 SC - It has been firmly established that the court can grant compensation for established breach of fundamental rights and abuse of power, while exercising jurisdiction under Article32 of the Indian Constitution.

S.R. Bommai v. Union of India (1994)3 SCC - The Court held that judicial review is the touchstone and repository of the supreme law of the land. It is a vital principle of our constitution which cannot be abrogated without affecting the basic structure of the Constitution.

Characteristics of Judicial review in India - Judicial review power is used by both the Supreme and High Court, as both the Supreme Court and High Court exercise the power of judicial review. But the final power to determine the constitutional validity of any law is in the hands of the Supreme Courts.

Principle of procedure established by law, judicial review in India is governed by the principle: 'procedure established by law' . There under the court conducts one test, i.e., whether the law has been made in accordance with the powers granted by the constitution to the law-making body and follows the prescribed procedure or not. It gets rejected when it is held to be violative of procedure established by law.

Grounds for Judicial Review - The judicial review of any administrative action can be exercised on four grounds, i.e., illegality, irrationality, procedural impropriety or fairness and proportionality. These grounds of judicial review were developed by the Lord Diplock in Council of Civil Services Union v. Minister of Civil Services (1984)3 AII ER

Illegality, the choice or decision makers must understand the law that regulate them. if they fail to follow the law properly, their decision, action or failure to act will be illegal. Thus an action or decision may be illegal on the basis that the public body has no power to take that action or decision, or has acted beyond its power.

Irrationality, the courts may also intervene to quash a decision if they consider it to be so unreasonable as to constitute 'irrationality' or 'perversity' on the part of the decision maker. The benchmaker decision on this principle of judicial review was made as long ago as 1948 in the Wednesbury case.

Associated Provincial Picture Houses Ltd. v. Wednesbury Corpn. [1948]1 KB 223 HL

Lord Greene, if a decision on a competent matter is so unreasonable that no reasonable authority could ever have come to it, then the courts can interfere but to prove a case of that kind would require something overwhelming.

Procedural Impropriety, decision makers must act fairly in reaching their decisions. This principle applies solely to matters of procedure, as opposed to considering the substance of the decision reached. The case must be heard and decided by the person to whom it is delegated and not by another. The process to arrive at some decision must be followed as it is expressed in the statute. The rule of natural justice must be applied by the deciding authority.

Proportionality, this principle provides that the means for achieving some object ought to be sufficient but not exercise for the purpose of achieving that object. Under this principle, the court will see that the legislature and administrative authority maintain a proper balance between the adverse effects which the legislation or the administrative order may have on the rights, liberties or interests of persons keeping in mind the purpose for which they were intended to serve.

Conclusion - The growth of judicial review is the inevitable response of the judiciary to ensure proper check on the exercise of public power. Growing awareness of the rights in the people. There is a general perception that the judiciary in this country has been active in expansion of the filled of judicial review into non-traditional areas, which earlier were considered beyond judicial purview. Under the traditional theory, courts of law used to control existence and extend of prerogative power but not the manner of exercise thereof.

References :-

1. Manu-VII-17
2. (2003)4 SCC 579
3. AIR 1980 SC 1789
4. 1911 AC
5. 1915AC
6. (1993)4 SCC119

****

Independency And Accountability Of Judiciary - A Study In Indian Perspective

Anjum Parvez * Subhra **

Abstract - The Indian judiciary is consider to be the guardian and the protector of the people's fundamental rights and also a balancing wheel between the rights and social control. The Indian judiciary has been assigned a vital role in various areas like upholding the federal principle, interpretation of the laws made by respective legislatures, testing the validity of such laws and more importantly in protecting the fundamental right of the citizens. The search work consists of introduction, historical perspective, brief overview, legal framework and at last conclusion.
Key Words - Independency and accountability of judiciary, Supreme court of India, High Court guardian, protector, etc.

Introduction - Judiciary is one amongst the three important pillars of the Indian democracy that is governed by rule of law. The Supreme Court of India is the Apex Court and is the final interpreter of the Indian Constitution and the laws of the land. The courts are also known as the guardian and the protector of the people's fundamental rights and also a balancing wheel between the rights and social control. The other arms of the government i.e. the legislature and the executive creatures of the Indian constitution. All the organs of the government plays other role but judiciary is consider to be the most powerful as is the guardian of the Indian constitution. However, operation of the theory of separation of powers and checks and balances require each one of the three organs not to interfere in the jurisdiction of the other. Accountability of Judiciary is one of the fundamental characteristics of an independent judiciary. As an Australian Judge MICHAEL KIRBEY observed that "In a pluralist society Judges are the equalizers. They neither serve majority or minority. Their duty is towards law and justice, military, to money, to tabloid media or the screaming mob. In upholding law and Justice, Judges have vital function in pluralist society to make sure that diversity is respected and the rights of all protected".

The judiciary in Indian has been assigned a vital role in various areas like upholding the federal principle, interpretation of the laws made by respective legislatures, testing the validity of such laws and more importantly in protecting the fundamental right of the citizens. The Supreme Court stands at the top of the hierarchy of the courts constituted under the constitution. It is the final arbiter as to the upholding of the federal principle, the validity of a law or executive action and as to the enforcement of fundamental rights of the citizens. The decision of the supreme court is binding on all the other courts in India which include the High court as well as the subordinate courts. The independency of judiciary seem to be sometimes known as judicial activism. The writers are of the opinion that the Indian judiciary is said to be the most powerful one in the world in view of its judicial powers and functions. However Judiciary, higher Judiciary in particular is under obligation to act according to the constitution which is supreme. This calls for the necessity of having an independent judiciary which is free from all influences, political or otherwise.

Historical perspective - In order to know the role of the judiciary under the present Constitution it will be necessary to discuss the historical perspectives in relation particularly to the Supreme Court. The position of the supreme court under the constitution came up for consideration before the constituent assembly at a very early age. As already pointed out elsewhere almost simultaneously with the appointment of the Union Constitution Committee, a special committee was set-up to consider and report on the constitution and powers of the Supreme Court. The Committee sent its recommendations highlighting the upholding of federal principle and suggesting the various jurisdictions it should exercise.[3] Its recommendations were mainly based on the provisions of the Government of India Act,1935.

The Sapru Committee Report recommended that, under the new Constitution the position of the Federal Court would have to be greatly strengthened and that it would need to have wider, jurisdiction and must be the interpreter and guardian of the Constitution. The Report further emphasized that, the expanded jurisdiction should include a special responsibility for difficult cases, concerning the "Civil rights and liberties of people".[4]

Dr. B.R.Ambedkar, one single integrated judiciary

*Asst. Professor (Law) Uttaranchal University, Dehradun (Uttaranchal) INDIA
**LLM Student, Uttaranchal University, Dehradun (Uttaranchal) INDIA

having jurisdiction and providing remedies in all cases arising under the Constitutional Law , the Civil Law, or the Criminal Law. Such a judicial system, plus uniformity of law, were essential to maintain the unity of the country. [5]

It becomes clear that the framers of the Indian Constitution envisaged a higher judiciary, independent, impartial and powerful to check the arbitrary exercise of State power which might violate the fundamental rights of the citizens. It was expected that the Supreme Court should play the role of the final arbiter in the adjudication of federal problems. The framers of the Constitution wanted the Supreme Court to protect the sanctity of the Indian Constitution and to be its ultimate interpreter and to be the final guardian of the unalienable rights of the citizens of India.

A brief overview of independency of judiciary - The Constitution of India is the basic law of the country. Any inconsistent with or in derogation of the provisions of the constitution is void. Basic principles embodied in the Constitution is Judicial independence among things such as popular sovereignty, socialism, fundamental rights, and directive principles of state policy. During the British rule executive and judicial functions were combined in Collector-Magistrate in a district, making him a local dictator. The makers of the Constitution did not want this to happen in the independent India. That's the reason the framers established a judicial system under which from the highest court of the land to lowest, every level and each of the level, function in the virtue of independency of judiciary.

The Indian Constitution contemplates an independent and impartial judiciary in view of numerous functions assigned to it. The Judiciary led by the Supreme Court is regarded as one of the co-equal branches of the government along with the legislature and the executive. A majority of framers of the Constitution did not envisage a supreme judiciary which is capable of encroaching upon the domain of the legislature and the executive. The independency of judiciary has another unique feature known as unified system. The judicial power is not distributed between the Centre and the States, even though the Constitution uses the nomenclature of Union Judiciary and State Judiciary, to describe the Supreme Court and the High Courts. Chapter IV of Part V of the Constitution deals with the Union Judiciary in Articles 124-127. Similarly Chapter V of Part VI of the Constitution deals with the High Courts in the States in Articles 214-233. Chapter VI of Part VI the Constitution deals with the Subordinate Courts in Articles 233-237. Thus the entire judicial provisions are contained in the Constitution and they have uniform application throughout the country.

In the India, the constitution contemplates a three-tier system of administration of justice, two-tiers in the States namely the subordinate judiciary, the lowest in the hierarchy, and the High Courts, the middle, and at the top Supreme court. The judgments of the Supreme Court are binding on all other courts in the territory of India i.e. the High Court and the Subordinate courts.[6].

The Supreme Court and the High Courts of India play a very important role in protecting the fundamental rights of the citizens as well as the person by exercising the writ jurisdiction under Art. 32 and 226 respectively. Thus the Supreme Court is treated as the guardian of the fundamental rights under the Article 32 of the Constitution. The Supreme Court of India is denoted as the appellate Court in India and the final interpreter as to the validity of any law, constitutional provision or even a constitutional amendment.

Legal Framework of independency of judiciary - The Constitution of India provides the legal framework for the appointment of judges of Supreme Court, High Court and the Subordinate Court as under Article 124,217 and 233 respectively. As per the Article 124 Establishment and constitution of Supreme Court provides that there shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law prescribes a larger number, of not more than seven[7] other judges. Every Judge of the Supreme Court of India shall be appointed by the president by warranty under his hand and seal after consultation with such of the Judges of the Supreme Court and High courts in the states as the President may deem necessary for the purposes and shall hold office until he attains the age of sixty-five years. As per Article 217 Appointment and conditions of the office of a Judge of a High Court provides that every Judge of a High Court shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal after consultation with the Chief Justice of India, the Governor of the State , and, in the case of appointment of a Judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of the High Court, and shall hold office, in the case of an additional or acting Judge, as provided in Article 224, and in any other case, until he attains the age of sixty-two years. As per Art.233 Appointment of district judges provided that appointment of persons to be, and the posting and promotion of, district judges in any State shall be made by the Governor of the State in consultation with the High Court exercising jurisdiction in relation to such State. And also says that a person not already in the service of the Union or of the State shall only be eligible to be appointed a district judge if he has been for not less than seven years an advocate or a pleader and is recommended by the high court for appointment.

Conclusion - From the above analysis the independence of judiciary makes it clear that independency of judiciary is the hall mark of an independent republic which has adopted a constitution which is scared and superior to any one of three branches of government the legislature, executive and the judiciary. The accountability is the sinquonon feature of an independent judiciary. A question arises which method we should have to ensure judicial accountability. Judges of the higher judiciary are to be accountable to whom, is it to the legislature, or to the chief executive, the President of India, or the people of India. A retired Justice Mohamad

Dzaiddin Abdullah of Malasia make a important guidelines about Judges and Judicial Accountability "To be faithful to his oath is the test of his integrity as a Judge. Implicit in this is that he must resist any influence or temptation. Indeed independence is a vital component of a judicial accountability, since Judiciary which is not truly independent competent or possessed of integrity would not be able to give any account of itself. This Judicial accountability is an indispensable counter balance to the judicial independence, for an unaccountable judge would not be free to disregard the ends that independence is supposed to serve". The above statements the writers conclude that despite all the criticism the Indian judiciary of High qualities of head and heart except for few who cannot be identified.

References :-

1. The Committee sent its report on May, 1947. The text can be found on p.193 of the select Documents, the Framing of India's Constitution, Ed. B. Shiva Rao , Vol. IV
2. Constitutional Proposal of the Sapru Committee (Dec,1945).
3. Constituent Assembly Debate, Book-2, Vol. VII, at p.948.
4. Under Article 131 of the Constitution of India.
5. Now "thirty", vide the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1978, Sec.16 (11 of 2009).

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

Powers of Presiding Officer Under Xth Schedule of the Constitution

Mamta Goswami*

Abstract - The Anti-Defection law was passed in 1985 through 52nd Amendment to the constitution, which added the X[th] Schedule to the Indian Constitution. The main intent of the law was to combat "The evil of political defections". There are several issues in relation to the working of this law which need to be discussed. Does the law, while deterring defections, also lead to suppression of healthy intra-party debate and dissent? Does it restrict representatives from voicing the concern of their voters in opposition to the official party position? Should the decision on defections be judged by the speaker who is usually a member of the ruling party or coalition, or should it be decided by an external neutral body such as the election commission?

In this note, we summarise the main features of law relating to Anti-Defection in Xth Schedule which was added by 52nd amendment and the powers of Presiding Officer for defection.

Introduction - Entire Range of living beings naturally desires rule of law, and this desire is more immense and intense in human beings, because they have the capacity to differentiate and make rational judgments. Since the evolution of civilization era, various thinkers have been working to legitimize the concept of law. Legal thinkers and philosophers evolved many doctrines and system through which effective rule in society can be exercised and maintained. Efforts of Philosophers, right from Greek Era till date, finally zeroed in the concept of democracy. In the furtherance of democratic governance, a parallel concept of freedom developed simultaneously, which encompasses a variety of rights and liberties of which the freedom of speech and expression is comparatively significant. In democratic system of governance, the elected representative voice the aspiration and sentiments of the electorate in the legislature. For pursuing this legal, social and moral duty, the legislature are conferred upon certain rights, privilages and immunities. So that they may express fearlessly the sentiments of those, whom they represent. And when elected representative of one political party joined some other party for power and greed. It is called "defection" and the decision on question as to disqualification on ground of defection is referred for the presiding officer of the concerned house and his decision shall be final.

Litrature Survey - It was these circumstances that the government led by late Shri Rajeev Gandhi brought Fifty second constitutional Amendment bill. The fifty second Amendment Act 1985 added Xth Schedule to the constitution enacting the provisions in relation to disqualification on grounds of defection. It is in this schedule where the registered political parties found their significance and role to play in the formation of government and the conduct of business in a house of legislature.

Paragraph 2 of X[th] Schedule provides the grounds disqualification of a member of a house belonging to any political party.

1. If he has voluntarily given up his membership of such political party; or
2. If he votes or abstains from voting in such house contrary to any direction issued by his political party or any person authorized on this behalf.
3. An elected member who independently party after such election he would be deemed to have defected.
4. A nominated member of a house should be disqualified of being a member if he joins any political party.

Power of Presiding Officer Under X[th] Schedule of Indian Constitution - Article 105 and 194 gives privilages and immunities to members of legislature, but these privilages and freedom found new challenges and assault after the 52nd Amendment of the Indian Constitution in the form of Xth Schedule. The cumulative effect of Xth Schedule is that the speaker or the chairman has been made monarch of house.

According to paragraph 6 of Xth Schedule , If any question arises as to whether a member of a house has become subject to disqualification Under Xth Schedule, the question shall be referred for the decision of the chairman or, as the case may be, the speaker of such house (Presiding Officer) and his decision shall be final. But the decision of presiding officer is under judicial review, because judicial review is the basic structure of constitution. And the paragraph 7 of Xth Schedule declared unconstitutional in the case of Kihoto Hollohan Vs. Zachilhu and Others (1992)

*Research Scholar (Law) Mewar University, Chittorgarh (Rajasthan) INDIA

1 S.C.C. 309; because Para-7 bar the jurisdiction of courts.

Now the question arises whether paragraph 6 of Xth Schedule granting finality to the decision of the speaker/ chairman. The answer is yes, and courts come only after decision has been taken. The another question arises whether a speaker can review his own decision of disqualification a member under Xth Schedule. The answer is not, it helds in case of Kashinath Jalmi Vs. the speaker AIR 1993 S.C.

The Political defection Examples in India - In India, the political defection startd as soon as the general election of 1952 were over. Certain examples are very glaring in Indian Political Scenario, e.g. Ch. Charan Singh defected with his band of followers from congress party to pull down the government of the Chief Minister C.B. Gupta. The Central Government of Shri Morarji Desai, Shri Charan Singh , Shri V.P. Singh, Shri Chandra Shekhar had been the victims of defection.

Objectives of the study :

1. To study the scope of the power and functions of the speaker or chairman of the house in the light of the concept of the parliamentary democracy.
2. To study the system of Indian Political party and their inner democracies.
3. To study and proposes the way to maintain a balance between parliamentary privilages, llegislatures rights and anti-defection provisions.

Research Methodology - The present study in largely based on the practical working of Indian houses of legislature in the light of Anti-defection law. The study is basically a non-doctrinal study that is why it is not possible to adhere to any strict methodology of the research. An in-depth study of various text books, periodicals and journals and judicial decisions of different courts shall be undertaken which help in drawing conclusion.

References :-

1. V.N. Shukla : The constitution of India.
2. D.D. Basu : The constitutional Law of India.
3. J.N. Pandey : The constitutional Law of India.
4. Sir Thomas Erskine May : Parliamentary Practice 18th Edn.
5. Bare Act : Indian Constitution
6. The Hindu Articles.
7. Jethro K. Leberman : How the government breaks the law.
8. Constitutional Assembly debates.
9. Bulletin II of the Lok Sabha on different dates PRS.

****

The progressive and regressive constitutional arrangements in Nepali : A study in the light of constitution of India

Dr. Vijay Srivastava * Mr. Jivesh Jha **

Abstract - The Constitution of Nepal 2015 is the seventh Constitutional document before Nepal dwellers. The document has been under troubled water since its inception for not recognizing the concerns of Madheshi and Tharu population. Nevertheless, the charter has welcomes provisions as well. It succeeds to provide fair corpus of fundamental rights to people that include right to free legal aid, right to information, right to privacy or right to social security. Also, the Constitution obliges the state to ensure one-third representation of women in legislative spectrum. Still, the charter is loaded with regressive provisions on number of occasions, like citizenship, constituency delineation or judicial appointments.
Keywords - Nepali Constitution, citizenship, preamble, judiciary, women representation, Madhesh.

Introduction - A painful decade of bloody Maoist insurgency and then years of failed attempts later, Nepal on September 20, 2015 got a new Constitutional document, a development that led to celebrations in Hills but 135 days long protests in southern plains that claimed more than 40 lives. There was celebration in Kathmandu and the Hill regions by lighting lamps and firing crackers. But, the Madheshis and Tharus of Nepal, the half of the national population, observed a Black Day to mourn the deaths of their community memberswho had been gunned down by security forces while protesting against certain discriminatory provisions of the Constitution.

The drafting process (2008 to 2015) kicked off in 2008 with the formation of Constituent Assembly (CA)-I, the unicameral body of 601-member, after its election. In fact, the demand for a new Constitution was raised by Maoist rebels, who waged a decade long civil war which ended with 2006 comprehensive peace accord. Two new political forces emerged—the Maoists with 229 seats in the CA and the Madhesi parties with 80 seats[1]. The Maoists became the largest party in CA, leading to the abolition of 240-year old monarchy.But because of wrangles, the Assembly failed to give birth to new Constitution.

The political parties came in the CA with a two-year mandate to draw up a new statute for Federal Democratic Republic of Nepal. After 2010, the CA extended its life four times till, finally, the top court intervened while deciding a writ petition and the CA dissolved on May 28, 2012 without producing any outcome. The differences within the CA led to political deadlock.

The fresh CA-II was constituted for a four-year term following its poll held a year later on November 19, 2013. The Maoists were down to 81 seats and the Madhesis to 40; the older parties, the Nepali Congress (NC) and the Communist Party of Nepal-Unified Marxist Leninist (UML), emerged stronger with 201 and 175 seats, respectively[2]. The Assembly gave a deadline to promulgate the Constitution by January 2015 but it again failed to meet the deadline. After much back and forth, Nepal got its new Constitution on September 20, 2015 by approval of over 85 per cent of the 601 members of the CA, but without the stamp of approval of at least 60 Madheshi and Indigenous representatives.

"The Constitution was crafted completely by a handful of leaders of the big three parties—the Nepali Congress, the CPN-UML and the CPN-MC behind closed doors in collusion with some political elites and technocrats and was presented in the CA for a ritual and forced endorsement.[3]" Importantly, "The Interim Constitution of 2007 had introduced a wide range of provisions for progressive transformation, including federalism, citizenship, inclusion and secularism. The drafters of the Constitution watered down all of these provisions in 2015. As a result, the country stood psychologically divided on September 20, 2015, Nepal's Constitution Promulgation Day.[4]"

In contrast, "New Delhi was one of the major backers of the process over the past decade, but it believes the new constitution is not broad-based and is concerned that it could spur violence which could spill over into its own territory[5]".

However, apart from a few discriminatory provisions, there are provisions that have received much praise. This paper seeks to undertake a study onsome of the progressive and regressive provisions enshrined in the new Constitution

*Assistant Professor, Uttaranchal University, Dehradun (Uttaranchal) INDIA
** Student of LL.M (Constitutional Law) at Uttaranchal University, Dehradun (Uttaranchal) INDIA

of Nepal.

Progressive provisions:

I. Language - Everybody loves mother tongue and wants to see the language given by the mother flourish. Once you know the language, it is easier for you to make good relationship with people, and establish contact through effective communication. In order to flourish the languages given by mother, its been provisioned that all the languages given by mother shall be national language (Article 6). However, the position is different in India.

The Gujarat High Court, while hearing a PIL, had in 2010 observed that Hindi was not the country's national language. The PIL had sought direction of the Centre and the State to make it mandatory for print details of good to be in Hindi. But the court had observed, "Normally, in India, majority of the people have accepted Hindi as a national language and many people speak Hindi and write in Devanagari script but there is nothing on record to suggest that any provision has been made or order issued declaring Hindi as a national language of the country[6]."

Importantly, clause 1 of Article 343 states that "The official language of the Union shall be Hindi in Devnagari script." Not only this, "the Articles 350A and 350B were inserted by the Constitution (7thAmendment) Act 1956 to ensure the protection of linguistic minorities.[7]" To secure these goals, the charter recognizes 22 languages in the Eighth Schedule that includes Nepali, Bengali, Maithili, and Hindi.

The Constitution of Nepal (under article 7) envisages that in addition to Nepali language, a province can select one or more national languages to be used in the state if that is spoken by a majority of the people there. More or less, similar arrangement has been envisaged under Article 345 of the Constitution of India.

II. Right to privacy - Although right to privacy is yet to be expressly mentioned in Indian constitution, the same right has been enlisted under fundamental rights in Nepal. However, right to privacy is protected as an intrinsic part of 'right to life and personal liberty' clause in India.

III. Progressive Fundamental Rights - The provisions relating to fundamental rights have been embodies under Part-III (Article 16-48) of the Constitution. There are ample provisions which are progressive in nature. For instance, right to information, right to communication, right to justice, rights of victim of crime, right against torture, right to free legal aid, right to privacy, right to property, right to clean environment, right to language and culture, rights of women, rights of Dalits, rights of senior citizens, right to social security, and among others are the provisions which appear progressive for a number of reasons.

IV. One-third representation of women in legislative spectrum - Having gone through the constitution, one can firmly and proudly say, Nepal's new constitution is progressive, and institutes several positive elements for the upliftment of women in the country.

The cornerstones are set by two arrangements in particular. First, ensuring rights of women as a fundamental right (FR) through legislation from the very initial stage under Article 38; second, the constitutional provision setting aside 33% representation of women in Nepal's legislature is a major breakthrough.

Nepal sets aside 33% of parliamentary seats for women through legislation as envisaged under Article 84(8). Similarly, A-86 (2) (a) ensures that three berths shall be given in 59-member national assembly, where eights members to be elected from each province.

Regressive provisions:

I. Citizenship - The persons who have solemnized marital bonding with a non-Nepali national remained deeply offended after sensing that their husband or wife or their issues would be beneath their civil and political status.

The Article 11 (3) provides that in order to acquire citizenship by descent, it must be proved that both 'father and mother' are Nepali citizens. However, on non-fulfillment of this clause, meaning where a child whose 'father or mother' is a Nepali, a person is entitled to get citizenship by naturalization.

Moreover, if his/her father is found to be a foreigner, the citizenship to such a person shall be converted to naturalized citizenship, Article 11(5). Similarly, if a foreign woman married to a Nepali citizen so wishes, she may acquire naturalized citizenship of Nepal, says Article 11(6). Interestingly, Article 11 (7) of the Constitution allows a child born to a Nepali woman, whose father is a foreigner, to acquire naturalized citizenship. However, the authority to issue such citizenship lies with the District Administration Office under Ministry of Home Affairs which has not issued even a single citizenship certificate of that type till date[8].

Ironically, if a brother marries a foreigner, the children born from them would get citizenship without any hassles while the same treatment is not there with a sister marrying a foreigner. Isn't the provision generating gender bigotry?[9]

Despite this, Article 289 bars a naturalized citizen to hold any vital government post. In this way, Constitution itself makes clear that the naturalized citizens are inferior to descent citizens. Unfortunately, this type of derogatory provision was not embodied in Interim Constitution-2007, and other five repealed Constitutions.

II. Electoral Constituency - The parameters for delineation of electoral constituency became the other most disputed provision.

Nepali parliament made provision of taking 'geography and population' both into account while delineating the electoral constituencies. Conversely, 'population' is only the basis for constituency delimitation in India.

In this context, it bears relevance to acknowledge the reading of former Indian envoy to Nepal Rt. His Excellency Rakesh Sood who observes: "The 2015 Constitution reduces the weightage given to proportional representation. Terai (Madhesh) constitutes 51 per cent of the population but according to calculations, it would currently get only 62 out of a total of 165 seats under the first past the post

system, instead of 83, as per its population. The notion of fixing electoral constituencies after taking into account 'population and geography' was intended to ensure that the sparsely populated trans-Himalayan districts are not left out of the democratic process[10]."

III. Judiciary - Independent and impartial judiciary is one of the hallmarks of the democratic government. To give the executive, cabinet or legislature an unfettered discretion in deciding the philosophy of judges is to make judiciary obedient to government.

It has been provisioned that judicial appointment shall be made on the recommendation of Judicial Council (JC), where the Law Minister shares a berth. The constitution of JC has been provided under Article 153. It envisages that the Chief Justice of Nepal will be ex-officio Chairman of the Council, whereas the Federal Law Minister, senior-most judge of the SC, a legal expert nominated by the President on the recommendation of the Prime Minister, and a senior advocate appointed by the President on the recommendation of Nepal Bar Council will be acting as members.

In India, the appointment, removal and transfer of judges of higher courts and subordinate courts have been placed entirely in the hand of judiciary, leaving no room for the influence of executive and legislature.

IV. Preamble - The second paragraph of preamble accepted the glorification of various movements in past such as people's war and the armed conflicts. Surprisingly, it fails to acknowledge the Madhesh movements that led to the inclusion of federalism. "The Constitution has undermined three big Madhesh movements that took place in the country since 2007…. Had the Madhesh movement been recognized in the Constitution, it could have increased the acceptance of the Constitution in Madhesh.[11]"

Conclusion - It may be noted that 2015 charter is the seventh Constitution before the Nepali people. The Government of Nepal Act, 1948 was the first Constitutional document in Nepal. Since 1950, the Himalayan state has experimented with various constitutions. It has had two Interim Constitutions (1951 and 2007) and three formal Constitutions (1959, 1962 and 1990).

Many thoughtful Nepalis believed that the new Constitution would succeed to end all discriminations lying in the country.But the charter, at the time of its promulgation, failed to strike a balance between dominant views (i.e., the agendas of major parties) and minority views (i.e., agendas of Madheshi parties). As a result, agitating Madheshi parties refused to give their stamp of approval to the new document, arguing that the "statute is not a broad-based document" and it would "politically marginalize the Madheshi people." The constitution failed to address the concerns of the Madheshi population in terms of federalism, electoral representation and citizenship, forcing the community to hold a five-month long blockade along the Indo-Nepal frontier. More than 40 people lost their lives while protesting against new statute. This Constitution has been under trouble from its inception as there was a sense of triumphalism in Hills but dissidence in Madhesh.

A just Constitution cannot be discriminatory. So, there is dire need of an amendment in it, not only for incorporating the aspirations of Madhesh, half sky of Nepal, but also for ensuring its wider ownership and everlasting progress.

References :-

1. Rakesh Sood, "Himalayan Upgrade" *The Hindu* , Nov. 21, 2017,
2. Ibid
3. Dipendra Jha, *EDERAL NEPAL: Trials and Tribulations 11 (*Aakar Books, New Delhi,2018)
4. Dipendra Jha, *FEDERAL NEPAL: Trials and Tribulations 05 (*Aakar Books, New Delhi,2018)
5. http://www.bbc.com/news/world-asia-india-34313280
6. https://www.huffingtonpost.in/2017/06/24/for-the-last-time-hindi-is-not-the-national-language-of-india_a_22952944/ accessed on March 3, 2018
7. MP Jain, *Indian Constitutional Law* 796 (Lexis Nexis ,Gurgaon 2016)
8. http://english.lokaantar.com/articles/view-constitutions-citizenship-provisions-south-asian-states/ (accessed on March 3, 2018)
9. Ibid
10. http://www.thehindu.com/opinion/lead/overcoming-the-stasis-in-nepal/article7823808.ece
11. Dipendra Jha, *FEDERAL NEPAL: Trials and Tribulations 85 (*Aakar Books, New Delhi,2018)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

Rights Of Women In India-With Special Reference To Workplace

Dr. Vijay Srivastava* Divya Priyadarshni**

Introduction - In India women are not safe. Heinous and heart tormenting crimes are being perpetrated over them every minute. Be it a girl at school, a sister at home or a strong corporate lady in the magnetic world of money; they are all vulnerable. Exploitation of women in India is not synonymous touneducation. It is also in no way related to their exposure. If that would be true women could have felt safer at home. Educated women working with some fine corporate firm would have never complained of harassment by their counter male colleagues. But that's not the prevailent scenario. Women is an epitome of shakti yet she is drained out of all her modesty and dignity by perpetrating such evil crimes over her. A women discharges so many important functions as daughter,sister then stepping into someone's life as wife,giving birth to a child as mother and at workplace as someone's employee. It is well settled principle and not an issue of debate that physically she is a weaker sex. For the very first time this remark was made by the supreme court of United States of America in a case. Biologically also she is somewhere at loss,discharging so many functions she is somewhere standing on an unequal pedestal compared to male counterpart. So it is somewhere responsibility of the society to make her feel safer at her workplace. A society cannot progress by crushing one gender of the society or by making her feel weaker section of the society. If society is a vehicle women is an important wheel. She has all the rights to be felt safe and protected at her workplace. There are several constitutional provision in India safeguarding women rights. For instance, we have Article 14, Article 15 and Article 21. Article 14, thogh,is general in nature yet it is there to safeguard equality before law.under article 15 there is specifically use of word 'sex' in regard to prohibiting discrimination. Also Article 21 is there to safeguard life and liberty of working women in India. Also there is Convention On Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women,Maternity Benefit Convention. After this we have a leading case of Vishaka v. State of Rajasthan (1997)6S.C.C. 323. They all help us to know how women's rights in India are safeguarded at their workplace. We will address these key issues in paragraph one after the other.

But before we delve deep into intricacies of protections and safeguards it is important to understand that what actually amounts to sexual harassment.

What Amounts To Sexual Harassment - In India there is no adequate and sufficient laws protecting women from sexual harassment at their workplace. Expecting such enactment in a male dominated society would definitely take considerable amount of time and we need to show some more patience. Prior to Vishaka case,we had no legislation in this regard. After Vishaka we have 'The Sexual Harassment of Women At Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 which is a legislative Act in India that seeks to protect women from sexual harassment at their place of work. It was passed by the Lok Sabha(the lower house of the Indian Parliament) on 3 september 2012.

However, in Vishaka's case a definition of sexual harassment was suggested by J.S. Verma J. . He opined that for this purpose sexual harassment includes such unwelcome sexually determined behaviour (whether directly or by implication) as -

(a) Physical contact and advances
(b) A demand or request for sexual favours
(c) Sexually coloured remarks
(d) Showing pornography
(e) Any other unwelcome physical,verbal or non verbal conduct of sexual nature.

When we analyse the above definition we get to know that sexual harassment is something which is in the form of descrimination on the basis of sex which is projected through unwelcome sexual advances,request for sexual favours and other verbal or physical conduct, specifically when submission to or rejection of such a conduct by the female employee was capable of bein used for affecting the employment of the female employee and her work performance gets interfered unreasonably and the effect of such an act is that an adverse and hostile work environment is created against her.

Sexual Harassment Of Working Women And Indian Constitution - The Constitution of India talks of gender equality. Sexual harassment of any women at her place of employment is in totality against the principle of gender equality. It is also violation of the fundamental rights in

*Asst. Proffesor (Law) Uttaranchan University, Dehradun (Uttarakhand) INDIA
**LLM -2nd Semester (Law) Uttaranchan University, Dehradun (Uttarakhand) INDIA

particular Article 14, Article 15 and Article 21 of the Indian Constitution which enshrines principles of equality before law and prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex and place of birth. Article 21 is also said to be violated by sexual harassment of women at workplace as it deals with the protection of life and personal liberty.

Any International conventionnot inconsistent with the Fundamental Rights and in harmony with its spiritmust be read into these provisions to enlarge the meaning and content thereof to promote the object of the constitutional guarantee. This is implicit in Article 51(c). Article 73 also is relevant in this regard.

Next in reference we have -

C.E.D.A.W (Convention On Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) 1979

We can say that this convention is a step towards protecting the honour and dignity of the women. The message is loud and clear that 'she' has all right to feel safe and protected at her workplace. Allow her to work. Don't crush her. Allow her to grow and multiply.

The Government of India has ratified the CEDAW'S resolution on 25th june, 1953 with some reservation which are no material in the present context.

The relevant provisions in the context are:

Article 11 - State parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights in particular:

(a) The right to work as an inalienable right of all human beings;

(f) The right to protection of health and to safety in working conditions, including the safeguardingof the function of reproduction.

Article 24 - State parties undertake to adopt all necessary measures at the national level aimed at achieving the full realization of the rights recognized in the present convention.

The general recommendations of the CEDAW in the matter relating to sexual harassment at workplace in respect of Article 11 are:

Violence and equality in employment - Equality in employment can be seriously empaired when women are subjected to gender specific violence, such as sexual harassment at the workplace.

Sexual harassment includes such unwelcome sexually determined behaviour as physical contacts and advances,sexually coloured remarks, showing pornography and sexual demands, whether by words or actions. Such conduct can be humiliating and may constitute a health and safety problem; it is discriminatory when the women has reasonable grounds to believe that the objection would disadvantage her in connection with the employment, including recruiting or promotion, or when it creates a hostile working environment whats needed to be provided for is effective complaints, procedures and remedies, including compensation.

States in their reports must include information about sexual harassment, And what measures have been adopted to protect women from sexual harassment and other forms of violence and coercion in the workplace.

Vishaka V. State Of Rajasthan (1997)6 S.C.C. 323 - Then came the leading judgement of Vishaka v. State of Rajasthan in which a writ petition was filed for the enforcement of Fundamental Rights of working women under Articles 14 , 15, 21 of the Indian Constitution. The present petition was brought as a class action by certain social activists and NGO. The progress made at each hearing in Vishaka, culminated in the formulation of guidelines to which Union ofIndia gave its consent through the Solicitor General, indicating that these should be the guidelines and norms declared by the Supreme Court to govern the behaviour of employees and all others at workplace to curb this social evil.

At present we have legislation in the form of Sexual Harassment of Women At Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

Conclusion - Thus in nutshell we can conclude that any action or gesture whether direct or implied which aims at or has tendency to outrage the modesty of a female employee constitutes sexual harassment. Even an attempt to do so is sufficient to constitute sexual harassment. Article 32 of the Indian Constitution which empowers the Supreme court for the enforcement of the Fundamental Rights and the executive power of the union both have to meet in order to address the issue of sexual harassment of working women and to turn their fundamental rights into reality. Governance of the society by rule of law mandates this requirement as a logical commitment of the constitutional scheme. The meaning and content of the Fundamental Rights guaranteed in the Constitution of India are of sufficient amplitude to encompass all the facets of gender equality which includes prevention of sexual harassment or abuse.

References :-

1. Dr.Tripathi, Law relative to women And children, central Law Publication
2. Mamta Raw, Law Relative to women And children, Eastern Book Company Third edition
3. It's Constitution of india act, 1950
4. Convention on the elimination of all forms of discrimination against women

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

Academic Stress In Relation To Study Habit Among Higher Secondary Students

Dr. Harendra Kumar * Tabassum **

Abstract - Stress is on of the most important concept in contemporary Psychology. "stress[1] refers only to a stress with significant negative consequences, or distress in the terminology advocated by Hans Selye, stress and anxiety are every where, now a days stress is not confined to adults alone but also affect children and adolescents. Stress due to education is called academic stress. The purpose of the present study was to find out relationship between academic stress and study habit among higher secondary students. For this purpose 400 students from UP. Board schools and C.B.S.E. board schools were randomly selected from Meerut District of UP. state of India. The students were selected all the basis of their scores on academic stress scale and study habit inventory. The collected data were statistically treated by using pearson's correlation formula and 'X^2 - Test. The result clearly revealed that academic stress of higher secondary students of UP. Board and C.B.S.E. Board was negatively correlated with study habit.
Key Words - stress, academic stress, anxiety, adolescence, study habit.

Introduction - The present century has been rightly referred as "The century of fear" & "The age of anxiety & stress " by thinkers like Albert camiess and W.H.Auden stress has become a common symptom of the present day man, therefore attracted the attention of teacher, social workers, physician, parents, psychologist and a variety of other people. Today's man is facing the danger of war, economic, ecological imbalance and environmental pollution, a fast changing social structure that is becoming more complex day by day. All these problems make man increasingly stressful prone.

Stress is one of the most important concept in contemporary psychology. The concept of stress enjoys central position in the theories of human behaviour and personality and is regarded as basic conditions of human existence by many thinkers. Now a days stress is not confined to adults alone but also affect children and adolescents. There are so many conditions in educational field, Which are stressful to child like negative consequences of failures, future life, too much home work etc. academic stress increase day by day because of various situations and condition in schools and colleges and influence so many factors like anxiety, time management, leisure satisfaction, achievement motivation, study habit etc. Stress due to education is called academic stress, academic stress is becoming increasingly common and widespread among adolescents(Garcia, 1986 and Gupta 1989), Shakespeare's description of the child "creeping like snails unwilling to school" reminds us of the stresses which exist in the system and neurotoxin limitation at educational places according to Raina (1983) physical effects of academic stress are pale faces, sunken cheeks and disheveled hour, psychological effects are still more serious in natures, they includes anxiety, aggression apathy bored depression, fatigue, nervousness and loneliness etc. (Patri, 1995)

Study Habit William James (1890) defined habit in terms of dependable and stable way of behaving. Jones (1952) defined 'habit' as a customary pattern of "" behaviour either cognitive or emotional response predictable according to the condition that operates at the time of learning.

Crow and Crow (1903) state study habit can be interpreted as a planned programme of subject matter mastery its chief purposes are (i) to acquire knowledge and habits. Which will be useful in new situation, interpreting ideals and general enrichment of life (ii) to perfect skill, and (iii) to develop attitude?

According to Percival and Ellington (1984) study habits to the methods or techniques of effective learning which in turn involve a set of study skills as organization of time, effective use of time, reading skills, essay writing, report writing skill, note taking skill. Christenson et. al. (1991) defined study habits as behaviour, which relate to organization of time space, or resources for learning.

In earlier Balli (1998) was also examined the effect of parents help on relieving academic stress of 6th grade children and was discovered that when parents help their children then they do better in school. Hoover-Dempsey et al (2001) conducted a study on effect of academic stress on parents and familiar. They found that academic stress has a positive effect on parents and familiar by allowing them to show an interest in their children's academic

*Associate Professor (Teacher's Training) Digamber Jain College, Baraut, Distt. Baghpat(U.P.) INDIA
**Lecturer Pt. DDUMC, Meerut (U.P.) INDIA

progress. John L. Paul (2007) did an expert counselling for academic stress the purpose of the study was to examine the extent to which college students academic coping style and motivation mediate showed they find that there is relationship between college students academic stress and course grade was influence by problem focused coping and motivation but not emotion focused. Larry G, Richards (2005) conducted a study on class performance from study habit and also compared Asian Verses non- Asian students and concluded that particular the gender difference on the surface study scale was evident there woman who attended every class and completed their homework regularly. Vijayalakshmi (2006) analysed the study habit and achievement in physics of students of class XII for the present study random sampling method was used. Five colleges have been selected from Shimoga district He concluded that (1) Sex has no impact upon the various categories of study habits (2) Type of college has no impact upon the various study habit (3) There is a significant difference between the achievement of boys and girls in physics (4) There is significant difference in the government and private college students achievement in physics (5) There is a significant relationship between the study habit and achievement in physics.

Objectives Of The Study-

1. To find out the relationship between academic stress and study habit among higher secondary students of U.P. board
2. To find out the relationship between academic stress and study habit among higher secondary students of CBSE board

Hypothesis - The following null hypothesis are advanced to be tested in the present study

Hypothesis - 1. "There is no significant relationship between academic stress and study habit among higher secondary students of U.P. board"

The above hypothesis was further classified into two sub hypothesis on the basis of sex differences i.e. girls and boys.

Sub- Hypothesis - 1.1. "There is no significant relationship between academic stress and study habit among U.P board girls".

Sub- Hypothesis- 1.2 "There is no significant relationship between academic stress and study habit among U.P board boys"

Hypothesis - 2 "There in no significant relationship between academic stress and study habit among higher secondary students of CBSE board".

Above hypothesis was further classified into tow sub-hypothesis on the basis of sex i.e. girls and boys.

Sub- Hypothesis - 2.1 "There is no significant relationship between academic stress and study habit among CBSE board girls".

Sub- Hypothesis - 2.2 "There is no significant relationship between academic stress and study habit among CBSE board boys".

Method - Survey method was used by researcher to identify the correlation between academic stress and study habit.

Sampling- It was not feasible to include all the students of senior secondary school in the study for data collection. It was considered inevitably to draw a representative sample. So the researcher took 20-20 students of higher secondary classes level from each school randomly, which they were selected earlier for the purposed study (10 schools of U.P board and 10 schools of CBSE board), for selecting these schools from Meerut district random sampling technique was used.

Tools Used - For measuring academic stress and study habit of the student the following tools were used.

a) Academic stress scale by Akbar Husain & Tabassum Rashid.

b) Study Habit inventory by Dr.S. K.Jain

Procedure Of Data Collection - After selecting the sample the researcher made personal contact to the principal of the sample institution. After getting the permission of principal, Researcher requested to the class teacher of the respective section. Firstly, Researcher gave two scale i.e. academic stress scale and study habit inventory, time has to be given for these two scales was 8.A.Mto 10AM.

Results Discussion - The data were analysed by using product moment correlation to examine the relationship between academic stress and study habit. The summary presented in Table-1

Table-1 Showing correlation coefficient value between academic stress and study habit

Group	Number	r- Value
U.P. Board	200	r = - 0.668**
Girls	100	r = -0. 6499**
Boys	100	r = - 0. 6806**
CBSE board	200	= - 0.905**
Girls	100	= - 0.504**
Boys	100	= - 0.669**

**Significant at .01 Level of Confidence

Table – 2.1 (See in the last page)

Table – 2.2 (See in the last page)

According to table-1 the correlation value between academic stress and study habit among U.P board students obtained is (r - 0.668), which is significant at .01 level on the basis of this velum the null hypothesis has been rejected. Further the finding was supported by 'x^2 – test method also (Table 2.1 and Table 2.2)

Correlation value was negatively significant shows academic stress of U.P board students was negatively correlated with study habit among U.P board students on the other hand the correlation value among CBSE board students (r = - 0.905) is more negative than U.P board students showing that students of CBSE board have more academic stress than U.P board students as well as CBSE board students shows slightly bad study habit than U.P board students It was argued that academic stress is high in CBSE board students and higher secondary students have very disturbing study habit this is because of study

medium in CBSE board schools is English which is responsible for high stressful condition, Indian houses have generally regional language environment so students always feel problem to understand syllabi and they do not take interest in teaching learning process another reason for stressful condition are competitive environment and students in CBSE board schools come from different socio-economic status so students compare themselves with the others.

On the other hand correlation value between academic stress and study habit among U.P board girls and boys are (r = - 0.6499 and r = - 0. 6806) respectively, these are significant at .01 level, showing that academic stress is negatively correlated with study habit in both girls and boys but value of coefficient was more negative in U.P board girls than boy, on the basis of this discussion the Sub-hypothesis 1.1 & 1.2 has been rejected. There are so many reasons for stressful condition for girls, girls have no proper time table for their study, they spend most of their time in playing indoor and outdoor game, cooking, painting, stitching etc. they always feel burden regarding their study and household works, and parents also do not cooperate girls for their study, environment of schools and home also effects the study habit of the students.

Correlation coefficient value among CBSE board girls and boys are (r = - 0.504, 0 - 669) respectively which is significant at .01 level on the basis of this finding Sub-hypothesis 2.1 and 2.2 has been rejected but correlation value is more negative in girls so CBSE board girls, have more academic stress and poor study habit then boys there are many reasons for this.

Medium is English, maximum time expend in internet, household works, illiterate parents, poor economic condition etc.

These finding are supported by some previous research finding. Love M. Nriy. (2002) conducted a study on study habit of Nigerian university students and concluded that Nigerian students read mostly for purpose of passing examination and they do not seem to pursue their studies correctly and thoroughly, Jeffery R.Stowell in (2003) did work on use and abuse of academic examination in stress research. He concluded that use subjective and objective measures of test difficulty with in subject design, cooper & *Nye (1994) conducted a study on home work and students study disabilities and concluded that appropriate home work can improve study habit of students.

Findings -

1. It has been found to be that academic stress of higher secondary students of U.P. board was negatively correlated with study habit the value of correlation coefficient obtained was (r=-0.668).

1.1.2 It has been also found to be that academic stress of U.P. board girls and boys was negatively correlated with study habit, but value of correlation coefficient obtained was slightly negative (r=-0.6499) among girls then U.P. board boys (r=-0.6806).

2. It has been found to be that academic stress of higher secondary students of CBSE board students was also negatively correlated with study habit (r=-0.905).

2.1.2 It has been also found to be that academic stress of CBSE board girls and boys was negatively correlated with study habit, but value of correlation coefficient obtained was more negative (r=-0.504) among girls then CBSE board boys (r=-0.669).

- Academic stress have negative relationship with study habit among higher secondary students, it means if academic stress increases than study habit become poor or vice-versa. But correlation between academic stress and study habit among CBSE board (r = 0.905) students is slightly lower than correlation among U.P. board (r = 0.668) students showing that the students of CBSE board have more academic stress than U.P. board students as well as CBSE board students shows slightly bad study habit.
- Academic stress also have negative relationship with study habit in both girls and boys of U.P. board, it means if academic stress increases that study habit become poor or vice-versa, but correlation coefficient value between above two variables among girls is slightly lower (r=-0.6499) than U.P. board boys (r=-0.6806) showing that U.P. board girls have more academic stress and poor study habit then boys.
- Academic stress also have negative relationship with study habit in both girls and boys of CBSE board but correlation coefficient value among girls is slightly lower (r=-0.504) then boys (r=-0.669), showing that CBSE board girls also have more academic stress and poor study habit then that of boys.
- Academic stress is negatively correlated with study habit among all the students of U.P. Board and CBSE Board it means if academic stress increases than study habit become poor or vice-versa showing that results is significant (x^2=219.796) for all the students of higher secondary level.

Implications of the Research Findings - The Research has implication for classroom environment and performance as well as school activities and school climate. The present study with its variables, as discussed in the study, has revealed that academic stress of the student is an important factor which influence to the study habit and achievement motivation etc. The findings of present research work shows that “Academic stress of higher secondary students is negatively correlated with study habit of student” if students show poor study habit it means they are in highly stressful condition. So the teacher could use the knowledge provided by present study to help the students to decrease their academic stress by solving difficulties of students and encourage them to improve their study habit. As well as the study is useful for school organizer also school management can improve school environment for students by making good time table, proper discipline etc. which is responsible for academic stress and study habit of children

parents also can take help from the research findings to improve study habits and remove academic stress of their children. So it is necessary for parents they should provide a positive atmosphere at home, they should have positive attitudes towards their children to solve their problems by giving a proper guideline. The knowledge generated by the study may make the parents of growing children aware of the right approaches. So that they may help their teenagers to develop their potential up to the maximum level.

References :-

1. Bosch, J.A., RingC.et.al. (2004) Academic examination and immunity; academic stress or examination stress? Psychosom Med (2004).
2. Carter V.Good, Dictionery of Education. New York : McGraw Hill P.42 1959.
3. Georgiady, Nicholas, P Romano, Louis, G (1994), Focus on study habit at home for middle school students. A guide for parents and students to increase learning at home ISBN- 0- 918449-05-7, 15P.
4. Nandita Tanime, S. (2007) study habit and attitude towards studies in relation to academic achievement in geography of secondary school students. Educational psychological linguistic. Journal association of India.
5. Nicholas, P. Georgiady (1994) Study habit at home American journal of Educational psychology. Vol.20, 152-159.
6. Paschat, R.A, Weinstein, T & Walberg H,J.(1984) The effects of home work stress on achievement of students A quantitative synthesis, Journal of Educational research, 78, 97.
7. Peer Influence on the study habit of secondary school adolescents in ogun state nigeria Requet Article (2007).
8. Ramana Sood. Dalivinder Kumar (2007) study habit and academic achievement of first generation learners and subsequent generation learners. MERI Journal of Educational psychology. Vol. II Oct, 2007 Number 2.

Table – 2.1

Percentage Distributed of Respondents According to Academic Stress and Study Habits among 200 Students of U.P. Board

Academic Stress	Study Habits			Total
	Poor	Moderate	Good	
Low	7.2% (3)	59.5% (25)	33.3% (14)	21.0%(42)
Moderate	6.6% (8)	80.2% (97)	13.2% (16)	60.5% (121)
High	70.3% (26)	29.7% (11)	0.0% (0)	18.5% (32)
Total	18.5% (37)	66.5% (133)	15.0% (30)	100% (200)

at 0.01 significance level, chi square value = 92.21927 , contingency value = 0.56197

Table – 2.2

Percentage Distributed of Respondents According to Academic Stress and Study Habits among 200 Students of C.B.S.E. Board

Academic Stress	Study Habits			Total
	Poor	Moderate	Good	
Low 0%	(0)	40.7% (11)	59.3% (16)	13.5%(27)
Moderate	1.6% (2)	83.6% (107)	14.8% (19)	64% (128)
High	64.4% (29)	31.1% (14)	4.4% (2)	22.5% (45)
Total	15.5% (31)	66% (132)	18.5% (37)	100% (200)

at 0.01 significance level, chi square value = 136.66440 , contingency value = 0.63713

****

महिला शिक्षिकाओं का सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन

डॉ. कौशिक वी. पाण्डया* डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव** समन्दर सिंह***

प्रस्तावना - सूचना का अधिकर लोकतंत्र की आत्मा है। इसे प्रशासन में उत्तारदायित्व, जवाबदेहिता, संवेदनशीलता विकसित करने का महत्तवपूर्ण साधन माना जाता है। 21वीं सदी में जबकि प्रशासन का दायरा सीमित हो रहा है और प्रशासक की भूमिका कम होने लगी है प्रशासन से ग्राहकोन्मुखता, बाजारोन्मुखता की मांग की जाने लगी है। पारदर्शिता इस ग्राहकोन्मुख प्रशासन को एक महत्तवपूर्ण गुण है। सूचना का अधिकार प्रशासन में इसी पारदर्शिता का विकसित करता है।

वैसे तो खुलापन की बातें सभ्यता की शुरूआत से ही की जाती है लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से जनता में सरकारी क्रियाकलापों को जानने की इच्छा पैदा हूई है उसी में सूचना के अधिकार आन्दोलन की कहानी निहित है। विषय की नवीनता सबसे प्रमुख कारण था जिसने मुझे इस विषय को चुनने के सूचना का अधिकर केवल प्रशासन में उत्तारदायित्व और जवाबदेहिता विकसित ही नहीं करता है बल्कि लोकतंत्र की सफलता के लिये आवश्यक जन सहभागिता के लिये आवश्यक है। भारतीय लोकतंत्र का अब तक अनुभव यह बतलाता है कि अच्छी नीतियाँ, योजनायें होन के बावजूद भी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसलिये असफल रहे क्योंकि प्रशासन को पर्याप्त जन सहयोग नहीं मिला। जनता को विभिन्न नीतीयों, योजनाओं इत्यादि जानकारी देकर उनसे सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। सूचित जनता व केवल अपने अधिकारों के प्रति सचेत होती है बल्कि उनमें परिणामों के बारे में सोचने की क्षमता विकसित की जा सकती है। जन सहभागिता के द्वारा नीतियों के निर्माण और उसके क्रियान्वयन में जन सहयोग प्राप्त किया जा सकता है और ऐसा केवल सूचना के अधिकार के माध्यम से किया जा सकता है।

इन सबका जवाब संविधान में सूचना के अधिकार के अन्तर्गत दिया जाता है। वास्तव में सूचना का अर्थ है लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध किसी भी रूप में रखी गई ऐसी सामग्री जो तैयार की गई, उपयोग में लाई गई और सुरक्षित रखी गई है।

धारा 2 (च) - 'सूचना' से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, ऑकड़ों सम्बन्धी सामग्री और किसी निजी निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुँच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है।

इस तरह देश का प्रत्येक नागरिक आयकर, बिक्री व उत्पाद कर के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। तब वह भी आशा रखता है या अपेक्षा रखता है कि उसके द्वारा दिये जाने वाला धन किस प्रकार खर्च होता है दूसरी ओर उस व्यक्ति को सरकारी कामकाजों की जानकारी लेना भी आवश्यक है जिससे कि पारदर्शिता स्पष्ट हो। यह सूचना का अधिकार आधुनिक एवं प्रगतिशील समाज के लिए बहुत आवश्यक है। सही समय पर प्राप्त सूचना से भ्रष्टाचार, कुप्रबन्धन एवं सरकारी तंत्र के दुरूपयोग पर अंकुश लगाया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार - सूचना का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है। सूचना के अधिकार के लिए अंग्रेजी शब्द है : राइट टू इन्फॉर्मेशन संक्षिप्त शब्द R.T.I.(आर. टी. आई.)

धारा - 2 (अ) सूचना का अधिकार किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रण धीन ऐसी सूचनाएं हासिल करने के अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है -

- निर्माण कार्यो, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण।
- नोट्स, उद्दरण, दस्तावेजों/अभिलेखों की प्रमाणित नकल लेना।
- सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना
- फ्लापी, टेप और वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके में या प्रिंट आउट के जरिए सूचनाएँ कम्प्यूटर या अन्य किसी युक्ति में स्टोर की जाती है।

अतः इसमें उन सभी रूपों का समावेश है, जिनमें सरकारी संगठनों द्वारा सूचनाएँ रखी जाती है और सूचनाओं का लगभग प्रत्येक रूप इस परिभाषा में सम्मिलित है तथा साथ ही निजी निकाय से सम्बन्धित दस्तावेज भी शामिल है।

सूचना के अधिकार को अधिक प्रभावी सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 में सम्मिलित करने हेतु कुछ परिवर्तन सुझाए तथा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा प्रस्तावित सुझाओं को जाँचने के बाद सूचना की स्वतत्रंता अधिनियम 2002 को निरस्त करने तथा दूसरा विधान अधिनियमित करने का निश्चय किया तथा भारत संविधान अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत सूचना के अधिकार को संसद में पारित करने पर बल दिया तथा सूचना का अधिकार बिल 2005, 11 मई, 2005 को लोकसभा तथा 12 मई, 2005 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 15 जून 2005 को इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।

यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। पंचायत से लेकर संसद तक लगभग सभी संस्थाए इसके दायरे में आती है।

*फेकल्टी (एज्यूकेशन) पेसिफिक यूनिवर्सिटी, उदयपुर (राज.)भारत
**डीन फेकल्टी (एज्यूकेशन) महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी, भरतपुर (राज.)भारत
***शोधार्थी, पेसिफिक यूनिवर्सिटी, उदयपुर (राज.)भारत

यद्यपि केन्द्रिय सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर, 2005 में लागू होने से पहले ही 9 राज्य सरकारें उक्त तिथि से पहले ही राज्य कानून के रूप में उसे पारित किये हुई थी। इसमें 1) जम्मू कश्मीर 2) तमिलनाडू (1997) 3) गोवा (1994) 4) राजस्थान (2000) 5) कर्नाटक (2002 में प्रभावी) 6) दिल्ली (2001) 7) असम (2001) 8) मध्यप्रदेश (2003) 9) महाराष्ट्र (2001)

सूचना के अधिकार में सूचना लोक प्राधिकारी से 30 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाती है तथा थर्ड पार्टी या प्राईवेट कम्पनी के मामले में 45 दिन और जीवन सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों में 48 घण्टों में सूचना मिल जाती है। ऐसा ना होने पर सम्बन्धित विभाग के अधिकारी पर एक केस के लिए 250/– रूपये प्रतिदिन के हिसाब से 25000/– रूपये तक जुर्माना हो सकता है। इस सूचना के लिए फीस 10 रूपये है। जो फीस कैश बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर के रूप में जमा करा सकते हैं।

कुछ खुफिया और सुरक्षा एजेन्सियों को इस एक्ट के बाहर रखा है। परन्तु इन्हें भी मानवाधिकार उल्लंघन और भ्रष्टाचार के मामलों में सूचना प्रदान करनी होती है।

समस्या कथन – किसी भी अनुसंधान कार्य को करने के लिए समस्या कथन अपना महत्तवपूर्ण स्थान रखता है। समस्या कथन को अर्थ शोध प्रबन्ध के शीर्षक का उल्लेख मात्र नहीं है। समस्या का कथन एक सुस्पष्ट लक्ष्य पर दृष्टि केन्द्रित करने का प्रयास करता है।

सी. वी. गुड और डी. ई. स्केट्स के अनुसार – 'नियमानुसार किसी शोध प्रबन्ध का शीर्षक उस अनुसंधान कार्य के विषय या उस अनुसंधान में प्रस्तुत किये गये विशिष्ट क्षेत्र को केवल नाम प्रदान करता है।'

समस्या का कथान एक प्रस्ताव रूप में प्राय: एक प्रश्नवाचक वाक्य में किया जा सकता है या फिर एक घोषणा के रूप में भी किया जा सकता है। प्रश्न विधि का लाभ यह है कि इनके द्वारा विषय के कथन में स्पष्टता आ जाती है या उस विषय पर ध्यान केन्द्रित हो जाता है। परन्तु घोषणात्मक कथान की विधि अधिक प्रचलित है।

स्टीफन एम. बोरे करलिंगर ने एक समस्या के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए निम्नलिखित चार कसौटियों का वर्णन किया है–

1. समस्या कथन स्पष्ट व सुनिश्चित होना चाहिए–
2. समस्या कथान इस प्रकार किया जाना चाहिये जिससे पूर्वगामी कारकों तथा पश्चात् गामी कारकों से सम्बन्धित विशिष्ट घटना तक स्वरूप सुनिश्चित रूप से स्पष्ट हो सके।
3. समस्या से सम्बन्धित चर तथा आश्रित चर पूर्णत: स्पष्ट होने चाहिए।
4. समस्या का कथन ऐसा होना चाहिए जिससे सम्बन्धित चरों का अध्ययन अनुभाविक अधार पर किया जा सकें।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अनुसंधानकर्त्ता ने वर्तमान समस्या का कथन इस 'ग्रामीण व शहरी महिला शिक्षिकाओं का सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन' प्रकार किया है।

समस्या के उद्देश्य – शोध का उद्देश्य शोध कार्य का प्रकाश स्तम्भ है जो उसे राह से विचलित होने से बचाकर सही मार्ग दिखाता है। जीवन के सभी कार्य सौद्देश्य होते हैं, उद्देश्य के बिना जीवन दिशाहीन हो जाता है।

बी. डी. भाटिया के अनुसार – उद्देश्यों का निर्धारण ही कार्य को गति को प्रदान करता है। उद्देश्यों की स्पष्टता अनुसंधान को सरल एवं सफल बना देती है।

उद्देश्यों का महत्व – 'उद्देश्यविहीन कार्य उस रेत के समान है जो समय के क्षेत्र के साथ–साथ धूमिल हो जाता है।'

किसी भी कार्य की सफलता उसके निर्धारित किए गये उद्देश्यों पर निर्भर करती है। उद्देश्यों की स्पष्टता अनुसंधान को सरल एवं सहज बना देती है। उद्धेश्य किसी भी कार्य का अन्तिम बिन्दु है, जहां तक पहुंचने का सतर्क प्रयास किया जाता है।

बेसले एण्ड बोर्न्सिकी के अनुसार 'उद्देश्य का कार्य रास्ता बताना है। आदर्शों को इंगित करना है तथा चुनौती प्रस्तुत करना है।'

बेसले एवं बोर्न्सिकी के उपरोक्त कथन के आधार पर समस्या के महत्ता को स्पष्ट किया जा सकता है। सामान्यत: प्रत्येक स्वस्थ मस्तिष्क में किसी कार्य को पूर्ण करने के उद्धेश्य होते हैं और वास्तव में देखा जाए तो उद्धेश्य ही कार्य को जन्म देने वाला होता है।

उद्देश्यों के अभाव में अध्यापक उस नाविक के समान है जो अपनी मंजिल नहीं जानता और विद्यार्थी पतवारविहिन नौका की तरह जो लहरों के थपेड़ों को खाकर किसी भी तट पर जा लगेगी। किसी भी कार्य की सफलता उसके निर्धारित किये गये उद्धेश्य पर बहुत निर्भर करती है। उद्देश्यों व लक्ष्यों का निर्धारण ही कार्य को गति प्रदान करता है। उद्धेश्य विहीन कार्य उस रेत के समान है जो समय के साथ–साथ धूमिल होता जाता है।

जीवन का प्रत्येक क्षण किसी न किसी उद्देश्य से संलग्न है ताकि शोधकार्य को दिशा मिल सके, जो निम्नलिखित है –

1. सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण व शहरी महिलाओं का सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन हेतु परिकल्पनाएँ – शोध कार्य के व्यापक क्षेत्र को न्यून करने के लिए परिकल्पना का निर्माण आवश्यक है ताकि अध्ययन का स्वरूप स्पष्ट, सूक्ष्म और गहन हो सके। यदि परिकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता है तो अनेक अनावश्यक व व्यर्थ आँकड़े एकत्रित होने की सम्भावना रहती है।

लुण्डबर्ग के अनुसार – 'एक प्राकल्पना एक सामाजिक या कार्यवाहक सामान्यीकरण होना है जिसकी सत्यता का परीक्षण करना अभी शेष रहता है।'

बेस्टर एवं इन्टरनेशनल डिक्शनरी ऑफ दी इंग्लिश लेंग्वेज के अनुसार – 'एक परिकल्पना एक विचार दिशा का सिद्धान्त होता है जो कि सम्भवत: बिना किसी विश्वास के मान ली जाती है जिससे कि उससे तार्किक परिणाम निकाले जा सके तथा ज्ञात किये जाने वाले तथ्यों की सहायता से हम विचार की सभ्यता की जाँच की जा सके।'

इस तरह परिकल्पना एक ऐसी पूर्व विचार अमूर्तिकरण निष्कर्ष या सामान्यीकरण होता है जो कि अध्ययनकर्ता अपने अनुसंधान की समस्या के बारे में बना लेता है जो कि अध्ययनकर्त्ता अपने अनुसंधान की समस्या के बारे में बना लेता है व फिर उसकी जाँच करने के लिए आवश्यक तथ्यों को एकत्रित करता है। यदि अनुसंधान में खोज व प्राप्त किए गए तथ्यों से सार्थकता सिद्ध हो जाती है तो यह विचार जिसे परिकल्पना कहा जाता है, एक सिद्धान्त का रूप धारण कर लेता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन की निम्न परिकल्पना निर्धारित की गई है –

1. ग्रामीण व शहरी महिला शिक्षिकाओ का सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अध्ययन में प्रयुक्त आदर्श – आधुनिक समय में समस्या का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत सम्पर्क करना असम्भव है।

किसी भी मनोवैज्ञानिक तथ्य या मानव व्यवहार के सत्यापन के लिए पूर्णतया समग्र अध्ययन सम्भव नहीं होता है, अत: अधिकांशत: समस्याओं में न्यादर्श द्वारा कार्य किया गया है।

न्यादर्श –

पी. वी. यंग के अनुसार 'प्रतिदर्श एम समष्टि का वह अंग होता है, जिसमें अपनी समष्टि की समस्त विशेषताओं का स्पष्ट प्रतिबिम्ब रहता है। वह अपने समस्त समूह का लघुचित्र होता है।'

न्यादर्श के आधार पर पूरी जनसंख्या के विषय में कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। न्यादर्श से निकाले गए निष्कर्ष सम्पूर्ण जनसंख्या पर भी उसी प्रकार लागू होते है। हालांकि न्यादर्श व सम्पूर्ण जनसंख्या के निष्कर्षो में थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकती है जो कि एक निश्चित सीमा तक नगण्य मानी जाती है।

बोगार्ड्स के अनुसार – 'एक प्रतिदर्श अपने समस्त समूह का लघ्ङ्ग चित्र होता है।'

सारणी

'ग्रामीण व शहरी महिला शिक्षिकाओं का सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता को अध्ययन'

क्र.सं.	श्रेणी	उप श्रेणी	कुल महिला
1.	शिक्षिका	ग्रामीण	50
2.		शहरी	50
	कुल		100

अध्ययन में अपनायी गई विधि – किसी अनुसंधान की सफलता उसकी योजना एवं क्रियाविधि पर आधारित है। शिक्षा, मनोविज्ञान तथा अनुसंधान की अनेक विधियाँ प्रयुक्त की जाती है। प्रत्येक अनुसंधानकर्त्ता अधिक विश्वसनीय एवं ठोस परिणामों की प्राप्ति हेतु कतिपय विधियों का चयन करता है। अनुसंधान कार्य की सफलता में अपनाई गई अध्ययन विधि का अत्यधिक एवं आधारभूत महत्व है। शिक्षा क्षेत्र के विस्तृत रूप में उत्पन्न होती हुई अनेक समस्याओं का अध्ययन करने हेतु अनुसंधान की अनेक विधियां प्रयोग में लायी जाती है। शोधकर्त्ता ने प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है।

प्रस्तुत अध्ययन में **सर्वेक्षण विधि** के अन्तर्गत **मानकीय सर्वेक्षण विधि** को अपनाया गया है जो कि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वांछनीय आँकड़ों के संकलन हेतु उपयुक्त है।

शोध अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण – अध्ययन के लिए दत्ता संकलन हेतु प्रयुक्त होने वाले साधनों को उपकरण कहते है। अनुसंधान की सफलता उपयुक्त उचित उपकरण के चयन पर निर्भर करती है। एक अनुसंधान में केवल एक ही उपकरण का प्रयोग न होकर कई उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। यह जरूरी नहीं है कि जो उपरकण एक क्षेत्र में प्रभावी होता है वह अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावी सिद्ध है।

जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार – 'एक बढ़ई के सन्दूक में औजारों की भाँति प्रत्येक अनुसंधान उपकरण विशिष्ट उद्देश्यों की पूति हेतु किसी विशिष्ट परिस्थितियों में प्रयुक्त होता है।'

अनुसंधानकर्त्ता ने स्वंय के द्वारा निर्मित स्वनिर्मित परीक्षण **'सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता मापनी'** को उपकरण के रूप में काम में लिया है।

उपकरण चयन के आधान – अनुसंधानकर्त्ता को उपकरणों का चुनाव करते समय निम्न बातों का ध्यान में रखना चाहिए –

1. उपकरण ऐसा होना चाहिए जिसके प्रयोग से चयन की गयी समस्या का समुचित समाधान हो सके।
2. उपकरण दी गई समस्या के प्रति विभिन्न अवसरों पर दी गई मानकीकृत स्थितियों के अन्तर्गत समान परिणाम प्रदान करने वाला हो।
3. उपकरण समय व धन की दृष्टि से मितव्ययी हो।
4. उपकरण समस्या के प्रति वैध उत्तार उपलब्ध कराने वाले हो।
5. जहाँ तक सम्भव हो उपकरण प्रमाणीकृत हो उससे एक अच्छे उपकरण के सभी गुणों का समावेश होता है।

शोध अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी – किसी भी शोध में सर्वप्रथम उस शोध से संबंधित आंकड़ों का संकलन किया जाता है किन्तु मात्र दत्त संकलन से शोध कार्य पूर्ण नहीं होता अपितु दत्ता संकलन को वैज्ञानिक रूप देने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है।

परीक्षणों को प्रशासित करने के पश्चात् प्राप्त आंकड़ों को सांख्यिकीय रूप में प्रस्तुत करने हेतु सर्वप्रथम गणना के लिए मध्यमान, प्रमाप–विचलन व टी–परीक्षण ज्ञात किया।

शोध अध्ययन में निम्नपरिकल्पना जांची गई है –

परिकल्पना – ग्रामीण व शहरी महिला शिक्षिकाओं का सूचना के अधिकार के प्रति सार्थक अन्तर नहीं है। प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि ग्रामीण शिक्षिकाओं का सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता का मध्यमान 2.86 है जबकि शहरी शिक्षिकाओं का सूचना के अधिकार के प्रति जागरुकता का मध्यमान 65.10 है।

जिसमें टी. मूल्य 2.32 आया है जो कि .05 विश्वास स्तर (टी. मूल्य 1.96) पर सार्थक है अर्थात् ग्रामीण व शहरी महिला शिक्षिकाओं का सूचना के अधिकार के प्रति सार्थक अन्तर पाया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. अग्रवाल, जे. सी. – 'एज्युकेशन रिसर्च'
2. एलिस, आर. एस. (1951) – 'एज्युकेशन साइकोलॉजी'
3. बेस्ट, जॉन, डब्ल्यू (1957) – 'मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं विनोद मूल्यांकन', पुस्तक मन्दिर, आगरा
4. अग्रवाल रामनारायण एवं अस्थाना विपिन – 'आधुनिक मनोविज्ञान शिक्षण एवं मापन', आगरा
5. बुच. एम. बी. (1975) – 'दी सर्वे ऑफ रिसर्च ऑफ एज्युकेशन'
6. बुच. एम. बी. (1984) – 'ए सर्वे ऑफ रिसर्च इन एज्युकेशन', तृतीय संस्करण
7. डॉ. कपिल एच. के. – 'अनुसंधान परिचय'
8. गेरेट, हेनरी ई. – 'शिक्षा एवं मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग', नई दिल्ली, कल्याण पब्लिशंस।
9. गेरट, एन. डी. – 'शिक्षा एवं मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग'
10. मंगल, एस. के. (1985) – 'शिक्षा मनोविज्ञान', दिल्ली, राजकमल प्रकाशन
11. शर्मा, आर. ए. (1990) – 'शिक्षा अनुसंधान', मेरठ इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस
12. सचदेवा, अनिल (2011) – 'सूचना के अधिकार', 2005
13. सिंधवीं रनिश (2012) – 'सूचना के अधिकार अधिनियम', 2005
14. राय, के. बी. (2009) – 'सूचना के अधिकार'
15. जैन, राजीव कुमार (2009) – 'भारतीय लालफीताशाही पर सूचना अधिकार अधिनियम का असर', नई दिल्ली: भारतीय लोकप्रशासन

संस्थान

16. कटारिया, एस. के. (2009) – 'भारतीय प्रशासन के पुन: निर्माण में सूचना के अधिकार अधिनियम की भूमिका', नई दिल्ली: भारतीय लोकप्रशासन पत्र
17. Singh, Shiv Sahay & Government must spend more money for awareness about RTIAct. www. indian express.com
18. Singh, Shalini (2012) & Genesis of Right to Information Act in, Research Journal of Social Science.
19. www.righttoinformation.org
20. rti.gov.in
21. www.rtiindia.org

****

विद्यालयों में सांस्कृतिक व साहित्यिक आयोजनों में विद्यार्थियों की रूचि

सुषमा सिंह चुण्डावत*

प्रस्तावना – भारत एक सांस्कृतिक विभिन्नताओं से परिपूर्ण देश है। विश्व में भारत की पहचान सिर्फ एक राजनीतिक देश के रूप में ही नहीं है बल्कि सांस्कृतिक स्वरूप में भी यह महत्वपूर्ण स्थान हासिल किये हुए हैं।

ऊर्जा से भरी पीढ़ी यदि सकारात्मक व उच्च मानवीय मूल्यों से युक्त हो तो देश को नई बुलंदियों पर ले जाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मानवीय मूल्यों के निर्माण में विद्यार्थी जीवन एक उपयुक्त काल है। बालकों को देश का भविष्य कहा जाता है अत: यह आवश्यक हो जाता है कि उन्हें ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए जिससे उनमें मानवीय मूल्य जाग्रत हो। इसलिए विद्यालयों में पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त समय समय पर विभिन्न सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है।

प्राय: देखा गया है कि निजी विद्यालय राजकीय विद्यालयों की अपेक्षा अधिक उमंग व उत्साहपूर्वक सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियाँ आयोजित करते हैं। राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थी निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की तुलना में इन गतिविधियों में कम सहभागी होते हैं। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में तो फिर भी विद्यार्थीगण इन गतिविधियों में रूचि लेते हैं तथा इनमें भाग लेना पसन्द करते हैं परन्तु उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी विभिन्न सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों के आयोजन के अवसर पर या तो विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं या फिर अनमने ढंग से उनमें भाग लेते हैं।

यही सोचकर शोधार्थी ने राजकीय व निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों के आयोजनों की वर्तमान स्थिति एवं विद्यार्थियों की रूचि का अध्ययन विषय का चयन किया है। इस शोध कार्य द्वारा राजकीय व निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों के आयोजनों की वर्तमान स्थिति का पता चल सकेगा तथा विद्यार्थियों की इन गतिविधियों के प्रति रूचि का पर्याप्त ज्ञान हो सकेगा।

शोध समस्या के उद्देश्य –

- उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों के आयोजन की वर्तमान स्थिति के प्रति समग्र न्यादर्श विद्यार्थियों के अभिमत का पता लगाना।
- उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों के आयोजन की वर्तमान स्थिति के प्रति राजकीय एवं निजी विद्यालय के विद्यार्थियों के अभिमत का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों के आयोजन में समग्र न्यादर्श विद्यार्थियों की रूचि का अध्ययन करना।
- उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों के आयोजन में राजकीय एवं निजी विद्यालय के विद्यार्थियों की रूचि का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध समस्या की परिकल्पना

- उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों के आयोजन की वर्तमान स्थिति के प्रति राजकीय एवं निजी विद्यालय के विद्यार्थियों के अभिमत में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
- उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों के आयोजन में राजकीय एवं निजी विद्यालय के विद्यार्थियों की रूचि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

समस्या का परिसीमन –

- यह समस्या उदयपुर जिले की गिर्वा तहसील के उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक ही सीमित रखी गयी।
- उदयपुर की गिर्वा तहसील के केवल 2 सरकारी व 2 निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों को ही अध्ययन हेतु चुना गया।

शोध विधि – प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया।

जनसंख्या व न्यादर्श – यह अध्ययन 120 विद्यार्थियों तक सीमित रखा गया, जिसमें 60 छात्र व 60 छात्राएं सम्मिलित है।

उपकरण – इस शोध कार्य हेतु शोधार्थी द्वारा 2 स्वनिर्मित उपकरणों का प्रयोग में किया गया :-

- सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों के आयोजनों की वर्तमान स्थिति संबंधित प्रमापनी।
- सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों के आयोजनों के प्रति विद्यार्थियों की रूचि सम्बन्धित प्रमापनी।

प्रयुक्त सांख्यिकी प्रविधियाँ – इस शोध हेतु निम्नलिखित सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग किया गया –

1. मध्यमान
2. मानक विचलन
3. टी-टेस्ट

सारणी संख्या - 1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

सारणी संख्या - 2 (देखे आगे पृष्ठ पर)

निष्कर्ष –

- समग्र न्यादर्श विद्यार्थियों के अनुसार उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नृत्य-गायन, निबंध, कहानी लेखन प्रतियोगिता, वाद विवाद आदि अनेक प्रकार की सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियाँ पूरे जोश व उल्लासपूर्ण तरीके से आयोजित की जाती है।
- समग्र न्यादर्श विद्यार्थियों के अनुसार उच्च माध्यमिक विद्यालय में

*59, राज वैभव हाउस, गोकुल विलेज, तीतरड़ी, उदयपुर (राज.) भारत

प्रधानाचार्य सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों के आयोजन के दौरान विद्यार्थियों हेतु प्रेरक, मार्गदर्शक व सहयोगी के रूप में दिखाई देते हैं, ताकि विद्यार्थी भी उत्साहित होकर अधिक से अधिक संख्या में भाग ले सके।

- उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों के आयोजन की वर्तमान स्थिति के प्रति राजकीय विद्यालय केविद्यार्थियों की अपेक्षा निजी विद्यालय के विद्यार्थियों का अभिमत अधिक सकारात्मक पाया गया।
- छात्रों की अपेक्षा छात्राएँ विद्यालय में होने वाली सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों के आयोजन में रूचि अधिक लेती है।
- समग्र न्यादर्श विद्यार्थियों का मानना है विद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों से अन्तर्निहित कौशलों का विकास होता है, जिससे समग्र विद्यार्थियों में आत्मबल व प्रोत्साहन स्तर में वृद्धि होती है।

सुझाव –

- समयाभाव के कारण प्रस्तुत शोध में शोधकत्री ने 120 उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में लिया है इससे भी बड़ा न्यादर्श लेकर इसे और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाया जा सकता है।
- प्रस्तुत शोध उदयपुर शहर तक सीमित है भावी शोध के लिए राजस्थान के अन्य शहरों के विद्यार्थियों का चयन किया जा सकता है।
- प्रस्तुत शोध सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय के शिक्षकों एवं प्राचार्यो को लेकर भी किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Good & Hatt (1952) -`Method in Social Research', New York : McGraw Hill, page-33.
2. शर्मा, डॉ. आर.ए. (2011) – 'शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।'
3. शर्मा, राधेश्याम – 'पाठ्यसहगामी प्रवृतियों का महत्व', राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर अक्टूबर–2005।
4. सारस्वत, राकेश– 'माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाने वाली सृजनात्मक प्रतियोगिताएँ : एक परिचय', शिविरा पत्रिका, निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, राजस्थान, सितम्बर 2008।
5. Co-curricular Activities are On Integral Part of Curriculum which Provides Educational Activities to the Students - Education hp.org/ board/chapter-10
6. http://www.education-nic.in

सारणी संख्या – 1

क्र.सं.	क्षेत्र	मध्यमान		मानक विचलन		टी–मान	.05/.01स्तर पर सार्थकता
		राजकीय	निजी	राजकीय	निजी		
1.	वर्तमान स्थिति	35.95	42.90	3.66	4.11	3.75	.01 स्तर पर सार्थक अन्तर पाया गया

सारणी संख्या – 2

क्र.सं.	क्षेत्र	मध्यमान		मानक विचलन		टी–मान	.05/.01स्तर पर सार्थकता
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा		
1.	रूचि	35.95	42.90	3.52	3.99	4.48	.01 स्तर पर सार्थक अन्तर पाया गया

****

शिक्षक शिक्षा में मूल्यों का समावेश - पाठ्यक्रम

डॉ. सुनीता शर्मा *

प्रस्तावना - मानव जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व है। शिक्षा ही तो है जो मानव को यथार्थ रूप में मानव बनाती है। शिक्षा के बिना मनुष्य जीवन पशु तुल्य ही होता। मानव और पशु में यही अंतर है कि मानव शिक्षा के द्वारा ही अपने को उन्नति के शिखर पर ला सका है। मानव शिक्षा ग्रहण करके शिक्षा प्रचार प्रसार करता हैं किंतु पशु ऐसा नहीं कर सकते। मनुष्य जब से जन्म लेता है और जब तक जीता है कुछ न कुछ सीखता है और सीखाता है।

शरतीय शिक्षा स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से अपने विस्तार के मार्ग पर अति द्रुत गति से अग्रसर हो रही थी, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा के अनेक क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की माँग में उत्तारोत्तार भारी वृद्धि हुई। सम्भवत: इसीलिए हमारे देश की शिक्षा की पुनर्रचना में शिक्षक प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया था। उसकी कमियों और गुणात्मक उन्नति के उपायों से परिचय प्राप्त करने के लिए शिक्षा आयोगों की नियुक्ति की गई है, जिन्होंने इसे सफल एवं सार्थक बनाने के उद्देश्य से विविध कार्यक्रमों का समारम्भ किया गया है और इस प्रकार इसकी धारणा में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया गया है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश के शिक्षाशास्त्रियों एवं राजनीतियों ने शिक्षक प्रशिक्षण को एक नवीन रूप प्रदान करने हुए उसको व्यापक बनाया और इसको शिक्षक शिक्षा (Teacher Education) का नया आकार प्रदान किया।शिक्षक शिक्षा जीवन के समस्त क्षेत्रों को प्रभावित करती है, साथ ही बालकों के दैनिक जीवन से भी संबंधित है। अत: केवल कला शिक्षण का प्रषिक्षण, शिक्षक को अपने उत्तारदायित्वों का निर्वाह करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं कर सकता है।

शिक्षक शिक्षा का प्रारूप ऐसा होना चाहिये जो छात्रों, विद्यालय, समाज तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इस दृष्टि से शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम को जनतान्त्रिक मूल्यों, राष्ट्रीय एकता, धर्म निरपेक्ष समाज के निर्माण में सहायक होना चाहिये। अत: समाज की समस्याओं, राष्ट्र के आर्दषो को दृष्टि में रखकर पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार किया जाना चाहिये।राष्ट्रीय मूल्य व लक्ष्य बदलते रहते हैं, इसलिये पाठ्यक्रम का प्रारूप भी बदलते रहना चाहिये, जिससे राष्ट्रीय मूल्यों व लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके, तभी उसे सार्थक माना जायेगा। शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम को ज्ञान वृद्धि की गति की तीव्रता के अनुसार बदलना भी चाहिये, क्योंकि दस वर्ष में मानवीय ज्ञान दूना हो जाता है।

सेवारत शिक्षकों के लिये आवश्यक है कि उन्हें नवीन पाठ्यवस्तु तथा षिक्षण विधियों से अवगत कराया जाए। इसके लिये ऐसे कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाए, जिसमें सेवारत अध्यापक भी नवीन प्रवर्त्तानों से अवगत हो सकें। इसके लिये सतत् शिक्षा के कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाए।उच्च स्तर पर अन्य विषय के प्रवक्ताओं तथा विशेषज्ञों की भी सहायता लेनी चाहिये, जैसे मनोविज्ञान, दर्शन, सांख्यिकी आदि विषय की शिक्षा हेतु इस विषय के प्रवक्ताओं की सहायता लेनी चाहिये।

शिक्षा केवल शिक्षक प्रषिक्षण की प्रक्रिया मात्र न होकर अध्ययन का क्षेत्र भी है। कोठारी आयोग ने इसे एक विषय के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया है, क्योंकि इसके विकास का वृहद् क्षेत्र है। शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नये पाठ्यक्रमों को विकसित करना चाहिये। शिक्षक शिक्षा में शिक्षण सिद्धान्त का अनुशासन की दृष्टि से विशेष महत्व है व इसे शिक्षण शास्त्र भी कहते हैं।

शिक्षण अभ्यास अथवा छात्र षिक्षण के लिये मेडिकल कक्षाओं की तरह इन्टर्नशिप की भी व्यवस्था की जानी चाहिये। छात्र-शिक्षक को विद्यालय में रहकर सभी प्रकार के कार्यो में भाग लेना चाहिये तथा उन्हें कक्षा-शिक्षक का पूरा उत्तारदायित्व देना चाहिये।शिक्षक ही विद्यालय में सीखने के लिये वातावरण में रोमांच उत्साह और सृजन का रंग भरते है। विद्यालयी संस्कृति में शिक्षक की भूमिका के निर्वहन के लिये शिक्षकों को तैयार करने में शिक्षक शिक्षा की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। अत: जरूरी है कि शिक्षकों की तैयारी भी गुणवत्तापूर्ण हो। शिक्षकों की शिक्षा एक सतत् प्रक्रिया है और इसके सेवा पूर्व और सेवाकालीन अंशों को अलग नहीं किया जा सकता। जिसके अंतर्गत शिक्षकों को शिक्षा दी जाती है।किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम की सफलता या असफलता उस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाले शिक्षकों पर निर्भर करती है। शिक्षकों के आचार विचार, आस्थायें, मान्यतायें, सामाजिक पृष्ठभूमि एवं शैक्षिक योग्यता आदि पाठ्यक्रम को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। शिक्षक,शिक्षा प्रक्रिया की महत्वपूर्ण धूरी है। अत: शिक्षक से जुड़ा प्रत्येक पक्ष इस प्रक्रिया को प्रभावित करता है। उदाहरणार्थ-अधिकांश शिक्षक समाज के मध्यम एवं उच्च वर्ग से आते हैं, अत: वे केवल ऐसे ही अधिगम अनुभव ही कक्षा में प्रस्तुत करते हैं जो केवल उसी वर्ग के बालकों के लिए उपयुक्त होते हैं। साथ ही शिक्षकों का आयुवर्ग भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। युवा एवं प्रौढ़ शिक्षकों की सोच एवं अनुभव में पर्याप्त अन्तर होता है। पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव दो प्रमुख रूपों में कार्य करता है -

1. वैयक्तिक रूप में,
2. संगठित शक्ति के रूप में।

प्रत्येक शिक्षक कुछ नैतिक मूल्यों में आस्था रखता है तथा जाने-अनजाने वह उनका शिक्षण भी करता रहता है। इसीलिए कहावत भी प्रचलित है कि प्रत्येक शिक्षक अनिवार्य रूप से धर्म का शिक्षक होता है। यहाँ पर धर्म का तात्पर्य सामान्य नैतिक आचरण से है। पाठ्यक्रम शिक्षक के लिये अपने

*व्याख्याता, प्रशांति कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, उज्जैन (म.प्र.) भारत

विचारों को बालकों तक पहुंचाने का माध्यम होता है। वह प्राय: पाठ्यक्रम की अन्तर्वस्तु का उपयोग अपने विश्वास, दृष्टिकोण एवं मान्यताओं को विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए करता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष ढंग से शिक्षक व्यक्तिगत रूप में पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है।

वर्तमान समय में शिक्षक संगठन शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। अन्य व्यावसायिक वर्गो के समान ही शिक्षक वर्ग के संगठन भी कार्य करने लगे हैं जो उनकी आर्थिक एवं सेवा संबंधी मांगों को पूरा करवाने के साथ साथ कुछ सीमा तक पाठ्यक्रम को भी प्रभावित करते हैं। ऐसा ही देखने में आया है कि शिक्षक संगठनों के अलग-अलग गुटों का संबंध अलग-अलग विचार धाराओं वाले राजनीतिक दलों के साथ होता है।वे अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार पाठ्यक्रम पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरणार्थ, ब्रिटेन की सरकार पाठ्यक्रम के बारे में कोई भी निर्णय लेने से पहले वहाँ के शक्तिशाली शिक्षक संघ एन.यू.टी. (नेशनल यूनियन ऑफ टीचर्स) से अवश्यक परामर्श करती है। अपने देश भारत में भी शिक्षक संगठनों का प्रभाव क्षेत्र उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर 'ऑल इण्डिया सेकण्डरी टीचर्स एसोसिएशन', 'ऑल इण्डिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन' आदि तथा राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय शिक्षक संगठन पाठ्यक्रम विकास कार्य को प्रभावित करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में तो पाठ्यक्रम विकास का अधिकांश कार्य वहाँ का प्रभावशाली एवं संपन्न शैक्षिक संगठन 'नेशनल एजूकेशन एसोसिएशन' अपने पाठ्यक्रम विभाग के माध्यम से कर रहा है। इस प्रकार संगठित शक्ति के रूप में शिक्षक वर्ग पाठ्यक्रम विकास में एक समूह के रूप में कार्य करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Empowering Women Economically Through Traditional Crafts

Dr. Sabra Qureshi*

Introduction - Traditional embroidery has always been a form of self-expression for women. It mirrors their lives; reflects their hidden desires and aspirations and expresses the cultural traditions and religious beliefs of the society to which they belong. Embroidery, the art of working raised design in threads of silk, cotton, gold or silver upon the surface of woven cloth with the help of a needle, has been known in India from very early times.

India had attracted migrations from pre historic times and people came with their customs and traditions, which were absorbed and formed the rich cultural traditions of the country. The starkness of the desert, the arid, colorless landscape is balanced by the brilliant range of colors found in the textile of Rajasthan. By way of relief to the monotony of dull tones visible in the landscapes the people of the region have a deep seated need for color, which vented in the vibrancy of their clothes, animal trapping and house decoration. The color and vibrancy of Rajasthan extends into its embroidery as well. A wealth of stitchery, motif and design is spread across the state, each region and community practicing its own style.

Present women embroider their own garments, those of their children and family members as also clothes for the household cattle - the camel, the bullock and the horse which are often decorated with beautifully embroidered cloths.

Objectives -

1. Planning, research, study and identification of regions for visits.
2. Travel to identify villages, towns and cities. Study the techniques of embroidery currently in practice and bring back samples as well as photographs.
3. Documentation of existing traditional embroideries.
4. To assist communities in achieving economic self-sufficiency, through facilitating innovation within tradition to transform traditional art into contemporary products.
5. To organize exhibitions and to develop sale outlets for the work of art.

Methodology - The detailed information about embroidery of Western Rajasthan in respect to the technique, base colour, design, pattern, colour combination was obtained through survey and relevant data's were collected with personal interaction with craft women of Western Rajasthan at work places, homes and villages. Further information about marketing techniques, self help groups, and government and non government assistance was obtained.

Locale of the Study - The study was conducted in the districts of Western Rajasthan i.e. Jaisalmer, Jodhpur, Barmer, Bikaner, and Pail. The total comprised of 650 women of Western Rajasthan.

Sample and its Selection - Sample was randomly selected from Western Rajasthan 650 (women) and 50-factory owner were interviewed. Interview cum questionnaire method was selected for collecting the data because a large number of respondents were illiterate.

Result And Discussion - In the view of the objectives of the study the findings of the study have been presented in this paper in the form of data interpretation of results and their discussion. Evaluation and probing into the cultural depth is very difficult. As an essential part of the survey personal interviews were conducted to identify the various aspects of Traditional Embroideries and its present status in Western Rajasthan. Rajasthan is a large state; the population is very sparse in rural area. These areas were the main targets for the survey. Role of women, and determining the ways to use embroidery as a tool for their economic empowerment were studied.

Table- I (See in the last page)

Table- C (See in the last page)

Shows the income generated through embroidery. 42.8 % of women earn between 500 – 1000 rupees, 40 % of women earn between1001 – 1500 rupees, 13 % earn between 1501 – 2000 rupees and only 4.2% of women earn more than 2000 rupees per month.

Table – 2 (See in the last page)

Embroidery of Jodhpur District

*Asst. Professor, Maulana Azad University, Jodhpur (Raj.) INDIA

Jodhpur: - In this district sindhi embroidery, gota work, zardoji, chain stitch, kanthas, bead work is done extensively. All colours of thread are used. Pearls, big and small pebbles, coins, tiny bells etc are used to enhance the beauty of embroidery. Birds, animals, flowers, leaves & round etc are common designs.

Embroidered samples of Jodhpur District

Embroidery of Barmer District: Barmer: - In this district heavy embroidery is done and work includes, kantha, mirror work, chain stitch, bharat, buta, sindhi, mukka, kharak, patch work, appliqué work etc. These works are exported throughout the world. Usually threads of dark red, yellow, green and blue colours are used.

Embroidered samples of Barmer District

Embroidery of Jaisalmer District Jaisalmer **-** The women folk of sindhi community indulge in embroidery work they use chain button hole, kantha and patch work. Usually dark coloured thread is used.

Embroidered samples of Jaisalmer District

Pieces of cloth are cut and glued to the base fabric, and then it is hand embroidered with bright coloured threads

Table – 2 (See in the last page)

- The colour and vibrancy of Western Rajasthan extends into its embroidery as well.
- Peasant women embroider their family's garments as well as the cloths of the household cattle camel, bullock

and horse are often decorated with beautifully embroidered cloths.

- 77% women add their earnings into their family income and spend it on household expenses, 11% spend the money on their children and only 12% save it for future use.
- The women work force is unorganized therefore they are given low wages and rarely get incentives or bonus.

Reason For Doing The Embroidery - In the erstwhile princely desert states of western Rajasthan, embroidery workshops were developed to serve the nobility. Table No. 2 indicates that almost 94.4% of the women take up embroidery to earn money

Table - 3 (See in the last page)

Hand embroidery is a time consuming art. Increased demand of this handiwork affects the quality. In spite of this very few women have had the opportunity to exhibit their handiwork.

Job Satisfaction -

- Today, Indian embroidery has been well taken into international haute couture. Consequently, various traditional embroideries have found a foothold in fashion houses.
- Table No. 3 indicates the marketing and demand for traditional embroidery of Western Rajasthan. At an average 84% women in all the areas now do embroidery on demand but the income satisfaction is very low ranging from 8% to 24%.
- Most of the women are dissatisfied with the wages they are paid for embroidery work

Table – 4 (See in the last page)

Table No. 4 indicates that embroidery work takes a toll on the health of the women. Over a period of time women's eyesight is affected and constant use of needle causes wounds on the fingers. Over 90% women are not provided medical aid by the workshop owners.

Table - 5 (See in the last page)

Western Rajasthan and especially Barmer and Jaisalmer districts, have outstandingly beautiful embroidery with a multitude of stitches combined with mirror-work. Contrasting colours create a dramatic effect.

According to Table No.5 the women have reported that there is an increasing demand for hand embroidery and the customers demand both small as well as large articles. Bedspreads, table covers, stoles, cushion covers, bags, wall hangings and dress material are in demand.

Table - 6 (See in the last page)

Table No. 6 indicates that the Government help and intervention is almost negligible for the women workers and they need loans and subsidies to venture out on their own rather than doing job work. SHG's are active in Barmer where as in Jaisalmer, Pali, Bikaner and Jodhpur less number of SHG's are functional.

Conclusion:-

- The craft or handicraft sector is the largest decentralised and unorganised sector of the Indian economy, and is among India's largest foreign exchange earners.
- Craftspeople form the second largest employment sector in India, second only to agriculture.
- Dastkar (1995) believes that 'Income generation programmes reviving crafts and providing livelihood, are by themselves, not synonyms for development. But, used skilfully, they could be the entry point for many other aspects of the development process.
- They can become the key and catalyst to development's many other aspects: independence, education, health, community building, women's emancipation and the discarding of social prejudices - in short, the revitalization, both economic and social, of splintered and marginalized rural and urban communities
- The traditional craft skill, however beautiful, needs sensitive adaptation, proper quality control, correct sizing and accurate costing, if it is going to win and keep its place in the market place. Helping women redesign their products is one part of helping them redesign their lives.

References :-

1. Ali Abbasi Saiyed Mehar(1997) ,"Art of Marwar" Delhi.
2. Bhandari Vandana(2004),"Costume, Textiles and Jewellery" Delhi.
3. Brijbhushan Jamila (1996),"Indian Embroidery" Hyderabad.
4. Crill Rosemarry(1998),"Handicraft of India" Singapore
5. Dhamija Jasleen, (2004),"Embroidery: An Expression of women's creativity" Bombay.
6. Hudson James (1989),"Traditional Embroidery of India "Delhi.
7. Jain Kalpana (2004),"Women Empowerment through SHG's" Calcutta.
8. Kokyo Hatanaka(1993),"Traditional Embroideries of Rajasthan" London.
9. Pamela Claburn (2000), " The Needle Worker" New York.
10. Rankawat (2006),"Development of Rural Women" Bombay.
11. www.dastkar .com

Table- I
Surveyed Areas

Districts	No. of sample	Surrounding towns
Jodhpur	150	Dangiawas, Birsalpur, Salawas, Mandore, Jodhpur city, Banar, Jhalamand.
Bikaner	125	Nokha, Kolayat, Kakku, Panchu, Gajner, Ganglu
Barmer	150	Chouhtan, Gadra road, Ramser, Kenchuli
Pali	100	Madri, Jhakurla, Rohit.
Jaisalmer	125	Khudi, Mulana, Bajju, Pugal
Total	**650**	

Table- C
Socio – Economic Status of Women

District	(c) Income per month			
	500-1000	**1001-1500**	**1501-2000**	**Above 2000**
Jodhpur	32%	44%	16.8%	7.2%
Bikaner	32%	53.3%	10.66%	4%
Barmer	58.8%	36.6%	3.6%	1.8%
Pali	36%	42%	22%	-
Jaisalmer	55.6%	24.3%	12.17%	7.8%
Average	**42.8**	**40.0**	**13.0**	**4.2**

Table – 2
Types of Embroidery

District	Used Stitches	Color of threads	Design	Community
Jodhpur	Sindhi, Chain, filling, running, Mirror work, Zardoji, Bead work, Gota work, Satin stitch.	All types of colours light & dark	Flowers, Animals, Rounds, Line	Mochi, Bishnoi, Jat, Rajput, Meghwal.
Bikaner	Chain, Gota, Stem Stitch	Gold & Silver	Leaves, Flowers, Peacock	Sharma, Rajput, Meghwal
Barmer	Running, Mirror work, Bead, Sindhi, Applique, Karak, Suf, Khambhiri	Green, yellow, Blue, Dark Pink, Red, Black etc. Dark Colours	Geometrical Patterns, Flowers, Animal Birds etc.	Sindhi Muslim, Meghwal, Suthar
Pali	Chain stitch, Cross, Satin	Bright Green, Red, Yellow, Gold, Orange, Purple, Blue, White, Silver	Rasmandala, Krishna leela, Shrinath ji	Jain, Brahmins Sevak
Jaisalmer	Chain, button hole, Kantha	Indigo Blue, White, Red, Yellow, Dark Colours.	Squares, Chaklas, animal figure.	Suthar, Rajput, Sindhi, Muslim

Table – 2
Embroidery – Providing Economic Empowerment

Districts	Reason for doing Embroidery			Earned Money Spent			Bonus Received	
	Passing Time	Earning	Any Other	House	Saving	Children	Yes	No
Jodhpur	19.2	80.8	-	72	8	20	10.4	89.6
Bikaner	4	96	-	93.3	4	2.6	4	96
Barmer	-	100	-	81.8	10.9	7.2	-	100
Pali -	100	-	84	12.4	4	-	100	
Jaisalmer	5.6	94.7	-	73.04	18.26	8.6	-	100

Table – 3
Marketing of Embroidered Goods

Districts	Production of Embroidered Articles on Demand %		Income Satisfaction %		Bonus Received %	
	Yes	No	Yes	No	Yes	No
Jodhpur	79.2	20.8	12	88	16	84
Bikaner	80	20	4	96	-	100
Barmer	100	-	18.1	81.9	10	90
Pali	60	40	12	88	16	84
Jaisalmer	91.3	8.6	22.6	77.4	18	82

Table – 4
Effect on Health

Districts	Strain on eyes %		Finger Infection %		Medical Aid Received %	
	Yes	No	Yes	No	Yes	No
Jodhpur	80	12	89.6	11.4	2.4	97.6
Bikaner	80	20	93.3	6.6	6.6	93.3
Barmer	81.8	18.1	85.4	14.5	12.7	87.2
Pali	76	24	84	16	10	90
Jaisalmer	80.8	19.1	73.9	26.8	12.1	87.8
Average	**81.3**	**18.7**	**85.2**	**14.8**	**8.7**	**91.3**

Table - 5
Demand of Embroidery

Districts	Increase in Demand %		Articles in Demand %		
	Yes	No	Small	Big	Both
Jodhpur	98.4	1.6	56	20	24
Bikaner	94.6	5.3	12	62.6	25.3
Barmer	94.5	5.4	3.6	9.09	87.2
Pali	84	16	20	52	28
Jaisalmer	92.2	7.8	24.3	34.7	48.8

Table – 6
Assistance and Role of NGO / SHG

Districts	Govt. Aid Required			Support from Govt.		Faith in SHG/NGO		SHG / NGO functional in Area	
	Loan	Subsidy	Other	Yes	No	Yes	No	Yes	No
Jodhpur	64	36	-	16	84	48	52	56	44
Bikaner	93.3	6.6	-	4	96	32	28	40	60
Barmer	20	80	-	7.2	92.7	72.7	27.7	78.1	21.8
Pali	60	40	-	12	88	64	36	60	40
Jaisalmer	52.1	47.8	-	10.4	89.5	58.2	41.7	40	60
Average	**57**	**43**	**-**	**14**	**86**	**61**	**39**	**61**	**39**

****

भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास व विकास (शारीरिक भाषा के विशेष संदर्भ में)

डॉ. सचिन सैनी *

प्रस्तावना – विख्यात चित्रकार सेजां ने कहा है –'आत्माओं को पेंट नहीं किया जाता, पेंट देहों को किया जाता है और जब पेन्टिंग में देह पूरी तरह से रूपांतरित हो जाती है, तब देह के हर अंग की आत्मा, अगर ऐसी कोई चीज है, चमचमाने लगती है।म सेजां का यह कथन चित्रकला के रूपाकार और सशरीरी होने की ओर संकेत करता है। अमूर्त को मूर्त करने का विधान प्रत्येक कला का मूल रहा है। चित्रकला में मूर्तता या सशरीरी होना कितना आवश्यक है इस पर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हो सकता है, परन्तु चित्रकला में किसी न किसी रूप में शारीरिक भाषा की उपस्थिति अवश्य रही है। कभी वह पर्याप्त रूप से मुखर रही तो कभी कमोबेश। भारतीय आधुनिक चित्रकला में शारीरिक भाषा के प्रयोग का अध्न करने के प्रस्थानबिन्दु के रूप में भारतीय चित्रकला के इतिहास और विकास पर एक विहंगम दृष्टिपात अपरिहार्य है। भारतीय चित्रकला अपने स्वस्फूर्त रूप में मानव के आदिम संस्कारों की सहचरी के रूप में उद्‌भूत (उत्पन्न हुआ) होकर विकास को प्राप्त होती है।

भीम बैठका का भित्ति चित्र

इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों ने प्रकारांतर से अपने मत व्यक्त किये हैं– 'चित्रकला का इतिहास उतना ही पुराना कहा जा सकता है जितना मानव का इतिहास। मानव ने जिस समय प्रकृति की गोद में नेत्रोन्मीलन किया, उस समय से ही उसने निर्माण के तारतम्य से अपने जीवन को सुखी तथा समृद्ध बनाने की चेष्टा की और इस निर्माण कार्य के फलस्वरूप उसने ऐसी कृतियों का सृजन किया जो उसके जीवन को सुखद और सुचारू बना सकें। इसी समय से मनुष्य की ललित भावना भी जाग उठी और उसने अपनी मूक भावनाओं को अनगढ पत्थरों के यंत्रों तथा तूलिका से बनी टेढ़ी–मेढ़ी रेखाकृतियों के रूप में गुहाओं (गुफाओं) और चट्टानों की भित्तियों पर अंकित कर दिया।'[2]

इस सम्बन्ध में डॉ. आर. ए. अग्रवाल लिखते हैं कि–'कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अवयव है, जो मानव–मन को परिष्कृत एवं अलंकृत करता है। भारतीय दर्शन, साहित्य तथा धार्मिक मान्यताओं आदि की अभिव्यक्ति कला में विशेषतया चाक्षुष कला में देखी व अनुभव की जा सकती है।'[3]

चित्रकला के इतिहास एवं विकास के संदर्भ मे किसी देशकाल की संस्कृति महत्वपूर्ण भूमिका रखती है जिसके बारे में कहा गया है कि– 'किसी भी देश की संस्कृति उसकी अपनी आत्मा होती है, जो उसकी सम्पूर्ण मानसिक–निधि को सूचित करती है।......देश की काया संस्कृति के आत्मिक बल पर ही जीवित रह पाती है'[4]

चित्रकला में मानव और मानवेतर आकृतियों की शारीरिक भाषा के प्रयोग की दृष्टि से यूरोप और भारतीय पद्धति पर दृष्टिपात करते हुए डॉ. जगदीश गुप्त लिखते हैं कि–'योरोप में मानव–चित्रण का स्थान काल–क्रम, परिमाण और कलात्मक वैभव सभी दृष्टियों से पशु–चित्रण के बाद आता है। योरोपीय प्रागैतिहासिक कला के विशेषज्ञ बर्किट महोदय का निष्कर्ष है कि वहाँ के शिला–चित्रों में मानवाकृतियों का सापेक्षिक अभाव भी एक उल्लेखनीय तथ्य है तथा जहाँ मानव–अंकन हुआ भी है वहां मनुष्य को बहुत ही बुरी तरह से रूपायित किया गया है।[5] जबकि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में देखें तो हम पते हैं कि मानव और मानवेतर आकृतियों के चित्रांकन में जिस दृष्टि का उपयोग है वह यूरोपीय दृष्टिकोंण से भिन्न है। इस सम्बन्ध में विशेषज्ञ मत उल्लेखनीय है कि – 'भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों में पशु–चित्रण और मानव–चित्रण के बीच भी ऐसा कोई विभेद या विसंगति दृष्टिगत नहीं होती। प्राय: जिन शैलियों में जितनी कुशलता और शक्ति के साथ पशुओं को अंकित किया गया है उनमें लगभग उसी प्रकार मनुष्य को भी चित्रित किया गया है। इस बात को सामान्यत: पंचमढ़ी, रायगढ़, मिर्जापुर तथा चम्बलघाटी और होशंगाबाद इत्यादि सभी क्षेत्रों के उल्लेख करते हुए प्रमाणित किया जा सकता है क्योंकि इनमें से किसी भी क्षेत्र में केवल पशु–चित्रण ही हुआ हो, ऐसा सिद्ध नहीं होता। कुछ अपवाद भी मिलते हैं जैसे होशंगाबाद के शिलाश्रय नं. 10 पर नव लक्षित महाकाय महिष जिसके समानान्तर उसी प्रकार की दोहरी बाह्य–रेखाओं से अंकित उतने ही विशाल आकार की कोई मानवाकृति निर्दिष्ट नहीं की जा सकती।[6] –

भीम बैठका का भित्ति चित्र

* कला शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय, मुरैना (म.प्र.) भारत

प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला में अभिव्यक्त भाव-भंगिमाओं और विषयवस्तु को आकृतिओं के माध्यम से प्रकटीकरण करने के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले विशिष्ट भाषा-संकेतों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करने से सामने आता है कि - 'पाषाण-युग के मनुष्यों ने अपने चारों और के वातावरण की स्मृति को बनाये रखने के लिए तथा अपने विजय का इतिहास व्यक्त करने की भावना के वशीभूत होकर इन चित्राकृतियों का निर्माण किया। गुफावासी मानव ने अपनी अमूर्त भावना को मूर्त रूप प्रदान करने की प्रवृत्ति के कारण जिसमें जादू-टोना टोटका आदि भी आ जाते हैं, अधिकांश चित्रों की रचना की, मूलतः यही मनोवृत्तियां सम्पूर्ण मानवजाति की उन्नति की प्रेरक हैं।'[7]

इस युग की कला के विषय में डॉ. आर. ए. अग्रवाल का मत है कि शारीरिक भाव-भंगिमा की दृष्टि से रेखाओं और रंग की प्रभावशाली भूमिका है। वे लिखते हैं कि-'लहरदार रेखाओं से शारीरिक गठन का बोध कराने का प्रयास किया है। यहाँ लाल-पीले रंगों की अधिकता है। दूसरे स्तर में हाथ-पैरों वाली बेडौल ओजपूर्ण आकृतियों का निर्माण किया गया है। इनमें उनका अहेरिया रूप ही अभिव्यंजित होता है।'[8] डॉ. जगदीश गुप्त मानते हैं कि- 'पशुओं की खाल ओढ़कर छझवेश धारण किये अथवा प्रकृत वेश में मानवाकृतियों को नितान्त आरम्भिक युग से शिलांकित किये जाने की परम्परा न्यूनाधिक रूप में प्रायः अखण्ड नीति से प्रचलित रही है।'[9] वे यह भी लिखते हैं कि- 'इस युग में अधिकतर मानवाकृतियाँ पूरक शैली की हैं। जिनमें सिंघनपुर के कपि-मानव ..... की स्थिति विशिष्टतम कही जा सकती है। कुछ चौड़ी रेखाओं में रची गयी हैं तथा कुछ में शरीर प्रायः यष्टिवत् (आकारगत) पतला बनाया गया है। कुछ का आकार डमरू जैसा द्वि-त्रिकोणात्मक है। आयताकार एवं रेखालंकृत देह वाली मानवाकृतियाँ प्रचुर मात्रा में मिलती हैं।'[10]

पचमढ़ी भित्ति - चित्र, मध्यप्रदेश

श्री गुप्त इस काल की आकृतियों को समझने की विभिन्न दृष्टियों का तर्कसहित खण्डन भी करते हैं तथा मौलिकता के साथ इन मानवाकृतियों की रूप-विधि पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं- 'इसी प्रकार गॉर्डन ने सिंघनुपर और कबरापहाड़ की आयताकार पूरक शैली की आकृतियों से उनका परम्परागत सम्बन्ध जोड़कर मात्र ज्यामितिक रूप-सादृश्य के आधार पर ऐसी सभी मानवाकृतियों को सम-सामयिक मानने का दुराग्रह किया है। ....मानवाकृतियों की रूप-विधि कलात्मक दृष्टि से ही नहीं, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्तवपूर्ण है। आँख, नाक आदि वे वस्तुएँ जो शरीर की बाह्य रेखा के भीतर आती हैं अपवाद रूप में ही प्रदर्शित की गयी हैं। कुछ विद्वानों की यह धारणा है कि मनुष्य ने अपने अस्तित्व को सर्वप्रथम अपनी उस छाया के रूप में देखा होगा जो प्रकाशित वातावरण में निरन्तर शरीर के साथ रहती है और तदनुरूप अपने को चित्रित करने की प्रेरणा उसे इस सहज अनुभव से ही मिली होगी। यह सत्य है कि शिलाचित्रों में अंकित अधिकांश मानवाकृतियाँ छायाभास हैं यथापि उक्त धारणा एक संभावित अनुमान मात्र ही कही जा सकती हैं। कुछ आकृतियाँ ऐसी भी मिलती हैं जिनमें शिरोभाग(उपरी भाग) तथा कहीं-कहीं अन्य अवयव भी केन्द्रीय देह भाग से पृथक् चित्रित किये गये हैं। ......उनका पारस्परिक संयोजन कल्पना द्वारा ही घटित होता है जिससे रूपांकन की छायापरक व्याख्या अंशतः खंडित और मर्यादित हो जाती है।'[11]

जो क्रियाएँ इन चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त की जानी है उनके अनुरूप भाव-भंगिमाओं का चयन और प्रभावशाली अंग-विन्यास प्राप्त होता है। इस विषय में डॉ. जगदीश गुप्त लिखते हैं - 'छायाभास रूपों में भी कल्पनात्मक वैविध्य का इतना प्रसार मिलता है कि अन्ततः छायात्मक चित्रण को भी कल्पना का एक स्वाभाविक प्रकार मानना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। कदाचित् इसीलिए छायात्मक होने पर भी तथा मुख की भीतरी रेखाओं और नेत्रादि की स्थिति निर्दिष्टि किए बिना ही विविध भाव-भंगिमाओं और क्रियाओं के अनुरूप सशक्त और व्यंजक अंग-विन्यास सम्भव हो सका।'[12]

पद् मपाणि बोद्धिसत्व, गुफा 1, अजंता

चित्रकला में जब शारीरिक-भाषा की प्रेरणा शरीर तथा भाषा के मध्य स्थापित सेतु को समझने की ओर इशारा करती है तो यह सेतु जिसकी कॉन्क्रीट (सामग्री) रेखा, रंग, रूप आदि जो कि भाव तथा भंगिमाओं को प्रदर्शित करती है वह कलाकृति तथा कलाकार के आपसी सम्बन्ध को दर्शाती है। इस सम्बन्ध की दक्षता का श्रेय अगर चित्रकार द्वारा खींची गई रेखाओं को ही दिया जाये तो अधिक महत्वपूर्ण होगा क्योंकि किसी भी कलाकृति की पहचान उसकी रेखाओं पर निर्भर करती है, इसी संदर्भ में श्री आर. ए. अग्रवाल का मत है कि -'प्रागैतिहासिक काल का कलाकार जादूगर था, जिसकी रेखाओं में जादुई भावनाओं का आनन्द और मन्त्रमुग्ध कर देने के समस्त गुण थे। रेखाओं में गति व शक्ति का सम्पुंजन ऐसा है कि मानों शिलाश्रयों में बैठा कोई आधुनिक कलाकार किसी जनजाति के आखेटीय-जीवन का काजल व गेरू से रेखाकंन कर रहा हो। आकृति के रेखीय प्रभाव को उतारने में आदिम कलाकार ने अविश्वसनीय दक्षता प्रदर्शित की है।'[13]

इस विषय में विद्वानों ने यह भी माना है कि - 'इन चित्रों में मानव ने

अपने भावों को सरलतम रूपों तथा ज्यामितीय आकारों में संजोया है। यह कृतियाँ आदिम मानव की बालसुलभ प्रकृति की उत्तम झांकी हैं। इन चित्रों में प्रागैतिहासिक युग के मनुष्य का सम्पूर्ण इतिहास सिंचित है।'[14] जो कि, भारत ही नहीं वरन् सम्पूर्ण विश्व में परिलक्षित होता है। जिसका परिचय हमें इस शोध से प्राप्त होता है – 'स्पेन की अल्तामिरा, फ्रांस की लासौक्स उत्तारी अफ्रीका की सहारा, एटलस पर्वत, अहग्गर पर्वतमाला आदि में तथा लीबिया की रेगिस्तानी पहाड़ी में तथा आस्ट्रेलिया के गुहा–चित्रों में भारत के समान ही अंकन मिलता है। अत: आदिम कला देशकला की भौगौलिक सीमाओं से मुक्त एक व्यापक शैली के रूप में विकसित हुई'[15]

प्रागैतिहासिक काल के नव–प्रस्तर युगीन पंचमढ़ी नाम स्थल के भित्तिचित्रों की विशेषता मानी गई है कि इन चित्रों में विभिन्न स्तरों पर आकृतियों का निर्माण करने हेतु जिन तरीकों का इस्तेमाल किया गया है उनमें शारीरिक गठन को दर्शाने के लिए लहरदार रेखाओं को प्रभावशाली माध्यम के रूप में अपनाया गया है। इस सम्बन्ध में विशेषज्ञ अभिमत है कि – 'यहाँ चित्रों के कई स्तर प्राप्त हुए हैं। पहले स्तर में तख्तीनुमा व डमरूनुमा आकृतियों को बनाया गया है। लहरदार रेखाओं से शरीरिक गठन का बोध कराने का प्रयास किया है। यहाँ लाल–पीले रंगों की अधिकता है। दूसरे स्तर में हाथ–पैरों वाली बेडौल ओजपूर्ण आकृतियों का निर्माण किया गया है। इनमें उनका अहेरिया (शिकारी) रूप ही अभिव्यंजित होता है।'[16] इस युग से लेकर पूर्व बौद्धकाल तक का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि इस अवधि में चित्रकला का उपजीव्य सीधा और पर्याप्त प्राप्त नहीं होता। 'प्रागैतिहासिक काल के समाप्त होते ही धातु युग के साथ वैदिक काल का उदय होता है। दक्षिणी भारत में पाषाण काल के पश्चात लौह–युग ही आरंभ हुआ। परन्तु उत्तरी भारत में ताम्र और सिंध में कांस्य के पश्चात ही सम्पूर्ण भारत में लौह–युग आया।'[17]

सारांश के रूप में हम पाते हैं कि आधुनिक काल की जिस चित्रकला में हम शारीरिक भाषा, भाव–भंगिमा के विश्लेषण का विवेच्य लक्ष्य रखते हैं उसकी पूर्वपीठिका के कालक्रम में से शारीरिक भाषा विविध तरीकों से चित्रांकन में उपस्थित रही है। चित्रकला अपने आदिम रूप से ही समाज, संस्कृति, मनोभाव, संदेशप्रियता, प्रकृति और प्राणि व अप्राणितत्वों को देखने और समझने के चित्रकार के दृष्टिकोण की परिचायक रही है। गुहाओं के भित्तिचित्रों में यह शारीरिक भाषा अपने आरंभिक लेकिन चमत्कृत कर देने वाले रूपों के साथ विद्यमान है। गुहावासी मानव स्वयं की अनुभूतियों को इन चित्रांकनों में अभिव्यक्त हाव–भावों के माध्यम से प्रकट करने चेष्टा करता रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. जोशी, डॉ. ज्योतिष, जनता की कला के मायने, सं. समकालीन कला (ललित कला अकादेमी) 44–45 (दि.न.), पृष्ठ–6,
2. वर्मा, डॉ. अविनाश बहादुर व अन्य, भारतीय चित्रकला का इतिहास, पृष्ठ–8, 11वां संस्करण, बरेली, प्रकाश बुक डिपो, वर्ष–2006
3. अग्रवाल,आर.ए.,कला विलास–भारतीय चित्रकला का विकास, पृष्ठ–2,मेरठ, इन्टरनेशनल पब्लिशिंग हाऊस, 1984.
4. अग्रवाल,आर.ए.,कला विलास–भारतीय चित्रकला का विकास, पृष्ठ–1, मेरठ, इन्टरनेशनल पब्लिशिंग हाऊस, 1984.
5. गुप्त, डॉ. जगदीश, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, पृष्ठ–227, दिल्ली :7, नेश्नल पब्लिशिंग हाऊस,(वर्ष–दि.न.),
6. वही, पृष्ठ–227–228
7. वही, पृष्ठ–17
8. अग्रवाल, आर. ए.,कला विलास भारतीय,चित्रकला का विकास, पृष्ठ–8, मेरठ, इन्टरनेशनल पब्लिशिंग हाऊस,1984.
9. गुप्त, डॉ. जगदीश, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, पृष्ठ–228, दिल्ली :7, नेश्नल पब्लिशिंग हाऊस,(वर्ष–दि.न.),
10. वही,
11. वही,
12. गुप्त, डॉ. जगदीश, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, पृष्ठ–229, दिल्ली :7, नेश्नल पब्लिशिंग हाऊस,(वर्ष–दि.न.),
13. अग्रवाल, आर. ए., कला विलास, पृष्ठ–14, मेरठ, इन्टरनेशनल पब्लिशिंग हाऊस, 1984.
14. वर्मा, डॉ. अविनाश बहादुर व अन्य, भारतीय चित्रकला का इतिहास, पृष्ठ–18, 11वां संस्करण, बरेली, प्रकाश बुक डिपो, वर्ष–2006
15. अग्रवाल, आर. ए., कला विलास–भारतीय चित्रकला का विकास, पृष्ठ–13, मेरठ उ. प्र. : इन्टरनेशनल पब्लिशिंग हाऊस, 1984.
16. वही, पृष्ठ–8
17. वही, पृष्ठ–19.

****

देवात्मा का प्रकृति-दर्शन

डॉ. आशा चौधरी *

प्रस्तावना – 1850 में कानपुर के पास के एक गांव में जन्में शिवनारायण अग्निहोत्री जो कि आगे चलकर अपने सद्गुणों के कारण देवात्मा नाम से प्रसिद्ध हुए, आप रूड़की के थामसन इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी करके लाहौर में एक शासकीय स्कूल में नियुक्त हुए। कुछ समय बाद आप ब्रह्मसमाज के सदस्य बने। आगे चल कर आपने देवसमाज नामक एक आस्तिक विचारधारा वाली संस्था स्थापित की किंतु कुछ समय बाद इसका विकास एक निरीश्वरवादी संस्था के रूप में हुआ। यही देवात्मा एक वे समकालीन भारतीय दार्शनिक हैं जिनके विचारों में विशुद्ध प्रकृतिवादी चिंतन अपने उत्कृष्ट रूप में मौजूद है।

उन्होंने व्रत लिया था कि वे सत्यम्, शिवम् तथा सुंदरम् के लिये समर्पित रहेंगे व विश्व कल्याण के लिये ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। उनका नीतिशास्त्रीय मत भी उनके प्रकृतिवाद पर ही आधारित है।

प्रकृतिवादी तत्वमीमांसा – वैज्ञानिक मानवतावादियों की ही तरह देवात्मा भी अपनी तत्व-मीमांसा में प्रकृतिवादी है। उन्होंने प्रकृति को पूर्णरूप से जीवित तथा पदार्थ (Matter) तथा शक्ति (Energy) के निरंतर परिवर्तनशील स्वरूप में मान्य किया है। प्रकृति उनके मतानुसार एक सर्वथा स्वायत्ता चरित्र रखती है जिसके स्पष्टीकरण के लिये किसी सूक्ष्म, अभौतिक अथवा अतिव्याप्तता पर निर्भर करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रकृति केवल सत्य है। वे प्रकृति की परिभाषा में कहते है कि 'नेचर या प्रकृति सब छोटे और बड़े, जीवित और अजीवित अस्तित्वों के जोड़ का ही नाम है।'[1] स्वयं यह काई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। वस्तुओं का जोड़ स्वयं में कोई वस्तु नहीं होता। ऐसा ही प्रकृति के विषय में है।

उनके अनुसार प्रकृति या नेचर की तुलना सेना या विश्वविद्यालय शब्द से की जा सकती है। यदि कोई किसी विश्वविद्यालय को देखना चाहे तो उसे विश्वविद्यालय के भवन के भिन्न-भिन्न कमरे, सभागार, ग्रंथालय, ऑफिस, बरामदे आदि दिखाए जा सकते हैं। तब प्रश्न हो कि यह तो विश्वविद्यालय के ग्रंथालय, कक्षाएँ, ऑफिस वगैरह हुए, स्वयं विश्वविद्यालय कहाँ है ? वह तो दिखाई ही नहीं दिया ! इसका उत्तर है कि 'विश्वविद्यालय का न तो अलग से कोई अस्तित्व है और न ही इसका कोई सर्वव्याप्त अस्तित्व है जो इन सब भवनों में समाया हुआ हो। वह केवल इन सब भवनों और इनमें होने वाले *कार्य के जोड़* का नाम है। जोड़ का कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होता।'[2] इस प्रकार, इस तुलना से देवात्मा दर्शन में प्रकृति को समझाने का प्रयास किया गया है।

यदि पूछा जाए कि प्रकृति क्या है ? तब सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, पशु व मानवों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया जाएगा। बहुरंगी फूल, फल, पौधे तथा चिड़िया, पशु व मानवों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया जायेगा। फिर भी प्रश्न होगा कि ये सब तो ठीक है मगर स्वयं प्रकृति कहाँ है ? तो इस प्रश्न का उत्तार विश्वविद्यालय वाले प्रश्न के उत्तार के रूप में ही होगा। देवात्मा ने माना है कि नेचर या प्रकृति न तो किसी व्यक्तिगत अस्तित्व का नाम है, और न ही उसका सर्वव्याप्त अस्तित्व है। नेचर तो केवल छोटे-बड़े *अस्तित्वों के जोड* का नाम है जिनकी खोज वैज्ञानिक पद्धति से की जा सकती है। ईश्वर तथा प्रकृति में फर्क उपरोक्त धारणा से स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है।

प्रकृति परिवर्तनमय है – देवात्मा मानते है कि नेचर के समस्त अस्तित्वों में भौतिक-द्रव्य ऊर्जा या जड़ शक्ति-संपन्नता व्याप्त है। इसमें प्रत्येक अस्तित्व में प्रशिक्षण एक परिवर्तन सतत् रूप से घटित होता रहता है। मानव का शरीर तथा आत्मा भी सतत् परिवर्तनशील है। अत: उनका मत है कि नेचर प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। नेचर के समस्त अस्तित्वों को वे नियम बद्ध मानते हैं। इनमें से कोई भी नियम को तोड़ नहीं सकता। प्रकृति में उन्होंने अजीवित ही अजीवित शक्तियां मानी हैं। उनकी धारणा है कि इस प्रकृति में इन अजीवित शक्तियों की तुलना में जीवित शक्तियां नाम मात्र है। वे मानते हैं कि प्रकृति में ऐसे अस्तित्व पाए जाते हैं जिनके पृथक-पृथक अस्तित्व होते हुए वे अपनी सीमित शक्ति रखते हैं। प्रत्येक अस्तित्व का अपना पृथक, व्यक्तिगत अस्तित्व होता है किंतु ये सर्वशक्तिमान नहीं होते। इनमें एक दूसरे का विरोध भी परिलक्षित होता है। इस प्रकार ये एक-दूसरे का विरोध करके एक-दूसरे को सीमित करते हैं।

प्रकृति को वे जीवित तथा अजीवित शक्तियों का अनमेल कहते हैं। नेचर में न कोई सर्वज्ञ है न कोई सर्वज्ञानी। ऐसा कोई नहीं इसमें, जो मनुष्य से अधिक ज्ञान रखता हो तथा मनुष्य भी ऐसा कोई नहीं जिसे सर्वज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो। क्योंकि देवात्मा की धारणा है कि नेचर प्रतिक्षण परिवर्तनमय है। अत: ज्ञान में सर्वज्ञता आनी असंभव है। न ही कोई ऐसा है जो सर्वथा त्रुटिहीन हो। सर्वज्ञानी जो होगा उसका व्यवहार त्रुटिहीन ही हो सकता है। किंतु देवात्मा को सर्वज्ञ की धारणा नामंजूर है। अत: उनके अनुसार 'नेचर में ऐसा कोई अस्तित्व भी नहीं जो अपने व्यवहार में कहीं कोई गलती न करता हो। नेचर सर्वश्रेष्ठ नहीं है। यह अस्तित्वों का जोड़ है और यह अस्तित्व अच्छे और बुरे दोनों व्यवहार प्रदर्शित करते हैं।'[3]

समस्त नियम प्राकृतिक हैं– विज्ञान का आधार ले कर कहा जा सकता है कि विश्व में जो भी कुछ घटित होता है अर्थात इसमें जो घटनाएं हैं उनमें ऐसी कोई घटना नहीं जिसकी व्याख्या के लिये विश्व से परे, विश्व से बाहर कहीं जाना पड़े। विज्ञान इस प्रकार यह मानता है कि पृथ्वी की रचना ईश्वर ने नहीं की, न ही मानव की रचना ईश्वर ने की। मानव को पशु की एक जाति से विकसित हुआ माना जाता है। मानव की उत्पत्ति के समस्त कारण व आधार इस जगत में ही हैं, इससे परे कहीं नहीं। देवात्मा का मत है कि चाहे भौतिक हो या जैविक, सामाजिक हों या मनोवैज्ञानिक, नैतिक हों या आध्यात्मिक, समस्त घटनाएँ प्रकृति के द्वारा समझी-समझाई जा सकती हैं। उपरोक्त से

* विभागाध्यक्ष (दर्शनशास्त्र) शा. जे. योगानंदम महाविद्यालय, रायपुर (छ. ग.) भारत

संबंधित सभी नियम प्राकृतिक हैं। चाहे वे नैतिक, आध्यात्मिक नियम हों कि आत्मा, समाज या मानव के स्वास्थ्य के नियम हों, वे प्राकृतिक ही हैं। 'इन समस्त नियमों की खोज वैज्ञानिक विधि द्वारा ही संभव है, उससे परे नहीं। जैसे विज्ञान के स्वास्थ्य के नियम की खोज करता है उसी प्रकार वह आध्यात्मिक नियमों की भी खोज करता है।'[4]

प्रकृति ही तत्व है **–** वे शक्ति-विषयक तत्व ज्ञान की चर्चा करते हुए बतलाते हैं कि यह हमारा विश्व जड़ तथा शक्ति विशिष्ट है। ये दोनों पदार्थ (अर्थात् जड़ तथा शक्ति) अविनाशी हैं। जगत के जड़ पदार्थो के साथ शक्ति का अकाट्य संबंध है। शक्ति अपने द्वारा जड़ पदार्थों को परिवर्तित करती है और स्वयं भी नाना रूपों में परिवर्तित होती है। जगत् की प्रत्येक घटना इन्हीं दोनों परिवर्तनों से उत्पन्न होती है। अत: वे प्रकृति व प्रकृति की अंतरस्थ जड़ तथा शक्ति को ही तत्व रूप में मान्यता देते हैं। इन्हीं के द्वारा जगत् की, मानव की सृष्टि होती है।

वे बात करते हैं निर्जीव अंध शक्तियों की, तथा सजीव अर्थात् जीवनी शक्तियों की-'भार, ताप, प्रकाश व विद्युत आदि निर्जीव अंधशक्तियाँ कही गई हैं। तथा उद्‌भिद्, पशु व मनुष्य आकारी-गठनकारी शक्तियों को सजीव जीवन शक्तियाँ कहा गया है।'[5] सारा का सारा जगत्, इसके समस्त जड़-सजीव पदार्थ उपरोक्त दोनों शक्तियों की ही वास्तविकता हैं। ईश्वर, ब्रह्म आदि जैसे किसी तत्व की इस सबके दौरान कहीं कोई आवश्यकता नहीं- न तो इनकी रचना के लिये, न इसके पालन के लिये, और न ही इनके संहार ही के लिये !

देवात्मा का मत है कि ***प्रकृति ही मूल*** है। इस प्रकृति का प्रत्येक अस्तित्व शरीर-युक्त है। अत: अशरीरी अस्तित्व का अनुभव मात्र मति भ्रम ही ठहरता है।

उनके दर्शन में प्रकृति का उत्कृष्ट दर्शन मिलता है किंतु यह प्रकृतिवाद की तरह जड़वाद नहीं है। वे इसमें जीव-सजीव दोनों प्रकार के तत्वों को सम्मिलित बताते हैं। उनके अनुसार प्रकृति ही एकमात्र सत्य है। यह तत्व शक्ति से निर्मित हुए अपने समस्त शरीरी अस्तित्वों के साथ उत्पत्ति रहित तथा स्व-अस्तित्व वाली है। इसके परिवर्तन को वे यथार्थ मानते हुए मानते हैं कि विश्व का निर्माण इसी से होता है। उनके अनुसार प्रकृति ही वह तत्व है जिससे मानव तथा समस्त जगत बना है। इनके एक क्रमबद्ध विकास से ही इनका निर्माण होता है। इस प्रकार,

वे मानते हैं कि इस नेचर से भिन्न, इससे परे अथवा इसके बाहर कुछ भी और कोई सत्ता भी और कोई बात भी सत्य नहीं। देवात्मा ने, इस प्रकार *अतींद्रिय सत्ता को अमान्य* किया है। प्राचीन भौतिकवादियों तथा चार्वाक मत में भी प्राय: अतींद्रिय तत्व को मूल-तत्व नहीं माना गया। चेतना की उत्पत्ति भी भौतिक तत्वों के सम्मिश्रण से ही होती मानी गई है।

देवात्मा ने डार्विन के योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत के स्थान पर श्रेष्ठतम की उत्तारजीविता के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए माना है कि मनुष्य व जगत के किसी निर्माता व नियंता की सत्ता को स्वीकारने की कोई आवश्यकता नहीं है।

वास्तव में उनका मत प्रकृतिवादी, आशावादी, प्रगतिशील तथा पदार्थवादी माना गया है। वैज्ञानिक मानवतावादियों की तरह देवात्मा ने भी प्रकृतिवादी तत्व-मीमांसा प्रस्तुत की है। विज्ञान का आधार लेकर कहा जा सकता है कि विश्व में जो कुछ भी घटित होता है अर्थात् इसमें जो कुछ भी घटनाएँ घटती हैं वे विश्व से परे, विश्व से बाहर नहीं होती। अत: उनकी व्याख्या के लिए भी विश्व से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। देवात्मा का मत है कि चाहे भौतिक हो या जैविक, सामाजिक हो याह मनोवैज्ञानिक, नैतिक हो गया आध्यात्मिक, सभी घटनाएँ प्रकृति के द्वारा समझी-समझायी जा सकती हैं। वे मानते हैं कि सभी नियम प्राकृतिक हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्निहोत्री, एस.न., मनुष्य आत्मा के संबंध में चार महातत्व, विषय प्रवेश, पृ. 01
2. कनल, एस.पी., निरीश्वरवाद एक अध्ययन, देवसमाज प्रकाशन, मोगा, पृ. 39
3. वही, पृ. 35
4. 82-अग्निहोत्री, एस.एन., देवशास्त्र, खंड-3, पृ. 162
5. अग्निहोत्री, एस.एन., मुझमें देवजीवन का विकास, देवसमाज प्रकाशन, पृ. 145

****

तुलसीदास का जीवन और समाज सम्बन्धी दृष्टिकोण

कामिनी देवी *

प्रस्तावना – तुलसीदास का जन्म संवत् 1554 में राजापुर ग्राम (अवध) में माना जाता है और इनकी मृत्यु संवत् 1680 को वाराणसी के अस्सी घाट पर हुई थी। रामकाव्य का प्रतिनिधि कवि तुलसीदास को ही माना जाता है। उन्होंने राम के चरित्र को आधार बनाकर साहित्य रचना की है। वह अपने साहित्य से मनुष्य जीवन में आदर्शों की स्थापना करना चाहते थे। तुलसीदास द्धारा रचित रचनाएं रामचरितमानस, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली रामलल्ला नहछू, गीतावली, कृष्णगीतावली, विनयपत्रिका है।

तुलसीदास की यदि काव्यगत विशेषतांए देखी जाएं तो वह राम मार्गीशाखा के कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं।तुलसी के राम विष्णु के अवतार हैं जिनमें शील, शक्ति, सौंदर्य तीनों गुण विद्यमान हैं। उनमें इतनी शक्ति हैं कि वह दुष्ट रावण का दलन कर सकते हैं। अपने सभी भक्तों के संकटों का निवारण भी करते हैं:–

‘हरिहि हरिता, विधिहि् विधिता, सिवहि् सिवता जो दई।
सोई जानकीपति मधुर मूरति, मोदमय मंगलमयी।।’[1]

इनकी यदि भक्ति की बात की जाए तो इनकी भक्ति दास्य भक्ति है। वैसे तो इन्होंने नवधा भक्ति के सभी अवयवों जैसे श्रवण, स्मरण, पादसेवन, कीर्तन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन की चर्चा की है। लेकिन आत्मनिवेदन तथा दास्य भाव इनकी भक्ति का विशेष आधार रही हैं इनकी भक्ति का स्वरूप विनयपत्रिका की इन पंक्तियों में दृष्टिगोचर होता है।:–

‘राम सो बड़ो है कौन, मोंसो कौन छोटो?
राम सों खरों है कौन, मोंसो कौन खोटो?’[2]

इनके काव्य में प्रकृति–चित्रण का भी बड़ा सुन्दर चित्रण मिलता है। राम सीता के वियोग में हर लता, पक्षी–पशु से सीता के बारे में पुछते रहते हैं कि कहीं तुमने मेरी सीता को देखा है।

‘हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी।
तुम्ह देखी सीता मृग नैनी?’[3]

तुलसीदास जी एक ऐसा आदर्श राज्य स्थापित करना चाहते थे यहां पर कोई दुखी, दरिद्र न हो। इसलिए उन्होंने अपने काव्य में आदर्श समाज को दिखाया है। राम आदर्श राजा है।, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति है। हनुमान जी को आदर्श सेवक के रूप में दिखाया है। सीता आदर्श पत्नी है। कौशलया को आदर्श माता के रूप में दिखाया है। इसलिए राम राज्य एक आदर्श राज्य है– जहां पर किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं है।

‘अल्प मृत्यु नहिं कवनिउँ पीरा।
सब सुन्दर सब दिरूज सरीरा।।
नहिं दरिद्र कोउ दुख न दीना।
नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना।।’[4]

तुलसीदास के जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण को हम दो भागों में बांट सकते हैं –

(1) आध्यात्मिक (2) लौकिक

आध्यात्मिक दृष्टि से तुलसीदास ने भगवान को ही सब कुछ माना है। इस संसार में जो कुछ घटित होता है वह ईश्वर की ही इच्छा से होता है। हम सब ईश्वर का ही अंश है। इन्होंने ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोंनों रूपों को स्वीकार किया है।

श्रीराम को इन्होंने ब्रह्म रूप में स्वीकार किया है। ससांर में सभी जड़–चेतन श्री राम में ही निवास करते हैं। तुलसी के राम निर्गुण भी हैं और सगुण भी है।

‘जड़ चेतन जग जीव, जत सकल राममय जानि
बंदउं सबके पदमकल सदा जोरि जुग पानि।’[5]

माया को तुलसी ने अज्ञान का कारण माना है। माया की वजह से जीव अपने –पराये के भेद–भाव में जकड़ा हुआ है। रामचरितमानस के बालकाण्ड में इसका उल्लेख हुआ है –

‘जासु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया।’[6]

इन्होंने ईश्वर और जीव दोनो को एक ही माना है लेकिन माया के कारण दोनो एक दुसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। जगत को इन्होंने मिथ्या माना हैं लेकिन मनुष्य माया में पड़ कर इसको सच मानने लगता है और जीवनभर दुखों में फंसा रहता है।

यदि हम इनके लैकिक पक्ष को देखे तो उसमें लोकमंगल की कामना निहित है। तुलसीदास ने समाज को वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्याग कर धर्म को अपनाने के लिए प्रेरणा दी है। हमारी संस्कृति में संस्कारों का बड़ा महत्व है इसलिए उन्होंने राम के आदर्श रूप में संस्कृति के विभिन्न अंगों का समन्वय दिखा कर समाज को शुद्ध आचरण अपनाने के लिए प्रेरित किया है।

तुलसीदास ने समाज की विसंगतियों को दूर करने के लिए कदम उठाये। इन्होंने हिन्दुसमाज में व्याप्त बुराईयों को दूर करने के लिए अपने साहित्य में एक आदर्श समाज को प्रस्तुत करते थे ताकि उस साहित्य को पढ़कर या सुनकर मनुष्य में लोककला तथा लोकमंगल की भावना जागृत हो सके। तुलसीदास के समय वर्णाश्रम व्यवस्था थी और समाज के धार्मिक तथा नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा था। इसलिए उन्होंने समाज को एक करने के लिए वर्णव्यवस्था का विरोध किया उन्होंने ऊंच और नीच जातियों में समन्वय किया। इसलिए इन्होंने राम को शबरी के झुठे बेर खाते हुए दिखाया है। राम उच्च कुल के थे और शबरी शुद्रा लेकिन राम स्वयं शबरी के निवास

* शोधार्थी, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू (जम्मू–कश्मीर) भारत

पर जाते हैं। इसके पीछे उनका उद्देश्य ऊंच-नीच का भेद-भाव खत्म करना ही है।

इन्होंने सगुण और निर्गुण का समन्वय किया है। ईश्वर को साकार और निराकार रूप में पूजने वालों में बहुत मतभेद था। तुलसी ने निर्गुण व सगुण में समन्वय स्थापित कर समाज में शान्ति लाने का प्रयास किया। तुलसी के राम निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं इसलिए वह कहते हैं-

'सगुनहिं अगुनहि नहि कहु भेदा। गांवहि मुनि पुरान वुध
अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेमबस सगुन सौ होई'[7]

इन्होंने शक्ति शील और सौन्दर्य का भी समन्वय किया है। जिसे इन्होंने राम के चरित्र में उभारा है। राम में शक्ति है, शील भी है और सौन्दर्य भी विद्यमान है।

तुलसीदास के युग में शैव मत और वैष्णव मत एक दूसरे का विरोध करते थे। ऐसी मनोवृति के कारण समाज में घृणा और द्धेष बढ़ रहा था। दोनों मतो के इसी द्धेष को मिटाने के लिए तुलसी जी ने शिव और विष्णु का समन्वय करवाया। इसलिए रामचरितमानस में कई स्थानों पर शिव से राम की तथा राम से शिव की महिमा का गान करवाया है।

तुलसीदास जी ने नैतिक आदर्शो का प्रबल समर्थन किया है। उनका मानना था कि यदि किसी समाज में नैतिकता नहीं हो तो वह समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता है। मनुष्य को ऐसे आचरण को अपनाना चाहिए जो लोक हितकारी हो।

तुलसीदास जी ने अपने समाज की अच्छाइयों- बुराईयों तथा गुणों- अवगुणो को बड़ी बारीकी से देखा- समझा इसलिए संसार के प्रति अपना उदारवादी दृष्टिकोण रखते हैं। उनका मानना है कि जोंक और जलज दोनों ही जल में उत्पन्न होते हैं लेकिन अपने गुणों की वजह से एक दूसरे से अलग माने जाते हैं ठीक उसी प्रकार एक ही संसार में अच्छे और बूरे लोग भी रहते हैं।

'उपजे एक संग जग माहीं।
जलज जोंक जिमि गुन बिलगाही।'[8]

वह समाज में जनता को न्याय दिलवाना चाहते थे इसलिए उनके राम भी न्याय के आधार पर अपना निर्णय प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसी देश का राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, राज्य की न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इन सब बातों पर प्रकाश डाला है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि तुलसीदास जी का जीवन के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण था। वे समन्यवादी कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। इन्होंने समाज की भलाई के लिए विभिन्न मतों का, जातियों का आपस में समन्वय करवाया है और समाज में शान्ति स्थापित करने का प्रयास किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हिन्दी साहित्य का सरल इतिहास, डॉ. ओम प्रकाश गुप्त, पृ.-26
2. हिन्दी साहित्य का सरल इतिहास, डॉ. ओम प्रकाश गुप्त, पृ.-26
3. हिन्दी साहित्य का सरल इतिहास, डॉ. ओम प्रकाश गुप्त, पृ.-28
4. हिन्दी साहित्य का सरल इतिहास, डॉ. ओम प्रकाश गुप्त, पृ.-26
5. तुलसी साहित्य में पौराणिक आरव्यानों का विनियोग, डॉ. बी. के. शास्त्री, पृ-216
6. तुलसीदास, रामचरितमानस; बाल काण्ड, पृ.-116/4
7. तुलसी साहित्य में पौराणिक आरव्यानों का विनियोग, डॉ. बी. के. शास्त्री, पृ-218
8. लोकवादी तुलसीदास, विश्वनाथ त्रिपाठी, पृ.-78

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

विश्व प्रसिद्ध भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ– महाराजा दक्ष प्रजापति

डॉ. ईश्वरलाल प्रजापति *

शोध सारांश– अद्य राज्याधीपति महाराजा दक्ष प्रजापति के बारे में जानकारी प्राप्त करना तथा वेद, संहिता एवं स्मृति आदि ग्रंथों में दक्ष प्रजापति को ही 'यज्ञ' नाम से अलंकृत किया गया है। जो 'यजुर्वेद' व 'यज्ञ विज्ञान' के स्वामी है। जिन्होंने अहंकार को त्यागकर 'देवयज्ञ' किए जाने का नियम सृष्टि में स्थापित किया है। यज्ञ विज्ञान एवं वेदों पर विश्व में कई संस्थाऐं कार्य कर रही है जबकि भारत में यज्ञ विज्ञान व वेदों की धरोहर धूल खा रही है। भविष्य में प्राकृतिक चिकित्सा के साथ 'यज्ञ विज्ञान' यज्ञों के द्धारा भी उपचार किया जाना संभव होगा क्योंकि फ्ल्यू व वायरल नामक बीमारी के कीटाणु हवा के द्धारा फैलते है जिसे यज्ञों द्धारा ही ठीक किया जा सकता है मानव के निवास स्थान पर भी DNA व RNA को सकारात्मक रुप यज्ञों के द्धारा ही प्राप्त होता है। भारतीय संस्कृति का मूल व सभी देवताओं की बलिष्टता का मुख्य आधार 'यज्ञ' है, जिसे वेदों, संहिताओं एवं स्मृतियों में 'दक्ष प्रजापति' कहा गया है जो विश्व प्रसिद्ध भारतीय संस्कृति का आधार स्तम्भ है, जिसे भारत को समझने की आवश्यकता है।

सर्वशास्त्रार्थतत्वज्ञ: सर्ववेदविदां वर:।
पारग: सर्वविद्यानां दक्षो नाम प्रजापति:।।

अर्थ– सम्पूर्ण धर्म और अर्थो के जानने वाले, सम्पूर्ण वेद और वेद के अंगों को जानने वालों में श्रेष्ठ सम्पूर्ण विधाओं के पार को जानने वाले दक्ष नामक प्रजापति हुए।

आज से लगभग दो अरब वर्ष पूर्व देव भूमि पर प्रजापति बह्माजी ने सर्वप्रथम क्रमश: प्राकृतिक सृष्टि, ब्रह्मी सृष्टि व मनसा सृष्टि को उत्पन्न किया इन सृष्टियों के कुशल संचालन के लिए बैजी (मैथुनी) सृष्टि को उत्पन्न किया ताकि नर–नारी के सामाजिक व धार्मिक संयोग से अनन्त–अनन्त काल तक सृष्टि का कुशल संचालन होता रहें। इन्हीं उद्देश्यों से प्रजापति बह्माजी ने बह्म पुत्र नदी के तट पर प्राकृतिक सृष्टि की है, बह्म सृष्टि के अन्तर्गत सभी 'जीव सृष्टि' करने के उपरान्त प्रजापति बह्माजी ने 'ऋग्वेद' की रचना 'सरस्वती नदी' के किनारे कि, जो सम्पूर्ण विश्व में निर्विवाद, अति प्राचीन व अद्धितीय ग्रंथ है । जिसमें प्रजापति को समस्त प्राणियों का प्रभु, सारी भौतिक व अभौतिक शक्तियों के स्रोत, देवाधिदेव एवं सर्वोपरि देव के रूप में माना गया है । प्रजापति ने चैत्र प्रतिपदा (नववर्ष) से सृष्टि का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था तथा सृष्टि संचालन हेतु पुष्कर, अजमेर (राज.) में आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन (1,96,53108 वर्ष पूर्व) अपने प्राणों से सम्पूर्ण ज्ञान से युक्त (यज्ञ) दक्ष प्रजापति को मानस पुत्र के रुप में प्रकट किया अर्थात् दक्ष प्रजापति अज (अजन्मे) है । जिनका सृष्टि में बार–बार जन्म नहीं होता है उन्हें अजन्मा (अज) कहा जाता है। वेदों में दक्ष प्रजापति को 'अज' कह गया है। 'अज' शब्द की व्याख्या करते हुए भाष्यकार माधवाचार्य ने लिखा है कि– वे सृष्टि के आरंभ में एक बार ही प्रकट होते है, सामान्यजनों की तरह जन्म–मरण के प्रवाह में नहीं पड़ते अर्थात् ज्ञान प्राप्त हो जाने के कारण मुक्त हो जाते है, या अधिकारी पुरुष के रुप में उसी शरीर में ही बने रहते है। (अज अर्थात् आगे जन्म न लेने वाला या अजन्मा जिनका जन्म नहीं होता) जो प्रकट होकर सदा सृष्टि के प्रत्येक कल्प में उसी शरीर में उपस्थित रहते है।

महाराजा दक्ष प्रजापति ज्ञान स्वरूप परमात्मा है जिन्हें ज्ञान लोक का स्वामी माना गया है। जो ब्रह्मा आदि से लेकर चींटी तक (सभी छोटे बड़े जीव) सभी प्रजा की ज्ञान स्वरूप आत्मा का जो पति है, वही दक्ष प्रजापति है।

'दक्ष' शब्द से 'द' व 'क्ष' वर्ग– परमात्मा– परब्रह्मा है।

'द' अक्षर भूमि वर्ण एवं 'क्ष' अक्षर अग्नि वर्ण का है। इन दोनों अक्षरों में मैत्री भाव है। इसलिए 'दक्ष' शब्द सुसन्गत व देव शब्द है। 'दक्ष शब्द में 'द' षड्भुज है एवं 'क्ष' दशबाहु है। 'द' में दुर्गा बीज है, 'क्ष' में पृथ्वी बीज है। 'द' अक्षर दंत का प्रतिनिधित्व करता है 'क्ष' अक्षर 'क्षय' का प्रतिरूप है। अर्थात् जिसका कभी दांत का 'क्षय' न हो वही 'दक्ष' है। इसीलिए महाराजा दक्ष प्रजापति ने 'दुर्गाजी' के निर्माण में अपने उज्वल मजबूत 'दाँत' के समान दाँत प्रदान किया था तथा 'द' अक्षर दुर्गा बीज का है इसलिए दक्ष ने दुर्गाजी को अपनी 'तलवार' भी प्रदान कर दी। 'द' अक्षर भूमि वर्ण को होकर भूमि स्वामी (राजा) से है तथा 'क्ष' अक्षर अग्नि वर्ण का होकर 'शक्ति' (तलवार) (दुर्गा) से है। दक्ष की शक्ति 'मुक्ति विद्युत' है। 'दक्ष' शब्द सम्पूर्ण परमात्मा है। ईश्वर है। ज्ञान स्वरूप है।

'दक्ष प्रजापति' का शाब्दिक अर्थ– 'दक्ष' अर्थात् निपुर्ण, समस्त ज्ञान से युक्त या परिपूर्ण या यज्ञ या जड़–चेतन दोनों प्रकार के जगत के विधाता या स्वामी से है तथा 'प्रजा' शब्द का अर्थ–जनता प्रजा से लिया जाता है इसी प्रकार 'पति' शब्द का अर्थ–स्वामी, मालिक या राजा से लिया जाता है। इस प्रकार दक्ष + प्रजा + पति के योग से 'दक्ष प्रजापति' शब्द बना है, जिसका सार्थक अर्थ– समस्त ज्ञान में निपुर्ण (परिपूर्ण) जनता या प्रजा के स्वामी अथवा मालिक से है ।

यजुर्वेद चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भेषज संहिता में दक्ष प्रजापित को 'यज्ञ' कहा गया है। जिसके द्धारा समस्त देवता संतुष्ट होते है और जो पर्यावरण को शुद्ध कर कई प्रकार की वायरल व फ्ल्यू नामक बीमारी पर रोक लगाता है जो टायफाइट के कीटाणू को नाश करने वाला व कृमि नाशक होता है। यज्ञ ही हमारे निवास के DNA व RNA को सकारात्मक रूप प्रदान करता है। इसी कारण भारतीय संस्कृति में यज्ञ करने का प्रॉवधान है।

*स्कीम नं. 21, मकान नं. 10,ग्वालटोली, नीमच (म.प्र.) भारत

वृक्षायुर्वे दव वनस्पति शास्त्र में दक्ष प्रजापति को वन सम्पदा का स्वामी माना गया है। दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद का प्रथम आचार्य माना गया है। (भगवान धन्वन्तरी 16 वें आचार्य है) इसी प्रकार प्रजापति ब्रह्मा द्वारा चार वेद को प्रकट किया (लिखा) जिस कारण प्रजापति ब्रह्माजी को प्रथम 'व्यास' क़ी उपाधि दी गई है। जबकि दक्ष प्रजापति को दूसरे नम्बर के 'व्यास' से अलंकृत किया गया है, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने एक लाख अध्याय का 'प्रजापति शास्त्र' लिखा है जबकि 24 वें नम्बर के व्यास ने 'श्रीमद् भागवत' को लिखा है। पुराणों में दी गई दक्ष कथा का उद्भव ऋग्वेदीय कथा में हुआ है। महाराजा दक्ष प्रजापति 'वनस्पति', 'यजुर्वेद' व 'यज्ञ विज्ञान' के महान पंडित व विद्वान हुए है। सभी देवता यज्ञ द्वारा पोषित होते है इसलिए देवताओं के पोषण हेतु अहंकार रुपी पशु गुण का यज्ञ में त्याग कर देव यज्ञ सम्पन्न करवाया है। जिसे भारत वर्ष में प्रत्येक नवरात्रि में अष्टमी का 'महायज्ञ' के नाम से जाना जाता है।

परम पिता बह्मा जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति का विवाह प्रजापति वीरण (पञ्चजन) की परम सुशील सर्वांग शोभना कन्या असिक्री (असि=तलवार) अर्थात् वीरिणी के साथ सर्व देवताओं की उपस्थिति में वैदिक मंत्रों से सम्पन्न हुआ।

महाराजा दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु के प्रथम प्रिय एवं परम भक्त हुए है। माता शक्ति (प्रकृति) के प्रथम उपासक हुए है। जिन्होंने शक्ति (सती) की उपासना 3000 वर्षो तक कर उन्हें 'पुत्री' रुप में प्राप्त किया।

प्रजापति बह्माजी की इच्छानुसार महाराजा दक्ष प्रजापति को वीरिणी से 10 हजार 'हर्यश्वगण' एवं एक हजार 'शबलाश्व' नामक पुत्र प्राप्त हुऐ। जो अपने काका नारद के सम्पर्क से सन्यासी हो गये। जिन्होंने सृष्टि निर्माण में अपने पिता का सहयोग नहीं किया। जिससे दक्ष प्रजापति दु:खी हुऐ। अपने पुत्रों को श्राप दिया जो आगे चलकर गंगा अवतरण का कारण बने एवं गंगा अवतरण के द्वारा जल के स्पर्श से मुक्ति को प्राप्त हुए। परन्तु अपने पिता की सन्त्वना के बाद 'क्षीर सागर' के तट पर 3 हजार दिव्य वर्षो तक माता सती (प्रकृति) की तपस्या कर प्रसन्न कर 'सती' सहित 59 बहनों (शक्तियों) को पुत्री रूप में प्राप्त किया। जिन सभी दक्ष कन्याओं को शिक्षित कर उनका विवाह योग्य देवताओं के साथ कर दिया, जिसमें से 10 दक्ष कन्या धर्मराज के साथ, 13 दक्ष कन्या कश्यप को, 27 दक्ष कन्या (नक्षत्र रूपी) चन्द्र को,1 दक्ष कन्या कामदेव को, 2 दक्ष कन्या कृशाश्वा को, 1 दक्ष कन्या अंगिरा ऋषि को, 4 दक्ष कन्या तार्क्ष्य कश्यम को, 1 दक्ष कन्या भूत को, 1 दक्ष कन्या शिव के साथ ब्याह दी गई।

दक्ष ने सृष्टि संचालन सिद्धांत के सृजन हेतु माता सती (सर्वांगशक्ति शोभना) का विवाह महादेव से कर दिया फिर दक्ष लीलानुसार 'दक्ष यज्ञ' (अहंकार) को भंग करवाकर महादेव के आशीर्वाद से 'दक्ष देव यज्ञ' सम्पन्न करवा कर माता सती के 51 शक्ति अंग (हिन्दी भाषा वर्ण शक्ति) से 51 प्रकृति शक्ति रूपा शक्तिपीठ देव भूमि अजनाभखण्ड पर स्थापित करवाये। जिससे प्रजा को शक्ति उपासना सुलभ हुई। यही सती शक्ति सम्पूर्ण मानव जाति की कुलदेवी या जगत माता है। कल्प भेद में माता सती ने हिमालय पुत्री पार्वती (पर्वत+शक्ति) के रुप में अवतार धारण कर महादेव की पत्नी होकर अपने अनुलेपन से भगवान प्रथम पूज्य श्री गणेशजी की रचना की। जो सृष्टि सभ्यता के विकास क्र म में पहली 'मृदा संस्कृति' का प्रमाण हैं।

दक्ष कन्या अदिति (अखण्ड शक्ति प्रवाह) व दिति का विवाह कश्यप ऋषि के साथ किया। कश्यप ऋषि को अदिति से सूर्य-मनु आदि समस्त वैदिक एवं पौराणिक देवता पुत्र-पुत्री रूप में प्राप्त हुए। आगे माता अदिति से ही सभी अवतारी भगवानजी जन्म लेते है। कल्प भेद में दक्ष प्रजापित को माता प्रसूति (मनु पुत्री) से 24 स्त्री गुण रुपी कन्या प्राप्त हुई। इन 24 दक्ष कन्याओं को भी राजा दक्ष ने शिक्षित कर योग्य देवताओं के साथ ब्याह दी गई जिसमें धर्मराज को 13 कन्या, रुद्र, मरीचि, अंगिरस , पुलस्त्य, पुलह, कृतु , अत्रि ऋषि, वशिष्ट ऋषि, अग्नि देव, भृगु ऋषि व पितृस को एक-एक दक्ष कन्या के साथ विवाह हुआ। (गायत्री छंद के 24 अक्षर) वाल्मिकी रामायण के 24000 श्लोक व शिव पुराण के 24000 श्लोक भी महाराजा दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं की व्याख्या पर आधारित है। विश्वकर्मा जी के गज (फीता) में 24 इंच, भगवान के 24 अवतार, 24 शंकर प्रोक्त सिद्धियां (रावण संहिता), राज व्यवस्था प्रशासन के 24 'पद' (कौटिलीयम अर्थशास्त्रम्), परशुराम के फरसे में 24 अंगुल का माप, 24 व्यास, 24 आयुर्वेद के आचार्य, 24 जैन तीर्थंकर, दिन के 24 घंटे (8 घंटे काम, अर्थ हेतु+8 घंटे की निन्द्रा+8 घंटे का नियमित कार्य), मानव के हाथों कीकलाई में 8 वात + 8 कब्ज+8 पित्त=24, नाड़ी परीक्षा, अण्ड, जल, पृथ्वीं में 24 तत्व, आधुनिक विज्ञान में 8 इलेक्ट्रॉन्स (ब्रह्म तत्व)+8 प्रोटॉन्स (विष्णु तत्व) + 8 न्यूट्रॉन्स (शिवतत्व) =24 प्रकृति के मुख्य तत्व, जमुना नदी पर 24 घाट, 24 केरेट का स्वर्ण धातु (सोना), दत्तात्रेय महाप्रभु के 24 गुरु, अशोक चक्र में 24 तिल्लीयां, वास्तु शास्त्र में 24 मुख्य द्वारा, 24 प्रकार के सोम (सुश्रुत संहिता), मानव की नाभी (पेट) में 24 नाड़ियों का स्फूटन, मानव नाभि का तापमान 24^0 डिग्री बना रहना, राम के चरण चिन्हों में 24 चिन्ह, सीता के चरण चिन्हों में 24 चिन्ह का होना सब दक्ष कन्याओं की शक्ति एवं (सृष्टि) सिद्धांत की व्याख्या को बनाए रखना या याद रखने हेतु है। जो सृष्टि संचालन के मुख्य घटक है। जो दक्ष प्रजापति के वेद, यज्ञ, योग, गृह-नक्षत्र, बह्मण्ड, अन्तरिक्ष, पर्यावरण, ज्योतिषी, खगोल, समुद्र, वास्तु, अर्थ (पृथ्वीवाणिज्य) संघ तथा समस्त मंत्र, तंत्र, जंत्र, यंत्र ज्ञान-विज्ञान के स्वामी होने का प्रमाण है जिस कारण दक्ष प्रजापति उत्पत्ति, प्रलय, रक्षा व संहार आदि करने में सामर्थ्यवान हुऐ है तथा जो वर्तमान ज्वलन्त समस्याओं के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के सुनियोजित प्रबंधक या प्रवर्तक हुवे हैं। दक्ष प्रजापति ने मानव जीवन के चार आदर्श लक्ष्य जो कि **पहला**- बह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास, **दूसरा**- धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष, **तीसरा**-साधना, स्वाध्याय, संयम व सेवा **चौथा**- शरीर बल, मनोबल, आत्मबल व बह्मबल आदि को प्राप्त करने के लिये अपनी स्मृति में (9x9) 81 (8+1=9) उपदेश दिये है, जिनके पालन से मानव पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित करने में सामर्थ्यवान होकर महामानव व विश्व गुरु बन जाता है। दक्ष स्मृति के 7 अध्याय, प्रजापति विवाह संस्कार पद्धति के 7 परिक्रमा या सात फेरें की व्याख्या करता है। जो गृहस्थ आश्रम के लिए एक अति उत्तम सुप्रसिद्ध स्मृति है। जिस दक्ष स्मृति को प्रत्येक गृहस्थी को वाचन करना चाहिए। सूर्य के रथ में सात प्रकाश रुपी घोड़े, 7 समुद्र, 7 द्वीप, सप्त ऋषि, 7 लोक आदि सभी दक्ष स्मृति के सात अध्यायों से जुड़ा हुआ है जो एक गृहस्थ को उत्तम जीवन शैली प्रदान करता है। महाराजा दक्ष देव भूमि पर अपने अजनाभ खण्ड नामक देश पर सुनियोजित सिद्धांत के प्रवर्तक व समस्त जाति, वंश, धर्म संस्कृति व ज्ञान के जनक होने के साथ कई दिव्य वर्षों तक राज्य किया है। जो भारतीय संस्कृति के आधार स्तम्भ है। कालांतर में जिनके द्वारा कई धर्म की शाखाऐं भी विश्व में आस्तित्व में आयी है।

मानव विकास एवं सभ्य समाज की रचना में पुत्र प्रचेता प्रजापति (प्रचेता-प्रकृष्ट चित्त वाला) के पुत्र रत्नाकर प्रजापति प्राप्त हुए जो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि हुऐ है जिन्होंने 'वाल्मीकि रामायण' लिखी है। आगे

दक्ष प्रजापति को 16 पुत्र प्राप्त हुऐ है। जिन्होंने 16 ग्राम पाये (बसाये) थे। इन 16 पुत्रों को भी 16 गाँव की उपाधि प्राप्त हुई थी।

चट्टोऽम्बुली तैलवारी, पोडारिर्हडगूढ कौ।
भूरिश्च पालधिश्चैव पर्कटि: पुषली तथा।।
मुलग्रामी च कोयारी पलसायी च पीतक:।
सिमलायी तथा भट्ट इमे काश्यपसंज्ञका:।।

– जाति भास्कर 172

(1) चट्ट (2) अम्बुली (3) तेलवटी (4) पोडारि (5) हड (6) गूढक (7) भूरि (8) पालधि (9) पर्कटि (10) पुषाली (11) मूलग'ामी (12) कोयारि (13) पलसायी (14) पीतक (15) सिमलायी तथा (16) भट्ट ये 16 पुत्र कश्यप गोत्री दक्ष प्रजापति के कुमार हुए है, जो अपने-अपने क्षेत्र के स्वामी थे।

आगे दक्ष प्रजापति के पुत्रों के गोत्र प्रवर (प्रवर्ग्य साधक) हुए है जिनके नाम (गोत्राकार ऋषि) निम्न है- (1) आत्रेये (2) गाविष्ठर (3) पूर्वातिथि (4) व्यास (5) कश्यप (6) प्रजापति (7) मारिषा या यज्ञकर्ता ऋषि।

अजनाभ खण्ड में काबूल नदी के पश्चिम से सिंध नदी से लेकर सम्पूर्ण अखण्ड भारत सम्मिलित था। जिनकी राजधानी वर्तमान स्थान -कंनखल हरिद्वार (उत्तरांचल) गंगा नदी के तट पर है। जिसे इतिहासकार ..गंगा घाटी संभ्यता,हडप्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं जो कि 'दक्ष कालीन सभ्यता' होकर 'दक्षद्वीप' है जहां मृदा संस्कृति के प्रमाण खुदाई में आज भी मिलते हैं।

स्तुति मंत्र -

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यों,विश्वारुपाणि परिता बभूव।
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयीणाम्।।

-ऋग्वेद

भावार्थ- हे प्रजापति देव ! तुम से भिन्न दूसरा कोई इस पृथिव्यादि भूतों तथा सब पदार्थों एवम् रूपों से अधिक बलवान नहीं हुआ है, अर्थात् तुम्हीं सर्वोपरि बलवान हो। अतएव हम जिन कामनाओं से तुम्हारा यजन (स्तुति) करते हैं, वह हमें प्राप्त हो, जिससे हम सब धनों के स्वामी बनें।

संदर्भ ग्रंथ सूची : -

1. वेदकालीन समाज-डॉ. शिवदत्तज्ञानी, उज्जैन।
2. प्रजापति का तत्व दर्शन- डॉ. ईश्वरलाल प्रजापति, नीमच।
3. नक्षत्र चिकित्सा ज्योतिषम्- अभय कात्यायन, वाराणसी।
4. पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश-खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुम्बई।
5. अष्टादश स्मृति- पं. सुन्दरलालजी त्रिपाठी,
6. शक्ति तत्व एवं शाक्त साधना- डॉ. श्यामाकांत द्विवेदी, वाराणसी
7. 'प्रजापति स्मृति' मुम्बई।
8. 'दक्ष स्मृति', मुम्बई।
9. महानिर्वाण तंत्र, मुंबई।
10. ऋग्वेद, यजर्वे द-आर्य समाज संस्था पुष्कर रोड, अजमेर (राज.)
11. शिव पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण।
12. आयुर्वेद प्रर्वतक देवता, रघुवीर शरण शर्मा, वाराणसी (उ.प्र.)
13. तंत्र दुर्गा सप्तशती- डॉ. रामचन्द्रपुरी, दिल्ली।
14. संस्कृत- साहित्य-कोश-डॉ. राजवंश सहाय 'हीरा'
15. वृक्षायुर्वेद,डॉ. कृष्ण 'जुगनू' वाराणसी
16. दक्ष प्रजापति की पुत्रियों और उनके पतियों के नाम (हिन्दी) धर्म संसार दिनांक 9 अक्टूबर 2016
17. ऋग्वेद 10-143 में दक्ष पुत्रों का वर्णन
18. ऋग्वेद 1-15-3 इंद्र द्वारा दक्ष पुत्रों की रक्षा
19. ऋग्वेद 10-143-1 में अश्विनी कुमारों द्वारा दक्ष पुत्रों को वृद्ध अवस्था से तरुण अवस्था प्रदान करना आदि

20. **संबंधित संस्थाऐं -**

1. श्री दक्ष वेलफैयर एण्ड चेरिटेबल सोसायटी, होशियारपुर (पंजाब)।
2. महाराजा दक्ष प्रजापति वरदिया (कुम्हार) समाज समिति, नीमच।

****

Climate Change: A Health Hazard

Dr. Kiran Yadav *

Introduction - Climate change endangers human health, affecting all sectors of society, both domestically and globally. The environmental consequences of climate change, both those already observed and those that are anticipated, such as sea-level rise, changes in precipitation resulting in flooding and drought, heat waves, more intense hurricanes and storms, and degraded air quality will affect human health both directly and indirectly. Addressing the effects of climate change on human health is especially challenging because both the surrounding environment and the decisions that people make influence health. For example, increases in the frequency and severity of regional heat waves—likely outcomes of climate change—have the potential to harm a lot of people. Certain adverse health effects can probably be avoided if decisions made prior to the heat waves result in such things as identification of vulnerable populations such as children and the elderly and ensured access to preventive measures such as air conditioning. This is a simplified illustration; in real-life situations a host of other factors also come into play in determining vulnerability including biological susceptibility, socioeconomic status, cultural competence, and the built environment. In a world of myriad "what if" scenarios surrounding climate change, it becomes very complicated to create wise health policies for the future because of the uncertainty of predicting environmental change and human decisions. The need for sound science on which to base such policies becomes more critical than ever.

Categories of human health consequences of climate change:

1. Asthma, Respiratory Allergies, and Airway Diseases
2. Cancer
3. Cardiovascular Disease and Stroke
4. Foodborne Diseases and Nutrition
5. Heat-Related Morbidity and Mortality
6. Human Developmental Effects
7. Mental Health and Stress-Related Disorders
8. Neurological Diseases and Disorders
9. Vector borne and Zoonotic Diseases
10. Waterborne Diseases
11. Weather-Related Morbidity and Mortality

Global climate change is visibly and profoundly affecting oceans, which in turn, affects human health. The warming of ocean waters contributes to increases in incidence and severity of toxic algal blooms, alterations in aquatic and estuarine food webs and seafood quality and availability, and effects on sentinel aquatic species.High concentrations of carbon dioxide in the atmosphere increase the amount that is dissolved into the ocean, leading to acidification and disruption of ecosystems. As large portions of the world's populations, including those in the United States, live in coastal areas, and many depend on marine protein for daily subsistence, the consequences of perturbing delicate ocean and coastal systems will be far-reaching.

Climate changes including increased heat in certain arid and semi-arid parts of the United States can dramatically alter existing ecosystems, presenting new challenges to agricultural production and coastal ecosystems, with consequences for food quality and availability. Changes in plant habitat can result in reduced availability of grazing lands for livestock. Climate changes also are directly associated with many pest habitats and disease vectors, and changes in temperature can extend or reorient habitats such that organisms are introduced to new geographic areas or life cycles are altered, requiring increases in pesticide use or use in new areas to achieve the same yields. Global warming is also causing shifts in the ranges of disease vectors that require specific environments to thrive (for example, Lyme disease), and increasing the threat and incidence in humans of waterborne, vector borne and zoonotic (those transferred from animals to humans) diseases.

There is abundant evidence that human activities are altering the earth's climate and that climate change will have significant health impacts both domestically and globally. While all of the changes associated with this process are not predetermined, the actions we take today will certainly help to shape our environment in the decades to come. Some degree of climate change is unavoidable, and we must adapt to its associated health effects; however, aggressive mitigation actions can significantly blunt the worst of the expected exposures.Still, there will be effects on the health of people in the United States, some of which are probably already underway. As great as the domestic risks to U.S. public health are, the global risks are even

***Associate Professor (Zoology) Maharana Pratap Govt P.G. College, Hardoi (U.P.) INDIA**

greater.

Climate change and health issues transcend national borders, and climate change health impacts in other countries are likely to affect health in the United States as well. Famine, drought, extreme weather events, and regional conflicts—all likely consequences of climate change—are some of the factors that increase the incidence and severity of disease, as well as contributing to other adverse health impacts, making it imperative to address climate change-related decision making at local, regional, national, and global levels. The complicated interplay of these and other factors must be considered in determining the scope and focus of both basic and applied research on climate change and health.

References:-

1. Macdonald, R.W., T. Harner, and J. Fyfe, Recent climate change in the Arctic and its impact on contaminant pathways and interpretation of temporal trend data. Sci Total Environ, 2005. 342(1-3): p. 5-86.
2. Macdonald, R.W., et al., How will global climate change affect risks from long-range transport of persistent organic pollutants? Human and Ecological Risk Assessment, 2003. 9(3): p. 643-660.
3. Jones, L., et al., Severe mental disorders in complex emergencies. Lancet, 2009. 374(9690): p. 654-61.
4. Kalkstein, L.S. and J.S. Greene, An evaluation of climate/mortality relationships in large U.S. cities and the possible impacts of a climate change. Environ Health Perspect, 1997. 105(1): p. 84-93.
5. Kang, D., et al., Cancer incidence among pesticide applicators exposed to trifluralin in the Agricultural Health Study.Environ Res, 2008. 107(2): p. 271-6.
6. Kar, B.R., S.L. Rao, and B.A. Chandramouli, Cognitive development in children with chronic protein energy malnutrition. Behav Brain Funct, 2008. 4: p. 31.
7. Karl, T., J. Melilo, and T. Peterson, Global Climate ChangeImpacts in the United States. 2009, New York: Cambridge University Press.
8. Curriero, F.C., et al., The association between extreme precipitation and waterborne disease outbreaks in the United States, 1948-1994. Am J Public Health, 2001. 91(8): p. 1194-9.
9. D'Amato G. and L. Cecchi, Effects of climate change on environmental factors in respiratory allergic diseases. Clinical and Experimental Allergy, 2008. 38(8): p. 1264-1274.
10. D'Amato G., et al., The role of outdoor air pollution and climatic changes on the rising trends in respiratory allergy. Respiratory Medicine, 2001. 95(7): p. 606-611.
11. Davido, A., et al., Risk factors for heat related death during the August 2003 heat wave in Paris, France, in patients evaluated at the emergency department of the Hopital Europeen Georges Pompidou. Emerg Med J, 2006. 23(7): p. 515-8.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

सेवासदन उपन्यास में आधुनिक जीवन बोध

डॉ. जगमोहन सिंह गुर्जर *

प्रस्तावना – प्रेमचंद का प्रारम्भिक साहित्यिक जीवन बहुत कुछ अस्पस्ट एवं उलझा सा रहा है। अमृतराय ने प्रेमचंद सम्बंधी जो नवीन साहित्यिक-सामग्री प्रकाशित की है, उससे भी सभी समस्याओं का निराकरण नही होता। 'सेवा सदन' के पूर्व उनके द्धारा लिखे गए सभी उपन्यासें की संख्या क्रम तथा लेखन तिथि विवादास्पद रही है, सेवासदन तथा उनके कुछ बाद के उपन्यासें में भी इसी प्रकार की स्थिति दिखाई देती है। यह स्पष्ट है कि प्रेमचंद उर्दू से हिन्दी में आये थे। अत: यह बात स्पष्ट है कि प्रेमचंद ने अपने उपन्यास पहले उर्दू में लिखे बाद में उनका हिन्दी में अनुवाद किया गया। प्रेमचंद ने 27जनवरी 1921 को अपने मित्र इम्तयाज अली को लिखा था 'हम खुर्मा व हमसवाव' किशना वगरैह मेरी इब्दताई तसानीफ है। पहली पुस्तक लखनऊ के नवल प्रेस से प्रकाशित हुई, दूसरी पुस्तक बनारस के मेडिकल हाल प्रेस ने प्रकाशित की। सन् 1904 में एक हिन्दी नॉविल 'प्रेमा' लिखकर इण्डिन प्रेस से प्रकाशित कराया।

'हस- के फरवरी सन् 1932 के अपने आत्मकथात्मक लेखन में प्रेमचंद ने लिखा है कि उन्होंने 1901 में अपना पहला उपन्यास लिखना आरम्भ किया और वह 1902 में प्रकाशित हुआ। इसके विपरीत 7 सितम्बर 1934 को डॉ. इन्दुनाथ मदान को लिखे अपने पत्र में प्रेमचंद ने अपनी प्रथम पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1903 में बताया गया है। इस प्रकार स्वयं प्रेमचंद ने ही अपने उपन्यासें के बारे में विरोधी विचारों की जानकारी दी है। ऐसी स्थिति में प्रेमचंद के उपन्यासों की लेखन तिथि, प्रकाशन तिथि, उनकी संख्या एवं क्रम का निर्धारण बड़ी सतर्कता की उपेक्षा रखता है। इस प्रकार प्रेमचंद के उपन्यासों के प्रकाशन की तिथि संख्या एवं क्रम के बारे में विरोधी विचार होने पर भी कुछ संकेत उनकी विश्वसनीयता बताते है जिससे उनके काल, तिथि एवं क्रम का अनुमान लगाया जा सकता है।

सेवासदन को प्रेमचंद के उपन्यासों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेमचंद को हिन्दी जगत में उपन्यासकार के रूप में प्रंशसनीय बनाने में 'सेवासदन' का महत्वपूर्ण स्थान है। सेवासदन से पूर्व प्रेमचंद पांच उपन्यास लिख चुके थे। मगर उनमें से केवल 'प्रेमा' ही हिन्दी में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने 24 जनवरी 1917 को लिखे अपने एक पत्र में इसी और संकेत करते हुए लिखा है कि किस्सा दिलचस्प है और मुझे ऐसा खयाल होता है कि मैं अबकी बार नॉविल नवीसी में भी कामयाब हो सकूगां। इस प्रकार प्रेमचंद का अनुमान सही साबित हुआ और हिन्दी लेखकों और आलोचकों ने उसका स्वागत किया।

प्रेमचंद ने अपने 24 अप्रेल 1919 के पत्र में बडे आह्लाद के साथ मुंशी दयानारायण निगम को इस सफलता की सूचना देते हुए लिखा 'आप यह सुनकर खुश होंगे कि मेरे हिन्दी नाविल ने खूब शोहरत हासिल की है और अक्सर नक्कादों ने उसे हिन्दी जवान का बहतरीन नॉविल कहा है।'

इस प्रकार 'सेवा सदन' में पहली बार प्रेमचंद ने मानवतावादी धरातल पर वेश्या का चित्रण किया है और उसे घ्रणास्पद न मानकर उसके प्रति सहानुभूति अभिव्यक्त करके उसका जीवन सुधारने के प्रयास करने का अवसर प्रदान किये है। आलोचक उसे पाश्चात्य उपन्यासों की तुलना में उपन्यास नाम को सार्थक बनाने वाली हिन्दी की प्रथम रचना स्वीकार करते है। इस प्रकार 'सेवासदन' हिन्दी का प्रथम आधुनिक और साहित्यिक उपन्यास के रूप में प्रतिष्ठित हुआ।

आकार की दृष्टि से उपन्यास में लेखक ने सुमन के वेश्या बनने की घटनाओं और वेश्यावृत्ति त्यागकर विधवाश्रय में पहुँचने की कथा के लिए विभिन्न परिच्छेदों के माध्यम से कथा को उद्घाटित करने के लिए परिच्छेदों की संख्या दी है। इनकी कथा लगभग तेइस परिच्छेदों में फैली पडी है। वास्तव में सुमन की कथा, उसके वेश्या होने की कथा उसके सामाजिक एवं पारिवारिक प्रतिक्रिया कथा के सम्मिलन से पूर्ण होती है। प्रेमचंद ने सेवासदन उपन्यास को आधुनिक संदर्भो में प्रस्तुत करने का पूर्ण इमानदारी के साथ परिचय दिया हैं। प्रेमचंद के विचार आज के संदर्भ में भी प्रांसगिक है कि एक वेश्या की समस्या को रेखांकित करके समाज में फैली हुई इस बुराई को सेवासदन के माध्यम से एक नवीन विचार के रूप में जगह मिली है। सेवासदन में वेश्या समस्या के समाधान के लिए वेश्याओं को नगर से दूर बसाने, वेश्या नाच का बहिष्कार करने तथा वेश्या पुत्रियों के लिए 'सेवासदन' की स्थापना में लेखक ने युग का चित्रण किया है। प्रेमचंद ने सेवासदन में वेश्या जीवन के अतिरिक्त दहेज-प्रथा, रिश्वत, पुलिस व्यवस्था, अनमेल विवाह, धार्मिक स्थिति, विवाह में अपव्यय, शिक्षित वर्ग का रहन-सहन फैशन, अंग्रेजी शिक्षा, ठेकदार, सम्पादक आदि सामाजिक जीवन की अनके स्थितियों का चित्रण किया है। इन सामाजिक विसंगतियों से युग का सामाजिक-जीवन उभर कर आया है।

प्रेमचंद ने उपन्यास में देशकाल चित्रण में भी उन्होंने अपने युग की विधमान सामाजिक विद्धुपताओं अव्यवस्थाओं आदि को रेखांकित किया गया है। 'सेवासदन' प्रेमचंद की एक ऐसी कृति है जिसमें उद्देश्य की दृष्टि अत्यन्त पैनी दिखाई देती है।

यही कारण है कि विभिन्न आलाचकों ने उद्देश्य की भमि का भिन्न-भिन्न रूपों में विवेचन किया है।

* व्याख्याता (हिन्दी) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दौसा (राज.) भारत

वृजरत्नदास के अनुसार 'दहेज प्रथा बेमेल विवाह हो, परिवार में कितना अनर्थ हो सकता है इसी का अतिरंजित वर्णन है।'

नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार 'प्रेमचंद ने इस उपन्यास में नारी समाज के प्रश्नों को उठाया है, उनसे सम्बंध रखने वाली समस्याओं पर विचार किया है, विशेषकर वेश्या-समाज के सुधार का लक्ष्य प्रेमचंद के सम्मुख रहा है। ' इस प्रकार प्रेमचंद सामाजिक विशमतओं तथा विडम्बनाओं का चित्रण उपन्यास का मूल उद्देश्य रहा है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रेमचंद ने सामाजिक सुधार एवं विसंगतियों का निराकरण करने की उपन्यास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उपर्युक्त विवेचन के बाद हम कह सकते है कि प्रेमचंद ने उपने उपन्यासों में कथ्य के साथ भाषा शिल्प विधि का भी अच्छा प्रयोग किया है। उनके उपन्यासों में भाषा कौशल का एक सफल प्रयास हैं। प्रेमचंद अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे और इसलिए उनके साहित्य में भाषा का मिश्रण रूप देखने को मिलता है। पात्रों के चरित्र चित्रण में प्रेमचंद ने एक श्रेष्ठ चितेरे का कार्य किया है। चाहे कही कही उनके उपन्यासों में पात्र अपनी भाषा का सही प्रयोग नहीं करते हैं लेकिन प्रेमचंद ने अपने अधिकतर उपन्यासों में भाषा का पात्रानुकूल बनाने का भरसक प्रयास किया है और इस प्रयास में वे सफल हुए प्रतीत होते है ।

इस तरह प्रेमचंद ने अपने युग की उन परिस्थितियों का चित्रण किया है जिनमें मानव स्वार्थी, अहंकारी अत्याचारी तथा एक दूसरे के प्रति शोषण का चक्र मानव को अंधकार मेंढकेलने का प्रयास कर रहा था। ग्रामीण संस्कृति का उनके उपन्यासों में सफल प्रयोग हुआ है। सामाजिक विद्रुपता के साथ-साथ प्रेमचंद अपने अन्य उपन्यासों में एक गांव के किसान, मजदूर शोशित एवं पीड़ित की समस्याओं को भलि-भांति अपने उपन्यासों में उकेरा है। समय की राजनैतिक परिस्थितियों में राजनेता अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर किस तरह नरहत्या में लगे हुए थे और समाज को किस तरह से खोखला बनाने के प्रयास में जुटे हुए थे। इन सभी समस्याओं को प्रेमचंद ने व्यापक धरातल पर अपनी साहित्यिक रचनाओं में उद्धारित किया है। अंत में हम कह सकते है कि प्रेमचंद ने एक संवेदनशील कथाकार थे उन्होंने अपने समय को पूर्ण इर्मानदारी के साथ चित्रित करने का प्रयास किया है। अतएव वे एक लेखक ही नहीं थे बल्कि एक महान संत समाज सुधारक और राष्ट्रसेवी रचनाकार थे। जिनके मन में दया सहानुभूति, प्रेम, करूणा आदि के विचार कूट-कूट कर भरे थे। अत: प्रेमचंद साहित्य की दुनिया में स्मरणीय रहेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रेमचंद - साहित्य का उद्देश्य पृष्ठ -2
2. डॉ. कमल किशोर गोयन का - प्रेमचंद के उपन्यासों का शिल्प विधान पृष्ठ - 112
3. डॉ. कमल किशोर गोयन का - प्रेमचंद के उपन्यासों का शिल्प विधान पृष्ठ - 148
4. डॉ. कमल किशोर गोयन का - प्रेमचंद के उपन्यासों का शिल्प विधान पृष्ठ - 152

****

Algorithm Methods(Single Black Hole Attack and Cooperative Black Hole Attack)

Dharmendra Kumar Meena *

Introduction - Black hole Attack is an error node procedure its routing protocol to promote itself having the shortest path towards the destination node. At the point route is set up, then error node forwards it to the malicious attacks wants address.

The Black Hole Attack must make RREP with Destination arrangement more noteworthy than the destination arrangement of the receiver node and sender node trusts that black hole node and additional interconnects with blackhole node in its place of real destination node. This mischievous frequently harm nodes interface and thus waning all asset usage in accumulation to losing packets. Here Blackhole Attacks are categorized into two categories.

Single Black Hole Attack: In this scenario, single blackhole attacks are represent which acts as malicious node within the networks topology.

Cooperative Black Hole Attack: In this scenario, cooperative blackhole attacks are represent which acts as malicious node and provide the false reply to neighbor node within the networks topology shows in (Figure 3.2).

Algorithm-I: Secure-AODV

Assumption: RREP header is modified with additional field that is Speed of node.

Step 1: Source S broadcasts RREQ message to the network.

Step 2: If Destination D replies RREP then S will start transmission.

END

Step 3: If intermediate node (say B) replies with RREP and when packet reaches node Y's preceding node@ (say A), it checks the following:

if (Speed of Node** > speed_threshold or SequenceNo** > seq_no_threshold)

GOTO Step 4. else

GOTO Step 5.

Step 4: If (hopcount** >= 2)

Node X will send a Modified Hello signal (MHELLO) with HopCount equal to 2 (in case hopcount** = 2)

or

HopCount equal to 3 (in case hopcount** > 2) to a Node@@ (say Z) which is few hops (equal to hopcount**)

away from A.

If A receives acknowledgment from Z successfully then A forwards RREP to S and S will transmit the data.

Else

Node next to B is Blackhole and an alert signal will be transmitted by A to S. Else

Node B is Blackhole node and an alert signal will be transmitted by Ato S. Step 5: A forwards RREP to S and S will transmit the data.

Note:-

1. MHELLO is same as HELLO packet with hop count = hopcount**.
2. Threshold value is updated every time intermediate node receives a RREQ packet.
3. Threshold value of sequence no is calculated as sequence_number_threshold = sequence_number(of RREQ packet) * hop count
4. Threshold value of node speed is taken as speed_threshold = 100 m/s

** all the values have to be taken from the RREP received from intermediate node B.

@ preceding node A is in the direction in which RREP is traversing from B towards S.

@@ Z node is in the path through which RREP packet has reached B.

Algorithm-II: RSA Algorithm

RSA algorithm is public key cryptographic algorithm that makes use of 2 keys namely public key and private key [5]. If RSA keys do not exist, they need to be generated. The key generation process is usually slow but it is performed seldom. It involves three steps: Key Generation, Encryption and Decryption [5].

Key Generation: Prime integers are used for key generation.

*SBP Government College, Dungarpur (Raj.) INDIA

1. n =p*q (n is used as modulus for both public key and private key)
2. Compute ij(p*q) = (p í 1)*(q í 1).
3. Choose an integer e such that 1 < e <ij(p*q), and GCD of e and ij(p*q) must be 1.

- e is released as the public key exponent.
- e having a short bit.

4. Determine d (using modular arithmetic) which satisfies congruence relation. d*e =1(mod(ij(p*q)) d is kept as the private key exponent

Encryption: Destination node transmits its public key (n, ,e) to Source node and keeps the private key secret then source wants to send message M to Destination.

It first turns M into an integer 0 < m < n by using an agreed-upon reversible protocol known as a padding scheme. It then computes the cipher text c corresponding to:

C= m^2 (mod n)

Decryption: Destination node can recover m from c by using its private key exponent d by the following

Computation: Given m, Destination can recover the original message M by reversing the padding scheme.

References:-

1. V.A. Hiremani and M. M Jadhao, “Eliminating Cooperative Black hole and Gray Hole using Modified EDRI Table in MANET,” IEEE,2013.
2. G. Wahane and S. Lonare, “Technique For Detection of Cooperative Black Hole Attack In MANET,” 4th ICCCNT 2013, July 4-6, 2013, Tiruchengode, India.
3. Trivedi, A. K., Arora, R., Kapoor, R., & Sanyal, S. (2009). Mobile ad hoc network security vulnerabilities, In Encyclopedia of Information Science and Technology, Second Edition (pp. 2557-2561), IGI Global.
4. Eriksson, J., Krishnamurthy, S. V., & Faloutsos, M. (2006, November). Truelink: A practical counter measure to the wormhole attack in wireless networks. In Network Protocols, 2006. ICNP’06. Proceedings of the 2006 14th IEEE International Conference on (pp. 75-84). IEEE.

****

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद : समस्या एवं निदान

डॉ. भरत लाल मीणा *

प्रस्तावना – भारतीय राजनीति के परिवर्तित परिदृश्य में क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग मे एक गंभीर चुनौती बन गई है। क्षेत्रीयतावाद की प्रवृति को समाप्त करने और देशवासियों को राष्ट्र के प्रति निष्ठावान होने की दृष्टि से हमारे संविधान में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था है। फिर भी कुछ भारतीयों के मस्तिष्क में भारतीय नागरिक होने की अपेक्षा, बंगाली, बिहारी, गुजराती या पंजाबी आदि होने की चेंतना अधिक परिलक्षित होती है। यह क्षेत्रीय संकीर्णता हमारी राष्ट्रीयता को विशाक्त एवं विभक्त करने की कुचाल बन रही है, जो एक विचारणीय प्रश्न है ?

क्षेत्रीयतावाद आज भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में एक अत्यन्त व्यापक घटक है। आधुनिक युग में संचार व्यवस्था के नये साधनों, अंग्रेजी शासन व्यवस्था की नीतियों, स्वतंत्रता के पश्चात्, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आदि क्षेत्रीयतावाद को अधिक बढ़ावा दिया है। इसलिए क्षेत्रीयतावाद के आद्योपान्त और सम्यक् विवेचन के पूर्व यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि यह किन कारणों से उभरा है ?[1]

क्षेत्रीयतावाद विभिन्नता का उत्पाद है। राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद अनेक क्षेत्रों में अलगाव का मनोभाव बना हुआ है। महाराष्ट्र के विदर्भ या मराठवाड़ा, गुजरात में सौराष्ट्र, बिहार में झारखंडर, मध्यप्रदेश में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल में गोरखालैण्ड तथा जम्मू कश्मीर में लद्दाख की माँग इसी मनोवृति का सहज परिणाम है।[2]

सांस्कृतिक विभिन्नता के परिणामस्वरूप क्षेत्रीयतावाद को प्रोत्साहन मिला है। कुछ राज्यों को अपनी भाषा और संस्कृति पर बड़ा गर्व है। इसी आधार पर वर्षो पूर्व मद्रास में द्रविडमुनेत्र कडघम ने भारतीय संघ से पृथक होने की लालसा को संजोया है।

वर्तमान में आन्ध्रप्रदेश में नायडू की सरकार तेलगू भाषा और तेलगू संस्कृति को गौरवान्वित करने के आधार पर अपनी राजनीति चला रही है। असम में असमगण परिषद् भी असमी संस्कृति की रक्षा के लिए प्रयत्नशील व संघर्षरत है।

सामाजिक अन्याय और जातिवाद के आधार पर भी क्षेत्रीयता की प्रवृति बढ़ी है। हरियाणा और महाराष्ट्र में क्षेत्रीयता की प्रवृति में जाति एक भयावह सिद्ध हुई है। बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश के आदिवासियों द्वारा झारखण्ड, छत्तीसगढ़ तथा उत्तरप्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों की जनता द्वारा उत्तराखण्ड की माँग सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन के उदाहरण है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीयतावाद के राजनैतिक, भौगोलिक और करिश्माई व्यक्तित्व आदि कारक भी उत्तरदायी है।[3]

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयातावाद की प्रवृति के अनेक रुप है, जिसमें भारतीय संघ से पृथक होने की माँग, अपने लिए पृथक राज्य की माँग, क्षेत्रीय भाषायी विवाद, अन्तर्राज्यीय विवाद, क्षेत्रीय आर्थिक टकराव, राजनैतिक नेतृत्व और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व प्रमुख है, परन्तु इनमें से आज क्षेत्रीयतावाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष पृथक् राज्य की माँग है जो भारतीय राजनीति को प्रभावित कर देश की एकता एवं अखण्डता को खतरा उत्पन्न कर रहा है। जिस पर विचार करना आवश्यक है।[4]

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता का सर्वाधिक आत्मघातक रूप पृथक् राज्य की माँग है, आर्थिक पिछड़ापन, जाति, भाषा, धर्म आदि को लेकर विभिन्न क्षेत्रों द्वारा पृथक् राज्यों की माँग के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष संघीय इकाइयों द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा करने की माँग है। इसी माँग के अनुसार सन् 1970 में हिमाचल प्रदेश, जनवरी, 1972 में त्रिपुरा–मणिपुर, 1967 में अरूणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। लेकिन भाषाई राज्य की माँग को पूर्ण करने के लिए सन् 1956 में राज्य पुनगर्ठन आयोग कुछ हद तक उत्तरदायी माना जाता है। क्योंकि भाषागत राज्यों की माँग ने राष्ट्रव्यापी अंसतोष को जन्म दिया, इसके द्वारा क्षेत्रीय भावनाओं को प्रोत्साहन मिला जिसके परिणास्वरूप सन् 1960 में बम्बई राज्य का विभाजन कर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना की गई। तत्पश्चात् सन् 1966 में पंजाब राज्य का पुनगर्ठन कर पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ को संघीय प्रदेश बनाया गया। सितम्बर 1968 में असम पुनगर्ठन की योजना घोषित की गयी थी जिसमें राज्य के पहाड़ी लोगों के लिए पर्याप्त रुप से स्वायत शासन व्यवस्था दी गई थी। असम राज्य के अंतर्गत मेघालय स्वायतशासी राज्य स्थापित होने पर सन् 1971 में त्रिपुरा–मणिपुर, सन् 1975 में सिक्किम, 1986 में मिजोरम तथा 1987 में विभिन्न कारणों से गठित भारत संघ में 25 राज्य हैं तथा 7 केन्द्र शासित प्रदेश कार्यान्यवन के बाद भी विभिन्न राज्यों में पृथक् राज्यों की माँग उठ रही है तथा आंदोलन हो रहे हैं जो भारतीय राजनीति के समक्ष एक गहन चुनौती है।[5]

प्राय: छोटे राज्यों की माँग के पीछे अधिक ठोस यथार्थवादी कारण उतने नही होते जितने की भावानात्मक होते है। स्थानीय नेता जनभावनाओं को उत्तोजित करके अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए समय–समय पर अलग राज्य की माँग उठाते रहते है जिससे एक राजनीतिक संस्कृति उत्पन्न होती है, लेकिन यदि एक ही राज्य के दो भिन्न क्षेत्रों के विकास में जमीन–आसमान का अंतर तथा विषमता चरम सीमा पर हो तो उनकी इस भावना को सबल आधार मिल जाता है।

प्रश्न छोटे राज्यों के निर्माण का नहीं है बल्कि राज्यों के आर्थिक विकास का है जो केवल उन्हें छोटे बना देने से हल नहीं हो सकता है इसके लिए आवश्यक है कि भूमि सुधार पर जोर दिया जाये। वहाँ स्थानीय उत्पादों के

* सह–आचार्य (राजनीति विज्ञान) एल.बी.एस. राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली (राज.) भारत

लिए बाजार विकसित किए जायें। वहाँ स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार विकसित किए जायें और जितने भी पिछड़े हुए राज्य हैं उनके विकास के लिए एक समन्वित नीति एवं योजना तैयार की जाये तथा राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवं वैधानिक शक्तियों का यथासंभव विकेन्द्रीकरण किया जाये। वास्तव में पिछड़े क्षेत्रों के लोगों में जो उत्पीड़न का भाव समाहित हो गया है, उसे समाप्त करके उस क्षेत्र का विकास करना तथा वहाँ के लोगो को रोजगार और शिक्षा उपलब्ध कराकर छोटे राज्य की माँग को कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाये तो यह सब हो पाना यदि असंभव नहीं तो कठिन सा अवश्य दिखाई देता है क्योंकि आज प्रत्येक क्षेत्र आलगाववाद की ज्वाला में धधक रहा है जिसके दुष्परिणाम स्वाभाविक हैं।

क्षेत्रीयता और प्रांतीयता की भावनाएँ जब राष्ट्रीय हितों से टकराती है तो देश की एकता और उसकी अखण्डता के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। इस शाश्वत सत्य का प्रमाण ढूँढ़ने के लिए इतिहास के पन्ने उलटने की आवश्यकता नहीं है। हाल के वर्षों में एशिया में ही क्षेत्रीयता और प्रांतीयता की भावना से कई देशों के टुकड़े हुए है। एक बार अगर यह जहर फैल जाये तो समस्त राष्ट्रीय जीवन को विशाक्त बनाकर छोड़ता है। हमारे देश में समय-समय पर क्षेत्रीयता की भावना उठती रही है। भाषायी विवाद जो लम्बे अर्से से दबे रहे हैं फिर उभरने लगे हैं। कुछ राज्यों में भाषा अथवा अन्य आधार पर टुकड़े कर पृथक् राज्य बनाये जाने की माँग भी उठाई जा रही है।[6]

इस प्रकार क्षेत्रीयता की भावना जन-जीवन में समाहित होने के कारण आज हमारा देश केवल भारत और पाकिस्तान में ही नहीं अपितु एकाधिक क्षेत्रों में बँट गया है और प्रत्येक क्षेत्र में लोग दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता को राजनीतिक औश्र मनोवैज्ञानिक संघर्ष और तनाव दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इससें केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच संबंधों में विकृति आती जा रही है तथा स्वार्थी नेतृत्व एवं संगठन विकसित हो रहे हैं। भाषा की समस्या और मिला है। क्षेत्रीय आंदोलनों ने अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए धर्म, भाषा, जाति जैसे विघटनकारी तत्वों का सहारा लिया है जिससे भारत में राष्ट्रीय एकीकरण में नवीन बाधायें पैदा हो रही है। इसके साथ-साथ यदि देखा जाये तो आज भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव क्षेत्रवाद के लिए उत्तरदायी है जैसे तमिलनाडु में टी.एम.सी., महाराष्ट्र में शिवसेना, असम कान्फ्रेंस आदि प्रमुख हैं जो अपने क्षेत्र विशेष के हितों का प्रतिनिधित्व करते है। पंजाब का अकाली दल जाट सिक्खों में से पूँजीवादी किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। अत: क्षेत्रीय दल न तो सामाजिक दृष्टि से तटस्थ रहते हैं, न ही प्रशासन का एक अच्छा प्रतिमान प्रस्तुत करते हैं। इतना ही नहीं कई राजनीतिक दल जो पहले की कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए प्रशासन का एक अच्छा प्रतिमान प्रस्तुत करते है। इतना ही नहीं कई राजनीतिक दल जो पहले ही कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए प्रशासन प्रतिमान के स्थान पर कोई नया विकल्प भी नहीं प्रस्तुत कर पाये हैं। इतना ही नही कुछ क्षेत्रीय दलों ने तो भाषायी विखण्डवाद की भावनाओं को बढ़ावा दिया है। कन्नड विकास अभिकरण कन्नड़ भाषा को आगे बढ़ाने में यथाशक्ति प्रयास कर रहा हैं।[7]

क्षेत्रीयतावाद को नियंत्रित करने के उपाय – किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिये विशेष रुप से ऐसा जो अभी भी राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याओं से जूझ रहा हो, क्षेत्रवाद की प्रवृति का विकास एक चिंताजनक विषय है, इसे नियंत्रित किया जाना न केवल उपयुक्त बल्कि समीचीन भी है, यथा:

1. सरकार द्वारा विकास कार्यक्रमों का निर्धारण इस प्रकार होना चाहिए ताकि संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिल सके।
2. पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
3. विशिष्ट जातीय समुदाय को अपनी विशिष्ट संस्कृति और पहचान को सुरक्षित रखने के लिये सरकार का सकारात्मक सहयोग मिलना चाहिये।
4. भाषायी विवादों का अविलम्ब सात्विक समाधान होना चाहिये।
5. केन्द्रीय मंत्रिमंडल में सभी क्षेत्रों का संतुलित प्रतिनिधित्व हो ताकि क्षेत्रीय पक्षपातपूर्ण नीतियों का खण्डन हो सके।
6. प्रकार माध्यमों और शिक्षा द्वारा क्षेत्रीयतावाद की संकीर्ण भावनाओं के विरुद्ध वातावरण तैयार किया जाये।
7. सभी क्षेत्रों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान आर्थिक सुविधायें प्रदान की जायें ताकि आवश्यक ईर्ष्या और असंतोष न होवे।

निष्कर्ष रुप में यदि देखा जाये तो पृथक् राज्यों की माँग जहाँ सैद्धान्तिक दृष्टि से एक ओर अव्यावहारिक है वहीं राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक भी है, दूसरी ओर वहीं व्यावहारिक दृष्टिकोण से पृथक् राज्यों की माँग उचित दिखाई पड़ती है क्योंकि इससे प्रत्येक क्षेत्र विशेष, अपना आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक विकास कर सके अपने जीवन स्तर को ऊँचा कर सकेगा क्योंकि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में लोगों की सच्ची भागीदारी के लिए सत्ता और आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण तभी सार्थक होगा जब आर्थिक, राजनीतिक सत्ता के विकन्द्रीकरण के लिये राज्यों को पुनर्गठित किया जाये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. आर.एन. त्रिवेदी : भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 1995
2. डॉ. वी.वी. तायल : भारतीय शासन और राजनीति।
3. डॉ. हरिशचन्द्र शर्मा : भारत में राज्यों की राजनीति।
4. डॉ. एम.पी. राय : भारत की राजनीतिक व्यवस्था।
5. डॉ. अरूण चतुर्वेदी: राजनीति के विविध आयाम।
6. डॉ. पुखराज जैन : भारतीय शासन एवं राजनीतिक।
7. इंडिया टुडे, नई दिल्ली।

****

Overview and Applications of Ionic Liquids

Mukesh Kumar Mehta*

Abstract - Extensive use of toxic and volatile solvents (Volatile) in the chemical industry leads to serious environmental damage. Therefore, finding a suitable alternative for these solvents, which are environmentally sound and at the same time have the properties of common solvents, is strongly felt in the pharmaceutical and chemical industries. New solvents known as solvents as well as green catalysts include supercritical carbon dioxide and Ionic liquids. Ionic liquids contain organic compounds that are all composed of ions. Ionic liquids (ILs) are a new category of compounds that have received a lot of attention in recent years. In this review, a general description about ILs, structure of Ionic Liquid and its classification are summarized. The basic applications also are discussed in detail.

Introduction - Ionic liquids are compounds that have revolutionized research centers and chemical industries in recent years.[1]These compounds, which are part of green chemicals like solvents, have a very important role in reducing the use of Hazardous, toxic, and environmentally harmful.

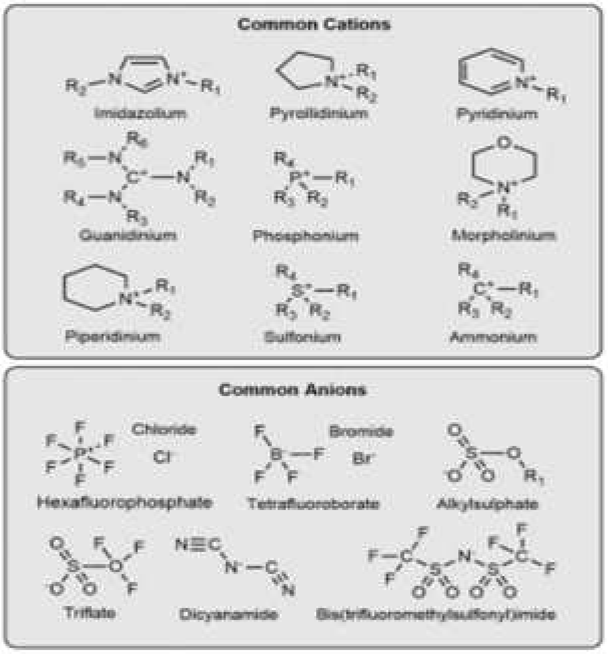

Figure 1. The cations and anions representing the common factor group[2]

Today, ionic liquids are organic compounds made up of ions that are Liquid at 100°C. One of the reasons that have intensified research on ionic fluids today is that scientists are looking for a viable alternative to volatile solvents in the industry.[2]Organic volatile solvents are the most important source of environmental pollution in the chemical and pharmaceutical.Of course, this does not mean that ionic liquids are all green solvents, even some of them are highly toxic.This new chemical group can reduce the use of hazardous and polluting organic solvents due to their unique characteristics as well as taking part in various new syntheses.ILs are known as salts that are liquid at room temperature in contrast to high-temperature molten salts.Studiespointedout in 1980, that there were only a few patent applications for ILs, in 2000, the number of patent applications increased to 100, and finally by 2004, there were more than 800. This is a clear indication of the high affinity of the academia and industry to the ILs.[3]

Structure Of Ionic Liquid: The molecular structure of ionic liquids consists of different cations and anions. The cation is usually played by a large organic compound (with a positive charge), but the anions are much smaller in volume than the cations (with a negative charge) and their structure is inorganic. Due to the difference in size between anions and cations, the bond between the two components of ionic liquids is weak, and these compounds are liquid at temperatures below 100°C. The structure of ionic liquid is similar to that of salt, but due to the strong bond between the cation and its anion (high similarity between anion and cation in terms of size, load, and nature), the salt structure has a strong crystalline structure and melts at 800°C. Temperatures of 100°C are considered for ionic liquids. Those that are liquid at temperatures above 100°C arecalled molten liquids, and those that are liquid below this temperature are called ionic liquids. Some ionic liquids are liquid at room temperature, called RTILs (Room temperature ionic liquids). The two major groups of ionic liquids are compounds composed of the organic moleculesimidazole (cation of the compound imidazole with the formula $C_3H_4N_2$) and pyridinium (the cation of the compound pyridine with the formula C_5H_5N), respectively.[4] The structures of both groups are shown in Figure 2.

*Deptt. of Chemistry, SMB PG College, Nathwara (Raj.) INDIA

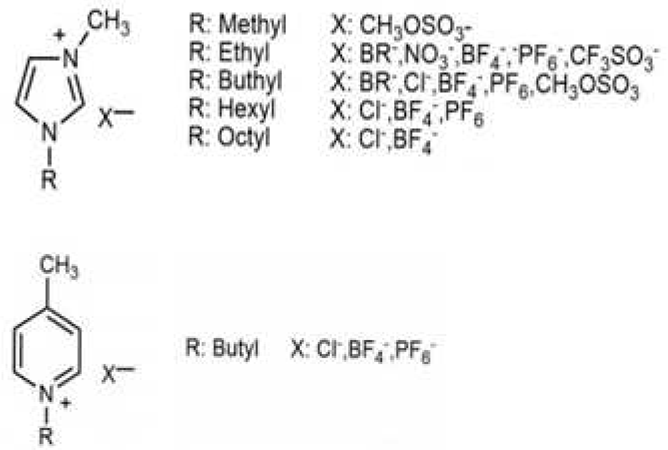

Fig. 2 -– Ionic liquids with cations of imidazole &pyridine

Various cations and anions are used to make ionic liquids, which can be made using a wide variety of ionic liquids with specific uses or enhanced physical-chemical properties (Tuning of Physicochemical Properties). Common anions include BF^{4-}, BF^{6-}, Br^-, Cl^-, and so on.

Advantages Of Ionic Liquid: The most important advantage of ionic liquids includes the following:

1. They are highly polar.
2. They have low vapor pressure and are non-volatile.
3. They are generally stable and resistant to heat up to 300°C.
4. They are liquid in a wide range of temperatures, up to 200°C.
5. The electrical conductivity of these compounds is very high.
6. These compounds are incompatible with many common organic solvents.

CLASSIFICATIONS OF IONIC LIQUIDS

1. Aprotic ionic liquids: The majority of ionic liquids, and certainly those responsible for the meteoric rise in the number of publications in this area since the mid - 90's, are liquids in which the cations are organic molecular-ions. Examples would be the resonance stabilized alkyl pyridinium and dialklyimidazolium cations that go back to Hurley and Weir [5]in the middle of the last century. They mixed N-substituted alkyl and aryl pyridinium halides with various metal chlorides and nitrates and obtained low-liquids with which they performed electrochemical extractions (though they seem to be best known for their efforts on aluminium deposition on which they took the first patents). Hurley and Weir presented the first phase diagram on an aluminium chloride + organic cation halide system,which showed the existence of stable ionic liquids at temperatures of - 40^{o}C. Much more recently developed have been the cyclic,[6]and non-cyclictetraalkyl ammonium salts like those with alkylpyrrolidinium cations, and particularly those with ether oxygenated sidechains. Such cations are usually charge-compensated by anions of oxidic character like nitrate perchlorate or more frequently fluorinated-oxidic character like triflate.Among the most common of the latter are the PF_6^-, BF_4^-, triflate (trifluoromethanesulfonate, CF_3SO_3), and bis-trifluoromethanesulfonyl-imide, $(CF_3SO_2)2N$, or NTf_2) ions. The fluorinated anions are prominent because of the viscosity-lowering reduction of the van der Waals interactions (thanks to the tightly bound, hence unpolarizable, character of the fluorine electrons). The particular success of the NTf_2^-anion, which is quite a large anion, may be due tothe feature pointed out by Henderson, namely, that this ion has two isoenergetic forms, hence can add an extra, (and therefore liquid-stabilizing) mode to the configurational entropy.

2. Protic ionic liquids: These are formed by the simple transfer of a proton from pure Brønsted acid to pure Brønsted base. Historically the first ILs made, as noted already, their development in the modern era was spearheaded by the Ohno[7][8]laboratory in Japan. The nature and reversibility of this process establishes a proton potential in the liquid product that lends this class of ionic liquids a special tenability to which more attention will be given in the last section of this article. The NTf2 anion mentioned in the previous section serve equally well to lower the cohesion, hence also the fluidity, of these liquids.

But the cohesion can also be manipulated by tuning proton transfer energy, with the result that it is possible for protic ionic liquids, according to eqn (1)(Λn = constant), to become more conductive than the aprotic cases. Indeed, by taking advantage of these features, some of the most conductive liquids ever known, have been obtained.

3. Inorganic ionic liquids: These may be obtained, in both aprotic and protic forms, by taking advantage of the same packing problems that lead to low-melting ILs of the organic cation type. There may be fewer of them, but there are aprotic like lithium chlorate (melting point 115°C), and its glassforming eutectic with lithium perchlorate, and protic examples like hydrazinium nitrate, Tm = 80°C, not to mention low-melting mixtures of ammonium salts, and finally the largely unexplored cases of salts with inorganic molecular cations, such as $PBr\mathbf{3}Cl^+$,$SCl3^+$, $ClSO2NH3^+$ etc., with appropriate weak base anions.

4. Solvate (chelate) ionic liquids: These form a largely unstudied class of ILs that needs to be recognized because the class includes cases of multivalent cation salts that would not ordinarily be able to satisfy the criterion of Tm < 100°C. The first recognized members of this class were molten salt hydrates, like $Ca(NO_3)_2 . 4H_2O$, whose mixtures with alkali metal salts were found to be almost ideal mixtures, most with liquidus temperatures well below ambient.[9] These were hailed as a ''new class of molten salt mixtures'', but there has been some question about the lifetime of the water molecules in the cation coordination shell. This should be long with respect to the diffusion time scale for the "ionic liquids" classification to be unambiguous. Recently the Watanabe laboratory has described new cases where long lifetime is guaranteed because the ligating groups all belong to the same molecule. Thus, instead of 4

water molecules, Tamura et al.[10] use 4 alkoxy groups linked together, e.g., tetra-glyme chelating the Li^+ cation, and find the salts with imide type anions to be ambient temperature liquids (with many desirable cell electrolyte properties).[11]

Different Types Of Ionic Liquid

There are four types of ionic liquid: -

No	Ionic liquids	Chemical structure
1	Imidazolium iodide derivatives	
2	Piperidinium iodide derivatives	
3	Pyrrolidinium iodide derivatives	
4	Pyridinium iodide derivatives	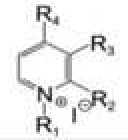

The 4 different types of ILs used in the present study and their chemical structures are listed in Table. ILs based on 4 different cations having 5-member (imidazolium and pyrrolodinium) and 6-member (piperidinium and pyridine) rings were used in the present study.[12]

APPLICATION OF IONIC LIQUID : Today, ionic liquids are widely used in various sciences and technologies. The most important use of ionic liquids is to act as a green solvent instead of volatile solvents. Today, ionic liquids have a wide range of other uses, some which are briefly mentioned[13]

1. ***Catalytic Reactions:*** **-**Ion fluids were first used as a catalyst 20 years ago in the Friedel-Crafts reaction. Ionic liquids are used as a two-phase catalyst or substrate to stabilize other catalysts. In the presence of ionic liquids, it is possible to reuse the catalyst.

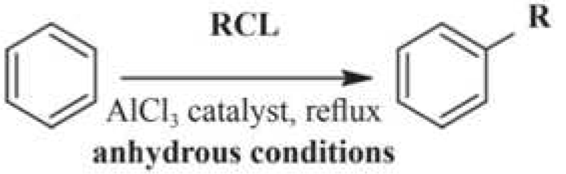

Stability of nanocatalysts in an ionic liquid medium**:** Metal nanocatalysts such as gold,platinum, palladium, rhodium, and ruthenium are widely used in organic reactions. The problem with nanocatalysts is that they bind together in reaction environments and become clumpy, greatly reducing their activity. A variety of ionicliquids are used to prevent this. Nanocatalyst Rhodium (Rh) for example, are more active in the ionic liquids mentioned in the hydrogenation reaction of alkenes and rains.

2. Solvent**:-** As mentioned, the main use of UV fluids is as a solvent. One of the most important benefits of using ionic liquids is increasing the speed of reactions and improving orientation relative to other solvents.

3. Electrochemistry**:-** More than 20 years ago, molten salts and ionic fluids were first used by electrochemists in power systems. Some ionic fluids were the best examples for electrochemical devices such as power storage, fuel cells, photovoltaic cells, and electric hydration. This is due to the very high electrochemical stability, high conductivity, and wide temperature performance range. The need for high-power batteries for various applications (portable electronics, electric thermopile, mobile phone, etc.) led to the search for more non-aqueous electrolytic solutions. The competition for rechargeable lithium-ion batteries has led to the introduction of high-conductivity electrolytes that are electrochemically stable and have a high capacity for reuse. The ionic liquid appears to be good electrolytes for rechargeable lithium batteries. Their wide range of electrochemical potential prevents the electrode from regenerating or oxidizing. This range is more than 4.5 volts for ionic liquids and 1.2 volts for blue electrolytes. Also, ionic liquids have higher thermal stability, higher conductivity, and higher solubility than conventional electrolytes. For example, their conductivity in lithium batteries is 5 times higher than in mixed and lithium salts in non-aqueous solvents.

4. Liquid – Liquid extraction**:-**One of the methods used for separation is liquid-liquid extraction. This method is widely used in industry because it is very energy efficient. In this method, two non-mixed phases, organic and blue phases, are used. Most of the solvents used for the organic phase of chloroform are volatile solvents. Aqueous ionic liquids are a good alternative to the organic phase. Ionic liquids are mainly used in the extraction of valuable metal ions such as gold, lanthanides, and actinides or toxic metal ions of drinking water such as mercury and cadmium.

Conclusion: Ionic liquids are compounds that have revolutionized research centres and chemical industries in recent years. These compounds which are part of green chemistry as a catalyst. Solvent play a very important role in reducing the use of hazardous, toxic, and environmentally harmful compounds in the chemical and pharmaceutical industries.

This article briefly describes the advantagesand classifications of ionic liquids, as well as the applications of these compounds. Today, ionic liquids are widely used in various discipline of sciences and technologies.

References:-

1. Welton, T. Room-temperature ionic liquids: Solvents for synthesis and catalysis. *Chem. Rev*. 1999, *99*, 2071-2084.
2. Short, P. L. Out of the ivory tower. *Chem. Eng. News*2006, *84*, 15-21.
3. Wilkes, J. S. J.; Levisky, A.; Wilson, R. A.; Hussey, C. L. Dialkylimidazolium chloroaluminate melts, a new class of room-temperature ionic liquids for electrochemistry, spectroscopy and synthesis. *Inorg.*

Chem. 1982*, 21,* 1263- 1264.
4. Zhao, Xia and Ma 2005.
5. F. H. Hurley and T. P. Wier, J. *Electrochem*. *Soc*., 1951, *98*, 203.
6. D. R. MacFarlane, S. A. Forsyth, J. Golding and G. B. Deacon, *GreenChem*., 2002,*4*, 444.
7. M. Hirao, M. Yoshizawa and H. Ohno, *Electrochim*. *Acta*, 2000, *45*, 1291.
8. H. Ohno and M. Yoshizawa, *SolidStateIonics*, 2002, *154*, 303.
9. C. A. Angell, J. *Electrochem*. *Soc*., 1965, *112*, 1224.
10. T. Tamura, T. Hachida, K. Yoshida, N. Tachikawa, K. Dokko and M. Watanabe, J. *PowerSources*, 2010, *195*, 6095.
11. Angell, Ansari, & Zhao,*Faradaydiscussion*.2012.154. 9 – 27.
12. Cho, Yoon, Sekhon, & Han, 2058 *Bull*. *KoreanChem*. *Soc*. 2011, Vol. 32. 6.

****

The Impact of Social Media on Children's Behavior

Dr. Sandhya Jaipal*

Abstract - Social media has become a ubiquitous presence in modern society, with an estimated 3.6 billion people using social media platforms worldwide. However, the impact of social media on children's behavior is a topic of ongoing debate and research. This paper examines the impact of social media on children's behavior, with a focus on the role of parents and caregivers in mitigating the potential risks. Several studies have found that social media use can have both positive and negative effects on children's behavior, including impacts on self-esteem, academic performance, and mental health. The paper outlines the positive and negative effects of social media use on children's behavior, and how parents and caregivers can mitigate the potential risks. It is argued that by setting limits, monitoring content, fostering healthy online relationships, encouraging alternative activities, setting a good example, and educating children, parents and caregivers can play a critical role in helping children to navigate the online world safely and to promote healthy social media habits.
Keywords- Social media, Children, Behavior, Impact, Cyberbullying, Online interactions, Social skills, Social development, Technology, Parental monitoring, Screen time, Mental health, Digital citizenship, Internet safety, Social media addiction.

Introduction - Social media platforms such as Facebook, Instagram, and YouTube have become an integral part of many children's lives, with usage rates among children and teenagers rising in recent years. While social media can offer children a means of communication and connection with others, it can also have a significant impact on their behavior. Studies have found that social media use can have both positive and negative effects on children's behavior, including impacts on self-esteem, academic performance, and mental health.

One of the main concerns about the impact of social media on children's behavior is that it can lead to addiction. Children and teenagers may spend hours each day scrolling through social media feeds, which can lead to a lack of face-to-face interaction and poor communication skills. Additionally, social media can be a source of cyberbullying and harassment, which can have a negative impact on a child's mental health and self-esteem.

On the other hand, social media can also have a positive impact on children's behavior. It can be a way for children to connect with their peers, share their thoughts and interests, and learn about different cultures and perspectives. Social media can also be a powerful tool for self-expression and creativity, allowing children to share their talents and ideas with a wider audience.

Another impact of social media on children's behavior is that it can expose children to a wide range of information, both positive and negative. Children may come across inappropriate content, such as violence, hate speech, or pornography. They also may be exposed to information that is not accurate or true. It's important for parents to monitor their children's use of social media and talk to them about online safety.

While social media can have both positive and negative impacts on children's behavior, it is important for parents and caregivers to be aware of the potential risks and to provide guidance and support to children to help them navigate the digital world safely and responsibly.

Positive impacts of social media on children's behavior: Several studies have found that social media use can have positive impacts on children's behavior. For example, social media can provide children with a sense of belonging and community, as well as opportunities for self-expression and creativity. Additionally, social media can be a valuable tool for children to develop their social skills and communication abilities.

Social media can have several positive effects on children's behavior.

1. Sense of belonging and community: Social media can provide children with a sense of belonging and community by connecting them with peers who share similar interests. This can be particularly beneficial for children who may feel isolated or have difficulty making friends in person.
2. Self-expression and creativity: Social media platforms offer children the opportunity to express themselves and showcase their talents. From sharing artwork, music or videos, to writing blogs, children can express themselves in creative ways and receive feedback from others.

*Associate Professor (Sociology) S.D. Govt. College, Beawar (Raj.) INDIA

3. Social skills and communication: Social media can be a valuable tool for children to develop their social skills and communication abilities. Through online interactions, children can learn how to express themselves effectively and how to interpret and respond to the emotions and perspectives of others.
4. Access to information: Social media platforms offer children easy access to a wide range of information on various topics. This can help children to expand their knowledge and interest in different subjects and stay informed about current events.
5. Support networks: Children may use social media to seek support from others, particularly if they are experiencing difficulties or challenges in their life, such as bullying or mental health issues. Connecting with others who have similar experiences can provide children with a sense of validation and understanding.
6. Support for mental health: Social media can also be a valuable resource for children who are dealing with mental health issues. Online support groups, for example, can provide children with a safe space to share their experiences and receive support from others who understand what they are going through. This can help to reduce feelings of isolation and loneliness and provide children with practical strategies for coping with mental health challenges.
7. Educational benefits: Social media can also have educational benefits for children. For example, there are many educational apps, games and websites that help children learn new skills and knowledge. Additionally, social media platforms such as YouTube have many educational videos, tutorials and lectures that can help children learn new subjects.
8. Opportunities for volunteerism and activism: Social media can also provide children with opportunities to get involved in volunteerism and activism. Children can learn about important social and political issues and be inspired to take action. Social media can also provide children with a platform to share their own causes and raise awareness about the issues they care about.

While social media can have many positive effects on children's behavior, it is important for parents and caregivers to be aware of the potential negative effects and take steps to mitigate these risks. Future research should continue to explore the complex relationship between social media and children's behavior to better understand the potential harms and benefits of social media use, and to provide guidance for parents, educators and policymakers.

Negative impacts of social media on children's behavior: However, there are also negative impacts of social media on children's behavior. For example, excessive social media use has been linked to decreased academic performance and increased risk of mental health issues such as depression and anxiety. Additionally, social media can also expose children to cyberbullying and other forms of online harassment.

Despite the many positive effects of social media on children's behavior, there are also several negative impacts to consider.

1. Decreased academic performance: Studies have shown that excessive social media use can lead to decreased academic performance in children. This may be due to the distraction caused by social media, as well as the potential for procrastination and reduced motivation to complete schoolwork.
2. Increased risk of mental health issues: Social media use has been linked to an increased risk of mental health issues such as depression and anxiety in children. This may be due to the negative impact of social comparison on self-esteem, as well as the potential for cyberbullying and other forms of online harassment.
3. Cyberbullying and online harassment: Social media can expose children to cyberbullying and other forms of online harassment. Children may be bullied or harassed by their peers online, leading to feelings of isolation and distress. In some cases, cyberbullying can even lead to self-harm or suicide.
4. Exposure to inappropriate content: Social media can also expose children to inappropriate content such as violence, sexual content, and hate speech. This can have a negative impact on children's behavior and development.
5. Lack of privacy: Social media can also impact children's privacy. Children may not fully understand the implications of sharing personal information online, and may be at risk of being exploited or targeted by predators.
6. Reduced face-to-face interactions: Excessive social media use can also lead to a reduction in face-to-face interactions among children. This can lead to difficulty in developing social skills and emotional intelligence and may contribute to anxiety and depression.
7. Impact on sleep: Social media use has been linked to poor sleep patterns in children. The blue light emitted by screens can suppress melatonin production and the constant stimulation can make it difficult for children to wind down before bed. This can lead to difficulty falling asleep, insomnia and daytime sleepiness.
8. Impact on body image: Social media can have a negative impact on children's body image. Children are exposed to a constant stream of images of idealized bodies, which can lead to feelings of inadequacy and body dissatisfaction. This can be particularly harmful for children who are already struggling with self-esteem issues.
9. Impact on physical health: Prolonged social media use can lead to a sedentary lifestyle which can contribute to obesity and other health issues. Additionally, children who spend too much time on social media may not be getting enough physical activity, which is essential for

their overall health and development.

10. Impact on cognitive development: Studies have shown that excessive social media use can lead to a reduction in cognitive skills such as attention, memory, and decision making. This may be due to the constant distractions and over-stimulation caused by social media.
11. Impact on addiction: Social media use can lead to addiction, particularly in children who are already susceptible to addiction. This can lead to a loss of interest in other activities, difficulty in regulating emotions and a decline in mental and physical well-being.

It is important to note that these negative effects of social media on children's behavior are not inevitable and can be mitigated by responsible social media use and appropriate supervision. Parents and caregivers play a crucial role in helping children to navigate the online world safely and to promote healthy social media habits.

Role of Parents: It is also important to consider the role of parents and caregivers in shaping children's social media experiences. Positive parenting practices, such as open communication, setting clear guidelines, and monitoring social media use, can help to mitigate the negative effects of social media and promote healthy social media habits among children. Furthermore, parents and caregivers can actively use social media to stay connected with their children, and to promote positive behaviors such as sharing and teamwork. Few positive parenting practices are:

1. Setting limits on time spent on social media: Parents and caregivers can set limits on the amount of time children spend on social media. This can help to prevent excessive use and reduce the risk of negative effects on behavior and academic performance.
2. Monitoring content: Parents and caregivers can monitor the content children are exposed to on social media. This can help to protect children from inappropriate content and cyberbullying. They can also use parental controls and monitoring tools to block access to certain sites and apps.
3. Fostering healthy online relationships: Parents and caregivers can teach children how to use social media in a positive way and foster healthy online relationships. They can teach children how to communicate effectively and respectfully online, how to recognize and report cyberbullying, and how to protect their personal information.
4. Encouraging alternative activities: Parents and caregivers can also encourage children to participate in alternative activities such as sports, music, and art. This can help to reduce the amount of time children spend on social media and promote healthy development in other areas.
5. Setting a good example: Parents and caregivers should also set a good example by using social media responsibly themselves. Children are more likely to adopt healthy social media habits if they see their parents and caregivers using social media in a positive and balanced way.
6. Open communication: Having open and honest communication with children about their social media use can help parents and caregivers to understand children's experiences and concerns. This can help to identify potential problems early and take appropriate action to mitigate them.
7. Education: Educating children about the potential negative effects of social media, as well as the importance of responsible and healthy use, is essential. Parents and caregivers can also educate themselves about the latest trends, risks and best practices to stay informed and better support their children.
8. Co-viewing and co-playing: Parents and caregivers can co-view and co-play social media with their children. This can help them to understand the content and context of what their children are engaging with and also provide opportunities for conversation, guidance and learning.
9. Encourage critical thinking: Parents and caregivers can encourage children to think critically about the information they see on social media. They can teach children to question the source and veracity of the information they see, and to be aware of the potential biases and manipulation tactics used on social media.
10. Establish rules and consequences: Parents and caregivers can establish rules and consequences around social media use to ensure that children understand the expectations and boundaries. This can include rules around time limits, content monitoring, and appropriate behavior online.
11. Encourage physical activity and healthy habits: Social media use can be sedentary and can contribute to a lack of physical activity. Parents and caregivers can encourage children to engage in physical activity and healthy habits such as regular exercise, proper nutrition, and adequate sleep to offset the potential negative effects of social media use.
12. Encourage offline activities: Encourage children to engage in activities that don't involve screens such as reading, playing board games, or spending time outdoors. This can help to reduce the amount of time children spend on social media and promote healthy development in other areas.
13. Encourage healthy self-esteem: Parents and caregivers can encourage children to have a healthy self-esteem by praising their children for their achievements and talents, rather than for their physical appearance, online popularity, or material possessions.

Parents and caregivers play a critical role in helping children to navigate the online world safely and to promote healthy social media habits. By setting limits, monitoring content, fostering healthy online relationships, encouraging alternative activities, setting a good example, and educating

children, parents and caregivers can mitigate the negative effects of social media on children's behavior.

Conclusion: Overall, the literature suggests that social media can have both positive and negative impacts on children's behavior. It has the power to shape their perceptions, attitudes, and beliefs, as well as their social interactions and relationships. While social media can be a valuable tool for communication and connection, it can also expose children to negative influences and harmful content. Parents and caregivers must be aware of the potential risks and take steps to protect children from the negative effects of social media. This includes setting boundaries, monitoring usage, and educating children on responsible social media behavior. By taking these steps, we can help children navigate the digital world and build healthy habits for a lifetime. Future research should continue to explore the complex relationship between social media and children's behavior to better understand the potential harms and benefits of social media use.

References:-

1. Carroll, J. A., & Kirkpatrick, R. L. (2011). Impact of social media on adolescent behavioral health. Oakland, CA: California Adolescent Health Collaborative
2. Ehmke, R. (2017). “How Using Social Media Affects Teenagers.”, Retrieved from: https://childmind.org/article/how-using-social-media-affects-teenagers/
3. Hyll, W., and Schneider, L. (2013). The causal effect of watching TV on material aspirations: Evidence from the ‘valley of the innocent’. Journal of Economic Behavior and Organization, 86, 37-51.
4. Le Heuzey M.-F. Social media, children and pediatricians. Arch. Pediatr. 2012;19:92–95. doi: 10.1016/j.arcped.2011.10.016

****

Women Empowerment in India: Challenges and Opportunities

Dr. Anjali Jaipal*

Abstract - Women empowerment in India is a complex issue that has been affected by a variety of cultural, social, and economic factors. Despite progress in recent years, women in India continue to face significant challenges in terms of education, employment, and access to healthcare. These challenges are compounded by deeply ingrained cultural attitudes that view women as inferior to men. However, there are also many opportunities for women in India to improve their status and achieve greater equality. These opportunities include increased access to education and employment, as well as the growth of women-owned businesses and the rise of women in leadership positions. With the right policies and programs in place, women in India can be empowered to reach their full potential and contribute to the overall development of the country.This paper aims to explore the current state of women empowerment in India, including the challenges faced by women and the opportunities that exist for progress.
Keywords- women empowerment, gender discrimination, inequality, violence, discrimination, patriarchal attitudes, societal norms, maternal mortality, healthcare access, workplace discrimination.

Introduction - Women empowerment in India refers to the process of increasing the social, economic, and political power of women. This includes increasing access to education, employment, and healthcare, as well as improving representation in politics and decision-making positions. Despite progress in recent years, women in India continue to face significant challenges in terms of gender discrimination and inequality.Women empowerment in India is a crucial aspect of the country's development and progress. Despite some progress in recent years, women in India continue to face significant challenges in terms of education, employment, and access to healthcare. According to a report by the World Economic Forum, India ranks at 136 out of 153 countries in the Global Gender Gap Index, which measures gender equality across four key areas: economic participation and opportunity, educational attainment, health and survival, and political empowerment.

Challenges: One of the major challenges faced by women in India is the persistent gender gap in terms of education and employment. According to the World Bank, only 66% of Indian women are literate, compared to 82% of men. Similarly, women are underrepresented in the workforce, with only 27% of women participating in the labor force compared to 82% of men.

Another significant challenge faced by women in India is the high levels of violence and discrimination they experience. According to the National Crime Records Bureau, a total of 3,78,277 crimes against women were reported in 2019, including crimes such as rape, domestic violence, and dowry-related harassment.

One of the major challenges faced by women in India is the persistent gender gap in terms of education and employment. According to the World Bank, only 66% of Indian women are literate, compared to 82% of men. Similarly, women are underrepresented in the workforce, with only 27% of women participating in the labor force compared to 82% of men. This is due to a lack of investment in education and training for girls, as well as societal norms that discourage girls from pursuing education and careers. Another significant challenge faced by women in India is the high levels of violence and discrimination they experience. According to the National Crime Records Bureau, a total of 3,78,277 crimes against women were reported in 2019, including crimes such as rape, domestic violence, and dowry-related harassment. This is a result of deeply ingrained patriarchal attitudes and societal norms that view women as inferior to men.

Women in India also face significant challenges in terms of healthcare. The maternal mortality rate in India is one of the highest in the world, with approximately 130 maternal deaths per 100,000 live births. This is due to a lack of access to quality healthcare, particularly in rural areas, as well as societal norms that discourage women from seeking healthcare.

Additionally, women in India also face discrimination and bias in the workplace. Despite laws and policies aimed at promoting gender equality, women still face barriers to equal pay, promotion and representation in leadership positions. This is due to unconscious bias and lack of

*Associate Professor (Sociology) S.D. Govt. College, Beawar (Raj.) INDIA

enforcement of laws and policies.

Another significant challenge for women in India is the lack of access to affordable childcare and support for working mothers. This often forces women to choose between their careers and their families, and limits their ability to fully participate in the workforce.

Women in India lack economic empowerment. Despite laws and policies aimed at promoting gender equality, women in India continue to face barriers in terms of access to credit, property rights, and entrepreneurship. According to a report by the International Labour Organization, only 14% of women in India own property, compared to 30% of men. This is due to societal norms that view women as financially dependent on men, as well as discriminatory laws and practices that make it difficult for women to inherit property or access credit.

Furthermore, there are notable difficulties for females in India concerning their participation and representation in politics. Despite constitutional provisions and laws aimed at promoting gender equality, women are underrepresented in politics and decision-making positions. As of 2019, only 14% of members of the Lok Sabha and 11% of members of the Rajya Sabha were women. This is due to a lack of political will and a culture of patriarchy that discourages women from participating in politics.

Women in India also face the issue of limited access to justice. Despite laws and policies aimed at protecting women's rights, the implementation of these laws and policies remains weak. This is due to a lack of awareness of laws and policies, as well as a lack of access to legal aid and representation for women. Furthermore, the judicial process in India is often slow and cumbersome, which further compounds the challenges faced by women seeking justice.

Women also encounter significant obstacles in terms of obtaining access to technology and the internet in India. According to a report by the Internet and Mobile Association of India, only 39% of internet users in India are women. This is due to a lack of access to technology and the internet, as well as societal norms that discourage women from using technology.

Women in India also face a significant obstacle in their lack of representation and involvement in the informal economy. The informal sector is the largest employer in India, providing livelihoods to approximately 90% of the country's workforce. However, the majority of workers in the informal sector are women, who are often paid less and have fewer rights and protections than men. This is due to a lack of formalization and regulation of the informal sector, as well as discriminatory attitudes and practices that view women as less capable and less deserving of rights and protections.

Additionally, there are significant obstacles for women in India when it comes to obtaining access to social protection and welfare services. Despite laws and policies aimed at providing social protection and welfare services to women, the implementation of these laws and policies remains weak. This is due to a lack of resources, as well as discriminatory attitudes and practices that view women as less deserving of social protection and welfare services.

Women in India also face a lack of visibility and involvement in the media industry. The media plays a crucial role in shaping public opinion and discourse in India. However, women are underrepresented in the media, both as consumers and as producers. This is due to a lack of investment in women-led media projects, as well as discriminatory attitudes and practices that view women as less capable and less deserving of representation and participation in the media.

Lastly, women in India also face major challenges in terms of access to housing and urban services. According to a report by the Ministry of Housing and Urban Affairs, only 37% of households in India are headed by women. This is due to a lack of affordable housing and urban services, as well as discriminatory attitudes and practices that view women as less capable and less deserving of access to housing and urban services.

Opportunities: Despite the challenges, there are also opportunities for progress in terms of women empowerment in India. One such opportunity is the increasing access to education for girls and women. The government of India has implemented several programs aimed at increasing enrolment and retention of girls in schools, including the Sarva Shiksha Abhiyan and the Beti Bachao Beti Padhao campaign.

Another opportunity for progress is the increasing representation of women in politics and decision-making positions. In recent years, there has been an increase in the number of women elected to political office in India. The government of India has also set a target of reserving 33% of seats in the Lok Sabha and the state legislative assemblies for women.

Strategies: To address the challenges faced by women in India, a multi-pronged approach is needed. Some strategies that can be implemented to empower women in India include:

Investing in education and training for girls and women: This includes increasing enrollment and retention of girls in schools, as well as providing training and education programs that equip women with the skills they need to succeed in the workforce.

Implementing laws and policies to protect women's rights: This includes enacting laws and policies that protect women from violence and discrimination, as well as implementing mechanisms to ensure the enforcement of these laws and policies.

Improving access to healthcare for women: This includes increasing access to maternal healthcare, as well as providing education and awareness programs that promote healthy behaviours and practices among women.

Promoting economic empowerment for women: This includes increasing access to credit, property rights, and

entrepreneurship opportunities for women, as well as providing training and education programs that equip women with the skills they need to succeed in the workforce. Increasing representation of women in politics and decision-making positions: This includes reserving seats for women in political office, as well as implementing mentorship and leadership programs that support the development of women leaders.

Improving access to justice for women: This includes providing legal aid and representation for women, as well as implementing awareness and education programs that promote knowledge of laws and policies that protect women's rights.

Increasing access to technology and the internet for women: This includes providing training and education programs that equip women with the skills they need to succeed in the digital economy, as well as investing in infrastructure and programs that promote greater access to technology and the internet for women.

Formalizing and regulating the informal sector, ensuring social protection and welfare services are provided to women, promoting representation and participation of women in the media, and providing affordable housing and urban services for women.

Conclusion: Women empowerment in India is a complex issue, and significant challenges still exist in terms of gender discrimination and inequality. However, there are also opportunities for progress, including through increasing access to education and representation in politics and decision-making positions. It is important to continue efforts to empower women in India in order to achieve gender equality and to unlock the full potential of the country.Women empowerment in India faces a plethora of challenges including; gender gap in education and employment, high levels of violence and discrimination, lack of access to healthcare, discrimination and bias in the workplace, and lack of access to affordable childcare and support for working mothers. These challenges are deeply ingrained in the Indian society and require a holistic approach to address them. Addressing the challenges faced by women in India requires a comprehensive and holistic approach, including investing in education and training for girls and women, implementing laws and policies to protect women's rights, improving access to healthcare for women, promoting economic empowerment for women, increasing representation of women in politics and decision-making positions, improving access to justice for women, increasing access to technology and the internet for women, formalizing and regulating the informal sector, ensuring social protection and welfare services are provided to women, promoting representation and participation of women in the media, and providing affordable housing and urban services for women.

References:-

1. Dr. (Smt.) Rajeshwari M. Shettar, "A Study on Issues and Challenges of Women Empowerment in India", IOSR Journal of Business and Management, Volume 17, Issue 4.Ver. I (Apr. 2015)
2. Goswami, L. (2013). Education for Women Empower -ment. ABHIBYAKTI: Annual Journal, 1, 17-18.
3. Nagaraja, B. (2013). Empowerment of Women in India: A Critical Analysis. Journal of Humanities and Social Science (IOSRJHSS), 9(2), 45-52
4. R. Talmaki, Socio-Economic Development of Tribal Women: Changes and Challenges, The Women Press, New Delhi, 2012.
5. Government of India. (2017). Beti Bachao Beti Padhao. Retrieved from https://wcd.nic.in/bbbp-schemes

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

Optimal Location of Phasor Measurement Units for Voltage Security of Power Systems

Sonali R. Nandanwar* N. P. Patidar**

Abstract - Now in India power systems are computerized to deal the practical size problems and equipped with simple, transparent and fast security assessment tool that can easily be trained and comprehensible. So efforts are made to assess the voltage security by optimal placement of Phasor Measurement Units by using Decision Tree (DT). DT examines and classifies the power system correctly to ensure that the system is operating in secure or in insecure mode. By using DT an algorithm is developed to identify the most sensitive buses which are most viable and hampered the security of power system. Such buses are ranked in terms of for monitoring using phasor measurement unit (PMUs) using joint bus ranking index. Therefore only top ranked buses are placed instead of all buses. On comparisons between PMU placed at all buses with optimally selected PMU buses, classification accuracy is observed more for optimally selected PMU buses. As numbers of PMUs are reduced with higher classification accuracy, reduces the cost of PMU devices in overall system. Implementation of PMUs in system will certainly enhance the reliability of the system equally and would avoid the blackout. To examine the above methodology a case study of 400 KV Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited is considered.
Keywords: Voltage security, Data mining, Phasor measurement unit.

Introduction - Development of restructured power system, the voltage security assessment has paramount importance important role. The main work of restructuring is to maximize the competition for decreasing costs and improving the quality of energy. Also the economic, political and environmental pressure and regulatory authorities enforces power system planners for commissioning of new transmission lines to meet the demand. As a result, pressure has increased on electricity markets and operators to enhance the sources of the system. Operators have a great challenge to operate the system with limited information for real time operation and decision-making. In such situation it is very difficult to maintain voltage profiles at the load buses within the acceptable limits and utilities are often face the problem of voltage instabilities. Several events of voltage collapse have been occurred in the past decade, resulting in widespread blackouts with potential sever social and economic consequences [1]. In power system security all around the world undergone very important changes which have the strong impact on the electric power sector. Because of this tendency power systems inclined towards better utilization of generation and transmission capacity and sometimes the systems are to operate much nearer to their security limits. In operational planning decision makers has to establish certain rules for operation of power system based on the upper/lower limits of the critical decision variables to identify the potential operating conditions, whether the post contingency system is secure or not [2]. Now, PMUs are used in monitoring system in real time. PMU's can measure direct synchronized measurements of voltage phasor of the located bus and current phasor of all the branches connected to that bus. PMUs have made monitoring and control of power system faster and accurate, however the cost of PMUs as well as the communication cost is very high. So, the optimal PMU placement is a major challenge. The main aim is to find a minimum set of hyper planes which describes accuracy of the system [3]. To estimate the voltage security from voltage collapse, PMU are synchronized with Global Positioning System (GPS) which gives the signal in form of voltage and current phasors to the central location. From this central location, status of the voltage security is found by Decision trees(DT) which one of the data mining algorithm, useful for knowledge acquisition by making if-then rules for classification of events from huge data base of power system and for optimal placement of PMUs [4],[5]. In real time monitoring power oscillations plays vital role in power system stability. It identifies the oscillation properties which are based on PMU data. Transportation of PMU data within a single network domain or between network domains or multiple utilities is the tedious work for operator [6], [7]. Several conventional techniques have been proposed for PMUs placement, but in this paper, DT approach is used to find critical location of PMUs placement. The DT technique was first suggested

*Electrical Engineering Department, Priyadarshini College of Engg, Nagpur, Hingna Road, Nagpur (Mh.)INDIA
**Electrical Engineering Department, Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal (M.P.) INDIA

by Wehenkal and it was used to monitor transient stability [8]. DT is a method for approximating linguistic as well as the numeric data in precision. Reference [9] has used regression tree for calculation of joint bus ranking (JBR) which estimate the approximate value of maximum loadability margin (MLM). But in this algorithm exact status of operating conditions whether it is secure or insecure is not known.

In this paper binary decision tree has been used for classification of power system operating conditions whether it is secure or insecure using data base of the power systems. Importance of decision variable which is based on information gain is calculated. DTs have been further used for calculation of JBR for optimal placement of PMUs. Results are compared with and without optimal placement of PMUs. PMUs are placed on selected top most sensitive buses which affect the MLM most.

Maximum Loadability Margin - For ensuring voltage security of power system, it is essential to know how much to operate steady state after some perturbation has been occurred within the specified limits of safety and supply quality constraints corresponding to contingencies [10]. After certain time period, power system reaches steady state operating conditions without disturbing power system parameters, like bus voltage violations or thermal limits of the line [11], [12]. To quantify the degree of security, Maximum Loadability margin (MLM) is commonly used as a voltage stability index which quantifies how close a particular operating point is to the point of voltage collapse to estimate the steady state voltage stability limits of the power system. Voltage stability margin is defined as distance with respect to the divergence parameter, of the current operating point to the voltage collapse point [13]. The system is said to be voltage secure if this margin is reasonably high. Fig.1 depicts the voltage Vs real loading variation of power system. In case of contingency the MLM is reduced to a lower value [14] margin is available from the voltage collapse point [15], [16]. Security is defined as the ability of the system to remain in secure equilibrium state even after contingency has been occurs.

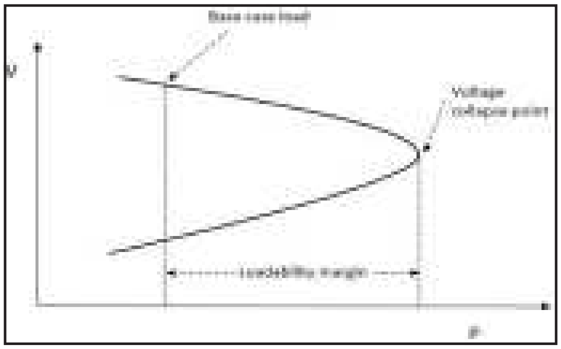

Fig. 1. P-V Curve

Phasor Measurement Unit

PMU Methodology -In power system to monitor the security of network, it is very important to understand the concept of wide area security. Phase measurement unit is a device which calculates voltage and current magnitudes and their angles in a real time. Angle difference between voltage and current phase is the fundamental measuring capacity of PMUs. There are some monitoring control stations which receives the signal continuously from various satellites. This helps administrator to control power system accurately. The PMU connected with the GPS is used to achieve the synchronization of sampled signals. In the real-life system, PMU receives current and voltage waveforms as input signal, which are generated from current and potential transformer. The input signals are sampled, isolated and filtered at an effective rate of samples per cycle of the fundamental frequency [17], [18].

Due to phasor technology and the PMU device, electric power network was found more reliable, stable and controllable in the following sections. The PMU has a vast potential of application in power system. These are:

1. Accurately measure frequency, magnitudes of voltages and currents
2. State estimation
3. Prediction of instability
4. Adaptive relaying

PMU is a very costly device. Placing PMUs at all buses is not economically feasible. To minimize the maintenance and per unit costs, optimal PMU placement is implemented to reduce the number of PMUs installed and to achieve entire degree of system observability.

In this work by using the advantage of DT, it is desired to consider least input features in order to accelerate the training process by keeping the acceptable prediction accuracy. Thus the input feature must capture the system behavior as much as possible. Therefore only basic measurements (i.e. Voltage magnitude, Voltage angle, Current magnitude and Current angle) from PMU installed buses has been considered in this research work.

Decision Tree - Decision tree learning is a method commonly used in data mining which is the branch of Machine Learning. The aim is to create a model that classify the events in terms of given classes based on many input variables. For classification of system decision tree is used because of its representation manner is very simple. There are many variations on the core decision tree algorithm and their root node procedure is almost same. Splitting criterion of the DT into smaller groups in such a manner that each new generation of nodes can have greater purity than its ancestors with respect to the target variable [19]. The binary tree is based on Classification and regression tree (CART) algorithm i.e. each non-leaf node has two children and leaves are not all at the same distance from the root. Each node represents a yes-or-no question, whose answer determines among the two paths, in which path a record proceeds to the next level of the tree and some stopping rules is used for stopping tree growing process. In this research CART algorithm has been used for building decision tree. The algorithm is based on binary trees which

classify the events in terms of secure/insecure operating states of power system [20].

Algorithm for PMU Placement - To find the optimal PMU location first considered that PMUs are placed at all buses throughout the power network i.e. 400 KV Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited (MSETCL)- 19 bus systems. Database is to be generated at each bus with different loading conditions and corresponding stability margin has to be calculated. With this database, binary decision tree will be trained. From the trained tree, variable importance and hence joint bus ranking (JBR) is calculated. And finally tree building and accuracy is calculated by assuming PMUs placement at 5 top ranked buses based on JBR. Proposed technique is explained in following steps:

1) Database generation- For database generation various operating and loading conditions have been considered which represents the knowledge of the system hidden into large data bases. Corresponding to each operating condition, continuation power flow (CPF) is performed. Result of CPF provides the maximum loading power at which voltage collapse will occur. By using (2) the voltage stability margin is calculated corresponding to each operating conditions. The same process is performed for different operating conditions under various contingencies (line outages).

2) Decision tree learning -DT acquires knowledge from database and utilizes for classifying secure/insecure operating states with the help of voltage, current magnitudes and their angles.

3) Variable importance (VI) -Variable importance is a special feature which will be calculated for each variable used. *VI* has great significance on voltage stability margin in terms of voltage and current phasors. Importance of variable has been calculated by impurity level of each split. Any voltage or current is used as a variable for splitting tree node and impurity level has to be checked at that splitting node which shows the importance of the selected variable. Variable importance is the contribution of each variable to the overall tree when all nodes are considered. To calculate the variable importance, find all splits $s \varepsilon S$ on variable x_m at each node $t \varepsilon T$ and discover the split s^*_m that gives the largest decrease in regression tree R.

$$\Delta R(s_m^*, t) = \max_{s \in S} \Delta R(s, t)$$

Suppose s^* is the best split of s^*_m split and s_m is the split on variable x_m that has the best agreement with s* in terms of partitioning cases. Mathematical expression of importance of variable x_m can be expressed as in (1)

$$VI(x_m) = \sum_{t \in T} \Delta R(\tilde{s}_m, t) \qquad (1)$$

4) Joint Bus Ranking (JBR)-Joint bus ranking (JBR) is to be calculated for each bus. Based on JBR values, buses are ranked in descending order. The buses with higher JBR values have more impact on voltage stability. JBR of a bus is calculated by adding *VI* of each variable monitored at that bus. Mathematical expression JBR of bus *i* can be expressed as in (2)

JBR_i= Sum of variable importance of each variable which is measured by i^{th} bus

$$JBR_i = \sum_{x \in i} VI(x) \qquad (2)$$

Where *X* is the vector of variables, x is the individual variable belongs to *X*, and *VI(x)* is its importance. By specifying $x \varepsilon i$ only the variables measured at bus *i* is counted [9].

After calculating combined bus ranking, buses are ranked in descending order on the basis of JBR values. Then top rank buses are selected for PMU placement. Firstly PMU placed at all buses so, all bus voltage and all branch current magnitude and angle is considered as a variable for training of tree. secondly JBR is calculated and based on that PMU is placed only on top ranked buses and only those variables is used which is associated only top ranked buses. Then DT is trained by using top rank bus variable.

Case Study (MSETCL) - In order to evaluate the applicability of the proposed method, MSETCL 400 KV system has been selected for the online security assessment. This system consists of 19 load buses and 5 generators in Fig 2. The loading patterns were generated by varying the real and reactive loads under each line outage, with the load variations in the range of 50% to 150% of their case based load. In this work loading patterns for critical lines are different by line to line outage. Accordingly training patterns and testing patterns of the loading lines are also different given in Table 1. Maximum loadability margin (MLM) for each of the load patterns and under each line outage were calculated. After calculating MLM, secure and insecure operating conditions were identified.

Table 1. Numbers of Instances are varying with Line Outages

S.	Line Outages	Total no. of instances	Training patterns	Testing patterns
1	Line outage 3	257	210	47
2	Line outage 4	1084	900	184
3	Line outage 5	304	260	44

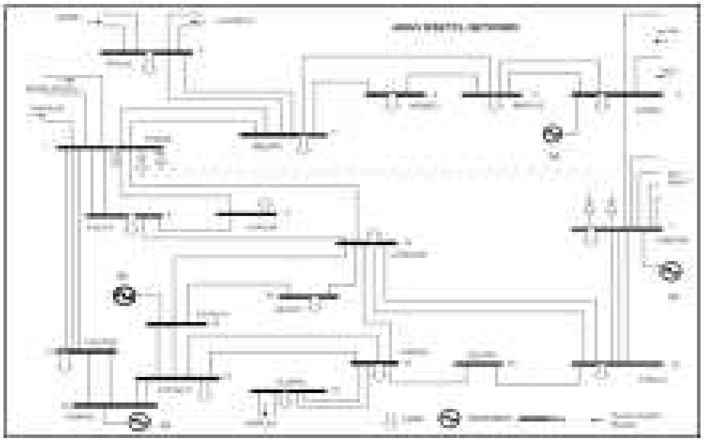

Fig. 2. 400 kV Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited System (MSETCL), India

MLM classified into two classes namely secure and insecure with respect to threshold or critical value (ëcr = 0.4 p.u.) In this work, for line outage no.3, out of 257 instances 210 were used for training pattern and 47 were used for testing pattern. Here the classification of these patterns is done in terms of their accuracy as in (3).

$$Classification_accuracy = \frac{N_{Test\ cases} - N_{Misclassified\ cases}}{N_{Test\ cases}} \quad (3)$$

Classification is given in Table 2 of insecure operating conditions for line outages-3. Results and analysis of line outage-3 is given the description of training set and testing set in Table 3 and Table 4.

Table 2. (see in last page)

For line outage-3 training set consists 210 OC's and testing set consists 47 OC's. Percentage of secure and insecure conditions of training set and testing set is given in Table 3 and 4. Percentage of secure/insecure cases in training set and testing set of line outage-3 is given in Fig.3.

Table 3. Training set

Class	No. Of OC's	Percentage
Class 1 (Insecure)	189	90%
Class 2 (Secure)	21	10%

Table 4. Testing set

Class	No. Of OC's	Percentage
Class 1 Insecure)	42	89%
Class 2 (Secure)	5	11%

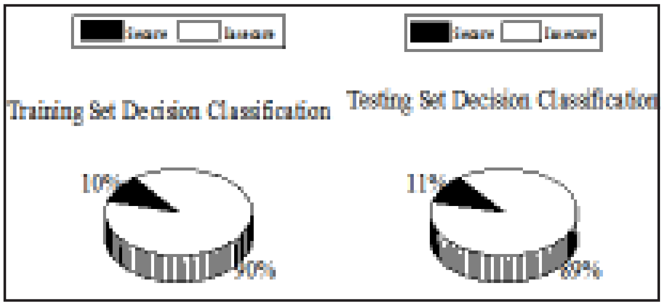

Fig. 3. Percentage of secure/insecure cases in training and testing sets

Database Generation - The database has been generated for 400 KV MSETCL-19 bus systems with the help of NR load flow and CPF using MATLAB software. Hidden knowledge in generated operating conditions is represented by these artificial huge data base. Since PMUs measure voltage and current phasors therefore voltage and current phasors on each bus is obtained by performing Newton-Raphson load flow under each operating condition are as follows:

1) V_{mj} Voltage magnitude at bus *j*, where *j=1,2,3,…..,n* , where *n* is number of buses

2) V_{aj} Voltage angle at bus *j*

3) I_{mjk} Current magnitude of transmission line from bus *j* to *k* , Where *j=1,2,3,…..,n* and *k=1,2,3,…..,n, j ≠ k* and there is a line between *j* and *k*

4) I_{ajk} Current angle of line from bus *j to k* , Where *j* to *k* , where *j=1,2,3,…..,n* and *k=1,2,3,…..,n, j ≠ k*

Feature Selection - Feature selection is a unique feature of decision tree which shows the role of particular attribute in decision making. By obtaining variable importance the impact of particular system parameter on voltage stability margin has been determined. The variable with higher variable importance will have higher impact on voltage stability margin.

Accuracy of decision trees: The classification accuracy of the system calculated by using (3). When the PMU placed at all buses the classification accuracy has been found less than PMU placed at 5 top ranked buses.

Table 5 shows the variable importance of each individual variable by assigning some numerical weights. Variables which are having zero numerical weights are not included.

Table 5. Variable importance of each variable at 400 KV MSETCL-19 bus system

Serial number	Variable name	Variable importance
1	Vm3	0.0006
2	Vm5	0.0018
3	Vm7	0.0003
4	Vm13	0.0001
5	Vm16	0.0001
6	Vm18	0.0002
7	Va1	0.0034
8	Va5	0.0001
9	Va6	0.0001
10	Va15	0.0001
11	Va19	0.0006
12	Im2	0.0003
13	Im3	0.0015
14	Im6	0.0001
15	Im11	0.0001
16	Im12	0.0002
17	Im14	0.0001
18	Im23	0.0002
19	Im29	0.0001
20	Im31	0.0004
21	Im32	0.0001
22	Im33	0.0011
23	Im34	0.0001

Joint bus ranking (JBR) has been calculated for each bus by using variable importance of each variable of decision tree. Higher the value of JBR implies that bus is a critical bus which affects the stability margin most. The JBR has been calculated from variable importance of each variable and it is used to find optimal PMU locations. Mathematical expression of JBR of i^{th} bus expressed as in (2). Table 6 shows the rank of each bus. Optimal PMU location has determined from the JBR. JBR gives the most sensitive buses to any load changes in the system so that they can monitor variables for security assessment. Most of the buses are not much sensitive to load changes and hence not important to monitor because PMUs are the costly

devices. So power system planners must optimize the cost of PMUs by proper selection of location of PMUs.

Testing of DT with and without optimal placement of PMU

From Table 6, it is observed that classification accuracy is found highest with 5 top ranked buses, are selected for PMU placement. The accuracy with 5 top ranked buses is found to be 91.3%. In case of PMUs placed at all the buses the accuracy is found to be 89%. As the number of PMU requirement is greatly reduced by this approach. Table 7 represents the variation of nodes and corresponding accuracy induced with PMU placement at various locations in the network for 400 KV MSETCL-19 bus Indian systems. These PMU locations have been determined on the basis of JBR. It is observed that number of node variation does not follow any pattern with PMU locations.

Table 6. Joint bus ranking of each bus at 400 KV MSETCL-19 bus Indian system

Rank	Bus no.	JBR
1	2(KORDY)	0.0037
2	3(BHSWL2)	0.0024
3	5 (BBLSR2)	0.0019
4	4 (ARGBD4)	0.0015
5	19 (PARLY2)	0.0006
6	17 (KARAD2)	0.0005
7	7 (PADGE)	0.0004
8	18 (SOLPR3)	0.0004
9	10 (LONKAND)	0.0004
10	16 (JEJURY)	0.0002
11	9 (KARGAR)	0.0001
12	14 (KOYNA-4)	0.0001
13	6 (DHULE)	0.0001
14	15 (KLHPR3)	0.0001
15	13 (KOYNA-N)	0.0001
16	1(CHDPUR)	0
17	8 (KALWA)	0
18	11 (NGOTNE)	0
19	12(NGOTNE)	0

Table 7. Comparison of Decision Trees with and without optimal number of PMUs

PMUs at number of buses	Number of nodes	% Accuracy in DT
PMUs at all 19 buses	53	89%.
PMUs at top 5 buses	72	91.30%

Conclusion- Due to the growing size and complexity of power systems, real time decision making and power system analysis becomes extremely difficult. In order to overcome the above challenges, DT (one of the data mining tool) is proposed which is generic and more efficient and accurate. It can capture full system behavior, and effectively characterize the weakness of the current operating conditions. It is also fast enough to take control actions as soon as a vulnerable event has occurs. It will be most suitable for implementation in power systems voltage security assessment. Since it can handle numeric as well as linguistic data with precision. Therefore after voltage security assessment, to identify the most sensitive buses which are most viable and hampered the security of power system. PMUs are monitoring devices and should be placed only on such buses which affect the security most. Such buses are ranked in terms of index called joint bus ranking. Therefore only top 5 buses are selected to place the PMUs in place of 19 buses. The accuracy of the classification of operating states is found more for optimally selected buses for PMU placement as compared to place the PMUs on all the buses. Economy is also one of the important objectives of the power system planners. As number of PMUs are reduced for same or higher classification accuracy, that reduces the cost of PMU devices in overall system. This paper will help the power system planners for optimizing the cost of PMUs which is likely to be implemented in future. PMU is the latest technology for monitoring the system which can be used for other functions also in the power systems. Implementation of PMUs in system will certainly enhance the reliability of the system equally and would avoid the blackout such as July 2012 of Northern and North-Eastern grids.

References:-

1. Behzad Farhangi Rad & Mehrdad Abedi, “An optimal Load Shedding scheme during contingency situations using Meta Heurisatics algorithms with applications of AHP method”, International conference on OPTIM, pp. 167-173, May 2008
2. Venkat Krishnan, James D McCalley, Sebastien Henry & Samir Issad, “ Efficient database generation for decision tree based power system security assessment”, IEEE Transactions on Power systems, Vol. 26, No. 4, pp. 2319-2327, Nov 2011.
3. Yuri. V. Makarov, Pengwei Du, Shuai Lu, Tony B. Nguyen, Xinxin Guo, JW Burns, Jim Gronquist, MA Pai,” PMU based wide area security assessment concept, method and implementation”, IEEE Transaction on Smart Grid, vol. 3, No. 3, pp. 1325-1332, Sept 2012.
4. R. Khatib, R. F. Nuqui, MR Ingram, AG. Phadke, “Real time estimation of security from voltage collapse using synchronised Phasor measurements”, IEEE PES General meeting, Vo. 1, pp. 582-588, 2004.
5. Borka Milosevic, and Miroslav Begovic,”Voltage-Stability Protection and Control Using a Wide-Area Network of Phasor Measurements”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 18, No.1, pp. 121-127, Feb 2003.
6. Aranya Chakrabortty and Pramod P. Khargonekar, “Introduction to Wide-Area Control of Power Systems”, American Control Conference, Washington, DC, June 17-19, pp. 6758-6770, June 2013.
7. Takuhei Hashiguchi, Hiroyuki Ukai, Yasunori Mitani, Masayuki Watanabe, Osamu Saeki and Masahide Hojo,” Power System Dynamic Performance Measured by Phasor Measurement Unit”, IEEE Power Tech, Lausanne, 1-5 July, pp. 1694-1699, July 2007.

8. Mahmoodianfard, Mohammadi, Gharehpetian and Askarian "Optimal PMU placement for voltage security assessment by using DT", IEEE Bucharest Power Tech Conference,June 28-July 2, 2009, Bucharest, Romania.
9. Ce Zheng, Vuk Malbasa, Mladen Kezunovic"Regression Tree for stability margin prediction using synchronous measurements", IEEE Transactions on power systems,Vol. 28, No. 2, May 2013, pp. 1978-1987
10. Mudthir F. Akorede, HashimHizam, IshakAris and MohdZainalAbKadir; "Contingency Evaluation for voltage security assessment of power systems"; IEEE student conference on Research and Development (SCOReI) 2009, UPM Serdang, Malasia, pp. 345-348; 16-18 Nov 2009.
11. M. Beiraghi, A. M. Rajbhar, "Online Voltage security assessment based on wide area measurements", IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 28, No.2 , pp. 989-997, April 2011.
12. S. Sach, A. Khairuddin, " Decision tree for state security assessment classification"; International conference on future computer and communication, pp. 681-684, 2009.
13. Gilles Nativel, YannickJacquemart, Vincent Sermanson and Guy Nerin;" Integrated framework for voltage security assessment"; IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 15, No. 4, pp. 1417-1422, November 2000.
14. T. Amoraee, A. M. Ranjbhar, R. Feuillet & B. Mozafari, "System Protection scheme for mitigation of cascaded voltage collapses", IET Gener. Transm Distribution, Vol.3, Iss. 3, pp.242-256,2009.
15. M. Suzuki, S. Wada, M. Sato, T. Asano & Y. Kudo,"Newly developed voltage security monitoring system", IEEE Tansactions on Power systems, Vol. 7, No. 3, pp. 965-973, August 1992.
16. Claudio A, Cnizares & Sameh K.M. Kodsi, "Tools for voltage collapse assessment," IEEE MELECON 2006, pp. 939-942, May 2006.
17. A.G. Phadke, "Synchronised phasor measurement in power system", in proc. IEEE Computer application in power,vol.6, No.2, Apr.1993, pp. 10-15 .
18. J.D. LaRee, S. Member,V. Centeno, J.S. Thorp, A.G. Phadke, "Synchronised phasor measurement Application in power system", IEEE Transactions on Smart Grid,Vol. 1, No. 1, 2010, pp. 20-27 .
19. J.Brownlee "Classification and regression tree for machine learning", Machine learning mastery, April 8 2016.
20. NP Patidar and Jaydev Sharma "Power system Voltage Security Assessment and Optimal Load Shedding Using CBR Approach" IEEJ Transactions on Power and Energy, Vol. 128, No.11, pp.-1304-1312,2008.

Table 2. Classification of Operating conditions for Line outage-3 OF 400 KV MSETCL-19

Test case number	Class estimated by CPF	Class predicted by Decision Tree with PMU at all 19 buses	Class predicted by Decision Tree with PMU at top 5 ranked buses
1	I	I	I
2	I	I	I
3	I	I	I
4	I	I	I
5	I	I	I
6	I	I	I
7	I	I	I
8	I	I	I
9	I	I	I
10	I	I	I
11	S	I	S
12	I	I	I
13	I	I	I
14	I	I	I
15	S	S	S
16	I	I	I
17	I	I	I
18	I	I	I
19	I	I	I
20	I	I	I
21	I	S	I
22	I	I	I
23	I	I	I
24	I	I	I
25	I	I	I
26	I	I	I
27	I	I	I
28	I	I	I
29	I	I	I
30	I	I	I
31	I	I	I
32	I	I	I
33	I	I	I
34	I	S	I
35	S	S	S
36	I	S	I
37	S	I	S
38	I	I	I
39	I	I	I
40	I	I	I
41	I	I	I
42	I	I	I
43	I	I	I
44	I	I	I
45	I	I	I
46	I	I	I
47	I	I	I

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

छायावाद के प्रवर्तक और आधार-स्तम्भ

हितेश कुमार*

शोध सारांश – प्रारंभ में छायावाद का प्रयोग व्यंग्य रूप में अस्पष्ट कविताओं के लिए हुआ, जिनकी छाया (अर्थ) कहीं और पड़ती थी। परन्तु कालान्तर में, यह नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया, जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता था और वेदना की रहस्यमयी अनुभूति की लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजना की जाती थी। **'प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमयी रहस्यपरक सूक्ष्म अभिव्यंजना लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में जिस काव्य में होती है, उसे छायावाद कहा जाता है।'**

शब्द कुंजी –'प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य का प्रतीक छायावाद।'

प्रस्तावना

छायावादी काव्य का स्वरूप:

1. स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता का चित्रण।
2. रहस्यवादी प्रवृत्ति की विद्यमानता।
3. प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य का काव्य।
4. स्वानुभूति की प्रधानता।
5. अंग्रेजी की रोमांटिक काव्यधारा से प्रभावित।
6. सांस्कृतिक चेतना एवं मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रमुखता।

द्विवेदी युग के प्रतिक्रियास्वरूप, स्थूलता, अतिशय नैतिकता एवं इतिवृत्तात्मकता के विरोध में छायावाद का जन्म हुआ। इसमें अतीत गौरव की अभिव्यक्ति, स्वाधीनता की चेतना, राष्ट्रप्रेम, त्याग और बलिदान, अस्मिता की खोज तथा गांधीवादी जीवन मूल्यों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

छायावाद के प्रवर्तक : पद्मश्री पण्डित मुकुटधर पाण्डेय –आपका जन्म महानदी एवं माण्ड नदी के संगम पर स्थित ग्राम बालपुर, जिला- जांजगीर चाम्पा, छ.ग. (अविभाजित म. प्र.) में एक साहित्यिक खानदान में 30 सितम्बर 1895 को हुआ। हिन्दी में आपकी प्रथम छायावादी कविता 'कुररी के प्रति' है, जिसमें आपने महानदी के तट पर उड़ती चिड़िया को देखकर अपने मनोभाव को अभिव्यक्ति प्रदान की। अभिव्यक्ति इस प्रकार हुई कि एक दिन आधी रात को किसी पक्षी के करुण विलाप से वे नींद से जाग उठे और करुणा से उनके हृदय के तार निम्न पंक्तियों में झंकृत हो उठे-

'बता मुझे ऐ विहग विदेशी अपने जी की बात।
पिछड़ा था तू कहाँ, आ रहा जो कर इतनी रात।।'
'कोई सुने न सुने, सुनता कुछ अपने ही आप।
अंतरिक्ष में करता है तू क्यों अनवरत विलाप।।'
'परदेशी पक्षी, चिंता की धारा को दे मोड़।
अंतर की पीड़ा को दे अब अन्तर-तर से जोड़।।'

आप कवि के साथ-साथ एक कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार भी थे एवं सबसे महत्त्वपूर्ण पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वहन भी किए। आपका निधन 06 नवम्बर 1989 को हुआ।

प्रकाशित कृतियाँ–

1. पूजाफूल, 1916
2. शैलबाला, 1916
3. परिश्रम (निबंध संग्रह), 1017
4. लच्छमा (अनुदित उपन्यास), 1917
5. हृदयदान (कहानी संग्रह), 1918
6. मामा, 1924
7. छायावाद एवं अन्य निबंध, 1979
8. स्मृति-पुंज, 1983
9. विश्वबोध (काव्य संग्रह), 1984
10. छायावाद एवं अन्य श्रेष्ठ निबंध, 1984
11. मेघदूत, 1984

छायावाद के प्रवर्तक पद्मश्री पण्डित मुकुटधर पाण्डेय की काव्यधारा एवं विचारों पर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर (अविभाजित म0 प्र0) के प्रथम कुलपति माननीय शरदचंद्र बेहार जी कहते हैं कि पाण्डेय जी ने भौतिकता, विज्ञान एवं रीतिकालीन प्रवृत्तियों का विरोध किया। उनके अनुसार, कला एवं संगीत, काव्य में निहित होना चाहिए; काव्य में मानव एवं मनुष्य की कोमल भावनाओं का चित्रण होना चाहिए; अपने व्यक्तित्व की छाप कविता पर जो दे न सके, वह कवि नहीं; प्रकृति पर विज्ञान के सहारे विजय न हो; वसुधैव कुटुम्बकम् समाप्त हो गया है और मनुष्य हाशिए पर चला गया है; मानव, मानव न रहकर वह उत्पादक और उपभोक्ता हो गया है। पाण्डेय जी के कविता लेखन के संबंध में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति प्रो0 जी डी शर्मा जी कहते हैं कि 14 वर्ष की उम्र में इनकी कविता के प्रकाशन होने से पाण्डेय जी कविताई में आगे प्रवृत्त हुए। प्रो0 शर्मा जी छायावाद के संबंध में आगे कहते हैं कि खड़ी बोली में प्रकृति की कल्पना करना, प्रेम की अभिव्यक्ति करना छायावादी कवियों के लिए चुनौतीपूर्ण काम था।

1920, भारत में स्वाधीनता आंदोलन के प्रारम्भ का समय था और इसी समय काव्य में सांस्कृतिक जागरण की शुरूआत भी हुई। साहित्य जगत को पाण्डेय जी 'छायावाद' शब्द देते हुए, उन्होंने जबलपुर की श्री शारदा नामक पत्रिका में इसका विस्तृत विश्लेषण किया है। काशी से डॉ0 अवधेश प्रधान छायावाद विचारधारा पर अपना विचार व्यक्त करते हैं कि

*आर/ओ कामसर एच.नंबर 169 वार्ड नंबर 3 तहसील हवेली, जिला पुंछ (जम्मू और कश्मीर) भारत

छायावाद चेतना के सौंदर्य को व्यक्त करता है; सौंदर्यबोध से ही मनुष्य, पूर्ण मनुष्य बनता है; बिना सौंदर्यबोध के मनुष्य डॉक्टर, इंजीनियर सब बन सकता है, परन्तु वह मनुष्य नहीं। प्रधान जी का मानना है कि तकनीकी की सहायता से हम छायावाद की चर्चा कर सकते हैं, छायावाद की रचना नहीं। इनके अनुसार, मानव 'संसाधन' कहना मानव चेतना का अपमान है तथा 'शिक्षा' के द्वारा जिसे हम सम्बोधित करते हैं, वह मनुष्य है।

राजभाषा आयोग छत्तीसगढ़ के पूर्व अध्यक्ष डॉ0 विनयकुमार पाठक जी छायावाद एवं रहस्यवाद में अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि छायावाद प्रकृति की 'मानवीय' चेतना का प्रतिरूप है, जबकि रहस्यवाद प्रकृति की 'ईश्वरीय' चेतना का प्रतिरूप है। छायावाद पर पाठक जी का मानना है कि गीत, छायावाद में उत्कर्ष पर पहुँचा एवं छायावाद में परम्परा का विद्रोह न होकर रूढ़ि का विद्रोह हुआ है। पं0 मुकुटधर पाण्डेय जी की काव्यधारा के संदर्भ में वे लिखते हैं कि पाण्डेय जी ने राष्ट्रीय काव्यधारा को आगे बढ़ाया है।

जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानन्दन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं महादेवी वर्मा छायावाद के चार आधार स्तम्भ हैं। यदि निराला ने उसे जन्म दिया तो प्रसाद ने उसे खड़ा किया, पंत ने उसे सवाँरा और महादेवी वर्मा ने उसमें प्राण प्रतिष्ठित किया।

छायावाद के आधार-स्तम्भ- पं0 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला-छायावादी युग में इनके तीन काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। (1) अनामिका, 1923 ई0, (2) परिमल, 1930 ई0, (3) गीतिका, 1936 ई0। इन संग्रहों में स्वाधीनता की भावना सर्वत्र विद्यमान हैं। इनके अलावा 1938 ई0 में प्रकाशित 'तुलसीदास' नामक कविता में भी छायावादी काव्यांदोलन का स्वर साफ सुनायी देता है। इन्होंने 'जूही की कली' में परम्परावादी काव्य शिल्प को तोड़कर हिन्दी कविता को स्वच्छन्द भाव-भूमि प्रदान की है। 1924 ई0 में 'मतवाला' पत्रिका में प्रकाशित 'बादल राग' कविता में इन्होंने बादल को क्रांति का प्रतीक मानकर लघु मानव के दुख को अपने काव्य की विषय वस्तु बनाया।

'जीर्ण बाहू, है शीर्ण शरीर,
तुझको बुलाता कृषक अधीर,
ऐ विप्लप के बीर !
चूस लिया है उसका सार,
हाड़-मात्र ही है आधार,
ऐ जीवन के पारावार !'

निराला जी के काव्य की विषय-वस्तु सर्वहारा वर्ग के दलित, गरीब, मजदूर किसान रहें हैं। छायावादी युग में रचित 'वह तोड़ती पत्थर', 'दीन', 'गरीबों की पुकार', 'भिक्षुक', 'विधवा' आदि कविताएँ इसके ज्वलंत उदाहरण हैं।

'जागो फिर एक बार' में निराला जी ने स्वाधीनता आंदोलन का शंख फूँका है-

'शेरों की मांद में
आया है आज स्यार
जागो फिर एक बार।'

छायावाद के आधार-स्तम्भ- जयशंकर प्रसाद - इनका 'झरना' काव्य संग्रह 1918 में प्रकाशित हुआ। इसमें छायावादी प्रवृत्तियों का सर्वप्रथम परिचय प्राप्त हुआ। 1931 में 'आँसू' प्रकाशित हुआ। इसमें छायावादी प्रवृत्तियाँ प्रौढ़ रूप में देखने को मिली। यह एक प्रेमकाव्य है, जिसमें कवि का व्यक्तिवाद तथा प्रेम वेदना की दिव्य झाँकी प्रकट हुई है। इस काव्य का नायक कवि स्वयं है। उसके आँसुओं के माध्यम से अतीत संयोग की सुखद स्मृतियाँ उसे झकझोर देती हैं-

'जो घनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति छा गई।
दुर्दिन में आँसू बनकर, वह आज बरसने आई।।'

'लहर' और 'कामायनी' इनके चरम साहित्यिक उत्कर्ष काल की रचनाएँ हैं। 'लहर' इनकी एक मुक्तक रचना है। इस संग्रह में प्रेमगीत, आत्मकथा, राष्ट्रीय गीत, प्रकृति चित्र, ऐतिहासिक आख्यान आदि विषय समाहित हैं।

प्रेमगीत-

'अरे कहीं देखा है तुमने, मुझे प्यार करने वाले को।
मेरी आँखों में आकर फिर, आँसू बन टलने वाले को।।'

प्रकृति चित्र-

'बीती विभावरी जाग री'

प्रसाद जी की कला का सर्वोच्च शिखर 'कामायनी' है। छायावादी युग का यह सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें मनोविकारों के सूक्ष्म चित्र, प्रकृति का मनोरम चित्र, नारी सौंदर्य एवं प्रणय के चित्र, प्रतीक चित्र, भाषा के चित्रात्मक लाक्षणिक चित्र जितने प्रभावकारी और सुन्दर है, उसका उद्देश्य उतना ही लोकोपकारी एवं आदर्श रूप है।

छायावाद के आधार-स्तम्भ- सुमित्रानंदन पंत-सुमित्रानंदन पंत का छायावादी काव्यधारा को संवारने में अद्भुत योगदान है। इनके काव्य की विशेषता यह है कि विषय-वस्तु की भिन्नता होने पर भी उनमें कल्पना की स्वच्छंद उड़ान, प्रकृति के प्रति आकर्षण और प्रकृति एवं मानव जीवन के कोमल और सरस पक्षों के प्रति अटूट आग्रह है। वे 'कल्पना तत्त्व' पर लिखते हैं- 'मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ,........मेरा विचार है कि 'वीणा' से लेकर 'ग्राम्या' तक अपनी सभी रचनाओं में मैंने अपनी कल्पना को ही वाणी दी है।'

अपने कवि जीवन के आरम्भिक दौर में पंत जी प्राकृतिक सौंदर्य से इतने अभिभूत थे कि नारी सौंदर्य के आकर्षण को भी उसके सम्मुख न्यून मान लिया था-

'छोड़ द्रुमों की मृदु छाया,
तोड़ प्रकृति से भी माया।
बाले तेरे बाल - जाल में,
उलझा दूँ मैं कैसे लोचन ?'

संध्या को एक आकर्षक युवती के रूप में मौन मंथर गति से पृथ्वी पर पदार्पण करते हुए दिखाकर कवि ने संध्या का मानवीकरण किया है-

'कौन तुम रूपसी कौन,
व्योम से उतर रही चुपचाप,
छिपी निज माया में छवि आप,
सुनहला फैला केश कलाप,
मंत्र मधुर मृदु मौन।'

पंत के काव्य में प्रकृति के विभिन्न रूप मिलते हैं, जो छायावादी काव्य की विशेषता है। प्रकृति के प्रति सुकुमार दृष्टिकोण, पंत जी की अपनी निजी विशेषता है।

छायावाद के आधार-स्तम्भ- महादेवी वर्मा - इनके काव्य का मूल स्वर दुख और पीड़ा है। इनकी रचनाओं में विषाद का वह भाव नहीं है, जो व्यक्ति को कुंठित कर देता है, बल्कि संयम और त्याग की प्रबल भावना है।

'मैं नीर भरी दुख की बदली,

विस्तृत नभ का कोई कोना,
मेरा कभी न अपना होना,
परिचय इतना इतिहास यही,
उमड़ी थी कल मिट आज चली।'

आधुनिक मीरा के नाम से अभिहीत 'महादेवी वर्मा' को निराला जी ने 'हिन्दी के विशाल मन्दिर की सरस्वती' भी कहा है।

'नीहार' इनका प्रथम कविता संग्रह है, जिसके बारे में वे खुद लिखती हैं– 'नीहार के रचना काल में मेरी अनुभूतियों में वैसी ही कौतूहल मिश्रित वेदना उमड़ आती थी, जैसे बालक के मन में दूर दिखायी देने वाली अप्राप्य सुनहली उषा और स्पर्श से दूर सजल मेघ के प्रथम दर्शन से उत्पन्न हो जाती है।' 1934 में प्रकाशित तीसरा कविता संग्रह 'नीरजा' में रश्मि का चिंतन और दर्शन अधिक स्पष्ट और प्रौढ़ हो जाता है। इसमें कवयित्री सुख–दुख में समन्वय स्थापित करती हुई पीड़ा एवं वेदना में आनंद की अनुभूति करती है। 1934 से 1936 तक रचित गीतों के संग्रह 'सांध्यगीत' में आँसू और वेदना, मिलन और विरह, आशा और निराशा एवं बन्धन–मुक्ति आदि का समन्वय है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. इस्लाम बाबू, निराला के छायावादी काव्य में समय से संघर्ष तथा स्वाधीनता की भावना, अलीगढ़।
2. hindikunj.com (जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में)
3. hindivibhag.com (सुमित्रानंदन पंत के संदर्भ में)
4. hi.unionpedia.org (महादेवी वर्मा के संदर्भ में)

****

21वीं सदी की चुनौतियाँ : मीडिया और साहित्य आलेख में आश्वस्त हूँ और आपको करना चाहता हूँ

डॉ. हजारी लाल मौर्य*

प्रस्तावना – भारत का परम आदिकालीन मीडिया था, नारद। यहाँ की सूचना वहाँ, वहाँ की सूचना यहाँ। आज प्रेस, टेलीविजन और इन्टरनेट ने नारद का स्थान ले लिया है। रेडियों लगभग खत्म हो चुका है और पत्रिकाएँ भी। ना नारद 'सूचना' देने में ईमानदार था ना आज का मीडिया है। सूचना प्रदाता की अपनी यसुरता' होती है तथा सूचना गृहीता की अपनी 'सुरता'। प्रत्येक सूचना 'समाचार' नहीं होती। प्रत्येक घटना के गवाह नहीं होते। प्रत्येक समाचार यज्ञान' होता है लेकिन प्रत्येक ज्ञान 'शिक्षा' नहीं होता। प्रत्येक शिक्षा 'बुद्धि' नही होती ओर सारी बुद्धियों के समुच्चय को 'विवेक' कहते है। विवेक, बुद्धि (तर्क प्रक्रिया के निष्कर्ष) ज्ञान, समाचार, सूचना और घटना को मनुष्य अपने जिस विशाल सॉफ्टवेयर में धारण करता है वह यसुरता' कहलाता है। यसुरता' शब्द का उपयोग कबीरदास रैदास आदि ने उस समय किया था जब सॉफ्टवेयर शब्द हमने सुना समझा नहीं था। समझते भी कहाँ से यूरोप के पास ऐसा कोई शब्द था ही नहीं। यसुरता' का लगभग सही अंग्रेजी है सॉफ्टवेयर। उर्दू में कहें 'होश'।

मेरी बात कहने से पहले मैं पारिभाषिक रूप से बताना चाहता हूँ कि यह दुनियाँ सरल रेखा की भाँति सीधी नहीं है बल्कि जलेबी की तरह प्रपचांत्मक है। आपकी जेब में रखा एक किलो सोना आपके परममित्र के दिमाग में इस विचार को पैदा कर सकता है कि वह आपकी हत्या कर दे। इसीलिए गीतकार पूछता है कि 'वाई दिस कोलावेरी कोलावेरी कोलावेरी डी।' कोलावेरी का अर्थ है प्रपंच। सभ्य हुए जाने की प्रक्रिया में मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रपंचों को मैं 'संस्था' कहता हूँ। ऐसी 134 संस्थाऐं मैंने ट्रेस आउट की है। जिन्हें मैंने 'सामाजिकता के सार्व' नामक पुस्तक में लिखा है। संक्षेप में यह कि हर संस्था का (या हर प्रपंच का) एक विचार या धर्म होता है उसका एक आदर्श या लक्ष्य होता है। कुछ उसके करण या उपकरण होते है जिनके माध्यम से कोई प्रपंच अपना आकार ग्रहण करता है। हर संस्था की ऐतिहासिक और समकालीन परिघटनाएँ होती है और जब से संस्था पैदा हुई तभी से उसके विचलन भी होते आये है। संस्थाओं में प्रपंच के गुण इसीलिए है कि वे मनुष्य से उत्पन्न हुई और मनुष्य को ही गुलाम बनाकर बैठ गई और अमरता भी प्राप्त करली वे मनुष्य पर इस प्रकार प्रभाव डालती है हिक स्वयं मनुष्य भौंचक रह जाता है कि जिस परिणाम की वह सपने में भी अपेक्षा नहीं करता वह परिघटित हो जाता है और जिसके पीछे कारण कोई प्रपंच होता है। संस्थाओं के समस्त पहलू मनुष्य की समझ से बाहर हो गये। अमेरिका की मूल प्रजाति 'अज्टेक' अत्यन्त आश्चर्य चकित रह गई जब जहाज के आविष्कार के बाद यूरोपीय लोगों ने उन्हें मार मारकर सोना हासिल किया। सोना उनके यहाँ पहाड़ में पड़े ढेलों से ज्यादा कीमती नहीं था। यह और भी आश्चर्य था कि यूरोपीय एक दूसरे को भी प्रत्यक्ष और षडयन्त्रपूर्वक मार रहे थे।

ठीक ऐसा ही आश्चर्य 21वीं सदी के मीडिया ने दिये। विश्व में घटित हो रही घटनाओं को सूचना या ज्ञान बनाकर देखना एक सीधी सी, सरल रेखीय, परिघटना होनी चाहिये। लेकिन सूचना को एकत्र करने में आये श्रम की कीमत, सूचना से उत्पन्न नाम, सूचना की वजह से जनता द्वारा लिये। किये गये निर्णय, स्वयं को सूचना बना देने की तड़प, तड़प की पूर्ति के लिए धन खर्च कर देने की इच्छा, सूचना से धन कमा लेने की इच्छा, सूचना से असत्य को सत्य बना देने की क्षमता, बड़ी सूचना को छुपाने के लिए छोटी या अन्य सूचना के आकार को पहाड़ बना देने जैसे पहलुओं ने 'सूचना' 'समाचार' या 'ज्ञान' को जलेबी से भी ज्यादा वक्र रेखीय और प्रपंचात्मक बना दिया। कितना आश्चर्यजनक था कि एक युवा ने अपना नाम अखबार में छपा देखने केलिए आत्महत्या करली। सूचना के प्रपंच को और विस्तार देने में 21वीं सदी या भारत के एक कानून द्वारा उत्पन्न मजबूरी ने तगड़ी भूमिका निभाई। वह मजबूरी है एक समाचार चैनल को दिनभर चलाए रखने हेतु उपग्रह के ट्रांसपोण्डर का किराया, संवाददाताओं की तनख्वाह, मंहगें कैमरे, मंहगे विस्तारक यन्त्र, उन यन्त्रों के संचालकों का मोटा वेतन और समाचार को इतना रोचक बनाये रखना कि टी.आर.पी. बनी रहे, आदि के लिए लगभग एक करोड़ रूपये प्रतिदिन कमाने की। भारत का दर्शक मुफ्त में सरकारी चैनल देखने वाला है। उससे प्रतिदिन एक करोड़ रूपये वसूल कर पाना अत्यन्त कठिन ही नहीं असम्भव कार्य है। इसलिए काहिर्मक या संवाददाता पर दबाव होता है कि वह कमाऊ बने। कमाऊ दो तरह से बनता है या तो विज्ञापन बटोर कर लाये या जनता को बांधे रखने वाले 'समाचार' लाये। यह कमाऊपन फिर प्रपंचात्मक हुआ। विज्ञापन बटोरू कार्मिकों ने धनपत्तियों की कमजोरियाँ पकड़कर ब्लेकमेल करके विज्ञापन बटोरने की विधि निकाली और लुभावने समाचार बटोरू कार्मिकों ने आत्महत्या तक को 'प्रायोजित' करके 'समाचार' बनाया। इस सारे कोढ़ में खाज पैदा की लोकतंत्र ने। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर शासक को गरियाना उसकी प्रमुख प्रवृत्ति बनी। लगा कि मीडिया बहुत 'बोल्ड' हो गया। ऊपर से 'बोल्ड' दिखने वाला मीडिया अन्दर से, 'टुकड़े' डालने वाले नेताओं के समक्ष, कुत्ते से भी बदतर स्थिति में है। 'बोल्ड' होने और 'टुकडखोर' होने ने नेताओं की अमेज भी खराब कर दी और स्वयं की भी खराब करली। इसी का नतीजा था कि अन्ना हजारे जैसा एक 'सभ्य गुण्डा' यह कह सका कि पिछले 60 साल से सत्ता 'गद्दारों' के हाथ में रही है। अन्ना हजारे को लगता था कि यह जनता इसी तरह उसके पीछे लगी रहगी और मीडिया को लगता था कि अन्ना ही सबसे बिकाऊ 'समाचार' है। इस अति में उसने जो किया वह हम सबने

* सह-आचार्य (हिन्दी) राजकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, कोटपूतली, जिला जयपुर (राज.) भारत

देखा।

सीधी सी बात कि मीडिया तो 'सूचना' का मीडियम है। मीडियम मतलब करण, उपादान, साधन, माध्यम, हेतु, उपकरण जिसकी स्वयं की कोई बुद्धि नहीं। बुद्धि, निष्कर्ष, निर्णय, क्रिया, प्रतिक्रिया, परिणाम, आन्दोलन आदि तो श्रोता के हिस्से के नाटक है। लेकिन मीडिया ने स्वयं को न्यायाधीश, कानून के जानकार, नैतिकता के ठेकेदार, विचलनों के विरूद्ध सरकार को आदेश देने के ठेकेदार, स्वयं के तक्रजाल को एकदम सही मानने वाले जिद्दी, ओछी व असम्माननीय भाषा बोलने वाले अनाड़ी, इतिहास का पुरोधा, हिन्दुत्व या धार्मिक भावनाओं के आहत होने के ठेकेदार, मुस्लिमों के रखवाले, दलितों के प्रहरी, औरतों के उद्धारक, सन्तों की महानता को बेशक सिद्ध करने वाले, अन्याय के विरूद्ध एकमात्र जागरूक सिद्ध करने के लिए अनेक बेइमानियाँ, बेशर्मियाँ, अन्याय, अमानवीयता, अतियाँ क्रूरताएँ, छल व घटिया व्यापार किये और कर रहा है। वह जनता को इतनी भोली, मूर्ख, अनुयायी, पिछलग्गू, अज्ञानी और लिजलिजी मानता है हिक उसे यह भ्रम हो गया है हिक वह जनता से सब कुछ करवा सकता है और सत्ता को चाहे जब, चाहे जितनी, चाहे जहाँ झुका सकता है। सत्य इससे बहुत भिन्न है। मिडिया को संरक्षण, स्वाधीनता, प्रविधि सुरक्षा आदि राजसत्ता ही देती है और वह जब चाहे इन्हें खत्म भी कर सकती है। जब मीडिया इतना बड़ा प्रपंच हो गया है तो राजा या राज्य तो अत्यन्त बड़े प्रपंच है। जो कार्य ईश्वर नहीं कर समता वह राजा कर देता हैे। इसीलिए माननीय कांशीराम जी ने कहा था कि 'सत्ता' सौ तालों की एक चाबी है। राजा राजा ही होता है चाहे वह 'राष्ट्रपति' के रूप में हो या चांसलर, तानाशाह, राणा या दीवार के रूप में। वह सबको दण्डित कर सकता है। उस पर कोई मुकदमा भी नहीं कर सकता है। वह प्राण नहीं दे सकता तो भी प्राण ले सकता है। अकबर ने गंगकवि को हाथी से कुचलवा कर मरवा दिया था। भारत सरकार का एक कानून मीडिया के 'डायनो' रूप को 'माइनों' में बदल सकता है। इसलिए कह सकते है कि मीडिया में संसथा होने का गुण 'अमरता' नहीं है। इसलिए कह सकते है कि मीडिया में संस्था होने का गुण 'अमरता' नहीं है। संस्थाएँ अमर होती है मीडिया अमर नहीं है।

अमरता का गुण है सूचना और ज्ञान में। जब तजक मनुष्य रहेगा तब तक सूचना के रूप में 'ज्ञान' और प्रक्रियाज्ञान के रूप में 'ज्ञान' रहेगा। सूचना ज्ञान पर उपनिषदकारों ने खूब माथा खपाया और इस ज्ञान को कहा यजानना ही होना है' अर्थात् जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है यह तभी सिद्ध है जब आप इसे जानते हैं। अफ्रीका का जो व्यक्ति इसे नहीं जानता उसके लिए यह विश्वविद्यालय नहीं है। आपमें से भी जो मुझे जानता है उसके लिए मैं हूँ जो मुझे नहीं जानता उसके लिए मैं नहीं हूँ। हम सब भी अगर राम की बुआ चन्द्रभागा को जानते है तो वह इतिहास में है वरना वह नहीं है। मीडिया और साहित्य में यह समानता है कि वे हमें जनाते हैं। जनाते शब्द का अर्थ जन्म देने के अर्थ में भी आप ग्रहण करें तो उचित ही होगा। ज्ञान का दूसरा रूप प्रक्रिया ज्ञान है जिसमें किसी कार्य के होने में कार्यरत कारण की तलाश होती है। किसी कार्य और उसके पीछे के कारण को जानना ज्ञान का दूसरा रूप है। नरेन्द्र कोहली के उपन्यास 'महासागर' की प्रशंसा का आधार यही था कि उसने महाभारत की घटनाओं (कार्यो) के पीछे निहित दबावों (कारणों) को तर्क सम्मत बना दिया था। वे तक्र बहुत सी जनता को ग्रहण हो सके थे।

परन्तु साहित्य में भी प्रपंच के गुण होते हैं। घटनाओं को कितना भी सीधा किया जाये उनके पेच बाकी रह ही जाते हैं। हम सब जानते है कि सोने का मृग कभी नहीं बना या पैदा हुआ फिर राम उसके पीछे क्यों दौड़ा? क्या यह राम की मूर्खता नहीं थी? पूरी रामायण में सीता या राम की दानशीलता नहीं मिलती पर रावण को कार लाँघकर भी भिक्षा देने की जिद क्या किसी तक्र से सिद्ध है? बली के घर कभी कोई ब्राह्मण भिक्षा माँगने नहीं आया फिर भी बावन्या को भिक्षा देना कही कोई बुद्धि है? जुआ खेल कर कभी कोई धनवान नहीं हुआ फिर युधिष्ठिर ने किस वीरता का परिचय दिया? मेरे इस काल में यहाँ उपस्थित और अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत विद्वानों, बुद्धिमानों और विवेकशीलों के पास इसका कोई उत्तर नहीं है।

इस प्रकरण में कहना चाहिये कि साहित्यकार और साहित्य दोनों में संस्था या प्रपंच के गुण है। साहित्य सहित है और साहित्यकार दुखी का हितकारी है। दुख निवारणकर्ता के रूप में तीन संस्थाएँ कार्य करती है। ईश्वर, राजा और साहित्यकार। राजा स्वयं ही जब दुख प्रदाता हो तो साहित्यकार दुखत्राता हो सकता है। इसके लिए साहित्यकार तीन प्रकार से बिम्ब बना सकता है एक भौतिक बिम्ब, दूसरा नाटक बिम्ब और तीसरा नाम रूपात्मक पठनीय बिम्ब। भौतिक बिम्ब बनाये बीरबल और अष्टावक्र ने। बीरबल का खिचड़ी पकाकर राजा की अक्ल ठीक करना जगत प्रसिद्ध बिम्ब है। अष्टवक्र ने राजा जनक की मूर्खतापूर्ण जिद को तोड़ा जिसमें वह कहता था कि राजा कुछ भी करने में सक्षम है और मैं पुत्री से विवाह करूंगा। दूसरा बिम्ब नाटक है जिसके विभिन्न स्वरूप है यथा रामलीला, रामसीला, नौटंकी, नुक्कड़, नाटक, फिल्में, धारावाहिक आदि। लेकिन ये जनता या व्यक्ति विशेष का हित करने के लिए राजा की अक्ल ठीक करने में पर्याप्त सक्षम नहीं है।

तीसरे नामरूपात्मक बिम्ब महाकाव्यों, उपन्यासों, पठनीय नाटकों और कहानियों में होते है ये व्यक्तियों की बुद्धि को विवेक में बदलने से ज्यादा हितकारी नहीं होते। इनके रचनाकारों का व्यक्तित्व गौण हो जाता है और रचना उनसे ज्यादा बड़ी हो जाती है फिर बहस का मुद्दा उसके द्वारा निर्मित बिम्ब रह जाता है वह स्वयं नहीं। तुलसीदास द्वारा अपरण से पूर्व सीता का अग्नि प्रवेश करवाया जाना ऐसा ही एक बिम्ब है। ऐसे बिम्बों से राजा की अक्ल ठीक करने का काम लगभग नहीं होता। साहित्य समाज का दर्पण नहीं होता। दर्पण सत्य बोलता है। साहित्यक रचना और साहित्यकार द्वारा किये गये बिम्ब निर्माण यअसत्य' है और इन्हीं असत्यों के सहारे रचनाकार इतिहास, तथ्य, सत्य और व्यापक मानवता को बचाता है। साहित्य का विचार (प्रेमचन्द के शब्दों में उद्देश्य) प्रगतिशीलता भी नहीं है। प्रगति वर्तमान में उपलब्ध स्थायित्व को तोड़कर नया (अच्छे या बुरे की परवाह किये बिना) निर्माण करने का नाम है। आज का नया कल पुराना हो जायेगा। प्रगति पुराने के सापेक्ष लगातार चलने वाली गतिविधि है और 134 संस्थाओं के विचार और आदर्श अपरिवर्तित और अमर होते है उनकी परिघटनाएँ बदलती है। कभी–कभी ये संस्थायें अपने करण भी बदल लेती है। वरना ये 134 संस्थाएँ यथास्थिति या जड़त्व ही चाहती हैं। साहित्य का विचार मनोरंजन, मन बदलाव और व्यंग्य करना भी नहीं है। मनबहलाव उद्देश्यहीन भी होता है। मनोरंजन अर्थात् मन को रंगा जाना अच्छा और बुरा भी हो सकता है। व्यंग्य तो गाली से अधिक कुछ नहीं है। व्यंग्य से तिलमिलाता व्यक्ति और राजसत्ता दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी प्राप्त करके सत्य का लेखन या प्रदर्शन भी साहित्य का विचार नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी भी व्यक्ति को नंगा करके देखना कानूनन अपराध न हो तो भी घोर अनैतिक कार्य है। राजसत्ता तो इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करती। वह ऐसे साहित्यकारों को मरवाने में कोताही नहीं बरतती। अकबर ने गंग को मरवा ही दिया। लेकिन किसी अज्ञात

साहित्यकार ने एक बिम्ब बनाकर राम के कुल में पथ भ्रष्ट लड़की 'चन्द्रभागा' (दशरथ की बुआ) के इतिहास को जीवित रख लिया। यही चन्द्रभागा नासिकेतु और श्रवण कुमार की माता थी। कंवारी माता बनी और नासिकेतु ने उनका विवाह कराया। साहित्य का विचार है तथ्य प्रस्तुत करके शिक्षा देना और विवेक का व्यक्ति में जन्म करवाना। विवेक मनुष्य द्धारा हासिल करली गई बुद्धियों के समुच्चय को कहते हैं। कन्फ्यूशियस विवेक जागरण की इस प्रक्रिया को 'औचित्य की जाँच' कहते हैं। औचित्य की जाँच होने से व्यक्ति के दु:खों का निवारण होता है। दुखों के निवारण दुखों को समाप्त करके सम्भव नहीं होता। दुखी होना व्यक्ति की मानसिकता पर निर्भर करता है। इसलिए साहित्य अनुकूलन सिखा कर दुख मुक्ति करता है। यही साहित्य का विचार और आदर्श है।

अब प्रश्न है इक्कीसवीं सदी की चुनौतियों के मध्य मीडिया और साहित्य की गति का। मीडिया एक करण मात्र है। तोता, कबूतर, हरकारे, ढाढी, बनजारे, डाकिया, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, अखबार, पत्रिकाएँ और इन्टरनेट में से किसी में भी अमरता का गुण नहीं है अत: इनके बदलते स्वरूप पर मातम मनाने की कोई जरूरत नहीं है। रहा सवाल साहित्य का? तो बता देना चाहता हूँ कि साहित्य के कारण लगभग वैश्विक ही रहते आये है। तेरहवीं शताब्दी के आसपास डाकण, चुडैल और स्यारण की अवधारणा भारत में यूरोप की तरफ से ही आई थी। बाद में फीनिक्स भी भारत में आया और यअनल' पक्षी या 'अगनपाखी' कहलाया।

इसीलिए कबीर ने इसका प्रयोग किया है–

मनदीयाँ मन पाइये, मनबिन मन नही होय।
मन उनमन उस अण्ड ज्यों अनल आकसां जोय।।

दादू और रैदास ने भी अनल शब्द का प्रयोग इसी अवधारणा के रूप में किया है। अत: मानना चाहिये कि साहित्य के नये करण हमेशा ही वैश्विक यात्रा करके विश्राम लेते हैं। साहित्य का विचार और आदर्श काल और देश से लगभग्र मुक्त हैं। समस्त संस्थाओं की परिघटनाएँ बदलती है आदर्श और विचार नहीं बदलते हैं। वे शास्वत हैं। मैं आश्वस्त हूँ और आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 21वीं सदी में चुनौती साहित्य को नहीं साहित्य के करणों और उपकरणों के सामने आयेगी। जो विज्ञान के प्रारम्भ अर्थत् फ्रांस की क्रान्ति के बाद से ही आ रही है। विज्ञानवादियों की जिद है हिक जीवन को सीधा करके जिया जाये। साहित्य के करण साहित्य की विधाएँ है और उपकरणों की एक लम्बी सूची है जिनमें श्राप, वरदान, स्वर्ग, नरक और अन्य साहित्यक मिथ हैं। आश्चर्य नहीं है कि पिछले 300 वर्ष में साहित्य में नये उपकरणों का निर्माण नहीं हुआ है। विज्ञान द्धारा साहित्य को दी गई चुनौती इस शताब्दी में भी रहेगी। जीवन प्रपंचनात्मक है उसे न सीधा होना है न होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. कबीर ग्रन्थावली, श्याम सुन्दर दास, 1986.
2. वाक्य पदीपम, भर्तहरि, 2007
3. विखण्डन की सैद्धान्तिकी: देरिदा– सुधीश पचौरी

****

लोकतंत्र में व्यवस्थापिका की भूमिका

डॉ. नीरजा शर्मा *

शोध सारांश – लोकतान्त्रिक व्यवस्था में व्यवस्थापिका का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह विधि निर्माण का कार्य करती है परन्तु समय की बदलती हुई आवश्यकताओं और जटिल होते हुये समाज में इसकी भूमिका एवं कार्यो का जटिल हो जाना स्वाभाविक है। समाज की समसायायिक आवश्यकताओं, जनसाधारण की आशाओं व आकांक्षाओं के अनुरूप अपने को ढाल लेने की प्रवृति किसी भी लोकतांत्रिक पद्धति में व्यवस्थापिका के लिए आवश्यक होती है। भारत विविधताओं का देश है इसके विषम समाज की आकांक्षाओं के अनुसरूप कार्य करना व इसकी आवश्यकताओं को पूरा करना व्यवस्थापिका के लिए एक चुनौती पूर्ण कार्य होता है।

भारतीय संसद भी महत्वपूर्ण विधिक कार्यो का सम्पादन करती है। प्रशासन के कार्यो पर निरंतर दृष्टि रखना तथा उसे निरंकुश होने से बचाये रखने का कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वित पर नियंत्रण, जनता की हितों के प्रतिकूल किये जाने वाले कार्यो की निगरानी, जनहित का संरक्षण, जनता की समस्याओं को प्रकाश में लाने के लिए एक मंच प्रदान करना एवं जनता के बीच से नवीन नेतृत्व को उभारने के लिए प्रशिक्षण कार्य करना आदि वे अन्य कार्य हैं जिन्हें भारतीय व्यवस्थापिका (संसद) सम्पन्न करती है। विधि निर्माण व कार्यपालिका पर नियंत्रण जैसे प्राथमिक कार्यो के सम्पादन के साथ ही व्यवस्थापिका विचार विमर्श के उपरांत एक मंच के रूप में कार्यो को करती है।

प्रस्तावना – भारतीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद का अर्थ होता है वाद-विवाद या विचार विमर्श करने वाली एक सभा। इस शब्द का उपयोग प्राचीन काल में विभिन्न सम्मेलनों के लिए भी किया गया था। मध्यकाल में राजतंत्र व चर्च के मध्य संघर्ष एक प्रमुख घटना रही है। इसी समय चर्च प्रमुखों व राज प्रमुखों के मध्य समझौता सम्मेलनों को पार्लियामेंट के नाम से संबोधित किया गया है। लुई ग्यारहवें और पोप इन्नोसेंट चतुर्थ के मध्य 1245 ई. में होने वाला सम्मेलन और इसके एक वर्ष पूर्व हुए स्कालैण्ड ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग 1239 ई. में पादरियों आर्लो और लार्डो की महान परिषद के लिए उपयोग किया गया था।

इस प्रकार व्यवस्थापिका एक ऐसा स्थान है जहाँ राज्य की समस्त नीतियों, लक्ष्यों, विषयों इत्यादि पर वाद-विवाद एवं विचार-विमर्श होता है इसमें शासन संबंधी सभी बातों पर विचार-विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिये जाते हैं। इस कृत्यों के माध्यम से व्यवस्थापिका अपने देश के विभिन्न हितों के मध्य समन्वय लाने का प्रयास करती है। आधुनिक सांसदों का उदय विधायी और न्यायिक कार्यो के केन्द्रीयकरण के फलस्वरूप हुआ। समय के साथ करारोपण व पूर्ति पर मतदान के कार्य भी इसके साथ जोड़ दिये गये। मध्य युगों में आमतौर पर राजा सहित परिषद की बैठक हुआ करती थी जिसमें न्यायाधीश भी आमंत्रित किये जाते थे। इन न्यायाधीशों की सहायता से राजा के समक्ष प्रस्तुत याचिकाओं और न्यायप्राप्ति के लिये की गई प्रार्थनाओं पर निर्णय दिया जाता था। ऐतिहासिक दृष्टि से इसका अवलोकन करें तो मैग्नाकार्टा के पश्चात् प्लैण्टगनैअ काल में पालियामेंट के उदय के चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं। सन् 1254 में सम्राट हेनरी तृतीय ने पार्लियामेंट की बैठक में भाग लेने वाले प्रत्येक काउन्टी से दो-दो नाइटों को बुलाया था। प्रस्तावित करो के संबंध में सामन्तों के मुखिया साइमन डिमाण्डफोर्ट की विजय हुई। उस समय संसद के यह बीज अंकुरित हुये बगैर ही मुरझा गये। इसके पश्चात् सन् 1295 सम्राट एडवर्ड प्रथम ने युद्ध के लिये धन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये सामन्तों व पादरियों के अलावा नागरिक प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया। प्रथम बार साधारण जनता के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया था अत: इसी सभा को मॉडल 'पार्लियामेंट' के नाम से सम्बोधित किया जाता है प्रकार्यत्मक दृष्टि से संसदीय संस्थाओं के स्वरूप समयानुसार परिवर्तित होते रहते हैं। विभिन्न देशों में भी इसकी भिन्न-भिन्न क्रियाएं एवं प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। इंग्लण्ड की सर्वोच्च संसद से लेकर गैर प्रभावशाली रूसी ड्यूमा एवं स्पेन की शक्तिविहीन संसद (कार्टेज) भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग कार्यो का सम्पादन करती रही है और नवीन स्वरूप धारण करती रही है। सम्पादन क्रिया जाने वाले कार्यो का अध्ययन समुचित व सामान्य दृष्टिकोण के आधार पर किया जाना ही उचित होगा। इस समन्वित व सामान्य दृष्टिकोण से बने प्रारूप की कसौटी पर कसकर भारतीय संदर्भो में संसद के कार्यो व उसकी प्रभावशाली का अध्ययन अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। इस संबंध में माइकल काइट्रिश ने इस सभी कार्यो को अनुदित करते हुये व्यवस्थापिका के द्वारा सम्पन किये जाने वाले विभिन्न कार्यो को वर्णित किया जाता है।

व्यवस्थापिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य विधि का निर्माण करना है। लोकतांत्रिक पद्धति में सरकार द्वारा विधेयक प्रस्तावित किय जाते हैं तथा व्यवस्थापिका भी इस विचार-विमर्श करने के पश्चात् उनको यथावत एवं संबोधित रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। विधेयको को पूर्णत: वैद्यता प्रदान करने के लिये इसके तीन वाचन करने की प्रथम प्रचलित है। ऐसा यह मानकर किया जाता है कि किसी नवीन नियम निर्माण को पूर्णत: जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए और इनको तीन वाचनों के मध्य पर्याप्त समय होना चाहिये। साम्यवादी देशों में इसके विपरीत विधेयकों का स्वीकार करने का कार्य समितियाँ करती हैं। सोवियत संघ और चीन इसके मुख्य उदाहरण हैं। जहां क्रमश: स्थाई तथा Presidium उन्हें स्वीकार करती है। इन समितियों में दल का वर्चस्व होता है। तथा इन विधेयकों को Deekree (डिक्री) के

* एसोसिएट प्रोफेसर, महारानी श्री जया कॉलेज, भरतपुर (राज.) भारत

नाम से जाना जाता है बाद में वैद्यता प्रदान करने के लिए व्यवस्थापिका इसे स्वीकार करती है। व्यवस्थापिका का महत्व इसी बात से प्रतिपादित होता है। अन्तत: स्पष्ट है कि कोई भी शासन तंत्र क्यों न हो वैद्यता प्रदान करने के लिये जनप्रतिनिधित्यात्मक संस्था का ही सहारा लेना पड़ता है।

संसदीय संस्थाएं भारतीय शासन तंत्र के सदा घूमते रहने वाले पहिये हैं। इन संस्थाओं के कार्य परिणामों का लेखा-जोखा हमारे लोकतंत्र गणराज्यों में जनतन्त्रात्मक उद्यन के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हमारे संविधान के अन्तर्गत केन्द्रीय विधान मण्डल को संसद की संज्ञा दी गई है और यह संसद हिंसदनात्मक सिद्धांत के आधार पर संगठित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 76 में लिखा है कि 'संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों ही सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमश: राज्यसभा और लोकसभा होंगे।' भारत में संसदात्मक लोकतंत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिये व्यवस्था और कार्यपालिका का समन्वय करना सिद्धान्तत: आवश्यक था। अत: राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न भाग बनाया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में **ग्रेनविल आस्टिन** ने भी लिखा है कि 'विधायी अनुच्छेदों को निर्धारित करते समय संविधान सभा का लक्ष्य लोकप्रिय जनमत को शासकीय कक्ष में लाकर भारतीयों को यह बताना है कि वे अपने समाज से में रहे हो परन्तु वे एक राष्ट्र है।' इसी संदर्भ में **दुर्गादास बसु** ने भी लिखा है कि 'भारतीय संविधान में अदभुत ढंग से अमरीका न्यायपालिका की सर्वोच्च के सिद्धांत एवं इंग्लैण्ड की संसदीय प्रभुसत्त के सिद्धांत के बीच का मार्ग अपनाया गया है।'

भारतीय संसद की संवैधानिक स्थिति (क्या संसद सम्प्रभु है?) इस संबंध में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि 'जनतंत्रात्मक प्रणाली का केन्द्र बिन्दु देश की संसद है प्रशासन की बागडोर चाहे किसी दल या वर्ग के हाथ में हो, जब तक संसद के अधिकार अक्षुण्ण हैं और कार्य क्षेत्र तथा कार्य संचालन की दृष्टि से उसका स्वरूप सम्प्रभु है। वह राष्ट्र बड़े-बड़े संकट का सामना कर सकता है।'

संसद की सम्प्रभुता पर विचार ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सर एडवर्क कोक का मत है कि 'संसद की शक्ति और अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि इसकी कोई सीमाऐं नहीं बांधी जा सकती' इसी व्यवस्था में डीलो में ने तो ब्रिटिश संसद के संबंध में यहां तक कह डाला है कि 'संसद सभी कुछ कर सकती हैं सिवाय स्त्री को पुरूष और पुरूष को स्त्री नहीं बना सकती हैं।' वस्तुत: ब्रिटिश संसद को जो अपरिबन्धित शक्तियाँ प्राप्त है इसे, संसदीय सार्वभौमिकता या सम्प्रभुता कहा गया है। संसद जो कुछ भी चाहे किसी भी रूप में चाहे विधि निर्माण कर सकती है तथा संसद जो कुछ विधि स्वीकृति करेगी वह देश का कानून होगा।

भारत में संसदीय ढाँचे की पद्धति को अपनाया गया है। भारतीय संविधान का स्वरूप किसी विदेशी संविधान का अनुकरण मात्र न होकर अपने में एक अनुपम और नवीन प्रयोग है। हमारे संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे कि ब्रिटिश ढंग की संसदीय प्रभुता स्वीकार करने में अनेक संस्थात्मक कठिनाईयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। वे तो भारत के लिए व्यावहारिक शासन व्यवस्था चाहते थे।

भारतीय संसद की सम्प्रभुता का प्रश्न अनेक अवसरों पर वाद-विवाद का कारण बना है। केशवानन्द भारतीय के मामले मं पालकीवाला ने इसी प्रश्न को उठाते हुए संसद की शक्तियों को मर्यादित बतलाया है उसके अनुसार संसद के क्षणिक बहुमत के द्वारा बुनियादी मानव स्वतंत्रता का हरण नहीं किया जा सकता। संसद संविधान के आधारभूत एवं मौलिक तत्वों को संशोधित नहीं कर सकती। महान्यायवादी नीरेन डे का मत था कि संसद के संविधान संशोधन के अधिकार पर कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती। प्राय: भारतीय संसद की स्थिति ब्रिटिश संसद से की जाती है जो उचित नहीं है। डॉ. सुभाष कश्यप का मत है कि 'भारत में प्रभुक्ता केवल जनता में निहित है संसद के अधिकार संविधान निर्दिष्ट मात्र हैं।' नारमन डी-पामर के अनुसार 'भारतीय संसद विस्तृत शक्तियों का प्रयोग करती है तथा महत्वपूर्ण कार्यो का सम्पादन करती है यद्यपि इसका मुख्य कार्य भारत राज्य क्षेत्र के लिए विधियों का निर्माण करना है तथापि इस दृष्टि से इसके कार्यो पर अनेक सीमाऐं हैं।' संघीय प्रणाली तथा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुर्ननिरीक्षण की शक्ति प्रदान करने से इनकी शक्तियाँ सीमित हो गई हैं इस प्रकार प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्तियों तथा कांग्रेस दल के प्रचन्ड बहुमत के कारण भी संसद की शक्तियाँ सीमित हो गई हैं। संक्षेप में भारतीय संसद की सार्वभौमिकता पर कुछ मर्यादाओं को दर्शाया है। संसद की सार्वभौमिकता हमारे लिखित संविधान के विभिन्न प्रावधानों द्वारा सीमित हैं संविधान के अनुच्छेद 245 (1) के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि व्यवस्थापन शक्तियों का उपयोग संसद संविधान के अनुसार करेगी। अमेरिका शासन प्रक्रिया के सदृश्य भारतीय प्रणाली में भी दो प्रकार के कानूनों का निर्माण संवैधानिक कानूनों के नाम से जाने जाते हैं। साधारण कानून का निर्माण संवैधानिक कानून के अन्तर्गत स्थापित विभिन्न व्यवस्थापिकाओं द्वारा किया जाता है। अत: यह स्वभाविक है कि संविधान के द्वारा स्थापित व्यवस्थापिकाऐं संविधान के विरूद्ध कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती।

भारत में संघात्मक व्यवस्था होने के कारण राज्य सूची के विषयों पर संसद की कानून बनाने की शक्ति सीमित हो गई है। इस संबंध में प्रो. टी.के. टोपे ने लिखा है कि 'भारतीय संसद एक संघीय संविधान के अन्तर्गत व्यवस्थापिका है ब्रिटिश संसद के तुल्य इसकी शक्तियाँ असीमित नहीं हैं।' संविधान के कतिपय अनुच्छेदों के संशोधनों हेतु संसद को राज्य विधान मण्डलों के सम्पुष्टिकरण पर निर्भर रहना पड़ता है। संविधान के वे अनुच्छेद जिनका संबंध केन्द्र राज्य संबंधों से है यदि इसमें कोई भी संशोधन करना हो तो संसद को कम से कम आधे राज्यों के विधान मण्डलों का समर्थन प्राप्त करना पड़ता है। संसद द्वारा पारित संविधान के विरूद्ध विधि को भारत का सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। संसदीय विधियों को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मान्यता प्रदान करना आवश्यक है न्यायमूर्ति बी.के. मुखर्जी के अनुसार यह निर्णय करना न्यायपालिका का काम है कि अमुक कानून वैधानिक है या नहीं। न्यायालय के इस अधिकार को न्यायिक पुर्नरावलोकन की शक्ति माना जाता है। यह सर्वविदित है कि गोपालन बनाम मद्रास राज्य, गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवान्द भारतीय आदि मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित किया अथवा संसद की शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाये।

राजनीतिक दृष्टि से संसद लोकमत के प्रतिकूल विधियों का निर्माण नहीं कर सकती उसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून का भी सम्मान करना पड़ता है संसद पर प्रधानमंत्री और मंत्री मण्डल का नियंत्रण रहता है प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन का विघटन कर सकता है। सत्य यह कि भारतीय संसद की शक्तियों का क्षेत्र लिखित संविधान एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुर्नरालोकन के अधिकार के द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है। किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि संसद केवल अनुमोदन करने वाली या प्रचार करने वाली संस्था मात्र बन गई है। वस्तुत: भारत में संसद वह आधारशिला है जिस पर हमारे लोकतंत्र की भव्य इमारत खड़ी है। संसद वह स्त्रोतस्विनी है

जो अपनी अभिरल निर्मल और उन्मुक्त धारण से भारतीय लोकतंत्र के हर खेत को सींचती है जिससे राष्ट्र को पोषण मिलता है। संसद हमारे देश का एक ऐसा केन्द्र बिन्दु है जहां जनता की आत्मा का वास है इस परिप्रेक्ष्य में राजेन्द्र प्रसाद ने लिखा है कि 'संसद एक दल की नहीं, एक बल की नहीं, किन्तु सभी की है और इसलिए यह सार्वभौम है।'

निष्कर्ष – यदि तुलनात्मक दृष्टि से इसका अवलोकन किया जाये तो भारतीय संसद की शक्तियाँ अन्य संघीय देशों की व्यवस्थापिकाओं से अधिक कांग्रेस तथा आस्ट्रेलिया की संसद राज्य संबंधी विषयों पर कानून निर्माण नहीं कर सकती जबकि भारतीय संसद को विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य के लिये कानून निर्माण करने का अधिकार है। सत्य तो यह कि कार्य एवं शक्ति के दृष्टिकोण से भारतीय संसद की स्थिति संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य की है। दोनों ही प्रकार की अतियों से संविधान निर्माताओं ने संसद की स्थिति की सुरक्षा की है। इस संबंध में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने लिखा है कि 'संसद की सम्प्रभुता इसी में निहित है कि वह अपने और जनता के अधिकारों के बीच भेद न करें। यदि प्रजातंत्र की स्थिति और सफल बनाना है तो संसद को अपने अधिकारों की रक्षा के साथ–साथ प्रजा की आवाज सुनने को भी सदा तैयार रहना चाहिये।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय संविधान अनु. 79
2. Norman D. Partmer-Indian Political Systems 1961 P-117
3. The Indian Constitution wonderfully cuts the Boston Houghton Co. via Media between the American System of Judicial Supremacy and the English Principal of Parliament Sovereignly D.D. Basu Commentary on the constitution of India IV act P-33.
4. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद स्वतंत्र भारत की झलक साहित्य संसार, पटना 1973 पृ.सं. 37
5. Sir Edword Cocke cited by Dr. B.D. Sharma Adhunik Shasar L.N. Agrawal, Agra 1987 P-87
6. De Lome cited by Dicky A.V. An introduction to the Macmillian, Law of the Constructions Eco London 1959 P=43
7. कश्यप सुभाष संविधान की आत्मा पूर्वोक्त 1973 पृ.सं. 174
8. कश्यप सुभाष, संविधान विकास और स्वाधीनता संघर्ष नेशनल, बुक ट्रस्ट इण्डिया, दिल्ली 1972 पृ.सं. 349
9. नई दुनिया इन्दौर 5 सितम्बर 1972
10. दिनमान नई दिल्ली 1973
11. कश्यप सुभाष संविधान की आत्मा पूर्वोक्त 1973 पृ.सं. 74
12. Palmer N.D. India Political System, Boston, Houghton Co. 1961, P-124 एवं भारतीय संविधान अनुच्छेद 79
13. भारतीय संविधान अनु. 146 (1)
14. अनु. 146 (1) 7वीं अनुसूची
15. T.K. Top Constitution of India: 1971 Eastem Co. Ucknow P. 268
16. Justice Mukherjee: Supreme Court Journal 1954 P-597
17. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद : स्वतंत्र भारत की झलक पूर्वोक्त: 1973 पृ.सं. 38
18. अनु. 250, 253
19. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद स्वतंत्र भारत की लक पूर्वोक्त: 1973 पृ.सं. 29

****

अलंकार : अर्थ एवं स्वरूप

डॉ. अनुपमा सक्सेना*

प्रस्तावना - 'सौन्दर्य' सृष्टि की किसी भी वस्तु एवं अवस्तु को सकारात्मक योगदान से अधिक ग्राह्य बनाने में सक्षम है। अत: यह ईश्वर प्रदत्त सृष्टि का एक अनुपम, अलौकिक, अद्‌भुत, अद्वितीय, आनन्ददायक, अनुभूतिपरक एवं आकर्षक वरदान अथवा आशीर्वाद है। 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम्' सूत्र की व्याख्या भी सौन्दर्य के साथ ही समाप्त होती है। सौन्दर्य को प्रत्येक क्षेत्र, शास्त्र एवं स्थिति में स्थान दिया गया है। सौन्दर्य अनुभूतिपरक होने के साथ ही बहुआयामी एवं बहुअर्थक है। प्रसंग, अवस्था, स्थिति एवं दृष्टिकोण के आधार पर इसका शोध होता है। काव्य का सौन्दर्य बहुत सीमा तक अलंकार पर निर्भर करता है। अत: अलंकार के अर्थ एवं स्वरूप की चर्चा अभिष्ट है।

अलंकार शब्द का साधारण अर्थ तो उस वस्तु से लिया जाता है, जो सौन्दर्य प्रदान करने का साधन हो, यथा आभूषण आदि। शास्त्रीय एवं शाब्दिक दृष्टि से अलंकार शब्द की विवेचना इस प्रकार हो सकती है 'अलंकार' शब्द दो शब्दों के संयोग से बना है, 'अलम्' एवं 'कार'। 'अलम' का अर्थ है-भूषण, जो अलंकृत अथवा भूषित करे, जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए तथा 'कार' का अर्थ है करने वाला।

अलंकार के अर्थ एवं स्वरूप को विभिन्न भाषाओं के साहित्याचार्यो ने अपने-अपने दृष्टिकोण से व्याख्यायित एवं विश्लेषित किया है। 'यूनानी काव्यशास्त्र' में अलंकार के सम्बन्ध में कहा गया है कि 'अलंकार उन विधाओं का नाम है, जिनके प्रयोग द्वारा श्रोताओं के मन में वक्ता अपनी इच्छा के अनुकूल भावना जगा कर उनको अपना समर्थक बना सकता है। अलंकार शास्त्र के प्रथम आचार्य 'भामह' के अनुसार 'अलंकार ऐसी शब्दोक्ति है, जो वक्रार्थ की विधायक होती है। वक्रोक्ति के बिना कोई अलंकार सम्भव नहीं है, क्योंकि अर्थ को विभामय करने वाली समस्त विद्या वक्रोक्ति ही है। वे कवि को इसी दिशा में प्रयास किए जाने के लिए निर्देशित करते हैं, क्योंकि वे इसी के से अलंकार का अस्तित्व स्वीकार करते हैं।' आचार्य दण्डी ने काव्य के शोभाकार धर्मो को अलंकार की संज्ञा दी है। आचार्य वामन व्यापक अर्थ में अलंकार का प्रयोग करते हुए कहते हैं 'अलंकार के कारण ही काव्य ग्राह्य-उपादेय है और वह अलंकार सौन्दर्य है।' आचार्य रुद्रट ने प्रतिपादित किया है कि 'अभिधान के कथन के प्रकार विशेष अर्थात् कवि प्रतिभा प्रादुर्भूत कथनविशेष ही अलंकार है।' आचार्य आनन्दवर्द्धन ने वाणी की अनन्त शैलियों को अलंकार कहा है। आचार्य कुन्तक कहते हैं कि 'विदग्धों की कथन शैली ही वक्रोक्ति है और वही अलंकार है।' आचार्य मम्मट के अनुसार 'काव्य में रस अंगी है, उसका उत्कर्ष नित्य धर्म गुण है। अलंकार आभूषण के समान है, यह कदाचित रस का उपकार करते हैं, सर्वदा नहीं अर्थात् रस के अभाव में भी अलंकार का अस्तित्व है।' आचार्य जयदेव कहते हैं कि 'रसवती कविता अलंकारयुक्त कविता विचार को उल्लसित करती है।' आचार्य विश्वनाथ के अनुसार 'शब्द और अर्थ के जो शोभातिशायी अर्थात् सौन्दर्य की विभूति बढ़ाने वाले अस्थिर धर्म हैं, वे ही अलंकार हैं।'

काव्यालंकारों के अर्थ एवं स्वरूप को स्पष्ट करते हुए हिन्दी के आचार्यो ने भी महत्त्वपूर्ण व्याख्याएँ की हैं। हिन्दी के अलंकारों की विवेचना करने वाले प्रथम आचार्य केशव ने अलंकारहीन कविता को नग्न माना है। आचार्य देव भी कविता-कामिनी को अलंकार सहित अधिक सौन्दर्यमयी मानते हैं। आचार्य दूलह अनुसार- 'उसी कवि को प्रसिद्धि मिलती है, जो अपने काव्य को अलंकारों से सुसज्जित करता है।' आचार्य भिखारीदास एवं आचार्य पद्माकर भी इसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा को स्वीकार करते हैं। आधुनिक काव्यशास्त्र के हिन्दी साहित्याचार्य 'आचार्य रामचन्द्र शुक्ल' के अनुसार 'अलंकार कथन की रोचक, सुष्ठु एवं प्रभावपूर्ण प्रणाली है ...वर्णन करने की अनेक प्रकार की चमत्कारपूर्ण शैलियाँ, जिन्हें काव्यों से चुनकर प्राचीन आचार्यो ने नाम रखे और लक्षण बताए अलंकार हैं। ये शैलियाँ न जाने कितनी हो सकती हैं, अत: यह नहीं कहा जा सकता कि जितने अलंकारों के नाम ग्रन्थों में मिलते हैं, उतने ही अलंकार हो सकते हैं।'

अलंकार के अर्थ एवं स्वरूप को स्पष्ट करने वाली विभिन्न आचार्यो द्वारा की गई उपरोक्त व्याख्याओं के परिणामों एवं परिभाषाओं से स्पष्ट है कि कुछ आचार्यो ने काव्यगत सम्पूर्ण सौन्दर्य को 'अलंकार' माने है और कुछ आचार्यो ने काव्य के प्राणभूत, रस, गुण आदि के प्रभावक एवं उत्कर्षक धर्म को 'अलंकार' कहा है। अलंकार की सन्तुलित, समन्वित एवं समग्र दृष्टिकोण से परिपूर्ण परिभाषा, जो अलंकार को उसकी सम्पूर्णता के साथ स्पष्ट करने का प्रयास करती प्रतीत होती है, कदाचित निम्नांकित हो सकती है-

'अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं भाषा की पुष्टि के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान है; वे वाणी के आचार, व्यवहार, रीति-नीति हैं; पृथक, स्थितियों के पृथक् स्वरूप; भिन्न अवस्थाओं के भिन्न चित्र हैं। हास, अश्रु, स्वप्न, पुलक, हाव-भाव है। जहाँ भाषा की जाली केवल अलंकारों के चौखटे में फिट करने के लिए बुनी जाती है, वहाँ भावों की उदारता शब्दों की कृपण जड़ता में बँधाकर सेनापति के दाता और समूह की तरह 'इक्सार' हो जाती है।'

काव्य में अलंकारों की उपयोगिता असंदिग्ध है तथा अर्थ-सौन्दर्य के सम्पादन में सहायक होने के कारण काव्य में इनका प्रयोग वांछनीय एवं

* सह-आचार्य (हिन्दी) राज कला महाविद्यालय, सीकर (राज.) भारत

विशेष महत्त्वपूर्ण है। किन्तु इसमें सन्देह नहीं है कि यह महत्त्व रस, ध्वनि और गुण रीति के बाद का ही है। अलंकारों से अर्थ में प्रेषणीयता, प्रभविष्णुता और स्पष्टता का सम्पादन होता है, परन्तु काव्य में अलंकारों का औचित्य वहीं तक है, जहाँ तक वे साधन रूप में ही हों, साध्य न बन जाएँ। यदि वे साधन के स्थान पर साध्य बन जाते हैं तब काव्य की शोभा बढ़ाने के स्थान पर उसका ह्रास ही करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

The Role Of Women In Regency Society As Portrayed In Jane Austen's Works

Dr. Panchali Sharma*

Abstract - This research paper delves into the depiction of women in Regency society as portrayed in Jane Austen's novels. By examining Austen's works within the historical context of the Regency era, this study explores the societal norms, limitations, and challenges faced by women during this period. The paper analyzes Austen's female characters, their personal ambitions, and the expectations imposed on them. Furthermore, it critically examines Austen's subtle critique of societal norms, the challenge to gender roles, and the exploration of individual agency and self-determination. The paper also considers the impact and significance of Austen's representation on contemporary perceptions of women in Regency society and the enduring appeal of her works to modern readers.
Keywords- Regency society, Jane Austen, societal norms, female characters, gender roles, critique.

Introduction - In the early 19th century, the Regency era in Britain marked a period of significant social and cultural transformation. Following the madness of King George III, his son, the Prince Regent, assumed the role of the de facto ruler of the country. This era, spanning from 1811 to 1820, and extending to the years leading up to the Victorian era, was characterized by distinct social customs, lavish lifestyles, and a vibrant cultural scene.Regency society was predominantly shaped by the aristocracy and the gentry, who held significant power and influence. The upper class lived in opulent country estates and elegant townhouses, indulging in extravagant balls, grand parties, and sophisticated cultural pursuits. Etiquette and decorum were of utmost importance, with strict codes governing social interactions and behavior.

Women played a prominent role in Regency society, albeit with limited rights and opportunities. They were expected to embody grace, beauty, and refinement, while their primary goal was to secure a desirable marriage. Education for women was focused on accomplishments such as music, drawing, and social graces, rather than intellectual pursuits.Literature and the arts flourished during the Regency era, reflecting the changing values and interests of the time. The Romantic movement, characterized by a celebration of emotions, nature, and individuality, greatly influenced the literary works of prominent writers like Jane Austen, Lord Byron, and Percy Bysshe Shelley.Political discussions and debates were also a significant aspect of Regency society, with ongoing concerns over the Napoleonic Wars and the effects of industrialization. Social issues such as the abolition of slavery and women's rights began to gain traction, laying the groundwork for future reform movements.

While the Regency era was a time of luxury and elegance for the privileged few, it was also marked by significant social disparities and a growing divide between the upper and lower classes. This period laid the foundation for the Victorian era, where societal changes and advancements would continue to shape the course of British history.

Overview Of Jane Austen's Works And Their Portrayal Of Regency Society: Jane Austen, a renowned English novelist of the late 18th and early 19th centuries, captured the essence of Regency society in her works. Austen's novels provide insightful and often satirical commentary on the manners, customs, and social hierarchy of the time, offering a vivid portrayal of Regency society.Austen's novels are known for their astute observations of human nature and their focus on the lives of women in a society heavily driven by marriage and social status. Her works typically revolve around the experiences and romantic pursuits of young, intelligent, and spirited heroines who navigate the intricacies of Regency society."Pride and Prejudice," perhaps Austen's most famous novel, delves into the complexities of love, reputation, and social class. Set in rural England, the story follows the spirited Elizabeth Bennet as she encounters the proud Mr. Darcy and navigates the expectations and conventions of courtship. The novel masterfully exposes the superficiality, snobbery, and hypocrisies of Regency society while advocating for love based on true understanding and mutual respect.

In "Sense and Sensibility," Austen explores the contrasting temperaments of two sisters, Elinor and Marianne Dashwood, as they face the challenges of finding love and security in a world driven by financial considerations. The novel delves into the precarious position of unmarried women, the constraints imposed on them, and the importance of balancing reason and emotion

*Lecturer (English) Govt. P.G College, Sawai Madhopur (Raj.) INDIA

in navigating relationships."Mansfield Park" delves into the themes of morality, duty, and social mobility. The story revolves around Fanny Price, a poor young woman who is taken in by her wealthy relatives at Mansfield Park. Through Fanny's perspective, Austen examines the rigid social structure, the influence of wealth and status, and the compromises individuals make to secure their place in society.

Austen's other notable works, such as "Emma," "Northanger Abbey," and "Persuasion," further explore the intricacies of Regency society. With sharp wit, keen observation, and a deep understanding of human nature, Austen's novels offer a nuanced portrayal of the challenges, restrictions, and societal expectations faced by individuals, particularly women, during the Regency era.Through her works, Austen not only provided a window into the manners and conventions of her time but also offered social commentary and critique. Her novels continue to resonate with readers today, captivating audiences with their timeless themes of love, class, and personal growth while shedding light on the intricacies of Regency society.

Jane Austen's Representation Of Women In Regency Society: Jane Austen's representation of women in Regency society is a significant aspect of her novels. Austen's works provide insightful and nuanced portrayals of women's roles, challenges, and aspirations in a society heavily focused on marriage and social status.Austen's heroines often defy traditional expectations of women in Regency society. They are intelligent, witty, and possess individuality and agency. Despite societal pressures, they strive to assert their own desires and make choices that align with their personal values and principles.A key theme in Austen's novels is the limited options available to women for securing their future in a society where marriage was seen as their primary goal. The financial security, social status, and domestic stability that marriage offered were crucial considerations. Austen explores the tension between the desire for love and the practical realities of marriage as a social contract.

Austen's heroines, such as Elizabeth Bennet in "Pride and Prejudice" and Elinor Dashwood in "Sense and Sensibility," challenge the expectations placed upon them. They seek genuine emotional connections and are unwilling to settle for loveless marriages or sacrifice their own happiness for societal approval. Austen critiques the notion of marrying solely for wealth or social standing and advocates for marriages based on mutual respect, understanding, and compatibility.Austen also highlights the vulnerability and precarious position of unmarried women in Regency society. The lack of inheritance laws and limited employment opportunities often left women financially dependent on their male relatives or subject to the mercy of potential suitors. Characters like Fanny Price in "Mansfield Park" and Anne Elliot in "Persuasion" navigate the challenges of their economic and social circumstances, grappling with the choices available to them.

Additionally, Austen's novels shed light on the restrictions placed on women's education and intellectual pursuits during the Regency era. Women were expected to excel in accomplishments such as music, drawing, and social graces rather than engage in intellectual pursuits. Austen's heroines, however, exhibit intelligence and wit, challenging societal expectations and showcasing the potential of women to contribute intellectually and emotionally.Through her realistic and multi-dimensional female characters, Austen offers a critique of the limitations imposed on women and the societal expectations that constrained their choices and aspirations. Her works champion the importance of personal integrity, self-awareness, and the pursuit of authentic relationships. Austen's representation of women in Regency society continues to resonate with readers, highlighting the enduring relevance of her observations and insights into gender roles and societal expectations.

Critique Of Regency Society Through Austen's Works: Jane Austen's works provide a subtle yet incisive critique of Regency society, offering a glimpse into its flaws, hypocrisies, and inequalities. Through her keen observations and satirical tone, Austen highlights the limitations, superficiality, and social constraints that governed the lives of individuals, particularly women, during the time.One of Austen's primary critiques is directed at the obsession with wealth and social status that permeated Regency society. The pursuit of advantageous marriages based on financial considerations is a recurring theme in her novels. Austen exposes the mercenary nature of certain characters and satirizes their shallow priorities. She challenges the notion that monetary wealth equates to personal worth and questions the integrity of a society that places material gain above genuine human connections.

Austen also criticizes the rigid social hierarchy that defined Regency society. The aristocracy and the landed gentry held significant power and privilege, while those from lower social classes faced limited opportunities for upward mobility. This disparity is evident in the contrasting social spheres portrayed in Austen's novels. She subtly exposes the prejudices and snobbery of the upper class, highlighting their disconnect from the realities and struggles of the lower classes.Gender roles and the limited agency afforded to women are central to Austen's critique. The expectation that women's primary goal should be to secure a respectable marriage and their lack of control over their own financial and social futures are recurrent themes. Austen challenges these societal expectations through her strong, independent heroines who defy conventions and seek personal fulfillment. She highlights the absurdity of a society that restricts women's choices and reduces them to objects to be acquired through marriage.

Austen's satirical approach also extends to the manners and social customs of the time. She exposes the hypocrisy and artificiality underlying polite society, revealing the performative nature of social interactions. Austen's witty

observations and sharp dialogue unveil the pretensions, gossip, and societal expectations that governed Regency society.Overall, Austen's critique of Regency society lies in her astute portrayal of its shortcomings and contradictions. Through her engaging narratives and memorable characters, she challenges the prevailing norms and values of her time. Austen's works offer a subtle but thought-provoking examination of the superficiality, social inequalities, and restrictive expectations that defined Regency society, inviting readers to reflect on the universal human experiences and values that transcend time and societal constraints.

Impact And Significance Of Austen's Representation: Jane Austen's representation of Regency society and her critique of its norms and values have had a profound and lasting impact on literature, culture, and the perception of women's roles and agency.Firstly, Austen's novels have become enduring classics, celebrated for their wit, charm, and astute social commentary. Her works continue to captivate readers, both for their engaging narratives and for the timeless themes they explore. Austen's portrayal of complex, relatable characters and her exploration of universal human experiences such as love, identity, and societal expectations have made her novels resonate across generations and cultures.

Austen's representation of women in Regency society has been particularly influential. Her heroines, with their intelligence, wit, and determination, challenged the prescribed gender roles of their time. They served as models of strength and resilience, inspiring subsequent generations of women to assert their own agency and pursue their desires and ambitions beyond societal expectations.Austen's critique of the shallow pursuit of wealth and social status also struck a chord with readers then and now. Her novels questioned the moral and ethical implications of valuing material gain over genuine human connections and personal integrity. This critique of a materialistic society continues to resonate in contemporary culture, where the pursuit of status and wealth often comes at the expense of deeper, more meaningful relationships. Furthermore, Austen's representation of the social customs and manners of Regency society has had a lasting impact on our understanding of the period. Her vivid descriptions and satirical depictions provide valuable insights into the social dynamics, class distinctions, and etiquette of the time. Austen's works serve as historical documents, offering a window into the everyday lives and concerns of people during the Regency era.In addition to their literary significance, Austen's novels have also influenced popular culture through numerous adaptations and reinterpretations. Film and television adaptations of her works have brought her stories and characters to a wider audience, ensuring their continued relevance and cultural impact.

Overall, Austen's representation of Regency society and her critique of its values and constraints have left an indelible mark on literature, cultural understanding, and the perception of women's roles. Her novels continue to be celebrated and studied, offering readers valuable insights into human nature, societal expectations, and the pursuit of personal happiness and fulfillment.

Conclusion: In conclusion, Jane Austen's representation of Regency society in her works and her astute critique of its norms and values have had a profound and enduring impact. Through her engaging narratives and memorable characters, Austen exposed the limitations, superficiality, and social constraints of the time while advocating for personal integrity, genuine human connections, and the empowerment of women.Austen's novels continue to captivate readers with their wit, charm, and timeless themes. Her portrayal of strong, independent heroines challenged the prescribed gender roles of the Regency era, inspiring generations of women to assert their own agency and pursue their desires and ambitions. Her critique of the obsession with wealth and social status resonates in contemporary culture, where materialistic pursuits often overshadow deeper human connections.Furthermore, Austen's works provide valuable insights into the social dynamics, class distinctions, and manners of Regency society. They serve as historical documents, enriching our understanding of the period and its cultural context.The impact of Austen's representation extends beyond the realm of literature. Her works have influenced popular culture through adaptations and reinterpretations, ensuring their continued relevance and cultural significance.

Jane Austen's contribution to literature, her exploration of human nature, and her critique of societal norms make her a remarkable and influential figure. Her works continue to be celebrated and studied, offering readers timeless wisdom and a profound understanding of the complexities of human relationships and the pursuit of happiness.Overall, Jane Austen's representation of Regency society and her critique of its values have left an indelible mark, shaping our understanding of the period, inspiring generations, and affirming her status as one of the most beloved and influential authors in literary history.

References:-

1. Backscheider, Paula. “Reflections on the Formation of the Modern Novel: Austen, Scott, Eliot.” Johns Hopkins University Press, 1992.
2. Copeland, Edward. “Sexuality in the Novels of Jane Austen.” The Cambridge Companion to Jane Austen, edited by Edward Copeland and Juliet McMaster, Cambridge University Press, 1997, pp. 161-178.
3. Fergus, Jan. “Jane Austen: A Literary Life.” Palgrave Macmillan, 1991.
4. Fergus, Jan. “Love and Money: Economics and Romance in Austen.” Jane Austen and Economics, edited by Michael Chwe, Oxford University Press, 2014, pp. 117-136.
5. Gilbert, Sandra M., and Susan Gubar. The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination. Yale University Press,

1979.
6. Halsey, Katie. “Jane Austen and Her Readers, 1786-1945.” Routledge, 2012.
7. Johnson, Claudia L. “Jane Austen: Women, Politics, and the Novel.” Oxford University Press, 1990.
8. Johnson, Claudia L. “Jane Austen’s Women: Some Pilgrims, Some Progress.” New Literary History, vol. 24, no. 2, 1993, pp. 303-322.
9. Jones, Hazel. “Jane Austen and Marriage.” Continuum, 2009.
10. Kelly, Gary. Women, History, and Theory: The Essays of Joan Kelly. University of Chicago Press, 1984.
11. Poovey, Mary. “Austen Anxieties: Marriage, Epistemology, and Romantic Fiction.” ELH, vol. 50, no. 2, 1983, pp. 233-249.
12. Poovey, Mary. “The Proper Lady and the Woman Writer: Ideology as Style in the Works of Mary Wollstonecraft, Mary Shelley, and Jane Austen.” University of Chicago Press, 1984.
13. RJohnson, Claudia L. “Austen’s Women and the Great Chain of Being.” Persuasions: The Jane Austen Journal, vol. 23, no. 1, 2001, pp. 40-51.
14. Tanner, Tony. “Jane Austen.” Harvard University Press, 1986.
15. Todd, Janet. Jane Austen: Her Life, Her Times, Her Novels. Methuen, 2006.
16. Todd, Janet. Women’s Friendship in Literature. Columbia University Press, 1980.
17. Wiltshire, John. Jane Austen and the Body: The Picture of Health. Cambridge University Press, 1992.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

Fluoride Contamination in Groundwater and the Effect of Fluoride on Flora and Fauna; A Brief Review

Dr. Pratibha Rao*

Abstract - The high fluoride content in groundwater and soil can be attributed to geology as well as anthropogenic activity. The rocks and sediments are rich in fluoride but the additional factors as over exploitation of groundwater through borewell, that are dug deeper and deeper to ensure continuous water supply, lack of rainwater storage, industrial setup, mining of rock phosphate ,soil contamination are equally responsible for higher concentration of fluoride. This article briefly review fluoride contamination in groundwater and fluoride toxicity on domestic animals and vegetation.
Keywords - Fluoride toxicity,fluorosis, ground water, vegetation, animals.

Introduction - Presence of fluoride in groundwater maybe natural , anthropogenic or sometimes both. natural sources of fluoride are generally correlated with geographical conditions of the area. Various rocks such as fluorite cryolitebiotite etc. contain significant amount of fluoride . Volcanic ashes also add fluoride in groundwater. Weathering process breakdown and crumble the rocks and when water crosses over these fluoride rich rocks it leaches into water and increases the fluoride concentration in it. types of rocks , soil properties, pH, temperature and depth of the water are major controlling factors of fluoride concentration in water.

Mining process, agriculture run off and industrial activities are also responsible for increased fluoride concentration in groundwater. Phosphate based fertilizers are generally used in agriculture fields whichenter into groundwater. Airborne fluoride rich emission from industries deposit on surrounding soil andwhen water come into the contact of this soil it becomes fluoride contaminated.

Groundwater is used for drinking purpose it becomes the main source of fluoride intake. The dietary need of fluoride is so less that it can be met easily without any supplements. In areaendemic to fluoride, groundwater ,vegetation ,soil etc. may contain F more than the permissible limit of 1.0 to 1.5mg/L. Although optimum level of fluoride prevents dental carries and helps in bone mineralization, butexcess consumption may lead to dental skeleton fluorosis and other abnormalities in the body. Whenexposure is for longer period it affects the bone health, increasing risk of fracture and decreasing themobility of the joints. Excess fluoride is not only harmful to live stock and human beings but also affect plants. Toxic effects of fluoride on vegetation are also very profound. Millions of people lack safe drinking water that's why negatively influences the health and well being of people in developing countries. Vital source of water is groundwater for majority of world population. Naturally water has a significant amount of fluoride which is predominantly influenced by local mineralogy and geography. Parent rocks structure and composition influence fluoride distribution in aquifers. Minerals like fluorspar, fluoroapatite, granite and mica contribute fluoride content in groundwater. Arid and semi arid climatic conditions, calcium deficiency distance from recharge sources also affect fluoride content in water.[1-6]The maximum permissible limit of a fluoride in drinking water is 1.5 ppm and highest desirable limit is 1.0 ppm.[7-8]Narsimha and Sudarshan reported about problem of excess fluoride drinking water.[9]Gopalakrishnan et al.[10] reported that 50% of groundwater resources in India are contaminated with fluoride and 90% of rural populations are dependent on groundwater supply.In Rajasthan the situation is very critical because of it's geo environmental factors. In Rajasthan almost all the districts are endemic to fluoride because of semi arid climate and inadequate water resources.[11]

Rajasthan has only one percent of nation' s water resources and due to unavailability of surface water, majority of population is dependent on groundwater,[12] same water is used for drinking and irrigation purpose which increases the problem.

Effect of excess fluoride on plants: Fluoride is not considered essential for normal plant growth even very low fluoride concentration can produce number of biochemical and physiological alteration in plants. Kamaluddin and Zwiazek reported that fluoride inhibits root water transport and effects leave expansion in Aspen (Populustremuloides) seedling[13] fluoride enters into plant tissues and affects its metabolic processes like respiration, photosynthesis, carbohydrate metabolism ,synthesis of proteins nucleotides

*Associate Professor (Chemistry) SMM Government Girls College, Bhilwara (Raj.) INDIA

etc.[14]

Fluoride also inhibits the ATP synthase enzyme in chloroplast mitochondria and plasma membrane .It affects energy metabolism in higher plants.[15] Initial and visible fluoride toxicity symptoms in plants are florosis, marginal necrosis and tip burning. Chronic exposure of fluoride may also induced falling or leaf notching.[16]A number of physiological and biological processes can be altered at lower level of fluoride without visible injuries or symptoms which may cause reduction in yield of plants.

Fluoride toxicity in animals: Excess fluoride in environment adversely affect animals and human health. Fluoride is required in minute amount for miinralization of bones and formation of dental enamel but higher amount may pose detrimental effects on body, chronic effect are chlorosis, weight loss ,anaemia, discoloration of teeth and osteosclerosis little bones, calcified ligaments . Excess fluoride may cause fluorosis, it is a chronic disease caused by accumulation of fluoride in hard and soft tissues. Livestocks can be severely affected by consumption of fluoride containing water and vegetation. Fluoride toxicity in human and different species of domestic animals has been reported worldwide including India specially in fluoride endemicareas.[17] In acute intoxication it induces increased salivation ,disturbed gastro intestinal functions, abdominal ache, weakness, respiratory arrest , cardiac failure etc.[18]

Fluoride has high affinity for calcium, that's why it is more prevalent in bones and teeth. Mottling, discoloration of teeth, pigmented spots, pits and horizontal and vertical streaks /bands on tooth surface and erosion of teeth are typical symptoms of dental florosis,skeletalflorosis has been symptomatized as stiff joints, painful gait, osteoporosis, bony exostoses in long bones.

Apart from teeth and bone deformity fluoride can cause disorder in gastro intestinal,neurological ,renalfunctioning and impare reproductive cycles[19]and disturb thyroid functions.[20]

Conclusion: Studies of fluoride toxicity becomes necessary because of rapid Industrial development with increasing use of chloride compound in fluoride endemic areas therefore studies on water quality exposure of animals to various sources of fluoride body fluids monitoring become a necessity. Studies on the measurement of fluorine in urine, milk serum, bone etc. would help in estimating the degree of exposure.

Studies of the vegetation growing in the area that are fluoride endemic are required to access the transmission of a fluoride form producers to consumers. Fluoride resistant varieties of plants need to be cultivated to prevent the accumulation of chloride in the vegetation. The assessment of fluoride contribution from water is required and if contributions from vegetation soil airborne pollutants and other sources are added total intake of fluoride by an individual can be estimated. Global researches and discoveries can be implemented locally to prevent fluoride toxicity in animals and plants.

References:-

1. Biswas G, Kumari M, AdhikariK,andDatta S; Current Pollution Reports,2017,3(2) 104-119
2. Rukah YA and Alsokhny K.Chemie der ErdeGeochem, 2004,64(2) 171-181
3. Raju NJ Quaternary Int. ,2017,443 265-278
4. Ozsvath DL Environ. Geol. ,2006,50(1)132-138
5. AminiM.,Mueller K. Abbaspour KC, Rosenberg T.,Afyuni M. Moller KN., Sarr M and Johnson CA Environ. Sci.Technol 2008,42(10) 3662-3668
6. Guo Q. Wang Y. Ma T. Ma R. GeochemExplor, 2007, 93(1) 1-12
7. World health organisation. “Fluorine and fluorides” Geneva, Environmental Health Criteria No. 36, 1984
8. Bureau of Indian Standards “Drinking water specification” (FirstRevision)IS 10500, 1991
9. Narasimha A. and Sudarshan V. Appl. Water Sci. 2017, 7(5) 2501-2512
10. Gopalkrishnan SB, Vishwanathan G and Ilango SS.Appl. Water Sci. 2012,2(4) 235-243
11. Hussain J, Sharma KC and Husain I. J. Tissue Res, 2004, 4(2) 263-27
12. Saxena S and Saxena U. Int. J Environ Sci. 2013, 3(6) 2251-2260
13. Kamaluddin M and Zwiazek JJ Physiol Plant., 2003 117(3) 368-375
14. Kumar K., Giri A., Vivek P., Kalaiyarasan T. and Kumar B. Peertechz J Environ Sci. Toxicol. 2017, 2(2) 043-047
15. Rakowski KJ. Trees 1997,11 (4) 248-253
16. Jafari M., Noori M. and MalayeriBE. Fluoride 2016, 49 (4) 441-448
17. Chaubisa SL. Mishra GV. Sheikh Z. Bhardwaj B. Mali P. Jaroli VJ, Adv. Pharm. Toxicol. 2011a, 12(2) 29-37
18. Chaubisa SL. Mishra GV. Sheikh Z. Bhardwaj B. Mali P. Jaroli VJ, Fluoride 2011 b 44(2) 70-76
19. Chinoy NJ, Pradeep PK and Sequeira E. J. Environ. Biol. 1992,13 55-61
20. Raghvendra M. Ravindra RK, Raghuveer YP. Narasimha JK Uma V. and Navakishor P. Fluoride 2016, 49 (1) 84-90

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

अर्थशास्त्र में कार्मिक व्यवस्था, चयन, नियुक्ति, सेवा शर्तें

डॉ. कुलकिरण गढ़वाल*

प्रस्तावना - (अ) चयन, नियुक्ति व वर्गीकरण- कौटिल्य ने शासकीय पदाधिकारियों को दो वर्गों में विभाजित किया है। कौटिल्य ने प्रशासकीय संवर्ग के निम्नतम पदाधिकारियों को युक्त और उच्चतम पदाधिकारियों को 'उपयुक्त' की संज्ञा दी है। कौटिल्य ने पद विशेष से सम्बद्ध अधिकारों के अनुसार निर्धारित योग्यताओं के अनुसार विभिन्न पदों पर विभिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति को उचित माना है।

कौटिल्य ने कार्मिक वर्ग की नियुक्ति के संदर्भ में सतर्कता बरतने पर विशेष बल दिया है, तथा कार्मिकों की नियुक्ति के लिए निश्चित प्रक्रिया का प्रतिपादन किया है। कौटिल्य ने शासक को परामर्श दिया है कि उसे सामान्य पदों पर अमात्यों की नियुक्ति करके, मंत्री और पुरोहति के सहयोग से अग्रलिखित गुप्त उपायों से उनके आचरणों की परीक्षा लेनी चाहिए, प्रथम धर्मोपधा अर्थात् धर्म के द्वारा अमात्य के हृदय की पवित्रता की परीक्षा; द्वितीय अर्थोपधा, गुप्त आर्थिक उपायों द्वारा अमात्य के हृदय की पवित्रता की परीक्षा; तृतीय 'कामोपधा' अर्थात् गुप्त काम सम्बन्धी उपायों द्वारा अमात्य के हृदय की पवित्रता की परीक्षा तथा चतुर्थ, भयोपधा अर्थात् गुप्त भय सम्बन्धी उपायों द्वारा अमात्य की शुद्धता की परीक्षा।

कौटिल्य ने प्रतिपादित किया है कि उक्त चार प्रकार की परीक्षाओं के उपरान्त जो अमात्य आचरण की पवित्रता व निष्ठा की अक्षुण्णता की परीक्षा में 'धर्मोपदा' की कसौटी पर खरे उतरें, उन्हें धर्म स्थानीय दीवानी कचहरी तथा कण्टक - शोधन फौजदारी कचहरी सम्बन्धी कार्यों में नियुक्त करना चाहिए।

कौटिल्य के अनुसार अर्थ परीक्षा में उत्तीर्ण अमात्यों को समाहर्ता कर-वसूली कार्य तथा सन्निधाता कोष के पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। कौटिल्य की मानयता है कि कामोपधा परीक्षा में परीक्षित अमात्यों को बाहरी-विलास स्थानों विहोरों तथा भीतरी अन्त:पुर सम्बन्धी रक्षा का व्यवस्था भार सौंपा जाना चाहिए। कौटिल्य ने परामर्श दिया है कि भय-परीक्षा में उत्तीर्ण अमात्यों को राजा अपना अंगरक्षक नियुक्त करें।

कौटिल्य के मत में जो अमात्य सभी परीक्षाओं में सफल हो उन्हें मंत्री पद पर नियुक्ति दी जानी चाहिए, और सभी परीक्षाओं में असफल अमात्यों को खादानों, हाथियों, और जंगलों आदि की परिश्रम साध्य व्यवस्था का कार्यभार सौंपा जाना चाहिए।

पूर्ववर्ती नीतिशास्त्रकारों के अभिमत के आधार पर कौटिल्य ने प्रतिपादित किया है कि धर्म, अर्थ, काम और भय द्वारा परीक्षित अमात्यों को, उनकी कार्यक्षमता के अनुसार कार्यभार सौंपा जाना चाहिए।

ग्रन्थ में धर्मपधा आदि उपायों द्वारा अमात्य वर्ग की परीक्षा कर लेने के अनन्तर राजा को गुप्तचरों की नियुक्ति का परामर्श दिया गया है। राजकीय पदों पर नियुक्ति के लिए कार्मिकों के पद में पर्याप्त सतर्कता के सामान्य परामर्श के अतिरिक्त अर्थशास्त्र के सन्दर्भ में यह भी उल्लेख मिलता है कि प्रत्येक विभाग में अनेक उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए किन्तु उन्हें एक ही विभाग में अधिक समय तक नहीं रहने दिया जाना चाहिए अपितु उनके समयबद्ध स्थानान्तरण की नीति निर्धारित की जानी चाहिए।

कौटिल्य ने राजा से अपेक्षा की है कि मंत्रियों की नियुक्ति करने से पूर्व वह प्रमाणिक, सत्यवादी एवं आप्त पुरुषों के द्वारा उनके निवास स्थान तथा उनकी आर्थिक स्थिति का, सहपाठियों के माध्यम से उनकी योग्यता तथा शास्त्र ज्ञान का; नये-नये कार्यों में नियुक्ति कर उनकी बुद्धि, स्मृति तथा चतुराई, व्याख्यानों एवं सभाओं में नियुक्ति कर उनकी वाक्पटुता एवं प्रतिभा का, आपत्तियों से उनके उत्साह, प्रभाव तथा सहिष्णुता का, व्यवहार से उनकी पवित्रता, मित्रता एवं दृढ़ स्वामिभक्ति का, सहवासियों एवं पड़ोसियों के माध्यम से उनके शील, बल, स्वास्थ्य और अप्रमाद तथा स्थिरवृत्ति का पता लगाये और उनके मधुर भाषी स्वभाव तथा द्वेष-रहित प्रकृति की परीक्षा स्वयं राजा करें।

कौटिल्य ने प्रशासन के उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिये अपेक्षित सामान्य योग्यताओं के अतिरिक्त विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिये विभिन्न कार्यक्षमताओं व योग्यताओं का प्रतिपादन किया है। उदाहरणार्थ कौटिल्य का मत है कि उच्चकुल्लोत्पन्न, शील गुण सम्पन्न, वेद-वेदांगों का ज्ञाता, ज्योतिष शास्त्र, शकुन शास्त्र, दण्ड नीति में पारंगत, अथर्ववेद में निर्दिष्ट उपासों द्वारा दैवी तथा मानुषी विपत्तियों का प्रतिकार करने में क्षमता आदि योग्यताओं से सम्पन्न व्यक्ति को पुरोहित के पद पर नियुक्त करना चाहिए। कौटिल्य ने कार्मिकों के चयन के सम्बन्ध में शासक के व्यक्तिगत निर्णय की अपेक्षा संस्थागत व प्रक्रियाबद्ध निर्णय प्राप्ति का समर्थन किया है।

डॉ. राधाकुमार मुकर्जी ने मौर्य कालीन प्रशासन के विषय में लिखा है - 'मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को छोड़कर अन्य सभी अधिकारियों की नियुक्ति राजा द्वारा अपने मंत्रियों, प्रधानमंत्री और पुरोहित की सहायता से की जाती थी। इस प्रकार राजा और उन दोनों मंत्रियों से मिलकर एक अन्तरंग परिषद बनी होती थी, जो एक प्रकार के लोक-सेवा आयोग की भांति कार्य करती थी। वह परिषद प्रशासन के उच्च पदों तथा विभाग के अध्यक्षों की नियुक्ति करती थी। ये नियुक्तियाँ अमात्य-पद के लिये योग्य उम्मीदवारों में से मानसिक एवं नैतिक योग्यताओं के आधार पर की जाती थी। उनकी चारों प्रकार के प्रलोभनों - धर्म, अर्थ, काम और भय से संबंधित परीक्षा भी ली जाती थी।

* सह-आचार्य (राजनीति विज्ञान) राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर (राज.) भारत

उक्त सन्दर्भ इस तथ्य को बल प्रदान करता है कि मौर्य प्रशासन में शासकों ने नियुक्ति के सम्बन्ध में कौटिल्य के सुझावों को व्यवहार में अपना लिया गया था।

(ब) आचार-संहिता -कौटिल्य का सुझाव है कि राजा के आचार-व्यवहार पर उसके कर्मचारियों का आचरण निर्भर करता है। यदि वह प्रमादी होगा तो उसके कर्मचारी भी प्रमादी होंगे, और इसके विपरीत राजा यदि उदार, परिश्रमी और विवेकशील होगा तो उसका सारा भृत्य वर्ग भी उसके इन गुणों को अपनायेगा। कौटिल्य का यह स्पष्ट मत है कि उक्त बातों को ध्यान में रखकर राजा को चाहिए कि वह यत्नूपूर्वक सावधानी से उपनी उन्नति की ओर सचेष्ट रहे।

राज्य के कार्मिक वर्ग के लिए कौटिल्य ने एक विस्तृत आचार संहिता का प्रतिपादन किया है।

कौटिल्य ने प्रतिपादित किया है कि राजा जिसे जिस अधिकार पर नियुक्त करें, वह उसी पर कार्य करे और राजा के समीप अगल-बगल में, न तो अधिक दूर और न अधिक नजदीक ही यथोचित आसन पर बैठकर वह कार्य करें।

कौटिल्य ने कार्मिकों को सत्य-भाषण का परामर्श दिया है तथा प्रतिपादित किया है कि आक्षेप लगाकर, असभ्य परीक्षा विषयक, अविश्वसनीय और झूठी बातें कार्मिक को नहीं बोलनी चाहिए।

कौटिल्य द्वारा कार्मिक द्वारा सामान्य व्यवहार में शिष्टाचार व शालीनता को आवश्यक माना गया है तथा अपेक्षा की है कि कार्मिक बिना अवसर के ऊँची आवाज से न बोले; बोलते हुए रखकार या डकार कभी न करें। कौटिल्य ने राजा की उपस्थिति में किसी दूसरे से बातचीत करने, किसी अफवाह को निश्चित रूप से हाँ या ना करने, राजा का या पाखंडियों को वेश धारणा करने, राजा के धारण करने योग्य रत्नों के लिए खुले तौर पर प्रार्थना करने, एक आंख या एक ओठ टेढ़ा करके बोलने, भौंहे चढ़ाने, उच्चतम प्राधिकारी की बात को बीच में काट देने, बलवान के सम्बन्धी से झगड़ा करने, स्त्रियों के साथ, स्त्रियों को चाहने वालों के साथ, विदेशी व्यक्तियों के साथ सम्पर्क रखने, एक ही बात करते रहने और गुटबाजी बनाकर रहने इत्यादि कार्यों का निषेध किया है।

राजकीय कर्मचारियों को कौटिल्य ने परामर्श दिया है कि वे राजा के हित की बात तत्काल ही राजा से कहने का प्रयास करें। उनका मत है कि कार्मिक को अपने हित की बात राजा के प्रिय तथा हितकारी व्यक्तियों से कहनी चाहिए, दूसरे के हित की बात उचित समय एवं स्थान देखकर करनी चाहिए और जो कुछ भी वह कहे अर्थ-धर्म से समन्वित होना चाहिए।

कौटिल्य ने यह भी उल्लेख किया है कि अधिकारियों को राजा के प्रश्न पूछने पर उसकी अनुमति से प्रिय एवं हिताकारी बात को कह देना चाहिए, प्रिय होते हुए भी अहितकारी बात को नहीं कहना चाहिए, किन्तु हितकारी बात अप्रिय हो तो भी कह देनी चाहिए।

कौटिल्य ने कार्मिकों को परामर्श दिया है कि उत्तर देते समय यदि अप्रिय बात सुनने में डर मालूम हो तो चुप हो जाना चाहिए, कार्मिकों को राजा के द्वेष पुरुषों से सम्बन्ध भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि राजा की इच्छा पर न चलने वाले निपुण लोग भी राजा के अप्रिय बन जाते हैं; इसके विपरीत राजा के इच्छानुसार चलने वाले अनर्थकारी लोग भी राजा के प्रिय होते देखे गए हैं। कौटिल्य का मत है कि राजा के हँसने पर दृश्य पर उपस्थित संबंधित कार्मिकों को काठ की तरह खड़ा न रहकर, हंसना चाहिए, किन्तु अट्टहास पर सदा नियंत्रण रखना चाहिए।

कौटिल्य के अनुसार कार्मिकों को किसी भयावह सन्देश को राजा से स्वयं नहीं कहकर किसी के द्वारा राजा से कहलवाना चाहिए। यदि अपने ही ऊपर ऐसी किसी बात का दायित्व आ जाये तो पृथ्वी के समान क्षमा-शील बनकर उसके परिणाम को सहन करना चाहिए।

(स) प्रशिक्षण-अर्थशास्त्र में कार्मिकों के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं परीक्षा को प्रशासन की दक्षता को सुनिश्चित करने के लिये अत्यन्त आवश्यक माना है।

कौटिल्य ने शासकीय उत्तराधिकार हेतु अधिकृत राजकुमार के प्रशिक्षण व शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया है।

कौटिल्य ने प्रतिपादित किया है कि राजकुमार का जन्म होने पर विद्वान पुरोहित विधिपूर्वक उसका संस्कार करें। जब वह समझने योग्य हो जावे तो विभिन्न विषयों के पारंगम विद्वान उसको शिक्षा दें।

अर्थशास्त्र में अयोग्य, अप्रशिक्षित पुत्र को राज्य भार देने की स्पष्ट वर्जना की गई है।

अर्थशास्त्र में अमात्यों को पर्यविक्षण काल (प्रोबेशन) में रखा जाने का उल्लेख है। यह एक प्रकार की प्रशिक्षण की अवधि ही थी। इसमें अमात्यों की, 4 तरीकों तथा धर्मोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा एवं भयोपधा द्वारा परीक्षा, जाँच किए जाने का वर्णन है, तदुपरान्त विशिष्ट प्रकार की जाँच में सफल होने पर, उसे संबंधित पद पर चयनित किया जा सकता है। जो परीक्षित अमात्य इन समस्त चारों प्रकार के प्रशिक्षण में सफल हो जाते वे मंत्री पर पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त माने जाते हैं। प्रशिक्षण तथा परीक्षण के पश्चात् सम्पन्न होने वाली इन सभी प्रकार की परीक्षाओं में असफल होने वाले अमात्यों को, खदानों, हाथियों और जंगलों आदि की परिश्रम साध्य व्यवस्था का भार सौंपने का परामर्श दिया गया है।

अर्थशास्त्र में शिक्षा के दो प्रकारों – कृत्रिम और स्वाभाविक की गणना की गई है। इस बात पर भी बल दिया गया है कि शिक्षा सुपात्र को ही योग्य बना सकती है, अपात्र को नहीं। कौटिल्य का मत है कि विद्या से वहीं योग्य हो सकते हैं जो शुश्रुषा, श्रवण, धारण, विज्ञान, तर्क – वितर्क में विवके तथा बुद्धि से काम लेते हैं।

अर्थशास्त्र में सेनापति के लिये अश्वाध्यक्ष से लेकर पत्याध्यक्ष तक सैन्य प्रशासक के विभिन्न अंगों में विभिन्न अधिकारियों के लिये निर्धारित समस्त प्रकार के कार्यों के निष्पादन में स्वयं भी भली-भांति प्रशिक्षित हों। चतुरंगिणी सेना के कार्य और स्थान की भी उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए।

अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा को चाहिए कि वह सेनाओं पर बराबर ध्यान रखे और उनकी कवायद का निरीक्षण करता रहे।

(द) वेतन, वेतनमान एवं वेतन वृद्धि-कौटिल्य ने प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों को उनके पद के अनुसार वेतन देने का समर्थन किया है। कौटिल्य का मत है कि कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन दिया जाना चाहिए जिससे कि वे अपने परिवार का अच्छी तरह भरण-पोषण कर सकें। उनका मत है कि कम वेतन प्राप्त होने से अधिकारी असंतुष्ट हो जाते हैं तथा वे रिश्वत लेने व गबन आदि कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। कौटिल्य ने विभिन्न वर्गों के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए उनके कार्यों व योग्यताओं के अनुरूप वेतनमान निर्धारित करने पर बल दिया है। जो जीवन स्तर के अनुरूप हो।

सारतः वेतन के निर्धारण के लिए कौटिल्य उस राज्य की आर्थिक स्थिति, कार्मिक की जीवन-निर्वाह की आवश्यकताओं तथा उसकी योग्यता सभी को दृष्टिगत रखते हुए संतुलित सिद्धान्त को अपनाने पर बल देते हैं।

कौटिल्य ने ऋत्विक, आचार्य, मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, राजमाता, और पटरानी आदि को वेतन की दृष्टि से एक ही श्रेणी में माना है तथा प्रतिपादित किया है कि इन्हें प्रतिवर्ष अड़तालीस हजार पण वेतन दिया जाये।

द्वारपाल, अन्तर्वेशिक, आयुधाध्यक्ष, समाहर्ता और सन्निधाता आदि का वेतन प्रतिवर्ष चौबीस हजार पण निर्धारित किया गया है। कौथ्टल्य की मान्यता है कि इतना वेतन प्राप्त करके ये अपने कार्यों को भली-भांति करते रहेंगे।

कौटिल्य का मत है कि युवराज के भाई कुमार उन भाईयों की माताएँ या धाय कुमार माता, नायक, पौर, व्यापार का अध्यक्ष व्यावहारिक, कर्मातिक, मंत्रिपरिषद के पूर्वोक्त 12 सदस्य राष्ट्रपाल और अन्तपाल, इनको बारह हजार पण वेतन प्रतिवर्ष दिया जाए।

इंजीनियर श्रेणी मुख्य, हाथी, घोड़े, रथों के अध्यक्ष और प्रदेष्टा इनको आठ सौ पण वार्षिक वेतन दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

पैदल सेना के अध्यक्ष, अश्वसेना, रथसेना तथा गज सेना, के अध्यक्ष और लकड़ी हाथियों के जंगल के अध्यक्षों के लिए चार हजार पण प्रतिवर्ष वेतन उचित माना गया है।

कौटिल्य का मत है कि शिक्षक , गज शिक्षक, चिकित्सरक, अश्व शिक्षक और मुर्गा सूअर आदि के पालने वाले का अध्यक्ष, इन सबको दो हजार पण वार्षिक दिया जाय।

सामुद्रिक कार्तान्तिक, शकुन बताने वाले नैमित्तिाक, ज्योतिषी, कथा वाचक, स्तुतिवाचक मागध, पुरोहित के नौकर और सुरा आदि के अध्यक्ष का वेतन एक हजार पण प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।

चित्रकार, पदाता खिलाड़ी, गणक और लेखक वर्ग के कर्मचारियों हेतु पाँच सौ पण प्रतिवर्ष वेतन उचित माना गया है।

कुशीलद नट, नर्तक, गायक आदि को ढाई सौ पण और उनमें से अधिकांश पारंगत कलाकार को पाँच सौ पण वेतन प्रतिवर्ष दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

दूसरे साधारण कारीगरों को एक सौ बीस पण वेतन दिया जाना उपयुक्त माना गया है।

पशु चिकित्सकों, चिकित्सकों, परिचारकों आदि को साठ हजार पण वार्षिक वेतन दिया जाना निर्धारित किया गया है।

आर्य सत्पुरुष, युक्त रोहक बिगड़ैल घोड़े का सवार माणवक वेदाध्यायी, विद्यार्थी, शैल खनक, निपुण, गायनाचार्य और विद्वान इन लोगों को योग्यतानुसार पाँच सौ से हजार पण वेतन प्रतिवर्ष देने की व्यवस्था की गई है।

ग्रन्थ में कहा गया है कि मध्य गति से एक योजन तक आने-जाने वाले दूत को दस पण वेतन दिया जाय तथा दस योजन से सौ योजन तक चलने वाले को बीस पण वेतन दिया जाये।

ग्रन्थ में राजा को परामर्श दिया गया है कि वह राजसूय आदि यज्ञों पर मंत्री, पुरोहित आदि को उनके निर्धारित वेतन से तिगुना वेतन दें। इसी प्रकार राजा को यज्ञ स्थान में लाने वाले सारथि को एक हजार पण वेतन प्रदान करें।

कापटिक, उदास्थित, ग्रहपतिक, वैदेहक और तापस आदि के वेश में कार्य करने वाले गुप्तचरों का वार्षिक वेतन हजार पण निर्धारित किया गया है।

धोबी, नाई आदि गाँव के नौकर, गाँव के मुखिया खत्री, तीक्षण तथा भिक्षु आदि के वेश में काम करने वाले गुप्तचरों का वेतन पाँच सौ पण निर्धारित किया गया है।

गुप्तचरों को इधर-उधर भेजने वाले कर्मचारियों को ढाई सौ पण वेतन दिये जाने अथवा परिश्रम के अनुसार अधिक वेतन दिये जाने की आवश्यकता की व्यवस्था की गई है।

ग्रन्थ में प्रतिपादित किया गया है कि शतवर्ग के या सहस्त्र वर्ग के अध्यक्षों को चाहिए कि वे नौकरों को यथोचित वेतन दिलायें।

ग्रन्थ में स्थाई और अस्थाई कर्मचारियों की योग्यता और कार्यदक्षता के अनुसार कम या अधिक वेतन दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

मल्लाहों के वेतन भत्तो के बारे में कौटिल्य ने कहा है कि नदियों के किनारे बसे हुए लोगों सरकारी टैक्स के अतिरिक्त कुछ निर्धारित भत्ता या वेतन भी मल्लाहों को दिया जाये।

कौटिल्य ने कहा है कि घोड़ों की परिचर्या करने वाले कर्मचारी यदि अपने कार्य को उचित रीति से न करें तो उसका दिन का वेतन काट लेना चाहिए।

अर्थशास्त्र में कहा गया है कि सात प्रकार की सेनाओं में से शत्रु सेना तथा आटिविक सेना को नियमित मासिक वेतन न देकर उसके ओढ़ने बिछाने तथा पहनने के लिए शत्रु देश से जीता हुआ माल ही वेतन के रूप में दिया जाना चाहिए।

कौटिल्य ने वेतन निर्धारण हेतु समय गणना का भी उल्लेख किया है। तीन सौ चौवन दिन-रात का एक कर्म-संवत्सर होता है। उसकी समाप्ति आषाढ़ी पूर्णिमा को समझना चाहिए। इसी वर्ष गणना के हिसाब से प्रत्येक अध्यक्ष का वेतन दिया जाना चाहिए। यदि अध्यक्ष की नियुक्ति वर्ष के मध्य में हुई है तो उसको कम वेतन और यदि उसने पूरे वर्ष कार्य किया है तो उसे पूरा वेतन दिया जाना चाहिए। कौटिल्य का मत है कि प्रत्येक कर्मचारी के कार्य का ब्यौरा उपस्थिति पंजिका से देखना चाहिए।

कौटिल्य ने सूत्राध्यक्ष के बारे में कहा है कि वह कारीगरों की नियुक्ति नियत कार्यकाल और निश्चित वेतन के अनुसार ही करें और उनसे सम्पर्क बनाये रखें। घर पर काते हुए सूत को लेकर जो स्त्रियों या दासियों को साथ लेकर प्रातःकाल ही सूत्रशाला में उपस्थित हों, उन्हें यथोचित मजदूरी अर्थात् अतिरिक्त समय का वेतन दें। अध्यक्ष को चाहिए कि मोटे-महीन सूत कातने बुनने वाले कारीगरों को इत्र, फुलेल तथा अन्य पारितोषिक देकर सदा प्रसन्न रखें।

कौटिल्य ने कहा है कि खेतों की रखवाली करने वाले ग्वाले, दास और नौकर आदि प्रत्येक को उसकी मेहनत के अनुसार भोजन वस्त्रादि दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रतिमास सवा पण वेतन मिलना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे कारीगरों को भी उनके परिश्रम के अनुसार भोजन, वस्त्र और वेतन आदि दिया जाना चाहिए।

अर्थशास्त्र में शराब का वेतन के रूप में दिया जाना एक अलोचना का विषय है। आचार्य ने कहा है कि घटिया शराब या तो दास जैसे छोटे कर्मचारियों को वेतन के रूप में देनी चाहिए अथवा बैल, उंट की सवारी हाँकने वाले तथा सुअर का पालन पोषण करने वालों को दे देनी चाहिए।

अर्थशास्त्र में अग्रिम वेतन का भी उल्लेख हुआ है। कौटिल्य ने कहा है कि यदि किसी मजदूर ने दूसरी जगहों से अग्रिम वेतन लिया हो तो पहले मालिक का पूरा कार्य करने पर ही वह दूसरी जगह कार्य कर सकता है।

कौटिल्य कार्य के अनुसार वेतन निर्धारण को आवश्यक मानता है, साथ ही वेतन के बदले में यथेष्ट श्रम की आवश्यकता को प्रतिपादित करता

है। उनका मत है कि वेतन कार्य करने का दिया जाता है, खाली बैठने का नही।

इस संदर्भ में कठोर नीति का समर्थन करते हुए उसने प्रतिपादित किया है कि यदि कारीगर काम बिगाड़ दे तो उन्हें मजदूरी न दी जाए वरन् उन पर वेतन का दुगुना जुर्माना किया जाये।

अर्थशास्त्र में वेतन वृद्धि के बारे में भी उल्लेख मिलता है। कौटिल्य ने राजा को परामर्श दिया है कि अमात्यों तथा सैनिकों के भत्तो और वेतन में समय-समय पर वृद्धि कर दें। कौटिल्य का यह भी परामर्श है कि शासक विभिन्न कार्मिकों को वेतन वृद्धि के प्रति आशान्वित व आश्वस्त करें।

(य) पदोन्नति- कौटिल्य ने कार्मिकों की पदोन्नति के विषय में भी एक स्पष्ट नीति का प्रतिपादन किया है। कौटिल्य का मत है कि जो पदाधिकारी आदिष्ट कार्य को पूरा करके, स्वेच्छा या किसी दूसरे हितकर कार्स को भी करता है तो उसे तरक्की और सम्मान दिया जाना चाहिए।

उसने शासक को परामर्श दिया है कि जो अध्यक्ष राज्य धन का अपहरण नहीं करते, वरन् न्यायपरायण होकर राजा की समृद्धि में यत्नशील रहते हैं और प्रिय समझकर राजा का हित करते रहते हैं, ऐसे सच्चरित्र अध्यक्षों को शासक सदा सम्मानपूर्वक उच्च पद प्रदान करें।

कौटिल्य जहाँ कर्त्ताव्य निष्ठा के आधार पर पदोन्नति का प्रावधान करते हैं, वहीं वह कर्त्ताव्य भ्रष्ट कार्मिकों को दण्डित करने तथा पदावनत करने की अनुशंसा करते हैं। उनका मत है कि कर्त्ताव्य भ्रष्ट अध्यक्षों का जब राजा पता लगा लें तो वह उन धन सम्पन्न अधिकारियों की सारी सम्पत्ति को छीन लें और उन्हें उनके उच्च पदों से गिराकर निम्न पदों पर नियुक्त कर दें, जिससे वे भविष्य में गबन न कर सकें एवं गबन को स्वयं उगल दें।

पदोन्नति से पूर्व कौटिल्य संबंधित कार्मिक की पदोन्नति हेतु पात्रता के सम्यक परीक्षण पर बल देते हैं। अर्थशास्त्र में चार उपायों यथा धर्मोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा, भयोपधा द्वारा परीक्षा ली जाकर भी अमात्यों को उक्त पदों पर पदोन्नत किये जाने का उल्लेख है।

(र) अधिलाभ बोनस, आशुतोष ग्रेच्युटी व पुरस्कार -कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शुक्रनीति की भांति अधिलाभ व आशुतोष के बारे में कोई व्यवस्था का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है।

(ल) सेवा निवृत्ति लाभ-अर्थशास्त्र में सेवा निवृत्ति लाभों का विस्तृत व व्यवस्थित वर्णन नहीं किया गया है, किन्तु प्रासंगिक उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि कौटिल्य ने कार्मिकों की सेवा निवृत्ति के पश्चात् उनके जीवनयापन की व्यवस्था राज्य की ओर से किए जाने पर बल दिया है। कार्यरत कार्मिक की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के भरण-पोषण की व्यवस्था कौटिल्य ने महत्तवपूर्ण माना है तथा इसके समाधान पर बल दिया है।

अर्थशास्त्र में प्रतिपादित किया गया है कि यदि कार्य करते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाये तो उसका वेतन उसके पुत्र व पत्नी को प्रदान किया जाये। कौटिल्य ने परामर्श दिया है कि मृत कर्मचारी के बालकों, वृद्धों और बीमार परिजनों पर राजा कृपा दृष्टि बनाये रखे तथा उनके घरों पर मृत्यु, बीमारी या बच्चा हो जाने पर उसकी आर्थिक तथा मौखिक सहायता करता रहे।

(व) अवकाश-अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है कि किसी अशक्तता, अस्वस्थता में या किसी आपत्ति में फंस जाने के कारण कार्मिक आकस्मिक छुट्टी ले सकता है, अथवा अपनी एवज में किसी दूसरे व्यक्ति को रखकर छुट्टी ले सकता है।

उपर्युक्त कथन में अस्वस्थता की स्थिति में अवकाश या आकस्मिक अवकाश दोनों का ही स्पष्ट संकेत मिलता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कौटिल्य का अर्थशास्त्र अधिकरण-1, अध्याय 8-10
2. कौटिल्य का अर्थशास्त्र अधिकरण-1, अध्याय-9, प्रकरण-3
3. कौटिल्य का अर्थशास्त्र अधिकरण-1, अध्याय-9, प्रकरण-5
4. कौटिल्य का अर्थशास्त्र अधिकरण-1, अध्याय-9, प्रकरण-5
5. कौटिल्य का अर्थशास्त्र अधिकरण-1, अध्याय-9, प्रकरण-5
6. कौटिल्य का अर्थशास्त्र अधिकरण-1, अध्याय-9, प्रकरण-5
7. कौटिल्य का अर्थशास्त्र अधिकरण-1, अध्याय-9, प्रकरण-5
8. कौटिल्य का अर्थशास्त्र अधिकरण-1, अध्याय-9, प्रकरण-5
9. कौटिल्य का अर्थशास्त्र अधिकरण-1, अध्याय-10, प्रकरण-6
10. कौटिल्य का अर्थशास्त्र अधिकरण-1, अध्याय-9, प्रकरण-25

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

The Chemistry of Water Treatment: Methods and Technologies

Dr. Anjul Singh*

Abstract - Water treatment is a vital process to ensure the provision of clean and safe water for various applications. This paper provides an overview of the chemistry behind water treatment methods and technologies. It explores the different approaches employed to purify water and remove contaminants, focusing on physical, chemical, and biological processes. The discussion encompasses commonly used techniques such as coagulation, flocculation, sedimentation, filtration, disinfection, and advanced oxidation processes. The chemical principles underlying each method are explained, highlighting their effectiveness in eliminating impurities, pathogens, and pollutants. Furthermore, emerging technologies and innovative approaches in water treatment are discussed, including membrane filtration, electrochemical processes, and nanotechnology. The significance of monitoring water quality and complying with regulatory standards is emphasized throughout. By understanding the chemistry of water treatment, engineers and scientists can develop efficient strategies to ensure the provision of clean and safe water resources for society.

Introduction - Water treatment is a critical process that aims to purify and improve the quality of water for various purposes, including drinking, industrial processes, and environmental protection. It involves the removal of contaminants, such as impurities, microorganisms, and pollutants, from water sources. The chemistry of water treatment encompasses a range of methods and technologies that rely on chemical reactions and principles to achieve effective water purification. Let's explore some of the key methods and technologies used in water treatment.

1 Objective: To explore and analyze the various methods and technologies employed in water treatment processes for efficient purification and safe consumption.

2. Water Contamination and Treatment Challenges

2.1 Sources of Water Contamination:

Water contamination can arise from various sources, both natural and human activities. Some common sources include:

1. Industrial activities: Industrial processes often release pollutants into water bodies. These can include heavy metals, toxic chemicals, and organic compounds that find their way into water sources **through improper disposal or accidental spills.**

2. Agricultural practices: The use of fertilizers, pesticides, and herbicides in agriculture can lead to water contamination. These chemicals can leach into groundwater or runoff into nearby water bodies, causing contamination.

3. Municipal wastewater: Sewage and wastewater from households, commercial establishments, and industries are typically treated before being discharged into water bodies. However, inadequate treatment or infrastructure failures can result in the release of untreated or partially treated wastewater, leading to contamination.

4. Mining activities: Mining operations generate large quantities of waste, known as tailings, which often contain harmful substances like heavy metals and sulfuric acid. If not properly managed, these tailings can contaminate nearby water sources.

5. Landfill leachate: Landfills receive various types of waste, including hazardous materials. As rainwater percolates through the landfill, it can pick up contaminants from the waste, forming leachate that can contaminate groundwater and surface water.

6. Natural sources: Natural sources of contamination include geological formations that contain minerals or chemicals that dissolve in water, such as arsenic, fluoride, or radon. These elements can enter groundwater and affect the quality of drinking water.

2.2 Impurities and Contaminants:

Water contaminants can be classified into several categories:

1. Microorganisms: Bacteria, viruses, and parasites are common microbial contaminants that can cause waterborne diseases like cholera, typhoid, and dysentery.

2. Chemical pollutants: These include heavy metals (lead, mercury, arsenic), organic compounds (pesticides, solvents, petroleum products), and synthetic substances (pharmaceuticals, personal care products). Chemical pollutants can have adverse health effects when consumed or come into contact with the skin.

3. Nutrients: Excessive levels of nutrients, primarily nitrogen and phosphorus, can lead to eutrophication in water bodies. This can cause harmful algal blooms, oxygen

***Associate Professor (Chemistry) Govt. PG College, Dholpur (Raj.) INDIA**

depletion, and disruption of aquatic ecosystems.

4. Sediments: Sediment runoff from construction sites, deforestation, or erosion can cloud water, reducing its clarity and adversely affecting aquatic life by blocking sunlight and smothering habitats.

5. Radionuclides: Naturally occurring radioactive substances, such as uranium or radium, can be present in water sources and pose health risks if consumed at high levels over extended periods.

2.3 Challenges in Water Treatment: Water treatment faces several challenges in ensuring the provision of safe and clean drinking water:

1. Aging infrastructure: Many water treatment facilities and distribution systems are old and in need of upgrades or replacements. Outdated infrastructure can lead to inefficiencies, leakage, and inadequate treatment, compromising water quality.

2. Emerging contaminants: The identification and treatment of emerging contaminants, such as pharmaceuticals, microplastics, and endocrine-disrupting compounds, present significant challenges due to their diverse nature and potential health impacts. Developing effective treatment methods for these contaminants is an ongoing research area.

3. Cost and resources: Implementing and maintaining water treatment infrastructure requires significant financial resources. Some communities, especially in developing regions, may struggle to invest in advanced treatment technologies, leading to inadequate water treatment and quality issues.

4. Climate change and water scarcity: Changing precipitation patterns and increased water scarcity pose challenges for water treatment. Drought conditions can reduce water availability, increase the concentration of contaminants, and intensify competition for limited water resources.

5. Large-scale contamination events: Accidental spills, industrial accidents, or natural disasters can
result in sudden and widespread contamination of water sources. Responding to such events and providing emergency treatment poses logistical and operational challenges

6. Regulatory compliance: Meeting and adapting to evolving water quality standards and regulations can be complex and costly for water treatment facilities. Compliance with strict regulations requires continuous monitoring, testing, and implementation of appropriate treatment technologies.

Addressing these challenges requires a combination of technological advancements, investment in infrastructure, robust monitoring and surveillance systems, public education, and proactive policies and regulations to protect water resources and ensure safe drinking water for communities.

3. Water Treatment Processes

3.1 Coagulation and Flocculation:

3.1.1 Mechanisms and Chemistry: Coagulation and flocculation are water treatment processes that involve the addition of chemicals to destabilize and aggregate suspended particles in water. The mechanisms and chemistry involved are as follows:

Coagulation: Coagulation is the process of destabilizing colloidal particles present in water. Positively charged coagulants, such as aluminumsulfate (alum) or ferric chloride, are commonly used. These coagulants neutralize the negative charges on the particles, allowing them to come together and form larger, heavier particles called flocs.

Flocculation: Flocculation involves gently stirring the water to encourage the collision and aggregation of the destabilized particles into larger flocs. This process enhances the settling characteristics of the particles and aids in their removal during sedimentation.

3.1.2 Coagulants and Flocculants: Coagulants and flocculants are chemicals used in the coagulation and flocculation processes. Common coagulants include aluminumsulfate (alum), ferric chloride, and polyaluminum chloride (PAC). These coagulants work by forming positively charged metal hydroxide precipitates, which neutralize the negative charges on the particles.

Flocculants, on the other hand, are typically high molecular weight polymers. They help bridge the particles together and form larger flocs. Examples of flocculants include polyacrylamides and polyDADMAC (polydiallyldimethylammonium chloride).

The selection of coagulants and flocculants depends on factors such as water quality, the nature of impurities, and the desired treatment objectives.

3.2 Sedimentation and Clarification:

3.2.1 Principles and Mechanisms:

Sedimentation and clarification processes involve the removal of settled particles and flocs from water. The principles and mechanisms are as follows:

Sedimentation: During sedimentation, water is held in large basins or tanks to allow sufficient time for the settling of particles and flocs. The force of gravity causes the heavier particles to settle at the bottom of the tank, forming a sludge layer, while clarified water is collected from the top.

Clarification: Clarification is the process of separating the settled solids from the clarified water. Various mechanisms are employed, such as inclined plates or tube settlers, to enhance the removal of settled particles. The clarified water is then passed on for further treatment.

3.2.2 Settling Tanks and Clarifiers: Settling tanks, also known as sedimentation basins or clarifiers, are the primary units used for sedimentation and clarification. These tanks are designed to provide a quiescent environment where settling can occur. They may have mechanisms to promote the settling process, such as the use of inclined plates or tube settlers, which increase the effective settling area.

Inclined plates or tube settlers provide additional surface area for particles to settle on, improving the efficiency of sedimentation. The settled particles accumulate

at the bottom of the tank and are periodically removed as sludge.

3.3 Filtration:

3.3.1 Types of Filters: Filtration is a water treatment process that involves passing water through a porous medium to remove suspended particles. Different types of filters commonly used in water treatment include:

1. **Rapid Sand Filters:** These filters consist of a bed of sand or other granular media. Water is forced through the filter bed, and suspended particles are trapped within the void spaces between the media particles.
2. **Multimedia Filters:** Multimedia filters use a layered bed of different media, such as anthracite coal, sand, and garnet, to improve filtration efficiency. The
3. larger media particles are placed at the top, gradually becoming finer towards the bottom.
4. **Granular Activated Carbon (GAC) Filters:** GAC filters are effective in removing organic compounds, chlorine, and some taste and odor-causing substances. They utilize a bed of activated carbon granules that adsorb impurities as water passes through.
5. **Membrane Filters:** Membrane filtration processes, such as microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration, and reverse osmosis (RO), use semipermeable membranes with varying pore sizes to physically separate particles and contaminants from water.

3.3.2 Filter Media and Operation: The filter media used in filtration processes can vary depending on the type of filter. Common media include sand, anthracite coal, garnet, and activated carbon. The selection of media depends on the desired filtration efficiency and the specific impurities to be removed.

Filtration operation involves the continuous or intermittent passage of water through the filter bed. As water flows through the filter media, suspended particles are trapped, and the filtered water is collected for further treatment or distribution.

Regular maintenance, such as backwashing, is necessary to remove accumulated particles from the filter bed and restore its filtering capacity.

3.4 Disinfection:

3.4.1 Common Disinfectants: Disinfection is a critical step in water treatment to inactivate or kill harmful microorganisms. Common disinfectants used in water treatment include:

1. **Chlorine:** Chlorine is one of the most widely used disinfectants. It can be applied in the form of chlorine gas, sodium hypochlorite, or calcium hypochlorite. Chlorine is effective against a wide range of microorganisms but can form disinfection byproducts (DBPs) when reacting with organic compounds.
2. **Chloramines:** Chloramines are formed by combining chlorine with ammonia. They provide a longer-lasting disinfectant residual compared to free chlorine and are effective against many microorganisms. Chloramines also produce fewer DBPs.
3. **Ozone:** Ozone is a strong oxidizing agent and disinfectant. It is generated on-site using ozone generators and rapidly reacts with microorganisms, destroying their cellular structures. Ozone does not produce significant DBPs but requires careful monitoring and control.
4. **Ultraviolet (UV) Light:** UV light disinfection involves exposing water to UV radiation, which damages the genetic material of microorganisms, preventing their replication. UV disinfection does not introduce any chemicals into the water but requires adequate contact time and proper lamp maintenance.

3.4.2 Disinfection Mechanisms: Disinfection mechanisms vary depending on the disinfectant used. Common disinfection mechanisms include:

1. **Chlorine:** Chlorine acts by disrupting microbial enzymes and cell structures, leading to the inactivation or killing of microorganisms.
2. **Chloramines:** Chloramines penetrate the cell walls of microorganisms, interfering with cellular functions and causing disinfection.
3. **Ozone:** Ozone is a powerful oxidizing agent that damages microbial cells through the oxidation of cellular components, such as proteins and DNA.
4. **UV Light:** UV light disrupts the DNA structure of microorganisms, preventing replication and rendering them unable to cause infections.

3.5 Adsorption:

3.5.1 Activated Carbon: Activated carbon is a highly effective adsorbent used in water treatment to remove organic compounds, certain chemicals, taste, and odor-causing substances. The key features of activated carbon are its large surface area and adsorptive properties.

Activated carbon is produced by heating carbonaceous materials, such as coal, wood, or coconut shells, at high temperatures in the absence of oxygen. This process creates a network of pores and increases the surface area available for adsorption.

3.5.2 Adsorbent Selection and Regeneration: The selection of the appropriate adsorbent depends on the specific contaminants to be removed. Different types of activated carbon, such as powdered activated carbon (PAC) or granular activated carbon (GAC), can be used based on the application.

Regeneration of activated carbon involves removing the adsorbed contaminants from the carbon surface, allowing it to be reused. Common regeneration methods include thermal reactivation, steam reactivation, and chemical regeneration. The choice of regeneration method depends on the characteristics of the activated carbon and the contaminants adsorbed.

3.6 Membrane Processes:

3.6.1 Reverse Osmosis: Reverse osmosis (RO) is a membrane process used to remove dissolved salts, ions, and other impurities from water. It operates by applying pressure to the water, forcing it through a semipermeable membrane. The membrane has very fine pores that allow

water molecules to pass through while rejecting dissolved solids.

RO is commonly used in desalination plants to produce freshwater from seawater or brackish water sources. It is also employed in water treatment for the removal of contaminants like nitrates, sulfates, and certain organic compounds.

3.6.2 Ultrafiltration and Nanofiltration: Ultrafiltration (UF) and nanofiltration (NF) are membrane processes that operate on a larger pore size range compared to RO. They are effective in removing suspended particles, colloids, bacteria, and some larger organic compounds.

UF membranes have larger pore sizes and primarily function as physical filters, while NF membranes have smaller pore sizes and can also selectively reject some ions and smaller organic molecules.

UF and NF are often used as pretreatment steps before RO to reduce fouling and protect the RO membranes. They can also be used independently for specific water treatment applications where the removal of larger particles and microorganisms is the primary objective.

4. Chemical Additives in Water Treatment

4.1 pH Adjustment and Acid/Base Reactions: pH adjustment is an essential process in water treatment to maintain the desired pH range for optimal treatment efficiency and water quality. Chemical additives are used to adjust the pH by promoting acid/base reactions. Some common chemicals used for pH adjustment include:

1. **Acids**: Strong acids like sulfuric acid (H2SO4) or hydrochloric acid (HCl) are used to lower the pH of alkaline water. They react with alkaline substances, releasing hydrogen ions (H+), which decrease the pH.
2. **Bases:** Bases like sodium hydroxide (NaOH) or lime (calcium hydroxide, Ca(OH)2) are used to raise the pH of acidic water. They react with acidic substances, releasing hydroxide ions (OH-), which increase the pH.

4.2 Oxidants and Reducing Agents: Oxidants and reducing agents are used in water treatment to facilitate oxidation or reduction reactions. Some examples include:

1. **Chlorine:** Chlorine is commonly used as an oxidant and disinfectant. It oxidizes organic compounds, kills microorganisms, and helps control odors and tastes in water.
2. **Ozone:** Ozone is a powerful oxidant that reacts with organic compounds, iron, manganese, and other substances, effectively removing them from water.
3. **Sodium Bisulfite:** Sodium bisulfite is a reducing agent used to remove excess chlorine or chlorine dioxide residual after disinfection.

4.3 pH Buffers and Alkalinity Control: pH buffers and alkalinity control chemicals are used to stabilize and maintain the desired pH level in water treatment processes. They help resist drastic changes in pH caused by acids or bases. Common chemicals used for pH buffering and alkalinity control include:

1. **Sodium bicarbonate:** Sodium bicarbonate (baking soda) is often used to increase alkalinity and provide buffering capacity, helping to maintain a stable pH.
2. **Lime:** Lime (calcium hydroxide, Ca(OH)2) is used to increase alkalinity and buffer the pH. It also provides calcium ions, which can assist in flocculation and precipitation processes.

4.4 Coagulants and Flocculants: Coagulants and flocculants are chemical additives used in the coagulation and flocculation processes to remove suspended particles and turbidity from water. They aid in the aggregation of fine particles into larger flocs for easier removal. Common coagulants and flocculants have been discussed in section 3.1.2.

4.5 Disinfectants and Biocides: Disinfectants and biocides are chemicals used to kill or inactivate harmful microorganisms in water. They play a crucial role in ensuring water safety. Common disinfectants and biocides used in water treatment include:

1. **Chlorine:** Chlorine is a widely used disinfectant due to its effectiveness against a broad range of microorganisms. It can be applied in the form of chlorine gas, sodium hypochlorite, or calcium hypochlorite.
2. **Chloramines:** Chloramines, formed by combining chlorine with ammonia, provide longer-lasting disinfection residuals and reduce the formation of disinfection byproducts.
3. **Chlorine Dioxide:** Chlorine dioxide is a powerful disinfectant that effectively kills bacteria, viruses, and other microorganisms. It is often used in situations where taste and odor control are important.
4. **UV Light:** Ultraviolet (UV) light is used as a physical disinfection method. It damages the DNA of microorganisms, preventing their replication and rendering them harmless.

4.6 Scale and Corrosion Inhibitors: Scale and corrosion inhibitors are chemicals used to prevent the formation of scale deposits on surfaces and corrosion in water treatment systems. These additives help protect pipes, equipment, and fixtures. Some common scale and corrosion inhibitors include:

1. **Phosphates:** Phosphates can form a protective layer on metal surfaces, reducing the likelihood of corrosion and scale formation.
2. **Polyphosphates:** Polyphosphates sequester hardness ions, such as calcium and magnesium, preventing their precipitation and the formation of scale.
3. **Silicates:** Silicates can provide a protective coating on metal surfaces, reducing corrosion and scale formation.
4. **Polymeric Dispersants:** Polymeric dispersants help keep particles suspended and prevent their agglomeration, reducing the formation of deposits and scale.

The selection and dosage of chemical additives in water treatment depend on the specific water quality parameters, treatment objectives, and regulatory requirements. It is important to carefully evaluate the water composition and consider the potential interactions and

impacts of the additives on the treatment process and water quality.

5. Emerging Technologies in Water Treatment

5.1 Advanced Oxidation Processes: Advanced oxidation processes (AOPs) are innovative water treatment technologies that involve the generation of highly reactive hydroxyl radicals (·OH) to degrade and remove persistent organic pollutants and micropollutants from water. AOPs typically combine an oxidant, such as ozone (O3) or hydrogen peroxide (H2O2), with a catalyst or energy source, such as ultraviolet (UV) light or ultrasound. These processes can effectively break down complex organic compounds and contaminants that are resistant to conventional treatment methods.

5.2 Electrochemical Water Treatment: Electrochemical water treatment utilizes electrochemical reactions to remove contaminants from water. This technology involves the use of electrodes and electrical current to facilitate oxidation or reduction reactions. Electrochemical methods, such as electrocoagulation, electrooxidation, and electrochemical disinfection, can effectively remove various pollutants, including heavy metals, organic compounds, and microorganisms. It offers advantages such as low chemical consumption, ease of operation, and the potential for resource recovery.

5.3 UV Disinfection: UV disinfection involves the use of ultraviolet light to inactivate microorganisms present in water. UV light at specific wavelengths damages the DNA or RNA of microorganisms, preventing their reproduction and rendering them harmless. UV disinfection is gaining popularity as an alternative to chemical disinfection methods because it does not introduce chemicals or produce harmful disinfection byproducts. It is effective against a wide range of microorganisms and is commonly used in drinking water treatment, wastewater treatment, and water reuse applications.

5.4 Membrane Bioreactors: Membrane bioreactors (MBRs) combine biological treatment processes with membrane filtration. MBR systems use microorganisms to degrade organic matter and remove nutrients, while ultrafiltration or other membrane technologies separate the treated water from the biomass. MBRs offer superior effluent quality, high treatment efficiency, and a smaller footprint compared to conventional activated sludge systems. They are widely used in wastewater treatment applications and can be integrated into decentralized treatment systems.

5.5 Nanotechnology Applications: Nanotechnology is increasingly being applied in water treatment to enhance treatment efficiency, remove contaminants, and improve water quality. Some nanotechnology applications in water treatment include:

1. **Nanofiltration and Reverse Osmosis Membranes:** Nanostructured membranes with fine pore sizes can effectively remove particles, salts, and contaminants from water.
2. **Nanoscale Adsorbents:** Nanomaterials, such as activated carbon nanotubes or nanoparticles, have high surface areas and enhanced adsorption capacities, enabling efficient removal of pollutants from water.
3. **Nanocatalysts:** Nanoscale catalysts can be used for advanced oxidation processes, facilitating the degradation of organic pollutants and micropollutants.
4. **Antimicrobial Nanomaterials:** Nanomaterials with antimicrobial properties, such as silver nanoparticles, can be used for disinfection and the control of microbial growth in water treatment systems.

5.6 Solar Water Disinfection: Solar water disinfection, also known as SODIS, is a simple and low-cost water treatment method that utilizes solar radiation to inactivate pathogens in water. It involves filling transparent containers, such as plastic bottles, with contaminated water and exposing them to sunlight for several hours. The combination of UV radiation and increased temperature effectively kills or inactivates microorganisms, making the water safe for drinking. SODIS is commonly used in developing regions with limited access to clean water and has been shown to be effective against a wide range of pathogens.

6. Water Quality Monitoring and Analysis

6.1 Importance of Water Quality Analysis: Water quality analysis is crucial for ensuring the safety, purity, and suitability of water for various purposes, including drinking water, industrial processes, agriculture, and environmental preservation. It helps identify the presence of contaminants, assess compliance with regulatory standards, monitor the effectiveness of water treatment processes, and detect emerging issues or potential health risks. Regular water quality analysis provides essential data for informed decision-making, effective management of water resources, and protection of public health and the environment.

6.2 Sampling Techniques: Accurate water quality analysis requires proper sampling techniques to obtain representative samples that reflect the true quality of the water. Common sampling techniques include:

1. **Grab Sampling:** Grab sampling involves collecting a single sample at a specific location and time. It is suitable for obtaining discrete samples for immediate analysis but may not capture variations in water quality over time.
2. **Composite Sampling:** Composite sampling involves combining multiple grab samples collected over a specified period or from various points within a water body. It provides an average representation of water quality during the sampling period and can help capture temporal and spatial variations.
3. **Automatic Sampling:** Automatic sampling systems use automated devices to collect water samples at pre-determined intervals. They are particularly useful for continuous monitoring and can provide high-frequency data.

Sampling techniques should follow established protocols, consider the location and depth of sampling, avoid contamination, and ensure proper preservation and handling of samples to maintain their integrity.

6.3 Analytical Methods and Instruments:
Various analytical methods and instruments are used to analyze water samples for different parameters and contaminants. Some common methods include:

1. **Physical Parameters:** Physical parameters such as temperature, pH, turbidity, conductivity, and dissolved oxygen can be measured using instruments such as thermometers, pH meters, turbidity meters, conductivity meters, and dissolved oxygen meters.
2. **Chemical Analysis:** Chemical analysis involves determining the concentration of specific substances in water. Methods include titration, spectrophotometry, chromatography (e.g., gas chromatography, liquid chromatography), and atomic absorption spectroscopy. These methods can be used to analyze nutrients, metals, organic compounds, disinfection byproducts, and other chemical constituents.
3. **Microbiological Analysis:** Microbiological analysis involves the detection and enumeration of microorganisms in water. Techniques include membrane filtration, multiple tube fermentation, and presence/absence tests. Microbiological analysis helps assess the presence of bacteria, viruses, and other pathogens that can pose health risks.

6.4 Online Monitoring Systems: Online monitoring systems provide real-time or near real-time monitoring of water quality parameters. These systems use automated sensors and instruments to continuously measure key parameters such as pH, turbidity, conductivity, dissolved oxygen, and temperature. The data from online monitoring systems can be transmitted to a central control unit or accessible through a web-based interface for remote monitoring and analysis. Online monitoring systems enable rapid detection of changes in water quality, early warning systems, process optimization, and timely response to deviations or incidents. They are particularly valuable in critical applications such as drinking water treatment, industrial processes, and environmental monitoring.

7. Environmental Considerations and Regulations

7.1 Environmental Impact of Water Treatment: Water treatment processes can have both positive and negative environmental impacts. Some of the key environmental considerations include:

a. **Energy Consumption:** Water treatment processes often require energy for pumping, filtration, disinfection, and other operations. The energy source can contribute to greenhouse gas emissions and air pollution.

b. **Chemical Usage and Disposal:** Chemical additives used in water treatment can have environmental impacts, such as the release of disinfection byproducts or the potential for chemical spills. Proper handling, storage, and disposal of chemicals are crucial to minimize environmental harm.

c. **Waste Generation:** Water treatment can produce waste streams, such as sludge from sedimentation or filtration processes. Proper management and disposal of waste materials are important to prevent pollution and ensure compliance with regulations.

d. **Habitat Disruption:** Water intake structures, such as dams or intakes for water supply, can disrupt aquatic habitats and impact fish migration and populations. Proper design and operation of these structures can help mitigate their environmental impact.

7.2 Water Treatment and Sustainability: Water treatment plays a vital role in achieving sustainability in water management. Some key considerations for sustainable water treatment include:

a. **Water Conservation:** Implementing water-efficient technologies and practices in water treatment processes can minimize water loss and maximize water reuse, reducing the strain on freshwater resources.

b. **Energy Efficiency:** Promoting energy-efficient processes, utilizing renewable energy sources, and optimizing energy consumption in water treatment can help reduce greenhouse gas emissions and environmental impact.

c. **Chemical Minimization:** Minimizing the use of chemicals or opting for environmentally friendly alternatives can reduce the environmental impact of water treatment processes.

d. **Resource Recovery:** Exploring opportunities for resource recovery from waste streams generated during water treatment, such as the extraction of valuable materials or the production of biogas from sludge, can contribute to sustainability and circular economy principles.

e. **Environmental Monitoring:** Regular monitoring of water quality, effluent discharges, and environmental impacts is essential to assess the effectiveness of water treatment processes, identify potential issues, and ensure compliance with environmental regulations.

7.3 Regulatory Framework and Standards:
Water treatment is subject to various regulatory frameworks and standards that aim to protect human health, preserve the environment, and ensure the quality and safety of water resources. These regulations and standards can vary between countries or regions but commonly include:

a. **Drinking Water Standards:** Standards for drinking water quality set limits and guidelines for various contaminants to ensure the safety of drinking water supplies. Examples include the World Health Organization (WHO) Guidelines for Drinking-water Quality and national drinking water standards.

b. **Wastewater Discharge Regulations:** Regulations govern the quality and quantity of effluent that can be discharged into water bodies. They set limits for various parameters and require compliance with specific treatment processes to protect receiving waters.

c. **Environmental Impact Assessments:** Large-scale water treatment projects or infrastructure developments may require environmental impact assessments to evaluate potential environmental impacts and propose mitigation measures.

d. Water Resource Management: Regulations and policies related to water resource management aim to allocate water resources efficiently, protect water sources, and manage water use in a sustainable manner. These may include water permits, water allocation plans, and water conservation measures.

Compliance with these regulations and standards is essential for water treatment facilities to ensure the protection of the environment, public health, and the sustainability of water resources.

8. Case Studies and Success Stories

8.1 Water Treatment Case Study 1: Industrial Wastewater Treatment

Case Study: A large industrial facility producing chemicals had a significant challenge in treating its wastewater before discharge to meet regulatory requirements. The wastewater contained high concentrations of organic compounds and heavy metals, posing a risk to the environment and public health.

Solution: The facility implemented an advanced treatment system combining multiple processes. The treatment train included coagulation and flocculation for solid removal, followed by activated carbon adsorption for organic compound removal and precipitation/filtration for heavy metal removal. Finally, disinfection was conducted using UV irradiation to ensure microbial inactivation.

Result: The implemented treatment system successfully achieved compliance with regulatory discharge limits. The coagulation and flocculation process removed suspended solids, while the activated carbon adsorption effectively reduced organic compound concentrations. Precipitation/ filtration removed heavy metals, and UV disinfection ensured microbial safety. The facility significantly reduced its environmental impact, protected water resources, and maintained regulatory compliance.

8.2 Water Treatment Case Study 2: Municipal Water Treatment Plant

Case Study: A municipality in a rapidly growing urban area faced challenges in providing safe and reliable drinking water to its residents. The existing water treatment plant was outdated and unable to meet the increasing demand and stricter regulatory standards for water quality.

Solution: The municipality upgraded its water treatment plant, incorporating advanced technologies. The new treatment process included coagulation and flocculation, followed by rapid sand filtration and disinfection using chlorine. Additionally, the plant implemented an online monitoring system to continuously monitor key water quality parameters.

Result: The upgraded water treatment plant successfully improved the quality of drinking water supplied to the municipality. The combination of coagulation, filtration, and disinfection processes effectively removed suspended particles, pathogens, and other contaminants. The online monitoring system provided real-time data, enabling proactive response to any deviations in water quality. The municipality achieved its goal of providing safe and reliable drinking water to its growing population.

8.3 Water Treatment Case Study 3: Groundwater Remediation

Case Study: A contaminated groundwater site required remediation due to historical industrial activities that had resulted in the presence of volatile organic compounds (VOCs) and hazardous chemicals. The contamination posed a threat to the local water supply and surrounding environment.

Solution: The remediation plan involved a combination of technologies, including pump-and-treat systems and in-situ chemical oxidation. Pump-and-treat systems were used to extract groundwater, which was then treated through activated carbon adsorption to remove VOCs. In-situ chemical oxidation was implemented to treat the residual contaminants in the subsurface using oxidants such as hydrogen peroxide or potassium permanganate.

Result: The remediation efforts successfully reduced the concentration of contaminants in the groundwater to acceptable levels. The pump-and-treat system effectively removed VOCs, while in-situ chemical oxidation targeted the remaining contamination in the subsurface. The remediation project restored the groundwater quality, eliminated the risk to the local water supply, and protected the environment.

These case studies demonstrate the successful implementation of various water treatment approaches to address specific challenges and achieve desired outcomes. Each case highlights the importance of selecting appropriate treatment processes, technologies, and monitoring systems based on the specific water quality issues and regulatory requirements.

9. Future Trends and Challenges

9.1 Advancements in Water Treatment Technologies: The future of water treatment will continue to see advancements in technology aimed at improving treatment efficiency, enhancing water quality, and reducing environmental impact. Some key trends include:

a. Advanced Membrane Technologies: The development of more efficient and selective membranes, such as forward osmosis and graphene-based membranes, will enhance desalination and water purification processes.

b. Nanotechnology Applications: Further exploration and utilization of nanomaterials in water treatment, such as nanofiltration membranes, nanoscale catalysts, and antimicrobial nanoparticles, will improve treatment efficiency and contaminant removal.

c. Sensor and Monitoring Technologies: The integration of advanced sensors, online monitoring systems, and data analytics will enable real-time monitoring, predictive modeling, and proactive management of water treatment processes.

d. Decentralized Treatment Systems: The adoption of decentralized treatment systems, such as small-scale membrane filtration units and modular treatment units, will

enhance water treatment capabilities, particularly in remote areas or during emergencies.

9.2 Water Reuse and Resource Recovery: Water reuse and resource recovery will play a significant role in the future of water treatment. With increasing water scarcity and the need for sustainable water management, the following trends are expected:

a. Water Reclamation and Reuse: The implementation of advanced treatment processes, such as membrane filtration, advanced oxidation, and reverse osmosis, will enable the safe and reliable reuse of treated wastewater for non-potable purposes, such as irrigation, industrial processes, and groundwater recharge.

b. Nutrient Recovery: Technologies that recover nutrients, such as phosphorus and nitrogen, from wastewater and convert them into valuable products like fertilizer, will help close the nutrient cycle and promote a circular economy approach in water treatment.

Conclusion: The chemistry of water treatment plays a crucial role in the purification and remediation of water sources. From coagulation and flocculation to disinfection, adsorption, membrane processes, and advanced oxidation processes, various chemical methods and technologies are employed to remove impurities and ensure the provision of clean and safe water. Understanding the chemistry behind these processes is essential for designing efficient water treatment systems and achieving sustainable water management practices. Continued research and development in water treatment chemistry are vital to address emerging challenges and secure access to clean water for future generations.

References:-

1. Burgess, J.E., S.A. Parsons and R.M. Stuetz (2001). Developments in odour control and waste gas treatment biotechnology: A review. Biotechnology Advances, 19: 35-63.
2. Caribbean Environment Programme Technical Report #40 (1998). Appropriate technology for sewage pollution control in the wider Caribbean Region.
3. Carter, C.R., S.F. Tyrrel and P. Howsam (1999). Impact and sustainability of community water supply and sanitation programmes in developing countries. Journal of the Chartered Institution of Water and Environmental Management, 13: 292-296.
4. Census of India (2001): Analysis and Articles on Population and Literacy Rates, Office of the Registrar General, India, Ministry of Home Affairs.
5. Chawathe, S. D. and D. Kantawala (1987). Reuse of water in city planning. Water Supply, 15: 17-
6. Chow, V.T., R. Eliason and R.K. Linsley (1972). Development and trends in wastewater Engineering. In Wastewater Engineering. McGraw-Hill Book Company. New York, St. Louis, Dusseldorf, Johannesburg, Kuala Lumpur, London, Mexico, Montreal, New Delhi, Panama, Rio de Janeiro, Singapore, Sydney, Toronto. pp. 1-11.
7. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)Vol. 1 Issue 5, July – 2012 ISSN: 2278-0181
8. Cooper, P.F. (2001). Historical aspects of wastewater treatment. In Decentralized sanitation and reuse concepts, systems and Implementation. Eds., Lens P., Zeeman G., and G. Lettinga. IWA Publishing. London. pp. 11-38.
9. Day, D. (1996). How Australian social policy neglects environments. Australian Journal of Soil and Water Conservation, 9: 3-9.
10. Deb, P.K., A.J. Rubin, A.W. Launder and K.H. Mancy (1966). Removal of COD from wastewater by fly ash. In proceeding of the 1966. 21st Indiana Waste conference. D.E. Bloodygood Ed.Published by Purdue University, W. Lafayette, Indiana. pp: 848 – 860.
11. Denny, P. (1997). Implementation of constructed wetlands in developing countries. Water Science and Technology, 35: 27-34.
12. Doorn, M.R.J., S. Towprayoon, S.Maria, M.Vieira, W.Irving, C.Palmer, R.Pipatti and C.Wang, (2006). Wastewater treatment and discharge. In 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. WMO, UNEP. pp. 5: 1-6.
13. Drizo, A., C. Forget, R.P. Chapuis and Y. Comeau (2006). Phosphorus removal by electric arc furnace steel slag and serpentinite. Water Research, 40: 1547–1554.
14. Eye, D.J. and T.K. Basu (1970). The use of fly ash in municipal waste treatment. Journal of the Water Pollution Control Federation, 42: 125-135.
15. Frijns, J. and M. Jansen (1996). Institutional requirements for appropriate wastewater treatment systems. In A.Balkema, H.Aalbers and E. Heijndermans (Eds.), Workshop on sustainable municipal waste water treatment systems, Leusdan, the Netherlands. ETC in cooperation with WASTE. 12-14 November, 1996. pp: 54-66.
16. Giles, H. and B. Brown (1997). And not a drop to drink. Water and sanitation services in the developing world. Geography, 82: 97-109.
17. Gupta, G.S., G. Prasad, and V.N. Singh (1990). Removal of chrome dye from aqueous solutions by mixed adsorbents: fly ash and coal. Water Research, 24: 45–50.
18. Harada, H., A. Tawficand A. Ohashi (2006). Sewage treatment in a combined up-flow sludge blanket (UASB)-down flow hanging sponge (DHS) system. Biochemical Engineering Journal, 29: 210-219.

****

Impact of Natural Elements Upon Wordsworth's Mind in His Autobiographical Epic the Prelude

Mahender Kumar*

Abstract - William Wordsworth, the representative poet of Romanticism, whose poems took on greater significance, brought a totally new and fresh stream of air to the European literary field. In his poems of nature he printed beautiful pictures full of the creation by the mighty God¯mountains, rocks, rivers and trees. All of them revealed the poets genuine love towards the nature, the fervent enthusiasm of pursuing the truth of life. The very sub-title of this great poem, Prelude tells us that its main theme is 'the growth of a poet's mind'. And if the mind of Wordsworth is the real hero, Nature plays the most vital part, the grand second role in this unique autobiographical epic The Prelude. The purpose of this research paper is to study analytically the impact of natural elements upon Wordsworth's mind in his autobiographical epic *The Prelude.*

Keywords- Natural elements, Autobiography, Romanticism.

Introduction - William Wordworth was born on April 7, 1770 in Cockermouth, Cumberland, located in the Lake District of England: an area that would become closely associated with Wordsworth for over two centuries after his death. He began writing poetry as a young boy in grammar school, and before graduating from college he went on a walking tour of Europe, which deepened his love for nature and his sympathy for the common man: both major themes in his poetry. Wordsworth is best known for *Lyrical Ballads*, co-written with Samuel Taylor Coleridge, and *The Prelude*, a Romantic epic poem chronicling the "growth of a poet's mind."

Wordsworth continued to write poetry with energy and passion over the several years, he composed "*The Solitary Reaper," "Resolution and Independence,"* and *"Ode: Intimations of Immortality,"* perhaps the greatest lyrics of his maturity. In 1805 Wordsworth completed a massive revision of the "poem to Coleridge" that would be published, after undergoing periodic adjustment and revision, after the poet's death in 1850. Many critics believe that the "1805 Prelude," as it has come to be called, is Wordsworth's greatest poetic achievement.

The connection between Wordsworth's poetry and his personal experience is of the closest kind, and he undertook the writing of *The Prelude* in a mood of self-examination. The poet aspired to create a literary work that might live; and he considered it right to examine his powers for such a task before he actually undertook it. The result was *The Prelude.* The poem is thus Wordsworth's assessment of his own powers and a record of those influences that moulded him. And in this psychological account of the growth of his own mind, and of the most significant of the influences that shaped it, he has done the biographer's work once and for all.

The true significance of Nature's role in molding the personality of the poet becomes crystal clear to us when he tells us how from the very childhood, in a very lovely and favorable environment he was nursed and brought up by the various ministries of mother—Nature with the help of her most lovely as well as the sublime and awe-inspiring sights and sounds:

> Fair seed-time had my soul, and I grew up
> Fostered alike by beauty and by fear:
> Much favored in my birthplace, and no less
> In that beloved vale to which are long
> (The Prelude Book 1: 301-305).

The point has been very nicely elucidated by Legouis and Cazamian when they say: "To Wordsworth Nature appeals as a formative influence superior to any other, the educator of senses and mind alike, the sower in our hearts of the deep laid seeds of our feelings and beliefs."

The poem begins in his boyhood and continues to 1798. By the latter date, he felt that his formative years had passed, that his poetic powers were mature, and that he was ready to begin constructing the huge parent work. Alternating with his almost religious conviction, there is an unremitting strain of dark doubt through the poem. The poem itself therefore may be considered an attempt to stall for time before going on to what the poet imagined would be far more difficult composition. As he tells the reader repeatedly, his purpose was threefold: to provide a reexamination of his qualifications, to honor Coleridge, and to create an introduction to *The Recluse.*

The poem falls rather naturally into three consecutive

*Research Scholar, Tantia University, Sriganganagar (Raj.) INDIA

sections: Books 1-7 offer a half-literal, half-fanciful description of his boyhood and youthful environment; Book 8 is a kind of reprise. Books 9-11, in a more fluid and narrative style, depict his exciting adventures in France and London. Books 12-14 are mostly metaphysical and are devoted to an attempt at a philosophy of art, with the end of the last book giving a little summary.

Each of these three "sections" corresponds roughly to a phase in Wordsworth's poetic development and to a period in his life. The first dates from the time of his intuitive reliance on nature, when he wrote simple and graceful lyrics. The second represents his days of hope for, and then disappointment with, the Revolution, and his adoption of Godwinian rationalism, during which he wrote the strong and inspiring sonnets and odes. The last coincides with his later years of reaction and orthodoxy, when he wrote dull and proper works such as *The Excursion* and *Ecclesiastical Sonnets. The Prelude* is critically central to his life work because it contains passages representing all three styles.

The first Book is studded with several impressive incidents showing us the
means by which Nature affects her
discipline on young Wordsworth by evoking the emotions of pleasure and fear. Thus on a hot summer day, the child would have pure animal pleasure by bathing or basking:

Oh, many a time have it a five years' child,
In a small mill-race severed from his stream.
Made one long bathing of a summer's day;
Basked in the sun, and plunged and basked again
Alternate, all a summer's day… (I. 288-292)

The first Book is studded with several impressive incidents showing us the
means by which Nature affects her
discipline on young Wordsworth by evoking the emotions of pleasure and fear. Thus on a hot summer day, the child would have pure animal pleasure by bathing or basking:

Oh, many a time have it a five years' child,
In a small mill-race severed from his
stream.
Made one long bathing of a summer's day;
Basked in the sun, and plunged and basked again
Alternate, all a summer's day… (I. 288-292)

In *The Prelude,* Wordsworth states that the aim is the preservation of the spirit of the past "for future restoration" because the base of human greatness is childhood, which is father of manhood and, indeed, our days are bound together by the fibred piety, which the poet glances at in the remark that "feeling comes in aid of / feeling and a diversity of strength attends us / if once we have been strong" (XII. 269-271). Such feelings of childhood, the great visionary experiences, are "the spots of time to which human mind may return again and again to drink energy and new vitality, as it were, at an inexhaustible fountain."

The awakening of the poet's love of nature is the most significant element in his early education. At the early stage it was just a normal and healthy boy's love for open air sports and pastimes amidst lovely surroundings of nature. So in Books I and II we get an unforgettable recreation of his childhood involvement in physical activities and the joys and fears which were their consequence. In the first two Books, Wordsworth tells us of various exciting activities in which he used to take part with all joy and zeal. In the first Book we have the following—"bathing, bird-snaring, bird-nesting, and expedition in a stolen boat, skating, fishing, kite-sailing, noughts,-and-crosses and cards." In the second Book, also we find they still "ran a boisterous course" and their favorite pastimes were boat-races, boating excursions on the lake, walking tours and riding on horses "through rough and smooth."

The first Book is studded with several impressive incidents showing us the means by which Nature affects her discipline on young Wordsworth by evoking the emotions of pleasure and fear. Thus on a hot summer day, the child would have pure animal pleasure by bathing or basking:

Oh, many a time have it a five years' child,
In a small mill-race severed from his stream.
Made one long bathing of a summer's day;
Basked in the sun, and plunged and basked again
Alternate, all a summer's day… (I. 288-292)

So the beautiful and sublime objects and images of nature with their benign influence ennobled his emotions and moulded his mind, and the poet tells us: … purifying thus The elements of feeling and of thought, And sanctifying, by such discipline, Both pain and fear, until we recognize A grandeur in the beatings of the heart. (I. 410-414)

Another very significant aspect that strikes us in The Prelude, especially in the first two Books, is that in it the poet has traced the three stages of his love of nature. We are able to mark three phases of development. In the first phase, as a child we find the poet deriving simple animal or sensuous delight in Nature. In the second stage he could have more mystical and spiritual pleasure from his deep and close contact with Nature. And finally, we find the love of Nature leading to the love of man, and this change brings about a calmer and sober attitude. Again in Book II, we are aware of the other three phases in the process by which the transcendental or mystical relationship is established between Nature and the poet.

"Wordsworth had his passion for Nature fixed in his blood," observed De Quincy (1970). "It was a necessity of his being like that of the mulberry leaf to the silkworm, and through his commerce with Nature did he love and breathe." (p. 22). Hence it was from the truth of his love that his knowledge grew. If Wordsworth had a favorite subject, it was Nature, and when he treated of man it was essentially in relation to Nature. It was the love of Nature that led him to the love of man. In the words of Pater (2001), "Wordsworth approached the spectacle of human life through Nature. When he thought of man, it was as in the

presence and under the influence of effective natural objects and linked to them by many associations" (p. 12). These words indicate how Nature and Wordsworth used to interact faithfully and innocently with each other. And the solace and calmness the poet received from Nature positively affected his later relationships with human beings. This theme of the influence of Nature on man is the noblest part of Wordsworth's teaching in poetry. Nature is the best educator, and she is ever interested in Man and tries to impress human mind from its earliest dawn. The following words from Book I can clearly and faithfully illustrate this point:

> I believe
> That Nature, often times, when she would frame
> A favour'd Being, from his earliest dawn
> Of infancy doth open up the clouds
> As at the touch of lightening, seeking him
> With great visitation. (362-367).

If we consider the above quotation carefully, we will realize how nature made the poet love human kind in general, and how the poet found solace when his soul was troubled. Three things must impress even the casual reader of The Prelude: first, Wordsworth's love to be alone, he is never lonely with nature. Second, like every other child, who spends much time in the woods and fields, he feels the presence of some living spirit, real though unseen, and companionable though silent. Finally, His early impressions make him what he, later on, becomes: "The child is the father of man" (Wordsworth, My Heart Leaps Up, p. 7)

Elements of nature also recur throughout the poet's life and do so in ways that add to his experience, teach him more about life, and connect him with the spiritual. He talks of the river that "loved/ To blend his murmurs with my nurse's song" (I.270-271), for instance, and the voice of the river remains with the poet and is found ever after in his dreams. The sounds of nature are described as music, and it is always a music that brings calm and peace. The poet's appreciation of nature and its effects is evident, and he personifies nature and speaks to it directly to express his feelings:

> And on the earth! Ye visions of the hills!
> And Souls of lonely places! (I.464-466).

The importance of nature in the development of the poet is apparent in the way he begins linking himself to nature in his memory of his childhood and his days in school, and what he learns in a human classroom is rivaled by what he learns in the larger classroom of nature. Children seem to have a natural affinity for nature. They prolong their games to remain outside as daylight fails. They only go hoe to bed when all is dark and the stars come out in the sky (II.8-18).

Wordsworth traces the growth of his love of nature and the various stages through which it passed. It may be noted here that Wordsworth spiritualized nature by making her a moral teacher. As a poet this is his most important contribution and herein lies his chief originality that is wonderfully revealed in his poetry of nature. Compton-Rickett has rightly said: It was Wordsworth's aim as a poet to seek for beauty in meadows, woodland and mountains, and to interpret this beauty in spiritual terms. He is ever spiritualizing the moods of Nature and winning from them moral consolation. But this spiritual conception developed through various stages.

In the first stage, his passion for Nature was in its infancy and was kept enthused and nourished by his surroundings without any conscious or deliberate effort on his part—By nourishment that came unsought'.

The poet speaks about his second stage in the beginning of the second hook. In the previous stage he was almost totally interested in the exciting sports and pastimes and was not so much conscious of his natural surroundings; but now he seemed to have a conscious urge to have Nature 'collaterally attached' to all their plans for all sorts of games and pleasures:

> .....But the time approached
> That, brought with it a regular desire
> For calmer pleasures, when the winning forms
> Of Nature were collaterally attached
> To every scheme of holiday delight
> And every boyish sport, less grateful else
> And languidly pursued.
> (The Prelude, Book II: 48-54)

Their boating excursions 'over the shadowy lake' and their riding adventures on 'the galloping steed' over hills and dales, 'through rough and smooth' brought the poet in closer contact with the charming and sublime aspects of nature. Slowly Wordsworth's sympathies or spiritual powers enlarged and familiar and common objects became dearer to him day by day. He then began to love the sun not for its life-giving power but because it bathed the hills in its radiant beauty at dawn and touched the western hills with its golden-fingers before it set in the west.

In the final stage, we find the poet's attachment to Nature growing into a religious, love. At this stage, he has mystic visions and has had a feeling of the existence of a visionary power, a creative sensibility within himself and has a realization of the unity and harmony underlying all the diversities of Nature. When the poet is laid asleep in body' he becomes 'a living soul' and can 'see into the life of things'.

Wordsworth, through his sense experiences has become 'creator and receiver both', has acquired that highest intellectual power—imagination. In the last book of The Prelude the poet reveals it in its various aspects as the faculty of creation, the poetic faculty par excellence. And this poetic faculty par excellence is really the hero, the leading figure, the presiding genius of The Prelude. Wordsworth was deeply conscious of the power which fostered his genius, and when he probed into its sources he found that it came to him originally through a special awareness of Nature; it was there that a shaft opened which reached down to a new world of life'. Prof. Garrod has very

nicely elucidated this point in the chapter on Sense and Imagination: 'the glory of the senses passes into a glory of the imagination precisely being fastened to the affections.......The vision of the senses melts and dissolves. But it melts into the revelation of permanent super sensual realities. In every impression of sense Wordsworth conceives that there is present from the beginning an imaginative activity. Sense and imagination are two extremes in the scale of poetic or spiritual apprehension: but the higher faculty is always obscurely present in the lower.

Conclusion: Thus in *The Prelude,* we find the poet first trying to recapture and record the full intense life which he lived through his senses as a child and youth. Wordsworth had the extraordinary power to "live intensely in the past, he could revive and recreate; and it is a chief part of his purpose in 'The Prelude' to recall and quicken into permanent life those pregnant moments. For they were, he well knew, the making of him as a poet" (Moorman, 1957, p. 22).

In conclusion, we may justly assert that Wordsworth has rightfully been called by the critics and readers alike, 'the high priest of nature', the 'harbinger of nature' or the 'worshipper of nature', as no other poet has understood. Nature as Wordsworth does. His treatment of nature is original and unique. To Wordsworth nature is not inanimate. Nature is a living and organic unity with a life and personality of its own. "There have been greater poets than Wordsworth, but none more original," says Bradley. And to Abercrombie, "his whole life belonged to nature, and nature to his poetry was what it was to Lucy, both lay and impulse."

References:-

1. Cazamian, L. (1927). A history of English literature: Modern times (1660-1914). Trans. By W. D. MacInnes & Helen Douglas- Irvine. NY: Macmillan.
2. Darbishire, H. (1950). The poet Wordsworth. Oxford: Clarendon Press.
3. De Quincey, T. (1970). Recollections of the lakes and the lake poets (David Wright ed.). New York: Penguin Books.
4. Garrod, W. H. (1923). Wordsworth: Lectures and essays. Oxford: Oxford University Press.
5. Herford, C. H. (2004). The age of Wordsworth. Whitefish, Montana: Kissinger Publishing, LLC.
6. Ker, W. P. (1903). William Wordsworth. In Robert Chambers (Ed.), Cyclopedia of English Literature (2nd ed., Vol. 3). London: Chambers.
7. Lee, C. J. (2015). Between speech and silence in Wordsworth's The Prelude—transformation of self in text. EURAMERICA, 44(2), 193-238. Academia Sinica. Retrieved from http://euramerica.org Between Retrieved from http://go.galegroup.com/ps/i.do.
8. Legouis, E. (1965). The early life of William Wordsworth. 1770-1798. A study of The Prelude. Trans. by J.W. Mathews with a prefatory note by Leslie Stephen. New York, NY: Russel & Russel Inc.
9. Lindenberger, H. (1964). On Wordsworth's 'Prelude' (p. 316). Princeton, N. J.: Princeton University Press.
10. Miall, D. S. (Summer 1992). Wordsworth and 'The Prelude': the problematics of feeling. Studies in Romanticism, 31(2), 233-236. http://dx.doi.org/10.2307/25600953.
11. Moorman, M. (1957). William Wordsworth, a biography: The early years, 1770-1803. Oxford: Oxford University Press.
12. Pater, W. (2001). The aesthetic moment (pp. 1-226). David H. Wilson. Trans. Cambridge: Cambridge University.
13. Wordsworth, W. (1850). The Prelude; or Growth of a Poet's Mind. New York: Appleton.
14. Wordsworth, W. (1991). The thirteen-book of The Prelude. M. L. Reed (Ed.). Ithaca, NY: Cornell University Press.
15. Wordsworth, W. (1993). The letters of William and Dorothy Wordsworth. In A. G. Hill (Ed.), The New Leader: A Supplement of New Letters. Oxford: Clarendon Press.

****

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक तनाव, पर यौगिक क्रियाओं के प्रभाव का अध्ययन

डॉ. आर.पी. जैन* भारती**

प्रस्तावना - माध्यमिक स्तर की शिक्षा एक निर्णायक दौर होता है जो विद्यार्थियों के भविष्य की आधारशिला के निर्धारण के साथ-साथ जीवन की दिशा और दशा का भी निर्धारण करता है। जहां विद्यार्थी को अभिभावकों की अपेक्षाओ और अपने भविष्य की चिंता को साथ लेकर शिक्षा ग्रहण करनी होती है। ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थियों का तनावग्रस्त हो जाना स्वाभाविक है। परीक्षा शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग है। परीक्षा द्वारा न केवल विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का पता चलता है अपितु शिक्षा की गुणवत्ता एवं शिक्षक के ज्ञान व शिक्षण कौशल का आकलन भी सुगमता से हो जाता है। परंतु इसका एक पहलू यह भी है कि विद्यार्थी इसे अपने भविष्य से जोड़कर देखते हैं। अभिभावकों और शिक्षकों के अत्यधिक अनावश्यक दबाव में विद्यार्थियों में चिंता एवं तनाव का स्तर कभी-कभी इस सीमा तक बढ़ जाता है कि वह नकारात्मक सोच को बढाता वह डिपरेशन का रूप ले लेता हैं।

इसलिए पुरातन काल में योग के सिद्धान्त का सदुपयोग भरपूर होता था परन्तु इस समय बौद्धिक वर्ग योग साधना पर ना के बराबर निर्भर करता है। योग साधना अपने आप में अद्वितीय भारतीय धारणा है जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद अत्यधिक कठिन है। सामान्यतया यदि हम योग पर सावधानीपूर्वक विभिन्न प्रकार से सोच-विचार करें तो पाएँगे कि 'सभी का मूल विचार जोड़ना' है। योग सही जीवन-यापन का विज्ञान है और इसे ऐसे ही दैनिक जीवन-चर्या में समाविष्ट करना चाहिए। यह व्यक्ति के सभी पक्षों पर कार्य करता है- शारीरिक, मानसिकता, भावात्मकता, मनस्तत्व और आध्यात्मिकता। योग एक व्यक्तिगत रूप से स्वयं (जीवात्मा) का परमात्मा के साथ मिलन है।

चिन्ता या तनाव की आधुनिक संकल्पना हमें सरलता से पारम्परिक ग्रन्थों जैसे कि चरक संहिता, पतजँलि योग सूत्र और श्रीभागवद् गीता आदि में तथा भारतीय संस्कृति और परम्परा में आसानी से नहीं मिलती है। अनेक भारतीय विद्वानों ने चिन्ता और तनाव पर उल्लेखनीय विचारों को प्रकट किया उदाहरणार्थ। दुख, क्लेश, काम और तृष्णा, आत्मा और अहंकार आदि। यह उल्लेखनीय रोचक तथ्य है कि शरीर-चित संबंध के जिन लक्षणों का वर्णन आधुनिक तनाव शोध में है उसका महत्व आयुर्वेद (भारतीय) उपचार पद्धति में भी मिलता है।

राव (1983) ने भारतीय साँख्य एवं योग पद्धति के प्राचीन काल के अध्ययन में तनाव या चिन्ता के मूल कारणों की सारगर्भित खोज की है। उन्होनें अनुमानतया संस्कृत के दो शब्द क्लेश एवं दुख को ही तनाव या चिन्ता चिन्हित किया है। शब्द क्लेश मानसिक प्रणाली के लिए नहीं अपितु मन को क्रियान्वित करने में बाधा डालता है। इससे अशान्ति उत्पन्न होती है जो रूकावट के रूप में या जटिलता से मन को क्रियान्वित होने से रोकती है। सांख्य योग पद्धति मानसिक अविकसितता को मूल कारण मानती है जो असाधारण तनाव की ओर ले जाती है, वह अविद्या ही है। यह अविद्या ही अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश की ओर अग्रसर करती है।

पालसेन प्राचीन भारतीय चिंतन के अनुसार, कुंठा-आक्रामक तनाव की धारणा सबसे पहले जीव **वैज्ञानिक शल्य (1936)** द्वारा प्रस्तुत की गई। यह अवधारणा प्राकृतिक विज्ञान से अपनाई गई है। यह लतीनी भाषा के शब्द 'स्ट्रिंगेयर' से निकला है। सत्रहवीं शताब्दी में इसका अर्थ तंगहाली (जीवन की मूलभूत सुविधाओं की अपर्याप्तता)-दबाव-समस्याएँ या तनाव के रूप में प्रचलित था। अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में इसे बल-घोतक-कठिनाईयाँ या किसी पदार्थ या व्यक्ति के संदर्भ में जोड़ा जाने लगा। जिस भौतिकता के क्षेत्र से इस धारणा का प्रचलन, उपजा था वह क्षीण होने लगा लेकिन चिन्ता एवं तनाव की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग मनोविज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान शास्त्रों में जोर-शोर से फलता-फूलता रहा है। आधुनिक विश्व, जो कि उपलब्धियों का संसार कहलाता है, मानसिक अशान्ति एवं तनाव से भरपूर हैं। चहुँ ओर अशान्ति एवं तनाव व्याप्त हैं चाहे व्यापार हो, व्यापारिक संस्थान हो,उद्योग हो या दूसरी सामाजिक या आर्थिक गतिविधियाँ। ठीक जन्म से लेकर अंतिम साँस तक व्यक्ति को अनेक व्याधिपूर्ण परिस्थितियों से दो-चार होना पड़ता है। अतएव, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं जो वर्तमान शताब्दी में इस विषय पर रूचि समय के बढ़ने के साथ बढ़ती जा रही है। इसीलिए इस को 'अनिश्चय अशान्ति एवं तनाव' का युग कहा जाता है। तनाव एक चर्चा का विषय है। इससे बचना अत्यन्त कठिन है। यह शब्द न केवल हमारी दैनिक दिनचर्या में चर्चा का विषय है अपितु जनसाधारण में भी इस विषय की पूरी रूचि फैल रही है। चाहे कोई भी जनसंचार माध्यम हो जैसे आकाशवाणी-दूरदर्शन- समाचार पत्र या पत्रिकाएँ, सब मानसिक तनाव विषय पर बल दे रहें हैं। विभिन्न व्यक्तियों के भिन्न-भिन्न विचार है जो उन्होंने अपने अनुभवों से तनाव विषय के बारे में प्राप्त किए हैं। आप पाँच अलग-अलग व्यक्तियों से तनाव या चिन्ता पर प्रश्न पूछिए तो आप पाएगें कि पाँचों की परिभाषाएँ भिन्न हैं। तनाव व्यापारी के लिए खीझ या भावनात्मक दबाव हैं, हवाई यातायात नियंत्रक के लिए वैकल्पिकता के केन्द्रीकरण की समस्या है, जीव रसायनविद् के दृष्टिकोण से यह साफ रसायन-विषयक घटना है।

तनाव तथा दैहिक तनाव के बढ़ने की दशा में ही साधरणतया मनोवैज्ञानिक तनाव है।

*प्रोफेसर, बाबू कामता प्रसाद जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बडौत (बागपत) (उ.प्र.) भारत
** शोधार्थिनी, बाबू कामता प्रसाद जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बडौत (बागपत) (उ.प्र.) भारत

लेजारस (1984) के अनुसार, तनाव व्यक्ति और वातावरण के बीच में एक असंयोजन है जिसमें से एक व्यक्ति के साधन बढ़ने पर उन पर कर लगाया जाता है जो उसे संघर्ष के लिए विवश करते हैं ताकि जटिल तरीकों से सफलतापूर्वक निपटा जा सकें।

सन्दर्भ साहित्य की समीक्षा- बालकों के विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों को ज्ञात करने के लिए बहुत से अध्ययन किये गये हैं। इनमें से एक प्रमुख वातावरणीय कारण योग है, यद्यपि योग बालक के सम्पूर्ण विकास को प्रभावित करता है, तथापि अधिकांश लोगों का मानना है कि योग, बच्चों के शैक्षिक एवं सामाजिक तनाव को कम करने तथा भावात्मक परिपक्वता को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनेक शिक्षाविदों व मनोवैज्ञानिको द्धारा बालक के शैक्षिक विकास में योग की भूमिका का भी समर्थन किया है। परिस्थिति एवं घटनाक्रम के व्यक्तिगत अनुभवों एवं ज्ञान के अधार पर इस अनुसंधानकर्त्ता को भी विश्वास हो गया है कि बच्चों के शैक्षिक विकास में योग की प्रभावशाली सहभागिता है।

विरक (1971) ने शरीर की लोचशीलता पर योगासनों का प्रभाव देखने के लिए अध्ययन किया। उसने निष्कर्ष निकाला कि कुछ योगासन रीढ़ की हड्डी को आगे तथा पीछे की ओर झुकाते हैं जिससे शरीर में लचकता बढ़ती है। **प्रताप (1972)** ने इस तथ्य पर अधिक बल दिया कि योगाभ्यास, श्वास क्रिया तथा मानसिक स्थिति में अटूट सम्बन्ध पाया जाता है। **कोछर (1976)** ने 14.18 वर्ष के किशोर बालकों की मानसिक थकावट पर योगाभ्यास के प्रभाव का अध्ययन किया। सिंह राजेन्द्र **(1987)** ने अपने शोध में बताया कि व्यक्ति की श्वास-प्रश्वास एकाग्रता और ध्यान एक दूसरे से सम्बन्ध रखते हैं। डॉ. बेन्सन **(1987)** ने ध्यान के प्रभावों का अध्ययन किया और निष्कर्ष दिया कि नियमित 20 मिनट का ध्यान पूरे दिन तरोताजा हल्का-फुल्का बनाये रखने के लिए पर्याप्त है।वैष्णव, जी0 के0 ;**(1988)** ने अपने शोध कार्य के पश्चात बतायाकि योग शिक्षक शारीरिक शिक्षा के प्रति उच्च अनुकूल अभिवृत्ति रखते हैं- क्योंकि यह शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देती है। बेरान **(1992)** के अनुसार 'तनाव एक ऐसी बहुआयामी प्रक्रिया है जो लोगों में वैसे घटनाओं के प्रति अनुक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है जो हमारे दैहिक एवं मनोवैज्ञानिक कार्यो को विघटित करती है' तनाव आधुनिक दौर के परिप्रेक्ष्य में एक सामान्य बातचीत का हिस्सा नहीं है अपितु एक सार्वजनिक मुद्दा बन गया है। श्री वास्तव एस0 के0 **(2000)** ने अपने शोध निष्कर्षो में बतायाकि योगाभ्यासी छात्र-छात्राओं में अतिस्नेही, नैतिकवादी, उच्च सामाजिकता, आज्ञाकारी शालीनता एवं ओजस्वी शीलगुण गैर योगाभ्यासी छात्र-छात्राओं से अधिक होते हैं। दुबे, शैलेन्द्र **(2000)** ने अपने शोध निष्कर्षो में बताया कि योग शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों में लगन शीलता, मानवता, नैतिक मूल्य एवं आर्थिक शक्ति, व्यक्तिगत मूल्य योग शिक्षा ग्रहण न करने वालों की अपेक्षा अधिक है। भटनी देवी व मीतू **(2003)** के अनुसार यौगिक क्रियाओं के अभ्यास से चिंता का स्तर कम होता है और समायोजन क्षमता बढ़ती है। योग न केवल मानव मात्र के कल्याण की एक विधा है, अपितु संपूर्ण जीवन शैली को संयमित और संतुलित कर मानव जाति के उत्थान का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। रानी एवं राव **(2005)** के अनुसार योगाभ्यास के परिणाम स्वरूप हताशा व तनाव में एक विशिष्ट कमी आती है। मुछाल **(2008)** ने माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की योग अभिवृत्ति के अध्ययन में पाया कि अधिकांश विद्यार्थी जो योग के प्रति उच्च अभिवृत्ति रखते हैं, इस आधार पर कह सकते हैं कि किसी कार्य के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उस कार्य के प्रति सकारात्मक रुचि को प्रदर्शित करती है। अन्य उद्देश्य में योग अभिवृत्ति को विकसित होने के कारणों में 62% विद्यार्थियों को दूदर्शन व केबल कार्यक्रम को आधार बताया। 35% विद्यार्थियों ने समाचार पत्र से जानकारी, 30% ने योग शिविर तथा 24% विद्यार्थियों ने अपने माता-पिता के द्धारा योग सीखा। स्वास्थ्य एवं योग सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने में उपरोक्त चारों कारकों ने अपना मत व्यक्त किया है। मनानी, प्रीति तथा गौतम, कुमार **(2011)** द्धारा किए गए शोध अध्ययन के परिणामों से स्पष्ट है कि परीक्षा तनाव विद्यार्थियों को निराशा से भर देता है तथा उनके मस्तिष्क में आत्महत्या जैसे विचारों को भी जन्म दे देता है। यह तनाव उनके परीक्षा परिणामों पर भी बुरा प्रभाव डालता है। सिंह, जोगिंदर **(2012)** ने अपने लेख 'नो टेंशन' में लिखा कि हम यही सोचकर तनावग्रस्त रहते हैं कि हम सफल होंगे या नहीं। इससे हमारी सफलता संदेहात्मक हो जाती है और तनाव भी बढ़ता है। डब्लू0एच0ओ0 **(2016)** की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लगभग 8 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा तनाव के कारण आत्महत्या के मामले सामने आये। भारत में यही संख्या लगभग 2500 चिंहित की गई।

अध्ययन का औचित्य

संदर्भ साहित्य की समीक्षा करने से ज्ञात होता है कि विरक 1971 ने शरीर लोच शीलता प्रताप। (1972) योगासन व प्राणायाम मे सम्बन्ध। कोछर (1976) ने मानसिक थकावट परयोग का प्रभाव। सिंह राजेन्द्र (1987) ने श्वास-प्रश्वास एवं ध्यान। बेसन (1987) ने ध्यान के प्रभाव। वैष्णव जी. के. (1988) ने योग अभिवृत्ति। बेरान (1992) ने तनाव। श्री वास्तव एस. के. (2000) योगाभ्यासी छात्र- छात्राओं के गुण। दुबे शैलेन्द्र (2000) मे योगाभ्यासी के नैतिक मूल्यो। भटनी देवी एवं मीत (2003) योगाभ्यासी के समायोजन। रानी एवं राव (2005) ने तनाव। मुछाल (2008) में योग अभिवृत्ति। मनानी एवं गतिम 2012 ने परीक्षा तनाव। सिह जोगिन्दर (2012) में तनाव। डब्लू. एच. ओ. (2016) ने परीक्षा तनाव पर अध्ययन लेकिन माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक शैक्षिक तनाव, पर यौगिक क्रियाओं के प्रभाव का अध्ययन नही हुआ इसलिए शोधकर्त्ती ने योग की महत्वपूर्णता को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक शैक्षिक तनाव, पर यौगिक क्रियाओं के प्रभाव का अध्ययन करने का विनम्र प्रयास किया है।

अध्ययन का शीर्षक - 'माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक तनाव, पर यौगिक क्रियाओं के प्रभाव का अध्ययन'

1. **उद्देश्य -** माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के शैक्षिक तनाव का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के शैक्षिक तनाव की तुलना करना।

परिकल्पनाएं ;पूर्व परीक्षण के आधार पर माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के मध्य शैक्षिक तनाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

1. पश्च परीक्षण के आधार पर माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के मध्य शैक्षिक तनाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी लड़कों के मध्य शैक्षिक तनाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. माध्यमिक स्तर की योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी लड़कियों के मध्य शैक्षिक तनाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

4. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी लड़कों एवं योगाभ्यासी लड़कियों के मध्य शैक्षिक तनाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
5. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी लड़कों एवं गैर–योगाभ्यासी लड़कियों के मध्य शैक्षिक तनाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
6. माध्यमिक स्तर की योगाभ्यासी लड़कियों एवं गैर–योगाभ्यासी लड़कों के मध्य शैक्षिक तनाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
7. माध्यमिक स्तर के गैर–योगाभ्यासी लड़कों एवं गैर–योगाभ्यासी लड़कियों के मध्य शैक्षिक तनाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सीमांकन – यह अध्ययन केवल बागपत जनपद के माध्यमिक विद्यालयों के 100 विद्यार्थियों के शैक्षिक तनाव चर के अध्ययन तक ही सीमित है।

जनसंख्या एवं प्रतिदर्श – प्रस्तुत अध्ययन की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में पंजीकृत सभी विद्यार्थी है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रतिदर्श हेतु बागपत जनपद के कक्षा 10 के 100 विद्यार्थियों को शामिल किया गया। जिनका चयन यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया है।

प्रयुक्त उपकरण–किसी भी शोध अध्ययन में, आँकड़ों को एकत्र करने के लिए उचित उपकरणों का चुनाव करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित शोध उपकरण प्रयोग किये गये है :–

1. विद्यार्थियों के शैक्षिक तनाव को मापने के लिए आभारानी बिष्ट (1987) द्वारा निर्मित प्रमाणिक शैक्षिक तनाव मापनी का प्रयोग किया गया है।

आभा रानी बिष्ट बैटरी के तनाव पैमाने से शैक्षिक तनाव पैमाना – यह पैमाना 1987 में आभा रानी बिष्ट के द्वारा विकसित और मानकीकृत किया गया है। BBSS तेरह प्रकार के दबावों को मापनें के लिए विकसित किया गया है। 13 पैमानों में से 'शैक्षिक तनाव का पैमाना' चुना गया। इस पैमाने में मानकीकरण के लिए 80 मदें सम्मिलित थी। बैटरी के सभी पैमानों को माननीकृत करने के उददेश्य के लिए छः दृष्टिकोण अपनायें गए, जो निम्न है।

1. कार्यप्रणाली विषयक दृष्टिकोण
2. सैद्धान्तिक दृष्टिकोण
3. आनुपातिक दृष्टिकोण
4. तार्किक दृष्टिकोण
5. प्रयोग और अनुभव आधारित दृष्टिकोण
6. नारमेटिव दृष्टिकोण।

तनाव पैमाने के यंत्र को विकसित करने के लिए, विचार आरेखन (आइडियोग्राफिक) विधि ली गई है। क्योंकि यह व्यक्तिनिष्ठ भावनाओं, कष्ट एवं व्याख्यात्मक रूप से सरल प्रतिक्रियाओं के द्वारा तनाव को मापने का विस्तृत रूप से प्रयोग होने वाला तरीका है। तनाव को विचारात्मक बनाया गया जिसमें निम्नलिखित घटक है–

(1) हताशा,
(2) झगड़ा
(3) दबाव
(4) उत्कंठा

फलांकन– गणना के लिए, पाँच–बिन्दू का पैमाना चुना गया क्योंकि इसके द्वारा औसत श्रेणी को भी शामिल किया जाता है। दो नमूने लिए गए, जिसमें पहला आवृत्ति के रूप में था जैसे कि हमेशा ;(A) अक्सर (O) कई बार (S) दुर्लभता (R) और कभी नहीं (N) और दूसरा तरीका परिणाम के रूप में था जैसे कि बहुत अधिक (VM), अधिक (M), ठीक–ठीक ;(SS) कम (L) और बिल्कुल नहीं (N)।

तालिका : शैक्षिक तनाव पैमाने की गणना की मदों को दर्शाती तालिका

मदों की संख्या	A VM	O M	S SS	R L	NA NA
1,2,3,4,5,8,9,11,13,17,18,20, 22,24,25,26,27, 28,30,31,32, 34,35, 36,37,38,40,41,43, 44, 45,46,48, 50,52,53,54,55,56, 57,58,59,60, 61,62,64,65,68, 70,72,73,76,77,79,80	4	3	2	1	0
6,7,10,12,14,15,16,19,21,23, 29, 33,39,42, 47,49,51,63,66, 67,69,71,74,75,78	0	1	2	3	4

विश्वसनीयता – पैमाने की विश्वसनीयता जानने के लिए तीन विधियों से गणना की गई।

1. निर्भरता अर्थात अल्प अवधि परीक्षण–पुन: परीक्षण सहसंबंध।
2. स्थिरता अर्थात एक लंबे अंतराल के बाद पुन:परीक्षण।
3. आंतरिक दृढता अर्थात अर्द्ध विभक्त सहसंबंध।

शैक्षिक तनाव के लिए निर्भरता, स्थिरता और आंतरिक दृढता गुणांक क्रमश: 0.87, 0.82 एवं 0.88 थे तथा निराशा, झगड़ा, दबाव और उत्कंठा के लिए आंतरिक दृढता गुणांक (कुल और अवयव आँकड़ों के बीच संहसंबंध) क्रमश: 0.37, 0.52, 0.39 और 0.58 थे। सभी सहसंबंध विश्वसनीयता के 0.05 स्तर पर सार्थक थे।

वैधता – सभी पैमाने अंतनिर्हित विषय वस्तु की मात्रा की वैधता और वस्तु की वैधता पर जाचें गये। वस्तुओं के चुनाव की विधि ने इस मान्यता को सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त संरचना वैधता (अविवेकशीलता) का अनुमान **टू फोल्ड फैंक्शन** के द्वारा लगाया गया। पहले प्रकार के निरीक्षण में विभिन्न विद्यार्थियों से संबंधित संरचना मापी गई। द्वितीय निरीक्षण किया जो सिद्धांत के द्वारा अनुमानित संरचना पैमाने के द्वारा मापित संरचना से संबंधित नहीं थी। इसके लिए आंतरिक मूल्यांकन किया गया। दोनों परीक्षण में संरचना की वैधता दृढ़ थी।

प्रदत्त एकत्रीकरण की प्रक्रिया – प्रस्तुत परीक्षण को अधिकतम 100 विद्यार्थियों पर एक साथ प्रशासित किया गया। विद्यार्थियों को पृथक करके बैठाया गया ताकि विद्यार्थी एक दूसरे के साथ अथवा आपस में उत्तारों की नकल ना कर सकें। विद्यार्थियों को परीक्षण पत्र वितरित करने के पश्चात उस पर दिये गये निर्देशो को पढ़ कर सुनाया गया तथा परीक्षण पत्र पर दिये गये उदाहरणों को विद्यार्थियों को समझाया गया।

तालिका– 1: माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर–योगाभ्यासी लड़कों के शैक्षिक तनाव के मध्यमान, प्रमाणिक विचलन तथा 't' मान को प्रदर्शित करती तालिका

समूह	N	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	't' का मान
योगाभ्यासी लड़के	25	129.12	11.89	2.787✻
गैर–योगाभ्यासी लड़कें	25	139.24	13.72	

✻0.01 स्तर पर सार्थक

उपरोक्त तालिका **क्रमांक 1** दर्शाती है कि माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी लड़कों के शैक्षिक तनाव के अंकों का मध्यमान क्रमशः **129.12** एवं **139.24**, प्रमाणिक विचलन क्रमशः **11.89**एवं 13.72 तथा परिगणित t परीक्षण का मान **2.787** है, जो मुक्तांश 48 के लिए 0.01 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 2.68 से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना H3 '**माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी लड़कों के मध्य शैक्षिक तनाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है**' को अस्वीकृत किया जाता है। माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी लडको की तुलना में गैर-योगाभ्यासी लड़के ज्यादा शैक्षिक तनाव रखते है। क्योंकि योगाभ्यास के द्वारा मन स्थिर होता है एवं मानसिक चिन्ताओं से मुक्ति मिलती है। अतः योग विद्यार्थियों के शैक्षिक तनाव को कम करता है।

तालिका- 2: माध्यमिक स्तर की योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी लड़कियों के शैक्षिक तनाव के मध्यमान, प्रमाणिक विचलन तथा 't' मान को प्रदर्शित करती तालिका

समूह	N	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	't' का मान
योगाभ्यासी लड़कियां	25	121.23	13.04	4.81*
गैर-योगाभ्यासी लड़कियां	25	138.71	12.59	

*0.01 स्तर पर सार्थक

उपरोक्त तालिका **क्रमांक 2** दर्शाती है कि माध्यमिक स्तर की योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी लड़कियों के शैक्षिक तनाव के अंकों का मध्यमान क्रमशः 121.23 एवं 138.71, प्रमाणिक विचलन क्रमशः 13.04 एवं 12.59 तथा परिगणित t परीक्षण का मान **4.81** है, जो मुक्तांश 48 के लिए 0.01 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 2.68 से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना H4 '**माध्यमिक स्तर की योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी लड़कियों के मध्य शैक्षिक तनाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है**' को अस्वीकृत किया जाता है। क्योंकि योगाभ्यास के द्वारा मन स्थिर होता है एवं मानसिक चिन्ताओं से मुक्ति मिलती है जिससे विद्यार्थी एकाग्रचित्त हो कर अपने अध्ययन को रूचिपूर्ण तरीके से करते है जिससे तनाव कम हो कर शिक्षा में उनकी रूचि बढ़ती है। अतः माध्यमिक स्तर की योगाभ्यासी लडकियों की तुलना में गैर-योगाभ्यासी लड़कियां ज्यादा शैक्षिक तनाव रखती है।

तालिका- 3: माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी लड़कों एवं योगाभ्यासी लड़कियों के शैक्षिक तनाव के मध्यमान, प्रमाणिक विचलन तथा 't' मान को प्रदर्शित करती तालिका

समूह	N	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	't' का मान
योगाभ्यासी लड़के	25	129.12	11.89	2.235**
योगाभ्यासी लड़कियां	25	121.23	13.04	

**0.05 स्तर पर सार्थक

उपरोक्त तालिका **क्रमांक 4** दर्शाती है कि माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी लड़कों एवं योगाभ्यासी लड़कियों के शैक्षिक तनाव के अंकों का मध्यमान क्रमशः 129.12 एवं 121.23, प्रमाणिक विचलन क्रमशः 11.89 एवं 13.04 तथा परिगणित t परीक्षण का मान **2.235** है, जो मुक्तांश 48 के लिए 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 2.01 से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना H4 '**माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी लड़कों एवं योगाभ्यासी लड़कियों के मध्य शैक्षिक तनाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं है** को अस्वीकृत किया जाता है। माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी लडकियों की तुलना में योगाभ्यासी लड़कें ज्यादा शैक्षिक तनाव रखते है।

तालिका- 4: माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी लड़कों एवं गैर-योगाभ्यासी लड़कियों के शैक्षिक तनाव के मध्यमान, प्रमाणिक विचलन तथा 't' मान को प्रदर्शित करती तालिका

समूह	N	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	't' का मान
योगाभ्यासी लड़कें	25	129.12	11.89	2.768**
गैर-योगाभ्यासी लड़कियां	25	138.71	12.59	

**0.05 स्तर पर सार्थक

उपरोक्त तालिका **क्रमांक 4** दर्शाती है कि माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी लड़कों एवं गैर-योगाभ्यासी लड़कियों के शैक्षिक तनाव के अंकों का मध्यमान क्रमशः 129.12 एवं 138.71, प्रमाणिक विचलन क्रमशः 11.89 एवं 12.59 तथा परिगणित t परीक्षण का मान **2.768** है, जो मुक्तांश 48 के लिए 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 2.01 से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना H6 '**माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी लड़कों एवं गैर-योगाभ्यासी लड़कियों के मध्य शैक्षिक तनाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं है**' को अस्वीकृत किया जाता है और इस आधार पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी लडकों की तुलना में गैर-योगाभ्यासी लड़कियां ज्यादा शैक्षिक तनाव रखती है।

तालिका- 5: माध्यमिक स्तर की योगाभ्यासी लड़कियों एवं गैर-योगाभ्यासी लड़कों के शैक्षिक तनाव के मध्यमान, प्रमाणिक विचलन तथा 't' मान को प्रदर्शित करती तालिका

समूह	N	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	't' का मान
योगाभ्यासी लड़कियां	25	121.23	13.04	4.757*
गैर-योगाभ्यासी लड़कें	25	139.24	13.72	

*0.01 स्तर पर सार्थक

उपरोक्त तालिका **क्रमांक 5** दर्शाती है कि माध्यमिक स्तर की योगाभ्यासी लड़कियों एवं गैर-योगाभ्यासी लड़कों के शैक्षिक तनाव के अंकों का मध्यमान क्रमशः 121.23 एवं 139.20, प्रमाणिक विचलन क्रमशः 13.04 एवं 13.72 तथा परिगणित t परीक्षण का मान **4.757** है, जो मुक्तांश 48 के लिए 0.01 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 2.68 से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना H7 '**माध्यमिक स्तर के गैर-योगाभ्यासी लड़कों एवं योगाभ्यासी लड़कियों के मध्य शैक्षिक तनाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं है**' को अस्वीकृत किया जाता है। माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी लडकियों की तुलना में गैर-योगाभ्यासी लड़कें ज्यादा शैक्षिक तनाव रखते है।

तालिका- 6: माध्यमिक स्तर के गैर-योगाभ्यासी लड़कों एवं गैर-योगाभ्यासी लड़कियो के शैक्षिक तनाव के मध्यमान, प्रमाणिक विचलन तथा 't' मान को प्रदर्शित करती तालिका

समूह	N	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	't' का मान
गैर-योगाभ्यासी लड़कें	25	139.24	13.72	0.142***
गैर-योगाभ्यासी लड़कियां	25	138.71	12.59	

***असार्थक

तालिका **क्रमांक 6** दर्शाती है कि माध्यमिक स्तर के गैर-योगाभ्यासी लड़कों एवं गैर-योगाभ्यासी लड़कियो के शैक्षिक तनाव के अंकों का मध्यमान क्रमशः **139.24**एवं **138.71**, प्रमाणिक विचलन क्रमशः **13.72**एवं **12.59** तथा परिगणित t परीक्षण का मान **0.142** है, जो मुक्तांश 48 के लिए 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 2.01 से कम है। अतः शून्य परिकल्पना H8 '**माध्यमिक स्तर के गैर-योगाभ्यासी लड़कों एवं गैर-योगाभ्यासी लड़कियों के मध्य शैक्षिक तनाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं है**' को स्वीकृत किया जाता है। गैर-योगाभ्यासी लड़कें एवं लड़कियां दानो ही नियंत्रित समूह से है जिन्हे कोई भी योगोपचार नही दिया गया। अतः माध्यमिक स्तर के गैर-योगाभ्यासी लड़कों एवं गैर-योगाभ्यासी लड़कियो के शैक्षिक तनाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

मुख्य निष्कर्ष :- माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के शैक्षिक तनाव का अध्ययन तथा तुलना करने के पश्चात पाया गया कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के शैक्षिक तनाव पर योगाभ्यास का सार्थक प्रभाव पडता है। **अमित एवं अन्य (2009)** के अध्ययन के अनुसार जो विद्यार्थी योग करते है उनका शैक्षिक प्रदर्शन अच्छा था तथा जिन विद्यार्थियों ने योग का अभ्यास नही किया उनका शैक्षिक प्रदर्शन अच्छा नही था तथा तनाव ने उनके शैक्षिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है। प्रस्तुत शोध के आधार पर भी यही निष्कर्ष निकलता है कि योगाभ्यासी विद्यार्थी गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों की अपेक्षा कम शैक्षिक तनाव रखते है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. Banerjee, S. (2011). Effect of various counselling strategies on academic stress of secondary Level students. Unpublished Ph.D. Thesis, Punjab University, Chandigarh.
2. Batni devi and Meetu (2003) Effectiveness of selected yogic ezercise on anziey and adjustment of eleventh grades. Recent Research in Education and psychology, vol 8 (1) 85-88.
3. बेरॉन (1992) सन्दर्भित सामान्य मनोविज्ञान, अरूण कुमार सिंह (2010)दिल्ली मोतीलात बनारसी दास, पृ0 संख्या 754-756।
4. Bisht, A.R. (1980). A study of stress in relation to school climate and academic achievement (age group 13-17). Unpublished doctoral thesis, Education, kumaon university.
5. गुप्ता एवं गुप्ता, (2008), शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
6. J. V. Rama Chandra Rao (2015). Academic Stress among Adolescent Students, Conflux Journal ofEducation, ISSN 2320-9305 E-ISSN 2347-5706 vol 2(9). http://cjoe.naspublishers.com/
7. Krishan, L. (2014). Academic Stress among Adolescent In Relation To Intelligence and Demographic Factors, American International Journal of Research In Humanities, Arts And Social Sciences, ISSN (print): 2328-3734, ISSN (online): 2328-3696, ISSN (cd-rom): 2328-3688 pp123-129.
8. Kochar, H.C. (1976). Influence of Yogic Practices on mental Fatigue. *Yoga Mimansa*, Vol.28 (2), 3.
9. Lazarus, R.S. (1984) Puzzles in the study of daily hassles. *Journal of Behavioural Medicine*, Vol. 7, 375-389.
10. मुछाल, एम0 के0 (2004) योग के वैज्ञानिक पहलू, योजना, वोल्यूम 52 न0 2।
11. मुछाल, एम0 के0 (2005) मानसिक अवसाद एवं योग, योजना, वोल्यूम 49 न0 2।
12. मुछाल, एम0 के0 (2006) तनाव मुक्ति में योग, योजना, वोल्यूम, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली वर्ष, 51 न0 1।
13. मुछाल, एम0 के0 (2009) प्राणायाम: रोगोपचार की सामर्थ्यदायी प्रक्रिया, योजना प्रकाशन, विभाग नई दिल्ली, वोल्यूम 52 न0 2।
14. मनानी, प्रीति एवं गौतम, मुकेश कुमार (2011) एग्जामिनेशन एन्जाइटी एज ए डिटरमेन्ट ऑफ डिप्रेशन एण्ड सुसाइडल आइडिएशन एट हायर सकेण्डरी लेवल फोर्थ एनुअल इशु डी0 ई0 आई0 फोएरा पृ0 149-150।
15. Rani, J.N. and Rao, K.V.P. (2005) Impact of yoga training on body image and depression Andhra Unversity, Vishkhapatnam Psychological Studies, Vol 50(1)98-100.
16. राय, पी. एन., (2007). अनुसंधान परिचय, आगरा, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा प्रकाशन, आगरा।
17. सिंह, ए.के. (2009). मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन, दिल्ली।
18. सिंह, जोगेन्दर (2012) नो टेशन, अमर उजाला(उडान), आगरा संस्करण 08 फरवरी पृ0 1।
19. शर्मा श्रीराम 'व्यक्तित्व विकास हेतु उच्च स्तरीय साधनाएँ', अखंड ज्योति संस्थान मथुरा संस्करण द्वितीय वर्ष 1998
20. VIRK, J.S. (1971) EFFECT OF YOGIC ASANAS ON TRUNK FLEXIBILITY. *Unpublished M.A. dissertation*, Physical Education, Panjab University, Chandigarh

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, भारत में महिलाओं की स्थिति का समाजशास्त्र

डॉ. आराधना सक्सेना*

शोध सारांश – भारतीय समाज में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। प्राचीन भारतीय महिलाओं का सामाजिक स्तर उच्च था और वे उत्कृष्ट स्वास्थ्य में थीं। समानता, शिक्षा, विवाह और पारिवारिक जीवन, जाति और लिंग, धर्म और संस्कृति के संदर्भ में, समकालीन भारतीय समाज में महिलाएं अपनी प्राचीन और मध्यकालीन स्थिति को संरक्षित या कम करती हैं। वैदिक महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त थी। कुछ महिलाएं शिक्षक के रूप में काम कर रही थीं। उत्पादन का स्थान घर था। घर में कताई और बुनाई करके कपड़े बनाए जाते थे। महिलाएं अपने पति के कृषि कार्यों में भी सहयोग करती हैं। धार्मिक क्षेत्र में, महिला को पूर्ण अधिकार प्राप्त थे और वह अक्सर अपने पति के साथ अनुष्ठानों में भाग लेती थी। पति और पत्नी दोनों ने धार्मिक अनुष्ठानों और बलिदानों में भाग लिया। यहां तक कि धार्मिक चर्चाओं में भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई। पूरे बौद्ध काल में महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, लेकिन ज्यादा नहीं। प्राचीन भारतीय साहित्य में नारी का महत्वपूर्ण स्थान है।
शब्द कुंजी – प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, समाजशास्त्र, महिलाएं।

प्रस्तावना – भारतीय सामाजिक संरचना में महिलाओं ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निश्चित रूप से, ऋग्वैदिक भारत में, महिलाओं का एक उच्च सामाजिक पद और एक उत्कृष्ट जीवन स्तर था। यहां तक कि महिलाओं को भी बौद्धिक और आध्यात्मिक उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंचने का मौका दिया गया। हालाँकि, ऋग्वैदिक समाज में अप्रतिबंधित और प्रतिष्ठित भूमिकाओं का आनंद लेने के बाद, महिलाओं को शिक्षा और अन्य अधिकारों और सुविधाओं के मामले में बाद के वैदिक युग के दौरान भेदभाव का सामना करना पड़ा। भारतीय संस्कृति यह नहीं मानती है कि अब हम महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण क्रांति देख रहे हैं। विधायिका, अदालतों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की आवाज अधिक प्रमुख होती जा रही है। भारतीय संविधान ने हमेशा महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किया है, पश्चिम के विपरीत, जहां महिलाओं को अपने कुछ मौलिक अधिकारों जैसे वोट देने की क्षमता प्राप्त करने के लिए एक सदी से अधिक समय तक संघर्ष करना पड़ा था। समानता, शिक्षा, विवाह और पारिवारिक जीवन, जाति और लिंग, धर्म और संस्कृति के संदर्भ में, समकालीन भारतीय समाज में महिलाएं अपनी प्राचीन और मध्यकालीन स्थिति को संरक्षित या कम करती हैं। इस निबंध का उद्देश्य उन मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अंतर्दृष्टि प्रदान करना है, जिनका महिलाओं ने समय–समय पर सामना किया है और उनकी भूमिका क्या है। निबंध हमें यह कल्पना करने में सक्षम करेगा कि प्राचीन काल में महिलाओं ने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और घरेलू क्षेत्रों में कैसे भाग लिया था।

प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति – सामाजिक अंतर प्रत्येक मानव संस्कृति की एक निरंतर विशेषता है। एक लिंग के आधार पर भेद है। कमाई के लिए पुरुष जिम्मेदार थे, जबकि महिलाएं बच्चों की परवरिश और घर की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार थीं। प्रारंभिक भारतीय सभ्यता में महिलाओं की स्थिति के ऐतिहासिक विश्लेषण से उनकी स्थिति में गिरावट की प्रवृत्ति का पता चलता है। समाज में उनके स्थान की ऐतिहासिक परीक्षा के अनुसार, प्राचीन भारत में महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा प्राप्त नहीं था। केवल पति–पत्नी और माताओं को ही महिलाओं के रूप में स्वीकार किया गया था। उन्हें पुरुषों के समान ही अधीनता का दर्जा प्राप्त था। भारत में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर शासन करने वाली पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने कभी भी रसोई के बाहर किसी भी पेशे में महिलाओं का समर्थन नहीं किया है! प्राचीन काल से ही भारतीय महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में कम रही है और आमतौर पर वे कम शक्तिशाली होती हैं। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की जड़ें 19 वीं सदी के सुधार आंदोलनों में हैं। समाज सुधारकों का मानना था कि महिलाओं को शिक्षित करने और प्रगतिशील कानून पारित करने से सामाजिक बदलाव की शुरुआत हो सकती है। जागरूकता बढ़ाने और लैंगिक असमानता के प्रति संवेदनशीलता पैदा करने से सामाजिक बुराइयों को कम करने में मदद मिल सकती है।

प्राचीन भारत में महिलाएं – ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में देवी मां की पूजा की जाती थी। इससे स्पष्ट होता है कि उस काल में माता का आदर किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेदिक युग में महिलाओं की स्थिति को सम्मानित और मान्यता दी गई थी, खासकर जब धार्मिक गतिविधियों को करने की बात आती थी।

युवा लड़कियों की शिक्षा को विवाह के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में देखा गया। वैदिक साहित्य के संदर्भों के अनुसार, क्षत्रिय समाज में, जिसे 'स्वयंवर' के रूप में जाना जाता था, दुल्हनों को अपना जीवनसाथी चुनने की विशेष स्वतंत्रता थी। ऋग्वैदिक सभ्यता मं दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। हालाँकि, यह व्यापक रूप से माना जाता था कि विवाह एक उपहार या दान था। द्विविवाह का भी प्रचलन था, हालांकि यह केवल उच्च वर्गों में ही था य मोनोगैमी आदर्श था। नए पति ने महिला का सम्मान किया। महिला ने अपने पति के बलिदान में भाग लिया।

हालांकि, चूंकि बेटे ने अंतिम संस्कार किया और वंश को संरक्षित किया, इसलिए पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं से लड़कों को जन्म देने की उम्मीद

* सह आचार्य (समाजशास्त्र) राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर (राज.) भारत

की गई थी। विधवाएं विशिष्ट परिस्थितियों में पुनर्विवाह कर सकती हैं। हालाँकि पति से उतना वफादार होने की उम्मीद नहीं की गई थी, फिर भी महिला नैतिकता ने एक उच्च स्तर बनाए रखा। इस युग में तलाक आम बात नहीं थी। ऋग्वेद के अनुसार विधवा को अपने पति के भाई के साथ पुनर्विवाह करने का कानूनी अधिकार था। ऋग्वेद में अविवाहित पुत्रियों के अपने पिता की संपत्ति के वारिस होने के अधिकार को स्वीकार किया गया था, लेकिन विवाहित पुत्रियों को बाहर रखा गया था।

पुजारी अधिक बार धार्मिक संस्कार करने लगे, जिससे परिवार में महिलाओं का महत्व धीरे-धीरे कम होता गया। उपनिषदों के युग में, विवाह की 'अनुलोम' प्रणाली - एक उच्च जाति के पुरुष और निचली जाति की एक लड़की के बीच - बाद में प्रचलित हुई।

सूत्रों और महाकाव्यों के युग से 'गृह्य-सूत्र' विवाह के लिए सही मौसम और वर और वधू के लिए आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। दुल्हन की उम्र शायद 15 या 16 वर्ष होने की उम्मीद थी। जटिल प्रक्रियाओं से पता चलता है कि विवाह एक कानूनी समझौते के बजाय एक आध्यात्मिक बंधन था। घर में महिलाओं का सम्मानजनक स्थान बना रहता था। वह गाने, नाचने और जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र थी। सामान्य तौर पर, सती बहुत आम नहीं थी। विशिष्ट परिस्थितियों में विधवा के पुनर्विवाह की अनुमति थी।

सामान्य तौर पर, धर्म-सूत्र बाद के काल की स्मृतियों की तुलना में कम सख्त हैं। एक पति जो गलत तरीके से अपनी पत्नी का परित्याग करता है, उसे 'अपस्तंब' से कई दंडों का सामना करना पड़ता है। परन्तु जो स्त्री अपने पति का परित्याग कर देती है, उसे केवल तपस्या करनी पड़ती है। एक परिपक्व महिला तीन साल बाद अपना जीवनसाथी चुन सकती है यदि उसके पिता ने उचित अवधि में उससे शादी नहीं की। महिला प्रशिक्षकों की उपस्थिति, जिनमें से कई को गहरी आध्यात्मिक समझ थी, इस समय अवधि का सबसे आकर्षक पहलू है।

उस समय लड़की का जन्म अवांछित था, जैसा कि सभी पितृसत्तात्मक समुदायों में होता था। बेटे ने आर्थिक रूप से परिवार का समर्थन किया, खतरों को दूर किया, परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखा और अपने माता-पिता के साथ रहा। भारतीय महाकाव्य साहित्य महाभारत, पुराणों और रामायण से बना है। समाज के अलावा समाज और घर दोनों में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई है। उपनयन की समाप्ति, शिक्षा की उपेक्षा और विवाह की आयु कम करने से महिलाओं की स्थिति और स्थिति पर हानिकारक प्रभाव पड़ा।

इस समय महिलाओं को एक ऐसी वस्तु के रूप में देखा जाता था जिसे दांव पर लगाया जा सकता था, बेचा या हासिल किया जा सकता था। हालाँकि, महाभारत और रामायण दोनों ही हमें विपरीत दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। अहिल्या, तारा, द्रौपती और मंदोदरी सहित भारत की पांच आराध्य और आदर्श महिलाओं में से एक सीता हैं। महाभारत में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि कैसे महिलाएं धर्म और समाज के मामलों में पुरुषों को सलाह देती थीं। एक सभ्य महिला को अपने पति को उसके धार्मिक प्रयासों में समर्थन देना चाहिए था।

एक धार्मिक संस्कार, विवाह। महिलाओं को स्वतंत्रता के लिए अनुपयुक्त माना जाता था क्योंकि उन्हें जीवन भर सुरक्षा की आवश्यकता होती थी। जबकि 600 ईसा पूर्व से 320 ईस्वी तक की अवधि में अंतर्जातीय विवाह आम थे, एक ही जाति के भीतर विवाहों का समर्थन किया गया था। धर्म-सूत्रों में अनुशंसित आठ प्रकारों में विवाह का अर्श रूप सबसे आम था।

पूर्व वैदिक काल -जब पंद्रहवीं शताब्दी ईसा पूर्व में आर्य भारत आए, तो इतिहास जैसा कि हम जानते हैं, आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। वैदिक युग की शुरुआत में पितृसत्तात्मक समाज द्वारा मातृसत्तात्मक संस्कृति को नष्ट कर दिया गया था। इसे भारत में लैंगिक असमानता की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है।

ऋग्वेद में वर्णित ऐतिहासिक युग से पता चलता है कि धार्मिक सरोकार नागरिक जीवन पर हावी थे। आठवीं शताब्दी में मुसलमानों के प्रवेश तक, वैदिक संस्कृति व्यापक रूप से प्रचलित थी। मुस्लिम विजय के बाद, भारत के इतिहास को मध्यकालीन माना जाता है, उस दौरान पितृसत्तात्मक समाज का प्रभुत्व था।

समाज को नियंत्रित करने वाले पितृसत्तात्मक ढांचे के संदर्भ में इस्लामी और वैदिक युग काफी समान थे। 18 वीं सदी का ब्रिटिश राज मुस्लिम काल के बाद आया। इसके अतिरिक्त, यह ज्यादातर पितृसत्तात्मक था। पिछले युगों में, लैंगिक भेदभाव पितृसत्ता और पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना के साथ सह-अस्तित्व में था। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति और सत्ता के लिए उनकी लड़ाई वेदों, पुराणों, उपनिषदों और महाकाव्यों के अध्ययन के माध्यम से प्रकट होती है।

पूर्व-वैदिक युग के दौरान महिलाओं की स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि पुरापाषाण काल का मनुष्य एक खानाबदोश था जो प्रागैतिहासिक काल में रहता था। मुख्य कार्य भोजन प्राप्त करना था।

नवपाषाण काल के मनुष्य ने संस्कृति और सभ्यता का विकास किया क्योंकि वह धीरे-धीरे भोजन एकत्र करने के तरीके से खाद्य उत्पादन में से एक में परिवर्तित हो गया। पुरुषों ने नदी घाटियों में खुद को स्थापित करना शुरू कर दिया। किंवदंती के अनुसार, सिंधु घाटी सभ्यता, भारत में सबसे पहले दर्ज की गई सभ्यता, 25 वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास अपने चरम पर पहुंच गई थी।

इतिहास से पता चलता है कि इस पूरी सभ्यता में, लोग ज्यादातर महिला देवताओं का उल्लेख करते थे और प्राकृतिक तत्वों की पूजा करते थे। माँ प्रकृति एक सामान्य उपनाम थी। देवी माँ पहली देवत्व थीं जिनकी सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी पूजा करते थे।

उत्तार वैदिक काल में महिलाएं - दो महान भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं। जीवन शैली के इन महाकाव्यों के चित्रण आधुनिक सामाजिक वास्तविकताओं का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं। रामायण के बाद एक कथा है जिसे महाभारत में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी रचना संभवतरू बाद में की गई थी। महाभारत और रामायण हिंदू समाज के सबसे पुराने लिखित लेख हो सकते हैं।

स्वयंवर एक सामान्य प्रकार का विवाह है जिसे महाकाव्यों में दर्शाया गया है। विवाह की संस्था, विशेष रूप से उच्च जातियों में, स्वयंवर कहलाती है। इस पारंपरिक प्रकार के विवाह में महिलाओं को अपने जीवन साथी को चुनने के लिए अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता का प्रयोग करने की सूचना मिली थी। स्वयंवर के माध्यम से, रामायण से सीता और महाभारत से द्रौपती की शादी हुई थी।

चूँकि वधू की अपना जीवनसाथी चुनने की क्षमता अक्सर बाधित होती है, स्वयंवर समकालीन अर्थों में अपनी पसंद प्रदान नहीं करता है। 'स्वयंवर' की संस्था के तहत उसे एक प्रतियोगिता के विजेता की शादी करने की

आवश्यकता होती है, जो उसके संभावित दूल्हे की लड़ाई के कौशल का आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी।

महाभारत में सबसे सम्मानित महिला पात्र गांधारी है। अपने अंधे पति धृतराष्ट्र की खातिर, उसने एक वास्तविक सहधर्मिणी का उदाहरण पेश करते हुए, अपनी आँखों को पट्टी करने का उपक्रम किया। यह सवाल कि क्या गांधारी ने जानबूझकर अपनी दृष्टि को खराब करना उचित था, अभी भी बहस के लिए तैयार है।

अगर वह अंधी नहीं होती, तो क्या वह अपने पति के लिए एक बेहतर दोस्त और अधिक मूल्यवान मार्गदर्शक होती जो पूरी तरह से अंधा था ? हालाँकि, जब उसने देखा कि उसका पति गलत दिशा में जा रहा है, तो उसने उसका सामना करने का साहस दिखाया। क्या उसने अपनी दृष्टि से समझौता किया है ताकि वह अपने पति या पत्नी द्वारा किए गए गलत कामों को देखने से बच सके या उसके प्रति सहानुभूति महसूस कर सके ?

मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति

प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में महिलाओं के ऐतिहासिक संदर्भ –पूर्व युग की तरह, महिलाओं को अक्सर संज्ञानात्मक रूप से हीन माना जाता था। उन्हें अपने पति के आदेशों का आंख मूंदकर पालन करना पड़ता था। महिलाओं को अभी भी वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा, जिस उम्र में महिलाओं की शादी हो सकती है, उसे कम करने से आगे की शिक्षा हासिल करने की उनकी क्षमता में बाधा आती है। दरबारी महिलाएँ और यहाँ तक कि रानी की दासियाँ भी, उत्कृष्ट संस्कृत और प्राकृत कविता लिखने में सक्षम थीं, जैसा कि उस समय के कुछ नाट्य कार्यो से देखा जा सकता है।

कई किंवदंतियां महान कलाओं में विशेष रूप से संगीत और चित्रकला में राजकुमारियों की प्रतिभा का उल्लेख करती हैं। कविता उन कई प्रतिभाओं में से एक थी, जिनकी अपेक्षा उच्च अधिकारियों, दरबारियों और रखैलों की बेटियों से की जाती थी। स्मृति लेखकों के अनुसार, महिलाओं का विवाह छह से आठ वर्ष की आयु के बीच या उनके आठवें वर्ष और यौवन की शुरुआत के बीच किया जाना था।

मेधातिथि के दौरान अंतर्जातीय विवाह असामान्य हो गए। मामा की भतीजी से विवाह वर्जित है। मेधातिथि ने आपसी स्नेह के आधार पर विवाह करने से मना किया और एक ऐसी दुल्हन खोजने की सलाह दी जो खुद से काफी छोटी हो। दुल्हन की शादी आठ साल की उम्र और यौवन तक पहुंचने के बीच होनी चाहिए। यौवन तक पहुंचने के बाद तीन साल तक अपने पिता के साथ रहने के बाद, एक लड़की अपने पति या पत्नी को चुन सकती है यदि उसके अभिभावक विवाह योग्य उम्र तक पहुंचने से पहले उससे मेल खाने में असमर्थ हैं।

अपने माता-पिता की सहमति से, महिलाएं कभी-कभी स्वयंवर समारोह का चयन कर सकती हैं। विशिष्ट परिस्थितियों में पुनर्विवाह की अनुमति दी गई थी, जैसे कि जब पति या पत्नी ने त्याग दिया था, निधन हो गया था, एक साधु बन गया था, प्रजनन करने की अपनी क्षमता खो दी थी, या एक पारिया बन गया था। महिलाओं पर अक्सर अविश्वास किया जाता था। हालांकि, घर में उनका सम्मान किया जाता था। यदि पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है, भले ही वह दोषी हो, उसे भरण-पोषण प्राप्त करना था।

महिलाओं के संपत्ति अधिकारों का विस्तार भूमि संपत्ति अधिकारों के विस्तार के साथ हुआ। पारिवारिक संपत्ति की रक्षा के लिए महिलाओं को अपने पुरुष रिश्तेदारों की संपत्ति विरासत में लेने की क्षमता दी गई थी। कुछ प्रतिबंधों के साथ, एक विधवा कानूनी रूप से अपने पति की पूरी संपत्ति की हकदार थी यदि वह बिना किसी संतान के मर जाता है। बेटियों को भी विधवा की संपत्ति में वारिस करने का अधिकार था।

मध्यकालीन भारत में महिलाएं –पूरे मध्य युग में भारतीय इतिहास 500 साल पुराना है। यह ज्यादातर मुस्लिम अत्याचारियों के इतिहास पर केंद्रित है। भारत में सबसे पहले मुसलमान योद्धा वर्ग के रूप में पहुंचे। दिल्ली सल्तनत काल और मुगल काल भारत में उनके प्रभुत्व के दो काल हैं। रजिया सुल्तान एकमात्र ऐसी महिला थी जिसने कभी दिल्ली की गद्दी संभाली थी। हुमायूँ-नमा की लेखिका गुलबदन बेगम नामक असाधारण गीतात्मक कौशल वाली महिला थीं।

जहाँआरा और नूरजहाँ ने सरकारी मामलों में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत का सबसे महान मुस्लिम शासक नूरजहाँ था। वह सेना में सुंदरता और बहादुरी दोनों की प्रतिमूर्ति थीं। मुमताज महल असाधारण सुंदरता, असाधारण बुद्धि और उत्तम स्वाद वाली राजकुमारी थीं।

भारत ने मंगम्मल जैसी साहसी महिलाओं का भी उत्पादन किया है, जिनका उदार शासन अभी भी दक्षिण में एक हरी स्मृति है, चांदबीबी, जिनकी उपस्थिति अहमदनगर के किले की प्राचीर पर एक पुरुष के रूप में प्रच्छन्न थी, तारा बाई, महाराजा नायिका जो जीवन थी और औरंगजेब और अहल्या बाई होल्कर, जिनकी प्रशासनिक प्रतिभा सर जॉन मैल्कम ने अदा की है, के दौरान महाराजा प्रतिरोध की आत्मा और निश्चित रूप से, मुगल राजकुमारियां दिल्ली और आगरा के दरबारी जीवन में प्रमुख थीं। दरबारी संस्कृति में जहांआरा, दारा शिकोह के पक्षकार, रोशनारा, औरंगजेब के पक्षपाती, औरंगजेब की बेटी जेबुन्निसा, जिनकी कविता बची हुई है (कलम नाम मखफी के तहत लिखी गई), और अन्य जैसी महिलाओं द्वारा सन्निहित थी।

शिवाजी की माँ जीजा बाई एक वफादार महिला थीं, जो घर में जिद्दी और तानाशाह होने के बावजूद अपने बेटे की इच्छा को टाल देती थीं। मध्युगीन काल में महिलाओं के सामाजिक जीवन में काफी बदलाव आया। अपने जीवनसाथी या अन्य पुरुष रिश्तेदारों पर महिलाओं की निर्भरता इस समय की एक परिभाषित विशेषता थी।

औपनिवेशिक भारत में महिलाएं – साम्राज्यवाद विरोधी महिला आंदोलन औपनिवेशिक भारत में स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण थे। छह महिलाएं 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे सत्र में भाग लेती हैं। (कादंबिनी गांगुली और स्वर्णकुमारी देवी, उनमें से दो बंगाल से हैं।) स्वर्णकुमारी देवी और भारत श्री मंडल के नेतृत्व में सही समिति,(1887) जैसी महिला संगठन। ,(1910) सरला देवी चौधुरानी के नेतृत्व में, तोगोर परिवार की महिलाओं द्वारा बनाई गई थी। उस अपील के बाद ही ऐनी बेसेंट के नेतृत्व में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं को सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार दिया जाना चाहिए।

1930 के दशक में गांधी के 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' और 'भारत छोड़ो आंदोलन' ने एक बड़ा परिवर्तन लाया। सरोजिनी नायडू, प्रवाबती देवी, कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, ज्योतिर्मयी गांगुली, लतिका घोष, आशालता देवी, नेली सेनगुप्ता, कप्तान लक्ष्मी सहगल और अरुणा आसफ अली कुछ ऐसी उल्लेखनीय महिलाएं हैं, जिन्होंने भारत के लिए इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति

19 वीं शताब्दी के दौरान भारतीय महिलाएं – 1700 ई. से 1947

तक की अवधि को आधुनिक भारत कहा जाता है। 18 वीं और 19 वीं शताब्दी की बौद्धिक क्रांति के दौरान वैश्विक स्तर पर महिलाओं और पुरुषों की समानता पर जोर देने वाले स्वायत्ता, समतावादी राष्ट्रवादी समुदायों के गठन की मांग की गई थी।

भारतीय समाज की जाति व्यवस्था पर हमला हुआ। उपनिवेशवाद से भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई और कारीगरों के एक बड़े समूह को नए कस्बों और शहरों में काम की तलाश में अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। नई भू-राजस्व प्रणाली द्वारा ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के जंगल, सांप्रदायिक संपत्ति और संसाधनों के पारंपरिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया।

स्वामित्व नियमों के परिणामस्वरूप जमींदारों का एक नया समृद्ध मध्य वर्ग बनाया गया, जिसने पारंपरिक कृषि भूमि को एक ऐसी वस्तु में बदल दिया, जिसे बेचा जा सकता था, हस्तांतरित किया जा सकता था और किसानों से अलग किया जा सकता था। फिर इन जमींदारों ने किसानों को गरीब बनाने के लिए औपनिवेशिक अधिकारियों के साथ काम किया।

भारत में अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और 19 वीं शताब्दी में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई। ब्रिटिश शासन की स्थापना के समय भारत में महिलाओं की स्थिति सर्वकालिक निम्न स्तर पर थी। स्पष्ट रूप से बहुत सारी सती थी। मुस्लिम महिलाओं को परदे का सख्ती से पालन करना पड़ता है। नृत्य करने वाली महिलाओं के लिए लाभदायक करियर थे। हिंदू मंदिरों में अक्सर देवदासी को खुलेआम सहन किया जाता था। एक प्रश्न के बिना, ब्रिटिश सत्ता ने इन सभी गलतियों को रोकने का प्रयास किया।

पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे और अन्य महिला सुधारकों ने समकालीन पुरुष सुधारकों द्वारा रखे गए पूर्वाग्रहों की ओर ध्यान आकर्षित किया। चेन्नई में, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई, और डॉ. एनी बेसेंट, जो यूरोप से आकर बस गई थीं, शामिल हुईं। इसके अतिरिक्त, इसने सामाजिक परिवर्तन के लिए एक सामान्य एजेंडा बनाया और इसमें विशेष रूप से लिंग-समावेशी दृष्टिकोण का अभाव था।

इक्कीसवीं सदी में महिलाओं की स्थिति – महिलाओं ने अभी तक अपने भाग्य पर नियंत्रण नहीं किया है, और उनके साथ समाज द्वारा अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। आज पुरुषों के समान राष्ट्र, समाज और संस्कृति में रहते हुए, उन्हें उनके मूल मानवाधिकारों से वंचित किया जाता है और पितृसत्तात्मक समाज द्वारा उनका उपहास किया जाता है। नतीजतन, उन्होंने अभी तक अपनी स्थिति हासिल नहीं की है। उन्होंने शाम के बाद से अपनी चारदीवारी नहीं छोड़ी है, और आज उन पर समाज के पुरुष सदस्यों द्वारा एक गहरे जंगल में, एक छोटी सी सड़क पर, एक खाली मैदान में, दोपहर में, और रात में एक तूफान के दौरान हमला किया गया। वे पुरुषों से कम हैं क्योंकि वे स्त्री लिंग के हैं य वे महिलाएं हैं। 'अन्य' उनके पास मर्दाना लिंग नहीं है। लैंगिक समानता का मुद्दा फिर से उठाया जाता है और यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि यह व्यावहारिक रूप से स्थापित नहीं हो जाता क्योंकि महिलाओं को अभी तक इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में भी समाज से अपनी वास्तविक स्थिति प्राप्त नहीं हुई है।

भारतीय समाज में महिलाओं की वर्तमान स्थिति –अगर एक आदमी पूरी दुनिया को हासिल कर ले लेकिन अपनी आत्मा को खो दे तो उसे क्या फायदा ? दुर्भाग्य से, भारतीय महिला नागरिकों के विशाल बहुमत को अभी तक उसी स्वतंत्रता और समानता का अनुभव नहीं है जो भारतीय महिलाओं के पास है। जब तथ्यों का उपयोग करते हुए एक संक्षिप्त शोध किया गया, तो बालिकाओं पर पुरुष बच्चों के पक्ष में होने के परिणाम बेहद आश्चर्यजनक, बहुत परेशान करने वाले हैं, और फिर भी भारत में व्यावहारिक रूप से सभी क्षेत्रों और लोगों के सभी समूहों में अब भी आम तौर पर प्रचलित हैं। क्या यह सामूहिक हत्याओं का देश है ? सवाल है जो सामने आता है। क्या हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध देश में एक लड़की को शांत जन्म और पुरुष बच्चे के समान सम्मान का अधिकार नहीं है ?

यद्यपि एक देश के रूप में हमें अपने मजबूत पारिवारिक मूल्यों पर गर्व है, हम में से कितने वास्तव में 'कृत्रिम संतुलन' परिवारों में रहते हैं जहां बेटों को जन्म देने के लिए महिलाओं को मार दिया जाता है ? अंत में, हम एक पारिवारिक संबंध को कैसे संभालते हैं, इसका अंततः अन्य सभी पारिवारिक संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा। सभ्यता की मूलभूत संस्थाओं में से एक विवाह है। राष्ट्र विकास का एक प्रमुख घटक परिवार इकाई है जिसे समाज ने बनाया है। एक दुखी, असंतुलित परिवार और उसकी संतानों द्वारा एक अस्थिर और अराजक समाज का निर्माण किया जाएगा।

निष्कर्ष – एक घरेलू सहायिका के रूप में काम करना, एक छोटा व्यापारी, एक कारीगर, या एक परिवार के खेत में एक क्षेत्र कार्यकर्ता अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन पदों में से अधिकांश कम कुशल, कम वेतन वाले हैं, और कर्मचारी को लाभ प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन शायद अधिक महत्वपूर्ण रूप से, सांस्कृतिक रीति-रिवाज एक स्थान से दूसरे क्षेत्र मं भिन्न होते हैं। उत्तार भारत में दक्षिण भारत की तुलना में अधिक पितृसत्तात्मक और सामंती होने की प्रवृत्ति है, इस तथ्य के बावजूद कि यह एक सामान्यीकरण है। उत्तार भारत में, महिलाओं को उनके आचरण पर कठोर प्रतिबंधों के अधीन किया जाता है, जो रोजगार तक उनकी पहुंच को सीमित करता है। दक्षिण भारत में महिलाओं की अधिक स्वतंत्रता और एक मजबूत सामाजिक उपस्थिति होती है, जिसमें अधिक समान होने की प्रवृत्ति होती है। इस तथ्य के बावजूद कि देश भर में अभी भी कुछ नौकरियां उपलब्ध हैं, सांस्कृतिक बाधाएं लुप्त होती जा रही हैं और महिलाएं औपचारिक क्षेत्र में संलग्न होने के लिए अधिक स्वतंत्र हैं। हालाँकि, भारत में कामकाजी महिलाओं की परिस्थितियों में हाल ही में काफी सुधार हुआ है। अधिक से अधिक कंपनियां अब उन महिलाओं के कब्जे में हैं जो पुरुषों के समान पदों पर काम करती हैं, और अधिक से अधिक महिलाएं खुद को सम्मान और प्रमुखता के पदों पर पा रही हैं। कार्य करना अब केवल एक आवश्यक समायोजन नहीं है, बल्कि स्वयं को विकसित करने का एक उपकरण है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. मेनन, इंदु, एम. (1989) । भारत में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति। केरल का एक केस स्टडी। नई दिल्ली: उप्पल पब्लिशिंग हाउस।
2. नंदा, बी.आर. (1976) । भारतीय महिलाएं पर्दे से लेकर आधुनिकता तक। नई दिल्ली: विकास प्रकाशन
3. मिश्रा, आर.सी. (2006) । लैंगिक समानता की ओर। ऑथरप्रेस. आईएसबीएन 81-7273-306-2 https://www.vedams books.com/no43902.htm
4. पृथी, राज कुमार; रामेश्वरी देवी और रोमिला पृथी (2001) । महिलाओं की स्थिति और स्थिति: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में। वेदम ग्रंथ। आईएसबीएन 81-7594-078-6 । https:/ /www.vedamsbooks.com/no21831.htm
5. 'वैदिक महिलाएं: प्यार करने वाली, सीखी हुई, भाग्यशाली! http://

hinduism.about.com/library/weekly/aa031601c.htm, 2006-12-24 को पुन:प्राप्त.

6. 'इन्फो चेंज वीमेन: बैकग्राउंड एंड पर्सपेक्टिव' http://www.infochangeindia.org/WomenIbp.jsp 2006-12-24 को पुन:प्राप्त.

7. 'इतिहास में महिलाएं'। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संसाधन वीरय्अ http://nrcw.nic.in/index2.asp\sublinkid=450- 2006-12-24 को पुन:प्राप्त.

8. ज्योत्सना कामत (2006-1)। 'मध्यकालीन कर्नाटक में महिलाओं की स्थिति' http://www.kamat.com/jyotsna/women.htm 2006-12-24 को पुन:प्राप्त.

9. सरवनकुमार, ए.आर. (2016)। भारत में महिला शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य। चोल साम्राज्य में शैक्षिक प्रथाओं पर आईसीएचआर द्वारा प्रायोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में (850 - 1279 ईस्वी) एपिक - 2016 इतिहास और डीडीई विभाग, अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुडी द्वारा आयोजित।

10. सरवनकुमार, ए.आर. (2017)। मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों के बीच अंतर. मानव अधिकार शिक्षा पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में (एनसीएचआरई - 2017) शिक्षा विभाग, अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुडी द्वारा आयोजित।

****

Energy Empower with Intrusion Detection Routing Protocol with Intrusion Detection for Mobile Ad Hoc Networks

Dr. Makarand Rambhau Shahade* Dr. Sachin S Agrawal Prof. R.S. Jaiswal*****

Abstract - One important characteristic of MANETs is that the nodes are energy-constrained. Since, nodes are battery-operated, recharging frequently or replacing batteries may become undesirable or even impossible. The nodes in Mobile Ad-hoc Networks (MANET) are limited battery-powered. This not only leads to degradation in performance of the network but also reduces the lifetime of the network and in some cases makes the network partitioned. In order to maximize the lifetime of MANETs, routes having nodes with low energy and nodes with more buffered packets should be avoided. so, the energy efficiency is one of the primary metrics of interest. Energy efficient routing in MANETs is considered as a major issue.

In this Paper, a new energy efficient scheme in the routing protocol for mobile ad hoc network has been proposed which will efficiently utilize the battery power of the mobile nodes in such a way that the algorithm improves the network energy consumption and increases the lifetime of the network. The popular on demand routing protocols use shortest path between sources to destination without considering the energy of the intermediate nodes in the path. The proposed algorithm not only considers energy of the node while selecting the route but also takes into account the number of packets buffered in the node. More number of buffered packets means remaining energy will be less and time taken to deliver a packet will be more. Intrusion is any attempts to compromise the integrity, confidentiality, or availability of a resource and an intrusion detection system (IDS) is a system which detects such intrusions. Before describing a Mobility and Energy-aware Hierarchical Intrusion Detection System for MANETs, it is necessary to understand what intrusion detection systems (IDS) are and what they do?

Keywords -Mobile adhoc network; Routing Protocol; Energy Efficient Routing;Packet buffered; Intrusion Detection System (IDS).

Introduction - Intrusion Detection System Classification: The current IDS architectures for MANET consider under three essential classes [4]:

(a) Stand-alone architecture which utilizes an engine introduced at every node using just the node's local audit data. This reality restrains the Stand-alone IDS in terms of detection exactness and the sort of attacks that it could identify [5].

(b) Cooperative architecture which processes each host's locally. It is similar to standalone architecture, but it also uses collaborative techniques to detect more accurately a large list of attacks. Thus, the majority of the most recent IDS for MANET are based on them and the Hierarchical architectures as well [6].

(c) Hierarchical architecture which is an extended version of the cooperative architectures [14]. These architectures reach to a multilayer approach by dividing the network into clusters. Specific nodes are selected as cluster-heads and undertake various responsibilities and roles in intrusion detection, which are different from those of the simple cluster members [7].

(d) Intrusion Detection System architecture with mobile agent which uses mobile agents that can move through large networks. It allows the distribution of the intrusion detection tasks. Each agent is assigned to do a specific task and then one or more agents are distributed into each node in the network [8].

*Asst .Professor (Information Technology) Jawaharlal Darda Institute of Engineering and Technology, Yavatmal (Maharashtra) INDIA
** Assistant Professor (Computer Science and Engineering) College of Engineering and Technology, Akola (Maharashtra) INDIA
*** Assistant Professor (Computer Science and Engineering) College of Engineering and Technology, Akola (Maharashtra) INDIA

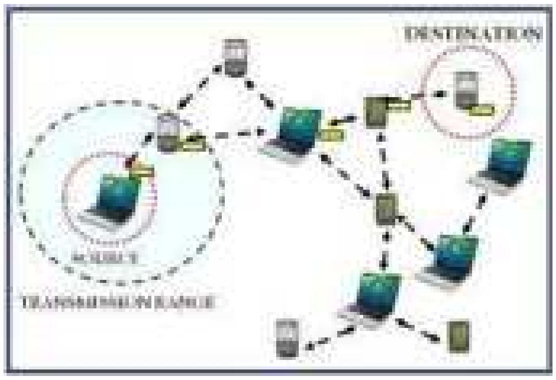

Fig. 1. Mobile Ad hoc Network

According to [9] Mobile Ad-hoc Network (MANET) is dynamic and self-configuring network that formed by collecting number of mobile nodes. Group of node make one cluster. It is necessary to have a good and efficient cluster formation and cluster head selection algorithm to connect with other neighbouring node. Their communication should do in very less time. The various techniques are available to make cluster. Battery life, speed, packet delivery ratio, delay these are some important parameter through which we can make efficient algorithm. In MANETs, the nodes themselves communicate with each other making dynamic network topologies. Because of their unusual topology, wireless shared system, heterogeneous resources and stringent resource limitations, MANETs are powerless against an assortment of attacks (i.e., target routing, participation, classification, trustworthiness, and so forth.) and therefore, adequate protection from them is essential necessity. The execution of an Intrusion Detection System (IDS) can distinguish such attacks and trigger the suitable protection mechanisms.

Nodes in Ad Hoc networks should be enabled to manage efficiently their energy consumption to prolong the network lifetime [1]. The energy consumption of each node varies according to its communication state: transmitting, receiving, listening or sleeping state. Any power failure of a node will affect the overall network lifetime.

One important characteristic of MANETs is that the nodes are energy-constrained. Since, nodes are battery-operated, recharging frequently or replacing batteries may become undesirable or even impossible. The nodes in Mobile Ad-hoc Networks (MANET) are limited battery-powered. This not only leads to degradation in performance of the network but also reduces the lifetime of the network and in some cases makes the network partitioned. In order to maximize the lifetime of MANETs, routes having nodes with low energy and nodes with more buffered packets should be avoided. so, the energy efficiency is one of the primary metrics of interest. Energy efficient routing in MANETs is considered as a major issue.

In this Paper, a new reliable power aware routing scheme for mobile ad hoc network has been proposed which will efficiently utilize the battery power of the mobile nodes in such a way that the algorithm improves the network energy consumption and increases the lifetime of the network. The popular on demand routing protocols use shortest path between sources to destination without considering the energy of the intermediate nodes in the path. This can lead to path breakage if any node runs out of energy. The proposed algorithm which not only considers energy of the node while selecting the route but also takes into account the number of packets buffered in the node as well as shortest routing path. More number of buffered packets means remaining energy will be less and time taken to deliver a packet will be more. Proposed algorithm more timely path setup and efficient route maintenance, that try to find the optimal route during route discovery phase and maintain the route reactively.

Energy aware Routing Protocol : A RPAR finds the most stable path out of the entire existing paths from source to destination using on-demand routing. The popular on demand routing protocols use shortest path between sources to destination without considering the energy of the intermediate nodes in the path. This can lead to path breakage if any node runs out of energy. The algorithm which does not always choose only the shortest path between source and destination but choose such routing path that nodes have the maximum residual energy as well as shortest path and algorithm which not only considers energy of the node while selecting the route but also takes into account the number of packets buffered in the node. More number of buffered packets means remaining energy will be less and time taken to deliver a packet will be more.

Algorithm for Route Discovery process in EAPR:

1. When any node has data to send, it generates route request packet (RREQ) and floods it on the network with a common transmission range.
2. The route request packet should carry two pieces of information: hop count and energy consumption.
3. Search for all shortest (Minimum hops) routes.
4. Among the shortest paths pick the route on which nodes have the maximum residual energy as well as minimum number of packets buffered in the node.
5. Destination node sends the route reply packet (RREP) on selected route.
6. The proposed scheme adds the following parameters in the header of route reply packet.

a. Residual Energy Status (RES): the residual energy of the node.
b. Buffered Packets (BP): the number of packets buffered in the node.

The algorithm does not always choose the shortest path between source and destination but chooses such routing path that has nodes with maximum residual energy as well as minimum number of packets buffered in the nodeamong theshortest paths. In figure 3, nodes with blue color have more than 50% of remaining energy and nodes with light blue color (2 & 6) have less than 50% of remaining energy. The small circle with the nodes gives the number of buffered packets. As shown in figure 3, the shortest path

from source node 1 to destination node 9 chosen by AODV is 1-2-3-9 (shortest hop), but due to low residual energy of node 2, it is not chosen. Node 5 and 6 also lie in the transmission range of source node 1. Out of the two, node 5 is chosen as it has the maximum residual energy, minimum packets in buffer and also it is nearest to source node 1. Thus the route 1-5-7-8-9 will be selected on the basis of above mentioned algorithm, which is more reliable and number of packets can be transferred before any node dies.

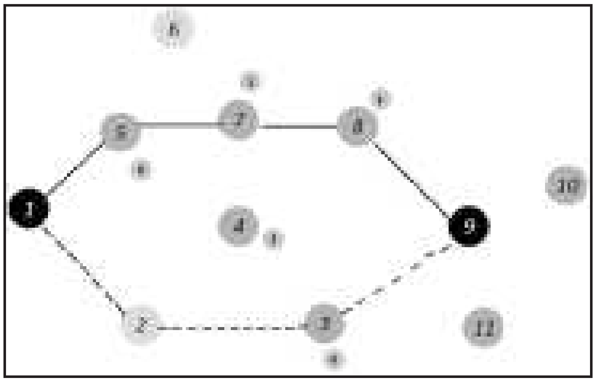

Fig. 2. Reliable Energy Aware Routing Scheme

Residual Energy Model

The energy consumed $e_c(T)$ by a node after time T is calculated as

$e_c(T) = n_t \times a + n_r \times b$ ---------------(1)

Where, n_t and n_r are number of packets transmitted and received by a node after time T respectively, a and b are constants with value between 0 and 1.

The residual energy $e_r(T)$ of a node at time T, is calculated as

$e_r(T) = e_i - e_c(T)$ ----------------(2)

Where, e_i is the initial energy of a node [19].

The residual energy of the node is calculated using equation (2)

Residual Energy Status (RES) is found as

If (Residual energy) < 50%

Then set RES = 0

If Residual energy > 50%

Then set RES=1

Simulation : In this section, it discusses some of the simulation parameters to measure the network performance.

Simulation Environment: The proposed model has considered an area of 1,000 mts × 1,000 mts with a set of nodes placed randomly. It simulated by using Network Simulator (NS-2.33). Here, each node is initially placed at a random position within the defined area. As it progresses, each node pauses current location for 2 sec and then randomly chooses new location. Each node maintains its behavior, alternately pausing and moving to a new location during the simulation time. The simulation parameters are shown in table I.

TABLE 1. SIMULATION PARAMETER

Parameter	Value
Topology area	1,000 × 1,000 mts
Simulation time	2,000 sec
Traffic type	CBR
CBR packet size	512 bytes
Node mobility	0 to 20 mts/sec
Frequency	2.4 Ghz
Channel capacity	2 Mbps
Transmission range	150 mts
Transmission power	1,400 mW
Receiving power	1,000 mW
Idle power	830 mW
Mobility model	Random waypoint
Voltage	5 V
Pause time	1 sec

Results and Discussion : In order to evaluate the network performance, it uses the metrics such as network lifetime & energy consumption.

Network Lifetime: In this experimental setup, it considered 25 nodes, which are deployed within the defined area. Number of packets sent between 5–20 packets/sec and each node moved 2 mts/sec. Group size versus the network lifetime as shown in Fig. 1. From the results, it concludes that the proposed model is always kept maximum number of nodes alive for longer period of time as compared to others. If the group size is 12, then the proposed model has kept the nodes alive for 8,150 sec, whereas the MIP model and LAM model have kept the nodes at 7,450 sec and 6,455 sec, respectively.

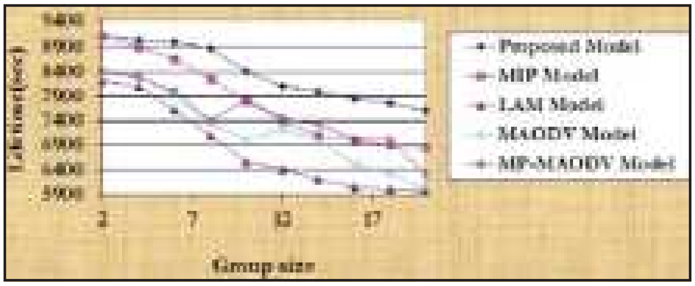

Fig. 3. Group size nodes verses *Network Lifetime*

Energy Consumption: Fig. 4 Erms for different time instances. From the results, it concludes that the MIP model has reached at the top position as compared to both the proposed model and LAM model in terms of Erms. As on time increases the energy consumption of all nodes will increase due to mobility. Then it system requires more number of route discoveries to perform well. Consequently, it takes high energy consumption over the network.

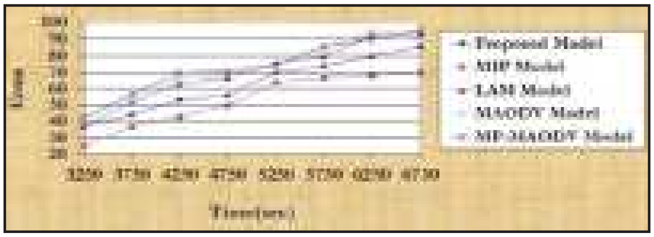

Fig. 4. Erms for different time instances

Conclusion : The algorithm efficiently utilizes the battery power of the mobile nodes in such a way that it will improve the network energy consumption and increase the lifetime of the network and This algorithm does not always choose only the shortest path between source and destination but choose such routing path that nodes have the maximum residual energy as well as shortest path.

This algorithm not only considers energy of the node while selecting the route but also takes into account the number of packets buffered in the node. More number of buffered packets means remaining energy will be less and time taken to deliver a packet will be more. This proposed algorithm is differed from existing algorithms.

The simulation results reported in this paper demonstrate that the proposed model improved the network lifetime by 20% on average. Extending network lifetime is accomplished by finding multicast that tends to minimize the variation of remaining energy of all the nodes.

References:-

1. J. Zhu, C. Qiao, and X. Wang, “On Accurate Energy ConsumptionModel for Wireless Ad-Hoc Networks,” *IEEE Trans. Wireless Comm*., vol. 5, no. 11, pp. 3077-3086, Nov. 2006.
2. J. Zhu, C. Qiao, and X. Wang, “A Comprehensive Minimum Energy Routing Protocol for Wireless Ad Hoc Networks,” *Proc. IEEE INFOCOM*, Mar. 2004.
3. C.K. Toh, H. Cobb, and D. Scott, “Performance Evaluation of Battery-Life-Aware Routing Schemes for Wireless Ad Hoc Networks,” *Proc. IEEE Int’l Conf. Comm. (ICC ’01),* June 2001.
4. A. Misra and S. Banerjee, “MRPC: Maximizing Network Lifetime for Reliable Routing in Wireless Environments,” *Proc. IEEE Wireless Comm. and Networking Conf. (WCNC ’02)*, Mar. 2002.
5. D. G. Reina, S. L. Toral, P. Johnson, and F. Barrero, “A Reliable Route Selection Scheme based on Caution Zone and Nodes Arrival Angle,” *IEEE Commun. Letters.*, vol. 15, no. 11, pp. 1252–1255, Nov. 2011.
6. L. Junhai, Y. Danxia, X. Liu, and F. Mingyu, “A Survey of Multicast Routing Protocols for Mobile Ad-Hoc Networks,” *IEEE Comm. Surveys and Tutorials,* vol. 11, no. 1, pp. 78-91, First Quarter 2009.
7. C. Papageorgiou, P. Kokkinos, and E. Varvarigos, “Energy-Efficient Multicasting in Wireless Networks with Fixed Node Transmission Power,” *Proc. ACM Int’l Conf. Comm. and Mobile Computing*, pp. 958-962, 2009.
8. E. Astier, A. Hafid, and A. Benslimane, “Energy and Mobility Aware Clustering Technique for Multicast Routing Protocols in Wireless Ad Hoc Networks,” *Proc. IEEE Wireless Comm. and Networking Conf*., pp. 1-6, 2009.
9. W. Liang, R. Brent, Y. Xu, and Q. Wang, “Minimum-Energy Allot-All Multicasting in Wireless Ad Hoc Networks,” *IEEE Trans. Wireless Comm.,* vol. 8, no. 11, pp. 5490-5499, Nov. 2009.
10. T. Mukherjee, G. Varsamopoulos, S.K.S. Gupta, “Self Managing Energy-Efficient Multicast Support in MANETs under End-to-End Reliability Constraints,” *IEEE Trans. Computer Networks*, vol. 53, pp. 1603-1627, 2009.
11. F. Ren, J. Zhang, T. He, C. Lin, and S. K. D. Ren, “EBRP: Energy Balanced Routing Protocol for Data Gathering in Wireless Sensor Networks,” *IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst.*, vol. 22, no. 12, pp. 2108–2125, Dec. 2011.
12. A. Sharif-Nassab and F. Ashtiani, “Connectivity Analysis of One Dimensional Ad hoc Networks with Arbitrary Spatial Distribution for Variable and Fixed Number of Nnodes,” *IEEE Trans. Mobile Comput.*, vol. 11, no. 10, pp. 1425–1435, Oct. 2012.
13. A. A. Jeng and R.-H. Jan, “Adaptive Topology Control for Mobile Ad hoc Networks,” *IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst.*, vol. 22, no.12, pp. 1953–1960, Dec. 2011.
14. Seon Yeong Han, Dongman Lee, “An Adaptive Hello Messaging Scheme for Neighbor Discovery in On-Demand MANET Routing Protocols,” *IEEE Communications Letters*, vol. 17, no. 5, pp. 1040-1043, May 2013.
15. Jinhua Zhu, Xin Wang, “Model and Protocol for Energy-Efficient Routing over Mobile Ad Hoc Networks,” *IEEE Transactions On Mobile Computing*, vol. 10, no. 11, pp. 1546-1557, November 2011.
16. Bulent Tavli, Wendi B. Heinzelman, “Energy-Efficient Real-Time Multicast Routing in Mobile Ad Hoc Networks,” *IEEE Transactions On Computers*, vol. 60, no. 5, pp. 707-722, May 2011.
17. Chi Ma, Yuanyuan Yang, “A Battery-Aware Scheme for Routing in Wireless Ad Hoc Networks,” *IEEE Transactions On Vehicular Technology*, vol. 60, no. 8, pp. 3919-3932*,* October 2011.
18. Golla Varaprasad, “High Stable Power Aware Multicast Algorithm for Mobile Ad Hoc Networks,” *IEEE Sensors Journal*, vol. 13, no. 5, pp. 1442-1446, May 2013.
19. V. Rishiwal, M. Yadav and S. Verma, “Power Aware Routing to Support Real Time Traffic in Mobile Adhoc Networks,” *International Conference on Emerging Trends in Engg. & Tech.,Proc.IEEE*, pp. 223-227, Dec. 2008.
20. Xiaojing Xiang, Xin Wang, Zehua Zhou, “Self-Adaptive On-Demand Geographic Routing for Mobile Ad Hoc Networks,” *IEEE Transactions On Mobile Computing*, vol. 11, no. 9, pp. 1572-1586, September 2012.
21. Ying Zhu, Minsu Huang, Siyuan Chen, Yu Wang, “Energy-Efficient Topology Control in Cooperative Ad Hoc Networks,” *IEEE Transactions On Parallel and Distributed Systems*, vol. 23,no.8, pp. 1480-149, August 2012.
22. D. G. Reina, P. Jonhson, F. Barrero, “Hybrid Flooding Scheme for Mobile Ad Hoc Networks,” *IEEE Communications Letters*, vol. 17,no.3,pp. 592-595, March 2013
23. Chuan-Chi Weng, Ching-Wen Chen,Po-Yueh Chen, Kuei-Chung Chang, “Design of an energy-efficient cross-layer protocol for mobile ad hoc networks,” *Communications, IET Journals*, Vol. 7 , Issue 3, May 2013.
24. Peng Zhao, Xinyu Yang, Wei Yu, Xinwen Fu, “A Loose-Virtual-Clustering-Based Routing for Power Heterogeneous MANETs,” *IEEE Transactions On Vehicular Technology*, vol. 62, no. 5, pp. 2290-2302, June 2013.

Impact of Climate Change on Horticulture Crops

Dr. Govind Prakash Acharya*

Abstract - Rainfall, atmospheric pressure and direction and speed of winds in a place or region over a long period of time is called climate. Changes in the climate of a place occur over a long period of time (usually 30 or more years). The only word that can fully describe the climate of India is monsoon . Monsoon is a seasonal reversal of winds because in winter season the winds blow from land to sea and in summer season from sea to land. Monsoon is a major feature of southern and south-east Asian climate and has considerable economic importance. Indian agriculture is considered a gamble of monsoon because in most areas agriculture is dependent on monsoon rains. In fact, monsoon is the axis around which the Indian economy revolves. Because the production capacity of agriculture is completely dependent on climate and weather. Agriculture in India is largely dependent on weather and seasonal changes caused by climate change have a great impact on it.

Global Climate change is change in Long term weather pattern that characterised by the region of the world. Agriculture and water and air changes are inextricably linked to each other, for example, crop yield, biodiversity, water use and soil strength are affected by climate change. Since the origin of life on Earth till today, its climate has changed many times. Is. These changes in climate occur due to natural processes. In the last few years, due to population growth, industrialization, urbanization, forest destruction, increase in the number of automated vehicles, technological development, agricultural development and high standard of living etc., the environment has been greatly damaged and various elements of climate. (temperature, air pressure, humidity, There have been extensive changes in rainfall, wind speed etc. Due to climate change, there is a possibility of continuous change in the frequency and intensity of rainfall, heat wave, and other extreme events which will affect agricultural production. Apart from this, combined climatic factors can reduce the productivity of plants. As a result of which there may be fluctuations in the prices of agricultural crops.

Introduction - Horticultural crops are more affected by climate than soil crops, due to which their areas are limited. The average of rainfall , light, humidity, temperature and air pressure of a place throughout the year is called the climate of that place. It is absolutely clear that the effect of all these means is not equal at all places. If the temperature is high at some places then rainfall and humidity are more at some places. Suppose there is excess rainfall at a place, then bananas can be grown successfully there but grapes cannot. In mango growing regions, rains and strong winds from January to March prove to be harmful. Therefore, it is clear that different types of fruits require different types of climate and they can be grown successfully only where suitable climate is available for them.

On the basis of climate, the country can be divided into the following main categories:

1. Temperate regional area
2. Subtropical country area
3. Tropical region

1. Temperate region : The main areas of this type in India are Kashmir, Kullu in Himachal Pradesh, Kangra valleys, Kotgarh and Nahan and Kumaon hills. Although these areas are famous for producing temperate fruits in large quantities, still some high altitude areas in the central and southern parts of India ; For example, Nilgiri and Palni hills are such that they produce these fruits to some extent.

Fruits and vegetables of this category are successfully grown in such areas where the temperature goes below the freezing point in winter. At this time these plants shed their leaves and go into dormancy. To end dormancy, a certain period of low temperature is required. In this region, more cold tolerant vegetables like cauliflower, cabbage, knobby cabbage, broccoli, bushels sprout, celery, potato, tomato, pea, salad, pod, asparagus, radish, carrot, turnip, jimikand etc. are grown with success.

2. Subtropical region: The main areas in this are the plains of Punjab and Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and West Bengal.

The northern districts are the areas of Rajasthan and Assam.

As shown in the map , this region can again be divided into two parts –

(a) North-Western Subtropical Region
(b) North-eastern subtropical region

This area is really hot And is situated in the middle of temperate regions. In this subtropical or intermediate region

*Lecturer (Agricultural-Extension) Govt. College, Uniara, Distt. Tonk (Raj.) INDIA

the temperature rarely falls below the freezing point and that too does not fall much. Those fruits are grown mostly in those plain areas where the climate is hot, relatively dry and there is less cold in winter. These fruits are cultivated in sub-mountainous areas , which are very close to the mountainous part.

Fruits grown in subtropical regions can also be grown in tropical regions.

Orange, lemon, lemon, litchi, phalsa, fig, date, grapes, guava, pomegranate etc. are sub - tropical fruits but still they can be grown in hot climate . Similarly, some fruits of tropical regions ; For example, mango, banana and jackfruit etc. can be grown commercially in subtropical regions. Some varieties of peach and pear, which grow in temperate climate, are also successfully grown in subtropical regions. All types of vegetables are produced here.

3. Tropical fruits : in this the southern districts of West Bengal and Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa , Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala etc. are included. This area can again be divided as follows-

A. Central part of the tropical region
B. Southern part of tropical region
C. Coastal part of tropical humid region

For tropical fruits, the climate is humid and hot in summer and mild in winter.

Cold climate is required. If there is facility of irrigation and rainfall in this area, fruits like mango, banana, cashew, sapota , pineapple, papaya and jackfruit etc. and tomatoes, onion, chilli, potato, garlic, onion etc. can be grown successfully. In this area, where there is uniform distribution of rainfall and surrounded by hills, grapes are grown commercially.

Low climatic factors which limit the production of horticultural crops are of special importance and have a special impact on the growth and fruits of these crops. Therefore, it becomes very important to have knowledge about them.

Climatic Factors :

1. Temperature: Temperature has special importance for successful cultivation of fruits and vegetables in any area. Every fruit and vegetable crop requires a specific temperature for its growth and fruition. Above or below that, it cannot grow properly nor give good yield, for example, fruit trees like apple, pear, strawberry etc. can be grown successfully in temperate climate. These fruit trees require temperatures so low that they can shed their leaves and go into dormancy for some time. In contrast, non-deciduous fruit trees; For example, mango, banana, etc. can be grown successfully in areas free from frost and snow where the temperature remains high. Due to low temperature these fruit trees suffer losses. It has been observed that due to low temperature, flowering starts late.

Due to relaxation of insects , pollination does not take place and most of the fruits and flowers fall, whereas due to high temperature the sugar content in the fruits increases and they become sweeter.

2. Rainfall: The amount of rainfall and its distribution are of special importance for the successful production of horticultural crops at a place. Fruits and vegetables cannot be grown successfully in those places where water rains in large quantities at short intervals. Can. Due to continuous excessive rainfall, water seepage occurs in the fruit gardens and this has a bad effect on the flowers and fruits. If there is excessive rainfall at the time of flowering, various parts of the flowers get damaged, pollen grains are lost and the crop is destroyed due to pollination not happening properly. In such a situation, there is a fear of many diseases affecting the plants. On the contrary , if rainfall is less and irregular then it becomes necessary to irrigate fruit trees and vegetable crops. About 100 cm annual rainfall is considered appropriate for successful fruit production, which should be properly distributed throughout the year.

3. Atmospheric Humidity: The amount of moisture required to produce fruits and vegetables depends to a great extent on the condition of the atmosphere. If the atmosphere is dry and the wind blows fast and hot, then plants will lose more water through transpiration. If the air is hot but there is humidity in it, the loss of water in it reduces. Trees bearing many fruits in high humidity and high temperature ; For example, banana and pineapple etc. grow well. Excessive humidity in the environment proves to be harmful for many fruits, in such a situation the qualities of the fruits get spoiled, they do not get good color, as a result the taste becomes less sweet and most of the fruits become diseased like winter guavas. In comparison, the rainy season guava crop is of poor quality. In this way, atmospheric humidity affects different crops differently. Therefore, it is necessary to have it as per the requirement of the particular crop.

4. Wind and light : Fruits cannot be grown successfully in places where the wind is strong or storms occur. In such a situation, the flowers and fruits of the trees fall to the ground and many branches of the plants break and get

destroyed. In Uttar Pradesh, such a situation is seen in summer due to which most of the mango crop becomes useless. Therefore, high speed of wind is undoubtedly harmful for fruit production. Due to hot winds, many fruits burst and become useless and fall on the ground.

Light also has special importance in the production of horticultural plants . Light is available in sufficient quantity in tropical and sub-tropical areas, but due to lack of adequate amount of light in temperate areas, white and black spots appear on the fruits, which reduces their market value. goes. Here the fruit trees are pruned in such a way that they get more amount of light. Due to its deficiency, the variety and yield of vegetables also decreases.

5. **Frost and hail** : Fruits and vegetables suffer a lot due to frost and hailstorm. Plants get destroyed due to frost when they are young. Therefore, mango , papaya, litchi and vegetables etc. cannot be grown in areas where there is severe frost. Even in tropical and sub-tropical regions, it becomes necessary to protect them from frost. The fruit gets spoiled due to hail. In northern India, hailstorm causes considerable damage to fruit orchards.

6. **Drought and Floods :** Water is very important for the successful growth and yield of fruit trees. Due to non-availability of sufficient amount of water to plants, their vegetative growth stops, which affects production. Due to very dry weather , fewer flowers are produced and most of them fall to the ground. Due to lack of water, fruits also start falling and they start bursting. Therefore, horticultural crops cannot be grown successfully in the absence of water.

On the contrary, where floods occur excessively, crops are destroyed. When the plants are submerged, their roots rot, their growth stops and they die. Thus, excessive dry weather and floods are harmful for the growth and production of horticultural plants.

Major measures to reduce climate impact

1. **Water Shed Management Technique:** With increase in temperature, crops require more irrigation. In such a situation, conserving land and collecting rain water and using it for irrigation can be a useful and helpful step. Through water shed management, we can store rain water and use it for irrigation. On the one hand, this will provide us with irrigation facilities and on the other hand, it will also help in ground water recharging.

2. **Organic Farming and mixed Cultivation:** On the one hand, the use of chemical fertilizers and pesticides in the fields reduces the productivity of the soil, while on the other hand, their quantity reaches the human body through the food chain. Due to which many types of diseases occur. Chemical farming also increases emissions of green gases. Therefore, we should give maximum emphasis on the techniques of organic farming. Instead of monoculture, we face less risk in integrated farming. In dedicated farming, many crops are produced so that if one crop fails due to any disease, the farmer can earn his living from the other crop .

3. **Development of new technique of crop production and grow resistant varieties:** Keeping in mind the serious effects of climate change, we will have to develop such varieties of seeds which are suitable for the new climate. We will have to develop such varieties which are capable of tolerating the ravages of high temperature, drought and flood . Varieties that can tolerate this will also have to be developed.

4. **Mixed Farming, Inter cropping and Agro-Forestry:** Along with climate change, we will also have to change the format of crops and the time of sowing their seeds. By coordination and integration of traditional knowledge and new technologies, the threats of climate change can be tackled by rain water conservation and use of agricultural water through mixed farming and intercropping. We can also get rid of the dangers of climate change by adopting agroforestry. To provide options for crop insurance and seasonal insurance so that small and marginal farmers can take advantage of these.

5. **Climate Smart Agriculture (CSA):** Essentially, CSA seeks to address three interrelated challenges: increasing productivity and incomes , adapting to climate change, and contributing to climate change mitigation. This means we have to be more selective about what we put into the fields. as an example But let's take irrigation - micro irrigation will have to be popularized for proper use of water. Adapting to climate change means that farms need to be made resilient to climate change. For example, agricultural areas will have to be identified based on the projected impacts of climate change. Equally important is the need to create a policy environment that strengthens local and national institutions. To adopt CSA practices, farmers need to be provided technical and financial assistance tailored to their geographical location. Prominent among these are zero budget farming and traditional agricultural development schemes, which are being promoted at a fast pace in India today. It is an integrated farming system which is locally sustainable by staying away from chemical fertilizers and pesticides. This method is very effective in increasing the ability of farms to withstand climate change and reducing climate change.

Conclusion: Neither the farmer nor the scientist nor the government alone can reduce the impact of climate change, hence we will have to do it collectively to avoid and save this problem of climate change.

To save Indian agriculture from the adverse effects of climate change, we will have to use our resources appropriately and by adopting the Indian philosophy of life, we will have to implement our mutual knowledge. Now give importance to such environment friendly methods in farming so that we can maintain the productivity of our crops and save our natural resources. Today, the biggest demand for farming is that in view of climate change, diversity in fields and combination of trees and animals with lotus is very important. Maay ne keeps.

From experiences and studies, it has been found that where overall, the percentage of loss due to climate change

was less, whereas where it flourished and got affected by animals, the loss was more.

1. To reduce the impact of climate change on crops, some special cultural adaptation techniques should be used. To develop such varieties of crops which can tolerate the stress of drought and salinity and the impact of drought and flood is zero.
2. To improve crop management system and irrigation water related system.
3 New “Agriculture Technology” Dirty Weather Based Early Warning Along with timely rainfall forecasting, crop diversification , crop diversification, conservation technology, improvement in pest management etc. should be adopted.
4. To promote vegetable farming and conservation farming - at the same time, different villages should be given complete information about 18 crop photos and epidemics of Williamson .
5. Many climate-mart agricultural initiatives for farmers are national level projects aimed at addressing the challenges of climate change and fertilizer security.

References :-

1. Critchfield HJ 1975. General climatology. Prentice Hall of India Pvt Ltd, New Delhi.
2. Ghadekar SR 2001. Meteorology. Agromet Publishers, Nagpur, India.
3. Gopalaswamy N 1991. Agricultural meteorology. Rawat Publications, Jaipur, India.
4. Krishnan A and Mukhtar Singh 1968. Soil-climate zones in relation to cropping patterns. Proc Sym on cropping patterns. Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, India.
5. Lenka D 1998. Climate, weather and crops in India. Kalyani Publishers, Ludhiana, India.
6. Mavi HS 1986. Introduction to agrometeorology. Oxford & IBH Publishing Co, Kolkata, India.
7. Penman HL 1948. Natural evaporation from open water, bare soil and grass. Proc Roy Soc Lond. 193: 120-145.New Delhi, India.
8. Ramkrishna YS, Rao GGSN, Rao AVRK and Kumar PV 2002. Weather resources management. In: Yadav JSP and Singh GB (eds) Natural resource management for agricultural production in India. Indian Society of Soil Science, New Delhi, India.
9. Reddy SJ 2000. Andhra Pradesh Agriculture - Scenario of the last four decades. Jeevan Charitable Trust, Secunderabad, India.
10. Reddy SR 2016. Principles of Agronomy (fifth edition). Kalyani Publishers, Ludhiana, India.
11. Reddy SR and Nagamani C 2016. Principles of crop production (fifth edition). Kalyani Publishers, Ludhiana, India.

****

Issues and Prospects in Teacher Education Programme

Dr. Kalpana Singh*

Abstract - Teacher's education is important programme to improve the quality of higher education. In a landmark directive towards ensuring quality teacher education, the National Council of Teacher Education has made sweeping changes from this academic session. It has increased the duration of B.Ed. programme from one year to two years with major changes in curriculum. However, the revision in the norms regarding duration of the course and curriculum is the result of extensive and exclusive debates and discussions. It has emerged as an idea that has been expressed at various forums over the years. Now that the execution phase has begun, the idea is to be analysed in terms of its actual feasibility. It is to be seen whether the prolonged course duration proves into historical transformation in the system of education or turns to be rather 'a not so preferable profession' in the era of professionalism and human capital. However, it is even more pertinent to understand why such changes were felt needed and what strategies have been evolved to implement the revisions effectively. So far the studies have established that the existing training programme does not provide adequate opportunities to the student teachers to develop competency because of the anomalies and defects in the system of implementation of the programme and curriculum of the programme.
Keywords: Teacher education programme,Issues.

Introduction - A student teacher should know the meaning of education, its objectives, the socio-cultural and politico-economics background, the principles that guide construction of curriculum etc. Teacher performance is the most crucial input in the field of education. Whatever policies may be laid down, in the ultimate analysis these have to be interpreted and implemented by teachers, as much through their personal example as through the teaching learning processes. We are on the threshold of the development of new technologies likely to revolutionize teaching in classrooms. But unfortunately, the process of updating curricula of teacher education has been very slow. Today teaching is a profession requiring specialization in terms of knowledge and skills. There exists a wide gap between theory and the knowledge and skills of teaching required in the actual classroom curriculum transaction. For this reason, a routine-bound teacher cannot act in accordance with the emerging needs unless he or she is trained and frequently oriented. One of the most important requirements to promote and strengthen education is the training of teachers who are the key resources in the reform, redirection and renewal of education. In this backdrop the present paper reflects upon the actual reasons of revision in the programme. The paper also focuses on various challenges and issues considerable enough in the implementation of the programme. Some of such challenges are increased financial burden on the parents of aspiring B. Ed. Students, setting up of enriched infrastructure to meet the needs of various curricular enhancements and most importantly the restructuring of teacher education curriculum that aims at all round human development. The paper tries to reflect upon the feasibility of the prolonged programme from the vantage point of the aspiring B. Ed. students and various stakeholders such as administrators, school managements, parents of aspiring candidates and curriculum designers.

Development of Teacher Education in India: The training of teachers assumes great significance in the educational system. Teacher education system is an important vehicle to improve the quality of school education. It is a continuous process. It is well recognized that the overall quality in education depends amongst other things on the quality of teacher and that a sound programme of profession education of teachers is essential. The Government of India realized the importance of Teacher Education as a result of which many reforms were brought out particularly after independence. Various committees and commissions have time and again made recommendations to bring about required changes in teacher education programme. The University Education Commission (1948) recommended that theory and practice of pre-service teacher education must support each other. The Secondary Education Commission (1952-53) recommended the adoption of new techniques of evaluation and suggested that more capable and intelligent persons should be attracted to teaching profession. Education commission (1966) stated that the professional preparation of teachers had been recognized to be crucial for the qualitative improvement of education since the 1960s. In the year 1973, the government of India constitutes the National Council of Teacher Education

*Assistant Professor, R.S. Govt. Degree College, Shivrajpur, Kanpur (U.P.) INDIA

(NCTE) to act as national advisory body on all matters relating to teacher education and review the progress plan scheme to ensure adequate standards in the field of Teacher Education. The expansion of pre service teacher education is impressive if one looks at the continuous growth in the number of teacher education institutes. From a mere 10 secondary teacher training institutions in 1948, the number increased to 50 in 1965 and 633 in 1995. These figures grew as high as 4868 in 2002 and 11712 in 2010. The significant revisions in the teacher education programme were last recommended in National Curriculum Framework for Teacher Education in 2009 and subsequently with amendment in the constitution to make Education a Fundamental Right, curricular reforms and duration of the programme were reviewed.

Issue of implementation of the two year programme: The primary issue that may emerge due to implementation of two year programme is of lack of interest among the students towards the B.Ed. course. Given the fact that two year programme would require higher financial burden on the parents of the aspiring student teachers, such parents are very likely to be reluctant to spend in the course. As far as the attitude of the students is concerned, it may be hypothesized that because of the prolonged duration and increased financial burden, students' participation in the B. Ed. Programme would go down. Importantly, the enrolment in various courses of Education discipline has been slightly fluctuating in the previous years. According to AISHE Report of 2011-12 the enrolment in Education discipline was 3.10%, which remained same in the session 2012-13. As concerns the data of 2013-14 the figures grew to 5.42% of the total enrolment in higher education. Though the pertinent data of 2015, the year in which two year B. Ed. Programme was launched is yet not available. It may be speculated as has been unofficially reported by number of B. Ed. Colleges across the country that the admission in B. Ed. Two year programme is going to be very scant. My visits as external examiner for B.Ed. practicals in couple of colleges affiliated to Kanpur University have revealed the ground realities of fewer admissions in the two year programme so far.

It is important to note that the attitude of the students who earlier got attracted towards the course and the profession was primarily guided by the possibility of easy access and short duration of the course. But now given the fact that the duration of the programme is prolonged and certain eligibility criteria is fixed for the entry in the profession, the students who found it an easy and attractive profession are likely to be reluctant. It has been observed that quite a few students have also dropped the course and most of them have reported the long duration of the course to be the reason for their withdrawal. Moreover, in the neo liberal and globalised world where human capital and professionalism is cherished, less number of students would get attracted towards a long and expansive course which leads to a low paid profession.

Implementation of Two Year B. Ed. Programme would also require great deal of infrastructural adjustments to meet the curricular requirements of the revised course. The revised curriculum as has been prescribed by the National Council of Teacher Education primarily requires the semester system to be in place, and the duration of teaching practice to be increased to not less than six months. Considering these revisions, there would be a need of more number of faculty members, experimental schools attached to various colleges, enriched library to fulfill the additional course requirements and proactive administration to execute the innovative programme more efficiently. As far as the new course curriculum is concerned, it has been observed that the curriculum constructed by NCTE is focused around complete personal and professional development of the pupil teachers. Drawing upon the constructivist approach of teaching, various changes have been called for. As has been earlier reported by various studies that one year B.Ed. programme is insufficient in realizing the goals of education, the new course focuses on the knowledge construction. Now the idea of learning is not remaining to be a passive process, as it has been established that learner its active himself in the process of learning. Courses like Gender and Education, Art Education and Curriculum Development are some of the newer additions making the B.Ed. course to be much more comprehensive and sensitive towards the present social scenario. However, it would be interesting to observe whether such courses are also transacted with adequate vigor and sensitivity. It is also to be seen whether the combination of theory and practical works towards the intellectual as well as the professional development of the pupil teachers.

Reasons for revisions in teacher education programme: An immense writing has appeared on educational quality in recent years, examining factors that help improve education and proposing ways to promote better learning in schools. The issue of quality has become critical in many countries. In countries like India where with constrained resources, the successful effort to increase access to basic education has often led to declining quality of education. In a search for the factors that promote quality, programs as well as the literature increasingly emphasize teachers, schools, societies and communities as the engines of quality, with teacher quality identified a primary focus. The rapid changes in society led to teachers facing new and complex issues, resulting in changes in the area of teacher education. Advances in technology have also posed an issue for future educators. Many educators have focused on ways to incorporate technology into the classroom. Television, computers, radio, and other forms of mass media are being utilized in an educational context, often in an attempt to involve the student actively in their own education. Hence, many teacher education programs now include courses both in technology operation and how to use technology for education purposes. With the coming on of distance learning utilizing mobile technologies and

the internet understanding of technology or we can say e-learning has become crucial for new teachers in order to keep up with the knowledge and interests of their students in these delivery systems. The emergence of a networked knowledge economy presents both opportunities and challenges for teacher education Considering these changes in the socio economic and political system of the nation, revisions in the existing teacher education programme appears to be the immediate need of the hour.

Conclusion: Revisions and experimentations in the existing B.Ed. programme was felt needed and required immediate implementation. However, it's too early to reach to any conclusions about the impact of the programme, as it has only been a few months that the revised programme is in practice. Various curriculum frameworks have time and again pointed out that teacher education programme have direct impact on education system of any country. Therefore, pedagogical revisions and addition of new courses in the existing programme would certainly result in revolution in the education system. It may be concluded that changes in teacher education programme was indeed required at the ideological as well as practical level. The new course should focus around critical pedagogy and realize the agency in every individual learner so that the true meaning of education may be realized. The new course should produce sensitive and innovative teachers trained in their profession of guiding children in building new knowledge. There is a need of effective campaigning of the new and prolonged programme which can attract quality students to pursue teaching as their profession. It is important to highlight that the new course should be implemented efficiently by all the stake holders involved. Though, critics point to the rundown nature of education and the public has accepted that it is because the teachers shirk work and are the problem. This decline in the status of academics has enabled the politicians, bureaucrats and businessmen to intervene even though they neither understand the ground realities nor accept their own role in running the system down. Therefore, it is expected that all those who have stake in the system of education should contribute in their specific and significant ways. In brief, if talent is to be nurtured, the revised Two Year B. Ed. Programme must overhaul the entire education system based on the ground realities and a holistic perspective. For this, diverse academic voices need to be heard rather than only of those at the top and who have actually been creating the problem and whose agenda may not be real reform.

References:-

1. All India Survey on Higher Education Report, Ministry of Human Resource and Development, Government of India, 2011-12.
2. All India Survey on Higher Education Report, Ministry of Human Resource and Development, Government of India, 2012-13.
3. Goel ER, Chhaya Goyal. Teacher Education Scenario in India: Current Problems & Concerns in MIER Journal of Educational Studies Trends & Practices. 2012 Nov;2(2):231-242.
4. Policy Perspective in Teacher Education: Critique and Documentation, National Council of Teacher Education, New Delhi, 1998.
5. Arora GL, Pranati Panda (Eds.). Fifty Years of Teacher Education in India: Post Independence developments, NCERT, New Delhi, 2004
6. Annual Report, Ministry of Human Resource and Development, Government of India, New Delhi, 2011.
7. Annual Report, Ministry of Human Resource and Development, Government of India, New Delhi, 2012.
8. Annual Report, Ministry of Human Resource and Development, Government of India, New Delhi, 2013.
9. Annual Report, University Grants Commission, Government of India, New Delhi, 2013.
10. All India Survey on Higher Education Report, Ministry of Human Resource and Development, Government of India, 2013-14.
11. Annual Report, Ministry of Human Resource and Development, Government of India, New Delhi, 2014.
12. Annual Report, University Grants Commission, Government of India, New Delhi, 2014.
13. Education For All Towards Quality and Equity India Report, National University of Educational Planning and Administration, New Delhi, 2014.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

Study of Energy and Momentum of Super Bis String Using String Bis Theory

V.P. Singh*

Abstract - In the present paper we study about the energy and momentum of super BIS-string, we also study about the annihilation of eco-system and periodicity and momentum of BIS-string.

Introduction -

1. Origin Of Bis Field

1.1. In this we study different bisophysical processes, which generate intense and very high BIS field.

1.2. Scattering Amplitude: Amplitude for a scattering of EP waves with two incoming and two outgoing nociceptons, reffered as BIS scattering amplitude. The amplitudes describe a one-dimensional object moving in space. The BIS surface described by the motion of nociceptons is called a world-sheet. Its embedding into space time is described by the functions X^μ (ρ,τ) where σ,τ are co-ordinates on the world sheet and X^μ yield the corresponding space time position.

1.3. Length Of Bis String: BIS strings have finite spatial extent. For open BIS Strings the standard choice is an interval of length π. For closed BIS strings the choice of circumference π. The world sheet dynamic is conformally invariant. In other worlds, the possible states of a single are described by a conformal BIS field theory, we make a Wick rotation of τ called Euclidean co-ordinate z.

1.4. Objective Of The Work: In the present work, we aim to study the properties of such strings under varying values of BIS impedance. Here we examine the perturbative aspects of BIS field and the dynamics of strongly interactive nociceptons.

1.5. Bis String Theory: Strings are concepts which can be considered as emerging from the study of nocieptons (point particles) which are the quanta of EP waves.

A Suitable action for the description of a massless nocicepton is

$$S = \int d\tau\, e^{-1}(\tau)\, \eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau}.\frac{dx^\nu}{dt} \qquad (1)$$

Here $\eta_{\mu\nu}$ denotes the Minkowski metric, τ is a parameter along the trajectory X^μ $(\tau)$of the nocicepton.

BIS strings are natural generalizations of nocicepton. The are world sheets described by X^μ (ρ,τ). The action for a BIS string is

$$S = \int d^2\sigma \sqrt{h}\, h_{\alpha\beta}\, \eta_{\mu\nu}\, \partial_\alpha X^\mu\ \partial_\beta X^\nu. \qquad (2)$$

Which is the area of the world sheet.

Here $h\alpha\beta$ is a metric on the world sheet, and h is its determinant.

Conformal gauges are the convenient parametrization of the world sheet, for which world sheet is conformaly flat:

$$h_{\alpha\beta} = \eta_{\alpha\beta}{}^{e\phi,} \qquad (3)$$

$\eta_{\alpha\beta}$ is a flat metric.

In this gauge, the action becomes.

$$S = \int d^2\sigma\ \eta_{\mu\nu}\ \partial_\alpha X^\mu\ \eta_{\alpha\beta}\ \partial_\beta X^\nu \qquad (4)$$

Variation of the action leads to the wave equation

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial\tau^2} - \frac{\partial^2}{\partial\sigma^2}\right) X^\mu = 0 \qquad (5)$$

And to the constant equation

$$T_{\alpha\beta} = \frac{\delta S}{\delta h_{\alpha\beta}} = 0 \qquad (6)$$

1.6. Bis Super String Theory: BIS superstring theory can be formulated either by the Neveu-Schwarz – Ramond or by the Green – Schwarz (GS) formalism. In the light cone gauge, out of ten fields X^m (ρ,τ)(m=0, ……….9), two are eliminated: defining ,$x^\pm = x^0 \pm x^9$, one sets x^+ τ to completely fix the gauge, while x^- turns-out to be completely fixed in terms of the transverse degrees of freedom. So the true degree of freedom of the theory are the transverse ones, +2 with i = 1, …….. 8. For super symmetric theory, we add the fermionic part, which consists of two sets of 2D Majorana – Wey l fermions : θ_s and θ_s

The GS light – cone is action is

$$S = \frac{1}{2\pi} \int_{\tau=-\infty}^{\tau=+\infty} \int_{\sigma=0}^{\sigma=\pi} d\sigma d\tau \left(\partial_\mu x^i\, \partial^\mu x^i - i\, \partial^\mu \vartheta\, \partial_\mu \vartheta\right)^{(7)}$$

1.7. Self Energy Of A Bis String: For self energy of a BIS string, we consider a totally branched curve from z = 0 to z = ∞

The polynomial

$p=y^3+czy+z(Z-a)$

Provides the solution over these points. Solutions are given by the points of the carrier on the q = 0 and p + q = N lines

*Associate Professor (Physics) D.J. College, Baraut (CCS University, Meerut) (U.P.) INDIA

respectively. One simple solution is given by the carrier shown in Fig. 1.6.1

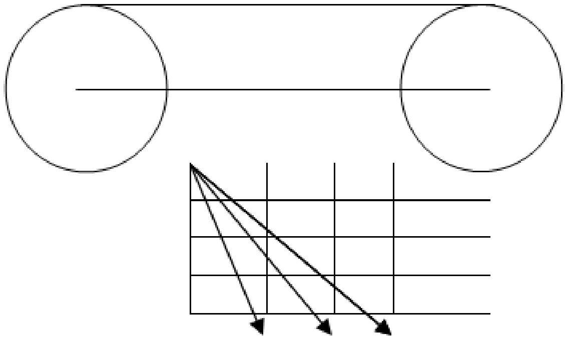

Fig. 1.6.1 Self energy of a BIS string

2. Bis Amplitude

2.1 Amplitude Of Bis String

String amplitude is to integrate over the Cartan modes in the functional integral with action

$$S = \frac{1}{\pi}\int d^2Z\ (\partial_z\tilde{X}^1\,\partial_z\tilde{X}^1 + i(\tilde{\theta}_s\,\partial_z\tilde{\theta}_s + \tilde{\theta}_c\,\partial_z\tilde{\theta}_c) \quad (8)$$

Since the action is free, the integration produces a ratio of determinants, which turn out be a constant. However we have to take account of the zero modes for the fields which have been rescaled. The rescaled fields in C are Maxwell and the ghost fields. The corresponding fields in will be rescaled to

$$\tilde{a}_z --> g\ \bar{a}_z, \tilde{a}_z --> g\bar{a}_z, \tilde{C} --> gc^{-}, c --> g\tilde{\bar{c}}.$$

In fact under this rescaling the Maxwell partition function

$$Z^{\Sigma}\ Maxwell = \int D\,[\tilde{a},\tilde{\bar{a}},\ \tilde{c},\tilde{\bar{c}}]\ e^{-s\Sigma}\ maxwell\ (\tilde{a},\tilde{\bar{a}},\ \tilde{c},\tilde{\bar{c}}).$$

2.2 Periodicity And Momentum Is Bis String

Let the compactified BIS string co-ordinate with the periodicity condition be Y (σ,t)

$Y(\sigma,t) + 2\pi R = Y(\sigma,t)$ (9)

The string co-ordinate is also periodic, when σ goes over 2π for the closed string.

The mode expansions for right and left moving sectors are

$$Y_R = Y_R + \sqrt{\frac{1}{2}}\ P_R(\tau - \sigma) + \text{oscillators}, \quad (10)$$

$$Y_L = Y_L + \sqrt{\frac{1}{2}}\,P_L(\tau + \sigma) + \text{oscillators}, \quad (11)$$

The momentum zero modes P_{RL} will have the following from to be consistent with

$$P_R = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{n}{R} - R_m\right) \text{and} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{n}{R} + R_m\right) \quad (12)$$

The total momentum is just $P = \frac{1}{\sqrt{2}}(P_R + P_L)$ which is the integral of momentum density over

The total Hamiltonian is

$H = L_0 + L_0 = 1/2\ (P_L^2 + P_R^2) +$ Oscillators (13)

In the general case of toroidal compactification

$$H = \frac{1}{2}\ G_{\alpha\beta}(Y^{\alpha}Y^{\beta} + Y'^{\alpha}Y'^{\beta}) \quad (14)$$

Where $G^{\alpha\beta}$ are constant backgrounds α,β=1––––,d nd $Y^{\alpha}(\sigma,t)$ are the string co-ordinates.

Conclusion : The present work reveals many useful features relevant to the perturbative aspects of BIS fields. The BIS theory describes the dynamics of strongly interacting nociceptons. One of the most important achievements of BIS string theory has been to address important issues in quantum bisology and provide answers to some of the unresolved puzzles.

BIS string theory will provide us extremely useful tools to comprehend the bisological consequences in diverse disciplines of human knowledge (seismology, medical science, astronomy and cosmology). The BIS string cosmology has opened up completely new horizons of thinking about our universe (both anatomy and physiology of the universe are affected by BIS process). Intense and far reaching BIS fields lead to BIS strings and BIS superstrings. In order to weaken these BIS strings it is necessary to reduce the BIS impedances.

References:-

1. Bajaj M.M. and Ibrahim M.S.M., Molecular and Cellular chaos in Aids, Cancer, multiple Sclerosis and Muscular Dystrophy, (a) The National Academy of Science, India (64th Annual Session), September 29- October 1, 1994, 64,pp. 7.(b) First International Scientific Conference, Cairo, Egypt, 20-30 March 1995, 1, pp.230
2. Bajaj M.M. and Ibrahim M.S.M., mathematical Foundations of Action and Scientific Bassis of Action Theraphy, First International Scientific Conference, Cairo, Egypt, 20-30 march 1995, 1, pp. 258
3. Bajaj M.M. and Ibrahim M.S.M, Mock – Theta Functions in Hansen's Disease Spectrum, First International Scientific Conference, March 20-23 March, 1995, Cairo, Egypt and Indian Science Congress Association., 82, 3-8 Jan. 1995
4. Bajaj M.M., Nath R. ad Ibrahim M.S.M., Quantum Chaos Created by the Cytomegalvirus and the Etiology of Guillain Barre Syndrome. First International Scientific Conference, march 20-23 1995, Cairo, Egypt and India Science Congress Association, 82, 3-8 Jan. 1995.
5. Bajaj M.M., Ibrahim M.S.M. and singh V.R., Origin of yersinia Pestis First International Scientific Conference, 20-23 March 1995, Cairo, Egypt.
6. Nur U., Werren J.H., Eickbush D.G., Burke W.D. and Eickbush T.H., A 'Selfish' B chromosome that enhances its transmission by elimination the paternal genome, Science, 240, 512-514, 1998.
7. Bajaj M.M.and Ibrahim M.S.M., A New Theory of Pin Perception by String made of 5-Hydroxytrptamine Receptors. First International Physiology Conference, 21-23 Dec 1993, Lahore (Pakistan).
8. IBRAIM M.S.M. and Bajaj M.M., Chaotic Vibration in Nociceptors and Annihilation of Davyog Solution, Asian

Journal of Physics, Vol. 4, No. 3 (1995), Indian Science Congress Assoc. 82, 1995.

9. Ibrahim M.S.M. and Bajaj M.M. Quantum Chaos created by the Carboxy Terminal of Dystrophin and the Origon of Muscular Dystrophy by Aperiodic Behaviour, First International Scientific Conference, 20-23March 1995, Cairo Egypt., 1, pp. 231

10. Bajaj M.M. and Ibrahim M.S.M. Hypergeometric Functions Pertaining to 5-HT Receptors, 4th International Congress of the International Pain Association, Telavia, Isreal, 27-30 Sept 1994, pp. 188.

11. Bajaj M.M. Ibrahim M.S.M. and Bajaj S.P., Multifrctals Hausdroff Dimension and Scaling Index Spectrum in Burn Traumatology, First International Scientific Conference, Cairo, Egypt, 20-23 March 1995, pp. 187 and Indian Science Congress Association 82, 3-8 Jan. 1995

12. Bajaj M.M. Ibrahim M.S.M. and Nath R., Se, Motherhood and AIDS, National Conference on AIDS Awareness and Prevention. 1 Dec. 1994, Delhi.

13. Bajaj M.M. and Ibrahim M.S.M., A String Theory of Human Feeling and its Association and Neural Networks, First International Scientific Conference, 20-13 March 1995, Cairo, Egypt.

****

Theoretical Study of Bis-Scalar Field,Bis- Phase in Seismology

V.P. Singh*

Abstract - In present study we discuss the BIS scalar field and its stochastic mechanics, bis phase in seismology due to intense slaughtering of marine –creatures.

Introduction - In this paper we study the propagation of EP waves, VLF signals and BIS effect caused by the killing of aqua-creatures. Induced BIS effect caused by the killing of fisheries, shrimps, crab etc. is responsible for configuration spaces and vector fields.

Aquaculture is the method of increasing the artificial or forced production of marine creatures (fish, shrimp, crab etc.) with the sole aim to kill them for earning money and selling living creatures for food. Eating of living creatures leads to more than 300 diseases in human beings.

1.2. Global Aquaculture and Killing of Marine Creatures: For global aquaculture, 30 billion dollars (*US \$ 30 × 10^9 = Rs. 1.5 × 10^{12}) have been invested by 150 countries. What surprises us is the great unity existing between murderers and killers. At present, 150 countries of the world are practising aquaculture. Of course, for those, who practice aquaculture, lives of fisheries and other marine creatures, have no meaning. The sole goal is to get food in India and abroad and earn foreign exchange forgetting the basic right of living of each and every creature. Annual growth rate of global aquaculture is 10%. Contribution to fish production through aquaculture is 36 million tons worth US$ 50 billions. Asia's share to this production is 91%.

1.3. Nociception Waves and VLF Signals: The communication theory for the propagation of EP waves, VLF signals and BIS processes play a very significant role in affecting the studies of cross-correlation functions of two random BIS processes, using Einstein-Weiner-Khintchinc relations. Infrasonics and VLF signals are responsible for the origin of earthquakes, cyclones, willy-willies, sea-quakes, excessive rainfall, draughts and several natural disasters,. The prime objective of the present chapter is to report a high tech study of living state forced annihilation operator of beta type and strong BIS mechanics of second category. Einstein pain is experienced by animals and living creatures at the time of slaughtering.

This type of pain also leads to cancer pain, headache, migraine, cluster pain etc.

2. Quantum BIS States in Seismology: In order to understand the far reaching implications of the energetic quantum BIS states in seismology, we have considered here the broad band BIS receiver functions abstracted from teleseismic P wave forms recorded by a 3-component Strekeison seismograph. We have constrained the BIS sheer velocity structure of the underlying crust. BIS receiver functions obtained from the records of both shallow and intermediate focus earthquake lying in different stations, BIS events azimuths exhibit coherence in arrival time and shape of the significant BIS shear wave phases : P_s, P_p, P_s, P_sP_s/P_pP_s indicating horizontal stratification with in the limits of resolution. This is also corroborated by the relatively small observed amplitude of the BIS tangential component and BIS receiver functions which are less than 10% of the corresponding BIS radial component.

2.1. BIS Receiver Functions: BIS receiver functions are selectively abstracted horizontal components of the BIS P-wave from ground motion, which represent P to S converted BIS phase and multiplies that are sensitive to the BIS shear velocity structure. These locally generated BIS sheer phases are very weak compared with the dominating BIS P phases. The use of teleseismic P wave forms that arrive at a distant station with constant horizontal phase velocities, approximating a plane BIS wave, their steep angle of incidence at the base of the lithosphere causes the amplitude of converted BIS shear phases.

2.2. Converted BIS Phase: Converted BIS phases constitute a BIS receiver function for the crystal structure by deconvolving the vertical component of the BIS P waveform from the corresponding horizontal components of the first 30 to 40 s of the ground motion record.

BIS receiver function thus obtained over a horizontally stratified earth appears as a scaled version of the component of ground motion with P multiplies entirely eliminated. The deconvolution is accomplished by division in the Fourier transformation.

*Associate Professor (Physics) D.J. College, Baraut (CCS University, Meerut) (U.P.) INDIA

Let $V^{BIS}(t)$ and $R^{BIS}(t)$ represent a ray description of the BIS-vertical and BIS-radial components of ground motion respectively and $V^{BIS}(w)$ and $R^{BIS}(w)$ their Fourier domain counterparts, then

$$V^{BIS}(t) = \sum_k V_k s(t - t_k) \qquad (2.2.1)$$

$$R^{BIS}(t) = \sum_k r_k s(t - t_k) \qquad (2.2.2)$$

The Fourier domain BIS receiver function is

$$H^{BIS}(\omega) = \frac{R^{BIS}(\omega)}{V^{BIS}(\omega)}. \qquad (2.2.3)$$

where s(t) is the source time function and tk the instant of arrival of the kth ray. The case k = 0 represents the direct P phase, but usually.

$$H^{BIS}(\omega) = \frac{R^{BIS}(\omega)V^{BIS}(\omega)F^{BIS}(\omega)}{\phi^{BIS}(\omega)}. \qquad (2.2.4)$$

where $V^{BIS}(\omega)$ is the complex conjugate of $V^{BIS}(\omega)$ and

$$F^{BIS}(\omega) = fe^{\left(\frac{-\omega^2}{\ldots}\right)} \qquad (2.2.5)$$

is the Gaussian filter formalized to unit amplitude in the time domain by the factor f and having a width a, and

$\phi^{BIS}(\omega) = \max$ [

$V^{BIS}(\omega)V^{BIS}(\omega), c \max [V^{BIS}(\omega)V^{BIS}(\omega)\}]$

(2.2.6)

The corresponding time domain BIS recover function $h^{BIS}(t)$ can be given by

$$h^{BIS}(t) = \frac{r_0^{BIS}}{v_0^{BIS}}[\delta(t) + r_{sk}(t - t_k)]$$

Here r_v^{BIS} and v_v^{BIS} are the vertical and BIS horizontal amplitudes of the direct P BIS phase and rsk, those of the various converted BIS shear wave phases. The factor (r^{BIS}_v / v^{BIS}_v) scales the BIS radial receiver function and depends on the epicentral distance as well as on the extent of contamination by scattered waves. In BIS receiver function analysis, this quantity used to be normalized to unity, thereby obliterating the effect of varying epicentral distances, through the incidence angle of BIS P waves. This is useful, while stacking BIS receiver functions from events covering a large geographical spread.

2.1.BIS Momentum

The momentum of a nociception with mass m and velocity u is a vector defined as

$$p = mu. \qquad (2.3.1)$$

follows from Newton's second and third laws, and experiment confirms, that in a system of particles possibly interacting with each other but free of any other forces, the total momentum is conserved in the sense that it does not change in time even if the individual momentum do change :

$$\frac{d}{dt}\sum_i m_i u_i(t) = \frac{d}{dt}\sum_i p_i(t) = 0 \qquad (2.3.2)$$

We wish to study systems where between reactions the nocicepton move freely, and where reactions happen fast enough for the time they take to be negligible or of no interest. Reactions can be induced by collisions, or it can happen that a particle disintegrates spontaneously into nocicepton of different types, without needing to be stimulated by collisions with particles already present. For instance, in a gas mixture the reaction quoted above would result from a collision between a hydrogen and a chlorine molecule, while an appropriate excited state of a complex enough molecule might disintegrate spontaneously into other smaller molecules. For such abrupt reaction affecting nocicepton that between reacions move freely, the conservation law (2.3.2) reduces to the same form as

$$\Delta \sum_i p_i = 0 \qquad (2.3.3)$$

The Galilean transformation of P follows from the rule of u and from the invariance of m :

$$p' \equiv \mu' = m(u - v) \Rightarrow p' = p - mv, p = p' + mv \quad (2.3.4)$$

Often one needs names for the total mass and the total momentum of a system of particles not interacting except through collisions. Hence we define

$$M \equiv \sum_i m_i \quad p \equiv \sum_i p_i \qquad (2.3.5)$$

with sums evaluated at any time when no collision is taking place. Then the conservation rules reduce to

$$\Delta M = 0, \quad \Delta P = 0 \qquad (2.3.6)$$

Derivation of the transformation rules for the total BIS momentum.

From equations (2.3.5) and (2.3.6).

$$p' \equiv \sum p'_i = \sum (p_i - m_i v) = \sum_i p_i - v\sum_i m_i = P - M_v \qquad (2.3.7)$$

where the second equality follows because v is a common factor that can be brought outside the summation. In other words, the total BIS momentum transforms just ask if the entire system constituted a single nocicepton with mass and momentum equal to the total mass and total momentum of the system.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018, Vol. II

One looks at a system of nociceptons sit were from the outside, temporarily ignores anything one might know about its internal structure, and treats it as if it were a single particle with mass M, momentum P, and eventually with the kinetic and total energies K and E to be introduced presently. For example, the frame S¢ where P¢= 0 is sometimes called the centre-of-mass frame of the system, through it is better referred to as the centre-of-momentum frame, a concept easier to generalize later on.

2.1.BIS Force

By Newton's second law, force is mass times acceleration, f = ma. Since mass and, as we have seen, acceleration are invariant, so is force :

$$f' = ma' = ma = f \qquad (2.4.1.)$$

The same follows from the alternative but equivalent definition of force as ratio of change of BIS momentum: since t = t′ we have d/dt = d/dt′, whence (v is not variable).

$$f' \equiv \frac{dp'}{dt'} = \frac{d(p - mv)}{dt} = \frac{dp}{dt} = f \qquad (2.4.2.)$$

THEORY

2.1. Scalar BIS Fields and their Stochastic Mechanics

The concept of scalar BIS fields emerges from the detailed and extensive experimental observations of the environmental and physical consequences of large-scale forced and deliberate annihilation of living creatures. These fields are extremely strong near the regular and mechanized abattoirs and vat oceanic areas from where innumerable marine creatures are caught daily using most modern techniques of fishing.

These fields are stochastic in nature, therefore they have not been given due importance in the development of mathematical bisology so far. We need stochastic mechanics to understand them. The free scalar BIS Field-Hamiltonian in natural units (t = c = 1) is

$$H = \frac{1}{2}\int [\delta_t \phi^2 + \nabla\phi^2 + m_v^2\phi^2] d^3x: \quad x \in R^2 \quad (3.1.1.)$$

Suppose {un(x)} (n = 1, 2, 3,.. , positive integers) is the complete set of basis vectors having box normalization in a finite box of Volume V.

For normalization

$$\sum u_n(k) u_n(k) d^3x = \delta_{nn'} \qquad ...(3.12)$$

where $\delta_{nn'} \overset{v}{=}$ Kronecker delta function

$$\delta_{nn'} = 1, \text{ if } n = n' \text{ and}$$

$$\delta_{nn'} = 0, \text{ if } n \neq n'$$

Completeness relation is

$$\sum_n u_n(x) u_n(k') = q^3(k) - (k') \qquad ...(3.13)$$

Harmonic oscillation equation is

$$\nabla^2 u(k) = -K_n^2 u_n(k) \qquad ...(3.14)$$

For the infinite volume,

We replace $\delta_v(k - k')$ by $\delta(k - x')$ where $\delta_{k-k'}(x \quad x) = \frac{}{(2\pi)^3}\sum e$ (3.15)

The free field is an infinite set of harmonic oscillators in a function of x and t.

We can expand it in the form of an infinite series consisting of the products of two independent functions. (One of x and another of t).

$$\delta(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) q_n(t) \qquad (3.1.6)$$

$$\delta_t^2 q_n(t) + w_n^2 q_n(t) = 0 \qquad (3.1.7)$$

$$\text{Hamiltonian } H_n = \frac{p_n^2}{2} + \frac{w_n^2 q_n^2}{2} \qquad (3.1.8)$$

The parisi-we stochastic quantization shows a Euclidean quantum BIS field P(x) as the stationary limit with respect to a fictitious time T (like the computer time of a Montu-Carol stimulation) of the stochastic relaxation defined. For T ≥ b a generalized. Langerian equation.

$$d\Psi(zx) = -\frac{ds[\Psi(x)]}{d\Psi(z, x)} + n(\tau, x) \qquad (3.1.9.)$$

Conclusion: When we capture more and more marine creatures, the pressure above the ocean increases due to the turbulence created by fisheries as a result of their basic instinct to live. This change desire of pressure is equalised by the flow of strong marine winds towards the surface where the atmospheric pressure is low. This particular phenomenon leads to different forms of sea-storms or oceanic storms.

Man creates turbulence in the ocean by following methods :

(i) Oil exploration, (ii) drilling of oil-wells and setting up of permanent oil platforms for oil extraction, (iii) motion of heavily loaded large-size ships and small size boats and motor boats. (iv) Killing of marine creatures.

Out of the above four reasons, most significant is the last one. The contribution of (iv) in the overall turbulences leads to sea storms. By killing or capturing the marine creatures, we generate turbulence in the ocean and the eye of the cyclone appears, which on manifestation becomes super cyclone. Random motion of the marine creatures is extremely helpful in stopping the water to rush in a particular direction.

BIS effect directly affects the tornado wind intensity. The number of living creatures killed and the velocity generated are based on authentic, well-documented published literature. More is the number of marine creatures deliberately by man, more is the speed of the wind associated with the tornado.

References:-

1. **Bajaj M.M., Ibrahim M.S.M. 1994.** Catalytic Factors Responsible for Quantum Chaos of Cell Mediated Immunity in Hanson's Disease, 28th Annual Convention of Indian College of Allergy and Applied Immunology, "AICONDESERT 94" 25-27 Nov. S.P. Medical College, Bikaner (Rajasthan), pp. 18.
2. **R.K. Jha and M.M. Bajaj.** Effect of BIS Load Enhancement on the DNA Sequence: Impact of LSFAO on the Human Chromosome 14; IV Annual Symposium on Frontiers in Biomedical Research at B.R.A. Centre for Biomedical Research, University of Delhi (13th-15th April 2003)
3. http/www.seismology,cyclones/2014-16.
4. **G.N. Navaneeth, N.P. Dhoptey, O.P. Nagpal & M.S.M. Ibrahim**
5. **H.F. 1992.** Radar for Monitoring Ionisopheric Disturbances, National Space Science Symposium, March 11-14, Physical Research Laboratory, Ahmedabad.
6. **Krantz, L.J. Copp, P.J. Coles, R.A. Smith, S.B.** Heard, Biochemistry 30 (1991) 4678.
7. **G.B. Fields, R.L.** Noble, Int. J. Pept. Prot. Res, 35 (1990) 161.
8. **Hegyi, J. Ziebuhr,** J. Gen. Virol. 83, (2002) 595.
9. **K. Anand** et al. EMBO J. 21 (2002) 3213.
10. **J. Horold,** T. Raabe, B. Schelle-Prinz, S.G. Siddell, Virology 195 (1993) 680.
11. **Bajaj M.M. and Ibrahim M.S.M. 1996.** Parkinsonism and Chaotically Interacting Bosons, XIIth International Biophysics Congress. Aug. 11-16, Amsterdam, The Netherlands.
12. **Lee, F.M. Richards,** J. Mol. Biol. 55 (1971) 379.
13. **A.A. Vaguine, J. Richelle, S.J. Wodale,** Acta Crystallogr. D55 (199) 191.
14. **R.A. Laskowski, M.W. MacArthur, D.S. Moss, J.M. Thornton,**
15. **J.** Appl. Crystallogr. 26 (1993) 283.
16. **R.J. Read,** Acta Crystallogr. A42 (1986) 140.
17. **M.M. Bajaj, R.K. Jha, S. Upadhyay and S. Singh.** Effect of BIS Load Enhancement on the DNA Sequence: Impact of LSFAO on the Human Chromosome 14; IVth Annual Symposium on Frontiers in Biomedical Research at B.R.A Centre for Biomedical Research, University of Delhi (13th April, 2003).
18. **Bajaj M.M., Ibrahim M.S.M. and R. Nath, 1994.** Muscular Dystrophy and MoehTheta Functions, 60th Annual Conference of Indian Mathematical Society, University of Poona, Dec.
19. **Bajaj M.M. and Ibrahim M.S.M., 1994.** Pain Transferability Theorem, 60th Annual Conference of Indian Mathematical Society: University of Poona, Dec.
20. **Bajaj M.M. and Ibrahim M.S.M. 1994.** The Crutchficid Information Metric in Muscular Dystrophy, Multiple Sclerosis and Other Neurological Disorders, 60th Annual Conference of Indian Mathematical Society University of Poona, Dec.
21. **Bajaj M.M., Ibrahim M.S.M. and V.R. Singh, 1995.** Quantum Chaos in Immunology and Proliferation of Plague in India: Investigation Based on 100 Years Statistical Data. Indian Science Congress Association, 82, Jan. 3-8.
22. **Z. Otwinowski, W. Minor, Meth.** Enzymol. 276 (1997) 307.
23. **J. Navaza,** Acta Crystallogr. D54 (1998) 905.
24. **A.T. Briinger** et al., Acta Crystallogr. D54 (1998) 905.
25. **G.N. Murshudov, A. Lebedev, A.A. Vaagin, K.S. Wilson, E.J. Dodson,** Acta Crystallogr. D55 (1999) 247-255.

****